सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली

प्रकाशित :
नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। www.mea.gov.in

सामने का कवर जवाहरलाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय के जून 2011 के बाद से नये भवन को दर्शाता है।

सामने कवर के अन्दर 1947 के बाद साउथ ब्लाक, विदेश मंत्रालय की सीट को दर्शाया गया है।

पिछले पृष्ठ के भीतरी भाग में जवाहरलाल नेहरू भवन के अन्दर प्रदर्शित वस्तु को दर्शाया गया है।

अभिकल्पन एवं मुद्रण :

डाल्फिन प्रिन्टो–ग्राफिक्स
4ई/7, प्रथम तल, पाबला बिल्डिंग,
झंडेवालान विस्तार, नई दिल्ली–110055
दूरभाष : 011–23593541–42
E-mail : dolphinprinto2011@gmail.com

विषयवस्तु

	प्रस्तावना और सारांश	i-xxxi
1.	भारत के पड़ोसी देश	1
2.	दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत	14
3.	पूर्वी एशिया	25
4.	यूरेशिया	29
5.	खाड़ी तथा पश्चिम एशिया	35
6.	अफ्रीका	44
7.	यूरोप और यूरोपीय संघ	63
8.	अमेरीका	83
9.	संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन	97
10.	निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले	111
11.	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	116
12.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)	122
13.	विकास सहयोग	124
14.	निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन	129
15.	ऊर्जा सुरक्षा	131
16.	आतंकवाद विरोध एवं नीति नियोजन	133
17.	नयाचार	135
18.	कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	141
19.	प्रशासन और स्थापना	149
20.	सूचना का अधिकार और मुख्य जनसूचना अधिकारी का कार्यालय	153
21.	ई–गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी	154
22.	समन्वय प्रभाग	155
23.	विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग	157
24.	विदेश सेवा संस्थान	164
25.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा विदेश में हिन्दी का प्रचार–प्रसार	166
26.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	167
27.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद्	169
28.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	172
29.	पुस्तकालय	175
30.	वित्त और बजट	177

परिशिष्ट

परिशिष्ट I :	वर्ष 2013–14 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत संधियां / अभिसमय / करार	179
परिशिष्ट II :	जनवरी, 2013 से अक्तूबर, 2013 तक की अवधि के दौरान जारी पूर्ण अधिकार के दस्तावेज	187
परिशिष्ट III :	जनवरी, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान जारी अनुसमर्थन / स्वीकृति दस्तावेज	189
परिशिष्ट IV :	आइटेक और स्काप देशों की सूची	192
परिशिष्ट V :	आइटेक / स्काप के पैनल में संस्थानों की सूची	195
परिशिष्ट VI :	नीति, आयोजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्णतः वित्तपोषित विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित किए गए सम्मेलन / सेमीनार / अध्ययन परियोजनाएं	197
परिशिष्ट VII :	जनवरी से दिसंबर, 2013 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या, प्राप्त कुल विविध आवेदन और प्रदत्त सेवाएं, तत्काल योजना के तहत जारी पासपोर्टों की संख्या और अर्जित राजस्व तथा पासपोर्ट कार्यालयों के कुल राजस्व और व्यय का विवरण	198
परिशिष्ट VIII :	31.12.2013 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की कैडर संख्या	200
परिशिष्ट IX :	31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों / केंद्रों में संवर्ग संख्या (जिसमें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट प्रदत्त पद तथा संवर्ग–बाह्य पद आदि शामिल हैं)।	201
परिशिष्ट X :	मंत्रालय में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती और आरक्षित रिक्तियों से संबंधित आंकड़े।	202
परिशिष्ट XI :	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भा.वि.सेवा अधिकारियों की संख्या	203
परिशिष्ट XII :	आरआईएस प्रकाशनों की सूची	204
परिशिष्ट XIII :	वर्ष 2013–14 में विदेश मंत्रालय का वित्तीय ब्यौरा	205
परिशिष्ट XIV :	वर्ष 2013–14 के बजट में मुख्य क्षेत्रों को आबंटन (संशोधित अनुमान)	206
परिशिष्ट XV :	भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के प्रमुख गंतव्य	207
परिशिष्ट XVI :	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लंबित लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति	208
संक्षिप्तियां		211

प्रस्तावना और सारांश

भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सार्थक संबंध पर बल देती है ताकि राष्ट्रीय आर्थिक बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुत्ता और भौगोलिक एकता सहित अपने मुख्य लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ हम अपनी मुख्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंताओं का समाधान कर सकें। भारत ने अपने सभी पड़ोसी और सार्क देशों के साथ अपने संपर्क को गहन बनाया है। हमने अमरीका, रूस, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ तथा इसके मुख्य सदस्य देशों, जिनमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी शामिल हैं, के साथ रणनीतिक भागीदारी के आर्थिक और राजनैतिक आधारों को सुदृढ़ और विस्तृत किया है। हमने अपने विस्तारित पड़ोस, आसियान, पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों के साथ सहभागिता को बनाए रखा है। भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नए मंचों को सुदृढ़ किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय लोक नीति के उभरते क्षेत्रों में स्वतंत्र स्थिति बनाई।

भारत ने 2 बिलियन अमरीकी डॉलर के एक व्यापक द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के जरिए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सतत् सहायता की। भारत एक जनतांत्रिक, स्थिर और संपन्न अफगानिस्तान हेतु अफगानिस्तान के नेतृत्व व स्वामित्व में संचालित शांति प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है। भारत ने सुरक्षा, अवसंरचना, व्यापार, विकास और लोगों के पारस्परिक विनिमय (पीपुल–टू–पीपुल एक्सचेंज) सहित अन्य क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया है। अपने सबसे बड़े व्यापार एवं विकास भागीदार भूटान के साथ भारत ने अपने अनोखे और विशेष संबंध को सुदृढ़ करना जारी रखा। मालदीव में सरकार और राजनीतिक दलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक सहयोग से भारत को जनतांत्रिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सहायता मिली। भारत नेपाल को संपन्न, शांतिपूर्ण, स्थिर और जनतांत्रिक देश बनाने में सहयोग करता रहा है और नेपाल गहन द्विपक्षीय विनिमय व विकास सहायता के माध्यम से प्रगति करता रहा है। हमने म्यांमा को लगभग 3000 करोड़ रूपए का सहायता अनुदान प्रदान करने की वचनबद्धता की है और सुरक्षा, सीमा संबंधी मामलों, व्यापार और ट्रांजिट, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता परियोजनाओं और क्षमता निर्माण में सृजनात्मक सहयोग दिया है। भारत ने श्रीलंका से अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय मेल–मिलाप और राजनैतिक समाधान से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करे। भारत हिंसा और आतंक से मुक्त माहौल में शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के जरिए पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मामलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या, नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा की पवित्रता का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है और इस संदर्भ में इस बात पर भी बल दिया कि द्विपक्षीय संबंध की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियंत्रण रेखा पर शांति और सदभाव बनाए रखना आवश्यक है। हमने मुंबई आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के संबंध में पाकिस्तान द्वारा शीघ्र निर्णय करने के महत्व पर भी बार–बार बल दिया है। सभ्यता से जुड़े और ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों के नेटवर्क का आधार हैं। हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं तथा ईरान की आपूर्ति क्षमताओं को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्पर्ण घटक है।

भारत ने चीन के साथ रणनीतिक आर्थिक संवाद (एसईडी) स्थापित किया है। विशेष प्रतिनिधियों ने राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा–विवाद के निपटारे के लिए एक संरचना की तलाश जारी रखी है। भारत और चीन इस बात से सहमत हैं कि भारत–चीन संबंधों को सतत विस्तार देने का आधार सीमा पर शांति और सदभाव है। भारत और चीन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांतों (पंचशील) की 60वीं वर्षगांठ की समृति में वर्ष 2014 को मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदान वर्ष घोषित किया है। दोनों देशों जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सतत सहयोग और समन्वय करते रहते हैं और ब्रिक्स तथा जी–20 के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर निकट संबंध बनाए रखते हैं।

आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति तथा लुक ईस्ट पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दक्षिण–पूर्व एशिया में हमारे विस्तारित पड़ोस के साथ राजनैतिक, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक भागीदारी में वृद्धि के माध्यम से अच्छे संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। आसियान–भारत संपर्क दोनों ओर की रणनीतिक प्राथमिकता है और भारत ने भारत–म्यांमा–थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे तथा कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में प्रगति की है।

अमरीका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय विनिमय तथा द्विपक्षीय सहयोग को प्रमुखता प्राप्त है। भारत ने भारत–अमरीका सिविल नाभिकीय सहयोग करार के वाणिज्यिक कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए और स्वच्छ ऊर्जा के लिए नई पहल की।

रूस के साथ भारत की परंपरागत भागीदारी को आगे बढ़ाया गया। रक्षा सहयोग हमारी रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण घटक है। रूस–निर्मित तीसरा युद्धपोत, आईएनएस त्रिकांड सुपुर्द किया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को अपेक्षित कार्य हेतु तैयार कर दिया गया। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के यूनिट 1 को अक्तूबर, 2013 में पावर–ग्रिड से जोड़ा गया और यूनिट–2 का कार्य 2014 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

अरब स्फुटन (स्प्रिंग) की घटनाओं के बाद, भारत उस क्षेत्र के सभी देशों की सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। हमने अपने हितों की रक्षा के लिए टिकाऊ कार्यतंत्रों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया। मिस्र के संबंध में हमने गैर–हस्तक्षेप, लचीलेपन और प्रकार्यात्मक स्तर पर व्यवहारवाद की नीति अपनाई और समावेशी परिवर्तन योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध किया। सीरिया के संबंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग पर आधारित तथा सीरिया के नेतृत्व वाले व्यापक राजनैतिक समाधान का समर्थन किया। भारत ने जिनेवा–।। में भाग लिया और मानवता आधारित सहायता तथा रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया। हमने नई इजराइल–फिलिस्तीन शांतिवार्ता का स्वागत किया और एक ऐसे संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य फिलिस्तीन संयुक्त राज्य की बात दोहराई जो इजराइल से जुड़ा हो, जिसकी सीमाएं सुरक्षित व मान्यता प्राप्त हो और पूर्वी यरूशलम जिसकी राजधानी हो। आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग को विविधीकृत एवं सुदृढ़ करने के लिए हमने लीबिया के साथ आदान–प्रदान किया। सूडान एवं दक्षिणी सूडान में अपने समग्र ऊर्जा हितों पर विचार करते हुए हमने विकास भागीदारी संबंधी पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तटस्थ दृष्टिकोण की नीति को जारी रखा। खाड़ी क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा एवं जन समुदाय संबंधी हित हैं, अतः नियमित राजनैतिक संबंधों एवं वाणिज्यिक विनिमयों द्वारा अपने रिश्तों को मजबूत बनाया गया।

जनतंत्र, विधि के शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता के बारे में पश्चिमी यूरोप के देशों और हमारे मूल्यों में समानता है। इस संबंध को उच्चस्तरीय राजनैतिक विनिमयों के जरिए मजबूत किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता की मान्यता बढ़ती जा रही है। भारत ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ व्यापक सहभागिता, संबंधों को गहरा और विविधीकृत बनाने की रणनीति जारी रखी।

अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को भारत–अफ्रीका के बीच दो मंच शिखरवार्ताओं के तहत राजनैतिक समर्थन तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से मजबूत किया गया। इन परियोजनाओं में छात्रवृतियां, प्रशिक्षण, अनुदान, ऋण तथा निजी क्षेत्र में निवेश शामिल है। आईएएफएस–।। में घोषित नई पहलों में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला, आगामी तीन वर्ष में 22000 से अधिक छात्रवृत्तियों तथा 80 से अधिक क्षमता–निर्माण संस्थानों की स्थापना शामिल है। भारत अपने सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए आगामी शिखरवार्ता के लिए उत्सुक है। भारत ने लैटिन अमरीका तथा कैरीबियन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उल्लेखनीय उच्चस्तरीय दौरों, बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार, विकास सहायता परियोजनाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र के साथ हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाया क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा में योगदान देने की व्यापक क्षमता है और वहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमा, मालदीव और श्रीलंका में अवसंरचना, जल–विद्युत, बिजली पारेषण, उद्योग तथा मेजबान सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त अन्य क्षेत्रों में बड़ी विकास भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। सीमा पर संपर्क की पहलों पर संतोषजनक प्रगति हो रही है। 161 विकासशील देशों के 8000 विदेशी राष्ट्रिकों को आईटेक, स्काप और कोलंबों प्लान के अंतर्गत स्लॉट प्रदान किए गए। वर्ष 2013–14 में अफ्रीकी देशों के लिए 1176.40 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा एशिया एवं लैटिन अमरीका के लिए 454.41 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला संस्वीकृत की गई।

परमाणु हथियारों से सज्जित एक राष्ट्र के रूप में निःशस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का रूख राष्ट्रीय सुरक्षा हितों तथा ऐसी चुनौतियों से निपटने में सहभागितापूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निकट सहभागिता की अपनी परंपरा से प्रेरित था। भारत वैश्विक एवं भेदभावरहित परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की सभी कार्रवाईयों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए बहुपक्षीयवाद में संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में भारत का चुनाव होने से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत की उपस्थिति और मजबूत हुई है। भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाली कार्रवाईयों में सबसे बड़े सैन्य टुकड़ी दाताओं में से एक रहा है। आधुनिक राष्ट्रमंडल के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है। भारत जी–20, बिम्सटेक, ब्रिक्स, इब्सा और इंडियन ओशियन रिम एसोशिएसन जैसे बहुपक्षीय निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

जी–4 और एल–69 समूहों में समान सोच वाले देशों के साथ भारत

ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने तथा उसकी सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि करने और समकालीन भौगोलिक राजनैतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए उसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक एवं जनतांत्रिक बनाने के लिए इसका विस्तार करने पर निरंतर बल दिया है।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तानः अफगानिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी मई, 2013 और दिसंबर, 2013 में राष्ट्रपति हामिद करजई की तथा अगस्त, 2013 में अफगानिस्तान के द्वितीय उप राष्ट्रपति मोहम्मद करीम खलीली की उच्चस्तरीय भारत यात्राओं से और अधिक मजबूत हुई। अप्रैल, 2013 में विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने अलमाती में आयोजित इस्ताम्बूल प्रोसेस की तीसरी मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने 18–19 नवंबर, 2013 तक नई दिल्ली में इस्ताम्बूल प्रोसेस के तहत ''अफगानिस्तान के साथ व्यापार'' नामक एक सम्मेलन–सह–प्रदर्शनी की भी मेजबानी की। अफगानिस्तान के साथ भारत का लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ है और इसमें सभी प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यकलाप शामिल हैं। विदेश मंत्री ने 15 फरवरी, 2014 को कांधार के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जहां राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ उन्होंने अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) का उद्घाटन किया।

बांग्लादेशः बांग्लादेश नेतृत्व के साथ विभिन्न स्तरों पर हमारे सतत एवं पारस्परिक लाभप्रद संवाद और व्यापक भिन्न–भिन्न वर्ग के क्षेत्रों से बातचीत ने बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2013–14 में द्विपक्षीय सहयोग का मुख्य बिंदु भारत और बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित करारों, प्रोटोकॉलों और समझौता ज्ञापनों के साथ–साथ 2010 की संयुक्त विज्ञप्ति एवं 2011 के संयुक्त वक्तव्य में सहमत पहलों का कार्यान्वयन रहा। इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ भारत से बांग्लादेश की ओर विद्युत प्रवाह को सुचारू बनाने हेतु ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना, अगरतला में इंटीग्रेटेड चैकपोस्ट का उद्घाटन तथा प्रत्यर्पण संधि का अनुसमर्थन शामिल था।

भूटानः भारत और भूटान के रिश्ते पारस्परिक विश्वास और भरोसे पर आधारित हैं तथा निकट एवं मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष 2013 में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनमें जल विद्युत, परिवहन, संचार, अवसरंचना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कृषि शामिल है, में द्विपक्षीय सहयोग में सतत प्रगति हुई। जुलाई, 2013 में भूटान के द्वितीय लोकतांत्रिक चुनावों की सफलता के बाद नए भूटानी नेतृत्व के साथ अनेक उच्च स्तरीय संवाद हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश सचिव ने भूटान की यात्रा की और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अगस्त–सितंबर, 2013 में भारत की यात्रा की। जनवरी, 2014 में भूटान नरेश ने भारत की यात्रा की। भारत सरकार ने भूटान सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2013–2018) के लिए 4500 करोड़ रूपए तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 500 करोड़ रूपए का सहायता पैकेज प्रदान करने पर सहमति दी है।

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार एवं विकास भागीदार रहा है। तीन–जल विद्युत परियोजनाएं– पुनात्सांगछू–। (1200 मेगावाट), पुनात्सांगछू–।। (1020 मेगावाट) और मांगदेछू (720 मेगावाट) का निर्माण तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। वर्ष 2013 में चूखा जल विद्युत परियोजना (336 मेगावाट) की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई और भारत सरकार की 400 करोड़ रूपए की सहायता से निर्मित डुंगसम सीमेंट संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।

चीनः वर्ष 2013 में भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों में चहुंदिश प्रगति हुई। भारत के प्रधानमंत्री और प्रीमियर ऑफ चाइना के कैलेंडर वर्ष 2013 में हुई आपसी दौरे 1954 के बाद पहली बार हुए। प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की वर्ष 2013 में दो बार बैठक हुई। पहली बैठक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 27 मार्च, 2013 को 5वीं ब्रिक्स शिखरवार्ता के मौके पर हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी तथा अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ 5 सितंबर, 2013 को सेंट पीटर्सबर्ग में जी–20 शिखरवार्ता की औपचारिक शुरूआत से पहले पुनः बैठक की।

मालदीवः भारत और मालदीव दोनों देश गहरे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने हेतु प्रयासरत रहे। मालदीव के नए राष्ट्रपति, डॉ0 अब्दुल यामीन ने जनवरी, 2014 में भारत की राजकीय यात्रा की। बहुदलीय गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाले मालदीव तक पहुंच के तौर पर भारत सरकार ने मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री मोहम्मद नशीद और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति श्री मौमून अब्दुल गयूम की भारत यात्राओं को सरल बनाया।

म्यांमाः भारत–म्यांमा बहुआयामी संबंधों का मूल ऐतिहासिक, नृजातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों में है जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान परस्पर उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से सुदृढ़ किया गया। इनमें से महत्वपूर्ण यात्राओं में दिसंबर, 2013 में म्यांमा संसद के उच्च सदन के स्पीकर की भारत यात्रा और जून, 2013 में म्यांमा में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में उपस्थित होने के लिए हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की यात्रा शामिल है। 11 दिसंबर, 2013को दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नेपालः भारत–नेपाल मैत्री और सहयोग की विशेषता मुक्त सीमाएं, लोगों के पारस्परिक संबंध और बहुआयामी सामाजिक–आर्थिक संबंध है। भारत ने नेपाल को एक संपन्न, शांतिपूर्ण, स्थायी और लोकतांत्रिक देश बनने में सहयोग दिया है। नवंबर, 2013 में उनकी द्वितीय संविधान सभा एवं संसद चुनावों के दौरान अनेक नेपाली

नेताओं के साथ गहन द्विपक्षीय विनिमय हुए। भारत सरकार ने चुनावों में उनके द्वारा मांगी गई संभारतंत्रीय सहायता प्रदान की और चुनाव लगभग 70 प्रतिशत मतदान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। प्रधानमंत्री ने श्री सुशील कोइराला को फरवरी, 2014 में नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी।

वर्ष 2013 में भारतीय और नेपाली सैन्य स्टाफ के मुखियाओं की पारस्परिक यात्राओं के जरिए और अप्रैल, 2013 में सुरक्षा मामलों पर 10वें द्विपक्षीय परामर्शदाता समूह में भारत–नेपाल रक्षा संबंधों को मजबूती दी गई। काठमांडू में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का कार्य पूरा होने वाला है, और इस प्रकार नेपाल को प्रदत्त विकास सहायता का प्रभावी उपयोग किया गया। भारत नेपाल में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और निवेशक बना रहा। दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के नेतृत्व में व्यापार व पारगमन संबंधी अंतर–सरकारी समिति की बैठक 21–22 दिसंबर,2013 को काठमांडू में हुई।

पाकिस्तानः भारत पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मुद्दों को आतंक एवं हिंसा से मुक्त माहौल में शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। आठ मुद्दों पर पुनः शुरू हुई बातचीत के दो दौर सितंबर, 2012 में पूरे हुए; वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक का तीसरा दौर भी उसी माह शुरू हो गया था। तथापि, जनवरी, 2013 में नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं और अन्य घटनाओं, जिनमें पाकिस्तान में चुनाव शामिल हैं, के कारण पुनः शुरू हुई बातचीत की आगे की वार्ता इस वर्ष के दौरान निर्धारित नहीं की जा सकी। तथापि, तकनीकी स्तरीय बैठकें आयोजित हुई और निजी व्यापार संवर्धन शिष्टमंडल परस्पर आते–जाते रहे।

मई, 2013 में पाकिस्तान के चुनावों में श्री नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी हुई। भारत ने नई पाकिस्तानी सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नए युग की शुरूआत करने की इच्छा जताई और ऊर्जा, व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई पाकिस्तानी सरकार द्वारा व्यक्त इच्छा पर सहयोग करने की सहमति जताई। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों के मारे जाने, बार–बार युद्धविराम के उल्लंघन और हमलों की घटनाओं के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा की पवित्रता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस संदर्भ में इस बात पर भी बल दिया कि द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान से बार–बार यह भी कहा है कि मुंबई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदारों के संबंध में भी न्यायिक कार्रवाई शीघ्र की जाए।

श्रीलंकाः भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का आधार सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी आदान–प्रदान है। वर्ष 2013–14 में उच्च राजनैतिक स्तरों पर निकट संपर्क स्थापित किए गए और सृजनात्मक बातचीत, बढ़ता हुआ व्यापार एवं निवेश, अवसंरचना विकास, शिक्षा, संस्कृति एवं रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय हित के बड़े मुद्दों पर व्यापक पारस्परिक समझ को इन संबंधों के दौरान पर्याप्त महत्व दिया गया। भारत के व्यापक विकास सहायता कार्यक्रम ने श्रीलंका के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उत्तरी पूर्वी प्रांतों के पुनर्निर्माण में योगदान किया। श्रीलंका में सम्पूर कोल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में अक्तूबर, 2013 में विदेश मंत्री के दौरे के दौरान करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

दक्षिण–पूर्व एशिया एवं प्रशांत

हाल ही के वर्षों में दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हमारे रिश्तों के विस्तार और गहराई ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया। सभ्यतागत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव और सहयोग को मजबूत करने की इच्छा जैसी विशेषताओं से परिपूर्ण हमारे संबंध बहुआयामी और भविष्यलक्षी हैं तथा इस क्षेत्र के पांच देशों (आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम) तथा आसियान के साथ इसने एक रणनीतिक स्वरूप ले लिया है। इस क्षेत्र में निरंतर आर्थिक प्रगति तथा स्थायित्व के रूख तथा एशिया की ओर उन्मुख सतत भौगोलिक राजनैतिक बदलाव ने इस क्षेत्र में देश–विशेष के साथ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय मंच पर हमारी साझेदारियों को सकारात्मक नई गति प्रदान की है।

हमारी संवर्धित लुक ईस्ट पॉलिसी ने इस क्षेत्र में और इससे परे गहरा प्रभाव डाला है और यह विभिन्न भागीदारों के क्षेत्रीय उपागम को संपूरित करती है तथा हमारे रणनीतिक एजेंडा का एक अभिन्न हिस्सा है। इस क्षेत्र के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण ने राजनैतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। सुरक्षा, संयोजकता तथा क्षेत्रीय एकीकरण नई प्राथमिकताओं के रूप में उभरे हैं।

स्मारक शिखर सम्मेलन 2012 के दौरान स्थापित आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी को संयुक्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं की श्रृंखला, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है, में निकट सहयोग के माध्यम से अधिक मजबूत बनाया गया। आसियान के लिए एक अलग राजदूत की नियुक्ति की घोषणा से इस साझेदारी को मजबूत करने तथा सहयोग एवं कार्यान्वयन को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।

उच्च स्तरीय दौरों को बढ़ाने, सहयोग के मौजूदा संस्थागत कार्यतंत्रों की नियमित बैठकों के आयोजन और आवश्यकतानुसार नए कार्यतंत्रों की स्थापना से संबंधों को मजबूती देने में सहायता मिली है और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति के रूख में भविष्य में वृद्धि की संभावना बढ़ी है। इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा थाईलैंड (मई, 2013) और इंडोनेशिया की (अक्तूबर, 2013) द्विपक्षीय यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर समझ बढ़ाने के अवसर प्राप्त हुए और साथ ही, विभिन्न महत्वपूर्ण करार हुए। प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने ब्रूनेई में इंडिया आसियान शिखर वार्ता तथा

ईएएस (अक्तूबर, 2013) में भी भाग लिया जहां उन्होंने बैठक से अतिरिक्त समय में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वियतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव की राजकीय यात्रा (नवंबर, 2013) की भी मेजबानी की।

विदेश मंत्री ने आसियान भारत और एआरएफ मंत्रिस्तरीय बैठक (जुलाई, 2013) के लिए ब्रूनेई की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने भाग लेने वाले देशों के बारह विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने सिंगापुर (जुलाई और अक्तूबर, 2013), लाओ (सितंबर, 2013), फिलिपीन्स (अक्तूबर, 2013) और आस्ट्रेलिया (अक्तूबर, 2013) का द्विपक्षीय दौरा किया तथा न्यूजीलैंड (जून, 2013), वियतनाम (जुलाई, 2013), सिंगापुर (जुलाई, 2013) और आस्ट्रेलिया (नवंबर, 2013) के विदेश मंत्रियों की भारत यात्राओं की मेजबानी की। हमारे शिष्टमंडलों ने इंडोनेशिया तथा आस्ट्रेलिया की यात्रा की तथा थाइलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, पपुआ न्यू गीतिया और मलेशिया के शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की जिससे संसदीय आदान–प्रदान का सुदृढ़ीकरण हुआ।

दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध हमारे रिश्तों के एक मजबूत स्तम्भ के रूप में उभरे हैं। भारत–आसियान मुक्त माल व्यापार करार के कार्यान्वयन से आसियान देशों के साथ हमारे व्यापार ने लगातार वृद्धि का रूख दर्शाया है जिससे वर्ष 2012–13 में आसियान के साथ कुल व्यापार लगभग 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया; और वर्ष 2013–14 के प्रथम छह माह में बढ़कर यह 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। सेवा एवं निवेश में भारत–आसियान मुक्त व्यापार करार निष्पन्न करने के करार से इस क्षेत्र के साथ हमारी बढ़ती आर्थिक सहभागिता को बल मिलेगा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी पर आसियान और भागीदार देशों के साथ बातचीत शुरू हो गई है जो आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढावा देगा। साथ ही, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार तथा आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार करारों पर बातचीत चल रही है जो प्रतिस्पर्धा एवं प्रगति को बढ़ावा देंगे। भारत के लिए इस क्षेत्र के साथ हमारी आर्थिक संलग्नता हमारी विकास प्राथमिकताओं के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस क्षेत्र के देश बड़े व्यापार एवं निवेश भागीदारों के रूप में उभरें हैं; सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड अवसंरचना विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं; तथा इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया एवं वियतनाम संसाधनों एवं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक, विश्वसनीय स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं। यही नहीं, हमारे कारपोरेट सेक्टर ने अपने समकक्षों के साथ व्यावसायिक संपर्क विकसित कर लिए हैं और आर्थिक रिश्तों को और बल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस क्षेत्र की बढ़ती रणनीतिक महत्ता के साथ, सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में नियमित आदान–प्रदान तथा संवादों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी की आस्ट्रेलिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर यात्राओं से आपसी समझ में सुधार हुआ है और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला है। आतंकवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने के लिए हमने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय सहयोग किया है। हमने कानून लागू करने वाले अभिकरणों तथा आपदा राहत के बीच सहयोग के लिए कार्यतंत्र भी स्थापित किया है तथा समुद्रतटीय सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में मुख्य भागीदारों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया है। फिलिपीन्स में तूफान हाइयान के पीड़ितों के लिए वायुमार्ग से महत्वपूर्ण राहत सामग्री तुरंत पहुंचाने के हमारे प्रयास की सराहना की गई। हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आदान–प्रदान को भी बढ़ावा दिया है और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को सहायता प्रदान की है जिससे आधुनिक प्रतिस्पर्धी एवं लोकप्रिय प्रौद्योगिकियों में सार्थक सहयोग हुआ।

भारत ने सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ, म्यांमा, वियतनाम) के साथ अपने संबंध को सामान्य हित के मुद्दों पर बातचीत तथा उनकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि एवं जल प्रबंधन, ऊर्जा एवं पारेषण लाइनों एवं मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण की परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरों पर सहायता के जरिए विस्तार प्रदान किया है। संयोजकता, उद्यमिता विकास संस्थाओं की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू की गईं। नए आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए अक्तूबर, 2013 में नई दिल्ली में भारत–सीएलएमवी व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने सिएम रीप, वाट फू और माईसन जैसी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

संबंधों को व्यापक बनाने तथा लोगों के पारस्परिक संपर्कों को बढ़ाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन विद्यापीठों की स्थापना की गई है, थिंक टैंकों के बीच संपर्क स्थापित किया गया है तथा पर्यटन एवं वायुमार्ग संपर्कों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक शिक्षा में नए शैक्षिक संपर्क एवं सहयोग स्थापित किए गए हैं तथा प्रशिक्षण हेतु आईटेक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया गया है। इस क्षेत्र के भारतीय मूल के समुदाय, जो संख्या एवं प्रभाव दोनों में महत्वपूर्ण हैं, को सक्रिय भागीदार बनाया गया है। सिडनी में क्षेत्रीय पीबीडी का आयोजन हुआ और पहली बार पीबीडी–2014 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मलेशिया से भारतीय मूल के एक प्रख्यात सदस्य को आमंत्रित किया गया।

विभिन्न द्वीप समूहों के साथ प्रत्यक्ष द्विपक्षीय आदान–प्रदानों के माध्यम से भारत और प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत किया गया है। हमने लघु विकास परियोजनाओं, संस्थागत सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नई पहलों के माध्यम से प्रशांत देशों के साथ अपनी सहयोग गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। इसके

अलावा, पेसिफिक आईलैंड्स फोरम के साथ बातचीत तथा मंचोत्तर वार्ता भागीदारी बैठकों में भागीदारों के साथ नियमित बैठकों से इस क्षेत्र में हमारी स्थिति और मजबूत हुई है।

पूर्वी एशिया

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके): भारत और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जुलाई, 2013 में ब्रूनेई में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत ने डीपीआरके को क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए आईटेक स्लॉट्स का आबंटन करना जारी रखा। डीपीआरके को मानवीयतापूर्ण खाद्य सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा था। भारत और डीपीआरके ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करना जारी रखा।

जापान: भारत और जापान के बीच शांति, समृद्धि तथा विकास के मजबूत द्विपक्षीय संबंध कायम हैं। दिसंबर, 2006 में प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह की जापान यात्रा के दौरान 'भारत–जापान रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी' में सहयोग के पांच स्तंभों की पहचान की गई–राजनैतिक, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग; व्यापक आर्थिक भागीदारी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहलें; लोगों के पारस्परिक आदान–प्रदान तथा क्षेत्रीय एवं बहु–पक्षीय मामले में सहयोग। वर्ष 2013 में भारत–जापान संबंधों में व्यापकता और गहराई आई तथा यह गत्यात्मक प्रगति दोनों देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी बातचीत में परिलक्षित हुई।

मंगोलिया: भारत–मंगोलिया संबंध मधुर बने रहे। मार्च, 2013 में भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें समग्र संबंधों का जायजा लिया गया और विस्तार किया गया। संयुक्त रक्षा सहयोग कार्य दल की छठी बैठक नवंबर, 2013 में नई दिल्ली में हुई जिसमें रक्षा संबंधों की समीक्षा और उनका विस्तार हुआ। दोनों देशों ने वार्षिक सैन्य अभ्यासों में भाग लिया। भारत ने मंगोलिया को विकास सहायता देना जारी रखा। मंगोलिया के साथ आर्थिक एवं व्यापार संबंधों में प्रगति हुई।

कोरिया गणराज्य (आरओके): भारत और कोरिया ने वर्ष 2013 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाई। 2010 में राष्ट्रपति ली म्यांग बक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्तर तक बढ़ गया। वर्ष 2012 में भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह की यात्रा के परिणामस्वरूप 'रणनीतिक भागीदारी को गहन बनाने संबंधी संयुक्त वक्तव्य' पर हस्ताक्षर किए गए। 15–18 जनवरी, 2014 को कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून–हे ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विमोचित 'रणनीतिक भागीदारी में विस्तार संबंधी संयुक्त वक्तव्य' ने राजनैतिक, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी, आईटी एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार को आधार प्रदान किया है।

यूरेशिया

भारत की समग्र नीति मध्य एशिया, जो भारत के विस्तारित पड़ोस में विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र है, के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए यूरेशिया में अपनी सहभागिता में वृद्धि करने, दक्षिणी कॉकासस (आर्मेनिया, अजरबेजान तथा जॉर्जिया) तथा उत्तरी यूरेशिय (यूक्रेन, बेलारूस) के देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने; और रूस के साथ अपनी परंपरागत भागीदारी से लाभ उठाने की है।

रूसी महासंघ: भारत–रूस की 'विशेष एवं विशेषाधिकृत' रणनीतिक भागीदारी दोनों राष्ट्रों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रही है। यह भागीदारी पारस्परिक लाभ तथा वैश्विक शांति व स्थायित्व, दोनों के लिए टिकाऊ संबंधों के महत्व में विश्वास पर आधारित है। 20 से 22 अक्तूबर, 2013 तक मॉस्को में आयोजित 14वीं वार्षिक भारत–रूस शिखरवार्ता गहरे द्विपक्षीय आदान–प्रदान की पराकाष्ठा थी। अनेक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह डरबन में पांचवीं ब्रिक्स शिखरवार्ता (मार्च, 2013) के समय राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मिले, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में जी–20 शिखरवार्ता (सितंबर, 2013) के दौरान संक्षिप्त चर्चा हुई।

वार्षिक सम्मेलन के बाद विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने रूसी विदेश मंत्री के साथ चर्चा की और द्विपक्षीय संयुक्त आयोग के उन्नीसवें सत्र की सह–अध्यक्षता की। रूस की अन्य द्विपक्षीय यात्राओं में गृहमंत्री (अप्रैल, 2013), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (अप्रैल, जून, और सितंबर, 2013), वित्त मंत्री (जुलाई, 2013) तथा रक्षा मंत्री (नवंबर, 2013) की यात्राएं शामिल थी।

कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के माहौल के बावजूद, वर्ष 2012 में द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 11 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचा। वर्ष, 2013 में यह थोड़ा कम होकर 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक के स्तर पर आ गया।

अक्तूबर, 2013 में कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के यूनिट–। को पावर ग्रिड के साथ जोड़ा गया। यूनिट–2 के कार्य को 2014 में पूरा करने का लक्ष्य है।

रणनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक रक्षा सहयोग है। वर्ष, 2013 में रूस निर्मित तीसरे युद्धपोत आईएनएस त्रिकांड की डिलीवरी एवं एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को सौंप दिया गया।

बेलारूस: भारत और बेलारूस के बीच परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। मई, 2013 में लोक सभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक तेरह सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल

ने बेलारूस की यात्रा की। वर्ष के दौरान अन्य आदान–प्रदान जारी रहे।

यूक्रेन: वर्ष 2013 में विभिन्न संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों से भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंध गहरे हुए। हमारे एयर स्टाफ के चीफ अक्तूबर, 2013 में कीव गए तथा एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और चल रही परियोजनाओं तथा संविदाओं की स्थिति पर चर्चा की। सितंबर, 2013 में नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग के पांचवें सत्र का आयोजन हुआ। फरवरी, 2014 में कीव में श्रृंखलाबद्ध हिंसक घटनाओं के बाद यूक्रेन में सरकार में बदलाव हुआ जिससे रूस एवं यूक्रेन के बीच तनाव पैदा हो गया। भारत ने इस समस्या के राजनयिक समाधान का आह्वान किया और 27 मार्च, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर मतदान से अलग रहा।

मध्य एशिया

मध्य एशिया को भारत के विस्तारित पड़ोस में महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त है। इसी तरह, मध्य एशिया के लिए भारत एक महत्वपूर्ण मित्र और इसकी प्रगति तथा विकास में भागीदार है। मंत्रालय ने जून, 2012 में 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति की घोषणा की जिसमें सामूहिक तथा द्विपक्षीय दोनों प्रकार से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान दिया गया है। इस नीति में मध्य एशिया के पांचों देशों (कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उजबेकिस्तान) के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय राजनैतिक तथा सुरक्षा स्थायित्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्य एशिया के साथ सामूहिक सहभागिता एवं द्विपक्षीय कार्यतंत्र के जरिए संबंधों को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। मध्य एशियाई देशों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत इस वर्ष जारी रही। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान की यात्रा की। जून, 2013 में अलमाटी, कजाकिस्तान में 'दी सैकंड ट्रैक–इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग' आयोजित हुआ और सितंबर, 2013 में ताशकंद में यूरेशियन क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्रीय एचओएम सम्मेलन आयोजित हुआ। अब सभी मध्य एशियाई देशों में आवासीय रक्षा अताशे तैनात हैं।

दक्षिणी कॉकासस

दक्षिणी कॉकासस देशों– आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबेजान–के साथ भारत के संबंध इस वर्ष अपने रचनात्मक दौर में रहे। इंडिया आर्मेनिया फोरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का सातवां दौर तथा इंटर–गवर्नमेंटल कमीशन का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल ने आर्मेनिया की यात्रा की और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। आर्मेनिया में अच्छी खासी संख्या में भारतीय छात्रों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए।

इंडिया–जॉर्जिया फोरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का चौथा दौर बिलिसी में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान अजरबेजान के साथ अनेक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं का आदान–प्रदान हुआ। इनमें अजरबेजान के विदेश मंत्री श्री अल्मार ममद्यारोव की प्रथम भारत यात्रा शामिल है।

खाड़ी देश, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंधों को विगत वर्ष के दौरान और मजबूत बनाया गया। खाड़ी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार बना रहा और द्विपक्षीय व्यापार 2011–12 के 167 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 181.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। वर्ष 2012–13 में भारत द्वारा पूरे विश्व से लगभग 18 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया गया था और 60 प्रतिशत से अधिक भाग खाड़ी क्षेत्र के देशों से आयायित था। भारत के सबसे बड़े तेल के पांच स्रोत देशों से चार खाड़ी क्षेत्र से थे जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई भारत को कच्चे तेल की निर्यात करने वाले पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें सबसे बड़े देश है।

भारत और खाड़ी क्षेत्र के देश परस्पर निवेशकर्ता हैं और भारत विशेषतः अवसंरचना क्षेत्र में खाड़ी क्षेत्र के देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। लगभग 7 मिलियन भारतीय खाड़ी क्षेत्र के देशों में रहते और काम करते हैं तथा भारत को वार्षिक रूप से लगभग 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की रकम भेजते हैं।

इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को अगस्त, 2013 में इराक के प्रधानमंत्री, नवंबर, 2013 में, कुवैत के प्रधानमंत्री फरवरी, 2014 में, बहरीन साम्राज्य के राजा तथा फरवरी, 2014 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री की भारत यात्राओं सहित उच्च स्तरीय यात्राओं से और मजबूत बनाया गया। वर्ष के दौरान विदेश मंत्री ने बहरीन, इराक, सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की। खाड़ी क्षेत्र के देशों की शांति, स्थायित्व, विकास और समृद्धि में हमारे महत्वपूर्ण हित के कारण भारत ने इस क्षेत्र की घटनाओं की मानीटरिंग जारी रखी।

अरब स्प्रिंग की घटनाओं ने पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका (वाना) क्षेत्र के देशों पर लगातार प्रभाव डाला है। ऐसा पाया गया कि गणतंत्र के लिए प्रगति की पूर्ववर्ती अत्यधिक अपेक्षाएं बदल गई हैं। यह क्षेत्र लगातार परिवर्तन और अनिश्चितता में फंसा रहा जिससे विश्लेषण कठिन हो गया।

अपने दीर्घकालिक रणनीतिक, ऊर्जा,खाद्य, आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों के प्रति सचेत रहते हुए हमने बनती बदलती स्थिति को नजदीक से मॉनीटर किया और अपने संबंधों के और विविधीकरण हेतु 'वाना' देशों के साथ सहयोजित रहे।

अरब देशों में राजनीतिक संकट के संबंध में भारत की नीति इस क्षेत्र में हमारे दीर्घकालिक संबंधों, प्रजातंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और विधि के शासन द्वारा निर्देशित थे। अहस्तक्षेप, गैर–आदेशात्मक और गैर–निर्णायक रहने के अपने सिद्धांतों ने हमारा सतत मार्गदर्शन किया और साथ ही, हम जनतांत्रिक मान्यताओं का उपयुक्त रूप से समर्थन भी करते रहे। हमारे सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त हुआ।

इस क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद भारत इस क्षेत्र के सभी देशों की सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। मिस्र के संबंध में प्रकार्यात्मक स्तर पर हमने गैर हस्तक्षेप, लचीलेपन और उपयोगितावाद की नीति अपनाई जिससे हमारे दीर्घकालिक हित आगे बढ़ें। साथ ही, हमने समावेशी परिवर्तन योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का भी आग्रह किया। सीरिया के संबंध में, हमने सैन्य समाधान का विरोध किया और जिसे संयुक्त राष्ट्र का भी समर्थन प्राप्त था। सीरिया के नेतृत्व वाले व्यापक राजनैतिक निपटारे का समर्थन किया। हमने जिनेवा–।। में भाग लिया और सीरिया में मानवता आधारित सहायता (2 मिलियन यूएस डॉलर) तथा रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए वित्तीय सहायता (1 मिलियन यूएस डॉलर) प्रदान की। मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया में हमने इजराइल फिलिस्तीन के बीच पुनः बातचीत शुरू होने का स्वागत किया और एक संप्रभु, स्वतंत्र, एवं संयुक्त राज्य फिलिस्तीन, जिसकी इजराइल के साथ लगती सुरक्षित एवं मान्यता प्राप्त सीमाएं हों तथा जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो, के लिए समर्थन की बात दोहराई। अपने आर्थिक/ऊर्जा हितों को पूरा करने के लिए अपने रिश्तों का विविधीकरण करते हुए हम लीबिया से जुड़े रहे (क्रांति के बाद, अभी भी लीबिया कबीलावाद, धार्मिक भ्रांति, क्षेत्रीयतावाद और हाल ही के सैन्य हिंसा के चरम स्वरूपों के बीच अतिवादी विभाजनकारी प्रवृत्तियां परिलक्षित कर रहा है।

सूडान और दक्षिणी सूडान में हमने दोनों देशों में अपने समग्र ऊर्जा हितों को देखते हुए तटस्थ दृष्टिकोण तथा विकास भागीदारी हेतु पहल की अपनी नीति को जारी रखा (ओवीएल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सूडान और दक्षिणी सूडान में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं)। अपने परस्पर लाभप्रद राजनैतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमने अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लेबनान, जॉर्डन और जिबूती के साथ जुड़े रहे। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, अवसंरचना, आवासन, हॉस्पिटलिटी, ऊर्जा उत्पादन एवं पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की गई। सोमालिया के साथ हमारा सहयोग अपने पकड़े गए नाविकों को छुड़ाना सुनिश्चित करने तक सीमित रहे।

अफ्रीका

अफ्रीका के साथ भारत के जो ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण, निकट एवं सभ्यतागत संबंध है वे वर्ष 2013–14 के दौरान और आगे बढ़े। वर्ष के दौरान दोनों तरफ से विभिन्न उच्च स्तरीय यात्राएं हुईं जिनमें मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग (जनवरी, 2013 में), जंजीबार के राष्ट्रपति अली मोहम्मद शीन (फरवरी, 2014 में) और लिसोथों के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन (मार्च, 2014 में) की यात्राएं शामिल थीं। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मार्च, 2013 में मॉरीशस की यात्रा की। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने मई, 2013 में अफ्रीकन यूनियन की विशेष स्वर्ण जयंती स्मृति शिखरवार्ता में भाग लेने के लिए इथोपिया जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स शिखरवार्ता में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मार्च, 2013 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रलापों के संबंध में आईएएफएस के निर्णयों के कार्यान्वयन, ऋण श्रृंखला के विस्तार तथा भारत–अफ्रीका व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देकर भारत–अफ्रीका सहयोग को आगे बढ़ाया गया। भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2013–14 में 70 बिलियन यूएस डॉलर से पार हो गया। भारत–अफ्रीका में लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के संचयी निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में भी उभरा है।

यूरोप

पश्चिमी यूरोप

पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध गहरे और मजबूत रहे। भारत और इस क्षेत्र के देशों में जनतंत्र, विधि के शासन, नागरिक स्वतंत्रता आदि के बारे में एक समान मूल्य हैं। भारत के संबंधों की गहराई इन देशों के साथ बार–बार उच्च स्तरीय आदान–प्रदान से स्पष्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को पश्चिमी यूरोप ने लगातार मान्यता दी है तथा वहां भारत में निवेश की रूचि बढ़ी है। इस क्षेत्र में ऋण की अत्यधिक समस्या के बावजूद, यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। व्यावसायिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान से इस क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास चलता रहा। विदेश कार्यालय परामर्शों तथा अन्य संवाद तंत्रों के जरिए उच्च स्तरीय आधिकारिक आदान प्रदान जारी रहे। विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत ने इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को गहराई प्रदान की। इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दिखाने के प्रयास किए गए। विशेषतः राष्ट्रपति द्वारा 2 से 5 अक्तूबर, 2013 तक बेल्जियम की यात्रा के दौरान बेल्जियम नरेश फिलिप के साथ यूरापालिया–इंडिया 2013–14 फेस्टिवल का उदघाटन किया गया। इस अवधि के दौरानअन्य राज्याध्यक्षों/सरकारों द्वारा की गई यात्राओं में 14–15 फरवरी, 2013 को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांक्वा हॉलेंड और 18–20 फरवरी, 2013 तथा 14–15 नवंबर, 2013 को यूनाइटेड किंगडम के

प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून की यात्राएं शामिल थी। द्वितीय द्विपक्षीय अंतर सरकारी परामर्श के लिए प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने 10–12 अप्रैल, 2013 को जर्मनी की यात्रा की। जर्मनी के राष्ट्रपति श्री जोकिम गौक 4–9 फरवरी, 2014 को भारत यात्रा पर आए।

मध्य यूरोप

भारत ने मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देशोंके साथ व्यापक सहभागिता की अपनी नीति को जारी रखा और इस क्षेत्र के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों का और गहरा होना तथा विविध रूप लेना जारी रहा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों मंचों पर राजनैतिक मुद्दों पर अच्छी पारस्परिक समझ बनी रही। इस वर्ष अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं की गई जिनमें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की 5–7 अक्तूबर 2013 को तुर्की की यात्रा तथा हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर ओर्बन की एक सशक्त व्यावसायिक शिष्टमंडल के साथ 16–18 अक्तूबर 2013 के दौरान भारत यात्रा शामिल हैं।

अमरीका

कनाडाः परस्पर हित के मुख्य क्षेत्रों में भारत–कनाडा संबंध गहरे हुए और इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक संवाद, ऊर्जा संवाद, सुरक्षा संवाद और आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र नीतिगत संवाद की उद्घाटन बैठकें हुईं। लगभग पन्द्रह वर्ष के बाद कनाडा के गवर्नर जनरल ने फरवरी, 2014 में भारत की राजकीय यात्रा की।

सितंबर, 2013 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में भारत–कनाडा सहयोग करार का लागू होना, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सामुदायिक कॉलेज, अनुसंधान, श्रव्य–दृश्य सह उत्पादन, लौह–इस्पात के क्षेत्रों में द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर तथा क्यूबेक प्रांत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता इस अवधि की महत्वपूर्ण प्रगतियों में शामिल हैं।

आतंकवाद रोध, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, परिवहन तथा खनन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को संयुक्त कार्यसमूहों की द्विपक्षीय बैठकों के जरिए मजबूती मिली।

दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार हेतु वार्ता में प्रगति के जरिए और प्राथमिकता के आधार पर द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार को अंतिम रूप देने की साझी प्रतिबद्धता के जरिए द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए।

भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, व्यापार तथा निवेश, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य जैसे द्विपक्षीय सहयोग के विविध क्षेत्रों में अपनी गहन सहभागिता को जारी रखा। परस्पर हित के अनेक क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दोंपर रणनीतिक एवं राजनीतिक परामर्श हुए जो हिंद महासागर क्षेत्र तथा संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर अतिरिक्त संवाद से और मजबूत हुआ। वर्ष में वरिष्ठ स्तर पर सत्तर से अधिक आपसी यात्राएं की गई जिनमें सितंबर, 2013 में प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह का यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा भी शामिल है। यूएस की ओर से बड़ी यात्राओं में जुलाई, 2013 में यूएस के उप राष्ट्रपति जोसफ आर. बिडेन, जून, 2013 में विदेश मंत्री, जॉन एफ. केरी तथा मार्च, 2014 में ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी डॉ0 अर्नेस्ट मोनिज की यात्राएं उल्लेखनीय हैं। वर्ष के दौरान मंत्री स्तरीय मुख्य द्विपक्षीय संवादों में रणनीतिक संवाद, होमलैंड सुरक्षा संवाद, आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी बैठक, ऊर्जा संवाद, उच्च शिक्षा संवाद तथा भारत–यूएस नागरिक उडड्यन शिखरवार्ता शामिल थी। पुनर्गठित सीईओ फोरम की बैठक जुलाई, 2013 में हुई।

सितंबर, 2013 में प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा के दौरान सुरक्षा सहयोग हेतु सिद्धांतों की संयुक्त घोषणा भी की गई जिसमें यूएस ने भारत को प्रौद्योगिकी रिलीज के लिए अपनेसबसे निकट भागीदार के रूप में मानने की प्रतिबद्धता की और दोनों देश वर्ष के दौरान परिवर्तनकारी सह–विकास एवं सह–उत्पादन परियोजनाओं की पहचान करने के लिए सहमत हुए। यूएस कंपनी वेस्टिंग हाउस द्वारा गुजरात में एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की आरंभिक वाणिज्यिक संविदा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वहनीय एवं नवीन स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में वृद्धि करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुलभता संवर्धन (पीस) हेतु एक समझौता ज्ञापन पर भी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। सितंबर, 2013 में जलवायु परिवर्तन कार्यसमूह की स्थापना के निर्णय से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत–अमरीका सहयोग को बल मिला। वर्ष 2014 में भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में यूएस पहली बार भागीदार देश होगा।

अप्रैल–दिसंबर, 2013 के दौरान, माल के संबंध में यूएस भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2014 की अवधि में यूएस भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा।

लाटिन अमरीका और कैरीबियाई

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उच्चस्तरीय बैठकों, द्विपक्षीय करारों के निष्पादन, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय करारों, विकास परियोजनाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लाटिन अमरीका एवं कैरिबियाई क्षेत्र के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई।

कैरीबियाई क्षेत्र के साथ, जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है, हमारे मजबूत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपर्क हैं। वर्ष के दौरान इस क्षेत्र से महत्वपूर्ण दौरे किए गए, जैसे इक्वाडोर के उप राष्ट्रपति, निकारागुआ, क्यूबा, अर्जेंटीनाऔर वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों की यात्राएँ। नई दिल्ली में जून और दिसंबर, 2013 में क्रमशः अर्जेंटीना और वेनेजुएला के साथ संयुक्त आयोग बैठकों की विदेश

मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने सह–अध्यक्षताकी। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने अक्तूबर, 2013 में पेरू और क्यूबा की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने ब्राजील की यात्रा की और छठी भारत–ब्राजील जेसीएम की सह–अध्यक्षता की तथा अक्तूबर, 2013 में रियो में एलएसी रीजनल एचओएम कांफ्रेंस की अध्यक्षता भी की। चिली के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मार्च, 2014 में राजस्व राज्य मंत्री ने चिली की यात्रा की।

एलएसी क्षेत्र के साथ 2013 में द्विपक्षीय व्यापार 46 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर जाने की उम्मीद है और इस क्षेत्र में हमारे संचयी निवेश अनुमानतः 16 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हैं। इस क्षेत्र में हमारी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के मामले में बड़ी संभावनाएं हैं और हमारे बढ़ते उद्योग के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत दक्षिण–दक्षिण सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के पालन के भाग के रूप में आईटेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ऋण श्रृंखला, सहायता अनुदान और आईटी केन्द्रों के माध्यम से इस क्षेत्र के विभिन्न विकासशील देशों को सहायता भी प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भारत बहुपक्षवाद में संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय भूमिका के महत्व का समर्थक है। भारत ने जी–4 और एल–69 समूहों के समान सोच वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार और इसकी विश्वसनीयता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि करने और समसामयिक भौगोलिक राजनैतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करने के लिए इसे और अधिक प्रतिनिध्यात्मक एवं जनतांत्रिक बनाने के लिए इसकी सुरक्षा परिषद के विस्तार पर निरंतर बल दिया है।

प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने 27–30 सितंबर, 2013 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के उच्चस्तरीय सेगमेंट के लिए आधिकारिक भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार एवं पुनर्गठन का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ पर सुधारों को पूरा करने का आह्वान किया।

भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाली ऑपरेशनों के लिए सबसे बड़े टुकड़ी दाताओं में से एक रहा। भारत ने वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र में शांति बहाली के लिए तीसरी सबसे बड़ी टुकड़ी दाता का स्थान बनाए रखा और भारत के 7,923 सैन्य एवं पुलिस कार्मिक विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के नौ शांति बहाली मिशनों तथा अफगानिस्तान में एक संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में तैनात हैं।

राष्ट्रमंडल के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इसके मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत राष्ट्रमंडल बजट का चौथा सबसे बड़ा अंशदाता बना रहा। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कोलंबों में 15–17 नवंबर, 2013 तक आयोजित 'कॉमनवैल्थ हैड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (सीएचओजीएम) में आधिकारिक भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री ने 13 से 14 नवंबर, 2013 तक प्री–सीएचओजीएम कॉमनवैल्थ फोरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी भाग लिया। उन्होंने लंदन में 13–14 मार्च, 2014 को आयोजित 43वें कॉमनवैल्थ मिनिस्टरियल एक्शन ग्रुप में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रमंडल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने 2013 के सीएचओजीएम से पूर्व और पश्चात भारत की आधिकारिक यात्रा की।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 22 जनवरी, 2014 को मांट्रेक्स (स्विट्जरलैंड) में सीरिया के संबंध में जिनेवा–।। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

भारत ने बाली, इंडोनेशिया में नवंबर, 2013 में आयोजित छठे बाली प्रजातंत्र मंच (बीडीएफ) में भी भाग लिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बृजबिहारी टंडन ने छठे बीडीएफ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने जनतांत्रिक समुदायों, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कांटेक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ दी कोस्ट ऑफ सोमालिया (सीजीपीसीएस) और अन्य बहुपक्षीय मंचों के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष के दौरान विभिन्न अंतर सरकारी प्रक्रियाओ में उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय भागीदारी से बहुपक्षवाद के प्रति भारत की सतत मजबूत प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई। आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री अजय माकन ने नैरोबी में अप्रैल, 2013 में यूएन हैबीटैट की शासी परिषद के 24वें सत्र के लिए शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने जिनेवा में मई, 2013 में 66वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने सितंबर, 2013 में न्यूयॉर्क में सतत विकास विषयक उच्चस्तरीय राजनैतिक मंच की उद्घाटन बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। सितंबर, 2013 में न्यूयॉर्क में एमडीजी तथा निःशक्तजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मत अन्य विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा ने किया। सितंबर, 2013 में विंदहोक, नामीबिया में आयोजित 'कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज टू दी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टीफिकेशन (यूएनसीसीडी) के ग्यारहवें सत्र में एक अंतर मंत्रालयी शिष्टमंडल ने भाग लिया। पर्यावरणएवं वनमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने नवंबर,2013 को वारसा में आयोजित 'नाइनटीन्थ कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज टू दी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कलाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।लोक सभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार और राज्य सभा के उप राष्ट्रपति प्रो0 पी.जे. कुरियन ने अंतर–संसदीयसंघ (आईपीयू) की क्रमशः 129वीं और 130वीं सभा के लिए उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने जनवरी, 2014 में स्विट्जरलैंड में सीरिया पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मंत्री स्तरीय

सेगमेंट में भाग लिया।

वर्ष के दौरान यूएन सिस्टम में भारत की उपस्थिति को और सुदृढ़ किया गया। भारत यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उडड्यन संगठन परिषद (आईसीएओ), कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स (सीएनडी), एचआईवी/एड्स विषयक संयुक्त यूएन कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड (यूएनएआईडीएस), महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग (सीएसडब्ल्यू), लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र संस्था के कार्यकारी बोर्ड(यूएन–वूमेन) के लिए निर्वाचित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतटीय संगठन कार्यकारी परिषद (आईएमओ) के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक बोर्ड के लिए चुना गया। भारत के प्रत्याशी को डब्ल्यूएचओ दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। महानिदेशक, इंडियन मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डब्ल्यूएमओ की कार्यकारी परिषद के लिए चुना गया।

भारत को वर्ष 2014 के लिए मानवाधिकार परिषद ब्यूरो में उपाध्यक्ष (एशिया–प्रशांत समूह के प्रतनिधित्व के लिए) चुना गया। एचआरसी ने 2014 में 25वें सत्र में देश सापेक्ष संकल्पों पर ध्यान दिया। सीरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), म्यांमा, ईरान और श्रीलंका (तीसरी बार) के सबंध में संकल्पों को अंगीकृत किया गया।

भारत को मई, 2013 में आयोजित किरूना मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान आर्कटिक परिषद में 'पर्यवेक्षक' का दर्जा दिया गया। भारत ने लक्जमबर्ग, आस्ट्रिया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में सदस्यता स्वीकार की। ट्रेडमार्कों से संबंधित मैड्रिड प्रोटोकॉल में भारत की पहुंच अन्य महत्वपूर्ण प्रगति थी।

भारत ने वक्तव्य देकर मानवाधिकार परिषद की सार्वभौमिक अवधिक समीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया। भारत ने अप्रैल, 2013 में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, इसके कारण और परिणामों के विषय में यूएन विशेष रैपरटुअर के भारत दौरे को मार्ग प्रशस्त किया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

पड़ोसी देशों के प्रति नए दृष्टिकोण के भाग के रूप में वर्ष 2004 से सार्क में भारत की सक्रिय स्थिति, घोषणा से कार्यान्वयन के चरण तक संगठन का धीरे–धीरे और अप्रत्यावर्तनीय बदलाव सुनिश्चित करने में एक परिवर्तनकारी घटक है। सार्क के सदस्य देशों द्वारा अपने घरेलू विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए सार्क का आश्रय लेने से इस संगठन की प्रगति का पथ प्रशस्त हुआ है।

भारत के प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह द्वारा सोलहवीं थिम्पू सार्क शिखरवार्ता के दौरान सार्क के सबसे कम विकसित देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल) के छात्रों के लिए घोषित 'सार्क इंडिया सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप्स' के तहत 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की है। नवंबर, 2011 में मालदीव में आयोजित सत्रहवीं सार्क शिखरवार्ता के दौरान हमारे प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने इन छात्रवृत्तियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है।

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (इंटर समिट) का पैंतीसवां सत्र मालदीव में 17 से 20 फरवरी, 2014 को आयोजित हुआ। इंटर समिट से पूर्व सार्क प्रभाग प्रमुखों (प्रोग्रामिंग कमिटी मीटिंग, 17 फरवरी 2014), और विदेश सचिव (18–19 फरवरी, 2014 विशेष सत्र एवं स्थायी समिति) के स्तर पर प्रारंभिक बैठकें हुई।

बैठकों में सार्क के कार्यतंत्रों, जिनमें सार्क सचिवालय, क्षेत्रीय केन्द्र और सार्क के विशिष्ट निकाय शामिल हैं, के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्क सचिवालय द्वारा संचालित अध्ययन पर विचार किया गया। समिति ने सिफारिश की कि सार्क शिखरवार्ता, जो अभी वार्षिक रूप से होती है, दो वर्ष में एक बार होगी। बैठकों के आयोजनार्थ एक पूर्व निर्धारित समय सीमा तय की जाएगी। सार्क सचिवालय के कार्यकरण में सुधार हेतु अनेक सिफारिशो को अनुमोदित किया गया। बैठक में चुनिंदा क्षेत्रीय केन्द्रों को बंद करने और विलय करने पर सहमति हुई।

निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

वर्ष के दौरान भारत ने निःशस्त्रीकरण और अप्रसार, विशेष रूप से परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्राथमिक मुद्दे, के संबंध में, अपनी नीतियों का अनुसरण जारी रखा और सार्वभौमिक एवं गैर विभेदकारी परमाणु निःशस्त्रीकरण के साथ–साथ सामान्य एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुपालन में विभिन्न बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामला मंचोंके साथ इन मुद्दों को उठाया है। निःशस्त्रीकरण के विषय में भारत का रूख भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हित तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निकट संबंध की अपनी परंपरा द्वारा निर्देशित है।

भारत ने यूएन फर्स्ट कमिटी, यूएन निःशस्त्रीकरण आयोग, निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स और यूएन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत वर्ष 2013 सत्र में प्रेसीडेंसी ऑफ कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के छह प्रेसीडेंटों में से एक रहा। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रेसीडेंट के रूप में भारत ने उल्लेखनीय कार्य शुरू करने के सभी प्रयासों पर बल दिया और सम्मेलन के सभी सदस्य राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया। भारत ने शस्त्र व्यापार संधि पर राजनयिक सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच तथा कांफ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड

कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया तथा अपने संवाद को बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था से जोड़ा। मंत्रालय ने भारत के निर्यात नियत्रंण कानूनों तथा वेपंस ऑफ मास डेस्ट्रक्शन एकट 2005 के कार्यान्वयन की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसायटी संगठनों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा गया।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

विगत वर्ष के दौरान जी–20, ब्रिक्स, इब्सा, आइओआरए (पूर्व मेंः आईओआरएआरसी) जैसे प्रमुख बहुपक्षीय समूह कमजोर वैश्विक आर्थिक प्रगति, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में प्रगति, बहुपक्षीय व्यापार पद्धति, सतत विकास आदि जैसी चुनौतियों के समाधान में निरंतर प्रयासरत रहे। भारत अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के लिए और विकासशील विश्व के सरोकारों को आवाज प्रदान करने के लिए इन बहुपक्षीय समूहो में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा। भारत इब्सा का अध्यक्ष बना हुआ है और मार्च, 2013 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पांचवें सम्मेलन में ब्रिक्स की तथा नवंबर, 2013 में पर्थ, आस्ट्रेलिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 13वीं बैठक में आईओआरएआरसी की अध्यक्षता छोड़ दी।

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने मार्च, 2013 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पांचवें ब्रिक्स सम्मेलन में तथा सितंबर, 2013 में सेंटपीटर्सबर्ग, रूस मे 8वें जी–20 सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने सितंबर, 2013 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर इब्सा की 10वीं वर्षगांठ की स्मृति में इब्सा विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सितंबर, 2013 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मध्याह्न भोजन बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने नवंबर, 2013 में पर्थ, आस्ट्रेलिया में आईओआरए की मंत्रिपरिषद की 13वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और साथ ही मार्च, 2014 में हेग में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के समय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारत ने अपनी अध्यक्षता में जुलाई, 2013 में पोर्ट लूइस, मॉरीशस में आईओआरए के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की मध्यावधि बैठक की मेजबानी भी की। भारत ने जुलाई,2013 में पोर्ट लूइस में आइओआरए की आर्थिक एवं व्यावसायिक परिषद की प्रथम बैठक की मॉरीशस के साथ मेजबानी भी की। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने नवंबर, 2013 में नई दिल्ली में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 12वीं त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की।

दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान)

आसियान–भारत कूटनीतिक भागीदारी से संबंधित कार्यों की अधिकता रही जिसमें अलग–अलग क्षेत्रों के 26 अंतर सरकारी कार्यतंत्रों की बैठकें, 2010–15 के लिए आसियान–भारत कार्य योजना का कार्यान्वयन तथा छात्रों, किसानों, मीडिया, राजनयिकों तथा सांसदों सहित लोगों से गहन पारस्परिक संपर्क के कार्यक्रम शामिल थे। भारत ने सितंबर, 2013 में आसियान अंतर संसदीय सभा की 34वीं महासभा में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। संयोजकता संबंधी मुद्दों को रणनीतिक प्राथमिकता दिए जाने के मद्देनजर भारत ने आसियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेंटिंग कमिटी (एसीसीसी) के साथ वार्षिक बैठक शुरू की और चीन और जापान के बाद ऐसा करने वाला आसियान का तीसरा संवाद भागीदार बना। दिल्ली संवाद तथा आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैक्स के जरिए ट्रैक वन एंड ए हाफ में चर्चा जारी रही।

पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत की भागीदारी में वृद्धि हुई जिसमें भारत ने आपदा प्रबंधन तथा शमन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में पहलें की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 अक्तूबर, 2013 को आठवें ईएएस के समय आठ ईएएस सदस्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने आसियान तथा इसके अन्य पांच एफटीए भागीदारों के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के विषय में संयुक्त चर्चा की।

भारत ने 'एएसईएमः प्रगति एवं विकास हेतु भागीदारी सेतु' के विषय में 11–12 नवंबर, 2013 को एएसईएम के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक की मेजबानी की। एएसईएम की पूर्व की बैठकों में घोषणाकारी स्वरूप को छोड़कर, एएसईएम एफएमएम 11 ने एएसईएम की कार्य पद्धतियों में महत्वपूर्ण प्रगति की जिनमें, सहमति और परामर्श के आधार पर अध्यक्ष का वक्तव्य, 'जो वार्ता से परिणाम' की दिशा में एक कदम था, तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों के गहन आदान–प्रदान को सुलभ बनाने के लिए निर्णय बदलने के सृजनात्मक फार्मेट का समावेश शामिल है।

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। हाल ही के वर्षों में विदेशों में भारत के विकास कार्यक्रमों में भौगोलिक पहुंच तथा क्षेत्रीय कवरेज दोनों तरह से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इनमें ऋण श्रृंखला, अनुदान सहायता, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्तियां तथा लघु अवधि सिविलियन एवं सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित अनेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

संकल्पना, आरंभ, कार्यान्वयन एवं कमीशनिंग के चरणों के माध्यम से भारत की विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए विदेश मंत्रालय में जनवरी, 2012 में विकास

भागीदार प्रशासन की स्थापना की गई।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमा, श्रीलंका और मालदीव में अवसरंचना, जल विद्युत, विद्युत पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मेजबान सरकारों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अभिचिन्हित अन्य क्षेत्रों में बड़ी विकास परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। भारत के पड़ोसियों के साथ सीमा पार जुड़ाव को मजबूत बनानेकी विभिन्न पहलों की प्रगति संतोषजनक है। पड़ोस से दूर, दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में पुरातात्विक संरक्षण, सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों में द्विपक्षीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

विगत कुछ वर्षों में भारत की विकास सहायता का एक मुख्य पहलू अन्य विकाशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला प्रदान करना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अफ्रीका के देशों को 1497. 47 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण श्रृंखला आबंटित की गई तथा एशिया एवं लेटिन अरीका के देशों को 479.79 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण श्रृंखला संस्वीकृत की गई।

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान 161 विकासशील देशों के नामितियों के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी), अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी)) तथा कोलंबो योजना की तकनीकी सहायता स्कीम (टीसीएस) के अंतर्गत 8000 से अधिक सिविलियनों को प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न भागीदार देशों के लगभग 1500 रक्षा कार्मिकों को भारत में विभिन्न रक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारत के सिविलियन एवं रक्षा विशेषज्ञों को विशेषज्ञता बांटने तथा क्षमता निर्माण हेतु अनेक विकासशीलदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया है।

निवेश एवं तकनीकी संवर्धन

निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग (आईटीपी), आर्थिक राजनय को बढ़ावा देता है और विदेशी निवेश, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन एवं अंतरण से जुड़े कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। यह संबंधित मंत्रालयों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ समन्वयन से काम करता है और आर्थिक एवं वाणिज्यिक मुद्दों का कार्य देख रहे मंत्रालयों को नीतिगत सलाह देता है।

वर्ष 2013–14 में इस प्रभाग ने हमारे मिशनों और केंद्रों को निर्यात एवं निवेश बढ़ाने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए संवितरित किए। वर्ष के दौरान, आईटीपी ने निर्यात संवर्धन परिषद् तथा अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बैठक की मेजबानी की तथा टेलीकॉम सेक्टर में विदेशों में अवसर विषय पर एक बैठक की। पीएच.डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, विदेश मंत्रालय ने ''कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकाः ए लैंड ऑफ अपॉरच्यूनिटी'' के मेजबानी की। सीआईआई तथा वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय ने दो दिवसीय ''सीआईआई–इंडिया, लेटिन अमेरिका एंड कैरीबियन कॉन्क्लेव'' की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय ने फिक्की के साथ मार्च, 2014 में मध्य यूरोप व्यावसायिक शिखरवार्ता की भी मेजबानी की। इस प्रभाग ने संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा संवर्धन करारों की बातचीत में भाग लिया। इसने सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई तथा वियतनाम के साथ वायु सेवा वार्ताओं में भाग लिया।

आईटीपी प्रभाग की वेबसाइट www.indianbusiness.nic.in को पुनराभिकल्पित किया गया और भारतीय अर्थव्यस्था तथा नए नीतिगत कार्यक्रमों पर सूचना प्रदान करना जारी रखा गया। आईटीपी प्रभाग के वार्षिक प्रकाशन के अद्यतन संस्करण का विमोचन जनवरी, 2014 में विदेश सचिव द्वारा किया गया। यह प्रावधान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, जिनमें भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवस्था के अवसरों संबंधी सूचना शामिल है, पर अद्यतन जानकारी देता है।

ऊर्जा सुरक्षा

विदेश मंत्रालय का ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए नोडल प्वाइंट के रूप कार्य करता है। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने संबद्ध मंत्रालयों के साथ गहन चर्चा जारी रखी और ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चाओं में योगदान किया।

इस प्रभाग ने अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित क्लीन एनर्जी मिनिस्टिरियल, 2013, 6–7 मई, 2013 को सियोल में आयोजित ऊर्जा दक्षता सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की 7वीं नीतिगत समिति की बैठक, 27–29 मई, 2013 को ब्लाडीवोस्टक में एशिया–प्रशांत ऊर्जा मंच, 10 सितंबर, 2013 को टोकियो, जापान में आयोजित द्वितीय एलएनजी उत्पादक–उपभोक्ता सम्मेलन और 11–12 सितंबर, 2013 को सियोल, कोरिया में आयोजित 5वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक, 25–27 सितंबर, 2013 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 7वीं पूर्वी एशिया शिखरवार्ता ऊर्जा मंत्रियों की बैठक तथा 19–20 नवंबर, 2013 को पेरिस में आयोजित द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने ऊर्जा सुरक्षा पर तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया जो 3 सितंबर, 2013 को फिक्की और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सीआईआई के साथ सहयोग से विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 27 नवंबर, 2013 को तृतीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी की। 3–4

दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में 8वां एशियन गैस भागीदारी सम्मेलन आयोजित हुआ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भागीदारी मंत्रालय के तत्वाधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन तथा प्रदर्शनी, पेट्रोटेक–2014 का अयोजन दिल्ली, एनसीआर में 12–15 जनवरी, 2014 को किया गया।

इस वर्ष के दौरान प्रस्तावित 'तापी' पाइपलाइन परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसमें चार पक्षों, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल, तापी लिमिटेड का गठन तथा चारों पक्षों द्वारा एडीबी, जिसे परियोजना के निष्पादन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, के साथ निष्पादन सलाहकार सेवा करार पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस परियोजना का आगामी चरण कंसोटियम लीड का चुनाव करना होगा।

कौंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

विगत पांच वर्षों में, पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र और आकार दोनों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। पासपोर्ट सेवाओं की ऊंची मांग की चुनौतियों का समाधान करने तथा पासपोर्ट सेवा निर्गम प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिए नागरिक केंद्रित व आईटी–संचालित पासपोर्ट सेवा परियोजना को देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना और क्रियान्वयन के साथ जून, 2012 में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना ने सरकार के उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त की है तथा विभिन्न पुरस्कार जीते है।

पासापोर्ट जारी करने की प्रणाली को सहज, त्वरित तथा सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में लोक शिकायत निवारण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, 17 भाषाओं में कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना, सितंबर, 2013 में पासपोर्ट पोर्टल का पुननिर्माण, जुलाई, 2013 से पासपोर्ट शुल्क का ऑनलाइन भुगतान शुरू करना, पासपोर्ट संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन, नागरिकों को एसएमएस अलर्ट तथा अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रीमियम ऐच्छिक एसएमएस सेवा, शिकायत निवारण हेतु पासपोर्ट सेवा शिविरों, पासपोर्ट मेले और अदालतों का आयोजन, हज आवेदकों को उच्च प्राथमिकता, अपील और आरटीआई मामलों का समय पर निपटान, पासपोर्ट कार्यालयों में भौतिक अवसंरचना में सुधार तथा पासपोर्ट पुस्तिकाओं में नई सुरक्षा विशेषताओं का समावेश और ई–पासपोर्ट परियोजना को त्वरित बनाने के लिए एक कार्य बल का गठन शामिल है। 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, पासपोर्ट सेवा संबंधी 1.56 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटान किया गया और नई प्रणाली के जरिए 1.41 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान की गई है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, देश में पासपोर्ट सेवा सुपुर्दगी में स्पष्ट सुधार हुआ है। देश भर में कुल पासपोर्टों का 24% पासपोर्ट 3 दिन के भीतर जारी किए जाते हैः सामान्य पासपोर्टों का 60%7 दिन के भीतर जारी कर दिए जाते हैं और 82ः पासपोर्ट 14 दिन के भीतर (पुलिस सत्यापन में लगे समय को छोड़कर) जारी कर दिए जाते हैं। तत्काल पासपोर्टों के मामले में, 10% उसी दिन जारी कर दिए जाते हैं तथा 64% 3 दिन के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। यदि सुपुर्दगी प्रक्रिया के प्रारंभ से अंत तक लगने वाले समय पुलिस सत्यापन में शामिल समय जोड़ दे तो 49% पासपोर्ट एक माह के भीतर जारी कर दिए गए। पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के मामले में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5 शीर्ष राज्य हैं जहां से कुल आवेदनों के 55%ः से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जनवरी–दिसंबर, 2013 के दौरान, भारत के 37 पासपोर्ट कार्यालयों ने 71.30 लाख पासपोर्ट जारी किए (जिनमें 2092 राजनयिक पासपोर्ट तथा 23038 ऑफिसियल पासपोर्ट शामलि है), जो 14% से अधिक की वृद्धि दर्शाते है। यही नहीं, विदेश में भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा लगभग 13.83 लाख पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं। इस प्रकार, भारत सरकार ने विगत वर्ष लगभग 85. 19 लाख पासपोर्ट सेवाएं प्रदान की। यह सर्वकालिक उच्चतम संख्या है और वर्ष 2000 से तीन गुना अधिक है। 31 दिसंबर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार, 5,19,29,139 नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट थे। वर्ष 2013–14 में सभी पासपोर्ट सेवाओं से कुल और प्रत्याशित राजस्व 1600 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2013–14 में केंद्रीय पासपोर्ट संगठन को 429.47 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई।

24 जून को 'पासपोर्ट सेवा दिवस' घोषित किया गया है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 अधिनियमित किया गया था। चुनिंदा भारतीय मिशनों/केंद्रों में पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई तथा पीआईओ आवेदनों के डिजीटलाइजेशन के माध्यम से ''क्रिएशन ऑफ इमेज रिट्रीवेबल डाटाबेस'' परियोजना शुरु की गई। मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 7.28 करोड़ पृष्ठों को डिजीटलाइज किया गया है।

विदेशी मामलों की संसदीय संबंधित स्थायी समिति ने 16 जनवरी, 2013 और 17 दिसंबर, 2013 से ''पीएसपी दृ लक्ष्य एव उपलब्धियां'' विषय का गहन परीक्षण किया और बंगलौर, भोपाल, गुड़गांव, दिल्ली और गाजियाबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्रों के तत्स्थान मूल्यांकन हेतु 12 से 18 जुलाई, 2013 की अवधि के दौरान निरीक्षण किया। प्राक्कलन समिति ने भी 10 जनवरी, 2013 को पासपोर्ट कार्यालय, गोवा तथा 1 जून, 2013 को चंडीगढ़ का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए चेन्नई, जयपुर, जम्मू , गाजियाबाद, बंगलौर और भुवनेश्वर के पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया।

विदेश में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र प्रति वर्ष लगभग 4 मिलियन वीजा जारी करते हैं। मिशनों/केंद्रों द्वारा वीजा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है जिसमें जारी करने की प्रणाली का कंप्यूटरीकरण तथा वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग, जो 2006 में शुरू हुई थी, शामिल हैं। वर्तमान में विदेश स्थित 70 मिशनों/केंद्रों में वीजा कार्य की आउटसोर्सिंग की गई है। विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में आईवीएफआरटी (इमीग्रेशन, वीजा एंड फारेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग) परियोजना प्रणाली 2014 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। वर्तमान में विदेश स्थित 139 भारतीय मिशनों/केंद्रों में आईवीएफआरटी स्कीम (बायोमीट्रिक बिना) शुरू कर दी गई है।

जनवरी से दिसंबर, 2013 तक की अवधि में सीपीवी प्रभाग के सत्यापन प्रकोष्ठ ने 373358 व्यक्तिगत तथा 177509 वाणिज्यिक दस्तावेज सत्यापित किए और प्रमाणक (अफोस्टिल) सदस्य देशों में उपयोग के लिए 290864 दस्तावेजों को प्रमाणित किया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी स्थित विदेश मंत्रालय के चार शाखा सचिवालयों मं 44490 दस्तावेज सत्यापित/अफोस्टिल किए गए। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा कांसुलर दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाता है।

जनवरी से दिसंबर, 2013 की अवधि के दौरान, भारत ने बांग्लादेश, अजरबेजान और थाइलैंड के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम और बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन विलेख का आदान–प्रदान किया गया। इस अवधि के दौरान, भारत को विभिन्न देशों से पांच प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुए और विदेशी सरकारों को चार प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए। इसके अतिरिक्त, भारत को स्थानीय अभियोजन हेतु 62 अनुरोध प्राप्त हुए।

समन्वय

संसद अनुभाग मंत्रालय एवं ससंद के बीच संपर्क की कड़ी है और इस मंत्रालय में संसद संबंधी समस्त कार्यों का नोडल प्वाइंट हैं। इस अनुभाग ने विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की तथा विदेशी मामलों की स्थायी संसदीय समिति तथा अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कार्यों का समन्वय किया।

समन्वय प्रभाग ने मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों तथा निजी संस्थाओं, जिनमें गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं, के बीच संपर्क का समन्वय किया। इस अनुभाग ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के लिए राजनैतिक क्लोयेरेंस का कार्य किया। इसने भारत में विदेशी भागीदारी वाले सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं, भारत में खेल टूर्नामेंटों, जिनमें विदेशी प्रतियोगी आमंत्रित थे और विदेश में खेल टूर्नामेंट, जिनमें भारतीय प्रतियोगी आमंत्रित थे, के आयोजन, विदेशी सैन्य उड़ानों के उतरने/उड़ान भरने तथा विदेशी नौसेना जहाजों की यात्रा आदि के लिए क्लियरेंस पर कार्रवाई की।

इस मंत्रालय के शिक्षा अनुभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को आबंटित सीटों पर स्व–वित्तपोषित विदेशी छात्र योजना के तहत भारत की विभिन्न संस्थाओं में 65 मित्र, पड़ोसी और विकासशील देशों के विदेशी छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बी.फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में चयन, नामांकन और दाखिले के संबंध में कार्रवाई की।

प्रशासन एवं परियोजनाएं

प्रशासन

वर्ष 2013 में मंत्रालय ने वर्ष 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 10 वर्षीय भारतीय विदेश सेवा विस्तार योजना के छठे भाग को कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय में विभिन्न उप–संवर्गों के लिए समयबद्ध ढंग से विभागीय पदोन्नति समिति बैठकों के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की। मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012' की सिफारिशों के अनुसार एक व्यापक प्रशिक्षण संरचना बनाई है जो मंत्रालय की क्षमता–निर्माण एवं प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करेगी। प्रशिक्षण संरचना की सिफारिशों के आधार पर विदेश सेवा संस्थान विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने की प्रक्रिया में है जिसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। भारत सरकार ने सिटवे, म्यांमा में एक नया कांसुलेट खोलने का निर्णय लिया है। इस नए केंद्र को खोलने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

परियोजनाएं

वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रभाग ने विदेश में चांसरी/आवासों के रूप में संपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण जारी रखा। निर्मित संपत्तियों में वाशिंगटन में (मिशन का सांस्कृतिक स्कंध) और पोर्ट मोर्सबी में (चांसरी और आवास) संपत्तियां शामिल है। हनोई (चांसरी एवं दूतावास निवास), यागून (चांसरी) तथा बेलग्रेड में निर्मित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्थानीय सरकारों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए। समन्वित प्रयासों से यह प्रभाग ब्राजीलिया में नए चांसरी/आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर पाने में सफल रहा है और निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद बहरीन में चांसरी–सह–आवास के निर्माण हेतु संविदा दे दी है। काबुल तथा आबुजा में निर्माण परियोजना पूरी होने वाली है तथा वारसा, इस्लामाबाद, कांठमांडू और ढाका में चल रही निर्माण परियोजनाओं के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार

विदेश मंत्रालय ने अपने मुख्यालय के कार्यालयों, विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों और पासपोर्ट कार्यालयों में दैनंदिन कार्यालयी कामकाज में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी के प्रचार और संवर्धन का दोहरा लक्ष्य बनाया है।

अपने मिशनों और केंद्रों की भागीदारी से हिंदी के प्रचार हेतु मंत्रालय का नियोजित कार्यक्रम है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को विदेश मंत्रालय में अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर):

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान आईसीसीआर ने अपनी प्रसार गतिविधियों के जरिए विदेश में 36 पूर्णतः सुसज्जित सांस्कृतिक केंद्रों तथा 2 उप केंद्रों और भारत में ही 20 क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुरक्षण किया। परिषद् के पास विदेशी विश्वविद्यालयों में 76 प्रचालन पीठें (11 हिंदी पीठों सहित) है। आईसीसीआर ने भारत सरकार तथा अन्य एजेंसियों की ओर से विदेशी छात्रों के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की है और लगभग 5200 छात्रवृत्ति धारकों को नामांकित किया है। यह भारत में विदेशी छात्रों के कल्याण के लिए नोडल एजेंसी है। परिषद् ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनियां, सम्मेलन और सेमीनार, बेल्जियम में ''यूरोपालिया इंडिया'' उत्सव का आयोजन, प्रदर्शनकारी कलाकारों और समूहों के अनेक आदान–प्रदान तथा संबंधित प्रस्तुतियों एवं व्याख्यान प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान, परिषद् ने विदेशों में कार्यक्रमों के लिए लगभग 85 समूहों/कलाकारों को प्रायोजित किया और भारत में 73 विदेशी समूहों तथा 95 भारतीय समूहों की प्रस्तुतियों का आयोजन किया। परिषद् ने सूफी उत्सव, वर्ल्ड परक्सन फेस्टिवल, इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल, चौथा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत उत्सव तथा 7वां दक्षिण एशियाई बैंड उत्सव 2013 जैसे प्रतिष्ठित उत्सवों का आयोजन किया। परिषद् अपने विशिष्ट विजिटर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियमित रूप से आमंत्रित करता है और दुर्लभ पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के संकलन वाले एक सज्जित पुस्तकालय के अनुरक्षण के अलावा, पांच अलग–अलग भाषाओं में पांच पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्ल्यूए)

इस अवधि के दौरान, आईसीडब्ल्यूए ने अपनी अधिदेशित गतिविधियों को जारी रखा और एशिया, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में राजनैतिक, सुरक्षागत एवं आर्थिक विकासों के अनुसंधान एवं अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दी है। वैश्विक भौगोलिक–रणनीतिक एवं भौगोलिक–राजनैतिक प्रगतियों का विश्लेषण किया गया। 3 सप्रु हाउस पेपरों, 14 इश्यू ब्रीफ तथा 46 व्यू–प्वाइंटों के रूप में निष्कर्षों का प्रचार किया और इन्हें आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर रखा गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, 16 पुस्तकें भी प्रकाशित कीगई। बड़ी संख्या में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासी परिषद् तथा शासी निकाय के निर्धारित 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनका पुनर्गठन किया गया। आईसीडब्ल्यूए सभागार का पुनुरूद्धार कार्य पूरा हुआ।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस)

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त थिंक–टैंक है। आरआईएस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर भारत सरकार को अनुसंधान नीति से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराती है। संस्थान ने इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः भारतीय विकास सहयोग कार्यशाला; भारत–कनाडा आर्थिक सहयोग संवाद; दक्षिण–दक्षिण सहयोग मुद्दे और उभरती चुनौतियां विषयक सदर्न प्रोवाइडर्स का सम्मेलन; दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोगः प्रवृत्तियां, चुनौतियां और परिप्रेक्ष्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; आसियान–भारत नेटवर्क के थिंक–टैंक का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (वियनटियान, लाओ पीडीआर में), आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र का उद्घाटन तथा आरआईएस में आसियान भारत उद्घाटन व्याख्यान, भारत में उद्यम नवाचार संवर्धन विषयक विचार सत्र; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार हेतु अफ्रीका–भारत सहयोग सम्मेलन; 'दोहा से बाली तक' विकास एजेंडा की चुनौतियां; विकास सहयोग सम्मेलन, व्यापार एवं वित्तः उभरते आकदमिक संदर्भ; भारत और म्यांमा के बीच संयोजकता के गलियारों से विकास के गलियारों तक विषय पर सेमीनार (ने पई ता, म्यांमा में); बाली में आयोजित डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर परव्यापार एवं विकास संगोष्ठी; भारत–चीन सहयोग एवं वैश्विक आर्थिक अभिशासन विषयक कार्यशाला; भारतीय विकास सहयोग नीति विषयक सम्मेलन; बहस की स्थिति; आसियान–भारत समुद्रतटीय परिवहन सहयोग विषयक राष्ट्रीय सेमिनार; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नीतिशास्त्र, औचित्य तथा समावेश विषयक सम्मेलन; भारत–सिंगापुर संबंध संवाद; और लद्दाख के चंगथांग सीमा क्षेत्रों पर चर्चा बैठक। आरआईएस में भारत विकास सहयोग (एफआईडीसी) हेतु मंच भी शुरु किया गया। इसके कार्यक्रम के भाग के रूप में, मासिक सेमीनारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है।

विदेशी सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से आरआईएस ने निम्नलिखित विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति (विदेश मंत्रालय के आईटेक/स्काप के अंतर्गत); और व्यापार एवं आर्थिक समेकन के वैश्विक एवं क्षेत्रीय पहलू; व्यापार एवं आर्थिक सहयोग; वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य; और डब्ल्यूटीओ एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य। संस्थान ने 'दी लिविंग ट्रीः ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ इन चायना एंड इंडिया' शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन किया गया तथा 'दक्षिण–दक्षिण सहयोगः मुद्दे और उभरती चुनौतियां विषय पर सदर्न प्रोवाइडर्स का सम्मेलन; भारत–चीन व्यापारिक संबंध; आसियान–भारत रणनीतिक भागीदारीः आसियान–भारत थिंक–टैंक नेटवर्क का परिप्रेक्ष्य; भारतीय स्वैच्छिक संगठनों का नेटवर्क 2013' और 'एशिया–प्रशांत में जैव–प्रौद्योगिकी क्षमता पर सर्वेक्षणः राष्ट्रीय पहल एवं क्षेत्रीय सहयोग के अवसर' नामक रिपोर्टें प्रकाशित की। इन रिपोर्टों के अलावा, आरआईएस ने चर्चा शोध पत्र, पॉलिसी ब्रीफ और पत्रिकाएं भी प्रकाशित की, नामतः 'दक्षिण एशियन आर्थिक पत्रिका' और 'एशियाई जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास समीक्षा।' आरआईएस विकासशील देशों के अग्रणी थिंक–टैंक के रूप में कार्य करने का अपना प्रयास जारी रखेगा।

विदेश प्रचार एवं लोक राजनय

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश प्रचार प्रभाग एवं लोक राजनय प्रभाग को 24 जनवरी, 2014 को विदेश प्रचार एवं लोक राजनय प्रभाग (एक्सपीडी डिवीजन) नामक एक प्रभाग में एकीकृत कर दिया गया। एक्सपीडी ने विभिन्न विदेशी नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत सरकार की स्थिति से अवगत कराने के साथ–साथ अपनी विदेश नीति एवं विश्व के साथ भारत की सहभागिता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए घरेलू एवं वैश्विक श्रोताओं–दर्शकों के साथ कार्य करने के अपने अधिदेशित कार्य को किया।

अपने नियमित कार्य के अलावा, विविध नए मीडिया मंचों पर मंत्रालय की उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में प्रभाग ने 29 जुलाई, 2013 को एक समेकित स्मार्टफोन एप्लीकेशन 'एमईए इंडिया' लांच की जो भारत सरकार के किसी मंत्रालय का पहला ऐसा एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन पब्लिक सेवाओं, जिनमें भारत में कहीं भी आवेदित पासपोर्ट की स्थिति, भारत में दस्तावेजों का सत्यापन करने वाले केंद्रों, हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की स्थिति की जानकारी के लिए एकल माध्यम है। इस नए टूल को मंत्रालय के सूचना प्रसार प्रयासों से भी जोड़ा गया है। भारत और विदेश दोनों जगह व्यापक रूप से व्यक्तियों से जुड़ने तथा एक डिजीटल पहचान को पुष्ट करने के लिए प्रभाग ने ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, फ्लिकर तथा गूगल+ जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। विदेश मंत्रालय का यूट्यूब चैनल अब प्रेस ब्रीफिंग/मीडिया से बातचीत का लाइव वेबकास्ट नियमित रूप से करता है। प्रेस विज्ञप्तियों और वक्तव्यों का हिंदी, ऊर्दू और अरबी में अनुवाद साथ–साथ है, तमिल, मलयालम, बांग्ला और असमिया जैसे भारतीय भाषाओं को भी शामिल करके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

प्रभाग ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे ट्विटर (212,000 से अधिक फॉलोअर) और फेसबुक (196,000 से अधिक लाइक्स) के साथ–साथ प्रभाग की वेबसाइट का प्रयोग भी मंत्रालय की नीतियों तथा कार्यकलापों को दर्शाने और विश्व भर से वार्ताकार नियुक्त करने के लिए किया है। भारत की विदेश नीति की पहचान को विस्तार देने के लिए यह प्रभाग थिंक–टैंकों, विश्वविद्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से जुड़ा रहता है और विदेश नीति पर सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करता है। विदेश मंत्रालय के सार्वजनिक नीति सम्बोधन और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभाग की विशिष्ट व्याख्यानमाला ने भारतीय विदेश नीति को आम जनता तथा विशेषतः युवाओं को पूर्णतः स्पष्ट करने में मदद की है। प्रभाग ने समसमायिक हित के विषयों पर डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जिसका स्वागत किया गया, उन्हें स्वीकार गया और इन्होंने पुरस्कार भी जीते। दूरदर्शन चैनल ने एक्सपीडी डॉक्यूमेंट्रियां प्रसारित करना शुरू किया है जिन्हें व्यापक पहुंच के लिए यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है। प्रभाग की मुख्य पत्रिका 'इंडिया पर्सपेक्टिव्ज' वेब और मोबाइल प्लेटफार्म पर डिजीटल संस्करण के साथ–साथ चौदह भाषाओं में मुद्रित की जा रही है। यह प्रभाग विदेश में स्थित भारतीय मिशनों को भारत की एक सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने के लिए लगातार पुस्तकें एवं प्रकाशनों की आपूर्ति कर रहा है।

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई)

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अनुसार मंत्रालय के लिए एक नई प्रशिक्षण संरचना को अंगीकृत करना विदेश सेवा संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति रही। नई प्रशिक्षण संरचना को विदेश मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया और जुलाई, 2013 में विदेश सचिव द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संसूचित किया गया। एफएसआई ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और स्टाफ तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ–साथ विदेशी राजनायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत रूप से आयोजित किए।

1996 बैच के निदेशक–स्तरीय अधिकारियों के लिए वर्ष 2013 में ई–मेल आधारित मिड–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। एफएसआई ने अनुभाग अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सहायकों एवं लिपिकों के लिए बुनियादी व्यावसायिक

पाठ्यक्रम और रक्षा कार्मिकों के लिए अनुकूलन कैप्सूल संचालित किए। एफएसआई ने समेकित मिशन लेखांकन प्रणाली में प्रशिक्षण सत्रों का भी संचालन किया।

एफएसआई ने विदेशी राजनयिकों के लिए दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आसियान राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तथा बांग्लादेश एवं आईओआर–एआरसी देशों के राजनयिकों के लिए अन्य विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए। इन पाठ्यक्रमों के दौरान, शिक्षण–कक्ष प्रशिक्षण के अलावा, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के विभिन्न स्थानों एवं संस्थाओं में ले जाया गया।

एफएसआई ने सितंबर और नवंबर, 2013 में आदान–प्रदान कार्यक्रम में भारत का दौरा करने वाले 250 आसियान छात्रों के लिए भारत की विदेश नीति पर व्याख्यानों का आयोजन भी किया।

एफएसआई ने ईरान, इराक, लाइबेरिया और कुबैत की राजनयिक अकादमियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। चीन गणराज्य, जर्मनी, मोजमविक और मलेशिया के विदेशी शिष्टमंडलों ने एफएसआई की यात्रा की और विचारों का आदान–प्रदान किया।

विधायी एवं संधियां

वर्तमान वर्ष के दौरान, विधायी एवं संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (छठी समिति) और इसकी विभिन्न उप समितियों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल), अंतर्राष्ट्रीय विधि एकीकरण संस्थान (यूनीड्राइट), निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी संबंधी हेग सम्मेलन (एचसीसीएच), अंटार्कटिक परामर्शदात्री समिति (एटीसीएम) की छत्रीसवीं बैठक, जलदस्युता, निःशस्त्रीकरण एवं जलसंसाधन मुद्दों पर संपर्क समूह की बैठकों में सक्रिय भाग लिया।

प्रभाग ने एशियन–अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन (आलको) के वार्षिक सत्र एवं मुक्त व्यापार, निवेश संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रत्यर्पण एवं परस्पर कानूनी सहायता संबंधी करारों पर विभिन्न देशों केसाथ द्विपक्षीय बातचीत में भी भाग लिया।

इसके अलावा, इस प्रभाग ने अप्रैल, 2013 में जम्मू और कश्मीर में वूलर झील संरक्षण परियोजना के कार्य के निरीक्षण हेतु उस स्थान की यात्रा की।

यह प्रभाग बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के साथ सीमा के पुनः सीमांकन पर मध्यस्थता में सक्रिय रूप से शामिल रहा। फरवरी, 2010 में एक 5 सदस्यीय मध्यस्थ पैनल का गठन किया गया। इस प्रभाग ने बांग्लादेश मेमोरियल और के संदर्भ में बांगला डेरा की भारत का उत्तर तैयार करने के लिए विधिक सलाहकारों और अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठकों में भी भाग लिया और 31 जुलाई, 2013 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। बांग्लादेश के अनुरोध पर न्यायाधिकरण पक्षकारों के संगत तटों की यात्रा करने और भारत और बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित आधार बिंदुओं को देखने के लिए मुहाना क्षेत्र का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। न्यायाधिकरण के लिए 23 से 25 अक्तूबर, 2013 को स्थान का दौरा आयोजित किया गया। तत्पश्चात् 9–18 दिसंबर, 2013 तक हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने मामले की मौखिक सुनवाई की गई।

इलैक्ट्रॉनिक अभिशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्रालय ने साइबर मामलों से जुड़े अंतर–मंत्रालयी परामर्शों में भाग लिया। भारत ने वैश्विक साइबर मामलों से जुड़े बहुपक्षीय विचार–विमर्शों में भाग लिया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र समूह, संवर्धित सहयोग पर यूएन–सीएसटीडी कार्य समूह तथा साइबर अपराध पर यूएनओडीसी ओपन एंडेड इंटर–गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप के साथ चर्चा शामिल हैं। फरवरी और मार्च, 2013 में क्रमशः रूस और फ्रांस के साथ साइबर मुद्दों पर द्विपक्षीय संवाद आयोजित हुए। मंत्रालय ने अपने अधिकिरियों को साइबर सुरक्षा पर विशेष बल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। ईजीएंडआईटी डिवीजन ने मंत्रालय को सभी प्रकार की आईटी सहायता तथा मंत्रालय एवं विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में विभिन्न ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के लिए सहायता प्रदान की।

नालंदा

नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विधिक संरचना को इसवर्ष अंतिम रूप देने और इसे कार्य शुरू करने की अनुमति देने वाले आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विश्वविद्यालय के वित्तीय विनियमों को दिसंबर, 2013 में अधिसूचित किया गया। अकादमिक स्टाफ को विशेषाधिकार व उनम्मुक्तियां प्रदान करने संबंधी मुख्यालय करार पर जुलाई, 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव करने वाले एक विधेयक को अगस्त, 2013 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। विदेश की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विधेयक के अंतिम स्वरूप को फरवरी, 2014 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय की वित्त समिति से जुड़ी संविधियों, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल के संविधान तथा विश्वविद्यालय के लिए संसाधन जुटाने वाली धर्मदाय समिति के संविधान को अनुमोदित किया गया। जनवरी, 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2021–22 तक परियोजना की पूंजीगत एवं आवर्ती लागत का वहन करने के लिए 2727 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया।

ब्रूनेई दारुस्लाम में अक्तूबर, 2013 में आयोजित 8वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया। अब तक इस समझौता ज्ञापन पर 10 देशों, अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कम्बोडिया,

चीन, भारत, लाओ, म्यांमा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनेक देशों ने विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वचनबद्धताएं अथवा अंशदान किए हैं। इनमें चीन (1 मिलियन अमेरिकी डॉलर), थाईलैंड (100,000 अमेरिकी डॉलर) और लाओस (50,000 अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं। सिंगापुर के नागरिकों ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वचनबद्धता की है। आस्ट्रेलिया ने पर्यावरण एवं पारिस्थिकी विषय पर एक विद्यापीठ के लिए 1 मिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर की वचनबद्धता की है।

नई सरकार की पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई, 2011 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क एवं मॉरीशस के नेताओं को दिया गया अप्रत्याशित निमंत्रण दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत का सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संबंध स्थापित करने की इच्छा तथा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने आने वाले प्रत्येक नेता नामशः अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचन्द्र राम गुलाम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोईराला, बांग्लादेश संसद की अध्यक्ष डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी तथा भूटान के प्रधानमंत्री लियोनशेन शेरिंग टोबगे के साथ ठोस द्विपक्षीय बैठकें कीं।

भारत ने भूटान के साथ अद्वितीय तथा विशेष संबंधों को सशक्त बनाना जारी रखा जो कि 15–16 जून, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा से प्रदर्शित होता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक तथा चतुर्थ ड्रक ग्यालपो, जिग्मे सिंजेवांग्चुक से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री लियोनशेन शेरिंग टोबगे से भी अधिकारी बातचीत की तथा साझा हित के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 16 जून, 2014 को ग्यालयोंग शोगखांग में संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बी–टू–बी संबंध अर्थात् भारत और भूटान संबंध के रूप में उल्लेख किया।

ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलवी बिन अब्दुल्लाह ने ओमान के सुल्तान यूसुफ बिन अलवी बिन अब्दुल्ला के विशेष दूत के रूप में 3 जून, 2014 को भारत की सरकारी यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ओमान के सुल्तान का संदेश भी दिया। विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज तथा ओमान के विदेश मंत्री ने अपनी बैठक के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

चीन तथा रूस ने जून, 2014 में नई सरकार के साथ उच्चस्तरीय संपर्क स्थापित किए। चीन के विदेश मंत्री वांग यि ने 8 जून, 2014 को राष्ट्रपति झी जिनपिंग के विशेष दूत के रूप में नई दिल्ली की यात्रा की तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ सौहार्दपूर्ण, उपयोगी तथा ठोस चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।

रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दामित्री रोगोजिन ने 17 जून, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25–27 जून, 2014 को बांग्लादेश की पहली यात्रा की। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुहम्मद अब्दुल हामिद तथा प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना से मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री अबुल हसन महमूद अली के साथ भी उपयोगी चर्चा की। विदेश मंत्री ने चेम्बर ऑफ कामर्स, सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों और शैक्षिक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की तथा'' भारत–बांग्लादेश संबंधः सहयोग का एक ढांचा'' विषय जो बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय एवं रणनीतिक अध्ययन संस्थान (बीआईआईएसएस) द्वारा आयोजित या सहयोग हेतु पर एक व्याख्यान दिया।

सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश' स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोगी प्रयास अमरीका के साथ भारत की रणनीतिक सहभागिता की विशेषता है। राष्ट्रपति ओबामा ने शपथ ग्रहण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी तथा उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका आने का न्योता दिया।

■■

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आठ सार्क–देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, तथा श्रीलंका–के नेताओं के साथ, जो 27 मई, 2014 को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद की अध्यक्षा डॉ. शीरीन शर्मन चौधरी के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री श्री लियोनशेन शेरींग टाब्गे के साथ

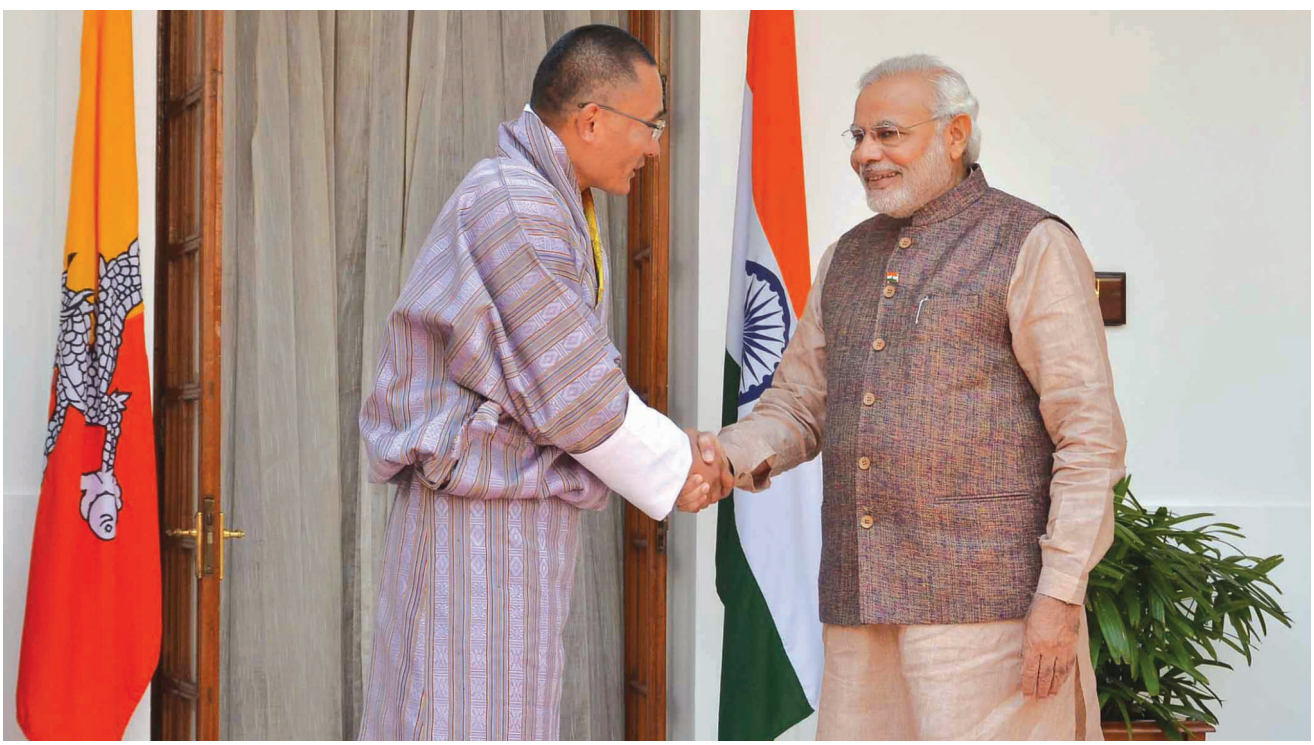

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री नवीनचन्द्र रामगुलाम के साथ मिलते हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोईराला के साथ

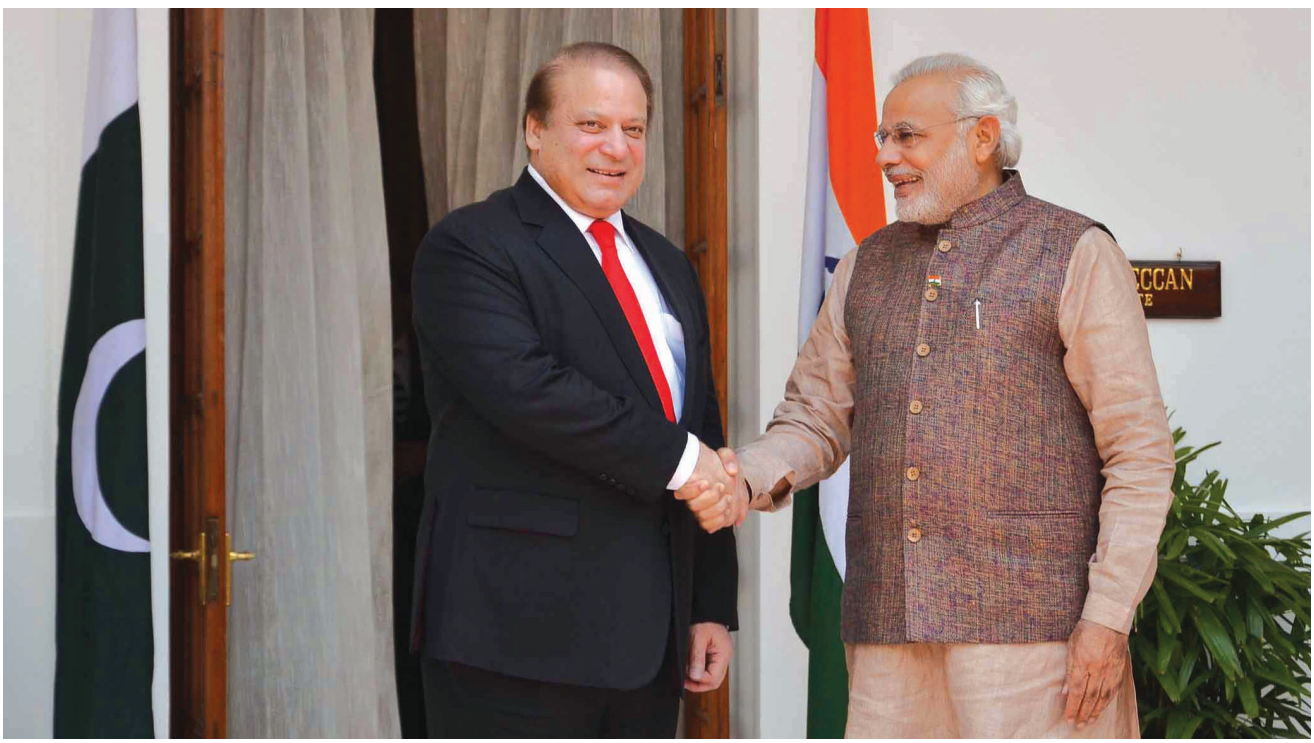

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2014 को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्द्रा राजपक्षे के साथ

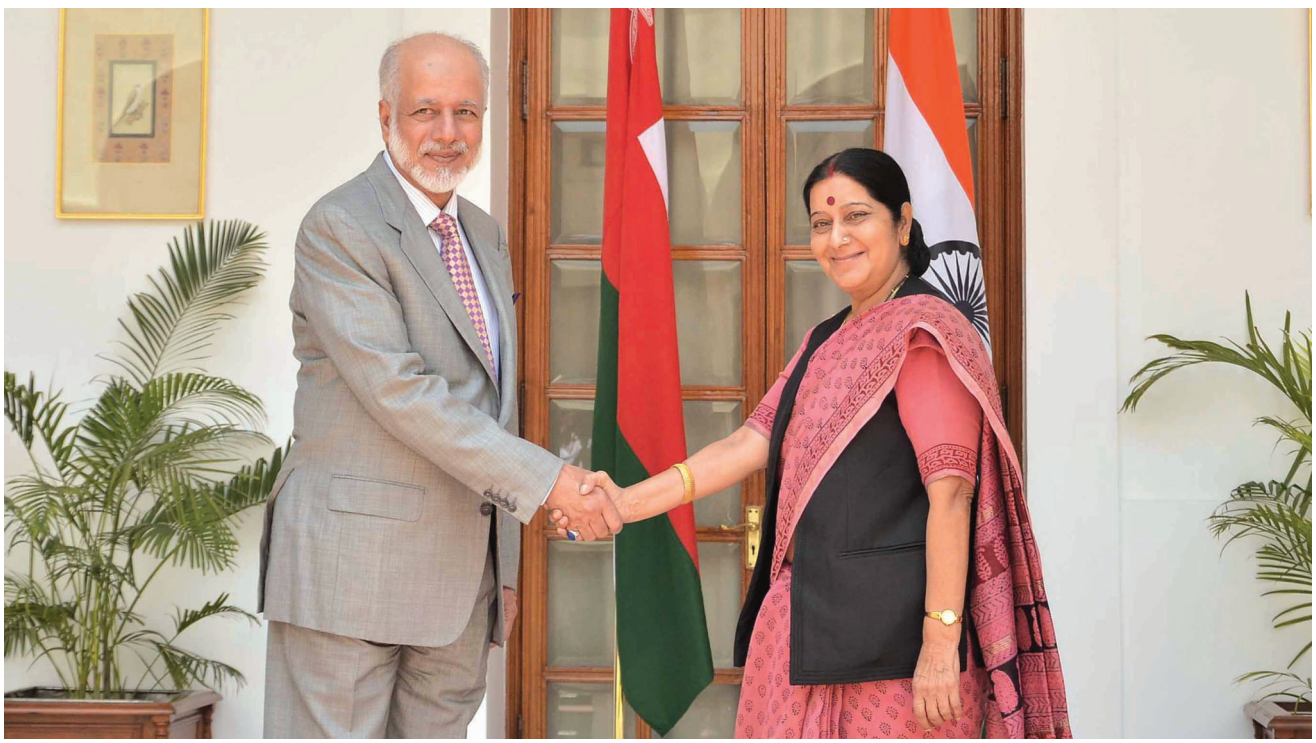

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 3 जून, 2014 को नई दिल्ली में ओमान की सल्तनत के विदेश मंत्री श्री यूसूफ बिन अलाबी बीन अब्दुल्ला के साथ

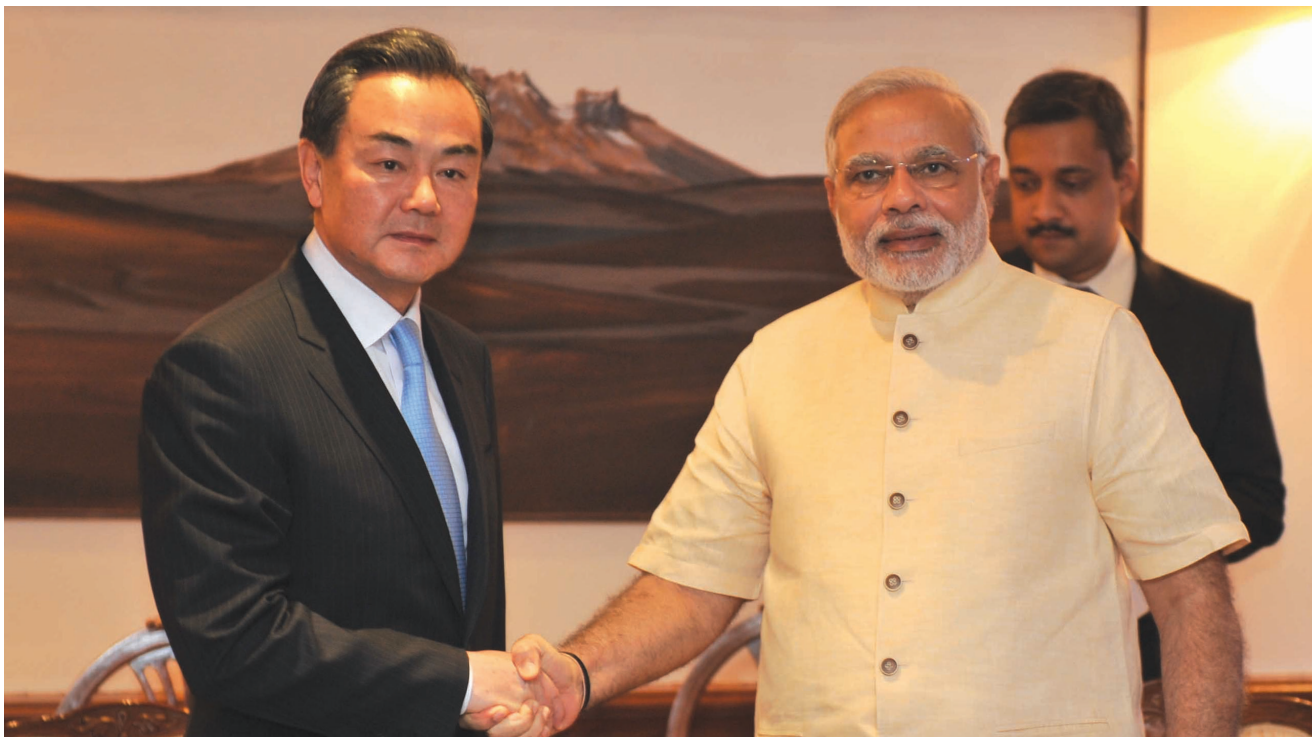

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 09 जून, 2014 को नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यि के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 8 जून, 2014 को नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यि के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15–16 जून, 2014 को अपने भूटान दौरे के दौरान भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक और पूर्व नरेश जिग्में शिंजे वांग्चुक के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15–16 जून,2014 को अपनी भूटान यात्रा के दौरान पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गॉर्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15–16 जून, 2014 को अपनी भूटान यात्रा के दौरान भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15–16 जून, 2014 को अपनी भूटान यात्रा के दौरान भूटान के प्रधान मंत्री श्री शेरिंग टोब्गे के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15–16 जून, 2014 को अपनी भूटान यात्रा के दौरान भूटान के उच्चतम न्यायालय के भवन का उद्घाटन करते हुए

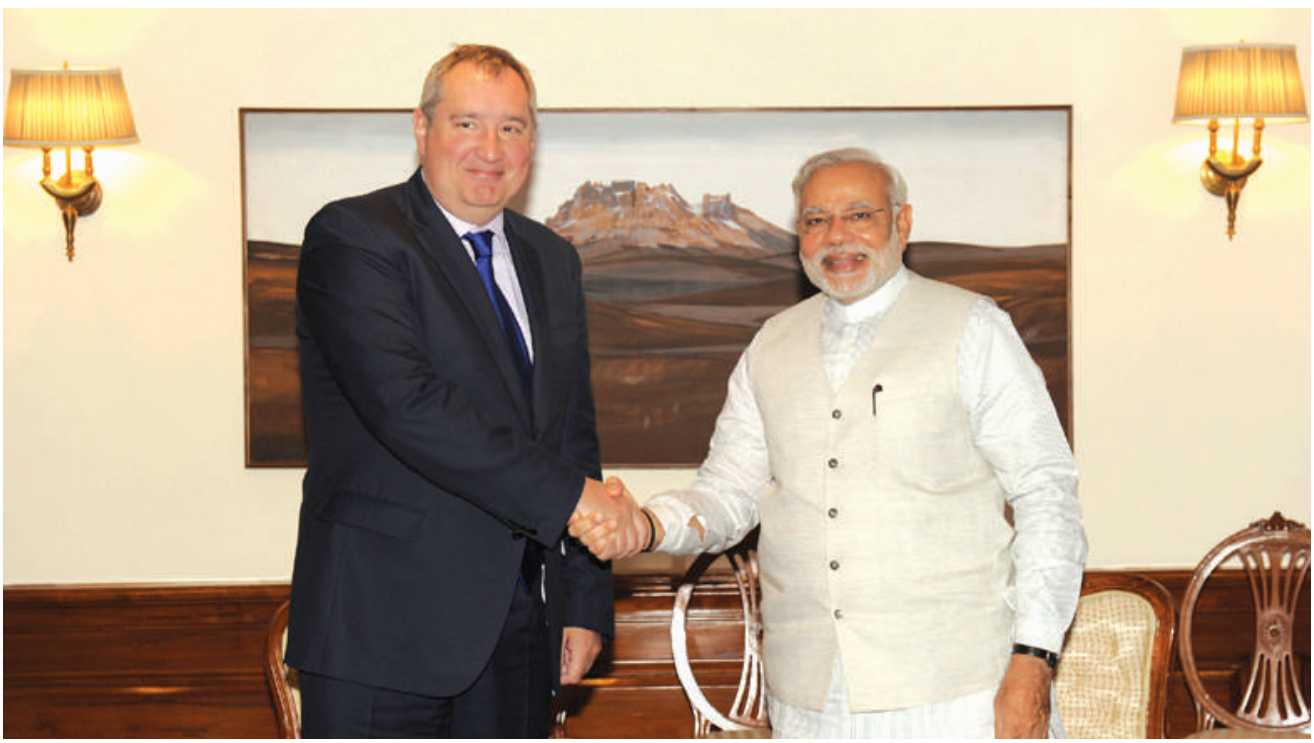

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जून, 2014 को दिल्ली में रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री श्री दमित्री रोगोजिन के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 18 जून, 2014 को दिल्ली में रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री श्री दमित्री रोगोजिन के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 25–27 जून, 2014 तक अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 25–27 जून, 2014 तक अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मो. अब्दुल हामिद के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 25–27 जून, 2014 तक अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री अब्दुल हसन महमूद अली से मुलाकात करते हुए

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 25–27 जून, 2014 तक अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान जातीय संसद में विपक्ष की नेता सुश्री रौशन ईरशाद के साथ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज इराक की स्थिति पर और भारतीय नागरिकों को सहायता दिए जाने के बारे में खाड़ी देशों में भारतीय राजदूतों के साथ नई दिल्ली में 29 जून, 2014 को बैठक करते हुए

भारत के पड़ोसी

1

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच गहन रणनीतिक भागीदारी है जिसे अक्टूबर 2011 में रणनीतिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर करके कार्यरूप दिया गया तथा इसके तहत राजनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास और शिक्षा तथा सामाजिक संस्कृति तथा लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध सहित कई व्यापक क्षेत्र शामिल है। यह हमारे ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है और अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में भारत की भूमिका द्वारा इसे सुदृढ़ किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता तथा आर्थिक विकास लाने के साधन के रूप में उसके पुनःनिर्माण प्रयासों में सहायता की है।

अफगानिस्तान हेतु भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम देश भर में फैले हुए हैं जिसमें 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की वचनवद्धता शामिल है जो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गतिविधियों के लगभग पूरे क्षेत्र में फैली है। संभार तंत्रीय और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गई हैं दृ निमरोज प्रोविंस में जरांज से देलाराम तक 218 किलोमीटर लंबी सड़को का निर्माण और चिमताला में एक सब–स्टेशन के साथ पुल–ए–खुमरी से काबुल तक 220 कि.वाट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। काबुल में अफगानिस्तान के नए संसद भवन, जो बहुलता तथा लोकतंत्र में दोनों देशों की समान वचनबद्धता का प्रतीक है, का निर्माण तथा हेरात प्रोविंस में सलमा बांध का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है और 2015 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

इस अवधि के दौरान भारत तथा अफगानिस्तान के बीच प्रमुख उच्च स्तरीय आदान–प्रदान/वार्ताएं निम्नानुसार थीं:

- अफगान की संसद के उच्च सदन (मेशरानो जिरगा) के 102 संसद सदस्यों में से 94 संसद सदस्यों के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 11–17 फरवरी, 2013 तक भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने अपने विधायी अनुभवों को साझा किया तथा संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, नई दिल्ली में भारतीय संसदीय प्रक्रिया से भी परिचित हुए।
- भारत–अमरीकी–अफगान की दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अफगानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अफगान के उप विदेश मंत्री जावेद लुदिन द्वारा किया गया था तथा अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण तथा केंद्रीय एशिया मामले के सहायक सचिव रॉबर्ट ओ. ब्लेक, जूनियर ने किया। अपर सचिव (पीएआई) वाई.के. सिन्हा द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया।
- एनएसए ने अफगानिस्तान के संबंध में रूस तथा चीन के साथ त्रिपक्षीय परामर्श के 20 फरवरी, 2013 को मॉस्को की यात्रा की।
- एनएसए ने 26 फरवरी, 2013 को काबुल की यात्रा की जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति हामिद करजई तथा अफगान एनएसए, डॉ. रंगिन ददफार स्पंटा के साथ भेंट की।
- राष्ट्रपति हामिद करजई ने डॉ. जलमाई रसूल, पूर्व विदेश मंत्री, डॉ. रंगिन ददफार स्पंटा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा अन्य अधिकारियों के साथ 20–22 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की।
- राष्ट्रपति हामिद करजई ने 12–15 दिसंबर, 2013 तक भारत में एक कार्यचालन दौरा किया। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ईएएम तथा एनएसए ने अफगानिस्तानी राष्ट्रपति से भेंट की।
- हमारे उप–राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के द्वितीय उप राष्ट्रपति, मोहम्मद करीम खलीली ने 20–23 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ श्री अब्दुल हादी अरघंडीवाल, अर्थव्यवस्था मंत्री, श्री ओब्दुल्लाह ओबेद, उच्चतर शिक्षा मंत्री, श्री वहीदुल्ला शहरानी, खनन मंत्री तथा श्री शेर मोहम्मद करीमी, अफगानिस्तान के सेनाध्यक्ष भी थे।
- श्री फारूक वडराक, अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री ने मुम्बई में विश्व शिक्षा कांग्रेस में भाग लेने के लिए 26–29 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की।

- विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 23–25 अगस्त, 2013 तक काबुल तथा जलालाबाद की यात्रा की। उन्होंने अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री श्री इरशाद अहमदी से विचार–विमर्श किया तथा राष्ट्रपति करजई से भी भेंट की।
- श्री इरशाद अहमदी ने विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के लिए 17 सितंबर, 2013 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने ईएएम से भेंट की तथा विदेश सचिव के साथ विचार–विमर्श किया।
- अफगानिस्तान के संबंध में भारत–यूके के संयुक्त कार्य समूह की अधिकारिक स्तर पर पहली बैठक नई दिल्ली में 14 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई।
- भारत ने 16 जनवरी, 2014 को अफगानिस्तान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की मेजबानी की। इस बैठक में श्री ओमार दाऊदजई, अफगानिस्तान के गृह मंत्री, सुश्री हुस्न बानो गजनफर, अफगानिस्तान की महिला कार्य मंत्री, श्री इरशाद अहमदी, अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री, श्री अब्दुल सतार सादत, अफगानिस्तान के चुनाव शिकायत आयोग के अध्यक्ष, डॉ. अहमद युसुफ नूरिस्तानी, अफगानिस्तान के स्वतंत्र चुनाव आयोग के अध्यक्ष तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के लिए विशेष दूत और अन्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ईएएम ने बैठक का उद्घाटन किया।
- भारत ने 17 जनवरी, 2014 को 'हर्ट ऑफ एशिया' प्रक्रम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की।
- विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 15 फरवरी, 2014 को कंधार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जहां उन्होंने राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मई, 2011 में अपनी काबुल यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय हेतु सहायता का वचन दिया था।
- राष्ट्रपति हामिद करजई ने कोलंबो जाते हुए 10 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में पारगमन/संक्षिप्त प्रवास किया।
- उप राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद कासिम फहीम, जिनका 9 मार्च, 2014 को निधन हो गया था, के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 11 मार्च, 2014 को काबुल में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत अफगानिस्तान पर केंद्रित क्षेत्रीय सहयोग प्रक्रम 'हर्ट ऑफ एशिया' में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। ईएएम ने 26 अप्रैल, 2013 को प्रक्रम की तीसरी मंत्रालयी बैठक में भाग लिया। इस प्रक्रम के तहत भारत व्यापार, वाणिज्य तथा निवेश संभावनाएं, सीबीएम का नेतृत्व कर रहा है। इस सीबीएम के तत्वावधान में भारत सरकार एवं अफगानिस्तान की सरकार के सहयोग से फिक्की ने 18 नवंबर, 2013 को 'अफगानिस्तान के साथ व्यापार' संबंधी सम्मेलन'' सह प्रदर्शनी का आयोजन किया। डॉ. हजरत ओमार जाखीलवाल, वित्त मंत्री, डॉ. मोहम्मद आसिफ रहीमी, कृषि मंत्री, श्री मुजामिल शिनवारी, उप वित्त मंत्री तथा श्री जामिल हरेस, खनन मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया।

बांग्लादेश

भारत से बांग्लादेश को की गई महत्वपूर्ण यात्राओं में गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे की 28–29 जनवरी, 2013, विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की 16–17 मार्च, 2013, राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की 3–5 मार्च, 2014, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ की 17–20 जून, 2013, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री के. रहमान खान की 14–18 सितंबर, 2013, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला की 21–22 मार्च तथा 4–6 अक्तूबर, 2013 और विदेश सचिव सुजाता सिंह की 4–5 दिसंबर, 2013 की यात्राएं शामिल हैं।

बांग्लादेश से भारत में मंत्रालयी स्तर की यात्राओं में विदेश मंत्री डॉ. दीपू मोनी की 25–27 जुलाई तथा 10–12 नवंबर, 2013, वित्त मंत्री श्री अबुल माल अब्दुल मुहित की 2–5 मई, 2013 तथा सूचना मंत्री श्री हसनुल हक इनू की 10–13 अप्रैल, 2013 की यात्राएं शामिल है। वर्ष 2014 का आरंभ श्री तोफेल अहमद, वाणिज्य मंत्री की उच्च स्तरीय यात्रा से हुआ जिन्होंने 5वें दक्षिण एशिया व्यापार अग्रणी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16–17 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की। श्री असदाजुमन नूर, बांग्लादेश के संस्कृति मंत्री ने 28–29 जनवरी, 2014 को एक पुस्तक मेले में भाग लेने के लिए कोलकाता की यात्रा की। डॉ. शिरिन शर्मिन चौधरी, जतिया संसद के अध्यक्ष ने स्पीकर के रूप में पहली बार 12–15 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध डॉ. गोहर रिजवी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार की 12–13 मार्च, 2014 तक नई दिल्ली यात्रा के दौरान और मजबूत हुए और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से मुलाकात की। वर्ष के आरंभ में उच्च स्तरीय आदान–प्रदान में और प्रगति लाने के लिए बांग्लादेश के विदेश सचिव श्री मोहम्मद शाहीदुल हक ने 19–21 मार्च, 2014 तक नई दिल्ली की यात्रा की तथा विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया और भारत के गृह सचिव, वाणिज्य सचिव, जल संसाधन सचिव, ऊर्जा सचिव तथा पोत परिवहन सचिव से मुलाकात की।

संयुक्त परामर्श आयोग (जेसीसी) की दूसरी बैठक 16–17 मार्च, 2013 तक ढाका में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा किया गया। जेसीसी ने 2011 के संयुक्त वक्तव्य तथा 2010 की संयुक्त विज्ञप्ति के कार्यान्वयन सहित भारत तथा बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण आयामों की समीक्षा की। जेसीसी से पहले विदेश सचिव श्री रंजन मथई द्वारा 9–11 फरवरी, 2013 तक ढाका की यात्रा की गयी। 19–22 जुलाई, 2013 तक गृह सचिव स्तर पर; 19 जुलाई, 2013 को सुरक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह; तथा 14–18 सितंबर, 2013 तक महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल तथा बॉर्डर गॉर्ड बांग्लादेश द्वारा संस्थागत वार्ता के दौरान सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया। हमारे सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ढ़ाका में 23 अक्तूबर, 2013 को डॉ. मुहिउद्दीन खान आलमगीर, बांग्लादेश के गृहमंत्री की उपस्थिति में प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन के कागजातों का आदान–प्रदान किया गया।

इस वर्ष व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुकर बनाने के लिए संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया। श्री अब्दुल लतीफ सिद्दीकी, वस्त्र एवं पटसन मंत्री, बांग्लादेश ने 19 अगस्त, 2013 को दिल्ली की यात्रा की। दोनों सरकारों के बीच फैशन प्रौद्योगिकी, कौशल आदान–प्रदान, उत्पादकता वृद्धि तथा वस्त्र विकास में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश के निवेश बोर्ड द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ तथा भारत–बांग्लादेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड के सहयोग से जून, 2013 में मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता में आयोजित निवेशक रोड शो से भारत तथा बांग्लादेश की कंपनियों के बीच बांग्लादेश में निवेश के लिए लगभग 100 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश को अत्यधिक संवेदनशील 46 वस्त्र टैरिफ लाइनों तक कर मुक्त, कोटा–मुक्त पहुंच एवं तम्बाकू, स्प्रिट और एल्कोहल 25 टैरिफ लाइनों को छोड़कर सभी मदों तक कर–मुक्त, कोटा–मुक्त पहुंच को देखते हुए भारत को बांग्लादेश का निर्यात 2011–12 के 498.4 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2012–13 में 563.9 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि है। यह बांग्लादेश से भारत को अब तक के निर्यात का सर्वोच्च स्तर है और यह बांग्लादेश को वर्तमान में सार्क देशों के बीच भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बनाता है।

व्यापार, वाणिज्य तथा संपर्क के क्षेत्र में सहयोग नई दिल्ली में 13–14 जून, 2013 को आयोजित व्यापार संबंधी 8वीं जेडब्ल्यूजी बैठक; 21–22 अक्तबूर, 2013 को ढ़ाका में आयोजित सीमा–शुल्क संबंधी 9वें संयुक्त समूह; तथा ढ़ाका में 29 सितंबर, 2013 को आयोजित अंतर्देशी जल पारगमन तथा व्यापार प्रोटोकोल (पीआईडब्ल्यूटीटी) के अंतर्गत 16वीं स्थायी समिति की बैठक के माध्यम से जारी रखा गया। गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा बांग्लादेश के गृहमंत्री डॉ. मुहिउद्दीन खान आलमगीर की उपस्थिति में 17 नवंबर, 2013 को अगरतल्ला में समेकित चैक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। व्यापार संबंधी संयुक्त कार्य समूह का नौंवा दौर 12–13 मार्च, 2014 को ढ़ाका में आयोजित किया गया जिसके दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और सूचना के आदान–प्रदान, परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन तथा व्यापार में बाधाओं को दूर करके व्यापार को सुकर बनाने हेतु सीमा अवसंरचना में सुधार करने के उपायों पर विचार–विमर्श किया।

वस्त्र सहयोग, स्वास्थ्य सहयोग, मत्स्य पालन तथा व्यापार सहयोग के क्षेत्रों में संस्थागत वार्ता जारी रही। वस्त्र सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक ढ़ाका में 27 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई। स्वास्थ्य सहयोग संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक नई दिल्ली में 26–27 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई। मत्स्य पालन सहयोग संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक ढ़ाका में 12–13 मार्च, 2014 को आयोजित की गई। इसी प्रकार, नकली नोटों से संबंधित कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में 22–24 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई।

इस अवधि के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग में संतोषजनक प्रगति हुई है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच ग्रिड संपर्क का भारत तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा 5 अक्तूबर, 2013 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया जिसने बांग्लादेश को भारत से 500 एमडब्ल्यू ऊर्जा के आयात को सुकर बनाया है। ऊर्जा सचिव श्री उमाशंकर के अप्रैल, 2013 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान तीन करार नामतः ऊर्जा क्रय करार (पीपीए), क्रियान्वयन करार (आईए) तथा 1320 एमडब्ल्यू समता के विद्युत के लिए अनुपूरक संयुक्त उद्यम करार (एसजेवीए) पर खुलना में हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग संबंधी भारत–बांग्लादेश संयुक्त संचालन समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में 26–27 जून, 2013 को आयोजित की गई थी तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग संबंधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक नवंबर, 2013 में ढ़ाका में आयोजित की गई।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तथा पेट्रोबांग्ला ने 17 फरवरी, 2014 को बंगाल की खाड़ी में दो उथले जल ब्लॉकों में तेल तथा गैस की खोज और उत्पादन के लिए उत्पादन संबंधी दो साझा करारों पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है जबकि बांग्लादेश ने भारत सरकार द्वारा संचालित तेल कंपनी ओवीएल को गैस तथा तेल की खोज के लिए जल ब्लॉक प्रदान किए।

बांग्लादेश को विस्तारित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण

श्रृंखला के उपयोग में नियमित प्रगति प्राप्त की गई है, जो कि भारत द्वारा किसी देश को प्रदान की गई सबसे बड़ी एकल ऋण श्रृंखला है। 795 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजनाओं पर पहले ही सहमति प्रदान की गई है और ग्यारह परियोजनाओं के लिए चौदह संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से अधिकांश कार्यान्वयनाधीन/संपूर्णता के चरण में है। इसी प्रकार, सहायता अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान तीन भागों में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने भी, प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 4 सितंबर, 2013 को उद्घाटित, बांग्लादेश के 64 जिलों में प्रत्येक के मॉडल स्कूलों में आईटी प्रयोगशालाओं की स्थापना करके अपनी वचनबद्धता पूरी की। भारत ने चक्रवात सिडर, जिसने नवंबर, 2007 में तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत्यु और विनाश किया, से प्रभावित परिवारों को 2800 सौर लैंप भी वितरित किए। भारत तथा बांग्लादेश ने लघु विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर 11 अप्रैल, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जल तथा ऊर्जा एवं पारगमन तथा संपर्क के संबंध में बांग्लादेश, भूटान तथा भारत के बीच ढ़ाका में क्रमश 18 अप्रैल, 2013 और 19 अप्रैल, 2013 को पहली उप क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अपनी किस्म का पहला कदम था और इससे उप क्षेत्रीय संदर्भ में परस्पर लाभ के लिए क्षेत्र के आर्थिक विकास और समृद्धि की समान इच्छा की प्राप्ति हेतु भविष्य के व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।

रक्षा क्षेत्र में सतत् आदान–प्रदान के भाग के रूप में बांग्लादेश सेनाध्यक्ष जनरल इकबाल करीम भुइयान ने 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2013 तक भारत की यात्रा की और जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ, पूर्वी कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल दलवीर सिंह ने 23–26 सितंबर, 2013 को बांग्लादेश की यात्रा की। ढ़ाका में 25–28 अगस्त, 2013 तक थल सेना स्टाफ के बीच चौथी वार्ता और 15–17 अप्रैल, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित जल सेना स्टाफ के बीच पहली वार्ता द्वारा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सुदृढ़ हुआ।

बांग्लादेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के प्रथम उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 14–19 दिसंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत तथा बांग्लादेश के बीच शैक्षिक सहयोग, आदान–प्रदान और संपर्कों को सुदृढ़ करना था।

ढ़ाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस तथा प्रबुद्ध बांग्लादेशी विद्वान और लेखक प्रोफेसर अनीसुजमान को 2014 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मभूषण प्रदान किया गया। प्रोफेसर अनीसुजमान बांग्लादेश में इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है।

भूटान

वर्ष 2013 में जल विद्युत, परिवहन, संचार, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा कृषि सहित महत्व के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में सतत प्रगति देखी गई।

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 14–15 जनवरी, 2013 तक भूटान की राजकीय यात्रा की। उन्होंने भूटान नरेश तथा रानी के साथ मुलाकात की और भूटान के सम्मानित व्यक्तियों के साथ भेंट की।

महामहिम जिग्मे खेसर नामउयाल वांगचुक, भूटान नरेश तथा महामहिम जेटसन पेमा वांगचुक, महारानी ने 23–30 जनवरी, 2013 तक भारत की यात्रा की। भूटान नरेश नई दिल्ली में आयोजित 64वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री जिग्मे वाई. थिनले ने 7–9 फरवरी, 2013 तक भारत की यात्रा की।

भूटान ने जुलाई, 2013 में अपने दूसरे लोकतांत्रिक चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन और विदेशी सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 9–10 अगस्त, 2013 तक भूटान की यात्रा की और भूटान के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वृहत विचार–विमर्श किए।

भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे ने कार्यग्रहण करने के पश्चात् प्रथम यात्रा के रूप में 30 अगस्त से 4 सितंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ विदेश मंत्री श्री रिनजिन डोर्जे भी थे। भूटान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा विपक्ष की नेता, लोकसभा के साथ मुलाकात की। उन्होंने परस्पर हित के मुद्दों पर वृहत विचार–विमर्श किया यात्रा के दौरान भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी) के अनुरोध पर भारत सरकार भूटान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013–18) के लिए 4500 करोड़ रुपए तथा इसकी आर्थिक प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हुई।

भूटान की राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष डॉ. सोनम किंगा के नेतृत्व में 14 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 जुलाई से 1 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी), लोकसभा सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और स्पीकर तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की। रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) के प्रमुख संचालन अधिकारी (सीओओ) मेजर जनरल बाटू शेरिंग ने 12–17 सितंबर, 2013 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने सेना अध्यक्ष के साथ मुलाकात की तथा रक्षा मंत्री से भेंट की। भूटान के वित्त मंत्री नाग्मे दोर्जी ने 27–30 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की तथा वित्त मंत्री के साथ विचार–विमर्श किए।

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार एवं विकास भागीदार बना रहा। भारत सरकार तीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं (एचईपी) अर्थात् पुनातसांगछू–I (1200 एमडब्ल्यू), पुनातसांगछू–II (1020 एमडब्ल्यू) तथा मांगदेछू (720 एमडब्ल्यू) के निर्माण में भूटान की सहायता कर रही है। 12वां अधिकार प्राप्त संयुक्त समूह (ईजेजी), जो भूटान में एचईपी के क्रियान्वयन के निगरानी करता है, की मार्च, 2014 में थिम्पू में बैठक आयोजित की गई।

चूखा एचईपी (336 एमडब्ल्यू) ने 2013 में अपनी 41वीं वर्षगांठ मनाई। भूटान ने भारत को चूखा संयंत्र से ऊर्जा की बिक्री के जरिए राजस्व के रूप में 4957.6 करोड़ रुपए अर्जित किए जिसने उसके सामाजिक–आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है। दुंगसम सीमेंट संयंत्र, भूटान में सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र है जिसे भारत सरकार की 400 करोड़ रुपए की सहायता से निर्मित किया है और इसने नवंबर, 2013 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया।

भारत–भूटान फाउंडेशन (आईबीएफ) द्वारा प्रायोजित भारत–भूटान साक्षरता उत्सव के चौथे अंक ''माउंटेन इकोज'' का थिम्पू में 9–11 अगस्त, 2013 तक आयोजन किया गया। आईबीएफ की 13वीं बैठक नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई। आईबीएफ, साहित्यिक उत्सवों और द्विपक्षीय आदान–प्रदान के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करता है।

भूटान नरेश तथा महारानी ने 6–10 जनवरी, 2013 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। शाही युगल दो दशकों में राष्ट्रपति भवन में ठहरने वाले पहले विदेशी मेहमान थे। नरेश ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ मुलाकात की। यात्रा के दौरान भारत सरकार ने मौजूदा 300 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान अवधि एक और वर्ष तक बढ़ाने के आरजीओबी के अनुरोध पर अपनी सहमति प्रदान की।

भूटान की राष्ट्रीय असेम्बली के स्पीकर जिग्मे जांगपू की अध्यक्षता में एक तेरह सदस्यी प्रतिनिधिमंडल ने 13–16 जनवरी, 2013 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा के स्पीकर तथा अन्य संसद सदस्यों के साथ भेंट की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारतीय संसद के संचालन संबंधी एक सेमिनार में भी भाग लिया जिसे बीपीएसटी द्वारा आयोजित किया गया था।

वाणिज्य सचिव के स्तर पर व्यापार तथा पारगमन संबंधी द्विपक्षीय बैठक थिम्पू में 21 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 4 मार्च, 2014 को म्यांमा में बीआईएमएसटीईसी के दौरान प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने चार संयुक्त उद्यम मॉडल एचईपी (600 एमडब्ल्यू कोलोंगछू एचईपी, 570 एमडब्ल्यू वांगछू एईपी, 180 एमडब्ल्यू बुनखा एचईपी तथा 770 एमडब्ल्यू चामखरछू एचईपी), तथा कोलोंगछू एचईपी के क्रियान्वयन हेतु अंतर–सरकारी करार के ढांचे पर भारत सरकार की सहमति सूचित की।

शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में घनिष्ट सहयोग जारी रहा। वर्ष के दौरान भूटान के छात्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 1100 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। भारत सरकार ने भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूटान के छात्रों को अवर स्नातक छात्रवृत्ति के रूप में 55 करोड़ रुपए प्रदान करने की वचनबद्धता दी।

चीन

चीन के प्रीमियम ली किक्यांग ने चीन के प्रमुख के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के प्रथम पड़ाव के रूप में 19–22 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। पूर्व में प्रमुख ली ने कार्यग्रहण करने के दिन 15 मार्च, 2013 को प्रधानमंत्री के साथ दूरभाष वार्ता की। प्रीमियर ली की आधिकारिक यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोबर यात्रा, सिस्टर शहर सहयोग और प्राचीन एवं समाकालीन कार्यों के अनुवाद, भैसें के मांस, मत्स्य उत्पादों, खाद्य एवं खाद्य घटकों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात, सीवेज ट्रीटमेंट में सहयोग, जल की कम खपत से सिंचाई, भारत को चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की हाइड्रोलोजिकल सूचना के प्रावधान तथा भारत–चीन संयुक्त आर्थिक समूह के अंतर्गत तीन कार्य समूहों के कार्यक्रमों सहित लोगों के पारस्परिक आदान–प्रदान से संबंधित 12 प्रोटोकॉल, करारों तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख ली केयांग की 19–22 मई, 2013 तक की यात्रा के दौरान भारत तथा चीन ने 2014 में शांतिपूर्ण–सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों (पंचशील) की 60वीं वर्षगांठ को ''मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष'' के रूप में नामित करते हुए मनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने 22–24 अक्तूबर, 2013 तक चीन की आधिकारिक यात्रा की। सड़क परिवहन क्षेत्र, सीमा पार नदियों, विद्युत उपकरण, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, नालंदा विश्वविद्यालय, सिस्टर–शहर संबंध तथा सीमा सुरक्षा सहयोग से संबंधित नौ करारों तथा समझौता ज्ञापनों पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। 23 अक्तूबर, 2013 को दोनों पक्षों ने – ''भारत–चीन नीतिगत एवं सहकारी भागीदारी के भावी विकास की योजना से संबंधित संयुक्त वक्तव्य'' जारी किया।

भारत तथा चीन के नेताओं के बीच अकसर उच्च स्तरीय संबंधों में मंत्रालयी स्तर पर बैठकें भी शामिल थी। विदेश मंत्री (ईएएम) श्री सलमान खुर्शीद ने चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ 2013 में 5 बार मुलाकात की। 9–10 मई, 2013 को ईएएम ने चीन की यात्रा की तथा विदेश मंत्री (एफएम) वांग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ईएएम ने राज्य काउंसलर यांग जेची के साथ भेंट की तथा प्रीमियर ली के साथ मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग पर एक प्रोटोकॉल पर एक हस्ताक्षर

किए गए। ईएएम तथा एफएम वांग ने 20वें एशियाई क्षेत्रीय मंच के दौरान ब्रूनेई दारूसलम में 02 जुलाई, 2013 को बैठक की। उन्होंने 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में 25 सितंबर, 2013 को पुनः बैठक की। एफएम वांग ने मई, 2013 में प्रीमियर ली के प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में भारत की यात्रा की और रूस–भारत–चीन (आरआईसी) के विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक तथा 11वीं एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक (एएसईएम एफएमएम11) की बैठक में भाग लेने के लिए 10–11 नवंबर, 2013 को पुनः मुलाकात की। उन्होंने 10 नवंबर, 2013 को ईएएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चीन के स्वास्थ्य मंत्री श्री चेन झू ने ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जनवरी, 2013 में नई दिल्ली की यात्रा की। श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने 14–17 जनवरी, 2013 को चीन की यात्रा की। वित्त राज्यमंत्री श्री नमोनारायण मीणा ने तियानजिन में भारतीय स्टैट बैंक की शाखा का उद्घाटन करने के लिए 17–20 फरवरी, 2013 को चीन की यात्रा की। चीन के उप शिक्षा मंत्री श्री लियू लिमिन ने 17–23 मार्च, 2013 तक दिल्ली तथा मुम्बई की यात्रा की। कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (प्रभारी) श्री सचिन पायलट ने 6–8 अप्रैल, 2013 को एशिया वार्षिक सम्मेलन के लिए बोआओ मंच में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री काओ जियानमिंग, चीन के सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूटेरोट के प्रोजीक्यूटर जनरल ने 7–11 अप्रैल, 2013 को भारत की यात्रा की। श्री वांग गांग, चीन के एसएंडटी मंत्री ने नई दिल्ली में चौथी स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी बैठक ख्सीईएम4, में भाग लेने के लिए 16–20 अप्रैल, 2013 को भारत की यात्रा की। उन्होंने श्री जयपाल रेड्डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू–विज्ञान मंत्री से भी मुलाकात की। श्री काई फचाओ, चीन के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म तथा टेलीविजन प्रशासन राज्य मंत्री (एसएपीपीआरएफटी) ने 17–20 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने 18 जून, 2013 को श्री मनीष तिवारी, राज्यमंत्री (सूचना एवं प्रसारण) से भेंट की और नई दिल्ली में चीन के फिल्म उत्सव का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने 4–7 जुलाई, 2013 को चीन की यात्रा की जो 2006 के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा चीन की प्रथम यात्रा थी। सुश्री ली जियाओलिन, चीन अंतर्राष्ट्रीय मित्र शहर संघ (सीआईएफसीए) की अध्यक्ष ने 27–31 अगस्त, 2013 तक दिल्ली तथा मुम्बई की यात्रा की।

वर्ष 2013 में भारत–चीन के बीच व्यापार 65.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चीन को भारत का निर्यात–17.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा चीन से आयात–48.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें 2012 की तुलना में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। व्यापार घाटा अब तक का सबसे अधिक अर्थात् 31.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2 भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार वर्ष दर वर्ष लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 2014 के पहले दो माह में 10.62 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। चीन को भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29ः बढ़ कर 3.543 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत द्वारा व्यापार असंतुलन तथा भारतीय औषधि, आईटी सेवाओं, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों तक बेहतर पहुंच का मुद्दा उच्चतम स्तर सहित विभिन्न अवसरों पर उठाया गया है।

दोनों पक्षों ने रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) की शुरूआत की है। एसईडी के अंतर्गत पांच कार्य समूहों (डब्ल्यूजी) की दो बैठकें 2013 में आयोजित की गई। पहली बैठक नई दिल्ली में 6–8 मई, 2013 तक और दूसरी बैठक बीजिंग में 25–27 सितंबर, 2013 तक आयोजित की गई थी। तीसरे एसईडी का आयोजन बीजिंग में 18 मार्च, 2014 को किया गया। इस वार्ता की सह–अध्यक्षता डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, भारत के योजना आयोग तथा श्री जू शोशी, अध्यक्ष, चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग द्वारा की गई थी। रेल अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा वित्त जैसे क्षेत्रें में द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया था। दोनों पक्षों ने एसईडी के तहत एक कार्य बल का गठन करने का निर्णय लिया ताकि चीन की कंपनियां भारत में उद्योग तथा औद्योगिक जोन में निवेश कर सकें। वार्ता में सतत शहरीकरण तथा आईसीटी में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सतत शहरीकरण तथा ऊर्जा आयोजना में संयुक्त अध्ययन संबंधी कार्य योजनाओं पर भी हस्ताक्षर किए गए। डॉ. आहलूवालिया ने बीजिंग में 19 मार्च, 2014 को प्रमुख ली केयांग के साथ मुलाकात की।

भारत–चीन संयुक्त आर्थिक समूह (जेईजी) के तहत व्यापार एवं सांख्यिकी विश्लेषण संबंधी कार्य समूह की बैठक बीजिंग में 26 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई। भारत–चीन सीईओ मंच ने अपनी पहली बैठक 20 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की थी। मंच ने फोरम प्रणाली के संबंध में एक संयुक्त विज्ञप्ति तथा एक दस्तावेज जारी किया। दूसरा भारत–चीन सीईओ फोरम प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान 23 अक्तूबर, 2013 को आयोजित किया गया। श्री अनिल अंबानी, अध्यक्ष, रिलायंस एडीएजी समूह की अध्यक्षता में नौ भारतीय कंपनियों के सीईओ तथा श्री जेंग झिजी, चीन विकास बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 10 चीनी कंपनियों ने फोरम में भाग लिया।

भारत तथा चीन ने अफगानिस्तान के संबंध में अप्रैल, 2013 में और केंद्रीय एशिया के संबंध में अगस्त, 2013 में पहली वार्ता संचालित की। अप्रैल, 2013 में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यचालन समूह के छठा दौर, मई, 2013 में कौंसली वार्ता का चौथा दौर तथा सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय मंच का सातवां दौर और अगस्त, 2013 में नीतिगत वार्ता का पांचवा दौर आयोजित किया गया । वित्तीय वार्ता का छठा दौर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत–चीन संयुक्त समिति की छठी बैठक सितंबर, 2013 में आयोजित की गई।

भारत और चीन ने राजनीति परिप्रेक्ष्य में सीमा विवाद सुलझाने के लिए ढांचा का पता लगाने हेतु विशेष प्रतिनिधिमंडल (एसआर) की नियुक्ति की। श्री यांग जेची, चीन के स्टेट काउंसलर तथा एसआर ने श्री शिवशंकर मेनन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) तथा एसआर के साथ एसआर वार्ता के 17वें दौर के लिए 10–11 फरवरी, 2014 तक नई दिल्ली की यात्रा की। विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद के हल के लिए ढांचे पर अपने विचार–विमर्श जारी रखे जो तीन चरणीय प्रक्रिया का दूसरा कदम है। विशेष प्रतिनिधियों ने चीन के प्रमुख ली क्यांग की भारत यात्रा और 2013 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की चीन यात्रा के परिणामस्वरूप भारत–चीन संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। एनएसए ने 28 जून, 2013 को प्रमुख ली क्यांग के साथ मुलाकात की जबकि राजदूत यांग जेची ने 11 फवरी, 2014 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

दोनों पक्षों ने जनवरी, 2012 में भारत–चीन सीमा मामलों संबंधी परामर्श एवं समन्वय (डब्ल्यूएमसीसी) हेतु कार्य तंत्र की स्थापना की। डब्ल्यूएमसीसी की 5वीं बैठक नई दिल्ली में 10 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में हाल की घटनाओं की समीक्षा की। दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर शांति और प्रशांति भारत–चीन संबंधों के सतत विस्तार का आधार है।

भारत–चीन सेना के बीच सहयोग भी जारी रहा। एयर वाइस मार्शल एस.एच. सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधिमंडल ने 8–11 जनवरी, 2014 को चीन की यात्रा की। छठी भारत–चीन वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 24 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई।

भारत चीन का तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हाथ में हाथ–2013' दिनांक 4–13 नवंबर, 2013 तक चेन्गडु में आयोजित किया गया। 16 सिख लाइट इन्फ्रेंटी के 160 व्यक्तियों के समूह तथा पीएलए से समान संख्या में सैनिकों ने इस कार्रवाई में भाग लिया। इस कार्रवाई के लिए भारत तथा चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 100 नकली आतंकवादियों को रखा गया था। एक पीएलए जल सेना अस्पताल जहाज 'आर्क पीस' ने भी 6–12 अगस्त, 2013 तक मुम्बई की यात्रा की।

दोनों देशों ने वर्ष 2014 को शांतिपूर्ण–सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों (पंचशील) की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ''भारत–चीन मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष'' के रूप में घोषित किया है। 11 फरवरी, 2014 में उप राष्ट्रपति ने चीन के दूतावास द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ''भारत–चीन मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष'' का शुभारंभ किया। चीन के उप राष्ट्रपति श्री ली यूआंचाओ 24 जनवरी, 2014 को बीजिंग में हमारे दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस आयोजन के दौरान ''भारत–चीन मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष'' का शुभारंभ किया।

यूनान प्रांत के गवर्नर श्री ली जीहेंग ने 24–29 मार्च, 2014 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने ईएएम तथा पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भेंट की। चीन जनवादी राजनीतिक परामर्श सम्मेलन ख्सीपीपीसीसी, शंघाई समिति के अध्यक्ष श्री वू झिमिंग ने 26–28 मार्च, 2014 तक भारत की यात्रा की। श्री पेंग क्वींहुआ, युआंगशी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव ने 30–31 मार्च, 2014 तक भारत की यात्रा की। भारत के विदेश मंत्रालय तथा चीन की वामपंथी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के बीच एक आदान–प्रदान कार्यक्रम भी है। श्री सन किंगयुंन, उप सचिव, सीपीसी शांगशी प्रांतीय समिति ने 5–9 दिसंबर, 2013 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की यात्रा की।

भारत–चीन उच्च स्तरीय मीडिया फॉरम की पहली बैठक 16 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ईएएम तथा चीन के राज्य परिषद् सूचना कार्यालय के विजिटिंग मंत्री श्री काई मिंगझाओ ने संयुक्त रूप से इस फोरम का उद्घाटन किया। वार्षिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 100 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने 13–22 मई, 2013 तक चीन की यात्रा की। उन्होंने प्रमुख ली केयांग से भी मुलाकात की। एक सौ सदस्यीय चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने 7–14 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

भारत तथा चीन के साझा हित हैं जिन्होंने हमें ब्रिक्स, जी–20 और जलवायु परिवर्तन वार्ताओं जैसे मंचों में इकट्ठा किया है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर समन्वय और सहयोग जारी रखा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर घनिष्ठ वार्ता जारी रखी।

मालदीव

मालदीव के राष्ट्रपति यामीन ने भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 1–4 जनवरी, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी, विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने मालदीव के राष्ट्रपति के साथ भेंट की। मालदीव के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन, इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की श्रमिक आवश्यकताओं के संबंध में समझौता ज्ञापन के विस्तार से संबंधित पत्रों का आदान–प्रदान तथा मालदीव के उच्चायोग को एक भूखंड आबंटित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत सरकार ने भारत से आयात के लिए समर्थन ऋण सुविधा में से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करने की घोषणा की और पत्थरों के पिण्ड की आपूर्ति की पुनः बहाली की तथा बीजा नियमों को उदारीकृत किया। यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के नवीकरण, विधि एवं प्रवर्तन अध्ययन संस्थान के निर्माण तथा रक्षा मंत्रालय भवन के निर्माण के निधियन के लिए भारत की वचनबद्धता को भी नवीकृत किया गया। भारत ने 2019–2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की गैर–स्थायी सीट के लिए मालदीव की उम्मीदवारी पर अपने समर्थन को पुनः दोहराया तथा मालदीव ने 2021–2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की गैर–स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने द्विपक्षीय यात्रा तथा 19–21 फरवरी, 2014 को सार्क मंत्री परिषद् के 35वें सत्र में भाग लेने के लिए मालदीव की यात्रा की। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री डुन्या माउमून के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया। यात्रा के दौरान उन्होंने मालदीव सरकार को मेहमान नवाजी तथा पर्यटन अध्ययन के लिए भारत–मालदीव मित्रता संकाय तथा एक नौसेना लेंडिंग क्रॉफ्ट सौंपा। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के नए भवन की स्थापना की आधारशिला भी रखी जिसे भारत की सहायता से निर्मित किया जाएगा।

मालदीव के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नाजिम ने 14–20 अप्रैल, 2013, 11–15 दिसंबर, 2013 तथा 5–7 मार्च, 2014 (समुद्री सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में सहयोग पर त्रिपक्षीय पहल विषयक एनएसए स्तरीय तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए) को भारत की यात्रा की। दूसरे प्रोन्नत लाइट हेलीकॉप्टर को श्री नाजिम की दिसंबर, 2013 में कोच्चि की यात्रा के दौरान मालदीव को प्रतीक रूप सौंपा गया।

मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री श्री मोहम्मद सईद ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 5वें बिजिनेस लीडर कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 15–17 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की।

लोकसभा की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार ने सार्क स्पीकरों तथा संसद सदस्यों के 7वें सम्मेलन के लिए 21–23 दिसंबर, 2013 तक मालदीव के लिए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 17 अक्तूबर, 2013 को मालदीव की यात्रा की तथा राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात की।

लोकसभा की स्पीकर के निमंत्रण पर पीपल्स मजलिस के स्पीकर श्री अब्दुल्ला शाहिद के नेतृत्व में मालदीव की पीपल्स मजलिस के एक बहु दलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 4–8 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार से मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा विदेश सचिव श्री रंजन मथई से नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा मजलिस हेतु क्षमता निर्माण में सहायता को सुदृढ़ करने के लिए उपायों पर विचार–विमर्श किया।

मालदीव के मुख्य न्यायाधीश श्री अहमद फैज हुसैन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर 8–12 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग पर विचार–विमर्श किया।

ईसीएम के अध्यक्ष फौद तौफीग के नेतृत्व में मालदीव के चुनाव आयोग (ईसीएम) के सात सदस्यीय वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने 4–9 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान ईसीएम को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने पर विचार–विमर्श किया गया।

सरकार ने संपूर्ण राजनैतिक परिदृश्य में नेताओं को शामिल करने की अपनी नीति को जार रखा और इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति गयूम, एमडीपी के नेता पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद तथा पीपीएम के नेता श्री अब्दुल्ला यामीन ने भारत की यात्रा की।

म्यांमा

रक्षा मंत्री (आरएम) श्री ए.के. एंटनी ने 21–23 जनवरी, 2013 तक म्यांमा की यात्रा की। यात्रा के दौरान आरएम ने राष्ट्रपति यू थेइन सेइन से मुलाकात की और रक्षा मंत्री लेफ्टीनेंट जनरल वाई ल्वीन तथा रक्षा सेवाओं के सी–इन–सी उप वरिष्ठ जनरल मिन ऑग लेइंग के साथ विचार–विमर्श किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने जून, 2013 में पूर्वी एशिया संबंधी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए म्यांमा की यात्रा की। नव गठित संयुक्त व्यापार एवं निवेश मंच की पहली बैठक भी इस यात्रा के दौरान आयोजित की गई। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री तथा रक्षा राज्य मंत्री, श्री जितेंद्र सिंह ने नई पाई ताव, म्यांमा में 11 दिसंबर, 2013 को आयोजित 27वें दक्षिण–पूर्वी एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेईफियू रियो ने 3–7 फरवरी, 2014 तक म्यांमा की 5 दिवसीय यात्रा की। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन ने 12–15 मार्च, 2014 तक म्यांमा की राजकीय यात्री की। यात्रा के दौरान उन्होंने यंगून में भारत इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (आईएनडीईई) का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटीईसी) समिट के लिए बंगाल की खाड़ी की तीसरी पहल में भाग लेने के लिए 3–4 मार्च, 2014 को नई पाई ताव की दो दिवसीय राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री के साथ विदेश

मंत्री (ईएएम), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए), विदेश सचिव (एफएस) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। बीआईएमएसटीईसी समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने म्यामांर के राष्ट्रपति श्री यू थेइन सेइन, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला, भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोगबे तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग के अध्यक्ष डॉ आंग सान सू की के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

लोकसभा की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार ने फरवरी, 2013 में म्यामांर को जाने वाले एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिधिनित्व किया। म्यांमा की संसद के उच्च सदन के स्पीकर श्री यू किंग आंग माइंट द्वारा एक 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 2–5 दिसंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की गई। ये आदान–प्रदान म्यांमा के साथ हमारे संबंधों को अधिक विस्तृत तथा गहन बनाने के प्रतीक के रूप में दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग का भाग है। स्पीकर श्री यू किन आंग माइंट ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और लोक सभा की स्पीकर के साथ मुलाकात की। म्यांमा के सागाइंग तथा मंडालय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों ने नवंबर, 2013 में मणिपुर शंघाई उत्सव में भाग लेने के लिए इम्फाल की यात्रा की। उन्होंने क्षेत्रीय मंत्रियों, अधिकारियों, व्यापारियों, सांस्कृतिक समूहों, कलाकारों, शिक्षाविदों तथा मीडिया सहित 110 सदस्यीय म्यांमा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। म्यांमा के मुख्यमंत्रियों ने डिब्रूगढ़, असम में आयोजित पूर्वोत्तर व्यापार समिट में भी भाग लिया।

म्यांमा थल सेना अध्यक्ष ने जुलाई, 2013 में भारत की यात्रा की। म्यांमा थल सेना उप कमांडर–इन–चीफ वाइस सीनियर जनरल सोई विन ने दिसंबर, 2013 में भारत की यात्रा की। भारतीय पक्ष से थल सेना अध्यक्ष ने अक्तूबर, 2013 में म्यांमा की यात्रा की। उन्होंने म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ भेंट की। नवंबर, 2013 में म्यामांर में जल सेना अधिकारियों के बीच वार्ता का दूसरा दौर भी आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान राजकीय स्तर पर आयोजित बैठकों में नई पाई ताव में जनवरी, 2013 में रेल संपर्क संबंधी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक; नय पाई ताव में फरवरी, 2013 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक; जनवरी, 2013 में सर्वेक्षण विभागों के प्रमुखों की 8वीं बैठक; जून, 2013 में गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय स्तर की बैठक; जुलाई, 2013 में क्षेत्रीय सीमा समिति की तीसरी बैठक; जुलाई, 2013 में विदेश कार्यालय परामर्श; जनवरी, 2014 में काले में क्षेत्रीय सीमा समिति की चौथी बैठक शामिल है।

वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 की पहली छमाही में द्विपक्षीय व्यापार 552.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। सीमा व्यापार समिति की दूसरी बैठक के दौरान भारत तामू, मणिपुर में मोरह में सीमा व्यापार प्वाइंट, में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने में म्यांमा को सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ। इससे म्यांमा के साथ अधिक सीमा व्यापार को सुकर बनाने के लिए मोरह में स्थापित किए जा रहें समेकित चैक पोस्ट का अनुपूरक होगा।

कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अप्रैल, 2013 में यंगून तथा मंडले को जाने वाले एक 21 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का आयोजन किया। मई, 2013 में मोनवया शहर, म्यांमा में 'क्षेत्रीय व्यापार तथा निवेश सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मणिपुर के पांच मंत्रियों के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री, नागालैंड के दो मंत्री, मिजोरम के एक मंत्री तथा अधिकारियों, व्यापारियों तथा निवेशकों सहित 110 सदस्यों ने भाग लिया। इस समारोह का सागाइंग तथा मणिपुर के मुख्यमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

सीआईआई द्वारा सितंबर, 2013 में एक 19 सदस्यीय सीईओ व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा आयोजित की गई। भारतीय मर्चेन्ट चैम्बर, मुम्बई ने भी यंगून में 25 नवंबर, 2013 को ''इंडिया कॉलिंग'' शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आरआईएस ने 28 नवंबर, 2013 को नय पाई ताव में ''भारत तथा म्यांमा के बीच संपर्क कॉरीडोर से विकास कॉरीडोर तक'' एक सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमीनार म्यांमा राष्ट्रीय आयोजना एवं आर्थिक विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

ओवीएल को अक्तूबर, 2013 में म्यांमा प्राधिकारियों द्वारा दो तटवर्ती ब्लॉक आबंटित किए गए।

भारत प्रशिक्षण, विशेषज्ञता के प्रावधान, ऋण श्रृंखला तथा/अथवा सहायता अनुदान सहित विकास परियोजनाओं के माध्यम से म्यांमा की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। प्रशिक्षण केंद्रों सहित कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं तथा नई परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में है। एचएमटी द्वारा मिंगयान में स्थापित किए जा रहे दूसरे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को पूरा किया गया तथा अक्तूबर, 2013 में इसे म्यांमा को सौंप दिया गया। वर्ष के दौरान आईटी कौशल संवर्धन हेतु भारत म्यांमा केंद्र के उन्नयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत ने आईटीईसी, टीसीएस तथा आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत म्यांमा की मानव संसाधन क्षमता निर्माण के लिए काफी सहायता प्रदान की है। म्यांमा को मई, 2012 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 500 आईटीईसी स्लॉट प्रदान किए गए हैं।

भारत तथा म्यांमा के घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है। इस वर्ष एक म्यांमा संगीत बैंड ने आईसीसीआर द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया संगीत उत्सव में भाग लिया। सगाइंग तथा मंडले क्षेत्रों के म्यांमा

सांस्कृतिक समूहों ने नवंबर, 2013 में मणिपुर शंघाई उत्सव में भी प्रदर्शन किया।

नेपाल

भारत–नेपाल मित्रता और सहयोग को मुक्त सीमा, लोगों के बीच गहन संपर्क तथा बहुआयामी सामाजिक–आर्थिक संपर्क के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। भारत ने नेपाल को समृद्धि, शांति, स्थिरता तथा लोकतांत्रिक देश के रूप में इसके परिवर्तन में सहायता करना जारी रखा।

19 नवंबर, 2013 को नेपाल में दूसरे संविधान सभा–सह–संसदीय चुनावों के संबंध में भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 1,000 वाहन उपहार में देने तथा दो प्रोन्नत लाइट हेलीकॉप्टर स्थायी रूप से देने सहित अनुरोध की गई संभार तंत्रीय सहायता प्रदान की। चुनावों के दौरान नेपाल के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा गया जिसमें विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की 9 जुलाई, 2013 तक नेपाल यात्रा तथा विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह की 14–15 सितंबर, 2013 को नेपाल यात्रा शामिल है। नेपाल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री तथा यूसीपीएन (एम) अध्यक्ष श्री पुष्प कमल दहल ष्प्रचंडष (अप्रैल, 2013), पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शेर बहादुर देउबा (जून, 2013), पूर्व प्रधानमंत्री तथा सीपीएन–यूएमएल के वरिष्ठ नेता श्री महादेव कुमार नेपाल (जुलाई, 2013) और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुशील कोइराला (अगस्त, 2013) ने भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर, 2013 में न्यूयार्क में मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष खिल राज रेगमी के साथ मुलाकात की। 19 नवंबर को चुनाव सफलतापूर्वक संचालित किए गए जिसमें नेपाल के लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने भाग लिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने फरवरी, 2014 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पर श्री सुशील कोइराला को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने 3 मार्च, 2014 को म्यांमा बीआईएमएसटीईसी समिट के दौरान प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ द्विपक्षीय बैठक की जिसके दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

माधव प्रसाद घिमिरे, नेपाल के विदेश तथा गृह मंत्री ने 14–16 जनवरी, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह तथा विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की।

भारत–नेपाल के सुरक्षा संबंधों को 2013 में भारत तथा नेपाल के थल सेना अध्यक्षों की यात्राओं तथा मार्च, 2014 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष की नेपाल यात्रा द्वारा सुदृढ़ किया गया। 8–12 अप्रैल, 2013 को बैंगलुरू में सुरक्षा मुद्दों संबंधी भारत–नेपाल द्विपक्षीय परामर्शी समूह की 10वीं बैठक आयोजित की गई। माउंट एवरेस्ट की विजय की 60वीं वर्षगांठ मनाने हेतु तथा पर्वतमाला से अपशिष्ट हटाने के लिए मई, 2013 में माउंट एवरेस्ट के लिए एक भारत–नेपाल अभियान आयोजित किया गया। उत्तराखंड, भारत में 23 सितंबर से 6 अक्तूबर, 2013 तथा रुपानदेही जिला, नेपाल में 5 मार्च से 18 मार्च, 2014 तक भारत तथा नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास श्सूर्य–किरणश के 5वें और 6वें सत्र का आयोजन किया गया। मार्च, 2014 में भारत को नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक की छः दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान भारत–नेपाल सीमा के पास अपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण हेतु एक विशेष तंत्र की स्थापना करने के लिए विचार–विमर्श किए गए।

“नेपाल को सहायता” बजट के अंतर्गत नेपाल को वित्तीय वर्ष 2014 हेतु 380 करोड़ रुपए मूल्य की विकास सहायता भारत द्वारा दी गई जिसका प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया। काठमांडू में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे आपात एवं ट्रामा केंद्र पूर्णत के अंतिम चरण में है और इसे 2014 के शुरूआत में नेपाल सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। वर्ष के दौरान भारत तथा नेपाल दोनों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नेपाल के छात्रों को लगभग 3000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। तेरई सड़क के 605 किलोमीटर के चरण–ᑊ तथा रक्सोल–बीरगंज एवं जोगबनी–विराटनगर में समेकित चेक पोस्ट (आईपीसी) का निर्माण जारी है। भारत–नेपाल सीमा के पास आईसीपी के विकास संबंधी छठी परियोजना अनुवीक्षण समिति की बैठक नई दिल्ली में 12 मार्च, 2014 को आयोजित की गई।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का स्रोत बना रहा, जिसमें नेपाल के कुल विदेश व्यापार का 66 प्रतिशत (4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा नेपाल में कुल विदेशी निवेश का 46 प्रतिशत (408 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है। संबंधित वाणिज्य सचिवों की अध्यक्षता में व्यापार तथा पारगमन संबंधी अंतर–सरकारी समिति की 21–22 दिसंबर, 2013 तक काठमांडू में बैठक हुई।

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मित्रता और सहयोगी संबंध चाहता है, जिसके लिए आतंकवाद तथा हिंसा से मुक्त वातावरण की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि पाकिस्तान की सरकार अपने क्षेत्र तथा अपने नियंत्रण के तहत क्षेत्र का भारत के विरूद्ध आतंकवाद की सहायता के लिए प्रयोग करने से रोकने के कदम उठाए। भारत पाकिस्तान के साथ आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में शांतिपूर्वक द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी बकाया मुद्दों का हल करने के लिए वचनबद्ध है।

मई, 2013 के चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्राप्त मजबूत जनादेश के पश्चात् प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने बधाई पत्र में पाकिस्तान की नई सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय लिखने हेतु कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा भारत

तथा पाकिस्तान के बीच शांति, मित्रता और सहयोग द्वारा परिभाषित संबंधों के लिए सार्वजनिक रूप से दर्शाई गई वचनबद्धता का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री के विशेष दूत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को औपचारिक रूप से कार्य ग्रहण करने से पहले ही अपना संदेश देने हेतु पाकिस्तान की यात्रा की। भारत ने ऊर्जा, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए नई सरकार की इच्छा का सकारात्मक प्रत्युत्तर देने की इच्छा भी जताई।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 29 सितंबर, 2013 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। भारत के विरूद्ध लगातार जारी आतंकवाद के मुद्दे को उठाने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने मुम्बई हमले के सभी अपराधियों पर शीघ्र न्यायिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यापार तथा अर्थव्यवस्था और व्यापार के सामान्यीकरण हेतु भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्मत कदमों सहित संबंधों के अन्य पहलुओं पर भी विचार–विमर्श किया गया। बैठक से उभरने वाली मूल सोच यह थी कि सभी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास परिस्थिति को तत्काल हल किए जाने के साथ चह सभी संभव होगा। यह भी सहमति हुई कि डीजीएमओ को नियंत्रण रेखा पर शांति तथा प्रशांति को सुदृढ़ बनाने हेतु विचार–विमर्श करने के लिए बैठक करनी चाहिए। यह बैठक 24 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विशेष सलाहकार सरताज अजीज से 02 जुलाई, 2013 को ब्रूनेई में एशियाई समिट के दौरान तथा 13 सितंबर, 2013 को बिशकेक में शंघाई सहयोग संगठन, राज्यों के प्रमुख के सम्मेलन 2013 के दौरान मुलाकात की।

मार्च, 2011 तथा सितंबर, 2012 के बीच 8 मुद्दों को शामिल करते हुए वार्ता के दो दौर पुनः प्रारंभ किए गए। इस्लामाबाद में 20–21 सितंबर, 2012 को वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता के साथ तीसरी दौर की वार्ता पुनः आरंभ हुई। तथापि, पुनः आरंभ की गई वार्ता के तहत जनवरी, 2013 से आगे और वार्ता नहीं की जा सकी। तकनीकी/संचलानात्मक स्तर की बैठकें जारी रही और निजी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का भी आदान–प्रदान किया गया।

भारत ने मुम्बई आतंकवादी हमले के संबंध में इस्लामाबाद में चल रहे मुकदमे की प्रगति को पाकिस्तान की अपनी धरती से आतंकवाद दूर करने की वचनबद्धता के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखना जारी रखा। तथापि, जांच और मुकदमा काफी धीमी गति से चल रहा है। मुकदमे में स्थान में परिवर्तन के अलावा बार–बार स्थगन, वकीलों का उपस्थित न होना तथा अभियोजक वकीलों को अकसर बदल देनी जैसी बातें पाई गई हैं। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग की दूसरी यात्रा मुम्बई में 24–25 सितंबर, 2013 तक तब हुई जबकि 4 भारतीय अभियोजन गवाहों की प्रतिपृच्छा की गई थी। भारत ने बार–बार यह सूचित किया है कि चूंकि आतंकवादी हमले की आयोजना, प्रशिक्षण और निधियन पाकिस्तान में किया गया था, इसलिए 99 प्रतिशत साक्ष्य जो वहां उपलब्ध होने चाहिए, और शीघ्र मुकदमे के तथा सभी शामिल व्यक्तियों पर न्यायिक कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान में न्यायालय के समक्ष इन्हें रखा जाना चाहिए।

एक दूसरे के जेलों में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मानवीय मामलों पर विचार करने के लिए दोनों देशों की उच्च न्याय पालिका के सेवानिवृत्त न्यायधीशों को शामिल करते हुए कैदियों से संबंधित एक संयुक्त न्यायिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने 26–30 अप्रैल, 2013 तक कराची, रावलपिंडी तथ लाहौर में पाकिस्तानी जेलों की यात्रा की और 25–31 अक्तूबर, 2013 तक भारतीय जेलों की यात्रा की। इनकी सिफारिशों पर संबंधित सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है।

2012–13 औपचारिक रूप से आकलित भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (पाकिस्तान को भारत का निर्यात 1.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा पाकिस्तान से आयात 513 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था। भारत को पाकिस्तान का निर्यात इस अवधि के दौरान पहली बार 500 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। दोनों देशों के 15 सर्वोच्च स्तर के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा गठित 'संयुक्त व्यापार परिषद् (जेबीसी)' ने 29 जून, 2013 को इस्लामाबाद में पहली गोष्ठि की। जेबीसी ने कृषि, औषधि, ऑटोमोबाइल तथा स्वास्थ्य देखभाल में आर्थिक सहयोग के वरीय क्षेत्रों की जांच करने के लिए दस कार्य बलों का गठन किया हैय जेबीसी को अब संयुक्त व्यापार मंच के रूप में पुनः नामित किया गया है और इसकी दूसरी बैठक नई दिल्ली में 10–11 अक्तूबर, 2013 को आयोजित की गई। वाणिज्यिक आधार पर ऊर्जा तथा गैस निर्यात की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए ऊर्जा एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आगे विचार–विमर्श के लिए 10–11 जून, 2013 तक पाकिस्तान की यात्रा की।

5वें सार्क व्यापार नेता सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा श्री खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने सामान्य व्यापार संबंधों की शीघ्र स्थापना करने तथा इस संदर्भ में गैर–भेदभाव पूर्ण बाजार पहुंच (एनडीएमए) प्रदान करने की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने व्यापार के सामान्यीकरण, उदारीकरण तथा सरलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने और तेज करने तथा फरवरी, 2014 के अंत से पहले सहमत उपायों का कार्यान्वयन करने में तेजी लाने का निर्णय लिया। तथापि, पाकिस्तान सम्मत समय–सीमा पर सहमत नहीं हुआ।

नियंत्रण रेखा पार व्यापार और यात्रा से संबंधित भारत–पाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की एक बैठक नई दिल्ली में 4 मार्च, 2014 को आयोजित की गई जिसमें नियंत्रण रेखा पार व्यापार और यात्रा से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

5 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में ऊर्जा विषयक विशेषज्ञों के समूह की बैठक के दौरान तकनीकी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

श्रीलंका

प्रोफेसर जी.एल. पेइरिस, श्रीलंका के विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के विशेष दूत के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को उनकी ओर से श्रीलंका में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की 22वीं राजकीय बैठक (सीएचओजीएम) में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने हेतु 17–18 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से भी मुलाकात की। उन्होंने 28–29 जनवरी, 2014 तक भारत की पुनः यात्रा की तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।

श्रीलंका के तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) के छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16–19 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की।

आर्थिक विकास मंत्री, श्रीलंका सरकार, बासिल राजपक्षे ने 4–5 जुलाई, 2013 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

श्रीलंका में विपक्ष के नेता तथा यूएनपी के प्रमुख श्री रानिल विक्रमसिंघे ने 1–4 अप्रैल, 2013 तथा 18–21 अगस्त, 2013 तक दो बार भारत की यात्रा की तथा राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता से मुलाकात की और एनएसए के साथ भेंट की।

श्रीलंका के मत्स्य पालन और जलीय संसाधन विकास मंत्री श्री राजिथा सेनारत्ने ने हमारे कृषि मंत्री श्री शरद पवार के निमंत्रण पर 14–16 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से भी भेंट की। मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर वार्तालाप को सुकर बनाने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन करने पर सहमति हुई।

श्रीलंका के वाणिज्य मंत्री श्री रिशाद बथीउद्दीन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 5वें व्यापार नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16–18 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।

27 जनवरी, 2014 को चेन्नई में भारत तथा श्रीलंका के मत्स्य पालक संघों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी जिसमें वार्ता आरंभ करने से पहले मछली पालकों को रिहा करना सुनिश्चित किया गया था। भारत सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने भी पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 7–8 अक्तूबर, 2013 तक श्रीलंका की यात्रा की। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे के साथ मुलाकात की और अपने समकक्ष प्रोफेसर जी.एल. पेइरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यात्रा के दौरान सामपुर कोयला ऊर्जा परियोजना ख्नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और सिलोन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच एक संयुक्त उद्यम, से संबंधित करारों और त्रिभाषी श्रीलंका के लिए राष्ट्रीय योजना हेतु भारत द्वारा तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने जाफना की यात्रा की और उत्तरी प्रांतीय परिषद् के नए मुख्यमंत्री सी.वी. विंगनेश्वरन के साथ वार्ता की। उन्होंने भारतीय हाउसिंग परियोजना के लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र सौंपने और क्षतिग्रस्त व्यापार परिसरों के नवीकरण की परियोजना बैठक में भी भाग लिया।

ईएएम ने 13–17 नवंबर, 2013 तक श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रमुखों की 22वीं राजकीय बैठक (सीएचओजीएम) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के नेताओं और अन्य सम्मानित व्यक्तियों के साथ मुलाकात की।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा संबंधी सहयोग के संबंध में त्रिपक्षीय पहल से संबंधित एनएसए स्तरीय दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 8–9 जुलाई, 2013 को कोलंबो की यात्रा की। यात्रा के दौरान तीनों पक्ष समुद्री सुरक्षा में आगे और सहयोग के लिए एक योजना बनाने पर सहमत हुए और उन्होंने एक परिणाम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। त्रिपक्षीय पहल से संबंधित एनएसए स्तरीय तीसरी बैठक नई दिल्ली में 6 मार्च, 2014 को आयोजित की गई। श्रीलंका का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव श्री गोटबया राजपक्षे और मालदीव का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री मोहम्मद नजीम द्वारा किया गया। सेशेल्स तथा मॉरीशस के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

वाणिज्य सचिव श्री एस.आर. राव ने द्विपक्षीय वाणिज्य सचिवीय स्तर की वार्ता हेतु 24–26 जून, 2013 तक श्रीलंका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारतीय निवेश को सुकर बनाते हुए श्रीलंका की निर्यात क्षमता में वृद्धि करने के तौर–तरीके पर विचार करने के लिए संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई। श्रीलंका के ट्रेजरी सचिव पी.बी. जयसुन्दरा ने वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता के अगले दौर के लिए 23–24 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की।

थल सेना अध्यक्ष (सीएनएस), एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी ने गाले वार्ता समुद्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24–29 नवंबर, 2013 तक श्रीलंका की यात्रा की। सीएनएस ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की और श्रीलंका के विदेश मंत्री, प्रोफेसर जी. एल. पेइरिस तथा रक्षा सचिव श्री गोटबया राजपक्षे से भेंट की।

2009 से भारत सरकार ने आवासन, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन उद्योग, हस्तशिल्प, संस्कृति और खेलों सहित श्रीलंका के तमिल समुदाय को लक्षित करते हुए श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते में विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। सरकार क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि करने के अलावा संघर्ष–प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार तथा निवेश हेतु संभावनाओं के सृजन के लिए सटीक प्रयासों में भी शामिल है। ऋण तथा अनुदान सहित द्विपक्षीय सहायता की कुल मात्रा लगभग 8000 करोड़ रुपए है।

श्रीलंका भारत सरकार द्वारा विस्तारित विकास क्रेडिट के मुख्य प्राप्कर्ताओं में से एक है। वर्तमान में भारत सरकार श्रीलंका में उत्तरी रेल पुनः निर्माण परियोजना के लिए श्रीलंका की सरकार को लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की रियायती ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। यह सुनामी से क्षतिग्रस्त कोलंबो–मतारा रेल लिंक (कालूतारा–गाले–मतारा के बीच चलने वाला रेलमार्ग), जिसे पिछले वर्ष समय से पहले ही पूरा कर लिया गया था, की मरम्मत और उन्नयन के लिए 167.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त है।

कुछ महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं में शामिल हैं, 50,000 घरों का निर्माण (उत्तरी, पूर्वी, केंद्रीय तथा युवा प्रांत), डिकोया में 150 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण, समपुर में एक कोयला ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, जाफना में दुरिअप्पा स्टेडियम का नवीकरण, अटचूवेली औद्योगिक क्षेत्र को पुनः सक्रिय बनाना, उत्तरी प्रांत में स्कूलों की मरम्मत के लिए सहायता तथा उत्तरी प्रांत में मुख्य रेल मार्ग की पुनः स्थापना।

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने कांकेसंतुरई हार्बर में निकर्षण, जाफना में फिशनेट फैक्ट्री नॉर्थसी लिमिटेड को संयंत्र एवं मशीनरी का दान तथा मेदावचचिया–मधू रोड (43 किमी) तथा ओमानथाई–किलीनोचाची (63 किमी) के बीच रेल ट्रेक का पुनः निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की।

भारत और श्रीलंका ने पिछले दशक में तेजी से बढ़ने वाले द्विपक्षीय व्यापार और कई प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा श्रीलंका में निवेश और उपस्थिति स्थापित करने के साथ घनिष्ठ व्यापार और निवेश संबंध स्थापित किए हैं। अब श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारों में से एक है, जबकि भारत श्रीलंका का विश्व में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2000 में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तेजी से बढ़कर द्विपक्षीय एफटीए लागू होने के पश्चात् 2013 में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

जहां तक श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यटकों का प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा स्रोत देश है। आज भारत श्रीलंका में सर्वोच्च दो निवेशकों में से एक है, जिसका संचयी निवेश 2003 से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

शिक्षा भारत तथा श्रीलंका के बीच सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब भारत श्रीलंका के योग्य छात्रों को वार्षिक रूप से लगभग 300 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग योजना और कोलंबो योजना के अंतर्गत भारत विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में लघु एवं मध्यम अवधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए श्रीलंका के नागरिकों को वार्षिक रूप से लगभग 200 स्लॉट प्रदान करता है।

■■

2 दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत

आस्ट्रेलिया

2013–14 में आस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों में अत्यधिक विस्तार जारी रहा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा आस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री श्री टोनी एबोर्ट के बीच 11वें आसियान–भारत और 8वें ईएएस शिकर सम्मेलन के दौरान 10 अक्तूबर, 2013 को ब्रूनेई में हुई पहली बैठक के साथ नीतिगत भागीदारी और गहन हुई।

श्री टोनी एबोर्ट ने संसद के निचले सदन के फेडरल चुनावों में लिबरल/राष्ट्रीय गठबंधन की निर्णायक जीत के पश्चात् 18 सितंबर, 2013 को आस्ट्रेलिया के 28वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लिबरल दल ने भारत के तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य तथा भारत तथा उसकी अर्थव्यवस्था के महत्व को मान्यता देते हुए आस्ट्रेलिया के स्वयं के भविष्य हेतु राजनैतिक और आर्थिक दोनों रूप से भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने की गहन इच्छा व्यक्त की।

विदेश मंत्री सलमान खर्शीद ने सुश्री जूली बिशप, आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री के साथ 9वीं विदेश मंत्री ढांचा वार्ता (एफएमएफडी) के लिए पर्थ, आस्ट्रेलिया में 31 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा क्षेत्रीय और बहु–पक्षीय मुद्दों सहित नीतिगत भागीदारी को सुदृढ़ बनाने पर जोड़ दिया। सुश्री बिशप ने 16–18 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया और वित्त मंत्री, एनएसए तथा आरबीआई के गवर्नर के साथ मुलाकात की। उन्होंने न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के लिए आस्ट्रेलिया के समर्थन की घोषणा की तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय के निधियन के संबंध में सीमा–शुल्क सहयोग और विषयक समझौता ज्ञापन में संशोधन और आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री की 4–5 जून, 2013 तक यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा आस्ट्रेलिया की पहली राजकीय यात्रा थी। रक्षा मंत्री ने श्री स्टीफन स्मिथ, आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ गहन वार्ता की। रक्षा मंत्रियों के बीच नियमित वार्ता जारी रखने और 2015 में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास करने पर सहमति हुई। यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। जनरल विक्रम सिंह, थल सेना अध्यक्ष ने 2–7 सितंबर, 2013 तक सिडनी तथा केनबेरा की यात्रा की तथा अपने समकक्ष और रक्षा सचिव के साथ विचार–विमर्श किया। अपर सचिव (रक्षा मंत्रालय) स्तर पर रक्षा नीति वार्ता का तीसरा दौर और आईडीएसए स्तर पर ट्रेक 1.5 रक्षा और सुरक्षा वार्ता का दूसरा दौर नई दिल्ली में क्रमशः 4 अक्तूबर, 2013 तथा 17 अक्तूबर, 2013 को आयोजित किया गया। आईएनएस सयादरी ने 3–11 अक्तूबर, 2013 के दौरान सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा में भाग लिया।

श्री वायालर रवि, आप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने सिडनी में 10–12 नवंबर, 2013 को आयोजित क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन में भाग लिया। जनवरी, 2014 में नई दिल्ली में वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान आस्ट्रेलिया के सिनेटर लीसा सिंह को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया।

डॉ. एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री ने केनबेरा में 9–12 जुलाई, 2013 तक वार्षिक शिक्षा मंत्री वार्ता में भाग लिया। इस अवसर पर दूसरा आस्ट्रेलिया–भारत कुलपति सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए कोयला तथा लौह अयस्क के आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श हेतु 26–29 जनवरी, 2014 तक आस्ट्रेलिया की यात्रा की।

डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने आस्ट्रेलिया में 31 मार्च, 2014 को ऊर्जा सुरक्षा वार्ता में भाग लिया और द्विमार्गी व्यापार तथा निवेश, वैश्विक एवं क्षेत्रीय ऊर्जा और संसाधन अभिशासन, गैस के मूल्य निर्धारण तथा गैस के बाजारों, ऊर्जा की दक्षता एवं सक्षमता तथा विद्युत बाजार में सुधार पर विचार–विमर्श किया।

श्री सचिन पायलट, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 3–8 जून, 2013 तक आस्ट्रेलिया की यात्रा की। यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे दोनों देशों के

प्रतिस्पर्धी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने में वृद्धि में सहयोग हेतु अवसंरचना की स्थापना की गई।

श्री अशोक कांता, सचिव (पूर्वी), विदेश मंत्रालय ने 9 अगस्त, 2013 को केनबेरा में श्री पीटरवर्गीस, सचिव, आस्ट्रेलिया विदेश एवं व्यापार विभाग के साथ वरिष्ठ आधिकारिक वार्ता की।

श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्वी), विदेश मंत्रालय ने लोवई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी एंड ओवजर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित आस्ट्रेलिया–भारत गोलमेज वार्ता के लिए 3–7 फरवरी, 2014 तक सिडनी, केनबेरा और मेलबर्न की यात्रा की।

श्री आर.एच. ख्वाजा, सचिव, खान मंत्रालय ने 21–25 अक्तूबर, 2013 तक पर्थ, पश्चिमी आस्ट्रेलिया में एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के खान एवं पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की तथा व्यापार समूहों के साथ फील्ड विजिट की और संपर्क बनाए।

सिविल न्यूक्लियर सहयोग संबंधी वार्ता का चौथा दौर तथा निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार प्रारंभिक वार्ता 10–12 फरवरी, 2014 तक केनबेरा में आयोजित की गई इसके पूर्व वार्ताओं का तीसरा दौर नई दिल्ली में 26–27 नवंबर, 2013 तक आयोजित किया गया तथा 19 मार्च, 2013 तक नई दिल्ली में वार्ता आरंभ होने के पश्चात् 29–30 जुलाई, 2013 को केनबेरा में दूसरा दौर आयोजित किया गया।

व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) का 5वां दौर मई, 2013 में केनबेरा में आयोजित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर लाभकारी तथा औचित्यपूर्ण करार आवश्यकता को स्पष्ट किया। जल संसाधन प्रबंधन संबंधी जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 29 अप्रैल तथा 3 मई, 2013 के बीच ब्राह्मणी–बेतरनी नदी के जल संसाधन प्रबंधन की तैयारी पर विचार–विमर्श करने के लिए आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। ऊर्जा एवं खनिज संबंधी जेडब्ल्यूजी की आठवीं बैठक नई दिल्ली में 11–12 जून, 2013 को आयोजित की गई जिसमें 2013–15 के लिए कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत सहयोग पर सहमति हुई। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक केनबेरा में 25 नवंबर, 2013 को आयोजित की गई जिसमें द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईडब्ल्यूसीए) ने 19–20 सितंबर, 2013 तक नई दिल्ली में हिन्द महासागर से संबंधित भारत–आस्ट्रेलिया–इंडोनेशिया की प्रारंभिक त्रिपक्षीय वार्ता की मेजवानी की। महानिदेशक आईसीडब्ल्यूए ने 16–23 मार्च, 2014 तक मेलबर्न तथा केनबेरा की यात्रा की और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर ट्रेक–प्प विचार–विमर्श करने के लिए आस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान (एआईआईए) तथा आस्ट्रेलिया नीति संस्थान (एएसपीआई) के साथ विचार–विमर्श किया।

ब्रूनेई में 8वें ईएएस समिट के दौरान आस्ट्रेलिया सहित सात देशों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; आस्ट्रेलिया पर्यावरण के संबंध एक पीठ की स्थापना करने में मदद करेगा।

एयर इंडिया ने लगभग 14 वर्षों के अंतराल के पश्चात् 30 अगस्त, 2013 की सुबह सिडनी में उद्घाटन फ्लाइट लैंड करते हुए सिडनी तथा मेलबर्न को दैनिक सीधी फ्लाइट का प्रारंभ किया।

ब्रूनेई दारूसलाम

इस वर्ष अधिक संपर्क और आदान–प्रदान हुए क्योंकि ब्रुनेई 2013 में एशियाई पीठ और भारत–एशियाई समन्वयक–पीठ का भी धारक था।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 11वीं एशिया–भारत और 8वें पूर्वी एशिया शिखर–सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9–10 अक्तूबर, 2013 तक ब्रुनेई की यात्रा की। यात्रा के दौरान कई ईएएस सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने एशियाई–भारत मंत्रालयी–सम्मेलन, 20वें एशियाई क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और तीसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित (ईएएस) विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 29 जून से 2 जुलाई, 2013 तक ब्रूनेई की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के समकक्षों के साथ 12 द्विपक्षीय बैठकें आयोजित कीं और प्रिंस मोहम्मद बोलकिया, ब्रूनेई के विदेश तथा व्यापार मंत्री से मुलाकात की। श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 17–21 अगस्त, 2013 तक ब्रुनेई में आयोजित 11वें एशियाई आर्थिक मंत्रियों की बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री जितेन्द्र सिंह, रक्षा राज्य मंत्री एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री ने ब्रुनेई दूसरी एशियाई रक्षा मंत्री प्लस की दूसरी बैठक (एडीएमएम+) में 28–29 अगस्त, 2013 तक भाग लिया। कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने ब्रुनेई में आयोजित आरसीईपी से संबंधित बैठकों सहित ब्रुनेई की यात्रा की।

दातो रहमान इब्राहिम, एडीबी ब्रुनेई दारूसलम के गवर्नर ने एडीबी गवर्नर बोर्ड की 46वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 2–5 मई, 2013 तक नई दिल्ली की यात्रा की। दातो अली अपोंग, ब्रुनेई आर्थिक विकास के अध्यक्ष और उप मंत्री ने ब्रुनेई में निर्माण हेतु भारतीय औषधीय कंपनियों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 2–5 सितंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

आईएनएस घड़ियाल, ने भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल टुकड़ी के साथ एशियन प्लस (एडीएमएम+) मानवीय सहायता तथा आपदा राहत और चिकित्सा अभ्यास (एचएडीआर एवं एमएम अभ्यास) में 10–22 जून, 2013 तक ब्रुनेई में भाग लिया। वाइस

एडमिरल अनिल चौपड़ा, एफओसी, पूर्वी नेवल कमांड ने इस संबंध में ब्रुनेई की यात्रा की। ब्रुनेई से एक नेवल शिप ने 3–9 फरवरी, 2014 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित मिलन–2014 में भाग लिया।

कम्बोडिया

कम्बोडिया तथा भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध अत्यधिक घनिष्ठ एवं मित्रवत रहे तथा इनमें 2013 में वृद्धि जारी रही।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डोनियर) श्री पबन सिंह घाटोवार ने 11–14 जून, 2013 को कम्बोडिया में एक मंत्रालयी–सह–व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

वर्ष के दौरान नेवल शिप आईएनएस सुदर्शनी की यात्रा, भारतीय विशेषज्ञों द्वारा शांति और बारूदी सुरंगों को हटाने में रॉयल कम्बोडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए प्रशिक्षण तथा आर्मी वार कॉलेज, महोव के उच्च कमांड पाठ्यक्रम से एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे रक्षा सहयोग सघन हुए।

भारत और कम्बोडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी भाषा तथा उद्यमशीलता हेतु संस्थाओं की स्थापना सहित कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा ट्रांसमिशन, क्षमता निर्माण से संबद्ध कई परियोजनाओं के माध्यम से विकास भागीदारी को सुदृढ़ किया। श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव (विकास भागीदारी प्रशासन), विदेश मंत्रालय ने नई परियोजनाओं की स्थापना का पता लगाने और चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए 8–10 मई, 2013 तक कम्बोडिया की यात्रा की। सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने से इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि हुई तथा एएसआई ने सीम रीप में ता प्रोम मंदिर परिसर की मरम्मत परियोजना तथा एमजीसी एशियाई पारंपरिक वस्त्र म्यूजियम, सीम रीप को आरंभ करने पर कार्य करना जारी रखा। श्रीमती संगीता गेरोला, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने कम्बोडिया में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में भाग लेने के लिए 16–27 जून, 2013 तक कम्बोडिया में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत ने 28 जुलाई, 2013 को कम्बोडिया की राष्ट्रीय असेम्बली के आम चुनाव के लिए कम्बोडिया को लगभग 900,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की अमिट स्याही की 40,000 बोतले दान की। श्री आशुतोष जिंदल, मुख्य चुनाव अधिकारी, त्रिपुरा ने पर्यवेक्षक के रूप में कम्बोडिया की यात्रा की।

13–18 फरवरी, 2014 को नोम पेन्ह तथा सीम रीप में भारतीय उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन श्री मिन किन, कम्बोडिया के संस्कृति एवं धर्म मंत्री तथा श्री रविन्द्र सिंह, सचिव (संस्कृति) द्वारा किया गया।

फिजी

भारत–फिजी द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण रहे और 2013 के दौरान यात्राओं के आदान–प्रदान के जरिए इसमें काफी प्रगति की गई।

रातू इनोक कुबुआबोला, विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री ने 9–12 फरवरी, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की तथा विदेश मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। यात्रा के दौरान विकास सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग तथा मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने श्री तारिक अनवर, कृषि राज्य मंत्री के साथ मुलाकात की। फिजी के विदेश मंत्री ने आईसीडब्ल्यूए में ''2007 के बार से फिजी में विकास'' संबंधी एक व्याख्यान भी दिया। सचिव स्तर पर एफओसी, जिसमें दोनों देशों के बीच संपर्क के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया था, का 11 फरवरी, 2014 को आयोजन किया गया।

श्री ऐय्याज सईद–खइयूम, अटॉर्नी जनरल तथा न्याय मंत्री ने बैंगलुरु में सीआईआई भागीदारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27–29 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने दिल्ली की यात्रा की तथा वित्त मंत्री के साथ 30 जनवरी, 2014 को दोहरे कर बचाव करार (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए।

फिजी के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नील शर्मा ने अस्पताल सुविधाओं का अध्ययन करने तथा फिजी में एक आंकलोजिकल इकाई की स्थापना के उपकरण के प्रापण का पता लगाने के लिए 31 मई, 2013 को भारत की यात्रा की और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। कृषि मंत्री श्री इनिया सेरूइरातू ने 12–15 अक्तूबर, 2013 तक भारत की यात्रा की तथा कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि संस्थान की यात्रा की।

संयुक्त सचिव (दक्षिण), विदेश मंत्रालय, संजय भट्टाचार्य ने 11–12 अप्रैल, 2013 को फिजी की यात्रा की और विदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, अटॉर्नी जनरल, और फिजी के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय को भी संबोधित किया और पेशेफिक आईलैंड फोरम से मुलाकात की। श्री सुधीर कुमार, सचिव (एफएंडपीडी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नाडी में 3–6 जून, 2013 को आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् के 43वें सत्र में भाग लिया। श्री रंगलाल जमूरा, अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने नाडी में 29–31 अक्तूबर, 2013 तक एशियाई उत्पादकता संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उत्पादकता संगठन के प्रमुखों की 54वीं कार्यशाला में भाग लिया। श्री बी.बी. गुप्ता, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद कर तथा मादक द्रव्य अकादमी, फरीदाबाद ने आरटीसी, सुआ में 5–6 नवंबर, 2013 तक 11वीं एशिया प्रशांत विश्व सीमा–शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

दो समूहों तथा जहाज यमुना और नालंदा में वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के 36 सदस्यीय दल ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की स्थापना के लिए प्रशांत क्षेत्र में पर्यवेक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु

अक्तूबर–नवंबर, 2013 में सुवा की यात्रा की।

सामाजिक–आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए प्रत्येक पीआईएफ देश को सहायता अनुदान के रूप में भारत की वार्षिक सहायता पहल के अंतर्गत भारत सरकार सुवा शहर कार्नेजी सचल पुस्तकालय के लिए सचल पुस्कालय वाहन तथा 300 सिलाई मशीनों की खरीद के लिए निधिया प्रदान करती है। फिजी चीनी निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत द्वारा जुलाई, 2005 में 3 चीनी मिलों– लाटोका, रारावाई और लबासा के उन्नयन हेतु प्रदत्त 50.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत उपकरण की आपूर्ति की प्रगति पर विचार–विमर्श करने के लिए 2–5 सितंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

फिजी के सामाजिक कल्याण, महिला एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री, डॉ. जीको लुवेनी ने समुदायों में सौर ऊर्जा अपनाने संबंधी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 24–25 अप्रैल, 2013 तक सुवा में राष्ट्रीय सौर ग्रांड मदर कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसमें दस उम्रदराज महिलाओं को पिछले वर्ष आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया, राजस्थान में प्रशिक्षित किया गया था।

अपोलो अस्पताल ने फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहयोग तथा एक टेलीमेडीसिन/सचल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अप्रैल, 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिजी मेडीसिन स्कूल, एफएनयू में टेलीमेडीसिन केंद्र का अगस्त, 2013 में आरंभ किया गया जिससे कि भारत में अपोलो के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा वास्तविक–समय निदान प्रदान किया जा सके।

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ने गिरमिट अराइवल डे तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की 134वीं वर्षगांठ सहित कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली में जनवरी, 2014 में प्रवासी भारतीय सम्मान फिजी में रामकृष्ण मिशन को प्रदान किया गया।

इंडोनेशिया

भारत–इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध में उच्च स्तरीय यात्राएं और रणनीतिक भागीदारी को समेकित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम उल्लेखनीय रहे।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10–12 अक्तूबर, 2013 तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा की जो कि राष्ट्रपति सुशीलो बेनबेंग यूधोयोनो के निमंत्रण पर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उनके साथ विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी थे। विदेश मंत्री ने 11 अक्तूबर, 2013 तक एक द्विपक्षीय बैठक में विदेश मंत्री आर मार्टी नाटालेगावा से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग तथा परस्पर हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जिसके पश्चात् लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और राष्ट्रीय जन प्रशासन संस्थान, इंडोनेशिया और आईसीडब्ल्यूए तथा इंडोनेशिया विश्व कार्य परिषद् के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने स्वास्थ्य देखभाल, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार का मुकाबला और मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के प्रयासों में वृद्धि करने के उद्देश्य से चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किए और भारत–इंडोनेशिया रणनीतिक भागीदारी पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों देशों के व्यापार अग्रणियों के साथ भारत–इंडोनेशिया सीईओ फोरम का आयोजन किया गया।

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 3–7 दिसंबर, 2013 को बाली, इंडोनेशिया में डब्ल्यूटीओ के 9वें मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य राष्ट्रों के 159 मंत्रियों ने भी भाग लिया। सप्ताह भर की वार्ता के पश्चात् मंत्रियों ने ''बाली पैकेज'' अंगीकार जो भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय करार है।

श्री रीजल अफांडी लुकमान, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग उप मंत्री तथा आर्थिक कार्य समन्वयन मंत्री ने 26–29 जनवरी, 2014 तक बंगलुरु में सीआईआई भागीदारी सम्मेलन में भाग लिया।

भारत तथा इंडोनेशिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों (एफओसी) की पहली बैठक बाली, इंडोनेशिया में 17 जून, 2013 को आयोजित की गई।

भारत के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बाली में 26–27 मार्च, 2013 तक कृषि संबंधी भारत–इंडोनेशिया जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक के लिए इंडोनेशिया की यात्रा की।

भारत तथा इंडोनेशिया के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक अपर सचिव स्तर पर 6–7 जून, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

जकार्ता में भारतीय दूतावास में अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, सीआईआई तथा आप्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (ओआईएफसी) के साथ 16 जुलाई, 2013 को मेडान में तथा 18 जुलाई, 2013 को जकार्ता में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया।

लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लांगर की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 20–21 मार्च, 2013 तक तीसरी जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय रक्षा वार्ता (जेआईडीडी) में भाग लिया। वाइस एडमिरल आर.के. पटनायक ने 19 मार्च, 2014 को जकार्ता में चौथी जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय वार्ता (जेआईडीडी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मलाका/अंडमान समुद्र में 6–26 मई, 2013 तक 21वीं भारत–इंडोनेशिया समन्वित पेट्रोलिंग का आयोजन किया गया।

सहकारी तंत्र के समेकन के लिए 27–29 अगस्त, 2013 तक जकार्ता में 6ठीं जल सेना से जल सेना वार्ता आयोजित की गई।

बाली में 11–14 फरवरी, 2014 तक तीसरी थल सेना से थल सेना वार्ता आयोजित की गई। इंडोनेशिया के एक नेवल शिप ने 3–9 फरवरी, 2014 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित मिलन–2014 में भाग लिया। फिक्की की अध्यक्ष सुश्री नैना लाल किदवई के नेतृत्व में एक 24 सदस्यीय सीईओ प्रतिनिधिमंडल ने बैंकिंग, आईटी, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खनन, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 25–27 अगस्त, 2013 तक जकार्ता की यात्रा की।

शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री कमलनाथ के नेतृत्व में तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 11–17 अप्रैल, 2013 तक इंडोनेशिया की यात्रा की। बिहार तथा राजस्थान के स्पीकर, श्री सुतानू बेहूरिया, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र संसद सदस्यों तथा एमडीजी त्वरण सीएसओ मंच और पोस्ट–2015 विकास एजेंडा के लिए 25–26 मार्च, 2013 तक बाली की यात्रा की।

मारी एल्का पंगेस्तू इंडोनेशिया पर्यटन एवं सृजनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्री ने 1 अप्रैल, 2013 को भारत की यात्रा की तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भेंट की तथा विकासशील देशों के लिए शोध एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) तथा फिक्की से भी मुलाकात की। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विकास आयोजना मंत्री तथा राष्ट्रीय विकास आयोजना एजेंसी के प्रमुख (बीएपीपीईएनएएस) डॉ. अर्मिडा एस. अलिसजाहवाना ने 2–5 मई, 2013 तक एडीबी वार्षिक बैठक के लिए भारत की यात्रा की। श्री ई गुस्ती अगुंग वेसाका पूजा, विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ने 19–20 फरवरी, 2013 तक दिल्ली वार्ता में भाग लिया।

मलिंडो एयर, लायन समूह की एक इकाई ने 30 दिसंबर, 2013 से क्वालालंपुर होते हुए जकार्ता से दिल्ली तक फ्लाइट आरंभ की। इससे जेट एयरवेज–गरुड़ वाया सिंगापुर की कोड शेयरिंग फ्लाइट में सहायता मिली।

लाओ पीडीआर

इस अवधि के दौरान लाओ पीडीआर के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ होते रहे।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने अपने समकक्ष डॉ. थोंगलोन सिसोलिथ, उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर 7वें लाओ–भारत संयुक्त मिशन की सह–अध्यक्षता करने के लिए 8–10 सितंबर, 2013 को विएनटिआन तथा लुआंग प्राबांग की यात्रा की। दोनों पक्ष एशियाई तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति चौम्माली सायासोन और श्री थोंगसिंग थामावोंग, लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 10 सितंबर, 2013 को विएनटिआन में आयोजित के एशिया–भारत थिंक–टैंक के नेटवर्क की दूसरी गोलमेज का भी उद्घाटन किया।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 30.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो ऋण श्रृंखला ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार द्वारा नाम बोन–2 हाइड्रो पावर प्लांट को प्रतिस्थापित करने हेतु 35.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की एक अन्य ऋण श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए गए।

डॉ. थोंगलोन सिसोलिथ, लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री ने 11–12 नवंबर, 2013 तक गुड़गांव, एनसीआर में एएसईएम–एफएमएम 11 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

डॉ. बोनथेवी सिसोपांथोंग, उप मंत्री, योजना एवं निवेश मंत्रालय, लाओ के नेतृत्व में लाओ के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 21–22 अक्तूबर को आयोजित ''नई आर्थिक संभावनाओं का सृजन'' शीर्षक के साथ कंबोडिया, लाओ, म्यांमा और वियतनाम (सीएलएमवी) संबंधी पहले सीआईआई व्यापार कन्क्लेव में भाग लिया।

9–11 फरवरी, 2014 को लाओ में भारतीय उत्सव का आयोजन किया गया और प्रोफेसर डॉ. बोसेंगखाम वोंगडारा, लाओ के सूचना, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा डॉ. रविन्द्र सिंह, सचिव (संस्कृति) द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

मलेशिया

वर्ष के दौरान पारंपरिक मित्रता और सौहार्द के साथ मलेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंध सभी प्रमुख क्षेत्रों में स्थिर और सुचारू रूप से सुदृढ़ हो रहा।

श्री के. रोसैया, तमिलनाडु के गवर्नर ने विश्व तेलुगु परिसंघ के 10वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12–13 अप्रैल, 2013 तक मलेशिया की यात्रा की। प्रोफेसर पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष राज्य सभा ने ''तीसरे विश्व महिला संसद सदस्य सम्मेलन मंचः महिला तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा अधिकारों की वृद्धि से संबंधित सफलता, चुनौतियां, बाधाएं'' में भाग लेने के लिए 28 मई, 2013 को मलेशिया की यात्रा की और दिवान नेगारा (उच्च सदन) के अध्यक्ष तान श्री अबु जहर बिन दातो, निका उजांग से भेंट की। श्री शरद पवार, केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कृषि एवं वन संबंधी तीसरी एशिया–भारत मंत्रालयी बैठक (तीसरी एआईएमएमएएफ) में भाग लेने के लिए 27–29 सितंबर, 2013 तक मलेशिया की यात्रा की। श्री के. रहमान खान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय, मलेशिया (आईआईयूएम) में इंटरफेथ सद्भावना और सहनशीलता संबंधी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार में प्रमुख वासन देने हेतु 3–5 फरवरी, 2014 तक मलेशिया की यात्रा की।

जी पलानीवेल, मलेशिया के प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्री

तथा मलेशिया भारत कांग्रेस (एमआईसी) के अध्यक्ष नई दिल्ली में 7–9 जनवरी, 2014 तक आयोजित 12वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।

तान श्री पांडीकर अमीन मुलिया, मलेशिया की दीवान रकयात (प्रतिनिधि सदन दृ निचले सदन) के स्पीकर ने 29–30 जुलाई, 2013 को भारत की यात्रा की तथा द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए श्रीमती मीरा कुमार, स्पीकर लोकसभा के साथ मुलाकात की। दातो श्री मुस्तपा मोहम्मद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री ने 27–28 जनवरी, 2014 तक ''सीआईआई भागीदारी– समिट'' में भाग लेने के लिए बंगलुरू में मलेशिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने सितंबर, 2013 में मलेशिया की यात्रा की। कई भारतीय नेवल जहाज मलय पोर्ट पहुंचे, जबकि पूर्वी बेड़े से चार भारतीय नेवल जहाजों का समूह (आईएनएस शक्ति, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस रणविजय और आईएनएस किर्च) पोर्ट केलांग में पहुंचे तथा जून, 2013 में ओएसडी–2013 में भाग लिया। 19–22 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं मलेशिया भारतीय रक्षा सहयोग समिति (एमआईडीसीओएम) के साथ नियमित तौर पर द्विपक्षीय रक्षा वार्ता की जा रही थी; जून, 2013 में नई दिल्ली में 5वें आईएन–आरएमएन जल सेना वार्ता भी आयोजित की गई; तथा अक्तूबर, 2013 में नई दिल्ली में थल सेना से थल सेना के बीच वार्ता आयोजित की गई। मलेशिया से एक नेवल जहाज ने 3–9 फरवरी, 2014 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित मिलन–2014 में भाग लिया।

सीमा शुल्क मामलों पर सहयोग और परस्पर सहायता के लिए सुश्री प्रवीण महाजन, अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड और दातो श्री खजाली बिन हज अहमद, सीमा शुल्क महानिदेशक, मलेशिया की रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क द्वारा नई दिल्ली में 13 जून, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लोक प्रशासन तथा अभिशासन के क्षेत्र में भारत तथा मलेशिया के बीच हमारे कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय तथा मलेशिया में इसके समकक्ष संगठन द्वारा 25 नवंबर, 2013 को क्वालालंपुर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री नीलांजन सान्याल सचिव, आयुष विभाग ने पारंपरिक औषधि प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग संबंधी दूसरी द्विपक्षीय तकनीकी बैठकों के लिए 26–28 मार्च, 2014 तक मलेशिया की यात्रा की। श्री के.वी. एल. नरसिम्हम, एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक ने भारत से नब्बे अंग्रेजी भाषा अध्यापकों की भर्ती पर विचार–विमर्श करने के लिए 13–17 मार्च, 2014 तक मलेशिया की यात्रा की तथा श्री पी. कमलनाथन, मलेशिया के उप शिक्षा मंत्री से मुलाकात की।

भारत ने अंडमान समुद्र में पांच नेवल तथा तटीय रक्षा जहाजों और दो डोरनियर एयरक्राफ्ट तथा एक एमआई–17 हेलीकॉप्टर को नियोजित किया तथा तदंतर मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट एमएच–370 एसएआर जो 8 मार्च, 2014 को लापता हो गई थी, का पता लगाने के लिए बहु राष्ट्रीय मिशन के भाग के रूप में भारतीय समुद्र में एक पी–8आई और एक सी–130 एयरक्राफ्ट को नियोजित किया। फ्लाइट में 5 भारतीय थे।

न्यूजीलैंड

श्री मूरे मेककुली, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने 4 जून, 2013 को भारत की यात्रा की तथा परस्पर हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र मंत्री, खल मंत्री और एनएसए के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

डॉ. एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 8–9 जुलाई, 2013 को वेलिंग्टन में भारत–न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् (आईएनजेडईसी) की दूसरी बैठक के लिए नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने 29 जनवरी से 1 फरवरी, 2014 तक न्यूजीलैंड की यात्रा की और श्री साइमन ब्रिजिज, ऊर्जा एवं संसाधन मंत्री से मुलाकात की तथा भारत–न्यूजीलैंड व्यापार परिषद् और राज्य क्षेत्र की कंपनी सॉलिड एनर्जी के साथ संपर्क किया।

प्रोफेसर पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 21–24 जनवरी, 2014 तक वेलिंग्टन में आयोजित राष्ट्रमंडल के स्पीकरों तथा पीठासीन अधिकारियों (सीएसपीओसी) के 22वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह, थल सेना उपाध्यक्ष ने ऑकलैंड में आयोजित ''जोड़ना बांटने से बड़ा है दृ संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में 21वीं सदी में शांति अभियान'' शीर्षक के 8वें द्विवार्षिक प्रशांत थल सेना अध्यक्षों के सम्मेलन (पीएसीसी–टप्प्) में भाग लेने के लिए 8–13 सितंबर, 2013 तक न्यूजीलैंड की यात्रा की।

चौथी भारत–न्यूजीलैंड आर्थिक नीति वार्ता 15–16 अप्रैल, 2013 को वेलिंग्टन में आयोजित की गई। भारत–न्यूजीलैंड सीईसीए वार्ता का नौवां दौर 29–30 जुलाई, 2013 को वेलिंग्टन में आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 नवंबर, 2013 को ''न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक के साथ विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षकों से पर्यवेक्षण सहयोग'' संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 5–8 नवंबर, 2013 को रोटोरुआ, न्यूजीलैंड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के 25वें एशिया प्रशांत वन आयोग सत्र में भाग लिया।

पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी)

श्री विलियम दुमा, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्री ने एक 8 सदस्यीय

प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ मुलाकात की, पेट्रोनेट के दाहेज टर्मिनल तथा मुम्बई हाई में ओएनजीसी की यात्रा की तथा 2 अप्रैल, 2013 को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रणीत कौर से शिष्टाचार मुलाकात की।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा पीएनजी मंत्री की यात्रा के अनुसरण में पेट्रोनेट/ओवीएल ने पीएनजी में दो प्रतिनिधिमंडल भेजे जिसने राज्य के स्वामित्व वाले पेट्रोमिन एलएनजी होल्डिंग्स लिमिटेड तथा एलएनजी क्षेत्र में विभिन्न अन्य पणधारियों के साथ गहन विचार–विमर्श किए। प्रस्तावित खाड़ी एलएनजी परियोजना से 22.5 प्रतिशत गैस निकालने के लिए पीएनजी के पेट्रोमिन के साथ सिद्धांततः करार पर एक समझौता ज्ञापन आरंभ किया गया है। खाड़ी एलएनजी परियोजना में भारत की संभावित भागीदारी के लिए इंटरऑयल तथा अन्य संबद्ध के साथ विचार–विमर्श भी चल रहा है। अब भारतीय कंपनियां भी हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र में दीर्घावधि भागीदारी के लिए पीएनजी की ओर देख रही हैं।

श्री थियोडोर जूरेनूक, पीएनजी संसद के स्पीकर के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 26–30 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की और लोकसभा की स्पीकर के साथ बैठक की तथा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

ब्रिगेडियर जनरल फ्रांसिस अगवी, पीएनजी रक्षाबल के प्रमुख भारतीय मिलिट्री अकादमी, देहरादून में पीएनजी डीएफ के कैडेट अधिकारियों के उत्तीर्णता समारोह में भाग लेने के लिए जून, 2013 में भारत की यात्रा की। उन्होंने भारतीय थल सेना अध्यक्ष, भारतीय जल सेना अध्यक्ष तथा भारतीय वायु सेना के उपाध्यक्ष के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की।

भारत आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करके पीएनजी को उसके क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता करता रहा है। इस वर्ष चार राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियों के अलावा भारत ने 30 छात्रवृत्तियां प्रदान की। प्रशांत क्षेत्र देशों के लिए क्षेत्रीय सहायता के हमारे कदम के भाग के रूप में भारत सरकार ने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु पीएनजी को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया।

पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय के साथ भारतीय उच्चायोग ने 7–12 जून, 2013 तक विश्वविद्यालय में भारतीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नई दिल्ली में जनवरी, 2014 को पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर शशिनदरन मुथुवेल को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया।

भारत सरकार ने पोर्ट मोरसबी में उच्च न्यायालय तथा अधिकारियों के आवास के लिए प्रसिद्ध ईला समुद्र तट के नजदीक एक दर्शनीय पहाड़ी पर एक परिसर की खरीद की। उच्चायोग सितंबर, 2013 में नए परिसर में स्थानांतरित हो गया।

फ़िलिपींस

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने द्विपक्षीय सहयोग संबंधी संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 21–23 अक्तूबर, 2013 तक मनीला की यात्रा की, जिसमें उन्होंने फ़िलिपींस के अपने समकक्ष श्री एल्वर्ट एफ. डेल रोजारियो, सचिव, फ़िलिपींस के विदेश कार्य विभाग के साथ सह अध्यक्षता की। उन्होंने फ़िलिपींस के उप राष्ट्रपति श्री जेजोमर बिनय के साथ मुलाकात की और फ़िलिपींस के विदेश सेवा संस्थान में 'रिजाल–नेहरू मेमोरियल श्रृंखला' का उद्घाटन व्याख्यान दिया। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए फ़िलिपींस को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की आपदा राहत सहायता की घोषणा की।

भारत सरकार ने 'हेयान' सुपर तूफान, जो फ़िलिपींज में 7–8 नवंबर, 2013 को आया था, के पीड़ितों के लिए फ़िलिपींस सरकार को आपदा राहत सहायता की भी घोषणा की। राहत सामग्री से भरा हुआ एक हवाई जहाज 16 नवंबर, 2013 को टकलोबन, भूकंप का केंद्र, में भारतीय एयरफोर्स सी–130 के जरिए फ़िलिपींस को भेजा गया था। फ़िलिपींस के उप राष्ट्रपति ने मनीला में भारतीय मिशन को एक प्रशंसा पट्ट प्रदान किया।

विदेश संबंधी सीनेट समिति ने 20 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में भारत–फ़िलिपींस प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन की सिफारिश की (इस संधि पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे)।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने एशिया विकास बैंक में 'भारत में स्त्री पुरुष अंतराल को पाटना' संबंधी एक प्रस्तुतीकरण देने के लिए 26–28 सितंबर, 2013 तक मनीला की यात्रा की। तमिलनाडु के कृषि मंत्री श्री एस. दामोदरन ने 26–27 जुलाई, 2013 तक मनीला की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आईआरआरआई) के मंत्री के साथ भेंट की। मंत्रिमंडल सचिव, श्री अजित सेठ ने एडीबी के सलाहकार परिषद् में भाग लेने के लिए 25–27 सितंबर, 2013 तक मनीला की यात्रा की। डॉ. रीता शर्मा, सचिव, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने 3 अप्रैल, 2013 तक आईआरआरआई के ट्रस्टी बोर्ड, लगूना की बैठक के संबंध में मनीला की यात्रा की। वित्त सचिव, श्री अरविंद मायाराम ने एशिया विकास बैंक में एक बैठक के लिए 21–22 अक्तूबर, 2013 को मनीला की यात्रा की। श्री एच.एस. ब्रह्मा, भारत के चुनाव आयुक्त ने एशिया चुनाव प्राधिकरण संघ (एएईए) कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए 11–15 नवंबर, 2013 तक फ़िलिपींस की यात्रा की।

फ़िलिपींस के विदेश नीति अवर सचिव श्री ईवान पी. गार्सिया ने 10–13 नवंबर, 2013 तक एसईएम एफएमएम11 की बैठक में भाग लेने के लिए भारत में फ़िलिपींस के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पूर्वी बेड़े से भारतीय नेवल जहाजों का एक बेड़ा नामतः आईएनएस

शक्ति, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस रंजीत और आईएनएस कीरच ने 12–16 जून, 2013 तक मनीला की यात्रा की। वाइस एडमिरल अनिल चोपड़ा, फ्लैग–ऑफिसर–कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट ने 15–18 जून, 2013 तक फ़िलिपींस की यात्रा की और फ़िलिपींस के रक्षा सचिव के साथ मुलाकात की। रक्षा प्रबंधन कॉलेज, सिकंदराबाद के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2013 तक फ़िलिपींस की यात्रा की।

व्यापार एवं निवेश संबंधी जेडब्ल्यूजी (जेडब्ल्यूजीटीआई) की 11वीं बैठक 29–30 अप्रैल, 2013 तक मनीला में आयोजित की गई। भारत–फ़िलिपींस नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक 11 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

आईसीसीआर द्वारा प्रदत्त मदर टेरेसा की एक मूर्ति का मनीला में सेंटो टोमस विश्वविद्यालय में 16 जुलाई, 2013 को अनावरण किया गया। फ़िलीपींस के 25 छात्रों के एक समूह ने 17–26 नवंबर, 2013 तक एशियाई देशों के छात्र यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की यात्रा की।

सिंगापुर

तीसरी भारत–सिंगापुर संयुक्त मंत्रालयी समिति की बैठक 23–24 अक्तूबर, 2013 तक सिंगापुर में आयोजित की गई और इसकी सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा सिंगापुर के उनके समकक्ष द्वारा की गई। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। पूर्व में विदेश मंत्री ने 3–4 जुलाई, 2013 तक सिंगापुर में एक द्विपक्षीय यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री/गृह मंत्री के साथ मुलाकात की। विदेश कार्य मंत्री तथा विधि मंत्री श्री के. सनमुगन ने 28–30 जुलाई, 2013 तक भारत की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के साथ भेंट की और नालंदा की यात्रा की। 12वीं एफओसी का आयोजन 12 अगस्त, 2013 को सिंगापुर में किया गया।

श्री अजित सिंह, नागरिक विमानन मंत्री ने 2–4 अप्रैल, 2013 तक सिंगापुर की यात्रा की जिसके दौरान एक संशोधित वायु सेवा करार (एएसए) पूरा किया गया तथा विमानन क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विचार–विमर्श किए गए। वाणिज्य, उद्योग तथा वस्त्र मंत्री, श्री आनंद शर्मा ने निवेश गोलमेज वार्ता में भाग लेने के लिए 14–16 मई, 2013 को सिंगापुर की यात्रा की। रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने रक्षा सहयोग में संवर्धन के लिए सिंगापुर में अपने समकक्ष के साथ विचार–विमर्श करने हेतु 3 जून, 2013 को सिंगापुर की यात्रा की। श्री कमलनाथ, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री ने 18 जून, 2013 को आयोजित 'भारतीय अवसंरचना मंच' के लिए सिंगापुर की यात्रा की। श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री ने 21 नवंबर, 2013 तक सिंगापुर में आयोजित दक्षिण एशिया प्रवासी सम्मेनल में आधार भाषण प्रदान करने के लिए सिंगापुर की यात्रा की। श्री तरुण गोगई, असम के मुख्यमंत्री ने भी 21–22 नवंबर, 2013 तक आयोजित कन्वेंशन में भाषण दिया। श्री पी. सथाशिवम, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 28–30 अक्तूबर, 2013 को एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के मुख्य न्यायधीशों के 15वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा की।

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने ली. कुआन यूव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में 'क्या उभरते हुए बाजार समाप्ति की ओर हैं' विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए 24–25 मार्च तक सिंगापुर की यात्रा की।

श्री एस. ईश्वरन, गृह कार्य और व्यापार तथा उद्योग द्वितीय मंत्री ने बंगलुरु में (सीआईआई) भागीदारी सम्मेलन 2014 में भाग लेने के लिए 26–29 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की।

सचिव (पूर्वी), श्री अनिल वाधवा, विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, 50वीं वर्षगांठ समारोह की तैयारी की समीक्षा करने तथा दिसंबर, 2013 में लिटल इंडिया में हुए दंगों के पश्चात् परिस्थिति का जायजा लेने के लिए 14–15 फरवरी, 2014 तक सिंगापुर की यात्रा की। उन्होंने ''भारत एशिया संबंधः आर्थिक पहलू'' विषयक दक्षिण एशिया अध्ययन संस्थान (आईएसएएस) में एक वार्ता प्रस्तुत की तथा प्रबुद्ध भारतीय व्यापार अग्रणियों के साथ एक इंटरएक्टिव सत्र को संबोधित किया।

भारत तथा सिंगापुर ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग जारी रखा। रक्षा मंत्री के सिंगापुर की यात्रा के दौरान सेना के प्रशिक्षण हेतु द्विपक्षीय करार का जून, 2013 में 5 वर्ष के लिए नवीकरण किया गया। चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा गोलमेज की सह–अध्यक्षता उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा स्थायी सचिव, सिंगापुर के राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय सचिवालय की सह–अध्यक्षता में 18–19 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सिंगापुर के एक नेवल जहाज ने 3–9 फरवरी, 2014 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित मिलन–2014 में भाग लिया। भारतीय सेना तथा सिंगापुर की सेना ने 1–31 मार्च, 2014 को संयुक्त सेना प्रशिक्षण तथा अभ्यास के द्विपक्षीय करार के तत्वावधान में ''बोल्ड कुरुक्षेत्र'' 10वें द्विपक्षीय सेना अभ्यास का संचालन किया।

भारत और सिंगापुर के गहन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध है जो चालू वर्ष के दौरान जारी रहे। सिंगापुर एशिया में एक प्रमुख व्यापार तथा निवेश भागीदार और इस क्षेत्र में भारतीय आर्थिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख हब के रूप में उभरा। सिंगापुर के सहयोग से निर्मित किए जा रहे विश्व स्तर के कौशल केंद्र के अस्थायी परिसर का नई दिल्ली में 19 सितंबर, 2013 को उद्घाटन किया गया।

सुश्री रोज़ा डेनियल, उप सचिव (संस्कृति) तथा राष्ट्रीय विरासत बोर्ड (एनएचबी), सिंगापुर की सीईओ ने 31 मार्च से 1 अप्रैल, 2014 तक भारत की यात्रा की तथा आईसीसीआर, एएसआई, राष्ट्रीय म्यूजियम के डीजी तथा सचिव, आईजीएनसीए के अतिरिक्त

संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की।

थाईलैंड

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा उनके साथ विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने 30–31 मई, 2013 तक प्रधानमंत्री सुश्री यिंगलक शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड की राजकीय यात्रा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक वार्ताएं कीं। प्रधानमंत्री ने साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में थाई नरेश भूमिबोल अदुल्यादेज को एक विशेष उपहार के रूप में बोधगया में बोधी वृक्ष का छोटा पौधा प्रस्तुत किया। यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण; आदान–प्रदान कार्यक्रम; हवाला तथा आतंकवादियों को वित्त पोषण; शहरी आरेखण; भारत–एशिया पुरातत्व एटलस और थम्मासात विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में 6 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और व्यापक आधार वाला संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने 29–30 अप्रैल, 2013 तक बैंकाक में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के 69वें सत्र में भाग लिया। जल संसाधन मंत्री, श्री हरीश रावत ने च्यांग माई में दूसरे एशिया–प्रशांत जल सम्मेलन में 19–20 मई, 2013 को भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोईली ने बैंकाक में मुख्य अतिथि के रूप में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी) के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और ऊर्जा मंत्री, श्री पोंगसाक रक्तापोंगपेसल के साथ मुलाकात की। श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 17 जून, 2013 को बैंकाक में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित एक व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री तारिक अनवर ने 30 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2013 तक एशिया–प्रशांत क्षेत्र में नारियल क्षेत्र विकास खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। असम के मुख्यमंत्री, श्री तरूण गोगई ने अचानक बाढ़ तथा प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 9–12 जून, 2013 तक बैंकाक की यात्रा की।

थाई उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री किटीराट ना–रानोंग ने 4–5 मई, 2013 तक नई दिल्ली में एशिया विकास बैंक गवर्नर बोर्ड की 46वीं बैठक में भाग लिया। उद्योग मंत्री, श्री प्रासर्ट बूनचेसुक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वोरवट ओपिनयाकूल ने 25–27 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की। उप प्रधानमंत्री तथा वाणिज्य मंत्री श्री निवाटुमरोंग बूनसोंगपेसन ने श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री के साथ 23 अक्तूबर, 2013 तक नई दिल्ली में भेंट की। विदेश कार्य उप मंत्री श्री जूलापोंग नोनसिरचई ने 11–12 नवंबर, 2013 तक नई दिल्ली में एशिया–यूरोप विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। श्री अपीचार्ट सुखागगनोंड, थाइलैंड के चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने राज्य असेम्बली चुनावों में चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए 28–30 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

रक्षा मंत्री, श्री ए.के. एंटनी ने 6 जून, 2013 को बैंकाक की यात्रा की और अपने थाई समकक्ष एयर चीफ मार्शल सुकुमपोल सुवानाटाट के साथ वार्ता की। चौथी द्विपक्षीय एयर स्टाफ वार्ता पटाया में 20–22 मई, 2013 को आयोजित की गई थी। समुद्र में व्यवस्था की स्थापना संबंधी जेडब्ल्यूजी की 10वीं बैठक तथा 6ठी भारतीय जल सेना–रॉयल थाई जल सेना वार्ता नई दिल्ली में 9 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई। समन्वित गश्त चक्र का 17वां दौर अंडमान समुद्र में 13–21 नवंबर, 2013 तक आयोजित किया गया।

थाईलैंड की राजुकमारी माहा चक्री सिरिंधोरन ने 23–28 फरवरी, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उन्होंने नई दिल्ली में पहुंचने से पहले बिहार में नालंदा तथा बोधगया और नागालैंड में कोहिमा की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री द्वारा उन्हें रात्रि भोज दिया गया।

सुरक्षा सहयोग संबंधी जेडब्ल्यूजी की 8वीं बैठक 18–19 जुलाई, 2013 तक नीमराना में आयोजित की गई जिसकी सह–अध्यक्षता श्री नेहचल संधू, उप एनएसए तथा श्री पैराडोन पाटानाटाबट, महासचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एनएससीएन) द्वारा की गई।

द्विपक्षीय एफटीए के लिए व्यापार वार्ता समिति की 27वीं तथा 28वीं बैठक क्रमशः बैंकाक में 10–12 जुलाई और नई दिल्ली में 6–7 नवंबर, 2013 को आयोजित की गई।

वीजा तथा दूतावास मामलों पर भारत–थाईलैंड तदर्थ कार्य समूह की तीसरी बैठक 27 अगस्त, 2013 को बैंकाक में विदेश मंत्रालय में आयोजित की गई।

संस्कृति पीठ जारी रखने के लिए आईसीसीआर और सिल्पाकोरन विश्वविद्यालय के बीच 19 जून, 2013 को बैंकाक में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्वी), विदेश मंत्रालय द्वारा 20–23 मार्च, 2014 तक थाईलैंड में आयोजित भारतीय उत्सव का उद्घाटन किया गया।

तिमोर लेस्ते जनवादी गणराज्य

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने जोश लुईस गटर्रेस, वरिष्ठ मंत्री और तिमोर लेस्ते के विदेश तथा सहयोग मंत्री के साथ भेंट की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग पर बस दिया किया तथा 11वें एशियाई–भारत पोस्ट–मंत्रालयी सम्मेलन (पीएमसी), तीसरी ईएएस विदेश मंत्री बैठक और 20वें एआरएफ मंत्रालयी के लिए 30

जून से 3 जुलाई, 2013 तक ब्रुनेई की अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में तिमोर लेस्ते का दूतावास खोलने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया।

डॉ. सेरियो जी.सी. लोबो, स्वास्थ्य मंत्री, तिमोर लेस्ते सरकार ने एसईएआरओ, डब्ल्यूएचओ बैठक के लिए सितंबर, 2013 में भारत की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भेंट की तथा स्वास्थ्य देखभाल और प्रशिक्षण के प्रमुख संस्थानों की यात्रा की तथा फिक्की के अधिकारियों के साथ भेंट की।

वियतनाम

श्री गुयेन फू ट्रोंग, वियतनाम के वामपंथी दल के महासचिव ने 19–22 नवंबर, 2013 तक भारत की राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री ने महासचिव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। महासचिव ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और उपराष्ट्रपति, स्पीकर, विदेश मंत्री और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भेंट की। दोनों देशों के बीच नीतिगत भागीदारी को सुदृढ़ और घना बनाने पर जोर देते हुए इस अवसर पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। यात्रा के दौरान वायु सेवा करार दस्तावेजों; हनोई में इंदिरा गांधी हाइटेक क्राइम लैब (आईजीएचसीएल) की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन; रक्षा मंत्रालयों के बीच गोपनीय सूचना के संरक्षण संबंधी करार; दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; हनोई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन; भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर (आईआईएमबी) तथा एचसीएम राष्ट्रीय राजनीतिक तथा लोक प्रशासन अकादमी के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन; वियतनाम तेल एवं गैस समूह तथा ओवीएल के बीच समझौता ज्ञापन; उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय तथा टाटा पॉवर लिमिटेड के साथ सोक ट्रांग, वियतनाम में लांग फू 2 थर्मल पॉवर परियोजना के विकास के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय जहाजरानी मंत्री, श्री जी.के. वासन ने 23–28 मई, 2013 तक वियतनाम की यात्रा की जिसके दौरान एक समुद्री शिपिंग करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वी. किशोर चंद्र देव, जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री ने यूएनडीपी के निमंत्रण पर वियतनाम में नृजातीय अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए 7–11 जनवरी, 2014 को वियतनाम की यात्रा की। राज्यमंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने 27–28 अप्रैल, 2013 तक वियतनाम की यात्रा की। श्री डी.पी. त्रिपाठी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में 29 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम यूनियन ऑफ फ्रेंडशिप संगठनों द्वारा आयोजित छठे वियतनाम–भारत जन मित्रता उत्सव में भाग लेने के लिए 20–26 अक्तूबर, 2013 तक वियतनाम की यात्रा की। सचिव (पूर्वी), विदेश मंत्रालय, श्री अशोक के. कांथा ने 13–15 अगस्त, 2013 तक वियतनाम की यात्रा की। शिक्षा संबंधी जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 नवंबर, 2013 तक आयोजित की गई।

वियतनाम के लोक सुरक्षा मंत्री, श्री तरान दाई क्वांग ने 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की और गृह मंत्री, विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ वार्ता की। यात्रा के दौरान दंडित व्यक्तियों के अंतरण संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। सूचना एवं संचार मंत्री श्री गूयेन बाक सोन ने 3–8 जुलाई, 2013 तक भारत की यात्रा की और उस दौरान वियतनाम दूर संचार प्राधिकरण (वीएनटीए) तथा भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बीच एक समझौता ज्ञापन तथा स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री ट्राउंग ची ट्रंग, उप वित्त मंत्री ने भारतीय सहायता तथा एलओसी के संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए 23–24 सितंबर, 2013 तक यात्रा की। डॉ. डोआन माउ डाइप, उप श्रम, निःशक्त तथा सामाजिक कार्य मंत्री ने एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में बाल अधिकारों के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग संबंधी दूसरी एचएलएम में भाग लेने के लिए 23–25 अक्तूबर, 2013 तक नई दिल्ली की यात्रा की। श्री हा किम नोक, उप विदेश मंत्री ने 9–12 नवंबर, 2013 तक एएसईएम एफएमएम11 में भाग लिया। श्री गूयेन काम तू, उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री ने व्यापार तथा संबंधित मुद्दों के बारे में भारत–वियतनाम उप समिति की पहल बैठक में भाग लेने के लिए 18–19 नवंबर, 2013 तक यात्रा की। उन्होंने 19 नवंबर, 2013 को मैकांग–भारत आर्थिक सहयोग संवर्धन के संबंध में आयोजित एडीबी–सीआईआई सम्मेलन में भी भाग लिया। श्री फाम कुआंग विन्ह, उप विदेश मंत्री ने 6–7 मार्च, 2014 तक दिल्ली वार्ता VI में भाग लिया।

वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित किए जाने वाले अन्य करारों/समझौता ज्ञापनों में शामिल हैं, राजनयिक संपदा तथा भूमि पट्टा; शांति उद्देश्यों के लिए आणविक ऊर्जा के प्रयोग हेतु सहयोग के लिए करार का मई, 2012 से मई, 2017 तक और पांच वर्षों के लिए विस्तार; माइक्रो, लघु तथा मध्य उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन तथा भारत और वियतनाम के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन विलेखो का आदान–प्रदान।

8 नवंबर, 2013 को हो ची मिन्ह शहर में 8वीं सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई जिसकी सह–अध्यक्षता श्री आर.के. माथुर, रक्षा सचिव और वियतनाम के उप रक्षा मंत्री द्वारा की गई। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का 2014–2019 तक पांच और वर्षों के लिए विस्तार किया गया। भारतीय थल सेना को वियतनाम की थल सेना के क्षमता निर्माण में शामिल किया गया है जिसके लिए भारत तथा वियतनाम दोनों में प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित किए गए। भारत तथा वियतनाम एडीएमएम+ मंच में मानवीय खनन कार्रवाई संबंधी

विशेषज्ञ कार्य समूह की सह–अध्यक्षता करेंगे। चार भारतीय नेवल जहाज जिनमें स्वादेश में निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा और फिलीट टैंकर आईएनएस शक्ति ने 6–10 जून, 2013 को डा नांग की यात्रा की। वियतनामी पक्ष की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल डो बा टाई, जनरल स्टाफ अध्यक्ष–सह–रक्षा उप मंत्री ने 23–27 सितंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

पिछले वर्ष के दौरान भारत तथा वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि जारी रही। हो ची मिन्ह शहर के एक वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 21–22 अक्तूबर, 2013 तक सीआईआई द्वारा आयोजित भारत–सीएलएमवी व्यापार कन्क्लेव में भाग लिया।

वियतनाम आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का बड़ा प्राप्तिकर्ता रहा है जहां उसके लिए 150 स्लॉट रखे गए हैं। उसने सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस) के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 16 स्लॉट, मैकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दस स्लॉट और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (ईईपी) के अंतर्गत 14 स्लॉट प्रदान किए गए हैं।

12 नवंबर, 2013 को हनोई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सी–डैक द्वारा स्थापित एक उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया था जिसमें आधारभूत दृश्य प्रयोगशाला और 16–नोड वाले क्लस्टर तथा एक 5 नोड ग्रिड युक्त कम्प्यूटिंग सुविधा उपलब्ध है। यह भारत की सरकार द्वारा विदेश में उपहार स्वरूप दिए गए सुपर कंप्यूटर का सर्वाधिक कॉन्फीग्रेशन हैं।

वियतनाम–हनोई, डा नांग तथा हो ची मिन्ह शहर में 5–15 मार्च, 2013 तक भारतीय उत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कला, संरक्षण तथा संगीत शास्त्र संस्थान म्यूजियम, भारत (एनएमआई) तथा चाम मूर्तिकला डानांग म्यूजियम (चाम म्यूजियम) के बीच 10 जून, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रशांत द्वीपसमूह

प्रशांत देशों के राजदूतों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 44वीं प्रशांत द्वीपसमूह मंच की बैठक के पश्चात् 25वीं पोस्ट फोरम वार्ता भागीदार बैठक में भाग लेने के लिए 3–6 सितंबर, 2013 तक मार्शल गणतंत्र द्वीपसमूह की राजधानी मजूरो की यात्रा की।

श्री ब्राउन मार्क स्टीफन, कुक द्वीप समूह के वित्त मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल; श्री डेनिस पी. मोमोटारो, मार्शल द्वीप समूह के वित्त मंत्री; श्री कुन रोनाल्ड, नॉरू के वित्त मंत्री; श्री फामूइना लियूगा, समोआ के वित्त मंत्री; श्री होनिपवेला रिक, सोलोमन द्वीप समूह के वित्त मंत्री; श्री अकोलो लिसीऐटे अलोविएटा, टोंगा के वित्त तथा राष्ट्रीय आयोजना मंत्री; श्री नतानो कौसी, तुआलू के वित्त एवं आर्थिक विकास मंत्री; श्री जिम्मी तपंगारारू विल्ले, वानुआटू के वित्त मंत्री, श्री इल्डेबिचेल सेकिलिल, पलाउ के राष्ट्रपति कार्यालय के वित्तीय सलाहकार, श्री यूआकेला ताकुला, उप सचिव, किरवाती वित्त मंत्रालय तथा श्री तुईलोमा नेरोनी सलादे, प्रशांत द्वीप समूह मंच के महासचिव ने 2–5 मई, 2013 तक ग्रेटर नोएडा में एडीबी गवर्नर बोर्ड की बैठक में भाग लिया। प्रशांत द्वीप समूह मंच के महासचिव ने नई दिल्ली में श्री पी. एस. राघवन, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय के साथ भी भेंट की।

डॉ. विता स्किलिंग, एफएसएम के स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य मंत्री; श्री विल्बर हेनी, मार्शल द्वीप समूह गणतंत्र के आंतरिक कार्यमंत्री; श्री जोन हेनरी, एसोसिएट मंत्री, कुक द्वीप समूह के आंतरिक कार्यमंत्री; माननीय तेईमा ओनोरियो, किरीवाती के उप राष्ट्रपति; माननीय देविड एडेन्ग, नूरा के न्याय, सीमा एवं नौटा नियंत्रण मंत्री; श्री पोनीपेट ताउनीसिला, टोंगा के उप निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय; फाउआ मानी, तूवाली के शिक्षा, युवा एवं खेल मंत्री ने 23–25 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में बाल अधिकारों के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के बारे में नई दिल्ली में दूसरी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

वर्ष के दौरान पीआईएफ के प्रत्येक देशों को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर की भारत की वार्षिक सहायता की पहल जारी रही। भारत ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रायोजन के लिए कूक द्वीप समूह को 10,000 अमेरिकी डॉलर; किरीवाती में स्वास्थ्य उपकरणों के निधियन के लिए 2,58,515 अमेरिकी डॉलर; टोंगा को सुनामी एलर्ट सिस्टम के लिए 3,00,000 अमेरिकी डॉलर; टूवालू को जल सप्ताह में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता हेतु 18,175 अमेरिकी डॉलर; मार्शल द्वीप समूह को पीआईएफ समिट की बैठक तथा संबद्ध बैठकों के आयोजन के लिए 1,62,833 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। भारत ने जून, 2013 में मार्शल द्वीप समूह की सरकार को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की आपदा राहत सहायता भी प्रदान की।

तुवालू के विदेश मंत्री, ताउकेलिना फिनीकासो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में तुवालू के नए दूतावास की स्थापना के लिए अगस्त, 2013 में भारत की यात्रा की।

भारत ने आईटीईसी तथा कोलंबो योजना के अंतर्गत इन देशों को लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा आईसीसीआर की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा।

■■

पूर्वी एशिया

3

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य

भारत तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, जिनमें मुख्यतः डीपीआरके की मानवीय तथा मानव संसाधन विकास सहायता पर जोर दिया गया। भारत ने डीपीआरके को उसके क्षमता निर्माण प्रयासों में मदद करने के लिए आईटीपीसी स्लॉट आबंटित करना जारी रखा। डीपीआरके को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान करना भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन थी।

अप्रैल, 2013 में संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया), विदेश मंत्रालय, श्री गौतम बंबावाले ने समग्र संबंधों की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता आयोजित करने हेतु अप्रैल, 2013 में प्योंगयांग में एक दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जुलाई, 2013 में श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्री तरुण विजय, संसद सदस्य और श्री मोहम्मद हमदुल्ला सईद, संसद सदस्य भी शामिल थे, ने डीपीआरके के फादरलैंड लिबरेशन दिवस की 60वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए प्योंगयांग की यात्रा की। जुलाई, 2013 में विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने ब्रुनेई में 46वीं एशियाई मंत्रालयी बैठक (एएमएम)/पोस्ट मंत्रालयी सम्मेलन (पीएमसी)/एशिया क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक के दौरान डीपीआरके के विदेश मंत्री श्री पाक यूई चुन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

भारत और डीपीआरके ने विभिन्न आयोजनों को मनाने तथा अपने लोकतांत्रिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाने हेतु उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान–प्रदान करने का निर्णय लिया। इन आयोजनों में विदेश मंत्रियों के स्तर पर बधाई संदेशों का आदान–प्रदान; नई दिल्ली तथा प्योंगयांग प्रत्येक में दिसंबर के शुरूआत में स्वागत करने जिसमें मेजबान सरकार के विदेश मंत्री द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया जाएगा; उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान; राष्ट्रीय दिवसों पर टीवी पर वृत्तचित्र का प्रसारण; तथा पुस्तकों को उपहार में देना शामिल था। दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा।

जापान

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 25–27 जनवरी, 2014 को भारत की यात्रा की। वे हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। शिखर सम्मेलन बैठकों के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा एक ''संयुक्त वक्तव्य'' पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मई, 2013 में वार्षिक जापान–भारत शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा की। उन्होंने जापान के सम्राट और साम्राज्ञी के साथ भेंट की। शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा 'संयुक्त व्कतव्यः लोकतांत्रित संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के बाद भारत और जापान के बीच नीतिगत तथा वैश्विक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना' पर हस्ताक्षर किए।

जापान के महामहिम सम्राट और साम्राज्ञी ने 50 वर्षों के पश्चात् इस देश में नवंबर, 2013 में भारत की ऐतिहासिक यात्रा की। उनके महामहिम ने राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से भेंट की और उन्हें भारत के उप राष्ट्रपति तथा लोक सभा के स्पीकर द्वारा आमंत्रित किया गया। दिल्ली के अतिरिक्त, सम्राट और साम्राज्ञी ने चेन्नई की छः दिवसीय यात्रा की। यह यात्रा भारत और जापान के बीच मजबूत और परिपक्व संबंधों के प्रतीक के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री योशीहिको नूरी, जिनके कार्यकाल में भारत–जापान संबंधों में अत्यधिक वृद्धि हुई, वे राजकीय यात्रा के प्रमुख के रूप में प्रतिनिधिमंडल का भाग थे।

मंत्रिमंडल स्तर पर विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 7वें वार्षिक रणनीति वार्ता के लिए मार्च में टोकियो की यात्रा की। उन्होंने टोकियो में 26 मार्च, 2013 को अपने समकक्ष जापानी विदेश मंत्री फूमियो किशीडा के साथ 7वीं रणनीति वार्ता की सह–अध्यक्षता की। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय नीति तथा वैश्विक भागीदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

जापान के रक्षा मंत्री सुनोरी ओनोडेरा ने 5–8 जनवरी, 2014 को भारत की यात्रा की तथा 6 जनवरी, 2014 को भारत के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी के साथ भेंट की।

जापान के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री अश्विनी कुमार ने

सितंबर, 2013 में टोकियो की यात्रा की, प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री फुमियो किशीडा के साथ बैठक की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डाइट के विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष डॉ. काटसूयूकी कवाई के नेतृत्व में जापानी संसद सदस्यों के समूह से मुलाकात की। जापान के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 2013 में भारत की यात्रा की और भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और संभावना की प्रशंसा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने फरवरी, 2013 में जापान की यात्रा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री आनंद शर्मा ने हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से कुछ ही समय पहले मई, 2013 के मध्य में अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की।

श्री आनंद शर्मा ने रणनीति वार्ता के भाग के रूप में दिल्ली में सितंबर, 2013 में आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री (एमईटीआई) के साथ मुलाकात की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोईली ने सितंबर की शुरूआत में टोकियो मे एलएनजी उत्पादक–उपभोक्ता सम्मेलन में भाग लिया। सितंबर, 2013 में उपाध्यक्ष, योजना आयोग श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया तथा एमईटीआई के बीच 7वीं मंत्रालयी स्तर की ऊर्जा वार्ता आयोजित की गई।

दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की वार्ता का पहला दौर 27 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

समुद्री मामलों से संबंधित वार्ता का पहला दौर जनवरी, 2013 में दिल्ली में आयोजित किया गया। निरस्तीकरण तथा गैर–प्रसार वार्षिक वार्ता का 6ठा दौर जुलाई, 2013 में टोकियो में आयोजित किया गया, जबकि सिविल परमाणु सहयोग का 6वां दौर दिसंबर, 2013 में दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत और जापान ने चेन्नई के तटवर्ती क्षेत्रों में दिसंबर, 2013 में दूसरा संयुक्त जल सेना अभ्यास आयोजित किया, थल सेना अध्यक्ष, जनरल बिक्रम सिंह ने फरवरी, 2013 में जापान की यात्रा की।

विदेश मंत्रालय के प्रतिष्ठित विजिटर कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित यात्राएं की गईं: (i) काजुओ कानजावा, वाइस गवर्नर, हयोगो प्रीफेक्चर ने 14–19 नवंबर, 2013 तक भारत की यात्रा की (दिल्ली, आगरा तथा अहमदाबाद), (ii) नाटसुओ यामागुची, मुख्य प्रतिनिधि, न्यू कोमिटो पार्टी ने 5–11 जनवरी, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की (दिल्ली, बंगलुरु, बम्बई तथा आगरा) (iii) योशीयूकी कसई, अध्यक्ष, जापान रेलवे सेंट्रल ने 9–15 मार्च, 2014 को भारत की यात्रा की (दिल्ली, बंगलुरू, मुम्बई तथा आगरा)।

जापान, पश्चिमी समर्पित बहु–मॉडल फ्रेट कॉरीडोर (डीएफसी) के विकास में भारत की सहायता कर रहा है; इस परियोजना के लिए मुख्य ऋण करार पर मार्च, 2013 में हस्ताक्षर किए गए।

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना संबंधी संयुक्त कार्यबल का अंतिम दौर अप्रैल, 2013 में आयोजित किया गया। एक अंतर–मंत्रालयी परामर्श तंत्र ने कई मुद्दों में तेजी लाने में सहायता की है। डीएमआईसी परियोजना में सितंबर, 2013 में डीएमआईसी ट्रस्ट द्वारा 6 परियोजनाएं अनुमोदित थीं। यह 2010 में जापानी कंपनियों तथा राज्य सरकारों के कंसोर्टियम के बीच हस्ताक्षरित ''स्मार्ट समुदाय और इकोफ्रेंडली शहर'' संबंधी समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त प्रगति का निर्माण करता है।

जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने चेन्नई–बंगलुरु औद्योगिक कॉरीडोर (सीबीआईसी) परियोजना के लिए एक संसदीय अध्ययन संचालित किया और सीबीआईसी के लिए मास्टर प्लान हेतु मसौदा संदर्भ शर्तों (टीओआरएस) का संचालन किया है।

भारत 2003–04 से जापान से विदेश विकास सहयोग (ओडीए) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जापान से वचनबद्ध ओडीए ऋण 353 बिलियन येन (लगभग 23,180 करोड़ रुपए/3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जोकि अब तक का सर्वाधिक है। आर्थिक विकास संबंधी 6वां उच्च स्तरीय परामर्श (ओडीए परामर्श) के परिणामस्वरूप अप्रैल, 2012 में जापान के प्रधानमंत्री ने मई, 2013 में घोषणा की कि आईआईटी–हैदराबाद के परिसर विकास परियोजना के लिए 17.7 बिलियन येन उपलब्ध करवाएं जाएंगे। 13 बिलियन येन तमिलनाडु निवेश संवर्धन परियोजना के लिए रखे गए हैं। मुम्बई मेट्रो लाइन–III परियोजना के लिए कुल 71 बिलियन येन के ऋण हेतु टिप्पणियों के आदान–प्रदान का दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा स्वागत किया गया। आईआईटी परियोजना तथा तमिलनाडु निवेश संवर्धन परियोजना के लिए टिप्पणियों के आदान–प्रदान पर नवंबर, 2013 में हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय वर्ष 2013–14 (मई, 2014 तक) जापान से वचनबद्ध ओडीए ऋण 101.703 बिलियन येन (लगभग 6812 करोड़ रुपए/1.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च को भारत सरकार ने 1) दिल्ली में मेट्रो के निर्माण, 2) हरियाणा में पॉवर वितरण प्रणाली में सुधार और 3) आगरा में सुरक्षित और स्थिर पेय जल आपूर्ति की तीन परियोजनाओं के लिए कुल 183.079 बिलियन येन हेतु जेआईसीए के साथ ओडीए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के बीच मौजूद एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करार को सितंबर, 2013 में 15 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर कर दिया गया।

कोरिया गणराज्य (आरओके)

कोरिया के प्रधानमंत्री पार्क जेउन–हाई ने 15–18 जनवरी, 2014 को भारत की यात्रा की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के बीच नियमित वार्ता करने तथा वर्गीकृत सैन्य सूचना का आदान–प्रदान करने, सीईओ मंच की स्थापना करने तथा सीईपीए के उन्नयन के लिए कार्य करने का निर्णय लिया गया। लोगों के बीच संपर्क तथा

यात्रा को बढ़ाने के लिए भारत ने आरओके के पर्यटकों को आगमन पर वीजा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान नौ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रेसीडेंट पार्क की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने महाबोधि मंदिर, बोध गया के बोधि वृक्ष से प्राप्त पौधे को भारत और कोरिया गणतंत्र के मध्य पुरातन संबंधों के चिह्न के रूप में कोरिया गणतंत्र को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। बोधि वृक्ष के पौध को श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय की उपस्थिति में दिनांक 19 मार्च, 2014 को हुए ''बोधि वृक्ष प्रस्तुतीकरण समारोह'' में कोरिया को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कोरिया गणतंत्र में भारत के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि श्री शिवशंकर मेनन ने जुलाई, 2013 में प्रेसीडेंट पार्क गूयेन–हाई से मुलाकात की। श्री मेनन के दोनों देशों के मध्य आर्थिक, समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर विचार–विमर्श किया।

जुलाई, 2013 में कोरिया–भारत संसदीय मित्रता समिति ने नई दिल्ली की यात्रा की और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और कोरिया–भारत संसदीय सोसायटी के अध्यक्ष, श्री एच.डी. देवे गौड़ा से बातचीत की।

सितंबर, 2013 में सियोल में तीसरी विदेशी नीति और सुरक्षा संबंधी बातचीत हुई जिसमें श्री अशोक कांथा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता में विदेश, रक्षा और नागर उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने भाग लिया। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार–विमर्श के साथ–साथ उन्होंन अंतरिक्ष और परमाणु सहयोग के संभावित क्षेत्रों, सीईपीए के स्तरोन्नयन और रक्षा सहयोग की भी जांच की। दोनों देशों ने समुद्री सहयोग के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति मैडम पार्क गूयेन–हाई की आने वाले यात्रा के परिणामों पर विचार–विमर्श किया।

भारत कोरिया गणतंत्र की 7वीं संयुक्त आयोग बैठक दिनांक 8 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जिसमें विदेश, रक्षा सिविल विमानन, पोत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों को प्रतिनिधि और ओडिशा सरकारके प्रतिनिधि शामिल थे। दक्षिण कोरिया दल का नेतृत्व विदेश मंत्री युन ब्युग–से ने किया। दोनों पक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा और इस बात पर विचार–विमर्श किया कि किस प्रकार इन संबंधों में और आर्थिक, सामाजिक महत्ता तथा आर्थिक संदर्भों को शामिल किया जा सकता है।

8वीं संयुक्त समिति बैठक वर्ष 2014 में सिओल में होगी। रक्षा और रणनीति स्तरों के अधिकारियों के बीच भी कई विचार–विमर्श हुए। अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउनी की अध्यक्षता में जुलाई, 2013 में त्रि–सेवा कार्यदल ने कोरिया गणतंत्र की यात्रा की। अध्यक्ष, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जंग सिउंग–जो द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए एसीएम ब्राउनी ने कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की जो वर्ष 2012 में भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने कोरिया रक्षा प्रशिक्षण स्थापनाओं की यात्रा की। भारत की यात्रा करने का निमंत्रण अध्यक्ष, ज्वाइंट चीफ स्टाफ द्वारा स्वीकार किया गया।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया ने अपने सहयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से मार्च, 2013 में भारत–मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की चौथी बैठक के दौरान अपने संबंधों की समीक्षा की।

रक्षा संबंधों की समीक्षा और विस्तार के लिए नई दिल्ली के नवंबर, 2013 में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य दल की छठी बैठक हुई।

''मंगोलिया को अनुदान सहायता'' आईटीईसी कार्यक्रम और अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के अंतर्गत भारत ने मंगोलिया को सिविल, रक्षा और रणनीति क्षेत्रों में विकासात्मक सहायता प्रदान करना जारी रखा है। भारत सरकार पहले चरण के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों और मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के दो नए ट्रेडो को कार्यान्वित करने हेतु उलानबतार में राजीव गांधी पॉलीटेक्निक कॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एंड आर्ट के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया। फरवरी, 2014 में कार्य समाप्त हो गया। भारत सरकार ने चरणों में कुल छः ट्रेड को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। नए ट्रेड के कार्यान्वयन की सुविधा हेतु अक्तूबर, 2013 में भारत और मंगोलिया के मध्य अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उलानबतार में ''भारत–मंगोलिया संयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और आउटसोर्सिंग केंद्र'' की स्थापना हेतु आसान शर्तों पर मंगोलिया को भारत द्वारा दिए गए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के जल्द उपयोग के लिए भारत सरकार ने मंगोलिया सरकार को कहा है।

दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा है। जबकि दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय औप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रगति संतोषजनक है तथापि दोनों पक्षों का मानना है कि अपनी ''विस्तृत भागीदारी'' को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उनके आर्थिक सहयोग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता है। भारत के नवीकरण ऊर्जा मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला ने जुलाई, 2013 में मंगोलिया के राष्ट्रपति एल्बेग्दरोज के शपथ समारोह में भाग लिया। भारत से मंगोलिया के अन्य दौरों में शामिल है– सितंबर, 2013 में श्री डी.पी. अग्रवाल, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल; जुलाई, 2013 में श्री सुभाष जोशी, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय दल; सितंबर, 2013 में नवीन और

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री तरूण कपूर; अक्तूबर, 2013 में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के संयुक्त सचविव डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद। इसके अतिरिक्त भारत के विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 13वें शंघाई को–ऑपरेशन आर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेर अधिवेश के बाहर बिशकेक में दिनांक 13 सितंबर, 2013 को मंगोलिया के राष्ट्रपति एल्बेग्दरोज से मुलाकात की; जुलाई, 2013 में 46वीं एएमएम/पीएमसी/आरएफ बैठक के साथ–साथ ब्रुनेई में मंगोलिया के विदेश मंत्री, श्री लुबोन्ड से द्विपक्षीय बैठक की; और अक्तूबर, 2013 में लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने जेनेवा में आईपीयू असेंबली के साथ–साथ पर मंगोलिया के स्पीकर श्री जेड. एन्खाबोल्ड से बैठक की। मंगोलिया की ओर से इसके विदेश उप मंत्री, श्री दंबा गानहुएगा ने 11–12 नवंबर, 2013 तक नई दिल्ली में हुई 11वीं एएसईएम विदेश मंत्री बैठक में भाग लिया। एएसईएम बैठक के साथ–साथ, उन्होंने सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, श्री अशोक के. कांथा के साथ दिनांक 10 नवंबर, 2013 को द्विपक्षीय बैठक की।

■■

यूरेशिया

4

रूसी संघ

दिनांक 20–22 अक्तूबर, 2013 तक मास्को में हुए 14वें वार्षिक भारत–रूस अधिवेशन में वर्ष के दौरान होने वाले विनिमय का चरमोत्सकर्ष था जिसमें दोनों राष्ट्रों के मध्य विद्यमान 'विशेष और प्राधिकृत' बहुआयामी रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा करने और गहन बनाने हेतु विकसित बुहस्तरीय द्विपक्षीय कार्य पद्धति को शामिल किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति ब्लदिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विस्तृत चर्चा की। अधिवेशन में जारी संयुक्त वक्तव्य (''वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करना'') में द्विपक्षीय मामलों की स्थिति और वैश्विक मामलों पर विचारों की समाभिरूपता पर विचार प्रकट किए गए। पांच दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें शामिलहैं– सजायाफ्ता बंदियों के स्थानांतरण पर संधि सहित ऊर्जा दक्षता, मानक, बॉयोटेक्नोलॉजी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर सहमति। दौरे के दौरान मास्को स्टेट इंस्टीट्यूट (यूनिवर्सिटी) ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स (एमजीआईएमओ) ने हमारे प्रधानमंत्री को मानद डॉक्टोरेट की उपाधि से सम्मानित किया।

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 2–4 अक्तूबर, 2013 तक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–रूस के अंतर्सरकारी आयोग के ग्प सत्र के लिए मास्को की यात्रा की जिसके सह–अध्यक्ष रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दमित्री रोगोजिन थे। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री, श्री सरगे लावरोव के साथ भी एक बैठक की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनंद शर्मा ने अप्रैल, 2013 में मास्को की यात्रा की। उन्होंने जून, 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की और सितंबर, 2013 में क्रमशः सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम और भारत–रूस व्यापार और निवेश फोरम में भाग लिया। डॉ. गिरिजा व्यास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री ने नेशनल कन्वेंशन ऑफ दि कानफेडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए जुलाई, 2013 में मास्को की यात्रा की। श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच, संस्कृति मंत्री ने नवंबर, 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को की यात्रा की। रक्षा मंत्री, श्री ए. के. एंटनी ने रूसी रक्षा मंत्री, श्री सरगे शोएगु के साथ इंटर–गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड टेक्निकल को–ऑपरेशन की वार्षिक बैठक की सह–अध्यक्षता 15–18 नवंबर, 2013 तक एवं सेवेरोदविनसक में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में शामिल करने के समारोह में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा की। पहले जून, 2013 में आईएनएस त्रिकाण्ड, गुप्त जलपोत, को कालिनिग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अक्तूबर, 2013 में भारत में सूरतगढ़ के नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त थल सेना अभ्यास, इंद्रा 2013 का आयोजन किया गया।

विदेश मंत्री श्री सरगे लावरोव ने रूस–भारत–चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक के लिए नवंबर, 2013 में भारत की यात्रा की।

अध्यक्ष, राज्य सभा और अध्यक्ष, लोक सभा के संयुक्त निमंत्रण पर सुश्री वेलेन्टीना मातविएंको, अध्यक्ष, संघ काउंसिल (रूसी संसद की उच्च सभा) के फरवरी, 2013 के भारत दौरे से भारत और रूस के संसदीय संबंध और सुदृढ़ हुए। रूसी आंतरिक गृह मंत्री के निमंत्रण पर गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने अप्रैल, 2013 में मास्को की यात्रा की।

बीआरआईसीएस (ब्रिक्स) एनएसए की बैठक में भाग लेने के लिए सचिव, रूस सुरक्षा परिषद् के श्री निकोलई पातरूशेव ने जनवरी, 2013 में नई दिल्ला की यात्रा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने (i) फरवरी, 2013 में अफगानिस्तान पर रूस, भारत और चीन की एनएसए की बैठक के लिए मास्को की (ii) जुलाई, 2013 में सुरक्षा परिषदों के प्रमुखों की चौथी बैठक के लिए वलादोस्तक का (iii) जुलाई, 2013 में द्विपक्षीय बैठक के लिए मास्को की यात्राएं की। रूस सुरक्षा परिषद् के उप सचिव, श्री येवगनी लुकयानोव की यात्रा के दौरान मई, 2013 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा उप–सलाहकार स्तर के संयुक्त समन्वयन समूह की बैठक हुई।

रूस संघ सरकार के उपाध्यक्ष श्री दमित्री रोगोजिन, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगकीय और सांस्कृतिक सहयोग के भारत–रूस अंतर्सरकारी आयोग के सह–अध्यक्ष भी हैं, ने 26 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने भारतीय

सह–अध्यक्ष, विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद के साथ कई विषयों पर चर्चा की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

मार्च, 2013 में मास्को में विदेशी सचिव स्तर और रूस के प्रथम उप विदेश मंत्री के मध्य विदेशी कार्यालय परामर्श हुए और भारतीय पक्ष से इसका नेतृत्व विदेश सचिव, श्री रंजन मथाई और रूस पक्ष से एफडीएफएम श्री एण्ड्री डेनीसोव ने इसका नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (मास्को, फरवरी, 2013); अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा (नई दिल्ली, फरवरी, 2013); मध्य एशिया (मास्को, सितंबर, 2013); शंघाई सहयोग संगठन (मास्को, सितंबर, 2013); राजनयिक संपत्ति मामले (मास्को, सितंबर, 2013) और कौन्सलुर मामले (मास्को अक्तूबर, 2013) के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के मध्य परामर्श हुए।

व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में भारत–रूस संबंधों में प्रगति हुई है। जुलाई, 2013 में कुडनकुलम नाभकीय ऊर्जा संयंत्र यूनिट–I ने की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। व्यापार और आर्थिक सहयोग (सितंबर, मास्को); पर्यटन और संस्कृति (सितंबर, मास्को); सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (सितंबर, मास्को); विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अक्तूबर मास्को); आधुनिकीकरण और औद्योगिकी सहयोग (अक्तूबर, मास्को); प्राथमिकता निवेश परियोजना ऊर्जा (अक्तूबर, मास्को); और ऊर्जा दक्षता (अक्तूबर, मास्को); के कार्यचालन समूहों ने बैठक की। पुनःगठित भारत–रूस सीईओ परिषद् की बैठक 2013 में दो बार हुई दृ"ि में सेंट पीट्सबर्ग में और अक्तूबर में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान मास्कों में। परिषद् ने अवसंरचना विकास, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र में भारत में निवेश के अवसरो की पहचान की।

रक्षा, ऊर्जा, उच्च–प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति हुई है। द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2013 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक विनिमय और लोगों के पारस्परिक संपर्क में बढ़ोत्तरी हो रही है और इस वर्ष 10 रूसी शहरों में भारतीय सांस्कृतिक मेले आयोजित किए गए।

बेलारूस

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय संसदीय दल ने 19–22 मई, 2013 तक बेलारूस की यात्रा की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात के दौरान कई मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

आर्थिक, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–यूक्रेन अंतः–सरकारी आयोग की छठी बैठक 23 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में हुई। अन्य मामलों के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, खाद्य उद्योग और लघु तथा मध्यम उद्योगों में सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जुलाई, 2013 में बेलारूस में अपना पहला पॉवर प्रोजेक्ट, ग्रोडनो थर्मल पॉवर स्टेशन–2 स्थापित किया और यह सफलतापूर्वक चल रहा है।

द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2011 के 547.806 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2012 में 494.431 अमेरिकी मिलियन डॉलर रह गया। यह कमी भारत द्वारा पोटारा के आयात में कमी के कारण आई। वर्ष 2012 में भारत से बेलारूस के निर्यात में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सांस्कृतिक क्षेत्र में मिन्सक में भारतीय मिशन द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य, फैशन शो, योग और आयुर्वेद आदि का प्रदर्शन सहित कई कार्यकलाप आयोजित किए गए।

यूक्रेन

यूक्रेन यूरोपियन संघ के साथ संबद्धता करार स्थगित किए जाने के बाद नवंबर, 2013 में किव के केंद्र में विरोध प्रारंभ हो गया। राष्ट्रपति विक्टर यानूकोविच को पदच्युत किए जाने के बाद किव में हिंसक घटनाओं की भरमार और क्रीमिया की स्थिति में बदलाव के बाद यूक्रेन सरकार बदल गई।

भारत ने यूक्रेन की स्थिति पर 6 मार्च, 2014 में एक वक्तव्य जारी कर सुझाव दिया कि यूक्रेन के आंतरिक मतभेदों का समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यूक्रेन की जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग की आशाएं इससे पूरी हो। वक्तव्य में इस बात पर भी बल दिया गया कि इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण होगा कि समेकित समाज के प्रावधान हेतु साफ–सुथरे चुनावों के माध्यम से वैधानिक गणतंत्रात्मक प्रक्रिया पूरी हो। भारत ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य मामलों को सकारात्मक बातचीत से सुलझाने को सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयास करने की मांग की।

क्रीमिया की स्थिति के संबंध में भारत सरकार ने 18 मार्च, 2014 को देशों की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के मामले पर अपनी दृढ़ स्थिति पर बल दिया। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ दूरभाष पर बात करते हुए यह उम्मीद जताई कि सभी पक्ष संयम से काम लेंगे और क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की वैधानिक आवश्यकताओं की सुरक्षा और यूरोप और अन्य देशों में दीर्घकालीन शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक और राजनयिक हल निकालने के लिए मिलकर सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे।

वर्ष के दौरान भारत और यूक्रेन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता जारी रही। दिसंबर, 2012 में राष्ट्रपति यानूकोविच की राजकीय

यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए कई भारतीय–यूक्रेन संयुक्त कार्यदलों की कई बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं। इसमें शामिल हैं; खाद (20 मार्च, 2013); व्यापार और आर्थिक सहयोग (20–21 मार्च, 2013); पर्यटन (8 अप्रैल, 2013); फार्मास्यूटिकल (15–16 अप्रैल, 2013); और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (22–23 अप्रैल, 2013)/कौंसली परामर्शों का तीसरा दौर मई, 2013 में किव में हुआ जहां भारत ने वीजा सुविधा करार पर जल्द निर्णय की आवश्कता पर बल दिया।

एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउनी के नेतृत्व में एक रक्षा दल ने 14–19 अक्तूबर, 2013 तक किव की यात्रा की। एयर चीफ ने यूक्रेन के प्रथम उप रक्षा मंत्री से बातचीत की और चल रहे कई अनुबंधों और करारों की स्थिति पर चर्चा की। यूक्रेन और भारतीय वायु सेना के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद की अध्यक्षता में 13 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–यूक्रेन अंतः सरकारी आयोग का 5वां सत्र आयोजित किया गया। यूक्रेन के दल का नेतृत्व आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री श्री इहोर माईकोलायोविच परासोलोव ने किया। इस दल में 15 अधिकारी और 12 बिजनेस सदस्य थे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और औषधीय उत्पादों से संबंधित यूक्रेन के राज्य प्रशासन के मध्य फार्मास्यूटिकल और बायो–फार्मास्यूटिकल में संयुक्त उद्यम और अनुसंधान और विकास पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एफआईसीसीआई द्वारा आयोजित बैठक में यूक्रेन उद्यम दल ने भारतीय व्यापारिक समुदाय से सक्रिय बातचीत की। चूंकि भारत से यूक्रेन में जाने वाले उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल का है अतः भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओ और वीजा समस्याएं विचार–विमर्श का बड़ा हिस्ता थी। व्यापारियों और पर्यटकों की आसान आवाजाही के लिए वीजा प्रक्रिया की आसान करने पर दोनों पक्षों ने एक समझौता करने पर सहमति जताई।

डिनी प्रोपेट्रोवसक राज्य के राज्यपाल श्री दमित्री कोलेसमिकोव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अधिकारी दल ने दिनांक 18–22 नवंबर, 2013 तक बंगलुरु की यात्रा की। बंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स और डिनी प्रोपेट्रोवसक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना के 24 अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल ने 20–25 अक्तूबर, 2013 तक यूक्रेन में अध्ययन दौरा किया।

दक्षिण काउकेसस

भारत ने आर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा। इन देशों के साथ व्याापार प्रतिनिधिमंडलों के आवागमन होते रहे।

भारत–जार्जिया अंतरसरकारी आयोग का प्रथम सत्र 29 अप्रैल, 2014 को नई दिल्लीी में आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष की अगुवाई श्री दिनकर खुल्लीर, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय तथा जार्जिया पक्ष की अगुवाई श्री डेविड जालागानिया, उप विदेश मंत्री ने की।"

अर्मेनिया

भारत–अर्मेनिया विदेश कार्यालय परामर्श का सातवां दौर और अंतः सरकारी आयोग का छठा सत्र सितंबर, 2013 में दिल्ली में हुआ।

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक दल ने अक्तूबर, 2013 में आर्मेनिया की यात्रा की। दल ने येरेवान में मेडिकल शिक्षा के मानकों और भारतीय छात्रों के रहन–सहन की स्थितियों मूल्यांकन हेतु सरकारी और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से मुलाकात की।

श्री पवन सिंह घाटोवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाले 8 सांसदों के संसदीय दल ने 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2013 तक आर्मेनिया की यात्रा की।

सितंबर, 2013 में भारतीय दूतावास ने ''थैलीसीमिया'' से पीड़ित 24 युवा बच्चों के लिए सियला की जीवन रक्षक दवाएं दान में दी।

10 सदस्यीय भारतीय आईसीटी दल ने 11–14 दिसंबर, 2013 तक आर्मेनिया का बिजनेस दौरा किया। 24 भारतीय फार्मा कंपनियों वाले प्रथम फार्मास्यूटिकल दल ने 2–5 फरवरी, 2014 तक आर्मेनिया की यात्रा की।

अजरबेजान

कई उच्च स्तरीय दौरों के आदान–प्रदान के माध्यम से भारत के अजरबेजान के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आई। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर 10वीं वार्षिक संसदीय नेटवर्क कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए 24–25 मई, 2013 तक भारत से नौ सदस्यी संसदीय दल ने बाकु की यात्रा की; 24–25 जून, 2013 में छह सदस्ययी अधिकारी दल ने बाकु की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ–सॉउथ ट्रांस्पोर्ट कोरीडोर की 5वीं समन्वय सहयोग परिषद् की बैठक में भाग लिया; और अरजबेजान में सिविल सोसायटी विकास संघ के निमंत्रण पर अजरबेजान में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ऑबजर्वर के रूप में भारत के 20 सदस्यीय संसदीय दल ने 6–10 अक्तूबर, 2013 तक बाकु की यात्रा की।

अजरबेजान के न्याय मंत्री श्री जिकरत मामादोव ने 3–6 अप्रैल, 2013 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान सिविल और

कॉमर्शियल मामलों में पारस्परिक विच्चिक सहायता संधि (एमएलएटी) और क्रिमिनल मामलों पर एमएलएटी पर और प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। श्री एल्मार मामाडेयारोव, विदेश मंत्री ने 2–5 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत और अजरबेजान के विदेश मंत्रालयों के मध्य सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए।

दिनांक 12–15 जनवरी, 2014 तक आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कांफ्रेंस और प्रदर्शनी, पेट्रोटेक–2014 में भाग लेने के लिए श्री नाटिग अलीयेव, ऊर्जा मंत्री ने भारत की यात्रा की।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत–अजरबेजान अंतः सरकारी आयोग का तीसरा सत्र 24–25 फरवरी, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

वर्ष 2013 में अजरबेजान के साथ 1.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 49.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.098 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

जॉर्जिया

भारतीय–जॉर्जिया विदेशी कार्यालय परामर्श का चौथा दौर 15–16 जुलाई तक बेलिसी, जॉर्जिया में आयोजित किया गया।

आईसीसीआर प्रायोजित 15 सदस्यीय दल 'शुगर–एन–स्पाइस' ने 18 सितंबर, 2013 को बेलिसी में कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालय, जॉर्जिया के सहयोग से आयोजित किया गया।

जॉर्जिया में उच्चतर शिक्षा के इच्छुक भारतीय छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक दल ने विशेष रूप से मेडिकल डिग्री की उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का मूल्याकंन करने हेतु अक्तूबर, 2013 में जॉर्जिया की यात्रा की। जॉर्जिया में बड़ी संख्या में भारतीय कृषि और खेती में लगे हुए है।

फार्माएक्सिल द्वारा प्रायोजित प्रथम भारतीय फार्मा दल ने 5–8 फरवरी, 2014 तक जॉर्जिया की यात्रा की।

मध्य एशिया

इस वर्ष मध्य एशियाई देशों के साथ अनेक उच्च स्तरीय बैठकें हुई। दूसरी ट्रैक प्प मध्य एशिया वार्ता अलमाटी, कजाकिस्तान में हुई और यूरेशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुखों का दूसरा मिशन कांफ्रेंस ताशकंद में हुआ। मध्य एशिया क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के साथ मध्य एशिया वार्ता की द्विपक्षीय संस्थागत प्रणाली के अंतर्गत विदेश मंत्रालय ने चीन, रूस और जर्मनी/ईयू से बातचीत की। दिसंबर, 2013 में तुर्की से बातचीत हुई।

प्रभावी सैनिक राजनय के लिए अब मध्य एशिया क पांच राष्ट्रों में प्रत्येक में, रेजिडेंट डिफेंस अटैची नियुक्त किए गए है।

भारत और मध्य एशिया के मध्य कनेक्टिविटी में वृद्धि के लक्ष्य के साथ विदेश मंत्रालय की की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ–सॉउथ कोरीडोर को पुनः प्रारंभ किया गया और कई वर्षों के अंतराल के पश्चात् जून, 2013 में बाकू, अजरबेजान में समन्वय परिषद् की 5वीं बैठक हुई।

कजाकिस्तान

भारत के कजाकिस्तान के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध है। इस्तान्बुल प्रक्रिया की तीसरी मंत्रीय कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 25–27 अप्रैल, 2013 तक अलमाटी की यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव और विदेश मंत्री श्री येरलान इंद्रीसोव से मुलाकात की। कांफ्रेंस के साथ–साथ उन्होंने अन्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की।

इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के साथ आईसीडब्ल्यूए ने 17–18 जून, 2013 तक अलमाटी में दूसरी भारत–मध्य एशिया द्वितीय वार्ता का आयोजन किया। बातचीत के आर्टीमक सत्र की अध्यक्षता श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने की। परिवहन और कनेक्टिविटी पर आधे दिन का सेमिनार भी 18 जून, 2013 को किया गया। कार्यक्रम में सरकार, फ्रेट फारवर्डर, परिवहन कंपनियों, विशेषज्ञों, अकादमियों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 20–21 फरवरी, 2014 तक आयोजित की गई।

सीआईआई द्वारा 27–30 मार्च, 2014 तक आयोजित अब तक के सबसे बड़े ''इंडियो शो'' में लगभग 140 कंपनियों ने भाग लिया।

किर्गिज गणराज्य

वर्ष के दौरान किर्गिज गणराज्य के साथ उच्च स्तरीय दौरौं के आदान–प्रदान में तेजी आई। भारत से निम्नलिखित यात्राएं की गईः

- तुया आशु में काफी ऊंचाई पर स्थित फील्ड स्टेशन के शुभारंभ हेतु डॉ. वी.के. सारस्वत, एसएटूआरएण और सचिव (डिफेंस आरएंडडी), डीजी, डीआरडीओ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय डीआरडीओ प्रतिनिधिमंडल ने 19–24 अप्रैल, 2013 तक किर्गिजस्तान की यात्रा की।

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के छठे अंतः सरकारी आयोग में भाग लेने के लिए डॉ. डागुबाती पुरंदेश्वरी, वाणिज्य राज्य मंत्री और 5 सदस्यीय दल ने 17–19 जुलाई, 2013 तक बिशकेक की यात्रा की। किर्गिज के सह अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री, और श्री ओसमोनबेक आर्टीकबाइव थे। अपनी यात्रा के दौरान मंत्री जी ने किर्गिज के उप प्रधानमंत्री जूमार्ट ओतोबाइव और विदेश मंत्री एरलान आबदेयलदाइव से भी मुलाकात की। यात्रा के

दौरान दूतावासी और आधिकारिक पासपोर्ट वालों के लिए वीजा–फ्री समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए।

- विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 12–13 अक्तूबर, 2013 तक बिशकेक की यात्रा की और विदेश मंत्री एरलान आबदेयलदाइव से मिले तथा राष्ट्रपति अल्माजबेक आत्मबाइव से मुलाकात की। तत्पश्चात् उन्होंने एससीओ सम्मेलन में भाग लिया और साथ ही विदेश मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, मंगोलिया के राष्ट्रपति तसाहिया एलबेगडोर्ग और एससीओ महासचिव, दमित्री फेडेरोविच मेजेनतसेव की द्विपक्षीय वार्ता की।

- पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 20–24 अक्तूबर, 2013 तक ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन फोरम में भाग लिया।

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद के निमंत्रण पर विदेश मंत्री एरलान आबदेयलदाइव ने भारत का सरकारी दौरा किया (13–15 फरवरी)। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ विस्तृत बातचीत की और वे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ई. एम. सुदर्शन नाचिआप्पन से भी मिले। यात्रा के दौरान आपसी कानूनी सहायता पर द्विपक्षीय संधि को कार्यात्मक रूप देने और दस्तावेज तथा आधिकारिक और सेवारत पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा–फ्री यात्रा के करार का विनिमय हुआ।

तजाकिस्तान

उप राष्ट्रपति, श्री एम. हामिद अंसारी ने 14–17 अप्रैल, 2013 तक तजाकिस्तान की राजकीय यात्रा की। उप राष्ट्रपति के साथ श्री तारिक अनवर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री और 4 सांसद गए। यात्रा के दौरान, उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति इमोमाली राहमोन से मुलाकात की और सुरक्षा, विकास भागीदारी, मिलिट्री तकनीकी सहयोग और आतंकवाद सहित कई मामलों पर विचार–विमर्श किया। उप राष्ट्रपति ने संसद की निम्न सभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और आर्थिक विकास मंत्री से भी मुलाकात की। उप राष्ट्रपति खाल्टोन प्रांत भी गए और नुरेक में हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना भी देखी। श्रीमती अंसारी ने दुशानबे के सबसे बड़े अनाथालय को दो मिनी बसें और भारतीय दवाइयां उपहार में दी और महिला खेल क्लब और नूरेक में अस्पताल को एक–एड मिनी बस भेंट की। उप राष्ट्रपति ने घोषणा की कि ताजिक तनकीकी विश्वविद्यालय में आईटी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

रक्षा सहयोग पर जेडब्ल्यूजी ने 10–11 मार्च, 2014 तक दुशान्बे में मुलाकात की।

द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं। आईटीईसी स्लॉट को तजाकिस्तान के लिए 100 से बढ़ाकर 150 प्रति वर्ष कर दिया गया है।

तुर्कमेनिस्तान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली ने तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन् की संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जुलाई, 2013 को अशगाबात की यात्रा की। परियोजना के सदस्य राष्ट्रों ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संघ बनाने का निर्णय लिया। टीएपीआई परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण कदम के रूप में टीएपीआई सदस्य राष्ट्रों और एडीबी द्वारा 19 नवंबर, 2013 को अशगाबाद में ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षकर किए गए।

श्री पवन सिंह घाटोवार, संसदीय कार्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय संसदीय दल ने 26–28 अक्तूबर, 2013 तक अशगाबात की यात्रा की और तुर्कमेनिस्तान के 22वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया।

श्री एक.के. एंटनी, रक्षा मंत्री ने 18 नवंबर, 2013 को अपने ट्रांसिट हॉल्ट के दौरान तुर्कमेनिस्तान के प्रथम उप रक्षा मंत्री से मुलाकात की।

9–11 जुलाई, 2013 को अशगाबात और मैरी में ''तुर्कमेनिस्तान में भारतीय संस्कृति दिवस'' का आयोजन किया गया।

भारत तथा अशगाबात के बीच तुर्कमेनिस्तान में तेल तथा गैस क्षेत्र में कार्यरत लगभग 2000–3000 भारतीयों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए 30 अप्रैल, 2013 को पहला दूतावास परामर्श किया गया।

भारत ने 12–15 नवंबर, 2013 तक आयोजित ईएजी के 19वें सत्र में अगले दो वर्षों के लिए हवाला तथा आतंकवाद निधियन का मुकाबला करने संबंधी यूरेशिया समूह (ईएजी) की अध्यक्षता ग्रहण की।

उज्बेकिस्तान

उप राष्ट्रपति, श्री एम. हामिद अंसारी ने 21–24 मई, 2013 तक उज्बेकिस्तान की यात्रा की उनके साथ पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री, श्रीमती जयंती नटराजन और संसद सदस्य भी गए।

उप राष्ट्रपति ने सीनेट अध्यक्ष ईल्गीजार सोवीरोव तथा स्पीकर ओली मजलिस, डिलोरोम टोसमुखामेडोवा के साथ बैठकों के अलावा राष्ट्रपति करीमोव के साथ मुलाकात की। उज्बेकिस्तान के विदेश आर्थिक संबंध मंत्री, इलयोर गानीव ने उप राष्ट्रपति के साथ भेंट की। अफगानिस्तान तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता, आतंकवाद का मुकाबला, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बैठकों में विचार–विमर्श किया गया। उप राष्ट्रपति

की उपस्थिति में उज्बेकिस्तान के विदेश आर्थिक संबंध मंत्री तथा सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू भारत–उज्बेक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के उन्नयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 13–15 सितंबर, 2013 तक उज्बेकिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान यूरो एशियाई क्षेत्र के मिशनों के प्रमुख के दूसरे सम्मेलन (एचओएमएस) का उद्घाटन किया। उन्होंने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअजीज कामीलो के साथ बैठक की।

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 28–29 नवंबर, 2013 को ताशकंद में सरकार के एससीओ प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

वस्त्र सचिव, श्रीमती जौहरा चटर्जी के नेतृत्व में एक दो सदस्ययी प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद में 16–17 अक्टूबर, 2013 तक कपास एवं वस्त्र मेले में भाग लिया और वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भेंट की।

श्री अखिल कुमार, निदेशक (सीटी), विदेश मंत्रालय ने ताशकंद में 25 अक्तूबर, 2013 को आयोजित एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी ढांचा (आरसीटीएस) की गोलमेज बैठक में भाग लिया।

श्री के.ए.पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव, आणविक ऊर्जा विभाग के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 24–28 सितंबर, 2013 तक उज्बेकिस्तान की यात्रा की जिसके दौरान भारत को उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति के संबंध में आणविक ऊर्जा विभाग तथा नवोई खनिज एवं धातुकर्मी कंपनी (एनएमएमसी) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

2013 में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से आंशिक रूप से बढ़कर 260 मिलिनय अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत से आयात की मुख्य मदों में दवा तथा औषधि, कागज और लकड़ी के उत्पाद, रसायन तथा प्लास्टिक, चाय इत्यादि हैं। 2013 में भारतीय निर्यात 2012 के 163.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 217.4 मिलियन अमेरिक डॉलर हो गया। भारतीय आयात में मुख्यतः रसायन तथा अलौह धातुएं और फलियां शामिल हैं।

खाड़ी तथा पश्चिम एशिया

5

खाड़ी देश

भारत के सभ्यता संबंधों के आधार पर खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ पारंपरिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। मित्रता संबंधों को राजनीतिक, व्यापार तथा वाणिज्यिक स्तर पर यात्राओं के नियमित आदान–प्रदान द्वारा और सुदृढ़ किया गया। खाड़ी क्षेत्र विश्व में भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र बन गया है और 2012–13 में द्विपक्षीय व्यापार 181.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। खाड़ी क्षेत्र भारत को कच्चे तेल और एलएनजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है तथा भारत का कच्चे तेल का आयात 60 प्रतिशत से अधिक है। भारत के सर्वोच्च पांच तेल स्रोत देशों में से चार खाड़ी क्षेत्र–सऊदी अरब, इराक, कुवैत तथा यूएई से हैं। खाड़ी देशों में लगभग 7 मिलियन भारतीय रहते है जो अपने मेजबान देशों के विकास में योगदान देते है।

बहरीन

शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, युवराज तथा उप सुप्रीम कमांडर, बहरीन अधिराज्य राज्य ने 17–18 मार्च, 2013 को केरल राज्य की यात्रा की।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर सुलतान हमद बिन ईशा अल खलीफा ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 18–20 फरवरी, 2014 को भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। उच्च संयुक्त आयोग की स्थापना, युवा एवं खेल के क्षेत्र में सहयोग तथा विदेश सेवा संस्थान एवं बहरीन राजनयिक संस्थान के बीच सहयोग संबंधी 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा ने हमारे मित्रवत और बहु–आयामी संबंधों को नई गति प्रदान की।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ई.अहमद ने 4–6 जून, 2013 को बहरीन की यात्रा की। उन्होंने बहरीन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ संयुक्त रूप से 22–24 अक्टूबर, 2013 को ''बहरीन–भारत प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन'' में भाग लेने तथा तदंतर 25 नवंबर, 2013 को 12वें एशियाई सहयोग वार्ता (एसीडी) विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बहरीन की पुनः यात्रा की।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने ''मनामा वार्ता'' वार्षिक क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नौवें सत्र में भाग लेने के लिए 6–9 दिसंबर, 2013 को बहरीन की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने बहरीन के सर्वोच्च नेताओं के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की।

ईरान

भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों देश उच्चतम स्तर पर परामर्श करते है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा मांग में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र ईरान के साथ द्विपक्षीय सहयोग का महत्वपूर्ण पहलू है।

इस अवधि के दौरान भारत तथा ईरान के बीच प्रमुख उच्च स्तरीय आदान–प्रदान/संपर्क में निम्नलिखित शामिल थेः

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के निमंत्रण पर डॉ. सईद जलीली, सचिव, ईरान सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने 2–4 जनवरी, 2013 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भेंट की। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय और ईरान की सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- लोकसभा की स्पीकर के निमंत्रण पर ईरान की मजलिस के स्पीकर डॉ. अली अर्दाशीर लारीजानी ने 24–28 फरवरी, 2013 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तथा स्पीकर तथा विदेश मंत्री के साथ भेंट की। ईरान के स्पीकर की यात्रा के दौरान भारत–ईरान संसदीय मैत्री समूह की एक बैठक भी आयोजित की गई।
- विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने भारत–ईरान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के 17वें सत्र के लिए 3–5 मई, 2013 को तेहरान की यात्रा की। विदेश मंत्री ने ईरान के पूर्व विदेश मंत्री डॉ. अली अकबर सालेही के साथ बैठक की सह–अध्यक्षता की। जेसीएम के दौरान दोनों पक्षों ने 3 समझौता ज्ञापनों अर्थात् (i) ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के मानक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय मानक ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन, (ii) विदेश सेवा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय

संबंध स्कूल, ईरान के बीच समझौता ज्ञापन तथा (पपप) जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. महमूद अहमदीनेजाद से मुलाकात की और मजलिस स्पीकर डॉ. अली लारीजानी तथा डॉ. अली अकबर विलायती, सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार के साथ भेंट की। इस यात्रा के दौरान तेहरान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का विदेश मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया।

- उप राष्ट्रपति, श्री एम. हामिद अंसारी ने नव निर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति डॉ. हसन रुहानी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 4 अगस्त, 2013 को तेहरान की यात्रा की।
- पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, श्री रोस्तम गासेमी ने 27–28 मई, 2013 को भारत की यात्रा की और श्री वीरप्पा मोईली, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ वार्ता की।
- ईरान के एशिया तथा प्रशांत उप विदेश कार्य मंत्री, श्री इब्राहीम रहीमपोर ने विदेश सचिव के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों के आयोजन के लिए 25 नवंबर, 2013 को भारत की यात्रा की।
- ईरान के विदेश मंत्री, मोहम्मद जावेद जारीफ ने 27–28 फरवरी, 2014 को भारत की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकें की।

इराक

भारत तथा इराक के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ तथा बहु–आयामी संबंधों को वर्ष के दौरान कई उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान–प्रदान के द्वारा और मजबूत किया गया।

इराक के प्रधानमंत्री श्री नूरी अल मालीकी ने 22–25 अगस्त, 2013 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय तथा इराक के विदेश मंत्रालय के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग तथा जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में 19–20 जून, 2013 को श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री की इराक यात्रा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉ. वीरप्पा मोईली द्वारा 8–9 जुलाई, 2013 को बगदाद में आयोजित भारत–इराक संयुक्त आयोग की बैठक की सह–अध्यक्षता शामिल थी।

इराकी पक्ष की ओर से जल संसाधन मंत्री, श्री मोहानद सलमान अल–सादी ने 19–24 मई, 2013 को भारत की यात्रा की। ऊर्जा मामलों के लिए इराक के उप प्रधानमंत्री, श्री हुसैन इब्राहिम सालेह अल–शहरिस्तानी ने आईआईएसएस द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14–15 अगस्त, 2013 को भारत की यात्रा की। श्री फालेह अल–फयाद, इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय समकक्ष के साथ सरकारी विचार–विमर्श करने के लिए 18–21 दिसंबर, 2013 को भारत की यात्रा की।

इराक 2012–13 में भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। क्षमता निर्माण के संदर्भ में भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत 80 स्लॉट तथा भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए 55 स्लॉट प्रदान किए।

इजरायल

एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन, वायु सेना अध्यक्ष ने द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 19–24 जनवरी, 2013 को इजरायल की यात्रा की।

भारत–इजरायल मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्ता का छठा दौर इजरायल में 20–23 जनवरी, 2013 को आयोजित किया गया। इजरायल के प्रमुख वैज्ञानिक श्री अवी हसन ने जारी द्विपक्षीय आरएंडडी सहयोग तथा संयुक्त निधियन कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 28–30 जनवरी, 2013 को भारत की यात्रा की।

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 26 अप्रैल से 1 मई, 2013 तक इजरायल की यात्रा की। उन्होंने इजरायल के कृषि मंत्री, श्री यायर शमीर के साथ भेंट की।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने 15–18 जून, 2013 को इजरायल की यात्रा की और इजरायल के संचार मंत्री, वित्त मंत्री तथा आर्थिक कार्य मंत्री के साथ मुलाकात की। मंत्री ने यह घोषणा की कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में संयुक्त औद्योगिक आरएंडडी का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग से एक संयुक्त निधि की स्थापना करेगा।

भारत से एक 29 सदस्यीय बहुक्षेत्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन, कृषि, आईटी, आंतरिक सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए फिक्की के तत्वावधान में 27–31 जुलाई, 2013 को इजरायल की यात्रा की।

श्री फ्रांस्सिको डीसूजा, गोवा के उप मुख्यमंत्री और दिलिप पारूलेकर, गोवा के पर्यटन मंत्री ने एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 20–25 अक्तूबर, 2013 को इजरायल की यात्रा की। उन्होंने इजरायल के पर्यटन मंत्री के साथ पर्यटन में सहयोग की संभावनाओं पर विचार–विमर्श किया।

भारत–इजराइल एफटीए के बीच बातचीत का सातवां और आठवां चरण क्रमशः दिल्ली और येरूशलम में 25–27 जून, 2013 और 24–26 नवम्बर, 2013 को आयोजित किया गया था।

मई, 2013 में भारत और इजराइल ने पांच वर्ष के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान करते हुए संयुक्त अनुसंधान कोष आरम्भ किया। पहला चरण (2013–14) गणितीय विज्ञान तथा मानविकी पर केन्द्रित होगा। यह कोष तीन वर्षें तक प्रायोगिक परियोजना के लिए 3,00,000 अमरीकी डॉलर तक अथवा सैद्धांतिक परियोजना के लिए 1,80,000 अमरीकी डॉलर से लगभग 50 सहकार्यों को सहायता देगा। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा इजराइल साइंस फाउण्डेशन इस कोष का संचालन करेंगे।

भारतीय दूतावास ने इजराइल में 'टीमवर्क प्रॉडक्शंस इंडिया' के सहयोग से भारत की शास्त्रीय और समकालीन सांस्कृतिक परम्परा दर्शाते हुए अप्रैल–मई, 2013 में भारत–महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया।

इजराइल में भारतीय यहूदियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन राम्ले, इजराइल में 23 सितम्बर, 2013 को आयोजित किया गया था जिसमें भारत के चार प्रमुख यहूदी समूहों ने अनुमानतः 5,500 लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने उन्हें प्रदर्शनियों, संस्कृति व खानपान आदि के जरिए अपनी भारतीय परम्परा मनाने का साझा मंच उपलब्ध कराया।

डॉ. टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इज़राल के साथ प्रस्तावित 40 मिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) कोष पर चर्चा करने के लिए 21–22 जनवरी, 2014 के दौरान इजराइल की यात्रा की।

संयुक्त आसूचना समिति (जेआईसी) के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने जेआईसी के अध्यक्ष श्री अजित लाल के नेतृत्व द्विपक्षीय परामर्श के लिए 11 से 15 मार्च, 2014 तक इजराइल की यात्रा की।

11 मार्च, 2014 को तेल अवीव में रक्षा कार्मिकों की अधिकारी स्तर की वार्षिक बैठक हुई जिसमें सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने 17–20 मार्च, 2014 को भाग लिया। जनरल सिंह ने रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ तथा कमांडर ऑफ ग्राउंड फ़ोर्सेज से मुलाकात की।

भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सचिव डॉ. सुतानु बेहुरिया ने 26 से 29 मार्च, 2014 तक इजराइल की यात्रा की तथा इजराइल विद्युत निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

जॉर्डन

जॉर्डन स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर भारत के निर्वाचन आयोग के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने वहां 23 जनवरी, 2013 के संसदीय चुनावों के प्रत्याशियों की सूची तैयार करने के लिए जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण की तैयारी में सहायता देने के लिए 2 से 10 जनवरी, 2013 तक जॉर्डन की यात्रा की।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ''द जॉर्डन टाइम्स'' की वरिष्ठ पत्रकार सुश्री अबीर न्यूमेन ने आइफ़ेक्स (भारतीय औषधीय एवं स्वास्थ्य रक्षा प्रदर्शनी) में भाग लिया जिसे फार्मेक्सिल ने 24 से 26 अप्रैल, 2013 को मुम्बई में आयोजित किया था। जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कम्पनी (जेपीएमसी) के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) द्वारा 11–13 दिसम्बर, 2013 को आयोजित 49वें वार्षिक सेमिनार में भाग लिया। जॉर्डन के शिष्टमंडल का नेतृत्व जेपीएमसी के अध्यक्ष श्री अमेर अल मजाली ने किया। 3–6 जून, 2013 के दौरान अम्मान में आयोजित 10वें इंटरनेशनल मशीन्स एण्ड इलेक्ट्रो–मेकेनिकल एग्जिबीशन–जेआईएमईएक्स–2013 में सोलह भारतीय इंजीनियरिंग कम्पनियों ने सहभागिता की। इन कम्पनियों ने ईईपीसी–इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद) के सान्निध्य में ''भारतीय पेवेलियन'' में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री इ. अहमद ने 2–3 जुलाई, 2013 तक जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा की और द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से आर्थिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ–साथ क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय विकास से संबंधित सभी मामलों पर विचार–विमर्श किया।

रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री श्रीकांत के जेना ने 8–11 जुलाई, 2013 तक जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने 9 जुलाई, 2013 को प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एन्सूर, व्यापार व उद्योग मंत्री हतेम हलावानी और ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्री मलिक कबाराती से मुलाकात की। दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर फॉस्फेट (इस समय फास्फोरिक अम्ल उत्पादन में संयुक्त उपक्रम चल रहे हैं) क्षेत्र में, को बढ़ाने पर सहमत हुए।

कुवैत

वर्ष के दौरान बड़ी तादाद में परस्पर उच्चस्तरीय दौरों से भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ व मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ना जारी रहा।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आमंत्रण पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जबर अल–मुबारक अल–हमद अल–सबा ने उपप्रधानमंत्री (डीपीएम) व विदेश मंत्री शेख सबा खालिद अल–हमद अल–सबा (डीपीएम) तथा तेलमंत्री श्री मुस्तफ़ा जस्सीम अल–शिमाली, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अनस खालिद अल–सालेह, वरिष्ठ अधिकारियों और 14 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधियों के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 7–10 नवम्बर, 2013 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान सजायाफ्ता लोगों के

हस्तांतरण पर विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) और सउद एन. अल–सबा कुवैत डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट के बीच समझौता–ज्ञापन, खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग के समझौता–ज्ञापन, सांस्कृतिक व सूचना विनियम कार्य–निष्पादन कार्यक्रम (2013–16) तथा शिक्षा व अधिगम में सहयोग के शैक्षिक आदान–प्रदान (2013–16) के करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अमीरी दीवान मामलों के मंत्री शेख नस्सर अल–अहमद अल–सबा ने 10–13 मार्च, 2013 तक भारत की यात्रा की। शेख नस्सर की यात्रा के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 1–3 जुलाई, 2013 तक कुवैत की यात्रा की।

विदेश राज्यमंत्री श्री इ. अहमद ने कुवैत में 15 जनवरी, 2014 को सीरिया के लिए आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सदभावना सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुवैत की यात्रा की। उन्होंने 6–7 जुलाई, 2013 को भी कुवैत की यात्रा की।

इस अवधि के दौरान अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में 20–22 मई, 2013 के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के शिष्टमंडल, 25–26 मई, 2013 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के प्रतिनिधिमंडल; 29–30 अक्टूबर, 2013 की फिक्की के प्रतिनिधिमंडल; कुवैत में 10–11 नवम्बर, 2013 को आयोजित चिकित्सा–सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल; 10 नवम्बर, 2013 को कुवैत पेट्रोलियम निगम के शिष्टमंडल तथा 12–13 नवम्बर, 2013 को हमारे सचिव (विनिवेश) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल की यात्रा शामिल है।

हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहाकार ने 8–9 अक्टूबर, 2013 को कुवैत की यात्रा की। इसके बाद नेशनल सिक्युरिटी एपरेटस ऑफ कुवैत के अध्यक्ष शेख थामर अली सबा अल–सलेम अल–सबा ने 17–19 फरवरी 2014 तक भारत का दौरा किया।

भारतीय नौवहन पोत आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश ने 10–13 सितंबर, 2013 को कुवैत की सदभावना यात्रा की।

कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च (केआईएसआर) के महानिदेशक डॉ. नाजी एम. अल–मुतैरी ने 18–22 नवम्बर, 2013 को भारत की यात्रा की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सहयोग के कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विशेष कुवैत प्रकोष्ठ

विशेष कुवैत प्रकोष्ठ (एसकेसी) खाड़ी युद्ध (1990–91) के प्रत्यर्पियों के क्षतिपूर्ति–दावों का निपटान करने के लिए स्थापित किया गया था। सभी वैध दावे पहले ही निपटा दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग (यूएनसीसी) अपने दावे संवितरण परिचालन बंद कर चुका है और भारतीय दावेदारों का कोई दावा बकाया नहीं है।

लेबनान

विदेश राज्यमंत्री श्री इ. अहमद ने 30 जून से 2 जुलाई, 2013 तक लेबनान की यात्रा की तथा लेबनान की सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं, समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और परस्पर हितों के क्षेत्रीय व वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। इस क्षेत्र में बढ़े हुए विनिमयों को सरल बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक द्विपक्षीय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वाना) श्री संदीप कुमार 27 दिसम्बर, 2013 को दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) की भारतीय बटालियन देखने गए। भारतीय बटालियन में इस समय 863 भारतीय टुकडियां और 11 चिकित्सक सेवारत हैं।

श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए 28–29 मार्च, 2014 को लेबनान गए। वे लेबनान के संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में प्रतिनियुक्त भारतीय सैन्य–टुकड़ी (आईएनडीबीएटीटी) से भी मिले।

ओमान

सात सौ हजार से भी अधिक भारतीयों के ओमान में जनसम्पर्क के सम्पर्कों के महत्व पर पर्याप्त मात्रा में योगदान से राजनीतिक दृष्टि से ठोस संबंध और बढ़ा है।

भारत–ओमान संसदीय मैत्री समूह की पहली बैठक के लिए 11 सदस्यीय ओमानी संसदीय शिष्टमंडल 22–26 अप्रैल, 2013 के दौरान भारत दौरे पर आया। विदेश मंत्री के आमंत्रण पर विदेश मामलों के ओमानी मंत्री युसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला भारत आए और उन्होंने 28 फरवरी, 2014 को आधिकारिक विचार–विमर्श किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा उप–सलाहकार श्री नेहचल संधु ने 21–22 अक्टूबर, 2013 को ओमान की यात्रा की। श्री अनिल वधवा सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने 20–21 जनवरी, 2014 को ओमान की आधिकारिक यात्रा की।

नौसेना प्रमुख के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 13–16 अप्रैल, 2013 को ओमान की यात्रा की तथा भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के शिष्टमंडल ने 9–11 सितम्बर, 2013 को ओमान की यात्रा की। भारत और ओमान ने 23 से 26 सितम्बर, 2013 तक ओमान के सागर में अपने द्विवार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास नसीम–अल–बहर

(सी ब्रीज) का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयरफोर्स द्विवार्षिक संयुक्त एयर अभ्यास अल जिस्र अल शर्की (ईस्टर्न ब्रिज) किया। ओमान के कमांडेंट नेशनल डिफेंस कॉलेज के 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 27 अप्रैल से 2 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की। सातवीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक 29–30 जनवरी, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

19–29 मई, 2013 तक भारत दौरे पर आए शिष्टमंडल का नेतृत्व पब्लिक अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डॅव्लप्मेंट ऑफ ओमान (पीएआईपीईडी) के अध्यक्ष ने किया। एक ओमानी व्यापार शिष्टमंडल ने कोची, कोझिकोड, चेन्नई और मुम्बई की सितम्बर–अक्टूबर, 2013 में यात्रा की और मिश्रित विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रतिनिधमंडल 9–13 जून तथा 21–25 अक्टूबर, 2013 के दौरान भारत आए। सीआईआई और एफआईईओ ने व्यापार के अवसरों का पता लगाने और व्यापार–प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए 10–15 सितम्बर, 2013 और 23–24 सितम्बर, 2013 के दौरान व्यापार–प्रतिनिधमंडलों के साथ बैठकें कीं। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने चिकित्सा उपकरणों के स्रोत और मानव–श्रम की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा भारत में चिकित्सा निदान के सम्भाव्य समझौते के लिए 15–22 मार्च, 2014 के दौरान अनेक शहरों का दौरा किया। ओमान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 17 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 23–27 मार्च, 2014 के दौरान सम्भाव्य समझौते, विशेषरूप से एसएमई के क्षेत्र में, के लिए बंगलौर का दौरा किया।

कृषि–क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्य–योजना के अनुसरण में हस्ताक्षर के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनेक दौरे किए गए। भारत और ओमान ने दोनों ओर के नए गंतव्यों को कवर करने के लिए नई उड़ानें बढ़ाई हैं जबकि, स्पाइस जेट एयरलाइंस ने ओमान के लिए अपनी सेवाएं शुरू भी कर दी हैं। ओमान के नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी के अधिकारियों ने जून, 2013 और मार्च, 2014 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) का दौरा किया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) के महानिदेशक ने 30–31 दिसम्बर, 2013 को ओमान का दौरा किया और अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग की कार्य–योजना पर मार्च, 2014 में हस्ताक्षर किए गए। ओमान के धोफ़ार विश्वविद्यालय के कुलपति ने 26–28 अगस्त, 2013 को दिल्ली, मुम्बई और बेंगलुरू का दौरा किया तथा भारत की कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

फिलीस्तीन

भारत ने इजरायल और फिलीस्तीन के बीच नौ माह की समय–सीमा के साथ जुलाई, 2013 में यूएस की मध्यस्थता से शुरू हुई शांति वार्ता का स्वागत किया।

विदेश राज्यमंत्री श्री ई.अहमद ने 2 जुलाई, 2013 को अम्मान में फिलीस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात की। वे 4–6 जुलाई, 2013 को फिलीस्तीन भी गए और उन्होंने सभी फिलीस्तीनी नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा सितम्बर, 2012 में फिलीस्तीन को दिए गए बजटीय सहयोग के प्रतिभूत के भाग के रूप में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चैक प्रधानमंत्री श्री रामी हम्दल्लाह को सौंपा गया।

भारत ने जून, 2013 में फिलीस्तीन में दो स्कूलों के निर्माण और साज–सज्जा के लिए 1.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के रूप में 0.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जारी की। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्लूए) के महाआयुक्त श्री फिलिपो ग्रांडी 3–4 सितम्बरए 2013 को विदेश मंत्रालय के साथ मानवीय सहायता कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भारत आए। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएनआरडब्लूए के सहायता कार्यक्रम के लिए वर्ष 2013 के यूएनआरडब्लूए को भारत सरकार के अंशदान के भाग के रूप में एक मिलयन अमेरिकी डॉलर का चैक महाआयुक्त को भेंट किया गया।

25 सितम्बर, 2013 को भारत के प्रतिनिधि कार्यालय रमाल्लाह ने अपने कार्यालय से वीजा जारी करना आरम्भ किया।

भारतीय पर्यटन मंत्रालय की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती रोमा सिंह ने फिलीस्तीन की यात्रा की और फिलीस्तीन में भारत के प्रतिनिधि श्री बी.एस.मुबारक के साथ फिलीस्तीन के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों से मिलीं तथा भारत और फिलीस्तीन के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की।

सऊदी अरब

भारत के सऊदी अरब के शताब्दियों पुराने आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक गठजोड़ से प्रभावित सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वर्ष के दौरान दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा व सुरक्षा सहयोग की दिशा में तेजी से प्रगति की है। सऊदी अरब में 2.9 मिलियन से भी अधिक भारतीय रहते हैं जो विदेश में सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है। किंग्डम भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति भी करता है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार का साझीदारी बना है और 2012–13 में दोनों ओर का व्यापार 43.78 बिलियन तक बढ़ा है।

प्रिंस सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सउदए क्राउन प्रिंसए उप प्रधानमंत्री और सऊदी अरब किंग्डम के रक्षामंत्री ने 26–28 फरवरी, 2014 को भारत की अधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशमंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 24 से 27 मई, 2013 तक सऊदी

अरब की यात्रा की। 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए वित्तमंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने 27–28 जनवरी, 2014 को सऊदी अरब का दौरा किया।

9वें संयुक्त आयोग की दूसरी समीक्षा बैठक 5–7 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में हुई। सऊदी अरब के शिष्टमंडल का नेतृत्व विधि एवं विनियम मामलों तथा विदेश व्यापार उपमंत्री डॉ. फहद अबुहिम्द ने किया।

सऊदी अरब के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मामलों के उपमंत्री डॉ. अहमद बिन फहद अल फुहिद श्रम मामलों पर जे डब्ल्यू जी की 30–31 मईए 2013 को आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए। घरेलू सेवा में कामगारों की भर्ती में श्रम–सहयोग के करार पर हस्ताक्षर के लिए सऊदी श्रम मंत्री इंजीनियर अब्देल बिन मोहम्मद फाकेह ने 1–4 जनवरी, 2014 को भारत यात्रा की। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स, एन्डॉवमेंट, कॉल गाइडेंस मंत्री शेख सालेह बिन अब्दुल अजीज अलशेख 15–20 फरवरी, 2014 के दौरान भारत के दौरे पर आए।

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण दौरों में 27–30 अप्रैल, 2013 के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री व्यालार रवि के साथ विदेश राज्यमंत्री श्री ई.अहमद तथा प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री टी.के.ए नायर की यात्रा, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री गुलाम हुसैन एस्साजी वाहनवती की 14–21 मई, 2013य प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव की 03 जुलाई, 2013 तथा विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) की हज–व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु 29 अगस्त, 2013 को की गई यात्राएं शामिल हैं।

रियाद स्थित भारतीय दूतावास और भारतीय महावाणिज्य दूतावासए जेद्दाह दोनों पवित्र मस्जिदों के परिरक्षक किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा अनुग्रह अवधि के दौरान घोषित रियायतों का उपभोग कर रहे सऊदी अरब राज्य में अधिक समय तक टिकने वाले भारतीयों की कानूनी स्थिति के सुधार के लिए बड़े अभियान में जुट गए। समूचे सऊदी अरब में दूतावास की सहायता के लिए 600 से भी अधिक पंजीकृत बिना पारिश्रमिक के स्वयं सेवकों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर, 2013 के अंत तक अनुग्रह अवधि के दौरान 1–4 मिलियन से अधिक भारतीयों ने रियायतों का उपभोग किया जिनमें 434667 वे भारतीय शामिल हैं जिन्होंने अन्य फर्मों में अपनी सेवाएं बदलवा दी हैं, 481233 वे भारतीय जिन्होंने अपना कार्य/व्यवसाय बदल दिया है और 470000 वे भारतीय जिन्होंने अपने लाइसेंस/जॉब परमिट नवीनीकृत कराए हैं। अनुग्रह अवधि में 1,34,281 भारतीय अंतिम रूप से निकल चुके हैं इसमें वे शामिल हैं जिन्होंने छूट का लाभ लिया है और दूसरे वे भी शामिल हैं जो अपनी अनुबंध–अवधि खत्म होने पर देश छोड़ चुके हैं। इस अवधि में 52,820 आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

वर्ष के दौरान अन्य प्रतिनिधिमंडल, मई, 2013 में पर्यटन मंत्रालय के सचिव, 15–18 सितम्बर, 2013 को रियाद में आयोजित 'सऊदीएग्रो फूड 2013' प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग के 40 प्रतिनिधियों के साथ आईटीपीओ के प्रतिनिधमंडल तथा 4–7 नवम्बरए 2013 को रियाद में आयोजित ''सऊदीबिल्ड'' 2013 प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए की गई सीआईआई शिष्टमंडल की यात्रा शामिल हैं।

कतर

इस वर्ष भारत और कतर के बीच बहुपक्षीय विनियोजन और सहयोग और अधिक बढ़ा है।

शेख तमीम बिन हमद अल थानी को उनके 25 जून, 2013 को कतर के अमीर का पद सम्भालने, शेख अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानीए प्रधानमंत्री व कतर के आंतरिक राज्यमंत्री बनने और कतर के विदेश मंत्री नियुक्त होने पर डा. खालिद बिन मोहम्मद अल अनिया को बधाई संदेश भेजे गए।

इस वर्ष के महत्वपूर्ण दौरों में 18–19 मई, 2013 का वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरमय दोहा में 1–3 अक्टूबर, 2013 को आयोजित मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की द्विपक्षीय कांफ्रेंस व 18वीं बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अगुवाई में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल का दौरा शामिल है। मानव संसाधनों पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 30–31 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

कतर सरकार के आर्थिक एवं वाणिज्य मंत्रालय के अवर सचिव सुल्तान बिन राशिद अल खतर की अगुवाई में 18 सदस्यीय उच्च स्तरीय संयुक्त शिष्टमंडल ने 25–26 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया। आगंतुक प्रतिनिधमंडल ने सीआईआई द्वारा आयोजित ''भारतकतर व्यापार मंच'' तथा फिक्की द्वारा आयोजित बिजनेस इवेंट में सहभागिता भी की।

नवम्बर, 2008 में दोहा में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग करार को पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े आईएनएस तबर और आईएनएस आदित्य दो पोतों ने 10 से 13 सितम्बर, 2013 तक कतर की यात्रा की और उसके बाद 15–16 सितम्बर, 2013 को दोहा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। एक तीन सदस्यीय दल ने 6–9 अप्रैल, 2013 के दौरान दोहा का दौरा किया।

एसोचेम ने मई, 2013 में दोहा में अवसंरचना क्षेत्र की एक बड़ी प्रदर्शनी कतर परियोजना में 30 से अधिक भारतीय कम्पनियों की

सहभागिता समन्वित की। सीआईआई व फिक्की ने क्रमशः सितम्बर, 2013 और अक्टूबर, 2013 में व्यापार मिशन कतर भेजा।

सीरिया

सीरिया सरकार व विद्रोहियों के बीच राजनीतिक गतिरोध, विद्रोहियों में इस्लामी चरमपंथियों के भारी प्रवेशय गहराई तक छिन्न–भिन्न विपक्षय विद्रोहियों के कुछ तबकों को शह देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों द्वारा विवादास्पद फैसलेय शिया–सुन्नी बिखराव की उत्तेजना के साथ–साथ सुरक्षा और मानवता की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण जनयुद्ध के घेरे में घिरा हुआ है। दूसरी दो चरणों की जेनेवा वार्ता (15 फरवरी, 2014) बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई।

विदेश राज्यमंत्री श्री इ.अहमद ने सीरिया के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी शपथ सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई की। भारत ने सीरिया के लोगों को जीवन–रक्षक दवाइयों, भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में मानवीय सहायता के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रतिभूत की है।

राजनीतिक तथा मीडिया सलाहकार और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल अस्सद (पीबीए) की विशेष दूत सुश्री बाउथैना शाबन 5–9 मार्च, 2013 को भारत आईं। उन्होंने विदेशमंत्री, विदेश राज्यमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित पीबीए का पत्र दिया जिसमें भारत, ब्रिक्स और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जेनेवा विज्ञप्ति लागू करने के लिए दबाव डालने के लिए समर्थन मांगा गया जिसमें सीरिया के संकट के समाधान के सभी तत्व हैं। वे 20–22 नवम्बर, 2013 को फिर भारत आईं और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) को सीरिया के हालिया बदलावों, इनके इस क्षेत्र में प्रभाव और जेनेवा–II के संयोजन की संभावना से अवगत कराया।

भारत ने सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने तथा अन्य संबंधित सुविधाओं के उपयोग के लिए ओपीसी डब्ल्यू में स्थापित न्यास निधि में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय अंशदान प्रतिभूत किया। भारत ने रासायनिक हथियारों के विनाशए अधिप्रमाणन व प्रशिक्षण कार्यकलापों में अपने विशेषज्ञों की सेवाएं देने की पेशकश भी की।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वाना) श्री संदीप कुमार ने 24–26 दिसम्बर, 2013 को दमिश्क का दौरा किया और सीरिया के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

विदेश राज्यमंत्री ने 15 जनवरी, 2014 को कुवैत में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्लजिंग सम्मेलन में भाग लिया और सीरिया के लिए अपने मानवतावादी कार्यक्रम के समर्थन में यूएन–सीरियन ह्यूमेनीटेरियन असिस्टेंस रेस्पांस प्लान (एसएचएआरपी/शार्प) को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिभूत किए।

विदेश मंत्री ने 22 जनवरी, 2014 को मांट्रेक्स, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित जेनेवा–II के मंत्री स्तरीय खण्ड में सहभागिता की। अपने वक्तव्य में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सीरिया के संघर्ष पर सभी पक्षों से हिंसा खत्म करने का अनुरोध करता है ताकि, एक समावेशी राजनीतिक संवाद के लिए वातावरण बनाया जा सके जो सीरिया के लोगों की वैद्य आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक राजनीतिक समाधान की दिशा में ले जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इसके लिए अपेक्षित किसी भी तरीके से शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और अपनी व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत है। सम्मेलन से हटकर विदेश मंत्री यूएसए डेनमार्क, फ्रांसए इटली, जॉर्डन और जापान के अपने समकक्षों से भी मिले।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध परम्परागत रूप से घनिष्ठ व मैत्रीपूर्ण रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात 2012–13 में दोतरफा व्यापार में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार साझेदार था। संयुक्त अरब अमीरात अनुमानतः 2 मिलियन भारतीय लोगों का घर है।

भारत–यूएई संयुक्त आयोग के क्रमशः 18 फरवरी, 2013, 18 मार्च, 2013 और 17–18 जून, 2013 को हुए दसवें अधिवेशन के अनुवर्तन में तीन बैठकों की तीन महत्वपूर्ण क्रियाविधियां नामतः (i) निवेश पर भारत–यूएई उच्चस्तरीय कार्यबल (एचएलटीएफआई), (ii) सुरक्षा मामलों की संयुक्त समिति (जेसीएसएफ) और (iii) कांस्युलर मामलों की संयुक्त समिति (जेसीसीएफ) गठित की गई। एचएलटीएफआई की मुम्बई में 3 मार्च, 2014 को हुई दूसरी बैठक में द्विपक्षीय निवेश–स्तर बढ़ाने पर सहमति हुई। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की छठी बैठक 27–28 अक्टूबर, 2013 को अबुधाबी में हुई।

इस वर्ष मंत्री स्तरीय महत्वपूर्ण दौरे हुए जिनमें विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद (13 मार्च, 2013); विदेश राज्यमंत्री श्री इ.अहमद (18–20 जनवरी 2013); वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा (18 फरवरी, 2013), वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम (23 मार्च और 26 मई, 2013)य नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी (16–19 अप्रैल, 2013); नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अजित सिंह (28 अप्रैल से 2 मई, 2013); पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोइली (9–11 नवम्बर, 2013); प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि (27–28 अक्टूबर, 2013); पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोइली (9–11 नवंबर, 2013); नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला (18–24 जनवरी, 2013) के दौरे शामिल हैं।

यूएई पक्ष के महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय दौरों में विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नहायन (12 दिसम्बर, 2013); अर्थव्यवस्था मंत्री सुल्तान बिन सईद अल मंसूरी (27–29 जनवरी, 2014 को बेंगलुरू का दौरा); ऊर्जा मंत्री सुहैल बिन मोहम्मद फराज अल मज़रूई (जनवरी, 2014)य और अबूधाबी क्राउन प्रिंस कोर्ट के अध्यक्ष शेख अहमद बिन ज़ायेद अल नहियन (3 मार्च, 2014) का दौरा शामिल है।

सज़ायाफ्ता व्यक्तियों पर द्विपक्षीय करार पर कार्रवाई की गई और इसे भारत व यूएई दोनों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बीआईपीपीए) पर 12 दिसम्बर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। भारत की जेट एयरवेज और यूएई की एतिहाद एयरवेज के बीच करार पर आबूधाबी में अप्रैलए 2013 में हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय नौसेना युद्ध पोतों के एक बेड़े ने सितम्बरए 2013 में यूएई की सदभावना यात्रा की। भारतीय तटरक्षक पोत– आईसीजीएस 'समुद्र प्रहरी' और दस भारतीय कम्पनियों ने 17–21 फरवरी, 2013 को अबूधाबी में आयोजित आइडेक्स–नेवेक्स में सहभागिता की।

खाड़ी क्षेत्र के प्रवासी भारतीयों के लिए महात्मा गांधी सुरक्षा योजना पेंशन, जीवन बीमा और पुनर्वास योजना भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय द्वारा दुबई में 27–28 अक्टूबर, 2013 को आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नियोजक सम्मेलन में औपचारिक रूप से आरम्भ की गई।

कोच्चिए केरल में 7–9 जनवरी, 2013 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के 11वें संस्करण में बावा हाजी पंदालिंगल, अध्यक्ष, इंडियन इस्लामिक सेंटर, अबूधाबी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस्लामिक शोध प्रतिष्ठान, मुम्बई के अध्यक्ष डा. जाकिर नायक को वर्ष 2013 के इस्लामी शख्सियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमीरात के कविए लेखक और काव्य–अनुवादक डा. शिहाब घानेम को मई, 2013 में कोलकाता में आयोजित एशियाटिक सोसायटी की 230वीं वार्षिक आम बैठक में एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टैगोर शांति पुरस्कार से नवाज़ा गया।

यमन

भारत के यमन के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध हैं और वह यमन के शांति व समृद्धि के मार्ग का सहयोगी होने के लिए प्रतिबद्ध है।

यमन के योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपमंत्री उमर अब्दुल अजीज अब्दुलगनी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 11–12 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–यमन संयुक्त समिति बैठक के 8वें सत्र की सहभागिता की। यमन–भारत व्यापार परिषद् (वाईआईबीसी) के अध्यक्ष श्री अहमद सलेम शम्मख की अगुवाई में यमन के उच्च स्तरीय व्यापार शिष्टमंडल ने मुम्बई में 14–16 मार्च, 2013 को आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएएस) में शिरकत की। इस वर्ष भारत के अन्य दौरों में विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री श्री सालेह हसन सुमिया 4–7 मई, 2013; जनस्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री डा. अहमद अल–अंसी का 4–7 जुलाई 2013 के दौरे शामिल हैं।

सर्वोच्च निर्वाचन एवं जनमत–संग्रह आयोग (एससीईआर) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद हुसैन अल–हकीमी के आमंत्रण पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री वी.एस. सम्पत ने 22–24 दिसम्बर, 2013 को यमन का दौरा किया। इस मौके पर ईसीआई और एससीईआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सीआईआई का सात सदस्यीय शिष्टमंडल 9–12 मार्च, 2013 को यमन गया तथा व्यापार बैठक के अनुसरण में सना'आए मुकल्ला और आदेन में व्यापार–सेमिनार में भाग लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पांच सदस्यीय दल ने 30 जून से 10 जुलाई, 2013 तक यमन का दौरा किया।

भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के रूप में मानवीय सहायता भेजी जिसे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) श्री मृदुल कुमार ने साना में 21 नवम्बर, 2013 को सौंपा। वर्ष के दौरान भारत ने यमन के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए एकतरफा शुल्क मुक्त टैरिफ प्राथमिकता स्कीम (डीएफटीपी) भी दी तथा भारत और यमन ने 9 जून, 2013 को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक करार पर हस्ताक्षर किए।

अरब लीग

अरब लीग के महासचिव के सलाहकार राजदूत खालिद हब्बास वर्ष 2014–15 के अरब–भारत सहयोग के लिए सहयोग व कार्यकारी कार्यक्रम के मसौदा ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 25–27 जून, 2013 के दौरान भारत के दौरे पर आए।

21 नवम्बर, 2013 को अरब लीग के राजदूतों का विदेश सचिव के साथ सम्पर्क–सत्र आयोजित किया गया जिसमें अरब लीग के महासचिव की भारत यात्रा और नए भारत अरब लीग सहयोग और कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर के संबंध में चर्चा की गई।

अरब राज्यों की लीग के महासचिव श्री नबील एलाराबी 17 दिसम्बर, 2013 भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों पक्षों ने अरब राज्य लीग और भारत के बीच सहयोग ज्ञापन और 2014–15 के लिए अरब–भारतीय सहयोग मंच के कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।

हज

हज–2013 पर भारत–सऊदी अरब के द्विपक्षीय करार पर जेद्दाह में 16 मार्च, 2013 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार में 2013 के हज कोटे में भारत के लिए 170,025 सीटों जिनमें भारतीय हज कमेटी (एचसीओआई), मुम्बई द्वारा सहायता–प्राप्त श्रद्धालुओं की 125,025 सीटों तथा निजी यात्रा संचालकों (पीटीओ) के जरिए 45000 श्रद्धालुओं की सीटों का विशेष उल्लेख किया गया है। सभी विदेशी हज यात्रियों पर 20 प्रतिशत छूट (सऊदी प्राधिकारियों द्वारा) के परिणामस्वरूप हज–2013 के लिए भारत का 136,020 सीटों का विशुद्ध कोटा निर्धारित किया गया। इनमें से 121,420 श्रद्धालुओं ने एचसीओआई और शेष ने पीटीओ के माध्यम से हज–यात्रा की।

भारत सरकार, भारत की हज कमेटी के समन्वयन से (प) मक्का, मदीना और जेहाद में स्थान की व्यवस्था तथा अन्य ढुलाई संबंधी सहायता (पप) चिकित्सकों, पराचिकित्सकों, समन्वयकों, सहायक हज अधिकारियों, हज सहायकों और हज के दौरान हाजियों की सहायता के लिए खादिम–उल–हुज्जाल की प्रतिनियुक्ति (पपप) मक्का, मीना, अराफात, मुज्दालिफा के पवित्र शहरों में हाजियों के लिए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और उन्हें एम्बुलेंस और दवाओं की पूर्ति (पअ) भारत में जेद्दा और वापसी के लिए हवाई यात्रा को सरल बनाते हुए 21 स्थानों का निर्धारण (अ) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण जो बदले में सऊदी अरब हज पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को प्रशिक्षित करते हैंय श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध कराती है।

हज–2013 का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। भारतीय श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था 20 नवम्बरए 2013 को स्वदेश लौटा। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने सऊदी अरब जाने वाले दो सदस्यीय भारतीय हज सदभावना शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

■■

6 अफ्रीका

अल्जीरिया

विदेश राज्य मंत्री श्री इ. अहमद ने 17–18 अप्रैल, 2013 को अल्जीरिया का दौरा किया और प्रधानमंत्री अब्देमालेक सेल्लाल और विदेश मंत्री मुराद मेदिल्सी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने अवसंरचना विकास, हाइड्रोकार्बन, खनन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग पर विचार–विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के और अधिक मजबूती पर कार्य–योजना प्रस्तुत की गई।

भारत और अल्जीरिया के बीच विदेश परामर्श कार्यालय का चौथा सत्र 20 से 22 अक्टूबरए 2013 तक अल्जीरिया में आयोजित किया गया।

भारतीय रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पर जनरल अब्देलक्रिम बेनियाहिया की अगुवाई में अल्जीरिया के चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने 22–25 अक्टूबर, 2013 तक भारत का दौरा किया और रक्षा–क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं पर विमर्श किया।

अंगोला

अंगोला में एग्जिम बैंक के जरिए दी गई ऋण की उच्च श्रृंखला (एलओसी) के अंतर्गत शुरू की जा रही दो परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र तथा अन्य द्विक्षीय करारों में समझौता–ज्ञापनों के अनुसरण में पेट्रोलियम गैस–क्षेत्र के साथ–साथ गैर–तेल क्षेत्रों में दोनों देशों की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के बीच सहयोग सही तरह से बढ़ रहा है। अंगोला को भारत के निर्यातों और वहां निवेशों ने प्रत्यक्ष वृद्धि दर्शाई है। भारत को अंगोला से निर्यात किए जा रहे 7157.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुख्यतया तेल के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 2006–07 में 446.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2012–13 में 7646.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पर्याप्त वृद्धि हुई है। अप्रैल से अगस्त, 2013 तक कुछ द्विपक्षीय व्यापार 2911.38 मिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच गया। सीआईआई शिष्टमंडल की अंगोला–यात्रा के दौरान सीआईसी ने अपने अंगोल समकक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ अंगोला (एआईए) के साथ 18 नवम्बर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बेनिन

अंगोला के उद्योग, व्यापार लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सेफियो इंद्रिस्सोड एफ्फो के नेतृत्व में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2013 तक जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय अफ्रीका–भारत व्यापार मंत्रालयीय सम्मेलन में सहभागिता की।

बोत्स्वाना

विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका) श्री रवि बांगड़ ने 15–17 सितम्बर, 2013 तक बोत्स्वाना का दौरा किया और विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शिक्षा व कौशल विकास मंत्रालय में बोत्स्वाना वीजा, प्रतिबंधित आप्रवासियों और भारत–अफ्रीका हीरा संसथान की स्थापना के मुद्दों पर चर्चाएं कीं।

बोत्स्वाना के खनिज, धातु और जल संसाधन मंत्री ने 10–16 नवम्बर, 2013 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य बोत्स्वाना की कोयला खदानों व टीकेआर परियोजना तथा हीरा–शोधन, जिसमें भारतीय हीरा संस्थान, सूरत जो आईएडीआई की कार्यान्वयन एजेंसी है के दौरे सहित भारतीय कम्पनियों के निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाना था।

भारत ने विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् आईटीईसी, भारत–अफ्रीका फोरम समिति,सी.वी. रमन छात्रवृत्तियों आदि के अंतर्गत बोत्स्वाना राष्ट्रिकों को 200 छात्रवृत्तियों की पेशकश की। बोत्स्वाना ने उसे प्रस्तावित क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया।

बर्किना फ़ासो

स्वास्थ्य मंत्री श्री लेने सेबगो ने 17–19 मार्च, 2013 को दिल्ली में आयोजित 9वें सीआईआई–एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में बर्किनेबे शिष्टमंडल की अगुवाई की। एक 19 सदस्यीय बहुक्षेत्रीय फिक्की शिष्टमंडल ने 10 से 14 अप्रैल, 2013 तक बर्किना फ़ासो का दौरा किया। एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने श्री अरविंद कौशल, अपर सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के नेतृत्व में 1–3 दिसम्बर, 2013 को भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के अंतर्गत जल और मृदा ऊतक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के संबंध में बर्किना फासो का दौरा किया। बर्किना फ़ासो के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, खनन एवं ऊर्जा मंत्री और

खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय के महानिदेशक के आधिकारिक शिष्टमंडल ने 9–11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित दसवें सीआईआई–एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में सहभागिता की।

बुरूंडी

बुरूंडी सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डा. रोज गहिरू ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के अधिकारियों से मिलने के लिए जून, 2013 में भारत का दौरा किया। एनएसआईसी द्वारा बुजुम्बुरा में एक व्यावसायिक केन्द्र/ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

फिक्की द्वारा आयोजित एशिया–अफ्रीका कृषि व्यापार फोरम में भाग लेने के लिए कृषि और पशुधन मंत्री श्रीमती काइतेसि ऑदित्ते ने फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया।

वित्त और आर्थिक विकास आयोजना मंत्री श्री टेबु अब्दुल्लाह मनिरकिज़ा ने बुरूंडी सरकार की ओर से दो करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए फरवरी, 2014 में भारत की यात्रा की। पहला करार एक फर्म यन्त्रीकरण परियोजना के लिए 4.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी के लिए और दूसरा करार बुरूंडी में एक समेकित खाद्य प्रसंस्करण परिसर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए 0.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोनों करारों पर 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे।

बुरूंडी में पैन अफ्रीका ई–नेटवर्क सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

केमरून

केमरून के प्रधानमंत्री श्री फिलोमन यांग ने मार्च, 2013 में अफ्रीका सीआईआई–एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए सात मंत्रियों व एक बड़े व्यापार शिष्टमंडल के साथ नई दिल्ली का दौरा किया।

केप वर्डे

फ्रेंकोफोन देशों के युवा सांसदों के लिए विदेश मंत्रालय के लोक राजन प्रभाग द्वारा 17 से 23 मार्च, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित ''भावी नेता'' कार्यक्रम में कैप वर्डे के दो युवा सांसदों सुश्री अनिल्दलनीदा तवारेस मॉन्टेरियो और श्री जोसेलतो मॉन्तेरियो फोंसेका ने भाग लिया। मार्च, 2014 में नई दिल्ली में आयोजित दसवें सीआईआई–एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में केप वर्डे का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश संबंधों के मंत्रालय में वैश्विक मामलों के महानिदेशक ने किया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)

बेंगुई में एक 400 मीटर/डे सीमेंट संयंत्र के निर्माण और उसकी शुरूआत के लिए भारत सरकार की 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्राप्त एलओसी परियोजना का कार्य अच्छी प्रगति पर है। हालांकि, सीएआर में चल रही अशांत स्थिति को देखते हुए भारतीय कामगारों को निकलना था फिर भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 2011–12 में 8.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2012–13 में 9.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है।

चाड

विदेश मामलों और अफ्रीकी एकीकरण चाड के मंत्री श्री मूसा फकी महमात के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल 12–14 अगस्त, 2013 के दौरान भारत आया। उन्होंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और सार्वजनिक सरोकारों के समग्र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल करते हुए विस्तृत विचार–विमर्श किए। चाड के व्यापार व उद्योग मंत्री श्री हामिद महामत दहालोब की अगुवाई में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2013 तक जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय अफ्रीका व्यापार मंत्रालयीय सम्मेलन में भाग लिया।

कोमोरोस

मोरोनी में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत सरकार के रियायती ऋण को लागू करने के करार पर उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री श्री मोहम्मद सोल्लिही ने 22 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए और यह करार लागू किए जाने की प्रक्रिया में है। कोमोरोस में टेली–मेडिसिन और टेली–एज्यूकेशन की पेन–इ–नेटवर्क परियोजना पहले से ही क्रियाशील है। प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलैक्ट्रिसिटी, सिविल कार्यों आदि में कौशल सिखाने के लिए मोरोनी में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र(वीटीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत कोमोरियन पक्ष द्वारा चयनित की जानेवाली परियोजनाओं के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसान ऋण देने की पेशकश कर चुका है।

कोट डी' आइवरी

कोट डी' आइवरी में उत्तर–निर्वाचन संकट के बाद द्विपक्षीय संबंध प्रबल हुआ है। प्रधानमंत्री श्री डेनियल कब्लान डंकन ने पांच केबिनेट मंत्रियों के साथ 2013 की शुरूआत में भारत की यात्रा की। यह भारत के 50 सदस्यीय व्यापार शिष्टमंडल के कोट डी' इवॉयर में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए किए गए वहां के दौरे के बाद किया गया था। विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर ने अपने समकक्ष के साथ दि्पपक्षीय विचार–विमर्श के लिए 22–24 जनवरी, 2014 को आबिदजान की आधिकारिक यात्रा की। आइवरी के डाक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री ने मार्च, 2014 में दसवें सीआईआई–एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में 6 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत सरकार समर्थित 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ककोबाला (9.3 मेगावाट) हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी), बंदुदु प्रॉविन्स और 168 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कटेंडे एचईपी (64 मेगावाट), कसाइ ऑक्सिडेंटल प्रॉविन्स की एलओसी परियोजना का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011–12 में 15.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2012–13 में दस गुणा अधिक 167.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा है।

जिबूति

अदन की खाड़ी में जलदस्युरोधी अभियानों को संभार–तंत्र की सहायता के लिए भारतीय नौसेना के नियमित अभ्यास के भाग के रूप में भारतीय नौसेना के दो पोत आईएनएस शारदा (7–8 जुलाई, 2014) और आईएनएस त्रिकंद (9–11 अगस्त, 2013) जिबूति पोर्ट ऑन ओवरसीज डिप्लॉयमेंट (ओएसडी) गए।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वाना) श्री संदीप कुमार ने 10 से 15 नवम्बर, 2013 तक सोमालिया तट से समुद्री डकैती खत्म करने के सम्पर्क समूह के 15वें पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

मिस्र

भारत–मिस्र विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) की बातचीत का 9वां चरण 24 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मोर्सी 18 से 20 मार्च, 2013 को भारत आए। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यम, संस्कृति, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा पर 6 समझौता–ज्ञापन और दो आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की 20 मार्च, 2013 को बैठक हुई।

भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की पहली बैठक 10 मार्च, 2013 को कैरो में हुई।

रक्षा पक्ष पर भारतीय नौसेना पनडुब्बकी आईएनएस सिन्धुरक्षक 22–26 मार्च, 2013 को एलेक्जेंड्रिया गई और अपनी रूस से भारत की वापसी यात्रा में 28 मार्च, 2013 को स्वेज नहर से गुजरी।

24 भारतीय औषधीय कम्पनियों ने फार्मेनिक्सल की छत्रछायामें 13 से 15 अप्रैल, 2013 तक कैरो में आयोजित इजिप्ट फार्म एग्जीबिशन में पहली बार सहभागिता की। फार्मेक्सिल के आमंत्रण पर मिस्र के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के शिष्टमंडल ने 1 से 5 दिसम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया। मिस्र के पशु–चिकित्सा सेवा महासंगठन के एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने मिस्र में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय मांस आयात के संबंध में भारत की वधशालाओं और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के लेखा परीक्षा निरीक्षण की समीक्षा और अनुपालन के लिए 11 जून से 4 जुलाई, 2013 तक भारत की यात्रा की।

भारत–मिस्र संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की चतुर्थ बैठक 29 अप्रैल से 2 मई, 2013 तक नई दिल्ली में हुई। मिस्र के शिष्टमंडल ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की ओर रक्षा संगठनों के स्थानीय दौरे भी किए।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए पहली बार अप्रैल–मई, 2013 में एक माह का सांस्कृतिक महोत्सव 'इंडिया बाइ नाइल' आयोजित किया गया।

मिस्र के विदेश मंत्री श्री नबील फहमी 4–6 दिसम्बर, 2013 को भारत आए और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। इस मौके पर द्विपक्षी, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अशोक के. कंथा और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वाना) श्री संदीप कुमार ने द्विपक्षीय व अनुवर्ती बैठकों के लिए 21 से 23 दिसम्बर, 2013 तक मिस्र का दौरा किया।

रियर एडमिरल एहाब सालेह अब्द–एल–लतीफ की अगुवाई में मिस्र की नौसेना के दो अधिकारियों के शिष्टमंडल ने 6 से 9 फरवरी, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित डीफेक्स्पो–2014 में भाग लिया। रक्षा प्रबंधन कॉलेज के चार अधिकारियों सहित भारतीय सशस्त्र बलों के शिष्टमंडल ने 23–26 फरवरी, 2013 के दौरान मिस्र हायर मिलिट्री अकादमी और मिस्र कमान तथा स्टाफ कॉलेज का दौरा किया।

इक्वेटोरियल गिनी

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर–सम्मेलन (आईएएफएस) प्रक्रिया के अंतर्गत भारत ने इक्वेटोरियल गिनी में ग्रामीण विकास के लिए भू–सूचना विज्ञान अध्यवसाय केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की जिसे सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

एरिट्रिया

भारत और एरिट्रिया के दोस्ताना रिश्ते हैं। 2013–14 के दौरान एरिट्रिया के राष्ट्रिकों के लिए आईटीईसी की तीन छात्रवृत्तियां दी गईं।

इथोपिया

भारत और इथोपिया के बीच राजनीतिक, वाणिज्यिक, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में भावप्रवण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध भारतीय कम्पनियों द्वारा निजी क्षेत्र में व्यापार, निवेशन और विनियोजन से प्रेरित है।

उपराष्ट्रपति श्री एम.हामिद अंसारी ने अफ्रीकी संघ के रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 25 मई, 2013, को इथोपिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इस मौके पर उन्होंने इथोपिया के प्रधानमंत्री श्री हेलिमेरियम डेसालेन के साथ बैठक की और द्विपक्षीय तथा परस्पर विभिन्न मामलों पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष डा. दलामिनी जुमा से भी मुलाकात की।

अफ्रीकी संघ आयोग के एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ब्यूरो ऑफ द एयूसी चेयरपर्सन राजदूत ज्यां बप्तिस्ते नतामा की अगुवाई में 4 से 7 नवम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान आईएएफएस–।। में सहयोग के विस्तृत कार्यढांचे की कार्य–योजना पारित की गई।

जनवरी, 2013 में अफ्रीकी संघ के 20वें कार्यकारी बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पश्चिम) श्री सुधीर व्यास के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अदिस अबाबा की यात्रा की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पश्चिम) श्री दिनकर खुल्लर की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने जनवरी, 2014 में अफ्रीकी संघ परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए एड्डिस अबाबा का दौरा किया।

इथोपिया के पर्यावरण और वन मंत्री श्री बिलेते तफेरे ने ऊर्जा व अनुसंधान संस्थान (टेरी) द्वारा 6 से 8 फरवरी, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 'दिल्ली सतत्विकास सम्मेलन' में भाग लिया।

भारत के एक्जिम बैंक द्वारा इथोपिया सरकार के साथ असैता में अफार रीजनल स्टेट ऑफ इथोपिया से जिबाउति में तजोरह बंदरगाह तक के रेलवे लाइन खंड के निर्माण के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण–श्रृंखला के एक करार पर 13 जून, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।

इथोपियाई वस्त्र उद्योग विकास संस्थान और भारत के फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने 17 अगस्त, 2013 को अदिस अबाबा में तीन वर्षीय जुड़वां भागीदारी योजना शुरू की जो इथोपिया के वस्त्र उद्योग की क्षमता बढ़ाएगी।

इथोपिया विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) में मौजूदा ऊर्जा संयंत्रों के दो वर्षों के प्रबंधन के लिए पॉवर ग्रिड–एनएचपीसी–बीआरपीएल कंसोर्टियम इंडिया ने 8 मई, 2013 को इथोपिया सरकार के जल एवं ऊर्जा मंत्रालय के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। ईईपीसीओ का प्रबंधन हाथ में लेने से पहले कंसोर्टियम अभी व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है।

इथोपियाई लैदर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 20–24 फरवरी, 2013 को आयोजित छठे ऑल–अफ्रीकन लैदर फेयर में 42 भारतीय कम्पनियों ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों की 44 भारतीय कम्पनियों ने 21 से 27 फरवरी आयोजित एडिडस चेम्बर इंटरनेशल ट्रेड फेयर में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के तत्वावधान में भाग लिया। एसोचेम के तत्वावधान में 37 भारतीय कम्पनियों ने 20 से 24 जून, 2013 तक अदिस अबाबा में आयोजित छठे कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मेले में सहभागिता की। केमेक्सिल इंडिया के 20 सदस्यीय व्यापार शिष्टमंडल ने 18–20 जुलाई, 2013 को अद्दिस अबाबा का दौरा किया।

आईएएफएस प्रणाली के अंतर्गत संस्थापित एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/इंक्यूवेशन केन्द्र का उद्घाटन इथोपियन शहरी विकास मंत्री और सचिव (पश्चिम) विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2014 में अदिस अबाबा के दौरे के दौरान किया गया।

अदिस आबाबा सिटी गवर्नमेंट मेयर कार्यालय के सदस्यीय प्रतिनिधमंडल ने भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षा पर भारतीय अनुभवों से कुछ सिखने के लिए 10–13 मार्च, 2014 को भारत का दौरा किया।

भारतीय अभिकल्पना संस्थान, हैदराबाद और उद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने आईएएफएस के तहत फरवरी, 2014 में भारत और इथोपिया में एक संयुक्त कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

गैबन

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2011–2012 में 193.26 मिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में चार गुणा से भी अधिक 870.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

घाना

श्री क्लेमेंट हुमादों, खाद्य एवं कृषि मंत्री ने 17–19 मार्च, 2013 को दिल्ली में हुई 9वीं सीईई–एक्जिम बैंक कान्क्लेव में घाना के शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। श्री सुधीर मित्तल, सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में भारत सरकार के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत–घाना संयुक्त उर्वरा परियोजना कार्यों पर विचार–विमर्श के लिए 23–28 जून, 2013 को घाना का दौरा किया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने घाना प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान (जीआईएमपीए) के सहयोग से 30 सितम्बर से 04 अक्टूबर, 2013 तक जीआईएमपीए, अक्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन किया। यह भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–।) निर्णयों के तहत एक पहल है।

''भारत–पश्चिमी अफ्रीका: एक गतिशील संबंध और उभरते रूझान'' शीर्षक पर भारतीय मिशन और आईसीडब्ल्यू द्वारा 14–15 अक्टूबर, 2013 को अक्रा में एक दो दिवसीय कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया।

घाना के मत्स्य एवं मत्स्यपालन मंत्री, वित्त मंत्रालय में उपमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय और ऊर्जा एवं वित्त मंत्रालय से वरिष्ठ

अधिकारियों से गठित 10 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः 9–11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं एक्जिम बैंक सीआईआई कानक्लेव में भाग लिया।

भारतीय डाक विभाग के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने घाना में प्रोजेक्ट एरो के कार्यान्वयन के सिलसिले में 16–21 मार्च, 2014 को घाना का दौरा किया। शिष्टमंडल ने घाना के अक्रा, कुमासी, तकोराडी और तमाले स्थित 04 डाक परियोजना कार्यस्थलों का दौरा किया।

गिनी

नई दिल्ली में गुइनिया के रेजिडेंट मिशन की स्थापना ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को ओर मजबूत बना दिया है। भारत ने गिनी सरकार को 175 कम्प्यूटर उपहार स्वरूप देने का निर्णय लिया है। श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 21–22 जनवरी, 2014 को कोनेक्री का दौरा किया। उन्होंने गुइनिया की अगुवाई में आपसी हित के मुद्दों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। गुइनिया की तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और कार्य, स्वास्थ्य मंत्रियों, उद्योग मंत्री, एसएमई, निजी क्षेत्र संवर्धन ने मार्च, 2014 में नई दिल्ली में आयोजित 10वीं सीआईआई–एक्जिम बैंक कान्क्लेव में प्रतिभागिता की।

गिनी बिसाउ

12 अप्रैल, 2012 को गैर–कानून ढंग से सरकार का तख्ता पलटने के कारण देश में सामान्य जन–जीवन प्रभावित हुआ। भारत देश को विशेषकर भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) और आईटीसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत क्षमता वृद्धि सहायता लगातार उपलब्ध कराता रहा।

कीनिया

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने केन्या में 4 मार्च, 2013 को हुए चुनाव में निर्वाचित राष्ट्रपति श्री उहुरू केन्यात्ता को शुभकामनाएं भेजी। डा. शशि थरूर, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशिष्ट राजदूत के रूप में 09 अप्रैल, 2013 को नैरोबी में आयोजित राष्ट्रपति अहुरू केन्यत्ता और उप राष्ट्रपति विलियम सभोई रूतो के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। डा. थरूर को राष्ट्रपति केन्यात्ता ने 10 अप्रैल,2013 को आमंत्रित किया।

भारतीय फर्मों ने केन्या में कतिपय व्यापार संवर्धन आयोजनों में भाग लिया। इसमें 4–6 अक्टूबर, 2013 को आयोजित 17वीं केन्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2013 और 13–15 मई को आयोजित दूसरी भारतीय शर्करा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मिलित हैं। भारत के एक्जिम बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक श्री टी. जी.ए. रंगानाथन ने केन्या की आर्थिक सफलता, संभावना और चुनौतियों पर 17–18 सितम्बर, 2013 को नैरोबी में केन्या सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय सेना के दो अधिकारियों ने केन्या रक्षा बलों के जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए अल्पावधि प्रतिनियुक्ति पर कीनिया का दौरा किया।

उच्चतर शिक्षा के लिए 38 कीनिया नागरिकों को आईसीसीआर छात्रवृत्तियां प्रदान कीं और 07 कीनिया नागरिकों ने आईटीईसी के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष डा. सुधा शर्मा ने 9–12 सितम्बर, 2013 को नैरोबी में हुई अंतर अमेरिकन कर प्रबंधन केन्द्र (सीआईएटी), तकनीकी सम्मेलन में भाग लिया।

नैरोबी के एक मॉल में 21 सितम्बर, 2013 को हुए आंतकी हमले में 04 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई और 05 अन्य घायल हुए।

केन्या सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 के दौरान भारत ने केन्या का 2983.79 मिलियन अमेरिकन डालर का निर्यात किया और 103.45 मिलियन अमेरिकन डालर का आयात किया। भारत, केन्या के लिए एकमात्र सबसे बड़ा निर्यातक था।

लेसोथो

लेसोथो नेतृत्व का भारत की ओर उपयुक्त झुकाव है और भारत की अफ्रीका में भूमिका के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखता है। श्री मोशोएशो डेविड सेहलोहो, प्रधान सचिव, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, लेसोथो साम्राज्य ने द्विपक्षीय दौरे पर 19–23 अगस्त, 2013 को भारत की यात्रा की।

श्री वीरेन्द्र गुप्ता, उच्चायुक्त की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने द्विपक्षीय संबंधों की ताजा स्थिति पर विचार–विमर्श करने और जेबीसीसी की पहली बैठक तथा दो भारत–अफ्रीका मंच शिक्षर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मासेरू में 12–13 सितम्बर, 2013 को हुई दूसरी संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (जेबीसीसी) की बैठक में भाग लेने के लिए सितम्बर, 2013 में लेसोथो का दौरा किया। भारत ने भी लेसोथो सरकार को 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर की अतिरिक्त ऋण व्यवस्था की पेशकश दोहराई।

जून, 2001 से लेसोथो में तैनात भारतीय रक्षा प्रशिक्षण बल ने लेसोथो रक्षा बल को माहिर बनाने में ओर भी प्रगति की।

भारत ने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 70 प्रशिक्षण स्लॉट्स उपलब्ध करवाकर तथा भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से लेसोथो को विकास सहायता उपलब्ध करवाई है।

लेसोथो के प्रधानमंत्री थोमस थाबेने ने अपने उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल के साथ नई दिल्ली में 9–11 मार्च, 2014 को हुए 10वें सीआईआई–एग्जिम बैंक अफ्रीका कांक्लेव में भाग लिया। लेसोथो ने कांक्लेव में एक भागीदार देश के रूप में भाग लिया। 11 मार्च, 2014 को भारत और लेसोथो के बीच एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय

बैठक हुई। इससे पहले लेसोथों के विदेश मंत्री ने लेसोथो के माननीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के लिए 04 मार्च, 2014 को मुम्बई और 05 मार्च, 2014 को हैदराबाद की यात्रा की।

लाइबेरिया

लाईबेरिया की राष्ट्रपति सुश्री एलेन जॉनसन सिरलीफ 9–13 सितम्बर, 2013 तक राजकीय दौरे पर लाईबेरिया से भारत दौरे पर आने वाली पहली राज्य प्रमुख बनीं। दौरे के दौरान संयुक्त आयोग स्थापना पर भारत और लाइबेरिया के बीच एक समझौता, भारत और लाईबेरिया के विदेश सेवा संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन, तेल और गैस क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, लाईबेरिया में बिजली प्रसारण और वितरण परियोजना निधियन के लिए 144 मिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण व्यवस्था पेशकश हेतु एग्जिम बैंक और भारत के बीच समझौता सहित 04 समझौता/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। वर्ष 2012 का शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार राष्ट्रपति सिरलीफ को उनकी भारत यात्रा के दौरान प्रदान किया गया।

लीबिया

संस्थानिक घाटे और सशस्त्र नागरिक सेना की भारी वृद्धि दोनों के मिलने से लीबिया की राजनैतिक और सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी रही। राष्ट्रीय सरकार की संप्रभुता को लगातार चुनौती दी जाती रही विशेषकर पूर्वी भागों में जहां नागरिक सेना ने तेल संसाधनों पर अपना नियंत्रण कर लिया था।

लीबिया वायु सेना के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बंगलौर, भारत में 6–10 फरवरी, 2013 को हुए एशिया के प्रीमियर एयर–शो एयरो इंडिया–2013 में भाग लिया।

श्री सईद अब्राहिम अल–खट्टाली, सहायक अवर सचिव, तकनीकी मामले, विदेश मंत्रालय, लीबिया की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 9वें सीईई–एग्जिम बैंक कांक्लेव में भाग लेने के लिए 17–19 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया।

श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने दिनांक 14–16 अप्रैल, 2013 को त्रिपोली का सरकारी दौरा किया। इस दौरे ने विशेषकर स्वास्थ्य, बहुआयामी मंचों में सहयोग सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

लीबिया की जनरल नेशनल कांग्रेस से 11 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधमंडल ने संसदीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली का अनुभव लेने के लिए अप्रैल, 2013 में भारत का दौरा किया।

उप स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक लीबियन उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने दिनांक 26–28 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

अफ्रीका की ओर से सबसे बड़े एक 27 सदस्यीय लिबियन व्यापार शिष्टमंडल ने इंडो–अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा 3–6 अक्टूबर, 2013 को मुम्बई में आयोजित 'आई फॉर अफ्रीका' में भाग लिया। इस दौरे के दौरान लिबियाई व्यापार परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री मोहम्मद अब्देलाजिज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विदेश मंत्री, लीबिया सितम्बर, 2013 में हुई 68वीं यूएनजीए के मौके पर विदेश मंत्री से मिले। विदेश मंत्री ने नए लीबिया के क्षमता निर्माण में भारत के सहयोग का आश्वासन दिया।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुआयामी मुद्दों की समीक्षा के लिए 10 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में महानिदेशक (संयुक्त सचिव) स्तर पर भारत–लीबिया एफओसी की बैठक हुई।

लिबियन निजीकरण और निवेश बोर्ड (पीआईबी) के अध्यक्ष ने दिनांक 9–11 मार्च 2014 को नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई एग्जिम बैंक कांक्लेव में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) में कार्यरत डॉ. तमन्ना चतुर्वेदी ने लीबियाई आर्थिक मंत्रालय के साथ आईएएफएस संरक्षण के तहत कार्यकारी विकास कार्यक्रम विचार–विर्मश करने के लिए 24–25 मार्चए 2014 को लीबिया का दौरा किया।

मेडागास्कर

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के भाग के रूप में मेडागास्कर में भारत का केन्द्र बिन्दु उच्च दक्षता/तकनीकी क्षेत्रों मेंए उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो आईटीसी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैंए प्रशिक्षण और भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन छात्रवृत्तियों सहित क्षमता निर्माण करना है। भारत ने वर्ष 2013 में हरूना भू–मध्यीय चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के लिए प्राकृतिक आपदा सहायता के रूप में 1,00,000 अमेरिकन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई।

एडसिल शिष्टमंडल ने 5 से 11 जून, 2013 को मेडागास्कर का दौरा किया एंटानानैरियों और मंजुगा विश्वविद्यालय के सहयोग से कार्यशालाएं और संगोष्ठियों आयोजित की जिनमें अच्छी भागीदारी हुई और यह उम्मीद है कि बहुत से छात्र उच्चतर शिक्षा के लिए भारत का रूख करेंगे।

वर्ष के दौरान पैन अफ्रीकन ई–नेटवर्क के माध्यम से 97 छात्रों ने टेली–मेडिसिन और टेली–एज्यूकेशन सुविधाओं का उपयोग किया। एक स्थानीय चिकित्सालय – इंस्टिट्यूट मेडिकले डी मेडागास्कर (आईएमएम) की सहायता से टेली–मेडिसिन सुविधा प्रदान की जाती है और वर्ष 2010 से बड़े अस्पतालों में मेलागासी

रोगियों द्वारा निःशुल्क परामर्श और निदान का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान 100 व्यक्तियों ने टेली–मेडिसिन सुविधा का प्रयोग किया गया।

आईआईएफटीए द्वारा वाणिज्य मंत्रालय और ''मेडागास्कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बोर्ड आईटीबीएम'' के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्षमता निर्माण संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आईएएफएस द्वारा एंटानानैरियो विश्वविद्यालय में 24 से 28 फरवरी, 2014 तक आयोजित किया गया।

मालावी

मलावी ने भारत सरकार द्वारा 2008 और 2010 में दिए क्रमशः 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूपये की ऋण व्यवस्था (एलओसी) का सफलता पूर्वक उपयोग किया है। ईधन भंडारण सुविधाओं, हरितक्षेत्र उपक्रम (ग्रीनबेल्ट इनिसिएटीव) के तहत सिंचाई नेटवर्क और हरित क्षेत्र उपक्रम (ग्रीनबेल्ट इनिसिएटीव) के तहत सालिमा में परिष्कृत शर्करा प्रसंस्करण उपकरण स्थापना के लिए 76.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का एक और ऋण व्यवस्था प्रस्ताव 13 दिसम्बर, 2012 को हस्ताक्षरित किया गया। इस योजना के अंर्तगत निर्मित न्गाबु कॉटन जिन्नरी का मलावी राष्ट्रपति डॉ. जोयसी बांडा द्वारा 27 अगस्त, 2013 को विधिवत् उद्घाटन किया गया।

भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को दी जाने वाली ऋण श्रृंखला (एलओसी) के तहत 18 फरवरी, 2014 को मलावी राष्ट्रपति डॉ जोयसी बांडा ने मलावी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित म्जुजु में बनाई जा रही महत्वपूर्ण तेल भंडार सुविधा की आधारशिला रखी।

दूसरे भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–प्प) के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) हैदराबाद द्वारा अफ्रीका में 05 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) संस्थापित किए जाएं। तदनुसार मलावी में 2014 तक आरटीपी कार्य करना शुरू कर देंगे। मलावी के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की सहायता के लिए भारत सरकार की ओर से प्रदान किए गए 05 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से एक व्यापार इंक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा दान दी गई 04 मैमोग्राफी मशीनों को 05 फरवरी, 2014 को विधिवत रूप से मलावी सरकार को सौंप दिया गया। यह दान भारत के उप राष्ट्रपति की जनवरी, 2010 में मलावी यात्रा के दौरान 05 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा का एक भाग था।

मलावी के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री श्री सैम गंडा की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय प्रतिनिधमंडल ने भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्री की तीसरी बैठक 01 अक्टूबर, 2013 को हुई भारत–अफ्रीका व्यापार परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया।

माली

हालांकि, द्विपक्षीय मंच पर बहुत कम बातचीत हुई परंतु देश ने खुद ही प्रमुख राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी विकास को महसूस किया। जुलाई–अगस्त 2013 में राष्ट्रपति चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन ने श्री इब्राह्म बॉबकर कैट को देश के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करके दिखाया। यह माली में प्रजातंत्र शासन की पुनः स्थापना की ओर एक प्रमुख घटनाक्रम था जिसे मार्च 2012 में हुए सैन्य तखतापलट के परिणामस्वरूप गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा था। इस संकट के दौरान माली में संवैधानिक व्यवस्था की पुनः स्थापना करने और साथ–साथ देश की क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पुरजोर सहायता की। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल हो चुकी है। भारत सरकार ने माली के साथ विकास सहयोग भागीदारी की ओर मजबूत बनाने के किए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

नई दिल्ली में 9–11 मार्च, 2014 तक 10वीं सीआईआई– एग्जिम बैंक कांक्लेव में माली का प्रतिनिधित्व निवेश संवर्धन तथा निजी पहलों के प्रभारी और अर्थव्यवस्था राज्य मंत्री श्री मुस्तफा बेन बरका द्वारा किया गया। उन्होंने "भारत–पश्चिम अफ्रीका भागीदारी–अनेक अवसर" पर प्रस्तुति दी।

मॉरिटानिया

मॉरिटानिया के राष्ट्रपति, श्री मोहम्मद ओल्ड अर्ब्दल अजीज ने भारत सरकार द्वारा ऋण श्रृंखला माध्यम से 11.3 मिलियन डालर की राशि से वित्तपोषित दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट का नीमा में 13 अगस्त 2013 को शिलान्यास किया। वाणिज्य, उद्योग, हस्तकला और पर्यटन मंत्री सुश्री नाहा मिंट मौकनेस्स ने 9–11 मार्च 2014 को नई दिल्ली में हुए 10वें सीआईआई एग्जिम बैंक कांक्लेव में मॉरिटानिया शिष्टमंडल की अध्यक्षता की।

मॉरिशस

भारत और मॉरिशस के संबंध समय पर खरे उतरने वाले गौरवमयी और बहुआयामी रहे हैं। साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में इन भागीदारी में विस्तार हुआ है और आज इसमें विशाल तथा विविध क्षेत्र शामिल है।

मॉरिशस राष्ट्रपति राजकेसवुर पुर्याग ने 3–10 जनवरी, 2013 को भारत का राजकीय दौरा किया। वे कोच्ची में 7–9 जनवरी, 2013 को आयोजित 11वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। वहां उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 11–13 मार्च, 2013 को मॉरिशस का दौरा किया इस दौरान वे 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति राजकेसवुर पुर्याग और प्रधानमंत्री नवीचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीयए क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया।

दौरे के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा निःशक्त व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों तथा पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग संबंधी तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी के दिनांक 2–7 फरवरी, 2013 तक के मॉरिशस दौरे ने मॉरिशस के साथ बहुआयामी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और गति प्रदान की। एक मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत के तटीय सर्वेक्षण जहाज "पाथफाइंटर" को उनके दौरे के दौरान मॉरिशस को भेंट किया गया।

मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईएफजैड) निगरानी, दस्युता रोधी गस्त और बाह्य–द्वीप सहायता के लिए भारतीय नौ सेना जहाज सुकन्या को 29 जून से 13 जुलाई, 2013 तक मॉरिशस समुद्र में तैनात किया गया। भारतीय नौ सेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के चार जहाज आईएनएस शारदा, आईएनएस घडियाल, आईएनएस तारांगिनी और आईसीजीएस वरूण ने 24 सितम्बर से 24 अक्टूबर, 2013 तक मॉरिशस समुद्र में बहुत ही सफल और उपयोगी दौरा किया। इस प्रशिक्षण के दौरान मॉरिशस रक्षा बलों के लिए गहन संयुक्त गश्त, निगरानी और बहुत से विशिष्ट प्रशिक्षण अभ्यास किए गए।

मॉरिशस प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ प्रमुख कार्यपालक श्री के. ओ.फांग वेंग–पुरून ने दिनांक 2 अगस्त, 2013 को कोलकाता में जीआरएसई लिमिटेड में एमओपीबी सीजीएस बैराकुडा के उद्घाटन समारोह तथा दिनांक 05 अगस्त, 2013 को दिल्ली में ओपीवी की 6वीं संयुक्त निगरानी समिति बैठक में भाग लिया।

मॉरिशस की सभी पैट्रोलियम जरूरतों की आपूर्ति के लिए जुलाई, 2013 में एमआरपीएल और मॉरिशस की एसटीसी के बीच तीन वर्षीय समझौते का नवीकरण किया गया।

4–5 जुलाई, 2013 की व्यापार मंत्री स्तर की पहली आईओआर–एआरसी आर्थिक एवं व्यापार सम्मेलन की भारत और मॉरिशस द्वारा संयुक्त मेजबानी की और मॉरिशस प्रधानमंत्री डां. नवीन चंद्र रामगुलाम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया।

डॉ.एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 19–20 नवम्बर, 2013 को मॉरिशस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मॉरिशस में अन्तर्राष्ट्रीय – प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी संस्थान स्थापित करने के लिए आईआईटी, दिल्ली और मॉरिशस अनुसंधान परिषद के बीच और शैक्षिक अर्हताओं को आपसी मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ तथा तृतीय शिक्षा परिषद, मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री के.एच. मुनियप्पा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, राज्य मंत्री ने 30 नवम्बर से 02 दिसम्बर, 2013 तक मॉरिशस का सरकारी दौरा किया। इस दौरे के दौरान लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मॉरिशस के व्यापार, उद्योग और सहकारिता मंत्री श्री जंगबहादुर सीताराम ने 31 अगस्त से 05 सितम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया, इस दौरान लघु और मध्यम उद्योग विकास प्राधिकरण, मॉरिशस (एसएमईडीए) और उद्यमीयता विकास संस्थानए अहमदाबाद तथा (एसएमईडीए) और भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बीच संस्थानिक स्तर के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।

मॉरिशस के चुनाव आयुक्त श्री इमरान अब्दुल रहमान ने 10–19 अप्रैल 2013 को भारत का दौरा किया। इस दौरान भारत के चुनाव आयोग और मॉरिशस के चुनाव आयोग के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री अजय माकन, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री ने अप्रैल, 2013 को मॉरिशस का दौरा किया। श्री माकन ने सुश्री शेलाबाई बापू, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और संस्था सुधार मंत्री और श्री अनिल कुमार बाच्चू, उप प्रधानमंत्री एवं सार्वजनिक अवसंरचना, राष्ट्रीय विकास एकक, स्थल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री के साथ विचार विमर्श किया।

भारत के चुनाव आयुक्त, डॉ. नसीम जैदी ने 6वीं अन्तर्राष्ट्रीय चुनाव मामले संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 26 मई से 01 जून, 2013 तक मॉरिशस का दौरा किया।

डॉ. डी.वाई.पाटिल ने मॉरिशस की मराठी मंडली संघ के निमंत्रण पर 1–5 मई 2013 को मॉरिशस का दौरा किया।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, सभापति, उत्तराखंड राज्य सभा और श्री एम.बी.दहाल, उप–सभापति सिक्किम राज्य सभा ने क्रमशः 06–08 सितम्बर, 2013 एवं 6–9 सितम्बर, 2013 को मॉरिशस का दौरा किया।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एच.कपाडिया ने 16–17 मई, 2013 को अन्तर्राष्ट्रीय कर विकास पर 7वें अफ्रीका/एशिया अन्तर्राष्ट्रीय राजकोषीय संघ सम्मेलन पर संयुक्त कार्य समूह के 10वें सत्र में भाग लेने के लिए 27–29 नवम्बर, 2013 को मॉरिशस का दौरा किया।

श्री पी.एस.राघवन, सचिव (ईआरएंडएडी), विदेश मंत्रालय ने 27–29 नवम्बर, 2013 पोर्ट लुइस में आयोजित हुए भारत–मॉरिशस दोहरे कराधान परिहार सम्मेलन पर संयुक्त कार्य समूह के 10वें सत्र के लिए मॉरिशस के लिए भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षता की।

मॉरिशस के तत्कालीन महाअधिवक्ता श्री यतीन्द्र वर्मा ने 15–20 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया और श्री अश्विनी कुमार, विधि एवं न्याय मंत्री एवं भारत के महाअधिवक्ता श्री जी.ई.वाहनवती से विचार–विर्मश किया।

श्री माइकल सिक येन, पर्यटन मंत्री, मॉरिशस की अध्यक्षता में मॉरिशस पर्यटन संवर्धन मिशन पर 20–28 अगस्त, 2013 को भारत का दौरा किया।

मॉरिशस गणतन्त्र के माननीय राष्ट्रपति श्री राजकेस्वुर पुर्याग ने विगत में भारत का तीन बार दौरा किया, केआईआईटी विश्वविद्यालय, ओडिशा के निमंत्रण पर वे 12–17 नवम्बर 2013 को भारत आए, 13–17 दिसम्बर, 2013 को लखनऊ आए जहां वे सिटी मान्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के प्रमुख न्यायाधीशों के 14वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि बने। 17–20 फरवरी, 2014 को कोच्ची आए, जहां वे विज्ञान एवं सामाजिक कार्यो में नवाचार केन्द्र (सीआईएसएसए) और केरल सरकार द्वारा आयोजित दूसरे वैश्विक आयुर्वेद उत्सव के मुख्य अतिथि थे।

मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बर्नाड सिक येन ने अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता परिषद और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधिवेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया। इस सम्मेलन में उन्हें 'अंतर्राष्ट्रीय विधिवेता पुरस्कार–2013' का सम्मान प्रदान किया गया।

जीवित और/अथवा संरक्षित लाभकारी कृमियों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भेजने हेतु खाद्य एवं कृषि अनुसंधान परिषद, मॉरिशस और भारतीय कृषि लाभकारी कृमि ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री गश्त और निगरानी करने के पश्चात भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम 13–16 फरवरी, 2014 को पोर्ट लुईस बंदरगाह पर पहुँचा। जहाज के अधिकारियों ने मॉरिशस राष्ट्रीय तटरक्षक के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया और कतिपय अन्य सामाजिक कार्यकलापों में उन्होंने रक्तदान अभियान में भाग लिया।

मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर 22 सदस्यीय भारतीय नौसेना परेड दस्ते ने अंजले स्टेडियम में मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस परेड में दिनांक 12 मार्च, 2014 को भाग लिया।

मॉरिशस के उद्योग, वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री कादर सयैद हुसैन ने 26–30 जनवरी, 2014 को भारत का दौरा किया। उन्होंने बंगलोर में 27–29 जनवरी, 2014 को आयोजित सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन 2014 में प्रतिभागिता की जहां वे अपने समकक्ष श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मिले। 30 जनवरी, 2014 को श्री हुसैन पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोइली और के.एस. राव कपड़ा मंत्री से नई दिल्ली में मिले।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारतजानो को कार्यक्रम' के 10 युवा प्रतिभागियों सहित भारतीय मूल के 150 से भी अधिक प्रख्यात मॉरिशस वासियों के एक शिष्टमंडल ने 7–9 जनवरी, 2014 को दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया। मॉरिशस के महाअधिवक्ता और कृषि–उद्योग एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री एस.वी. फागू ने अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के संरक्षण में अनुबंधित श्रमिक पर विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

मॉरिशस के कला और संस्कृति मंत्री श्री मुखेसुरू चुनी ने 18–20 फरवरी, 2014 को भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में मॉरिशस शिष्टमंडल के प्रमुख के रूप में हैदराबाद का दौरा किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थायी सचिव श्री मोतीचंद सीबा ने सिसेल्स के साथ अतिथि देश के रूप में मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच सामुदायिक सुरक्षा सहयोग पर 6 मार्च, 2014 को दिल्ली में हुई तीसरी एनएचए स्तर की द्विपक्षीय बैठक में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया।

मोरोक्को

मोरोक्को के उद्योगए व्यापार एवं नई प्रौद्योगिकी मंत्री अब्देल कादर अमारा ने मोरोक्को निवेश विकास एजेंसी और फाइनेंसियल टाइम्स समाचार पत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रोड शो में भाग लेने के लिए 29–30 मई, 2013 को मुम्बई का दौरा किया।

फिकी (एफआईसीसीआई) और भारतीय एग्जिम बैंक ने 30 मई 2013 को कार्रकेश, मोरोक्को में अफ्रीकन विकास बैंक की वार्षिक बैठक के अवसर पर "सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति में अफ्रीका के साथ भारतीय अनुभवों को साझा करना" शीर्षक पर आधारित ''भारत–अफ्रीका भागीदारी दिवस'' का संयुक्त आयोजन किया।

8 अगस्त, 2013 को भारत और मोरक्को ने दो देशों के बीच दोहरा कराधान परिहार समझौता में संशोधन के लिए एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय व्यापार की राशि जो 2005 में 573.87 मिलियन डालर वर्ष 2012 में बढ़कर 1.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। रैनबैक्सी ने दवा उत्पादन के लिए कैसाब्लांका में अपना उत्पादन प्लांट स्थापित किया।

श्री जे.डी.सलीम, वित्त (राजस्व), राज्य मंत्री ने अल जदीदा में यूएनडीपी द्वारा आयोजित जलवायु संसद सभा में भाग लेने के लिए 3–7 अक्टूबर, 2013 को मोरक्को का दौरा किया।

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री ने 30 जनवरी से 02 फरवरी, 2014 तक मोरोक्को का दौरा किया। इस दौरान किंग मोहम्मद–VI ने उन्हें आमंत्रित किया और वे प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सभापति, विदेशी मामले एवं सहयोग मंत्री से मिले। इस यात्रा के दौरान समुद्री मत्स्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और पर्यावरण सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

मोजाम्बिक

लोक निर्माण एवं आवास मंत्री श्री कैडमिल मुतम्बा (7 अप्रैल, 2013) उप परिवहन एवं संचार मंत्री श्री यूसेबियो सैदे (मई, 2013) एवं उप गृहमंत्री श्री जोश मन्द्रा (सितम्बर, 2013) सहित मोजाम्बिक की ओर से बहुत से मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। राष्ट्रीय योजना निदेशक, योजना एवं विकास मंत्रालय, मोजाम्बिक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25–29 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली का दौरा किया। सुश्री एस्पेरंसा बायस खनिज संसाधन मंत्री ने पैट्रोटेक–2014 में भाग लेने के लिए 12–15 जनवरी, 2014 को भारत का दौरा किया। 9–11 मार्च, 2014 के दौरान भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10वें सीआईआई–एग्जिम बैंक कांक्लेव में भाग लेने के लिए श्री जोस पासिको, कृषि मंत्री ने 20 सदस्यीय शिष्टमंडल, जिसमें श्री अरमांडोइरागा, उद्योग एवं व्यापार मंत्री भी सम्मिलित थे, की अध्यक्षता की। भारत से श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री (जुलाई, 2013), श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (सितम्बर, 2013), और महाराष्ट्र के ग्रामीण विकासमंत्री श्री जयंत पाटिल ने मोजाम्बिक की यात्रा की। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय सैंट्रेल बैंक, ओएनजीसी, बीपीआरएल, बीपीएसएल, फिक्की, सीआईआई,सीईएल, डब्ल्यूएपीसीओएस और कतिपय निजीक्षेत्र की भारतीय कम्पनियों ने भी वर्ष के दौरान मोजाम्बिक का दौरा किया।

इस यात्रा के दौरान श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और मोजाम्बिक व्यापार एसोसिएशन परिसंघ ने सीआईआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक 3 से 6 जुलाई, 2013 तक भारत–मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक मापुतो में हुई। बैठक में राजनीति, आर्थिक, व्यापार, निवेश, एसएंडटी, कृषि और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। एग्जिम बैंक ने मोजाम्बिक के साथ 217 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तीन ऋण श्रंखला समझौता हस्ताक्षरित किए। इनमें 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की टिका–बुजी–नोवा–सोफाला रोड परियोजना, टेटे जाम्बिजिया और कबोडेलगडो में 1200 घरों के निर्माण हेतु 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना और 20 मिलियन डॉलर की जन परियोजना सम्मिलित हैं।

राष्ट्रपति अर्माडो गुबुजा ने भारत सरकार द्वारा दी गई 200,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता से केबो डेलगेडो के उत्तरी प्रांत में स्थित नान्गडे जिले में स्थापित काजू प्रसंस्करण और पैकजिंग प्लांट का 24 अप्रैल, 2013 को विधिवत रूप से उद्घाटन किया। मालुने के एसएंडटी पार्क में प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार केन्द्र स्थापना के लिए भारत का 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी परियोजना 31 अगस्त, 2013 को मोजाम्बिक की ओर हस्तांतरित की गई। सोलर फोटोवोल्टिक उत्पादन प्लांट की स्थापना के लिए 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और अन्य एलओसी परियोजना का 22 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रपति गुबुजा द्वारा उद्घाटन किया गया। आईटीईसी और आईसीसीआर कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में मोजाम्बिक को दी जाने वाली सहायता जारी है।

नामिबिया

भारत ने नामिबिया के विभिन्न भागों में गंभीर अकाल स्थिति के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए नामिबिया सरकार के अकाल राहत कोष में 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का डोनेशन दिया। नामिबिया में क्षमता निर्माण संबंधी भारत की प्रतिबद्धता के रूप में भारत ने अगस्त, 2013 में नामिबिया विश्वविद्यालय (यूएनएएम) को 4.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान जारी किया। जारी की गई यह राशि यूएनएएम के उत्तरी परिसर में खनन और इंजीनियरिंग और आईटी/कम्प्यूटर के संयुक्त भवन निर्माण के लिए भारत की 12.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता का एक भाग थी। यूएनएएम ने सूचित किया है कि भारत सहायता से निर्मित भवन का नामकरण 'इंडिया विंग' के रूप में किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार, अपर सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 16–28 सितम्बर, 2013 के दौरान विंडहॉक में विश्वव्यापी बंजर भूमि को हरा–भरा बनाने संबंधी संघर्ष पर सीओपी–।। सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामिबिया का दौरा किया।

वाइस एडमिरल सुनील लांबा के नेतृत्व में एक 19 सदस्यीय राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) शिष्टमंडल ने शैक्षिक दौरे पर 12–17 मई, 2013 तक नामिबिया का दौरा किया।

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 4–5 फरवरी, 2014 को नामिबिया की दो दिवसीय यात्रा की। वे नामिबिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, व्यापार एवं उद्योग मंत्री और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री से मिले। इस बैठकों के दौरान नामिबिया को दी जाने वाली क्रेडिट लाइन सुविधाओं संबंधी मुद्दों, आईसीटी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, उद्यमीयता विकास केन्द्र, नामिबिया में एसएमई कौशल केन्द्र और भारत एसएसीयू अधिमान्य व्यापार समझौता पर विचार–विमर्श हुआ।

अपनी नीति भागीदारी कार्यक्रम के तहत नामिबिया लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संस्थान की शासक परिषद सदस्यों के शिष्टमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, प्रशासन एवं विकास अनुसंधान संस्थान, आगरा और एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर का 11–18 जनवरी, 2014 को दौरा किया।

नामिबिया के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री काले स्क्लेट्विन की

अध्यक्षता में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल 24–30 जनवरी, 2014 को बैंगलौर में भारत–अफ्रीका भागीदारी फोरम में भाग लेने के लिए भारत आया।

नाइजर

श्री अमादो बॉबकट सिसे, योजना, भूमि प्रबंधन, समुदाय विकास मंत्री ने 12–13 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली का दौरा किया और निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक के साथ 34.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। (प) फोटोवोल्टेनिम पद्धति के प्रयोग से 30 गांवों का विद्युतीकरण (9.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर) (पप) 5 मेगावाट की सोलर फोटो वोल्टिक प्रणाली की स्थापना (24.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत नाइजर को वर्ष 2013–14 के लिए 135 स्लाट्स आवंटित किए गए। आईएएफएस–। के तहत उद्यमियों, सरकारी कार्मिकों, पेशेवरों और कारपोरेट कार्यपालकों में अपेक्षित कौशल और व्यावसायिक क्षमता का विकास करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान संस्थान नाइजर गणराज्य के विदेश/वाणिज्य विदेश/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स मंत्रालयों और साथ ही नाईजर में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय के समन्वय से नियासमन्वयम्मे में 11–15 नवम्बर, 2013 नवम्बर तक तक 05 दिन की कार्यशाला आयोजित की।

नाइजर के वाणिज्य तथा निजी क्षेत्र संवर्धन मंत्री, श्री अल्मा उमारो ने 9–11 मार्च 2014 से नई दिल्ली में भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर सी आई आई एक्जिम बैंक कानक्लेव के दसवें संस्करण में एक शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। योजना, भूमि प्रबंधन तथा समुदाय विकास मंत्री श्री अमाडो बॉबकार ने नाइजर में उप–नगरीय तथा ग्रामीण समुदाय हेतु पेयजल के लिए एक्जिम बैंक के 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला करार पर हस्ताक्षर करने के लिए 13–14 मार्च 2014 को दोबारा नई दिल्ली की यात्रा की।

नाइजीरिया

आईएएफएस–।। के तहत भारत द्वारा नाइजीरिया को खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला डोनेशन के सिलसिले में राष्ट्रीय खाद्य एवं औषध प्रशासन एवं नियंत्रण एजेंसी (एनएएफडीएसी) के साथ व्यवस्था संबंधी बातचीत करने के लिए आईसीआरआईएसएटी से तीन सदस्यीय टीम ने 14–18 अप्रैल, 2013 को अबुजा का दौरा किया।

एयर वाइस मार्शल विपिन की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज शिष्टमंडल ने 6 दिन के शैक्षिक दौरे पर 11–17 मई, 2013 को नाइजीरिया का दौरा किया। एयर मार्शल के. एस. गिल, कमाडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला ने भारत के सहयोग से स्थापित कदुना आधारित नाइजीरियन रक्षा अकादमी के 49वें वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए 14–15, सितम्बर, 2013 को की यात्रा की। डा. सैमुअल ऑर्टाम, नाइजीरिया व्यापार राज्य मंत्री, नाइजीरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2013 तक जोहनेसबर्ग में आयोजित तीसरी अफ्रीका–भारत व्यापार मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया।

नाइजीरिया के ऊर्जा मंत्री प्रो. चिंडेडु नेबो के नेतृत्व में 04 सदस्यीय शिष्टमंडल ने नाइजीरिया ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भेल (बीएचईएल) के साथ बातचीत करने हेतु 7–9 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली का दौरा। नाइजीरिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल डेले जोसेफ अजिओबा के नेतृत्व में 06 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 9–13 दिसम्बर, 2014 को सरकारी भारत का दौरा किया। मार्च,2013 के सीआईआई–एग्जिम बैंक कांक्लेव में नाइजीरिया के 20 सदस्यीय उच्च अधिकारप्राप्त शिष्टमंडल ने भाग लिया। बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापकों के निमंत्रण पर नाइजरिया की जल संसाधन मंत्री सुश्री सराह रेंग ओसेक्पे ने 20–22 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित रीइंवेंट दी टायलेट फेयरः इंडिया 2014 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

कांगो गणराज्य (आर ओ सी)

70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देशों के बीच दि्पवक्षीय व्यापार वर्ष 2011–12 में 606.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 662.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। औद्योगिक विकास एवं निजी क्षेत्र संवर्धन के वरिष्ठ मंत्री श्री म्युबा इसिदोर ने भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10वें सीईई–एग्जिम बैंक कांक्लेव में दिनांक 9–11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आरओसी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ व्यापार मंत्री, आर्थिक क्षेत्र मंत्री और युवा मंत्री भी थे। दो अधिकारियों ने आरएएफएस के तहत वर्ष 2013–14 में प्रशिक्षण में भाग लिया।

रवाण्डा

भारत के एग्जिम बैंक और रवाण्डा सरकार के बीच निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचाई कृषि परियोजना और इसके विस्तार के लिए 120.05 मिलियन ऋण श्रृंखला हेतु किगाली में अक्टूबर, 2013 को एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। एग्जिम बैंक की 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के तहत निधिबद्ध न्याबारोंगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को वर्ष 2014 के आरंभ में पूरा होने की उम्मीद है।

फरवरी, 2014 में रवाण्डा के अवसंरचना मंत्री प्रो. सिलास ल्वाकबाम्बा ने अफ्रीका पर यूएन आर्थिक आयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

आईटीईसी/स्काप के अंतर्गत 2013–14 के लिए 30 स्लाट्स रवाण्डा को आवंटित किए गए थे जिनमें से 12 स्लाट्स का प्रयोग किया गया। इसके अलावा 4 प्रतिभागियों ने आईएएफएस के तहत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया और आईसीसीआर छात्रवृत्ति पर 12 छात्रों ने भारत का दौरा किया। रवाण्डा में पैन अफ्रीका ई–नेटवर्क प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

साओ टॉम व प्रिंसिप

दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंध निरंतर मजबूत हो रहे है। पैन–अफ्रीकन ई–नेटवर्क परियोजना सुचारू रूप से चल रही है।

सेनेगल

भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के दूसरे चरण के लिए 27.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला, मत्स्य विकास परियोजना के दूसरे चरण के लिए 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर, आधुनिक बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, रैंडरिंग और चर्मशोधन प्लांट और मार्केट स्थान सेनेगल सरकार को अनुमोदित किए। भारत सेनेगल को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण अवसरों को लगातार उपलब्ध करवा रहा है और देश को आईटीईसी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012–13 में 30 स्लाट्स आवंटित किए गए थे। भारत तकनीकी कौशल विकास भारत में रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए अवसर भी उपलब्ध करवाता है।

सेनेगल उपग्रह आधारित पैन–अफ्रीका ई–नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र स्टेशन होने के कारण यहां से पूरे अफ्रीकी देशों में टेली–मैडिसन और टेली–एज्यूकेशन कार्यक्रम लगातार प्रसारित किए जाते है। दकार के फान अस्पताल को अफ्रीकी सरकार द्वारा इसे रिजनल सुपर स्पेसिएलिटी हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। मरीजों के पास सुविधाएं (पीईएफ) पहले से कार्यात्मक और प्रचालन में हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक शिष्टमंडलीय सहयोग और व्यापार दौरों में वृद्धि हुई है। सेनेगल कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएसआरए) और अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध–शुष्क भू–मध्यीय फसल अनुसंधान (आईसीआरआईएसएटी) की 68वीं बोर्ड बैठक 7–10 अप्रैल, 2013 को दकार में आयोजित हुई जिसमें श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहयोग विभाग, डा. एस.अयप्पन, सचिव (डी) एवं डीजी, आईसीएआर और सुश्री मिन्नी मैथ्यू, प्रमुख सचिव, आंध्रप्रदेश ने भाग लिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी का सेनेगल के लघु और मध्यम उद्योग के लिए स्थानांतरण पर एक रोड शो 3–6 जून, 2013 को दकार में आयोजित किया गया। सेनेगल के संस्कृति मंत्री श्री अब्दुल अजीज म्बे ने 28–29 जुलाई, 2013 को भारत का दौरा किया गया और उन्होंने वर्ष 2013–15 के लिए सांस्कृतिक मामलों में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच, संस्कृति मंत्री ने कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। श्री अजीज सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम के तहत सूचना और प्रसारण क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री से भी मिले।

श्री सुतनु बेहुरिया, सचिव, भारी उद्योग विभाग और श्री पी.के. उप्पल, कार्यकारी निदेशक (ईडी), भेल (बीएचईएल) के संयुक्त शिष्टमंडल ने विद्युत और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सेनेगल प्रोजेक्ट्स के विकास/निधियन के लिए 14–16 जुलाई, 2013 को दकार का दौरा किया। सेनेगल के वाणिज्य, उद्यमशीलता और अनौपचारिक क्षेत्र मंत्री श्री अलिओन सार ने 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2013 तक जोहनसबर्ग में आयोजित तीसरी भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रीय बैठक में भाग लिया।

अफ्रीका में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विकास परिषद (सीओडीईएसईआरआईए) के सहयोग से आईसीडब्ल्यू ने ''इंडिया–फ्रांकोफोन अफ्रीका मुद्दे और चुनौतियां'' पर 17–18 अक्टूबर, 2013 को दकार में अकादमिक सम्मेलन का आयोजन किया।

30 कम्पनियां, जो एसोचैम (एएसएसओसीएचएएम) और फियो की सदस्य हैं, ने 28 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2013 तक दकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (एफआईडीएके) में भाग लिया।

सेनेगल के विदेश मंत्री श्री मनकेयूर नादिये ने 15 जनवरी, 2014 को कार्य दौरे पर नई दिल्ली आए। वे ईएएम श्री सलमान खुर्शीद और एमओएस (पीके) से मिले और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया।

सेशल्स

भारत–सेशल्स संबंध सुरक्षा विकास सहयोग, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहे। भारत सरकार ने सेशल्स को नवीनतम तकनीक का हवाई जहाज डोनियर भेंट किया जो वहां अप्रैल, 2013 को पहुंचा जिसका सेशल्स द्वारा अपने मईजैड के लिए समुद्री डकैती निरोधी ऑपरेशन और निगरानी हेतु प्रयोग किया जा रहा है। डोनियर के प्रचालन प्रशिक्षण और मूलभूत रख–रखाव हेतु भारतीय नौसेना विमानन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के लिए भारत और सेशल्स के बीच 20 सितम्बर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आईएनएस सुकन्या विक्टोरिया बंदरगाह पर जून, 2013 में पहुंचा। भारतीय नौ सेना प्लाटून और नौ सेना बैंड ने सिसेल्स द्वारा 1993 में नए संविधान के अंगीकरण को प्रदर्शित करने के लिए दिनांक 18 जून, 2013 को आयोजित सोशल्स राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लिया। पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 4 भारतीय नौ सेना प्रशिक्षण जहाजों आईएनएस–शारदा, घडियाल, तारांगिनी और भारतीय तटरक्षक जहाज वरूण अक्टूबर, 2013 के प्रथम सप्ताह के दौरान 4

दिन के दौरे पर विक्टोरिया बंदरगाह पहुंचे। यह दौरा 4–6 अक्टूबर, 2013 को सेशल्स–भारत दिवस समारोह आयोजन का एक भाग था।

यह वर्ष सेशल्स के साथ संसदीय बातचीत में हुई वृद्धि का साक्षी रहा। सेशल्स के एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 4–9 अगस्त, 2013 को भारत का दौरा किया और उन्होंने लोकसभा के सभापति, उपसभापति और अन्य गणमान्यों से बातचीत की।

सेशल्स के वित्त, व्यापार और निवेश मंत्री ने भारत से आवश्यक वस्तुओं की खरीद को वित्तीय सहायता देने के लिए एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से 6 सितम्बर, 2013 को 8 मिलियन अमेरिकी डालर के एक संशोधित डॉलर क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में वर्ष 2006 में सेशल्स सरकार द्वारा लिए गए 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में कमी/पुनःनिर्धारण करना भी समाविष्ट है।

भारत–सेशल्स संयुक्त आयोग का 8वां सत्र 8 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

श्री सुधीर व्यास, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय ने 4–7 अगस्त, 2013 को सेशल्स का दौरा किया और अर्थ, सैन्य, प्रशिक्षण, अनुसंधान और हवाई सम्पर्क सहित द्विपक्षीय सहयोग के कतिपय क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया।

भारतीय सेना के एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने दिसम्बर, 2013 की भारत–सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए प्रारंभिक योजना सभा आयोजन की टीम के भाग के रूप में 20–24 अक्टूबर ,2013 को सेशल्स का दौरा किया।

वर्ष के दौरान संस्कृति, पर्यटन और जन–जन सम्पर्क के क्षेत्रों में सहयोग नई बुलंदियों तक पहुंचा। पहली बार सेशल्स–भारत दिवस समारोह का 4–6 अक्टूबर, 2013 के दौरान विक्टोरिया, सेशल्स में आयोजन किया गया।

भारत–सेशल्स को व्यापार और अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों से जुडे सेशल्स नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीईसी कार्यक्रमों सहित और आईआईएफटी द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम' के माध्यम से मानव संसाधन विकास के लिए लगातार सहायता जारी रखे हुए है।

सेशल्स के प्राकृतिक संसाधन और उद्योग मंत्री श्री पीटर साइनॉन ने 4–6 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एशिया–अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम 2014 में भाग लिया। सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री डैनी फौटे ने नई दिल्ली में 6–8 फरवरी, 2014 को आयोजित दिल्ली धारणीय विकास शिखर सम्मेलन के 14वें संस्करण में भाग लिया।

सियरा लियोन

डा. रिचर्ड कोंटे, कार्मिक प्रमुख, राष्ट्रपति कार्यालय ने 17–19 मार्च, 2013 को दिल्ली में आयोजित 9वें सीआईआई एग्जिम बैंक कांक्लेव में सियरा लियोन शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। व्यापार एवं उद्योग उपमंत्री ने 9–11 मार्च, 2014 में नई दिल्ली में आयोजित 10वें एक्जिम बैंक–सी आई आई कानक्लेव में भाग लिया।

सोमालिया

भारत ने 7 मई, 2013 को लंदन में हुई सोमालिया पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जहां सोमालिया को क्षमता निर्माण में भारत की सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने न्यूयार्क में सितम्बर, 2013 को सोमालिया पर हुई अंतः सरकारी प्राधिकार (आईजीएडी) भागीदार फोरम की सरकारी बैठक में सोमालिया संघीय सरकार तथा साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकन यूनियन और आईजीएडी को सोमालिया में सामाजिक और आर्थिक विकास मजबूत करने संबंधी उनके प्रयासों के लिए उन्हें पूरी सहायता देने की पुनरावृत्ति की।

भारत के उच्च आयुक्त दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को नैरोबी में सोमालिया के पुंटलैंड राज्य के राष्ट्रपति से मिले और सोमाली लुटेरो द्वारा कैद शेष आठ भारतीय बंधकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने में उनकी सहायता मांगी।

सोमाली समुद्री डकैती निरोधी कार्यबल के अध्यक्ष और प्रो. मुहयाद्दीन अली युसुफ, समुद्री डकैती संबंधी मामलों पर भारत में सोमालिया के विशेष दूत, ने नवम्बर, 2013 में नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों से बैठकें की।

उच्च आयुक्त ने 21–22 जनवरी, 2014 को मोगादिशु की यात्रा की और वे सोमाली राष्ट्रपति श्री हसन शेख मोहम्मद, प्रधान मंत्री श्री अब्दीवली शेख अहमद और प्रधान सचिव, विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्री अब्दी दिर्शे से मिले। उच्च आयुक्त ने सोमाली कैद में आठ ज्ञात और एक अज्ञात समुद्री नाविकों के कारणों के बारे में जानना चाहा।

सोमाली विदेश राज्य मंत्री श्री बुरी मोहम्मद हमजा ने सीआईआई–एग्जिम बैंक भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी कांक्लेव में भाग लेने के लिए 8–11 मार्च, 2014 को भारत का दौरा किया। उन्हें श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व) विदेश मंत्रालय ने आमंत्रित किया और समुद्री डकैती, सोमालिया में भारतीय बंधकों, भारत की हिरासत में 120 सोमाली लुटेरों के मुकदमों और सोमालिया में क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका संबंधी मुद्दों पर बातचीत की।

दक्षिणी अफ्रीका

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 26–27 मार्च, 2013 को डर्बन में आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन में भाग लिए। उनके साथ वित्त मंत्री श्री पी.

चिदम्बरम एवं वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा थे। शिखर सम्मेलन में एक "थेकवीनी घोषणा" और एक कार्ययोजना को अपनाया गया।

श्रीमती प्रवीण महाजन, अध्यक्ष, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क ने श्री पशुपति नाथ पांडे, अपर निदेशक, राजस्व सतर्कता महानिदेशालय के साथ 7–8 मार्च, 2013 को हुई ब्रिक्स सीमा शुल्क प्रशासक प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया।

श्री वी.एस. सम्पत, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इलैक्ट्रोनिक मतदान और गणना तकनीक पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 10–14 मार्च, 2013 को दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया। श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय और श्री दिनेश भाटिया, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स शेरपा/सूस–शेरपा बैठक में भाग लेने के लिए 22–23 जुलाई, 2013 को दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया।

''विश्व खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव'' विषयक ब्रिक्स, कृषि एवं भू–सम्पदा विकास मंत्रियों की तीसरी बैठक 28–29 अक्टूबर, 2013 को प्रेटोरिया में आयोजित की गई। श्री शरद पवार, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल ने तीसरी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 5–8 नवम्बर, 2013 को केप टाउन का दौरा किया। श्री टी.रामस्वामी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पहली ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 9–10 फरवरी, 2014 को केप टाउन का दौरा किया। मंत्रीय बैठक का विषय ''उचित वृद्धि और धारणीय विकास के लिए अनुकूल भागीदारी'' था।

डा. बी.ए. अग्रवाल, विधि सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल विधायी सलाहकार संघ सम्मेलन–2013 में भाग लेने के लिए 9–14 अप्रैल, 2013 को केप टाउन का दौरा किया। दक्षिणी अफ्रीका संसद ने ''राष्ट्रमंडल विकासीय चुनौतियों का प्रभावी समाधान'' विषय पर 28 अगस्त से 6 सितम्बर, 2013 को 59वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सभा (सीपीए) का आयोजन किया। जोहनसबर्ग में आयोजित सम्मेलन में 25 भारतीय राज्यों की विधान सभा के शिष्टमंडल ने भाग लिया।

श्री राजीव महर्षि, सचिव, प्रवासी भारतीय मामले, मंत्रालय एवं सुश्री सुजाता सुदर्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र और सुश्री टीना कुराकोज जैकोब ने जोहनसबर्ग, केप टाउन और डरबन में आयोजित ''आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को गहरा बनाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका'' सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23–29 अप्रैल, 2013 को दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

श्री दिनेश भाटिया संयुक्त सचिव (बहुआयामी आर्थिक संबंध) विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 6ठे इब्सा शिखर सम्मेलन के संबंध में परामर्श हेतु 2–5 मई, 2013 को दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया। श्रीमती रीवा गांगुली दास संयुक्त सचिव (लोक कूटनीति)ए विदेश मंत्रालय ने "भारत–अफ्रीका एक सांझा भविष्य" आयोजन के सिलसिले में 16–17 मई, 2013 को दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। श्री टी.एस त्रिमूर्ति, संयुक्त सचिव (यूएनईएस), विदेश मंत्रालय और श्री रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, नई दिल्ली से युक्त दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने 15वीं बेसिक मंत्रीय समन्यव बैठक में भाग लेने के लिए 25–29 जून, 2013 को केप टाउन का दौरा किया।

डॉ. अरविन्द गुप्ता, महानिदेशक, रक्षा अध्ययन विश्लेषण और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) ने आईडीएसए और अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय मामले संस्थान (एसएआईआईए) वार्ता में भाग लेने के लिए 27–28 मई, 2013 को दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

23 मई, 2013 को भारत ने इंडिया हाउस प्रिटोरिया में आईओआर–एआरसी मिशन प्रमुखों के कार्य समूह की 14वीं बैठक की मेजबानी की।

श्री माधवलाल, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में एक 03 सदस्यीय शिष्टमंडल ने जोहनसबर्ग में सेटेक्स (एसएआईटीईएक्स) मेले में भाग लेने के लिए 30 जून से 03 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और डर्बन में उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।

श्री प्रवीण कुमार तिवारी, निदेशक, वित्त एवं सूचना एकक के नेतृत्व में एक 2 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 जून से 05 जुलाई 2013 को दक्षिण अफ्रीका में हुई इग्मोंट ग्रुप प्लेनरी और कार्यसमूह की बैठक में भाग लिया। श्री प्रेम आनन्द सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने "अवैधनशा उत्पादन और व्यापार संबंधित वित्तीय प्रवाह" पर सन सिटी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

श्री ए.आर. राथेर, वित्त एवं लदाख मामले मंत्री, जम्मू और कश्मीर के नेतृत्व में राज्य वित्त मंत्रालय की एक 28 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति शिष्टमंडल ने 24 जुलाई से 4 अगस्त, 2013 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। शिष्टमंडल श्री प्रवीण गोर्धान, वित्त मंत्री, दक्षिण अफ्रिका से मिला और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कोष और दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा से प्रिटोरिया में बैठकें की।

'तीसरी भारत–दक्षिण अफ्रीका व्यापार मंत्री स्तरीय' और दूसरी भारत–अफ्रीका व्यापार परिषद बैठकें 30 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2013 तक जोहनसबर्ग में आयोजित की गईं। श्री आनन्द शर्मा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

श्री हेम पांडे, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नेतृत्व में

एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने पहुच और लाभ साझा वार्ता (एबीएस) बैठक में भाग लेने के लिए 29–31 जनवरी, 2014 को केप टाउन का दौरा किया।

श्री अंशु प्रकाश, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एसटीपीओ–टीबी भागीदारी की बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए 29 जनवरी से 01 फरवरी, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया।

उप व्यापार और उद्योग मंत्री एलिजाबेथ थाबेथे के नेतृत्व में एक 40 सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल ने भारत में दक्षिण अफ्रीका को व्यापार और निवेश स्थान के रूप में बढ़ावा देते हुए दक्षिण अफ्रीका के मूल्यवर्धित उत्पाद एवं सेवाओं के लिए बाजार की पहुंच उपलब्ध कराने पर लक्षित 5 वें वार्षिक व्यापार उपक्रमों में निवेश (आईटीआई) के लिए फरवरी, 2014 में चेन्नई और मुम्बई का दौरा किया।

भारतीय नौ सेना का पाल जहाज (आईएनएसवी) 'महादेई' ने केप से रिओ जलयान दौड़ 2014 में भाग लिया जो 04 जनवरी, 2014 को केप टाउन से शुरू हुई थी।

दक्षिणी सूडान

राष्ट्रपति साल्वा कीर और पूर्व उप–राष्ट्रपति रेक मचार के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण दिसम्बर, 2013 में एक गंभीर राजनीतिक और नीतिपरक संकट खड़ा हो गया परिणामस्वरूप तेल उत्पादन (आर्थिक स्थिति का प्रमुख साधन) बंद हो गया। अन्तः सरकारी विकास प्राधिकारी (आईजीएडी) द्वारा गहन सरलीकरण के परिणामस्वरूप विद्रोहियों के युद्धविराम पर शांति समझौता हुआ और राजनीति बंधकों को छोड़ दिया गयाए तथापि वास्तविक रूप से कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बना रहा। श्री संदीप कुमार, संयुक्त सचिव (कार्मिक) सहित विदेश मंत्रालय की 02 सदस्यीय टीम ने देश में भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षा सहित पहली नजर में राजनीति और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए 5–7 जनवरी, 2014 को जुबा का दौरा किया। जुबा में स्थित मिशन ने 23 दिसम्बर 2013 को दक्षिण सूडान में भारतीयों को देश छोड़ने के लिए एक सलाह–पत्र जारी किया। भारी संख्या में भारतीय हवाई जहाज और सड़क मार्ग से पड़ोसी देश जैसे यूगांडा, इथोपिया और केन्या चले गए। 19 दिसम्बर 2013 को दक्षिणी सूडान (यूएनएमआईएसएस) में यूएन मिशन के दो भारतीय शांतिकर्ताओं (सुलहकार) अकोबो (जोगंलेई राज्य) में यूएनएमआईएसएस परिसर में विद्रोही हमले में मारे गए। इससे पहले 9 अप्रैल, 2013 को 05 भारतीय शांतिकर्ता जोगंलेई राज्य में यूएन काफिले पर एक सशस्त्र विद्रोही ग्रुप हमले में मारे गए।

भारत–दक्षिण अफ्रीका चैम्बर्स ऑफ कामर्स और उद्योग (आईएसीसीआई) द्वारा प्रायोजित एक 18 सदस्यीय व्यापार शिष्टमंडल ने 29 अप्रैल से 01 मई, 2013 को जुबा का दौरा किया। शिष्टमंडल दक्षिणी सूडान सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिला और दक्षिण सूडानी कम्पनियों और चैम्बर्स ऑफ कामर्स के साथ लाभकारी बात–चीत की।

सूडान और दक्षिणी सूडान में भारत के विशेष राजदूत श्री पी. एस. राघवन ने संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए)ए श्री संदीप कुमारए विदेश मंत्रालय के साथ दिनांक 8–9 अगस्तए 2013 को जूबा का दौरा किया और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना और जूबा शिक्षण अस्पताल के मातृत्व केन्द्र के उन्नयन के साथ–साथ दक्षिणी सूडान के साथ भारत के विकास संबंधी भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया। सूडान–दक्षिणी सूडान के राजनीतिक विवाद से उत्पन्न होने वाले ओवीएल के ऊर्जा हितों से संबंधित सरोकारों पर भी विशेष बल दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के दलों ने अपनी परियोजनाओं अर्थात दक्षिणी सूडान के संबंधित प्राधिकरणों के साथ ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए अगस्त, 2013 में जूबा का दौरा किया।

दिनांक 27 अगस्तए 2013 को राष्ट्रपति सेलवा कीर का भारत का दौरा तय थाए लेकिन आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनकी तरफ से दौरा रद्द कर दिया गया था।

सूडान

सूडान के वित्त और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री ने जुलाई 2013 में भारत का अधिकारिक दौरा किया और दो करारों पर हस्ताक्षर किए दृ (i) ऋण श्रृंखला पर ब्याज का पूंजीकरण (विगत में भारत सरकार द्वारा सूडान सरकार को प्रदत्त) (ii) मशकौर शूगर कंपनी के लिए ऋण श्रृंखला के 125 मिलियन अमरीकी डॉलर के दूसरे भाग को जारी करने के लिए एक्जिम बैंक और सूडान सरकार के बीच करार।

भारतीय–सूडान एफओसी का 5वां दौर दिनांक 28 नवंबर, 2013 को खार्तूम में आयोजित किया गया थाए जिसके दौरान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की गई और इससे संबंधित चुनौतियों की पहचान की गई।

भारत सरकार द्वारा सूडान सरकार को वित्तपोषित ऋण श्रृंखला की अवधि के दौरान बीएचईएल ने कोस्ती विद्युत संयंत्र की दो इकाईयों (125 मेगावाट) को सफलतापूर्वक सक्रिय किया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 4–5 फरवरी 2014 को सूडान का दौरा किया और राष्ट्रपति, विदेशमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की। सूडान पक्ष ने विदेश मंत्री को यह बताया कि सूडान के विदेश संबंधों में भारत उनका पसंदीदा देश रहा है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने सूडान के भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों

के साथ बातचीत की। इस यात्रा में सूडानी अल–जेईम अल–अज़र विश्वविद्यालय द्वारा विदेश मंत्री को डॉक्टर की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के नाटक 'सन्स ऑफ बालर' के अरबी संस्करण का भी विमोचन किया गया।

सूडान के उद्योग मंत्री श्री इल स्मैह इल सिद्दिकने सीआईआई–एक्जिम बैंक इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 8–11 मार्च, 2014 को भारत का दौरा किया। उन्होंने सीआईएमए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रीए विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य मामलों के सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय से बातचीत की।

स्वाजीलैंड

भारत ने स्वाजिलैंड को दो ऋण श्रृंखला प्रदान की अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर और स्वाजिलैंड में कृषि विकास और कृषि परियोजना के यांत्रिकीकरण के लिए 37.9 मिलियन अमरीकी डॉलर। ये परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत ने क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना जारी रखा। वर्ष 2012–13 में आईटीईसी के तहत सात स्वाजी नागरिक भारत आए। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 107.89 मिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया।

तंजानिया

दार–ए–सलाम शहर और चलिनज़े क्षेत्र में जल आपूर्ति संवर्धन के लिए अक्तूबर, 2012 में 178.125 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला को अंतिम रूप दिया गया। तंजानीया सरकार ने 40 मिलियन अमरीकी डॉलर की पिछली ऋण श्रृंखला के तहत 1800 ट्रैक्टर और संबंधित फार्म उपकरणों के सफलतापूर्वक आयात के बाद ट्रैक्टर और फार्म उपकरण की खरीद के लिए दूसरी ऋण श्रृंखला के लिए अपने अनुरोध को दोहराया है। वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही तक, सभी ट्रैक्टरों को या तो बेच दिया गया या पट्टे पर दे दिया गया। तंजानिया रक्षा सेनाओं को अशोक लेलैंड ट्रक और अन्य वाहनों की आपूर्ति के लिए 36.56 मिलियन अमरीकी डॉलर हेतु ऋण श्रृंखला के तहत, अक्तूबर, 2013 तक 85 प्रतिशत से भी अधिक आपूर्ति पूरी कर ली गई। दिनांक 7 अगस्त, 2013 की दर–ए–सलाम में औपचारिक सुपुर्दगी समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री ने भाग लिया।

आरूषा में नेलसन मंडेला अफ्रीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र की स्थापना में भारतीय सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत गैस प्राधिकरण (गेल) के अधिकारियों ने तंजानिया में गैस उद्यम के सभी खंडों में रोजगार के अवसरों में गेल के हितों पर तंजानिया पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ विचार–विमर्श करने के लिए वर्ष में दो बार दार–ए–सलाम का दौरा किया।

तंजानिया के एक बड़े शिष्टमंडल ने विशेष रूप से प्राकृतिक गैस सहित ऊर्जा संपत्ति के भारत के प्रबंधन को देखने के लिए सितंबर, 2013 में भारत का अध्ययन दौरा किया, इसमें ऊर्जा पर संसदीय स्थाई समिति के सभी सदस्य और ऊर्जा एवं खनिज मंत्रालय और टीपीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने 5–7 अप्रैल, 2013 को तंजानिया का दौरा किया। उन्होंने ऊर्जा और खनिज मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विचार–विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान सहयोग के क्षेत्रों पर, एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री ने 8–10 जुलाई, 2013 को दार–ए–सलाम का दौरा किया। उन्होंने तंजानिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ परस्पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के मामलों पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने भारतीय– तंजानिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह–अध्यक्षता की।

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने 24–26 सितंबर, 2013 को दार–उस–सलाम का दौरा किया। उन्होंने तंजानिया के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 'द इंडिया शो' के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त व्यापार समिति की तीसरीबैठक की सह–अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के एक 18 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मई 2013 में तंजानिया का दौरा किया और तंजानिया रक्षा बलों, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय तंजानिया रक्षा कॉलेज, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत की।

जिन्जीबार के श्रम, आर्थिक सशक्तिकरण और सहकारिता मंत्री ने 28–30 मई, 2013 को भारत का अध्ययन दौरा किया, इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के श्रम और रोजगार मंत्री के साथ बैठकें की। उन्होंने बेयरकुट कॉलेज, टिलोनिया का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जांजीबार की कुछ ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने और उसके रखरखाव के लिए प्रशिक्षण दिया और इस उद्देश्यार्थ तंजानिया में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

दिसंबर, 2013 में भारतीय नौसेना के 'आईएनएस जमुना', एक हाइड्रोग्राफिक जहाज ने तंजानिया का दौरा किया और दार–ए–सलाम बंदरगाह और आस–पास के तटीय क्षेत्रों का विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया।

जिन्जीबार के राष्ट्रपति, श्री अली मोहम्मद शीन, ने भारत के उप–राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद 1–9 फरवरी, 2014 के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों के शिष्टमंडल के साथ भारत का दौरा किया।

कैमेक्सिल के एक शिष्टमंडल ने इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को संघटित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई 2013 में बी–टू–बी बैठकें के लिए दार–ए–सलाम का दौरा किया। कर्मेशियल द्वारा आयोजित मध्यम और लघु उद्योगों से सम्मिलित भारतीय औषध उद्योग के 25 सदस्य शिष्टमंडल ने 12–15 मार्च, 2014 के दौरान तंजानिया का दौरा किया।

विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के दल ने भारतीय सहायता से जांजीबार में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर व्यवहार्यत अध्ययन करने के लिए 1–5 फरवरी, 2014 के दौरान जांजीबार और दार–ए–सलाम का दौरा किया।

गांबिया

भारत सरकार ने गांबिया में प्रतिष्ठित नेशनल असेंबली के निर्माण को पूरा करने के लिए गांबिया को 16.88 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी है। गांबिया के नागरिकों द्वारा हमारे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अवसरों के इष्टतम उपयोग के दृष्टिगत, गांबिया को एससीएएपी कार्यक्रम के तहत 40 स्लॉट आबंटित किए गए थे।

टोगो

श्री सुधीर मित्तल, सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में भारतीय उर्वरक शिष्टमंडल ने खनन और उर्वरक के क्षेत्रों में सहयोग पर विचार–विमर्श करने के लिए जून, 2013 में टोगो का दौरा किया।

वाणिज्य मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मण्डल (सीसीआईटी) और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के सहयोग से दिनांक 26 अगस्त, 2013 को लोम में सार्वजनिक और निजी सेक्टर के बीच भागीदारी के सशक्तिकरण के ढांचे के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की।

श्री अरविंद कौशल, अपर सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 03 सदस्य भारतीय शिष्टमंडल ने भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के तहत टोगो में कृषि बीज उत्पादन–सह–प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना के संबंध में 3–6 दिसंबर, 2013 को टोगो का दौरा किया।

टोगो के वाणिज्य एवं निजी सेक्टर संवर्धन मंत्री ने दिनांक 9–11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं एक्जिम बैंक–सीआईआई कॉन्क्लेव में 7 सदस्य शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

ट्यूनीशिया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ट्यूनीशिया–भारत संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का तीसरा सत्र दिनांक 24 मई, 2013 को ट्यूनीश में आयोजित किया गया। संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भारतीय और ट्यूनीशियन वैज्ञानिकों द्वारा विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों के लिए संयुक्त निधियन पर विचार–विमर्श किया गया।

श्री श्रीकांत के जेना, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारत–ट्यूनीशिया के संयुक्त उद्यम के टीआईएफईआरटी संयंत्र को प्रारंभ करने के उद्देश्य से 11–13 जुलाई, 2013 को ट्यूनीशिया का तीन–दिवसीय दौरा किया।

4 सदस्य आईआईएफटी विशेषज्ञ दल ने 22–28 सितंबर, 2013 तक ट्यूनिश का दौरा किया और ट्यूनीशिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय के राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से ट्यूनीशिया के अधिकारियों के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास कार्यक्रम (ईडीपीआईबी) का आयोजन किया।

अफ्रीका के पहले, महिन्द्रा पिक–अप ट्रक के नए असेंबली संयंत्र को दिनांक 30 अक्तूबर, 2013 को ट्यूनीशिया में स्थापित किया गया था।

औषधि पर संयुक्त कार्य समूह का 5 वा सत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 2–3 फरवरी, 2014 को ट्यूनिशिया का 2 दिवसीय अधिकारिक दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्यूनीशिया सरकार और नेतृत्व द्वारा सशक्त लोकतंत्र की संक्रांति पर की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर भारत द्वारा की गई प्रशंसा व्यक्त की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत की सहायता की पेशकश की।

युगांडा

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ मिशन सम्मेलन के क्षेत्रीय प्रमुखों की अध्यक्षता के लिए अप्रैल, 2013 में कंपाला का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने यूगांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात की और विदेश मंत्री और यूगांडा सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

सुश्री दीपा दास मुंशी, शहरी विकास राज्य मंत्री ने 7वें राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी फोरम में भाग लेने के लिए मई 2013 में कंपाला का दौरा किया।

यूगांडा सरकार के अनुरोध पर यूगांडा के सीनियर कमांड और कर्मचारी कॉलेज में संस्वीकृत भारतीय सेना प्रशिक्षण दल (आईएमटीटी) के कार्यकाल को तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यूगांडा में पैन अफ्रीका ई–नेटवर्क परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है।

चमड़ा निर्यात परिषद के शिष्टमंडल, एनएएसएससीओएम और एसटीओएनए ने जुलाई–सितंबर, 2013 के दौरान उपयुक्त व्यावसायिक भागीदारों की पहचान करने के लिए कंपाला का दौरा

किया।

प्रोफेसर डॉ. जेरूबाबेल एम नाइरा कृषि राज्य मंत्री, यूगांडा सरकार ने फरवरी, 2014 में फिक्की द्वारा आयोजित एशिया–अफ्रीका कृषि व्यवसाय फोरम 2014 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

यूगांडा के वित्त एवं आर्थिक योजना और विकास मंत्री, सुश्री मारिया किवानुका ने 10वें सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए मार्च, 2014 में भारत का दौरा किया।

ज़ाम्बिया

भारतीय–अफ्रीकी परियोजना भागीदारी पर दिनांक 17–19 मार्च, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें सीआईआई–एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में ज़ाम्बिया मुख्य देश रहा। ज़ाम्बिया के उपराष्ट्रपति डा. गॉय स्कोट ने कॉन्क्लेव में उच्चस्तरीय 25 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

वर्ष के दौरान, भारतीय–जाम्बियन व्यापार और व्यावसायिक संबंध सशक्त एवं जीवंत रहे और दोनों पक्ष इस संबंध का विकास करने और इसका विस्तार करने के इच्छुक रहे। सीआईआई के पूर्वी क्षेत्र के एक 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ने नए व्यापार और निवेश अवसरों को तलाशने के उद्देश्य से 26–28 जून, 2013 के दौरान जांबिया का दौरा किया। भेषज क्षेत्र में, गोवा की अन्य कंपनी, एनआरबी फार्मा लिमिटेड ने लुसाका दक्षिणी बहु–सुविधा आर्थिक क्षेत्र (एमएफईजेड) में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

भारत और जाम्बिया दोनों पक्षों ने ही स्वास्थ्य–देखभाल के क्षेत्र में निरंतर रूचि दिखाई है। भारत के अपोलो अस्पताल ने कौशल के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, चिकित्सा कैंप आयोजित करने, डाक्टरों के प्रशिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों के कौशल में सुधार लाने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2013 को जाम्बिया चिकित्सा संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री एमेन्यूल चेंडा, जाम्बिया के वाणिज्य व्यापार और उद्योग मंत्री ने 22–24 जनवरी, 2014 के दौरान मुंबई में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो 2014 में भाग लिया।

श्री ग्रिफोर्ड मोंडे, जाम्बिया के कृषि एवं पशुधन उप मंत्री ने 4–6 फरवरी, 2014 के दौरान नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित एशिया–अफ्रीका कृषि व्यापार मंच में भाग लिया।

लुसाका के मेयर, श्री डेनियल चेसेंगा ने 9–11 मार्च, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सीआईआई–एक्जिम बैंक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

जिम्बाब्वे

भारत के एक्सिम बैंक और जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार के बीच हरारे में दिनांक 21 जून, 2013 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग स्टेशन और रिवर वाटर इनटेक सिस्टम के संवर्धन के लिए 28.6 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला प्रदान की गई। मैसर्स वाटर एंड पावर इस परियोजना कंसल्टेंसी सर्विस (डब्ल्यूएपीसीओएस) को इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता नियुक्त किया गया।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, भारत द्वारा दिनांक 28 सितंबर से 06 अक्तूबर, 2013 के दौरान हरारे में भारतीय हस्तशिल्प क्रेता–विक्रेता सम्मेलन–सह प्रदर्शनी आयोजित की गई।

दिनांक 27–28 मार्च, 2013 को हरारे में दूसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री ने किया और जिम्बाब्वे पक्ष का नेतृत्व प्रो. वेल्समेन नूबे, तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने किया। श्री आनंद शर्मा ने दूसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 2–4 फरवरी, 2014 के दौरान हरारे का पुनः दौरा किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 8–10 अप्रैल, 2013 के दौरान जिम्बाब्वे का दौरा किया और जिम्बाब्वे के खान और खनन विकास मंत्री, पर्यटन और अतिथि सत्कार मंत्री, और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया।

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में 14–28 अप्रैल, 2013 के दौरान एक शिष्टमंडल जिम्बाब्वे गया और इस शिष्टमंडल ने ऊर्जा एवं विद्युत विकास मंत्री और जल संसाधन विकास और प्रबंधन मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया।

भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के अंतर्गत घटनाक्रम

अभी तक आयोजित दो भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलनों के दौरान किए गए विचार–विमर्श का कार्यान्वयन वर्ष 2013–14 के दौरान भी जारी है। मिस्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के बीच दिनांक 15 मार्च, 2013 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणामस्वरूप एनसीआईसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान 19 मार्च 2013 को मिस्र की नोडल एजेंसी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। सितंबर, 2013 में सेंट्रल टूल रूम प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर पर आईएएफएस के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राजदूत जीन–बेपटाइस्ट नटामा में, एयूसी अध्यक्ष ब्यूरो के सेना प्रमुख के नेतृत्व में अफ्रीकन संघ आयोग (एयूसी) से 4–7 सितंबर, 2013 के दौरान चार सदस्यों के शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान आईएएफएस–II के सहयोग के उन्नत ढांचे

की संयुक्त कार्य योजना नई दिल्ली में प्रारंभ की गई। विजिटिंग शिष्टमंडल ने कृषि और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श भी किया और उन्होंने एनएसआईसी, आईआईएफटी, टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड और वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस का दौरा किया।

भारत और अफ्रीका के बीच सांस्थानिक वचनबद्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान विभिन्न सम्मेलन और दौरे आयोजित किए गए, जिसमें 17–19 मार्च, 2013 को भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 9वीं सीआईआई एक्जिम बैंक कान्वलेव शामिल है। विमो सेवा ने अपनी परियोजना : ''अफ्रीकी लोगों के संगठन और गैर सरकारी संगठनों के सशक्तिकरण'' के तहत अप्रैल–मई, 2013 के दौरान डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्रों के दौरे किए और कार्यशाला आयोजित की। विमो सेवा ने 13–28 अगस्त, 2013 के दौरान अदिस–अबाबा, इथोपिया में स्थल निरीक्षण और कार्यशाला आयोजित की।

विभिन्न अफ्रीकी देशों से युवा सांसदों के एक शिष्टमंडल ने 8–16 मार्च, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। यह दौरा आईएएफएस निर्णयों के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने भारत–अफ्रीका कांक्लेव में भी भाग लिया।

8वां सीआईआई औद्योगिक सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम 9–18 मार्च, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष 18 देशों से वाणिज्य मंडल के 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ की भागीदारी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और अन्य भारतीय संस्थानों के लिए सी.वी. रमन अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के लिए 30 अफ्रीकी देशों से 137 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

विदेश मंत्रालय और एनएसआईसी के बीच बंजुल, गांबिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 28 मार्च, 2014 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंधों से संबंधित गतिविधियां

अफ्रीकी संघ के आरंभ से ही, भारत विभिन्न शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग लेता रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम. हामिद अंसारी ने दिनांक 25 मई, 2013 को अफ्रीकी संघ के विशेष स्वर्ण जयंती स्मरणीय शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

अफ्रीकी संघ आयोग (एयूसी) के एक 04 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 4–7 सितंबर, 2013 को भारत का दौरा किया।

श्री धिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय ने वार्षिक अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जनवरी, 2014 में अदिस–अबाबा के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

यूरोप और यूरोपीय संघ

7

अलबेनिया

सितंबर 2013 मे नई सरकार के कार्यभार ग्रहण करते ही, रोमानिया में भारत के राजदूत, जिन्हें इसके साथ–साथ अलबेनिया का कार्यभार भी सौंपा गया है, ने 19–21 दिसंबर 2013 को अलबेनिया का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर विचार–विमर्श किया। श्री बुराती ने फार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भारत के निवेश को आकर्षित करने की इच्छा भी व्यक्त की।

ऑस्ट्रिया

भारत और ऑस्ट्रिया में प्रगाढ और सौहार्दपूर्ण संबंध है। वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय दौरों, व्यावसायिक शिष्टमंडलों और सांस्कृतिक दलों के आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंधों से और सशक्त बनाया गया।

प्रवासी भारतीय मंत्री श्री वायलर रवि के नेतृत्व् में एक 2 सदस्यीय शिष्टंमंडल ने 3 से 6 फरवरी, 2013 को ऑस्ट्रिया का दौरा किया। दौरे के दौरान दिनांक 4 फरवरी, 2013 को दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 26–28 फरवरी, 2013 को यूएन–एलाइन्सं ऑफ सिविलाइजेशन (यूएनएओसी) पर ग्लोबल फोरम की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया का दौरा किया।

भारत की संस्कृति मंत्री, श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच ने 5–8 अप्रैल, 2013 को ऑस्ट्रिया का दौरा किया और सस्लो्स सेस्लारबर्ग में प्रदर्शित "इंडिया ऑफ द महाराजास" नामक प्रदर्शनी के साथ–साथ अनुप्रयुक्त् कला विश्वपविद्यालय, विएना के सरल केंद्र का दौरा किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री वी. नारायण सामी ने अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेतलन में भाग लेने के लिए 30 जून से 3 जुलाई, 2013 को विएना का दौरा किया।

भारत–ऑस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग के 13वें सत्र का आयोजन 11 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में किया गया।

ऑस्ट्रिया विदेश मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी डॉ. रेनॉल्ड लोपेटका के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने नई दिल्ली में आयोजित 11वीं एशिया–यूरोप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 11–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया।

बोस्निया और हरजेगोविना

भारत और बोस्निया और हरजेगोविना के संबंध मैत्रीपूर्ण और प्रगाढ़ है। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को बढाने के लिए ध्यान देते रहे हैं। विदेश मंत्री और मॉडरेट बोजनियेक पार्टी एसडीपी के अध्यक्ष डॉ. ज्लेटको लगुमजा के साथ एक बड़े व्यापार शिष्टमंडल ने दिनांक 24–28 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री और श्री फारूख अब्दुल्ला, नवीन एवं नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। डॉ. ज्लेटको लगुमजा ने बोस्निया और हरजेगोविना के विदेश व्याापार चैंबर और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''बोस्निया और हरजेगोविना के साथ व्यापार'' नामक एक बिजनेस फोरम को संबोधित किया।

बुल्गावरिया

वर्ष के दौरान भारत और बुल्गाररिया के बीच संबंध प्रगाठ बने रहे। विदेश मंत्री क्रिस्ट्रेन विगेनिन ने ऐरूम विदेश मंत्रियों 11वीं एएसईएम एफएम की बैठक में भाग लेने के लिए 11–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। उप विदेश मंत्री एंजिल वैलिटश्कॉफ ने नई दिल्ली में भारत–बुल्गारिया एफओसी के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2014 को एक शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया। आर्थिक और ऊर्जा उप मंत्री आना यानीवा ने मुंबई में इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो में भाग लेने के लिए 22 जनवरी, 2014 को भारत का दौरा किया। उप रक्षा मंत्री ईवान इवानोव ने दिनांक 6–9 फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया और डीईएफईएक्सवपीओ इंडिया–2014 में भाग लिया। बुल्गारिया के आर्थिक और ऊर्जा मंत्रालय से दो सदस्यीय शिष्टएमंडल ने फिक्की के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित भारत–मध्य यूरोप व्यावपार फोरम में भाग लेने के लिए दिनांक 27–28 मार्च, 2014 को भारत का दौरा किया।

बुल्गारिया ने 2013 और 2014 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले

एसएटीटीई पर्यटन प्रदर्शनी में भाग लिया।

बॉलीवुड की 100वीं वर्षगांठ पर नमस्ते बुल्गाईरिया भारतीय फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण 30 मई से 6 जून, 2013 तक सोफिया हाउस सिनेमा में आयोजित किया गया। सोफिया विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग ने 9–10 सितंबर, 2013 तक ''भारत से, भारत को– विचार और दृष्टिकोण'' नामक सम्मेलन के साथ अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई।

क्रोएशिया

भारत और क्रोएशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी रहे। इस अवधि के दौरान सतत आदान प्रदान के द्वारा ये संबंध और अधिक सशक्त हुए।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 11–13 फरवरी, 2014 तक क्रोएशिया का दौरा किया और अपने समकक्ष डॉ. वेस्ना प्युसिक, प्रथम उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं यूरोपीय कार्य मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया और क्रोएशिया के वित्त मंत्री स्लोवको लीनिक के साथ दोहरा कर परिहार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के एचएलएल बायोटेक आफ इंडिया ने क्रोएशिया इम्यूनोलाजी संस्थान के साथ एक करार किया, जिसके तहत क्रोएशिया संस्थान खसरे का टीका प्रदान करेगा और भारत में औषधि के उत्पादन के लिए भारत को प्रौद्योगिकी भी प्रदान करेगा। अगले 5 वर्षों में इस व्यापार की अनुमानित लागत 5 बिलियन अमरीकी डॉलर होगी।

भारतीय दूतावास ने क्रोशियाई गैर सरकारी संगठनों, लोटोस संघ और महात्मा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से 25 अप्रैल से 10 मई, 2013 तक जगरेब में 5वें "डेज ऑफ इंडियन कल्चर" का आयोजन किया। इस वर्ष का शीर्षक "भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष" था। 3 सदस्य क्रोएशिई लेखक शिष्टमंडल ने दिनांक 16–23 सितंबर, 2013 तक भारत का पारस्परिक दौरा किया, जिसकी मेजबानी साहित्य अकादमी द्वारा की गई।

साइप्रस

श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री ने 10–13 अप्रैल, 2013 तक साइप्रस का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निकोस एनसटासियाडेस, साइप्रस लोकसभा में साइप्रस–भारत मैत्री समूह के अध्यक्ष, एविरोफ न्योनटयू और विदेश मंत्री आयोनिश कासोलीडस के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विचार–विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुधार और यूएनएससी की स्थायी सदस्यंता के लिए भारत की सदस्यता भी विचार–विमर्श का विषय था।

साइप्रस के विदेश मंत्री आयोनिश कासोलीडस ने नई दिल्ली में आयोजित एएसईएम एफएमएम–11 में भाग लेने के लिए 10–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के विदेश मंत्री ने दिनांक 10 नवंबर, 2013 को विदेश मंत्री से मुलाकात की।

अंतरदेशीय राजस्व विभाग के निदेशक श्री जॉर्ज प्योफस के नेतृत्व में साइप्रस के एक शिष्टमंडल ने भारत–साइप्रस दोहरा काराधान करार (डीटीएए) के संशोधन/प्रोटोकॉल पर बातचीत के लिए 26–27 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया।

चेक गणराज्य

श्री मार्टिन कुबा, व्यापार एवं उद्योग मंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले भारत इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो–2013 में भाग लेने के लिए 11–15 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया। उनके साथ अधिकारी और व्यायपार शिष्ट मंडल भी आया और उन्होंने वाणिज्यम, उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा और कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें थी।

डॉ. जारोस्लो व वेकीक, निदेशक, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, पराम्वे में दक्षिणी और केंद्रीय एशियाई अध्ययन संस्थान, ने वर्ष 2009–10 के लिए दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्र पति से ''शास्त्री य तमिल राष्ट्रपति पुरस्कार'' ग्रहण किया।

विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर दिनांक 2 मई, 2013 में पराम्वे में आयोजित किया गया।

चेक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री जन कोहाउट ने दिनांक 10–12 नवंबर, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एएसईएम एफएमएम–11 में भाग लेने के लिए 6–11 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, भारी उद्योग मंत्री श्री प्रफुल्लो पटेल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा, संस्कृति मंत्री श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री मनीष तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने फिल्म उद्योग के क्षेत्र में भारत और चेक गणराज्या के बीच सहयोग को सशक्त करने की दृष्टि से भारतीय फिल्म निर्माता संघ के गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात की।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक प्रतिनिधि मंडल ने मेश्रेरक यूनिवर्सिटी में कोरियोग्राफी पाठ्यक्रम पर करार को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए 9–13 सितंबर, 2013 को चेक गणराज्य का दौरा किया। भारतीय नौसेना से एक अधिकारी सहित डीआरडीओ से 13 अधिकारियों ने मेश्रेक यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर से 20 दिसंबर, 2013 तक ''सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अल्पकालीन गहन पाठ्यक्रम'' पर पाठ्यक्रम में भाग लिया। यह पाठ्यक्रम डीआरडीओ और मेश्रेक यूनिवर्सिटी की बीच आपसी करार के आधार पर आयोजित किया गया था।

सचिव (वस्त्र), सुश्री जोहरा चौटर्जी ने 16–21 सितंबर, 2013 को चेक गणराज्य का दौरा किया और वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और पटसन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टेक्नीऔकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिबरेस में बैठकें की रक्षा प्रबंधन कॉलेज से 24 अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रबंधन दौरे के भाग के रूप में 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2013 तक चेक गणराज्य का दौरा किया।

चेक गणराज्य, भारत–मध्य यूरोप व्यापार फोरम (आईसीईबीएफ) में एक महत्वपूर्ण देश बन गया, जिसे विदेश मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से 27–28 मार्च, 2014 को आयोजित किया।

डेनमार्क

भारत– डेनमार्क के संबंध 1995 में पुर्लिया आर्म्स ड्राप केस में शामिल डेनमार्क के नील्स हॉक उर्फ किम डेवी को भारत प्रत्यायर्पित न करने से रूप से प्रभावित हुए है।

यात्रा के दौरान आय और पूँजी पर करों के संबंध में दोहरा काराधान परिधार और राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए हमारे राजदूत श्री नीनज श्रीवास्तमव और डेनमार्क के कर मंत्री श्री होलगर के नीलसन ने 10 अक्तूबर, 2013 को कोपेनहेगन में करार के प्राटोकोल संशोधन पर हस्ता क्षर किए।

एस्टोनिया

एस्टोनिया के विदेश मंत्री श्री उर्मस पेट, ने 12–13 फरवरी, 2013 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री, श्री सचिन पायलट, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री और श्री जी.के. वासन, नौवहा मंत्री के साथ बैठकें की। यात्रा के दौरान श्री पेट ने एस्टो निया दूतावास का उद्घाटन किया और फिक्की द्वारा आयोजित व्यांपार सम्मेलन में भाग लिया।

भारत से, एस्टोनिया का दौरा किया गया जिसमें अप्रैल, 2013 में कॉर्पोरेट कार्य राज्यं मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सचिन पायलट का दौरा, 14–16 जून, 2013 को पैट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री लक्ष्मी् पनाबका का दौरा और 20–22 सितंबर, 2013 को पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन का दौरा शामिल है।

एस्टोनिया से श्री जैक एविक्सो्, एस्टोानिया के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित साइबर सुरक्षा और साइबर अभिशासन पर भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 13–16 अक्तू बर, 2013 को भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान श्री एविक्सोद ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताभक्षर किए। न्यायमूर्ति मंत्री श्री हन्नोक पेवकुर ने 9–11 दिसंबर, 2013 को भारत का दौरा किया और फिक्की द्वारा आयोजित ''इ–गवर्नेन्स एंड ट्रांसपेरंसी– एक्पीररियन्सौ शेयरिंग'' नामक गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। आर्थिक और संचार मंत्री जोहान पार्ट्स ने 3–8 फरवरी, 2014 को भारत का दौरा किया और श्री कपिल सिब्बाल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कानून/न्याय मंत्री के साथ बैठक की। इस विचार–विमर्श में एस्टोनिया मैरीन्सर के मुकदमे और सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग पर फोकस किया गया। दोनों मंत्रियों ने सूचना प्रौद्योगिकी में शैक्षिक और व्याहवहारिक सहयोग को बढ़ाने पर एक करार पर हस्ता्क्षर किए जिसमें, ई–अभिशासन और क्लाउड कम्यूटिंग मुख्य रूप से शामिल थे जो एस्टोानिया की कंपनियों को सार्वजनिक और निजी सहयोग परियोजनाओं में उनके उत्पादों और सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बनाएंगे।

उप महासचिव, एस्टोनिया के विदेश मंत्री श्री वेनु रिनार्ट ने एएसईएम एफएमएम–11 में भाग लेने के लिए दिनांक 11–12 नवंबर, 2013 में भारत का दौरा किया।

फिनलैंड

सुश्री कृष्टा क्यूटरू, आवास और संचार मंत्री ने 15–19 जनवरी, 2013 को भारत का दौरा किया और श्री कपिल सिब्बल, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कमलनाथ, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री और श्री श्याम पित्रोडा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय भारत नवाचार परिषद के साथ बैठकें की।

सुश्री मारजा रिसलक्की, सेक्रेटरी आफ स्टेट, आर्थिक और रोजगार मंत्री के साथ एक बड़े शिष्टमंडल ने दिल्ली में आयोजित होने वाले चौथे स्वच्छा ऊर्जा मंत्री सम्मेलन (सीईएम 4) में भाग लेने के लिए 15–19 अप्रैल, 2013 को भारत का दौरा किया।

फिनलैंड ने विभिन्न, क्षेत्रों विशेष रूप से व्यापार क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2013 में ''भारत कार्य योजना'' प्रारंभ की।

फिनलैंड के विदेश मंत्री डॉ. इरकी टयूमियोगा ने 5–8 मई, 2013 को भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होॉंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम और विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर के साथ मुलाकात की।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 10–12 जून को फिनलैंड का दौरा किया और फिनलैंड के विदेश मंत्री डॉ. एरकी टियोनियोजा, यूरोपीय कार्य और विदेश व्याौपार मंत्री श्री एलेग्जेंटर स्टब, वित्त मंत्री मैसर्स टियूर सेंटामकी–व्योरी और श्री पर्ट्टी सालोनेन, फिनलैंड की संसद के विदेश कार्य समिति के अध्यरक्ष से मुलाकात की।

श्रीमती लक्ष्मी पनाबाका, राज्य पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ओएनजीसी और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से एक शिष्टिमंडल ने 11–14 जून, 2013 को फिनलैंड का दौरा किया और

फिनप्रो द्वारा आयोजित भारतीय फिनलैंड व्यापार सम्मेलन में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में फिनलैंड की कंपनियों ने भाग लिया।

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 17–19 जून, 2013 को फिनलैंड का दौरा किया। उन्होंने फिनलैंड उद्योग संघ के महानिदेशक द्वारा आयोजित फिनलैंड उद्योग गोल मेज को संबोधित किया। जिसमें फिनलैंड की 15 अग्रणी कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें अन्य के साथ नोकिया, सीमन्स, एबीबी, मैस्ट्रो शामिल थी।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण एवं वन मंत्री ने 'कोली फोरम 2013' में भाग लेने के लिए 16–20 सितंबर, 2013 को फिनलैंड का दौरा किया। इनकी यात्रा के दौरान हेलस्निकी में स्वच्छ–प्रौद्योगिकी और वेस्ट मैनेजमेंट पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई।

श्री एलेक्जेंचडर स्टौब, फिनलैंड के योरोपीय कार्य और विदेश व्या पार मंत्री ने 14–18 अक्तूडबर, 2013 को भारत का दौरा किया। फिनलैंड के अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री श्री पेक्काय हेविस्टों ने एएसईएम एफएमएम–11 में भाग लेने के लिए 11–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति तर्जा हलोनेन ने 6–8 फरवरी, 2014 से आयोजित होने वाले दिल्ली धारणीय विकास शिखर सम्मेालन, 2014 में भाग लिया।

फिनलैंड की संसद ने 24 अक्तबर, 2013 को सांसदों के लिए भारत की संस्कृति और राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों सहित अन्य पहलूओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत दिवस का आयोजन किया था।

ग्रीस

विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने 30 जनवरी से 3 फरवरी, 2013 तक ग्रीस का दौरा किया। श्रीमती प्रनीत कौर और उप विदेश मंत्री कोर्कुलस ने 1 फरवरी, 2013 को हेलेनिक विदेश मंत्रालय में राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट देने के लिए द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए।

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवाहर सिरकर ने 19–21 मई को एथेंस का दौरा किया उन्होंने वहां श्री विकास मनालिस, हेलेनिक रेडियो एवं टेलीविजन (ईआरटी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की और प्रसारण और टेलीविजन के दृश्य–श्रव्य सामग्री के आदान–प्रदान में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार–विमर्श किया।

पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरनजीत सिंह अटवाल ने 51वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कनाडाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्येयन दौरे पर जाने 25–28 जुलाई, 2013 को ग्रीस का दौरा किया।

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा ने जोहान्सबर्ग में 59वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्ययन दौरे पर 20–22 अगस्त, 2013 को ग्रीस का दौरा किया।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 'डेमोक्रेसी अंडर प्रेशर' नामक वैश्विक वार्ता की अंतरराष्ट्रीगय हेरल्ड ट्रिब्यून की श्रृंखला में भाग लेने के लिए 15–17 सितंबर, 2013 को एथेंस का दौरा किया।

उप विदेश मंत्री कायरकोस किरियाकास ग्रेनोटपोलस के नेतृत्व में 3 सदस्य शिष्टमंडल ने 11–12 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

श्री मोहम्मद आजम खान, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रडमंडल संसदीय संघ की उत्तर प्रदेश शाखा से 21 सदस्यों के उच्चतस्तरीय शिष्टमंडल ने 16–18 जनवरी, 2014 से एथेंस का अधिकारिक अध्ययन दौरा किया।

होली सी

फरवरी, 2013 में पोप बेनिडेक्ट XVI के त्यागपत्र के बाद कार्डिनल जॉर्ज बर्गोलियो को कार्डिनल के कोलेजियम द्वारा नए पोप के रूप में चुना गया। प्रोफेसर पी.जे. कुरियन, राज्य सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में श्री एंटो एंटोनी, सांसद सहित भारत से एक शिष्टमंडल ने 19 मार्च, 2013 को आयोजित नए पोप की नियुक्ति के समारोह में भाग लिया।

हंगरी

हंगरी के विदेश मंत्री, डॉ. जेनोस मार्टोनी ने विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद को दिनांक 16 जुलाई, 2013 को बुडापेस्ट में होने वाले हंगरी के राजदूतों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। वे इस सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए नाटो और यूरोपियन यूनियन के बाहर के पहले विदेश मंत्री थे विदेश मंत्री ने बैलेटोनफूर्ड का भी दौरा किया और उन्हें उस स्था न पर पौधा लगाने का सम्मान प्राप्त हुआ जहां उनके दादा जी डॉ. जाकिर हुसैन ने 1968 में पौधा लगाया था। वहां प्रवास के दौरान उन्होंने हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टोर ऑर्बन से मुलाकात की और उनकी आगामी भारत यात्रा की तैयारियों के साथ–साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विचार–विमर्श किया।

जल संसाधन मंत्री, श्री हरीश रावत ने भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व– किया और 8–11 अक्तूबर, 2013 को होने वाली बुडापेस्टं जल शिखर सम्मेउलन में 'ग्रीन इकोनॉमी फॉर ब्लू वॉटर' पर एक महत्वपपूर्ण व्याख्यान दिया।

हंगरी के प्रधानमंत्री, श्री विक्टोवर ऑर्बन के साथ 100 अधिकारियों सहित सशक्त व्याॉपार शिष्ट मंडल ने 16–18 अक्तूबर, 2013 से

भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ शिष्टमंडलीय स्तर की बातचीत के अतिरिक्त उन्हों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यूपीए की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। औषधि की परंपरागत प्रणाली, खेल के क्षेत्र में सहयोग, सूक्ष्म जीवी और रेडियोधर्मी का पता लगाने और सुरक्षा के रक्षात्मक पहलुओं के क्षेत्रों में सहयोग और 2013–15 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान–प्रदान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त रक्षा सेवा करार के संशोधन और भारतीय हंगरी सामरिक अनुसंधान कोष (2014–17 के लिए प्रत्येक हेतु 2 मिलियन यूरो के वर्धित अंशदान) के आश्य् पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। श्री ऑर्बन ने 'चुनौतीपूर्ण विश्व में हंगरी और यूरोप' पर आईसीडब्यूए में महत्वएपूर्ण व्याख्यान दिया। उन्हों ने मुंबई में सीआईआई द्वारा आयोजित अन्यक व्यापार फोरम के साथ–साथ नई दिल्ली में फिक्की, सीआईआई और एएसएसओसीएचएएम द्वारा संयुक्ती रूप से आयोजित किए गए व्या पार फोरम की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों की एक बैठक में हंगरी पर एक प्रैजेंटेशन भी दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री के आर्थिक प्रकरण पर बल दिये जाने के संबंध में यह दौरा सफल रहा और यह द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्व पूर्ण उपलब्धि है।

हंगरी के विदेश मंत्री डॉ. जेनोस मारटोनी ने नई दिल्ली में आयोजित की गई एएसईएम विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 11–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। डॉ. जेनोस मारटोनी ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श किया।

दौरों के अतिरिक्ति, वर्ष के दौरान कई संयुक्त कार्य समूहों ने हंगरी के प्रधानमंत्री के दौरों से पहले भी मुलाकात की। इसमें (i) भारत–हंगरी संयुक्त रक्षा समिति (ii) आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग (iii) संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति शामिल हैं।

आइसलैण्ड

आइसलैंड के राष्ट्रपति श्री ओलफुर रंगनार ने 31 मार्च से 6 अप्रैल, 2013 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने 01 अप्रैल, 2013 को तीसरे ध्रुवीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा अन्य भारतीय मंत्रियों से मुलाकात की। श्री मिलंद दियोरा जहाजरानी राज्य मंत्री के नेतृत्वं में एक शिष्टमंडल ने आईसलैंड के आंतरिक, जहाजरानी परिवहन मंत्री के निमंत्रण पर जुलाई, 2013 में आइसलैंड का दौरा किया। गैर–सरकारी संगठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप 13 अक्तूबर, 2013 को पहला ध्रुवीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉ. मिहिर शाह, योजना आयोग के सदस्य ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मोलन से लगभग 1000 प्रतिभागी और ध्रुवीय राज्यों से स्टेकहोल्डर और एक साथ ध्रुवीय कार्य करने वाले एकत हुए। आइसलैंड में रेकजाविक सांस्कृतिक रात्रि के रूप में 20–25 अगस्त, 2013 को भारतीय सप्ताह का आयोजन किया गया।

लातविया

जनवरी, 2014 में नई दिल्ली में लातविया दूतावास खुलने के साथ ही भारत के द्विपक्षीय संबंध नई ऊचांइयों पर पहुंच गए। लातविया के विदेश मंत्री एडगार रिंकइविस ने 15–20 सितंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। उनकी यात्रा के दौरान दोहरे कराधान परिहार पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। लातविया के विदेश मंत्री ने दिनांक 11–12 नवंबर, 2013 को भारत में होने वाले एएसईएम एफएमएम–11 में भी भाग लिया। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 2013 में रिगा में महानिदेशक स्तकर का विदेश कार्यालय परामर्श किया गया। लातविया ने भारत–केंद्रीय यूरोप व्याापार फोरम (आईसीईबीएफ) में भी भाग लिया। जो 27–28 मार्च, 2014 से फिक्की के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

लिथवेनिया

लिथवेनिया में दिनांक 24 अक्तूयबर, 2013 को विदेश कार्यालय परामर्श किया गया, जिसमें द्विपक्षीय राजनीतिक, व्याअपार और वाणिज्य, संस्कृति, शिक्षा, राजनैतिक गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के आदान–प्रदान, यूएनएससी, एनएसजी, ईयू जैसे बहुपक्षीय मंचो पर सहयोग और लंबित करार जैसे संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। लियवेमिया विदेश मंत्री, श्री लाइनेस लिंकीविकिस, ने एएसईएम एफएमएम–11 शिखर सम्मेसलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया और शिखर सम्मेलन से अलग विषयों पर विदेश मंत्री से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, लिथवेनिया के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए कम समय के लिए रूकने के वीजा में छूट देने संबंधी करार पर हस्तापक्षर किए गए।

मेसिडोनिया

मेसिडोनिया राष्ट्रीय सदन के राष्ट्र पति श्री तराजको वेलजनोस्कि ने 5–8 मार्च, 2013 के दौरान भारत के अधिकारिक दौरे पर एक संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

यात्रा के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री (प्रनीत कौर) से मुलाकात की। शिष्टनमंडल ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भी भाग लिया।

मेसिडोनिया के विदेश मंत्री, श्री निकोला पोपोस्कीस ने 16–17 दिसंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने

विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री (श्रीमती प्रनीत कौर) और वाणिज्य और उद्योग राज्यो मंत्री डॉ. ईएम सुदर्शन नाचीअप्पयन और सीआईआई के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दोहरे कराधान परिहार पर एक करार और मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थांन और मेपीडोमिया विदेश मंत्रालय के राजनयिक अकादमी निदेशालय के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मालटा

विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने दिनांक 7–10 अप्रैल, 2013 को मालटा का चार दिवसीय अधिकारिक दौरा किया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक अन्य सांस्थानिक ढांचा उपलब्ध कराने और व्यापार और आर्थिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य से दोहरे कराधान परिहार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री, डॉ. जॉर्ज डब्यूग. वेला, ने 11–12 नवंबर, 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एएसईएम एफएमएम–11 में भाग लिया और अन्य विषयों पर विदेश मंत्री से मुलाकात की। यात्रा के दौरान राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट देने संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत और मालटा के बीच दिनांक 31 अक्तूबर, 2013 में महानिदेशक स्तर का विदेश कार्यालय परामर्श हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

दिनांक 2–6 अक्तूबर, 2013 से 'मालटा में भारत के दिन' नामक उत्सव मनाया गया। जिसमें भारत के 10 सदस्य वाली लोक नृत्य मंडली का कार्यक्रम, फिल्म एवं खाद्य समारोह और महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी शामिल थी।

माल्डोवा

विदेश राज्या मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने 22–25 सितंबर, 2013 से माल्डोवा की यात्रा की। यात्रा के दौरान श्रीमती कौर ने राष्ट्रपति श्री निकोले तिमोफ्ति, प्रधानमंत्री श्री इयूरी लिएनका, विदेश एवं यूरोपीय एकीकरण मंत्री श्रीमती नटालिया ग्रेहमन, स्वास्थ्मं मंत्री, श्री अंदेरी उसाती और उप आर्थिक मंत्री श्री दमित्रू गोडेरोजा से मुलाकात की। उन्हों ने संस्कृति मंत्री सुश्री मोनिका बेबुक से भी मुलाकात की।

मोण्टेनेग्रो

मोण्टेनेग्रो में भारत के लिए पर्याप्त् सद्भाव और मैत्री का भाव है। वियना में भारत के राजदूत ने दिनांक 18–20 अप्रैल, 2013 को मोण्टेननेग्रो का दौरा किया। उन्होंरने उप प्रधानमंत्री श्री डुएस्कान मार्कोविक, श्री वुजिका लेजोविक और श्री रफात हेसोविक से मुलाकात की। उन्होंने दिनांक 27 मई, 2013 को मोण्टेनेग्रो के राष्ट्रपति श्री फिलिप वुजेनोविक को अपना प्रत्यंय पत्र प्रस्तुत किया।

नार्वे

इस वर्ष कई मंत्रालयी और आधिकारिक, द्विपक्षीय यात्राएं की गई। उप अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री श्री अरविन गाडगिल ने फरवरी, 2013 में दिल्ली धारणीय विकास शिखर सम्मेवलन में भाग लिया। वर्ष 2013–14 के दौरान 29 मई, 2013 को ओसलो में पर्यावरण के क्षेत्रों में दिनांक 15 मई, 2013 को नार्वे में शिक्षा पर और 14 फरवरी, 2014 को पुनरू नई दिल्ली मेंय दिनांक 31 मई, 2013 को ओसलो में समुद्री मामलों पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्यूर जी) आयोजित की गई।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री ने जैव विविधता पर 7वें तोरंधिम सम्मेतलन में भाग लेने के लिए 27–31 मई, 2013 को नार्वे का दौरा किया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 11–13 जून, 2013 को नार्वे का दौरा किया और अपने सहकर्मी नार्वे के विदेश मंत्री श्री एस्पिन बर्थ एडी से मुलाकात की, जो स्वलबार्ड के ध्रुवीय क्षेत्र में दो दिवसीय यात्रा में उनके साथ गए। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने नार्वे के प्रधानमंत्री स्टावलटर बर्ग और रक्षा मंत्री सुश्री एनी–ग्रेथे स्ट्रो म–एरिक्सन से मुलाकात की।

श्री बॉर्ज ब्रेंड, नार्वे के विदेश मंत्री ने दिनांक 11–12 नवंबर, 2013 को आयोजित होने वाले एएसईएम एफएमएम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री और श्री आनंद शर्मा, वाणिज्यि और उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की। नार्वे के रक्षा राज्य सचिव, श्री ओयस्टीरन बो ने 10–14 दिसंबर, 2013 से भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान वे रक्षा राज्य मंत्री, श्री जितेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार श्री नेहचल संधु और नैसेना अध्यक्ष एडमिरल जी के जोशी से मिले।

श्री बी के चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग ने दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को ''एनर्जी एंड द पोस्ट–2015 एजेंडा'' पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ओसलो का दौरा किया।

नार्वे सरकार पेंशन निधि से एक शिष्ट्मंडल ने 9–12 अप्रैल, 2013 के दौरान भारत का दौरा किया और वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की।

श्री एस.बी.सिंह, सलाहकार, जहाजरानी मंत्रालय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने समुद्री परिवहन पर 3 जेडब्यूह जी बैठक में भाग लेने के लिए 28–31 मई, 2013 को नार्वे का दौरा किया।

महानिदेशक स्तर पर एफओसी का 6ठां दौर 1 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली, में आयोजित किया गया।

श्री वी.एस. संपत, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 9 सितंबर, 2013 को होने वाले संसदीय चुनावों की समीक्षा करने के लिए 5–10 सितंबर, 2013 को नार्वे का दौरा किया।

पोलैंड

विदेश राज्य मंत्री, सुश्री प्रनीत कौर, ने 27–30 जनवरी, 2013 को पोलैंड का दौरा किया। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री, श्री रेडोसला सिकोर्सकी से मुलाकात की और पारस्प,रिक हितों के अन्य मामलों के साथ–साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान आय पर करों के संबंध में दोहरे कर को रोकने और राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए भारत और पोलैंड के बीच एक करार पर हस्ताोक्षर किए गए।

श्री जनार्दन द्विवेदी, सांसद और प्रख्यात हिंदी विद्वान ने 21–24 जून, 2013 को पोलैंड का दौरा किया। उन्होंवने ''भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण'' पर वारसो और रोक्लोल यूनिवर्सिटी में व्याख्यांन दिया। इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कोयला खनन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो देशों के बीच संभावनाओं को तलाशने के लिए 27–31 अक्तूबर, 2013 को पोलैंड का दौरा किया।

पोलैण्ड के विदेश मंत्री श्री राडोसला सिकोर्शी ने एएसईएम एफएमएम–11 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11–12 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से अन्य विषयों पर मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2014 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ सहित द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों पर चर्चा हुई।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्री ने 10–14 नवंबर, 2013 को वारसो में सीओपी–19 में भाग लेने के लिए एक शिष्टवमंडल का नेतृत्व–किया।

रक्षा पर भारत–पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक 9–10 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

60वीं वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में पोलिश शिष्टमंडल ने नई दिल्ली। में ''ऊर्जा शिखर सम्मेंलन'' और 5वें एशियाई खनन कांग्रेस में भाग लेने के लिए फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया। पोलैंड से एक बड़े शिष्टमंडल ने कोलकाता में दिनांक 13–16 फरवरी, 2014 को होने वाले 5वें अंतरराष्ट्रीय खनन, अन्वेषण, खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, धातु एवं मशीन प्रदर्शनी मे भाग लिया। पोलैंड फरवरी, 2014 में नई दिल्ली में होने वाले विश्व् पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि था। पोलैंड ने दिल्ली जैज फेस्टिवल और पोलैंड–भारत संग्रहालय शिखर सम्मेमलन में भी भाग लिया।

''भारत और पोलैंड–राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष विरासत और भविष्यं'' नामक सम्मेलन का उद्घाटन 6–7 मार्च, 2014 को वारसो विश्वविद्यालय में किया गया। एक पैनल को संबोधित करते हुए, पोलैंड के उप विदेश मंत्री सुश्री कटरजयान केपरसक ने पोलैंड और भारत के बीच विशेषकर खनन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर बल दिया। भारत से 6 सदस्यक शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया।

रोमानिया

भारत और रोमानिया द्विपक्षीय संबधों की स्थापना के 65 वर्ष मना रहे हैं और इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

रोमानिया के विदेशमंत्री, श्री टीट्स कॉर्लाटन ने 7–8 मार्च, 2013 को नई दिल्ली का दौरा किया। श्री कॉर्लाटन ने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और उनके दौरे के दौरान 8 मार्च, 2013 को 'व्यापक भागीदारी स्थापित करने' उच्च स्तरीय दौरों, (एसएण्डकटी, व्यानपार, संस्कृीति, शिक्षा, बहुपक्षीय सहयोग–यूएनएससी विस्तार इत्यादि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्याान केन्द्रित करते हुए) के संयुक्त विवरण और दोहरा कर परिहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री टीट्स कॉर्लाटन, रोमानिया के विदेश मंत्री ने 11वीं एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 10–13 नवम्बर, 2013 के दौरान पुनः नई दिल्ली का दौरा किया और एएईएएम के साथ–साथ ईएएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की।

रोमानिया की एसएमई, पर्यटन एवं व्यापार वातावरण मंत्री श्रीमती मारिया ग्रापिनी ने 22–24 अप्रैल, 2013 के दौरान भारत का दौरा किया। वस्त्रों के क्षेत्रों में सहयोग पर एक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव (निर्यात) की अध्यक्षता में एक वस्त्र शिष्टमंडल ने 19–21 जून, 2013 को रोमानिया का दौरा किया। सहयोग के दो समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया जिन पर आगामी जेईसी के दौरान हस्ताक्षर किए जाने हैं।

रोमानिया से दो–सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत–मध्य यूरोप व्यापार फोरम, जो 27–28 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुई, में भाग लिया और रोमानिया में व्यापार निवेश के अवसरों पर एक प्रस्तुति दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया।

सर्बिया

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर का 18–21 नवम्बर 2013 को सर्बिया का पृथक दौरा वर्ष की मुख्य विशेषता रही। दौरे ने दोनों ओर से ऐतिहासिक संबंधों को एक नए स्तर तक ले जाने की इच्छा स्पष्ट की। विशेष संबंधों का ध्यान रखते हुए, सर्बिया के राष्ट्रपति

श्री टॉमीस्लैकव निकोलिक और सर्बिया के प्रधानमंत्री श्री ईवीका डाकिक सहित देश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सर्बिया के विदेश मंत्री ईवान मार्किक और श्रीमती प्रनीत कौर ने 20 नवम्बर, 2013 को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पहले चरण को प्रवर्तन में लाने और इसके दूसरे चरण को आरंभ किया। दौरे के दौरान दो समझौतों (i) सर्बिया की डब्ल्यू टीओ परिग्रहण और (ii) दूतावास के लिए 99 वर्ष के पट्टा पर हस्ताोक्षर किए गए।

अप्रैल, 2013 में नोवी साद में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा इंडिया के साथ एक सर्बियन कंपनी ''अग्रोपनोंका एमटीजेडफिंक'' ने महेन्द्रा ट्रेक्टरों के लिए एक निर्माण शाखा खोली। भारतीय ट्रैक्ट र उत्पादक सोनालिका ने ट्रैक्टरों के निर्माण (एसैम्बली) हेतु मार्च 2013 में बोल्वेराक से सर्बियन कंपनी ''एफपीएम एग्रोमेहनिका'' के साथ एक समझौते पर हस्ताकक्षर किए। बोरोन की खोज और भारत में निर्यात के लिए जेवी हेतु उषा इंडस्ट्री ज ने आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय दूतावास, बेलग्रेड ने 27–29 जनवरी, 2014 तक बंग्लौार में सीआईआई भागीदारी सम्मेलन में भाग लेने हेतु सर्बिया के उद्योग और उद्यम चैम्बर (एससीसीआई) से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल का दौरा आयोजित किया।

राज्य द्वारा संचालित कंपनी यूगोइंपोर्ट एसडीपीआर और स्लौबोडा आर्मसी फैक्टरी की अध्ययक्षता में सर्बिया की रक्षा उद्यम ने नई दिल्ली में 6–9 फरवरी, 2014 तक डैफैक्स्पो में भाग लिया।

बेलग्रेड में भारतीय दूतावास ने 27 सितम्बर, 2013 को सर्बिया भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का आरम्भ किया। मिशन ने यूगोस्लाव फिल्मी आर्काइव (किनोटेका) संग्रहालय के सहयोग से 17–22 सितम्बर, 2013 तक भारतीय फिल्म समारोह ''भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष'' आयोजित किए।

स्लोवेक गणराज्य

उप प्रधानमंत्री और विदेश तथा यूरोपियन कार्यमंत्री श्री मीरोस्लौव लॉजक ने 17–19 जून, 2013 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने ईएएम, राज्यमंत्री (पीके) के साथ बैठकें कीं और उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी तथा रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी से मुलाकात की।

लगभाग सात वर्ष के अंतराल के पश्चात 11–12 जुलाई, 2013 को ब्राटीसलावा में भारत–स्लोवाकिया संयुक्त आर्थिक समिति का 7वां सत्र आयोजित हुआ। वाणिज्य् राज्य मंत्री डा. डी. पुरन्देश्वरी और स्लोवाक आर्थिक राज्य सचिव श्री पॉवेल पावलिस द्वारा सत्र की सह–अध्यक्षता की गई।

उप प्रधानमंत्री और विदेश तथा यूरोपियन कार्यमंत्री, श्री मीरोस्लौव लॉजक ने वर्ष के दौरान 11–12 नवम्बर, 2013 में एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दूसरा दौरा किया।

स्लोवानिया

आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री राडोवान जेराव ने व्यापार शिष्टमंडल के साथ 27–30 जनवरी 2013 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने आगरा में सीआईआई शिखर सम्मेलन और कोलकाता का भी भ्रमण किया।

लोकसाभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यकक्षता में भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल ने 26–30 मई, 2013 के दौरान स्लोविनिया का दौरा किया। लोकसभाध्यक्ष ने अपने समकक्ष के साथ वार्ता के साथ–साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। शिष्टमंडल ने बलेद और ब्राडा नगरों का भी दौरा किया जहां उन्हों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवक्ष–प्रतिमा का अनावरण किया।

विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने 2–3 सितम्बरर 2013 के दौरान बलेद में बलेद सामरिक फोरम में भाग लिया जहां वह पर 'बदलते विश्व में बदलता यूरोप' पर मुख्य पैनल के वक्ताओं में से एक थी। दौरो के दौरान उन्होंने स्लोविनिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री कॉर्ल अजैविक ने 11–12 नवम्बिर 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 11वीं एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसके साथ उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उनकी द्विपक्षीय बैठक के पश्चात राजनयिक पासपोर्ट धारकों को अल्पि–प्रवास वीजा से छूट देने के समझौते पर हस्तापक्षर किए गए। स्लोविनिया नेता के दौरे के दौरान एयर इंडिया और स्लोविनिया की अदरिया एयरवे के बीच कोड–भागीदारी पर समझौता और प्रसार भारती तथा आरटीवी दृ स्लोविनिया के बीच विषय वस्तु भागीदारी पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत–स्लोविनिया संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक का आठवां सत्र नई दिल्ली में 17 जुलाई 2013 को आयोजित हुआ। एसएमई, वित्तीय एवं बैंकिंग मामला, एसएण्डनटी में सहयोग सहित आपसी रूचि के मामलों पर चर्चा हुई। निम्नतलिखित क्षेत्रों की सहयोग हेतु मुख्य ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई : सूचना–प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विद्युत, फिल्म निर्माण, खनन, यात्रा सुविधा को व्यापार क्षेत्रों के बीच सहयोग हेतु।

भारत और स्लोविनिया ने 3–4 फरवरी 2014 को जुबलीयाना में 8वीं विदेशी कार्यालय परामर्श (एफओबी) आयोजित की। एफओसी संयुक्त सचिव डीजी स्तर पर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान भारतीय और स्लोविनियन कंपनियों के मध्य हुए कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापनों में – कोलेक्टार और सीडब्यूवि सी कम्यूचटेटर, बेलगाम के बीच समझौता ज्ञापन, इस्करा अवेटोलकृतिका और रूट्स, कोयम्बवटूर के बीच समझौता ज्ञापन और भारतीय कंपनी ऑरियंट इलैक्ट्रिकल्स औरस्लो विनियन कंपनी ईटीआई इलैक्ट्रोनलिमेंट के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है।

14 नवम्बूर, 2013 को दक्षिणी स्लोवानिया में डोब्रोवो में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरणीय जन्म दिवस और बालदिवस मनाया गया।

जुबलीयाना में भारतीय दूतावास ने 18–30 जनवरी 2014 को ''स्लोंविनिया में भारतीय दिन'' आयोजित किया।

स्वीडन

स्वीडन से भारत के मंत्रिमंडलीय दौरों में 21 से 23 मई 2013 तक उप–प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री जन बजोरलुंद तथा 11 अक्टूबर 2013 से वित्ती'य बाजार मंत्री श्री पीटर नॉर्मन के दौरे शामिल हैं। स्वीडिश विदेश मंत्री श्री कार्ल बिल्डस ने 11–12 नवम्बर 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसके साथ उन्होंने विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की।

स्वीडन से भारत के अन्य महत्वपूर्ण दौरों में 27–28 फरवरी 2013 तक के विदेश व्यापार सचिव श्री गुन्ना र ओम तथा 17–19 अप्रैल 2013 तक राज्य उद्यम और ऊर्जा मंत्री श्री डेनियल जोहानसन का दौरा शामिल है। 2–6 सितबूर 2013 तक संसदीय मित्रता समूह के 6 सदस्यन बहुदलीय शिष्टमंडल के भारत दौरे से संसदीय संबंध सुदृढ़ हुए हैं।

2013 में भारत से स्वीडन के मंत्रिमंडलीय दौरों में 11 से 13 अप्रैल 2013 तक कॉरपोरेट कार्य राज्य् मंत्री (स्वनतंत्र प्रभार) श्री सचिन पायलट 13 से 16 मई 2013 तक विद्युत राज्य मंत्री श्री ज्यो तिर्यादित्यत सिंधियाय 21–23 मई 2013 तक स्वाास्ट एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद और 12–14 जून 2013 तक विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के दौरे शामिल हैं। इन दौरों के दौरान मंत्रियों ने स्वीडिश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की।

26 अप्रैल 2013 को स्टॉकहोम में विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया गया जिसमें भारत की ओर से सचिव (पश्चिम) विदेश मंत्रालय तथा स्वीडन की ओर से राज्यं सचिव श्री फ्रैंक बेलफ्रेज ने अध्यक्षता की। नई दिल्ली में क्रमशः 23–28 जनवरी 2013 तथा 24–25 अक्टूबर 2013 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय संयुक्त समिति और रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह आयोजित हुए।

18–19 मार्च 2014 तक स्वीडन विदेश मंत्रालय से एक शिष्ट मंडल नई दिल्ली में प्रथम भारत–स्वीडन साइबर वार्ता में भाग लेने के लिए आया।

स्विट्जरलैंड

अप्रैल 2013 में जेनेवा में निवेश गोलमेज पर श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने स्विस व्यांपार नेताओं को संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री का स्विस उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर सत्र भी आयोजित हुआ। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने भारतीय ओलंपिक संघ के निलम्बन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ चर्चा के लिए मई 2013 में लुसाने में एक शिष्ट मंडल की अध्यक्षता की। कैप्टन अजय सिंह यादव, ऊर्जा मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता वाले एक शिष्टमंडल ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य में विद्युत आपूर्ति में सुधार के संबंध में जून 2013 में ज्यूमरिक में एबीबी सुविधाओं का दौरा किया।

स्विस विदेश मंत्री श्री दीदीयर बुरखाल्टर ने नवम्बर 2013 में गुड़गांव में एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम की अध्यक्षता में संसदीय कार्य तथा शहरी विकास मंत्री श्री कमल नाथ, वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिर्यादित्या सिंधिया सहित एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने 22–25 जनवरी 2014 तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में विभिन्न सत्रों में भाग लिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वी राज चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दूसरी वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में 12 जून 2013 को हुई।

फैडरल डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस के साथ चर्चा के लिए श्री समीरबजाज, संयुक्त निदेशक तथा श्री ए.सी. सिंह, उप–विधि सलाहकार के साथ प्रवर्तन निदेशालय के दो सदस्यी शिष्टमंडल ने 8–9 अगस्त, 2013 तक बर्न का दौरा किया।

वर्ष के दौरान जेनेवा तथा नई दिल्ली में भारत–ईएफटीए द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते आयोजित हुए। वार्ता का तेरहवां चरण नई दिल्ली में 25 नवम्बर 2013 से स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड तथा लिख्टेंटश्टीइन के शिष्टमंडलों की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ।

30 अगस्त। 2013 को सास फी नगर में स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्म शती समारोह आयोजित हुआ।

तुर्की

नवीन एवं नवीकरीय ऊर्जा मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला ने 24–27 जून 2013 के दौरान द्विपक्षीय बैठकों हेतु तुर्की का दौरा किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने तुर्की के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर द्विपक्षीय बैठकों हेतु 23–25 जुलाई 2013 के दौरान तुर्की का दौरा किया। उन्हों ने तुर्की के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

तुर्की का दौरा करने वाले अन्य गणमान्यों में मेघालय के मुख्यमंत्री और पंजाब के उप मुख्यमंत्री दोनो अगस्त 2013 में शामिल हैं।

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने तुर्की के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 5–7 अक्टूबर 2013 के दौरान तुर्की का दौरा किया। द्विपक्षीय विधायी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दौरे के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में 6 करारों के साथ–साथ 5 अंतर सरकारी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की के विज्ञान उद्योग तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री निहात अर्गुन ने 27–29 जनवरी 2013 तक भारत का दौरा किया।

अंकारा और नई दिल्ली के बीच राजनैतिक सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र अफगानिस्तान में राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है और विभिन्न तुर्की तथा भारतीय अध्येताओं ने 2013 के दौरान भारत और तुर्की में आयोजित सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लिया है।

भारत ने अस्तांना और कजाकिस्तानि सहित, तुर्की और अन्य राजधानियों में, आयोजित एशिया में क्षमता निर्माण उपायों के कार्यान्वयन पर सम्मोलन (सीआईसीए) की सभी बैठकों में भाग लिया है।

भारत और तुर्की ने नई दिल्ली में 11 दिसम्बर 2013 को मध्य एशिया पर दूसरा परामर्श आयोजित किया।

योरोपीय संघ

भारत और योरोपीय संघ ने अपने गठबंधन के 50 साल पूरे कर लिए हैं। संबंध का आधार आर्थिक है जो योरोपीय संघ अपने अनुरूप स्वयं तैयार करता है, परंतु कई वर्षो से और विशेष रूप से लिसबन संधि के लागू होने और योरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा के सृजन के बाद भारत–योरोपीय संघ 'सामरिक भागीदारी' राजनैतिक और सुरक्षा दायरे में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा लोगों को आपसी सम्पर्क संबंर्धित करना एक प्राथमिकता है।

योरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यारपारिक भागीदार है और अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ–साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष के दौरान बृहत आधार पर व्यापार और निवेश समझौतों को पूरा करने की वार्ता जारी रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने प्रक्रिया को गति देने के लिए 15 अप्रैल 2013 को श्री कारिल डी में और पुनः मई 2013 के अंत में पेरिस में ओईसीडी की बैठक के साथ यूरोपियन संघ के व्यापार आयुक्त श्री कारिल डी गुच्चम से मुलाकात हुई। मुख्य वार्ताकार निरंतर मिलते रहते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अप्रैल 2013 यूरोपियन संघ कृषि आयुक्त श्री डेशियन सियोलोस से भी मुलाकात की।

2012–13 की अवधि में योरोपीय संघ के साथ कुल द्विपक्षीय व्यायपार की राशि 102,696.28 मिलियन थी जिसमें 50,421.74 मिलियन का निर्यात और 52,274.54 मिलियन का आयात था। यह 2011–12 की अवधि में कुल द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 8.08 प्रतिशत की कमी है जब यह राशि 109,427.74 मिलियन थी।

प्रतियोगिता पर भारत–योरोपीयन संघ के समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों के बीच 21 नवम्बर 2013 को नई दिल्ली– में हस्ताक्षर किए गए। योरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिता आयोग श्री जैकविन अल्मुलनिया तथा भारत के प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक चावला ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो प्रतियोगिता विधि प्रर्वतन के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने और सूचना के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। 17–18 जून 2013 को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपियन संघ के सह–अध्यक्ष सदस्ये–वरिष्ठ अधिकारियों का राज्यत समूह (जीएसओ) की बैठक हुई जिसके पश्चात विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से 8 अक्टूबर 2013 को जीएसओ की पहली बैठक हुई। एसएंडटी निगरानी समिति की 9वीं बैठक 9 अक्टूबर 2013 को ब्रुसेल्स में हुई। जल चुनौतियां, द्विअर्थ–व्योवस्थाअ, वहनीय स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा की सहयोग के मुख्यग क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई। फरवरी 2012 में भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन में आरंभ किए गए भारतीय–यूरोपीयन अनुसंधान एवं नवाचार भागीदारी के प्रतीक के रूप में वहनीय और समावेशी नवाचार पर भारत–योरोपीय संघ नवाचार पुरस्कारर पर भी सहमति हुई।

स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता नीति पर यूरोपीयन संघ आयुक्त श्री टोनियो बोर्ग ने एपीआई, क्लीनिकल ट्रायलस इत्यादि पर यूरोपीयन संघ की नई व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए 10–13 अप्रैल 2013 को भारत का दौरा किया। 23–24 सितम्बर 2013 को ब्रुसेल्स–में औषधीय एवं जैव प्रौद्योगिकी पर भारत–योरोपीय संघ जेडब्यूजी की 5वीं बैठक हुई।

सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग ने 25 नवम्बर 2013 को ब्रुसेल्स में

आयोजित समन्वय समिति की दूसरी बैठक के तहत 'सम्मिश्रण ऊर्जा शोध के क्षेत्र में योरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच सहयोग हेतु समझौता' किया।

27 मार्च, 2014 को बुसेल्स में 7वीं भारत–यूरोपीयन संघ ऊर्जा पैनल बैठक भी हुई। सचिव (पश्चिम) विदेश मंत्रालय द्वारा पैनल की सह–अध्यभक्षता की गई। कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो के प्रतिनिधियों ने पैनल में भाग लिया। इसे पहले, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूह ने 17–19 जून 2013 को ब्रुसेल्स में मुलाकात की और कोयले पर जेडब्यू जी ने 28 नवम्बर 2013 को चेन्नई में अपनी 8वीं बैठक की। वस्त्र और कपड़ों पर संयुक्त कार्य समूह ने 28 मई, 2013 को ब्रुसेल्स में अपनी 7वीं बैठक की।

''सामाजिक सुरक्षा'' शीर्षक पर ब्रुसेल्स में 24–25 जून, 2013 को रोजगार और सामाजिक नीति पर भारत यूरोपीयन संघ का छठा संयुक्त सेमिनार आयोजित हुआ। 4 सितम्बर, 2013 को ब्रुसेल्स में सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्यसमूह का आठवां चरण आयोजित हुआ और इससे पहले 3 सितम्बर, 2013 को सूचना संचार प्रौद्योगिकी उद्योग व्यापार वार्ता आयोजित हुई। फरवरी 2012 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर और विकास पर चर्चा करने हेतु 10 सितम्बर, 2013 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और यूरोस्टेशट के बीच डिजीटल विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई।

11–12 नवम्बर, 2013 को एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए योरोपीयन संघ विदेशी कार्य और सुरक्षा नीति प्रतिनिधि बारोनेस कैथरीन एशटोन ने नई दिल्ली, का दौरा किया।

दूसरी भारत–योरोपीयन संघ जलस्युता निरोधक वार्ता 9–10 सितम्बर, 2013 को बुसेल्स और योरोपीयन संघ नौसेना मुख्यालय, नॉर्थवुड, यू.के. में आयोजित हुई। 27 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आठवीं भारत–यूरोपियन संघ मानवाधिकार तदर्थ वार्ता आयोजित हुई। तीसरा भारत–योरोपीयन संघ विदेश नीति परामर्श 24 जनवरी, 2014 को नई दिल्लीआ में आयोजित हुआ।

वर्ष के दौरान भारतीय और योरोपीयन संसद (ईपी) के बीच आदान–प्रदान जारी रहा। योरोपीयन संसद में भारत के साथ संबंधों हेतु शिष्टमंडल के अध्यचक्ष, श्री ग्राहम वाटसन ने 29 अप्रैल से 3 मई 2013 तक भारत में यूरोपियन संसद के नौ सदस्यों (एमईपी) के शिष्टिमंडल की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यारपार पर ईपी समिति के 6 एमईपी के एक शिष्टमंडल ने भी 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक भारत का दौरा किया। भारत की ओर से, लोकसभा सचिवालय के 10 अधिकारियों के शिष्टमंडल ने 17–21 जून, 2013 को यूरोपियन संसद का दौरा किया।

दिसंबर 2010 में संस्कृति पर हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणापत्र के अनुपालन में, 18 अप्रैल, 2013 को श्रीमती संगीता गैराला, सचिव, संस्कृति मंत्रालय और श्री जन ट्रुसुज्कीम, महानिदेशक शिक्षा, प्रशिक्षण, संस्कृत और युवा, योरोपीयन आयोग के बीच संस्कृति पर पहली भारत–योरोपीयन संघ नीति वार्ता आरंभ हुई। भविष्य में सहयोग हेतु जिस महत्वयपूर्ण क्षेत्र की पहचान की गई। वह भारतीय कलात्मक समृद्धि के डिजीटलीकरण में सहायता हेतु 'योरोपीयन डिजीटल मंच' पर अनुभव को बांटना था।

शिक्षा और बहुभाषावाद पर भारत–योरोपीयन वरिष्ठ अधिकारियों की दूसरी बैठक श्री अशोक ठाकुर, सचिव उच्चतर शिक्षा और श्री जन ट्रुसुज्स्कीद, महानिदेशक शिक्षा, प्रशिक्षण, संस्कृति और युवा, योरोपीयन आयोग के बीच दिल्ली में 17 अप्रैल, 2013 को हुई। भविष्य में सहयोग हेतु अर्हताओं की परस्पर मान्यता के क्षेत्रों में सहयोग, पाठ्यचर्या विकास, विश्वविद्यालय रैंकिंग और कौशल विकास की पहचान की गई।

9 अप्रैल, 2013 को ब्रुसेल्स में बारलेमांट में योरोपीयन आयोग मुख्या लय पर 'भारतीय शाम' का आयोजन किया गया। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 'कल्पना' नामक भारतीय कला प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय राजदूत श्री दिनकर खुल्लोर और योरोपीयन विदेश कार्रवाई सेवा के कार्यकारी महासचिव श्री पियरे विमोंट द्वारा किया गया।

योरोपीयन परिषद् के अध्यक्ष श्री हर्मन वान रॉमपुथ ने यूरोपालिया के उद्घाटन समारोह में उपस्थितों को संबोधित किया। भारतीय समारोह जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और महाराज फिलिप, बोल्जियन के राजा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यूरोपियन आयोग अध्यक्ष श्री जोस मैनुअल बारोसो ने 15 अक्टूबर 2013 को समारोह की 'इंडोमेनिया' नामक दूसरी प्रमुख प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

पश्चिमी यूरोप

अंदौरा

अंदौर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मामले में चर्चा 31 मार्च, 2014 को अंदौरा के विदेश मंत्री श्री गिलबर्ट सबोया सुने की विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (ईडब्यू क) के साथ हुए परामर्श के दौरान की गई।

बेल्जियम

भारत के राष्ट्रपति ने बेल्जियम के नरेश के निमंत्रण पर 2–5 अक्टूबर, 2013 तक बेल्जियम का राजकीय दौरा किया। द्विपक्षीय संबंधों के संबंध में आपसी रूचि के मामलों पर राष्ट्रपति ने बेल्जियम के महाराज, महाराजा फिलिप और प्रधानमंत्री श्री इलियो डिरूपो के साथ चर्चा की। दोनों देशों में शोध और नवाचार पर ध्यान देते हुए भारत और बेल्जियम के विश्वविद्यालयों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का पहला

बेल्जियम दौरा था। यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने बेल्जियम के नरेश के साथ संयुक्त रूप से 'योरोपीयन इंडिया' समारोह का उद्घाटन किया। आईसीसीआर द्वारा सह–प्रायोजित यह समारोह बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड के विभिन्न स्थानों पर भारतीय कला और पुरातनता, संगीत और नृत्यल, सिनेमा, रंगमंच, साहित्य, दर्शनशास्त्र और व्यजनों को दर्शाएगा। विदेशमंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 30–31 जनवरी, 2013 को ब्रूसेल्स का द्विपक्षीय दौरा किया। जिसके दौरान उन्होंने बेल्जियम के उपप्रधानमंत्री और विदेश व्यापार तथा विदेश मंत्री श्री दीदीयर रेंडर्स से मुलाकात की।

बेल्जियम के महाराज की बहन, राजकुमारी एस्ट्रिड ने 23–30 नवंबर 2013 तक भारत में एक आर्थिक मिशन की अध्यक्षता की। उनके साथ उपप्रधानमंत्री और विदेश व्यापार तथा विदेश मंत्री श्री दीदीयर रेंडर्स और फ्लैंडर क्षेत्र के मंत्री अध्यक्ष श्री कृस पीटर थे। 25 नवंबर, 2013 को शिष्ट मंडल ने ईएएम के साथ बातचीत की जिसके दौरान आपसी रूचि के मामलों पर चर्चा हुई।

भारत तथा बेल्जियम और लक्स मबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच 13वीं संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक ब्रूसेल्स में 1–2 जुलाई 2013 को हुई। दोनों ओर से परिवहन, अवसंरचना, उच्च तर शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रीति–रिवाज और द्विपक्षीय व्यापार की विविधता के उपायों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। संयुक्त आयोग ने 2015 तक भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार हेतु 15 बिलियन यूरो का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत–बेल्जियम की संयुक्त समिति की तीसरी बैठक ब्रूसेल्स में 27–28 मई 2013 को हुई।

भारत के साथ सांस्कृतिक गठजोड़ को बढ़ाने के लिए ल्यूतवेन नगर प्राधिकरण के सहयोग से ल्यूवेन कैथोलिक विश्वविद्यालय में एक इंडिया हाउस की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन आईसीसीआर के अध्यकक्ष डा. कर्ण सिंह द्वारा 5 अक्टूबर, 2013 को किया गया। आधुनिक भारतीय अध्ययन पर पीठ स्थापित करने हेतु आईसीसीआर और ल्यू वेन विश्वविद्यालय के बीच एक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।

वर्ष 2012–13 के लिए बेल्जियम के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार अमेरिकी डॉलर 15,554.17 मिलियन था, जिसमें अमेरिकी डॉलर 5,507.30 मिलियन का निर्यात और अमेरिकी डॉलर 10,046.87 मिलियन का आयात था बेल्जियम की ओर से अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 तक की अवधि का संचयी एफडीआई इनफलो 492.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

फ्रांस

1998 में सामरिक भागीदारी की स्थापना के बाद से नियमित उच्च स्तरीय विनिमयों और रक्षा, आणविक ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के माध्य म से फ्रांस के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को निरंतर समर्थन दिया है।

भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध 14–15 फरवरी, 2013 को राष्ट्र पति श्री फ्रांकोइस हॉलैंड की भारत यात्रा के पश्चात और सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्ररपति हॉलैंड ने 14 फरवरी 2013 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। संस्कृाति, अंतरिक्ष सहयोग, रेल एवं शिक्षा से संबंधित चार समझौतों पर हस्तामक्षर किए गए।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने फरवरी 2013 में राष्ट्रपति हॉलैंड की भारत यात्रा की तैयारी करने के लिए 10–11 जनवरी 2013 को पेरिस का दौरा किया। संस्कृकति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमार कटोच, 3–5 अप्रैल, 2013 को दो–दिवसीय सरकारी यात्रा पर फ्रांस गईं। श्री पी. चिदम्बरम, वित्ते मंत्री ने 17 मई, 2013 को पेरिस का दौरा किया। श्री अजित सिंह, नागर विमानन मंत्री ने 50वें पेरिस अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के उद्घाटन और द्विपक्षीय चर्चा के लिए 16–19 जून, 2013 के दौरान दौरा किया।

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्याापार गोलमेज मूवमेंट डेस एंटरप्राइसेस डि फ्रांस (एमईडीईएफ) में भाग लेने के लिए 26–27 जून, 2013 के दौरान पेरिस का दौरा किया। श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 8–9 जुलाई, 2013 के दौरान चार सदस्यीशय शिष्टममंडल की अध्येक्षता की और छठे भारत–फ्रांस सीईओ फोरम बैठक में भाग लिया। यात्रा के दौरान, उन्होंधने फ्रांस के विदेश व्यावपार मंत्री से मुलाकात की।

पर्यावरण और वन मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन ने मरीन प्रोटेक्टेवड एरिया कांग्रेस और समुद्री संरक्षण पर अजासियों मंत्रिमंडलीय सम्मेरलन में भाग लिया और 26 अक्टूगबर, 2013 को फ्रांस के पारिस्थोतिकी और धारणीय विकास तथा ऊर्जा मंत्री श्री फिलिप मार्टिन से द्विपक्षीय बैठक की।

फ्रांस और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर सामरिक वार्तालाप है जो भारत और फ्रांस दोनों के बीच द्विपक्षीय कार्यसूची के मुख्य् घटको और विशेषरूप से समग्र वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर उभरती हुई चुनौतियों की समीक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति श्री पॉल जीन ऑटिज के राजनयिक सलाहकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से नई दिल्ली में 12 जुलाई 2013 को मुलाकात की। वार्ता का अंतिम चरण 30 जनवरी 2014 को पेरिस में हुआ।

विदेश सचिवों के स्तर पर वार्षिक विदेशी परामर्श 17 जून 2013 को पेरिस में हुआ। भारत फ्रांस साइबर वार्ता का पहला चरण 24 मई 2013 को पेरिस में हुआ।

भारत और फ्रांस के बीच वाणिज्यिक और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए नागर विमानन पर तीसरी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भारत के नागर विमानन महानिदेशालय तथा फ्रांस के डायरेक्शन, एविएशन सिविल (डीजीसीएस) ने पेरिस में 2 अप्रैल 2013 को और टाऊलूस में 3 अप्रैल 2013 को मुलाकात की। सतत शहरी विकास पर भारत फ्रांस संयुक्तड कार्य समूह की पहली बैठक 20 सितम्बर 2013 को पेरिस में हुई। सूचना प्रौद्योगिकी पर भारत फ्रांस संयुक्तप कार्य समूह की 9वीं बैठक 15 अक्टू बर 2013 को पेरिस में हुई।

भारत फ्रांस ने अपने वित्त मंत्रालयों के बीच एक नई वार्षिक आर्थिक और वित्तीय वार्ता आरंभ की है। ऐसी पहली वार्ता 29 अक्टूबर 2013 को पेरिस में हुई।

फ्रांस को योरोपीय संघ देशों के मध्य भारत के व्यापार भागीदारों की सूची में पांचवा स्थान दिया गया (जर्मनी, बेल्जियम, यूके तथा नीदरलैंड के पश्चात)। 2012–13 की अवधि के लिए कुल द्विपक्षीय व्यापार की राशि अमेरिकी डालर 9,638.39 मिलियन थी जिसमें अमेरिकी डालर 4986.03 मिलियन का निर्यात और अमेरिकी डालर 4652.36 मिलियन का आयात था। भारत का व्यापार अधिशेष अमेरिकी डालर 333.66 मिलियन था (वाणिज्य विभाग)। फ्रांस भारत में 9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। जिसका अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 की अवधि के लिए संचयी एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 3685.37 मिलियन है जो इस अवधि के लिए भारत में कुल एफडीआई समान प्रवाह का 2 प्रतिशत दर्शाता है (औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग)। जून 2012 तक फ्रांस के साथ अनुमोदित तकनीकी और वित्तीय सहयोगों की संख्याग 952 है।

फरवरी 2013 में बंगलौर में विज्ञान सेमिनार और प्रौद्योगिकी कार्यशाला के दौरान संयुक्त सहयोगी प्रयासो पर चर्चा जारी रही। भारत का उन्नत मौसम उपग्रह इन्सेकट 3डी 25 जुलाई 2013 को छोड़ा गया तथा भारत का उन्नत सम्प्रेमक्षण उपग्रह जीसेट 7 कौरू, फ्रैंच गुआना से ऐरिंन लांच व्हीकल से 29 अगस्तत 2013 को छोड़ा गया।

रक्षा सहयोग दोनो देशों के बीच सामरिक भागीदारी के महत्वपपूर्ण घटकों में से एक है। जरनल विक्रम सिंह, थल सेना अध्यक्ष ने 27–30 मई 2013 तक फ्रांस का सदभावना दौरा किया। अक्टूबर 2013 माह में सेवा सह सेवा स्टाफ वार्ता, मिलिटरी उप समिति बैठक तथा रक्षा उद्योग पर उप समिति की बैठक, प्राप्ति तथा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी की बैठक हुई। जहां चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों की सम्भावना पर चर्चा की गई।

31 अक्टूबर 2013 को मैसन डि एल, इन्डेर इन सिटी इन्टनरनैशनल डि यूनिवर्सिटी डि पेरिस में भारतीय छात्रों एवं अध्येताओं के लिए अतिरिक्त 72 कमरे संलग्न करने का कार्य पूरा किया गया। फरवरी 2013 में राष्ट्रपति हॉलैंड की भारत यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय और फ्रांसिसी संस्थानों के बीच कई समझौता ज्ञापन आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय उन्नत अनुसंधान संवर्धन (सीईएफआईपीआरए) की वैज्ञानिक परिषद एवं औद्योगिक अनुसंधान समिति की बैठक ग्रेनोबल में मई 2013 में आयोजित हुई। पी.एच.डी. एवं पोस्ट डॉक्टरेट छात्रों के संवर्धन के लिए सीईएफआईपीआरए द्वारा अप्रैल 2013 में विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग तथा फ्रांसिसी दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से वितृ पोषित रमन चरक अध्येतावृति आरंभ की गई।

भारतीय सिनेमा की शताब्दी को फ्रांस में अधिक संख्या में फिल्म समारोह द्वारा बृहत रूप में मनाया गया जिसमें केन्स् अंतर्राष्ट्रींय फिल्म समारोह सहित भारती सिनेमा के पूर्ण शीर्षक समारोह को समर्पित किया गया। स्वामी विवेकानंद की 150वें जन्मदिवस के अवसर पर मिशन ने यूनेस्को और रामकृष्ण मिशन के सहयोग से 'स्वाामी विवेकानंद का सार्वभौमिक संदेश' पर डॉ. कर्ण सिंह का व्योख्यान आयोजित किया।

राजनयिक पासपोर्ट धारकों को अल्प प्रवास वीजा से छूट देने के आपसी समझौते पर विदेश सचिव श्री रंजन मथाई के दौरे के दौरान 17 जून 2013 को पेरिस में उनके समकक्ष महासचिव श्री पियरे सेलल के साथ हस्ताक्षर किए गए।

जर्मनी

भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ते हुए बहुमुखी सहयोग के अनूरूप तेजी से बढ़ रहे है। वर्ष की विशेषता, अंतर्सरकारी परामर्श का दूसरा चरण, जो 11 अप्रैल 2013 को बर्लिन में हुआ। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भारतीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की उनके साथ पांच वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री – विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री डॉ फारूख अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी वाणिज्य, उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एम. एम. पल्लोम राजू थे। चांसलर सुश्री अंजला मैरकल ने जर्मनी की ओर से अध्यक्षता की उनके साथ पांच मुख्य केन्द्रीय मंत्री तथा तीन राज्य मंत्री थे।

दूसरे अंतर्सरकारी परामर्श (आईजीसी) के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों में गति को बढ़ाने पर चर्चा के अतिरिक्त कृषि, उच्चतर शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में 6 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्तारक्षर किए गए। इसके साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणों, रेलवे, एसएंडटी तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर 10 अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्तारक्षर किए। इससे पहले विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आईजीसी की तैयारी के लिए 27–29 जनवरी 2013 को जर्मनी का दौरा किया।

दौरे के दौरान उन्हों ने चांसलर मैरकल से मुलाकात की और बृहत रूप में जर्मन विदेश मंत्री श्री गाइडो वैस्ट रवेल के साथ परामर्श किया।

जर्मनी के राष्ट्रपपति श्री ज्वा चिम गओक ने राष्ट्र पति के निमंत्रण पर 4–9 फरवरी 2014 को भारत का राजकीय दौरा किया उनके साथ मंत्रियों, संसद सदस्यों और व्यापार नेताओं सहित एक उच्च स्तिरीय शिष्टरमंडल था। राष्ट्रपति गओक ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बृहत स्तर पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने यात्रा के साथ–साथ द्विपक्षीय विकासात्मक वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग पर वार्षिक समावेशी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जर्मन चांसलर डॉ क्रिस्टोषफ हॉस्जंन के विदेशी एवं सुरक्षा नीति सलाहकार ने 1 जनवरी 2014 को नई दिल्ली का दौरा किया और एनएसए के साथ परामर्श किया। एनएसए ने 50वें म्यूननिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी 2014 तक म्यूनिख का दौरा किया जिसके दौरान उन्हों ने डॉ हॉस्जलन के साथ चर्चा भी की।

वर्ष 2012–13 के दौरान दोनो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वर्ष का समारोह 'जर्मनी में भारत के दिन' मनाया गया। समारोह हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में औपचारिक रूप से 11 अप्रैल 2013 को समाप्त किया गया। जर्मनी के विदेश मंत्री श्री गाइडो वेस्टपरवेल समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे जिसमें राजनीतिज्ञों, राजनयिकों, कार्यकारियों, शैक्षिकों तथा पीआईओ सहित जर्मन जनसाधारण समूह शामिल थे।

विदेशी कार्यालय परामर्श 9 सितम्बर 2013 को बर्लिन में आयोजित किया गया।

बर्लिन में अंतर्सरकारी परामर्श के दूसरे चरण के दौरान भारत और जर्मनी के बीच उन्नत व्यापार के संवर्धन के लक्ष्ये से उच्च प्रौद्योगिकी भागीदारी समूह (एचटीपीजी) स्थापित करने पर सहमति हुई। एचटीपीजी की पहली बैठक बर्लिन में 9 सितम्बर 2013 को हुई जिसमें भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षता विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह और जर्मन शिष्टमंडल की अध्यक्षता राज्य सचिव डॉ हैराल्ड ब्राउन द्वारा की गई। एचटीपीजी के कार्य समूह की बैठक भी बर्लिन में 5 मार्च 2014 को आयोजित की गई। इससे पहले 4 मार्च 2014 को द्विपक्षीय निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, गैर प्रसार तथा आयात नियंत्रण वार्ता की गई।

कृषि मंत्रालय और जर्मन के खाद्य, कृषि एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के बीच अप्रैल 2013 में दूसरी आईजीसी के दौरान बीजों के विकास पर आशय के संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार जर्मन बीज शिष्टमंडल ने 1–7 दिसम्बुर 2013 तक भारत का दौरा किया जिसके दौरान सहयोग के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई अर्थात् (i) पौधा विविधता सुरक्षा (ii) संरक्षण और आनुवांशिक संसाधनों का प्रयोग (iii) बीज विधि निर्माण।

मानकीकरण, समरूप मूल्यांकन और उपाद सुरक्षा पर अप्रैल 2013 में दूसरी आईजीसी के दौरान हस्ताक्षर किए गए आशय के संयुक्त घोषणा पत्र की अनुवर्ती के रूप में गुणवत्ता2 अवसंरचना पर भारतीय–जर्मन संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में 12–13 दिसम्बर 2013 को की गई।

जर्मनी योरोपीयन संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यारपार भागीदार है। 2011–12 में भारत–जर्मन द्विपक्षीय व्यापार में 26.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है और यह बढ़ कर अमेरिकी डालर 23543.93 मिलियन हो गई है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक मंदी ने 2012–13 में दोनो देशों के बीच व्यांपार पर प्रभाव डाला है और यह 8.38 प्रतिशत घट कर अमेरिकी डालर 21571.99 मिलियन (निर्यात–अमेरिकी डालर 7246.20 मिलियनय आयात–अमेरिकी डालर 14325.79 मिलियन) रह गया है।

जर्मनी भारत में 8वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 के दौरान जर्मनी से संचयी एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 5998.45 मिलियन था। जर्मनी विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अनुभव का महत्व.पूर्ण स्रोत भी है।

बंडस्टेरग के उप राष्ट्रपति डॉ हरमन ऑटो सोल्म. की अध्यरक्षता में एक संसदीय शिष्ट मंडल ने 28 मार्च से 7 अप्रैल 2013 तक भारत का दौरा किया।

जर्मन संघीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डेनियल बर्र की अध्यभक्षता में संसद सदस्यों3, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 15 सदस्यीय शिष्टमंडल ने स्वास्थ्य बीमा तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकी पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच संबंध सुदृढ़ करने के लिए 27–30 अप्रैल 2013 तक भारत का दौरा किया।

विद्युत राज्य मंत्री श्री ज्योतिर्यादित्य सिंधिया ने 12–13 मई 2013 को बर्लिन का दौरा किया उन्होंने अप्रैल 2013 के अंतर्सरकारी परामर्श के दौरान किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थाोपना पर आशय के संयुक्त घोषणा पत्र के कार्यन्वंयन पर जर्मनी के आर्थिक सहयोग व विकास राज्यमंत्री सुश्री गुदरन कॉप के साथ चर्चा की।

प्रधानमंत्री के विशेष राजदूत श्री एस.के. लाम्बा् ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की जर्मन विदेश कार्यालय द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए 13–15 मई 2013 तक बर्लिन का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन लिपजिग में 2–4 मई 2013 को आयोजित हुआ। श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग तथा श्री मनोज सिंह, सलाहकार योजना आयोग ने

इस सम्मेलन में भाग लिया।

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने 12–13 सितम्बर 2013 को फ्रैंकफर्ट का दौरा किया। उन्हों ने फ्रैंकफर्ट में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मोटर शो में भारत दिवस का उद्घाटन किया।

लोकसभा सांसद श्री यशवंत सिन्हा (बीजेपी) की अध्यक्षता में संसद सदस्यों के एक शिष्ट मंडल ने 8–14 सितम्बर तक बर्लिन, स्टकगार्ट तथा फ्रैंकफर्ट का दौरा किया। शिष्टमंडल की मेजबानी फ्रेड्रिक अबर्ट स्टिफटंग, एसपीडी से संबद्ध एक राजनैतिक प्रतिष्ठान ने की। दौरे का शीर्षक ''कल की अर्थव्य वस्थास–धारणीय एवं समावेशी वृद्धि के नए मॉडल की ओर'' था। शिष्ट मंडल ने जर्मनी के अनेक वार्ताकारों से मुलाकात की। शिष्टमंडल के अन्य सदस्य श्री विवेक गुप्ता (टीएमसी), श्री जय प्रकाश हेग्डे (आईएनसी), डॉ अजय कुमार (जेवीएम) तथा श्री शिव कुमार उदासी (बीजेपी) थे।

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूएसए के द्विपक्षीय दौरे और न्यूयार्क में यूएनजीए सत्र में भाग लेने के लिए आते और जाते समय 25–26 सितम्बर 2013 और 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 तक फ्रैंकफर्ट रूके। उन्होंने चांसलर सुश्री अंजला मैरकल से 25 सितम्बर 2013 को दूरभाष पर बात की और 22 सितम्बर 2013 को संघीय चुनावों में सीडीयू/सीएसयू की विजय पर उन्हें बधाई दी।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने न्यूंयार्क में यूएनजीए के साथ–साथ 26 सितम्बीर 2013 को अपने समकक्ष श्री गाइडो वेस्टशरवेल के साथ मुलाकात की। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, व्याबपार तथा आर्थिक महत्व के मामलों पर चर्चा की।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने 5–8 अक्टूबर 2013 तक कोलोन में हुए अनुगा खाद्य मेले 2013 का दौरा किया। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री श्री तारिक अनवर ने खाद्य और कृषि वैश्विक फोरम (जीएफएफए) तथा छठे बर्लिन कृषि मंत्री शिखर सम्मेलन 2014 में भाग लेने के लिए 16–18 जनवरी 2014 तक बर्लिन का दौरा किया।

उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अन्सारी पेरू जाते हुए 25–26 अक्टूबर 2013 को फ्रैंकफर्ट रूके। विदेश मंत्री श्री गाइडो वेस्टमरवेल ने 11–12 नवम्बर 2013 को 11वीं एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने एससीएम मंत्रिमंडल के हाशिये पर विदेश मंत्री से भेंट की।

7–10 नवम्बर 2013 को नई दिल्ली में इन्डो' जर्मन परामर्शी समूह (आईजीसीजी) की 22वीं बैठक हुई। आईजीसीजी भारत और जर्मनी के बीच मार्ग–2 वार्ता का एक मंच है जो वार्षिक रूप में बैठक करता है और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विचार विमर्शों के आधार पर अनुशंसाएं करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग भारत–जर्मन संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत–जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र ठीक प्रकार से प्रगति कर रहा है और उन दोनों सरकारों ने प्रत्येक ओर से 2 मिलियन यूरो के समान वार्षिक अंशदान के साथ सहयोग को 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ड्यूशेज इलेक्ट्रोकनन सिंक्रोट्रोन (डीईएसवाई), हमबर्ग पर पीईटीआरएध्एफएलएएसएच सुविधा पर बीमलाइन के उपयोग में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। दरमशद में एन्टीट प्रोटोन तथा ईओन शोध की सुविधा शुद्ध विज्ञान में समृद्धशाली भारत–जर्मन सहयोग का एक उदाहरण भी है। इस अवधि के दौरान संस्थागत स्तर पर अनेक संगोष्ठियां और वार्तालाप हुए।

वर्ष के दौरान जर्मन विश्वनविद्यालयों में निम्न लिखित अल्पावधि पीठें आरंभ की गई (i) जौहानसबर्ग विश्वविद्यालय, मेन्ज (ii) एवरर्हाड कार्लस विश्वविद्यालय, टुबिंन और (iii) मार्टिन लूथर विश्व विद्यालय, हॉल विटनबर्ग। आईसीसीआर कॉरपोरेट उत्तरदायित्व और अधिशासन पर लिपजिक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एचएचएल) में एक दीर्घावधि पीठ भी स्थापित की है। डॉ अर्नदत्तै मिशल को जर्मनी में भारत को अच्छी तरह से समझने की क्षमता सृजित करने और समकालीन विश्व में भारत की भूमिका के विषय में अपने प्रसिद्ध लेखों के माध्यम से भारत–जर्मन संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपने महत्विपूर्ण अंशदान के लिए 2013 के लिए जिसिला–बॉन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत–जर्मन रक्षा तकनीकी सहयोग उपसमूह (डीटीएसजी) की 8वीं बैठक 14–15 मई 2013 को नई दिल्ली में हुई।

ऑयरलैंड

ऑयरलैंड की बाल और युवा कार्य मंत्री सुश्री फ्रांसिस फिट्जगेराल्डय ने सेंट पेट्रिक दिवस के अवसर पर मार्च 2013 में भारत का दौरा किया। योरोपीय कार्य राज्य मंत्री श्री पाश्चकल दोनोहोय ने एएसईएम विदेश मंत्रिमंडलीय बैठक में भाग लेने के लिए नवम्बर 2013 में भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 11 नवम्बर 2013 विदेश राज्यमंत्री श्रीमती प्रनीत कौर से भी भेंट की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की।

रोजगार उद्यम और नवाचार मंत्री श्री रिचर्ड ब्रुटन ने भारत के लिए एक बड़े व्यायपार और शिक्षा शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के साथ बहुस्तकर पर चर्चा की।

इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दो वैज्ञानिकों ने डुब्लिन सिटी विश्वविद्यालय के साथ व्यापक संप्रेषण और परिगणन ग्रीन संप्रेषण प्रौद्योगिकियों इत्यादि में संयुक्त शोध एवं विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए 19–20 सितम्बर 2013 को डुब्लिन का दौरा किया।

2012–13 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की राशि अमेरिकी डालर 883.85 मिलियन थी (निर्यात अमेरिकी डालर 386.69 मिलियनय आयात अमेरिकी डालर 497.15 मिलियन)। अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 तक ऑयरलैंड से संचयी एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 301.55 मिलियन था।

इटली

भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 15 फरवरी 2012 की एन्रीका लेक्सी घटना की जांच और न्यातयिक कार्यवाही, जिसमें दो इटेलियन नाविकों (मरीन्सल) ने केरल के तट पर भारतीय मत्य्कक नौका पर गोली बारी की। जिसके फलस्वरूप दो भारतीय मछुआरों की मृत्यु हुई, फोकस में रहा। दोनो पक्षों ने एक–दूसरे से परामर्श जारी रखा जिसमें मामले से संबंधित सार्वजनिक नकारात्मक पक्ष को निपटाना शामिल है।

संघ के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री शरद पवार ने रोम में 15–22 जून 2013 तक एफएओ सम्मेलन के 38वें सत्र के लिए भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षता की।

संघ के स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने रोम में 1–5 जुलाई 2013 तक कोडेक्सय अलीमेनटेरियस की 50वीं बैठक में भाग लिया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण राज्येमंत्री प्रो. के. वी. थॉमस ने रोम में 7–11 अक्टूबर 2013 तक एफएओ, खाद्य सुरक्षा समिति के 40वें सत्र में भाग लिया।

अप्रैल 2013, में इटेलियन सांस्कृतिक धरोहर एवं कार्यकलाप मंत्रालय के इटेलियन संरक्षण एवं पुनरूद्धार संस्थान (आईएससीआर) ने रोम में 'भारतीय पर्वतीय कला स्थल के संरक्षण और चित्रित अजंता अध्ययन तकनीकों' नामक शीर्षक के द्विभाषी खंड का प्रकाशन प्रस्तुत किया। खंड में भारत में किए गए कार्यों में कार्यढांचे में भारत और इटली के बीच 'अजंता और एलोरा गुफाओं के चित्रों के संरक्षण हेतु सहयोग पर समझौता ज्ञापन' पर ध्यान दिया गया है।

भारतीय सिनेमा के शताब्दी समारोह के भाग के रूप में ''इसोला डेल सिनेमा'' फिल्म समारोह के कार्यढांचे के भीतर 16 अगस्त 2013 को भारतीय सिनेमा पर एक पुरावलोकन आयोजित किया गया।

गांधी जयंती के अवसर पर, रोम में ल्यूइस विश्वविद्यालय में रोम में विभिन्न प्रख्यात विश्वतविद्यालयों से अग्रणी शैक्षिकों को शामिल करते हुए 'आचार और नीतियों के भीतर आज का गांधी' नामक सेमिनार आयोजित किया गया और महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया।

2012–13 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की राशि अमेरिकी डालर 9,083.87 मिलियन थी (निर्यात अमेरिकी डालर 4,372.61 मिलियनय आयात अमेरिकी डालर 4,711.27 मिलियन)। यह पिछले वर्ष 2011–12 की तुलना में जहां द्विपक्षीय व्यापार अमेरिकी डालर 10,004.78 मिलियन था। 9.2 प्रतिशत की अवनति थी। अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 के अवधि के लिए इटली से संचयी एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 1,224.25 मिलियन था।

लाम्शैस्टिन

भारत और लाम्शैस्टिन के बीच कर मामलों पर सूचना के आदान–प्रदान पर एक समझौते पर 29 मार्च 2013 को बर्न में हस्ताक्षर किए गए।

लाम्शैस्टिन के राष्ट्राध्यक्ष शासक राजकुमार हंस आदम II, ने कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष राजकुमार अलोएस के साथ 13–19 अक्टूबर 2013 तक भारत का एक निजी दौरा किया (गुड़गांव में मैसर्स राइस टैक एजी की बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए)।

लक्समबर्ग

भारत, बेल्जियम तथा लक्समबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच 13वीं संयुक्त आर्थिक आयोग बैठक ब्रूसेल्स् में 1–2 जुलाई 2013 को आयोजित हुई। बैठक के दौरान भारत और लक्समबर्ग ने व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के मार्ग पर चर्चा की और 2015 तक 200 मिलियन यूरो के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया।

2012–13 में भारत और लक्समबर्ग के बीच कुल वार्षिक व्यापार अमेरिकी डालर 56.29 मिलियन था। जिसमें लक्स मबर्ग से भारत का आयात अमेरिकी डालर 48.09 मिलियन और निर्यात अमेरिकी डालर 8.20 मिलियन था। अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 तक लक्समबर्ग से भारत को एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 489.06 मिलियन था।

द नीदरलैंड

दोनों देशों ने जल प्रबंधन, अवसंरचना एवं रसद, जिसमें बंदरगाह और राजमार्ग शामिल हैं। जल परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, कृषि प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, बागवानी, फूलों की खेती, रचनात्मक एवं रचना उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों में साथ काम करने की संभावनाओं का पता लगाया। भारत नीदरलैंड संबंधों में मुख्य संघटक, व्यापार और निवेश सहयोग, ने संतोषप्रद वृद्धि दर्शायी है। 2012–13 में द्विपक्षीय व्यापार की राशि अमेरिकी डालर 12,944.11 मिलियन थी, जिसमें अमेरिकी डालर 10,565.02 मिलियन का निर्यात और अमेरिकी डालर 2,379.09 मिलियन का आयात शामिल था। यह 2011–12 की तुलना में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि है। नीदरलैंड एफडीआई प्रवाह का छठा सबसे

बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2,000 से जुलाई 2013 तक की अवधि में नीदरलैंड से संचयी एफडीआई प्रवाह अमेरिकी डालर 9,485.53 मिलियन था।

अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित मंत्रिमंडल स्तरीय आदान प्रदान हुएः

(i) शहरी विकास एवं संसदीय कार्यमंत्री श्री कमल नाथ (13–14 मई 2013) "स्थानिक आयोजना, जल प्रबंधन तथा गतिशीलता प्रबीधन" के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर एक सम्मेलन ज्ञापन पर हस्तीाक्षर किए।

(iii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री कपिल सिब्बल (19–21 जून 2013)।

(iii) युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री (स्व तंत्र प्रभार) श्री जितेन्द्र सिंह (27–28 जून 2013)।

(iv) राज्य मंत्री (जहाजरानी) श्री मिलिन्द देवड़ा (22–24 जुलाई 2013)।

(v) कृषि मंत्री, केरल राज्य सरकार, श्री के.पी. मोहनन (25–28 जुलाई 2013)।

(vi) डच विदेश व्यामपार एवं विकास सहयोग मंत्री सुश्री लिलियाने प्लोमेन की भारत यात्रा (2–5 सितम्बर 2013)।

(vii) एएसईएम विदेश मंत्रिमंडल बैठक (11–12 नवम्बर 2013) के लिए डच विदेश मंत्री श्री फ्रांस टिमरमंस का दौरा। उन्होनें एएसईएम मंत्रिमंडल के हाशिये पर विदेश मंत्री से भेंट की।

(viii) डच स्वास्थ्य, कल्याण एवं खेल मंत्री सुश्री इदिथ शिपर्स की भारत यात्रा (29–31 जनवरी 2014)।

रॉटरडेम में 13–16 मई 2013 तक जियोस्पेशियल वर्ड फोरम आयोजित किया गया। फोरम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के साथ–साथ निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आईएचसी हॉलैंड द्वारा तैयार किए गए ड्रेजर डीसीआई ड्रेज–XXI के शुभारंभ तथा नामकरण के लिए समारोह 8 अगस्त 2013 को किंडरदिजिक में आयोजित किया गया। यह ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आईएचसी हॉलैंड द्वारा तैयार किया गया तीसरा ड्रेजर था। इस श्रृंख्ला के पहले दो ड्रेजर क्रमशः नवम्बर 2012 और फरवरी 2013 में आरंभ किए गए थे।

''यूरोप में भारतीय प्रवासियों का उदय'' शीर्षक के साथ वार्षिक भारतीय प्रवासी सम्मेलन हक में लॉमेन संग्राहलय में 29 सितम्बर 2013 को आयोजित किया।

इंग्लैंड की स्वास्थ्य, कल्याण और खेलकूद मंत्री, श्रीमती इडिथ शिपर्स की दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2014 तक की भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग तथा खेलकूद अवसंरचना के विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्र मंडल संसदीय संघ की उत्तर प्रदेश शाखा के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 11 से 13 जनवरी, 2014 तक अध्ययन दौरे पर नीदरलैंड की यात्रा की।

दोनों पक्षों के विदेशी कार्यालयों के मध्य दिनांक 14 मार्च, 2014 को हेग में द्विपक्षीय राजनीतिक निदेशक स्तेरीय परामर्श किया गया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 24–25 मार्च, 2014 को हेग में तृतीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलिन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्री ने दिनांक 25 मार्च, 2014 को बेगम मैक्सिमा से भेंट की तथा हालैण्ड के विदेश मंत्री श्री फ्रांस टाइमरमैंस से बातचीत की।

पुर्तगाल

पुर्तगाल के विदेश मंत्री श्री पोलो पोरटास और संस्कृति उप–मंत्री श्री जार्ज बैरेटो जेवियर ने दिनांक 3 से 7 मार्च, 2013 तक भारत की यात्रा की। इन्होंने विदेश मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। इन्होंने विदेशी भारतीय कार्य मंत्री, श्री वायलार रवि के साथ भी द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार संपन्न किया।

पुर्तगाल के विदेश मंत्री श्री रूई मैचेटे ने दिनांक 11–12 नवम्बर, 2013 को ए एस ई एम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की।

18 अधिकारियों वाले राष्ट्रीय रक्षा कालेज प्रतिनिधिमण्डल ने विदेश अध्ययन दौरे के भाग के रूप में दिनांक 19 से 25 मई, 2013 तक पुर्तगाल की यात्रा की।

राष्ट्रीय अभिलेखाकार के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में अभिलेखागार से संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुर्तगाल मंत्री परिषद के प्रेजीडेंसी के मध्य सहयोग प्रोतोकाल सम्पन्न किया गया।

इसके साथ–साथ 528.46 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात और 378.21 मिलियन अमरीकी डालर के आयात वाले 906.67 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय भारत–पुर्तगाल व्यापार करार सम्पन्न किया गया।

सैन मैरिनो

भारत और सैन मैरिनो ने रोम में दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को कर सूचना आदान–प्रदान करार (टी आई ई ए) सम्पंन्न किया, जिससे भारत और सैन मैरिनो के मध्य कर सहयोग को और सुदृढ़ किए जाने की आशा की गई है।

स्पेन

वायु सेनाध्यपक्ष (सी ए एस) एयर चीफ मार्शल एन ए के ब्रोने ने स्पेगन के वायु सेनाध्यक्ष के निमंत्रण पर दिनांक 7 से 12 अप्रैल, 2013 तक स्पेन की सरकारी यात्रा की।

जैव– प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) के अधिकारियों के एक 17 सदस्यीयय प्रतिनिधिमण्डिल ने औधोगिक प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी डी टी आई), स्पेन के साथ सहयोग के लिए जारी कार्यक्रम के तहत दिनांक 20 से 22 मई, 2013 तक मैड्रिड और बार्सेलोना में अद्यतन विशेषज्ञता से युक्तम स्पेकनिश जैव–प्रौद्योगिकी केन्द्र और प्रांतों का दौरा किया।

सचिव, पेयजल और साफ–सफाई व्यवस्था मंत्रालय ने दिनांक 5–6 सितम्बेर, 2013 को जल के खारेपन को दूर करने जल को शुद्ध करने और शहर कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार करने के लिए मैड्रिड की यात्रा की।

स्पेन की महामान्या महारानी ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर दिनांक 2 अक्तूबर, 2013 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।

स्पेन के विदेशी मामले के मंत्री श्री गोन्जा लो डी. बेनिटो ने भारत की यात्रा की और दिनांक 11–12 नवम्बर, 2013 को ए एस ई एम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

कैटालोनिया (स्पेन) के मुख्य मंत्री श्री अरतुर मेस ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल के साथ दिनांक 23 से 29 नवम्बवर, 2013 तक भारत (नई दिल्ली, मुम्बई, पुणे और बेंगलुरू) की यात्रा की। इस यात्रा में भारत और स्पे न के कैटालोनिया क्षेत्र के मध्यो व्यापार तथा निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया।

जम्मू और कश्मीर के कृषि मंत्री श्री गुलाम हसन मीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रीय सैफरोन मिशन कार्यक्रम के तहत दिनांक 13 से 18 दिसम्बर, 2013 तक स्पेन की यात्रा की और एल्बा सेटे में सैफरोन क्षेत्रों का दौरा किया।

मैड्रिड में दिनांक 28 मार्च, 2014 को स्पेन के साथ द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श किया गया, जिसके दौरान द्विपक्षीय संबंधों के समग्र क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत और स्पेन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 4,681.41 मिलियन अमरीकी डालर (निर्यात – 2,865.75 मिलियनय आयात –1,815.66 मिलियन) का रहा है। वर्ष 2011–12 के आंकडे जो 4,809.06 मिलियन अमरीकी डालर थे, की तुलना में इसमें 2.65 प्रतिशत की कमी आई। अप्रैल 2000 से जुलाई 2013 तक की अवधि में स्पेन से 1,578.52 मिलियन अमरीकी डालर का कुल प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्त हुआ। आटो घटक, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय और स्पेनिश फर्मों के मध संयुक्त उद्यमों की स्थापना, विलियन तथा अभिग्रहण को जारी रखा गया।

अपेरेल और निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ए ई पी सी) ने दिनांक 19 से 24 सितम्बर, 2013 तक स्पेन (मैड्रिड तथा बार्सेलोना) में पांचवी महत्वपूर्ण अपेरेल क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की, जिसमें चार दिन की अवधि में ही 24 मिलियन अमरीकी डालर का कारोबार किया गया।

द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में योगदान करने के लिए सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को जारी रखा गया। इसके तहत दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मैड्रिड में राजनीतिक अध्ययन और संविधान केन्द्र में भारतीय संविधान का स्पेनिश भाषा में अनुवाद जारी किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में सात विद्वानों को भारत–स्पेन सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (सी ई पी) के तहत आई सी सी आर के माध्यम से अकादमिक वर्ष 2013–14 के लिए स्पेन का राष्ट्रि सम्मान प्रदान किया गया।

ब्रिटेन

ब्रिटेन के साथ भारत के बहु–स्तरीय द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा गया। इस संबंध में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने दिनांक 18 से 20 फरवरी, 2013 और 13–14 नवम्बर, 2013 को भारत की यात्रा की। फरवरी, 2013 की अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कैमरून ने भारत आने वाले अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारत की यात्रा की। उनके प्रतिनिधिमण्डनल संसद सदस्य, विश्वविद्यालयों के कुलपति और भारत–ब्रिटेन सी ई ओ मंच के नेता शामिल थे। इस संबंध में दिनांक 19 फरवरी, 2013 को प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई। इस संबंध में एक संयुक्त वक्तव्य् जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जबकि मई, 2010 के भारत–ब्रिटेन शिखर सम्मेालन से अब तक पर्याप्त प्रगति हासिल की गई है। तथापि इन संबंधों का विशेषकर व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में और विस्तार किए जाने की पर्याप्त संभावना है। प्रधानमंत्री कैमरून ने नवम्बर, 2013 में भारत की अपनी कार्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने दिनांक 14 नवम्बंर, 2013 को कोलकाता की संक्षिप्त यात्रा की जिसमें भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता विद्यार्थियों से चर्चा की।

वेल्सं के राजकुमार और कार्नवाल के डच ने दिनांक 6 से 14 नवम्बर, 2013 तक भारत की यात्रा की। वेल्सर के राजकुमार ने दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रपति से भेंट की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत–ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के आपसी हित के मुद्दों पर तथा वैश्विक हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

उप–राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने दिनांक 31 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2013 तक ब्रिटेन की यात्रा की। उन्हों ने ऑक्सफोर्ड इस्लामिक अध्ययन केन्द्र में "पहचान और नागरिकता" के संबंध में जन–व्याख्यान दिया। लोकसभा अध्याक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए दिनांक 9 से 11 अक्तूबर, 2013 तक ब्रिटेन की यात्रा की।

इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों के गणमाण्य व्यक्तियों ने एक–दूसरे देश की यात्रा की। भारत की ओर से की गई महत्वापूर्ण यात्राओं में निम्न लिखित शामिल हैं :

• वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने दिनांक 6 से 10 फरवरी, 2013 तक निवेश संवर्धन के लिए, दिनांक 22 से 25 जून, 2013 तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा करने तथा निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लेने और दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को भारतीय निर्यात और ऋण गारंटी निगम के लंदन कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यात्राएं कीं।

• संस्कृति मंत्री श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच ने 31 मार्च से 2 अप्रैल, 2013 तक इंडिया इंस्टीट्यूट, किंग्स् कालेज में टैगोर वैश्विक विचार केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए यात्रा की।

• नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा0 फारूख अब्दुल्ला ने दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को बारोनेस मार्गरेट थैचर की अंत्येष्टि में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यात्रा की।

• वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बवरम ने 15 से 17 मई, 2013 तक छठी आर्थिक तथा वित्तीकय वार्ता में भाग लेने के लिए यात्रा की।

• विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दिनांक 13 से 16 जून, 2013 तक ऑक्सलफोर्ड विश्वविद्यालय में "भारत–21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था" के संबंध में व्याख्यान देने के लिए यात्रा की।

• अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री के. रहमान खान ने दिनांक 16 से 19 जून, 2013 तक यात्रा की।

• रक्षा राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने दिनांक 9 से 11 सितम्बर, 2013 तक यात्रा की।

• विद्युत राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया ने दिनांक 13 से 16 सितम्बर, 2013 तक ब्रिटेन की विद्युत क्षेत्र कम्पनियों के साथ निवेश प्राप्त करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में विचार–विमर्श करने के लिए यात्रा की।

• विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने दिनांक 16 नवम्बर, 2013 को कोलम्बो में सी एच ओ जी एम 2013 के समापन पर विदेश सचिव श्री विलियम हेग से बातचीत की।

• विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने दिनांक 12 से 14 मार्च, 2014 तक ब्रिटेन के विदेश सचिव विलियम हेग के साथ वार्षिक विदेश मंत्री स्तरीय परामर्श करने और 43वें राष्ट्रमण्डल मंत्री स्तरीय कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने भारत–ब्रिटेन दल संसदीय समूह (सी एम ए जी) के साथ बातचीत की और प्राच्यभ और अफ्रीकी अध्यबयन स्कूंल (एस ओ ए एस), लंदन विश्वविद्यालय में "भारत में प्रजातंत्र की चुनौतियों" के संबंध में व्याख्यान दिया। इसके साथ–साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ बहु–स्तरीय और पश्चिम एशिया से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता का भी आयोजन किया गया।

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने दिनांक 2–3 फरवरी, 2014 को भारत–ब्रिटेन रणनीति वार्ता में भाग लेने के लिए लंदन की यात्रा की।

इसमें ब्रिटेन पक्ष की ओर से भाग लेने वालों में निम्नलिखित शामिल थे ।

• प्रधानमंत्री कार्यालय में बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री केनेथ क्लोर्क ने फार्मास्युटिकल कम्पनियों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ दिनांक 4 से 7 मई, 2014 तक भारत की यात्रा की।

• सरकारी रणनीति के लिए उत्तरदाई और यू.के. पी.एम. के वरिष्ठ सलाहकार श्री ओलिवर लेटविन ने मई, सितंबर और नवंबर, 2013 में भारत की यात्रा की।

• ऊर्जा और जलवायु मंत्री श्री ग्रेगरी बार्कर ने दिनांक 30 जून–3 जुलाई, 2013 को भारत की यात्रा की।

• व्यापार और निवेश राज्य मंत्री लार्ड स्टीफन कीथ ग्रीन ने दिनांक 19 से 21 सितम्बर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

• विदेश कार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्काटलैण्ड विकास मंत्री श्री हम्जा युसुफ ने दिनांक 10 से 16 अक्तूबर, 2013 तक भारत की यात्रा की। उनकी यह यात्रा ग्लाशस्गो के स्कोटिश शहर में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र मण्डल खेल, 2014 के लिए राष्ट्रमण्डल खेल की क्वीमन्सक बैटन रिले के आगमन के समय हुई।

• व्यवसाय, नवाचार और कौशल सचिव डा0 विन्सा केबल ने दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की जाने वाली नौवीं भारत–ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक (जे ई टी सी ओ) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

• ब्रिटेन के साथ नियमित रूप से विदेश कार्यालय परामर्श किए जाते हैं। इस प्रकार के परामर्श का पिछला दौर दिनांक 19 जून, 2013 को लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश सचिव रंजन मथानी और ब्रिटेन प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व स्थाई अवर सचिव, रिमोन फेजर ने किया।

• भारत–ब्रिटेन गोलमेज सम्मेलन की 15वीं बैठक दिनांक 6 से 8

दिसम्बर, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह गोलमेज प्रतिनिधिमण्डल उच्च स्तंरीय गैर–सरकारी समूह होता है जो द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए विचार–विमर्श करता है तथा इस संबंध में सिफारिशें करता है।

फरवरी, 2013 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की भारत यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के संबंध में गठित किए भारत–ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारत–ब्रिटेन रक्षा परामर्शदाता समूह (डी सी जी) की 15वीं बैठक दिनांक 3–4 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ब्रिटेन अभी भी भारत के सर्वाधिक महत्वहपूर्ण 20 व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2012–13 की इस अवधि के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार 14,905.62 मिलियन अमरीकी डालर (निर्यात –8,612.54 मिलियन अमरीकी डालर आयात – 6,293.09 मिलियन अमरीकी डालर था। पिछले वर्ष 2011–12 में यह द्विपक्षीय व्यापार 15724.23 मिलियन अमरीकी डालर का था, इस प्रकार इसमें 5.21 प्रतिशत की कमी आई। ब्रिटेन इस समय भारत में निवेश करने वाला तीसरा बड़ा देश है। अप्रैल, 2000 से जुलाई 2013 तक की अवधि के दौरान ब्रिटेन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 17621.65 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई है। ब्रिटेन की ओर से अपनी 2012–13 की आंतरिक निवेश वार्षिक रिपोर्ट में ब्रिटेन व्यापार तथा निवेश के बारे में जारी किए गए आंकडों के अनुसार भारत की ब्रिटेन में 89 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाएं हैं जिनसे वर्ष 2012–13 के दौरान 7255 रोजगार सृजित किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इस समय ब्रिटेन में पांचवा बड़ा निवेशक देश है।

दोनों पक्षों ने साइबर मुद्दों को द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में अभिनिर्धारित किया है। साइबर मुद्दों से संबंधित संयुक्त कार्य समूह की द्वितीय बैठक आयोजित की जानी है।

भारत–ब्रिटेन संबंधों में भारत–ब्रिटेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग इस समय तेजी से उभरता हुआ घटक है। दोनों सरकारों की सहायता पर आधारित द्विपक्षीय पहल, जिनमें से कुछ सार्वजनिक–प्राइवेट–भागीदारी पर आधारित हैं, ये दोनों पक्षों से कुछ वैज्ञानिक अभिकरणों को शामिल किया गया है।

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए :–

• भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) तथा ब्रिटेन के रसायन, जीव विज्ञान, विकिरण चिकित्सा विज्ञान और परमाणु रक्षा सहयोग गृह विभाग (सी बी आर एन) के साथ (फरवरी 2013) समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

• भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ब्रिटेन के व्यनवसाय, नवाचार तथा कौशल विभाग के मध्य भारत–ब्रिटेन शिक्षा और अनुसंधान पहल (यू के आई ई आर आई) 2013–2016 के तहत "सामुदायिक कालेजों के कार्यान्वयन की कार्य संरचना" के संबंध में और यू के आई ई आर आई 2013–2016 के तहत "विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्य संरचना" के, संबंध में (फरवरी 2013) में समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए।

• भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ब्रिटेन के व्यवसाय, नवाचार और कौशल विभाग के मध्य ब्रिटेन–भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यू आई के आई ई आर आई) 2013–2016 के तहत "कौशल विकास कार्य संरचना" के संबंध में (फरवरी 2013) में समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

• भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (टी एस बी) तथा ब्रिटेन सरकार के प्रौद्योगिकी रणनीति बोर्ड (टी एस बी) के मध्य औद्योगिक अनुसंधान और विकास के संबंध में सहयोग कार्यक्रम (2013–2016) मार्च, 2013 में सम्पन्न किया गया।

• स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और उत्कृष्टता संस्थान के मध्य दिनांक 14 जून, 2013 को संसूचित स्वास्थ्य देखभाल नीति और प्रक्रिया विधि के साक्ष्य के संदर्भ में लंदन में समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

■■

अमेरिका

8

कनाडा

कनाडा के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर की नवम्बर 2012 में की गई भारत यात्रा भारत–कनाडा संबंधों को आगे बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। इस यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें भारत के विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री की सह–अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित की गई भारत–कनाडा रणनीतिक संवाद की उद्घाटन बैठक को आयोजित करना; योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री की सह–अध्यक्षता में भारत–कनाडा मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद की प्रथम बैठक को आयोजित करना और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा उनके कनाडाई समकक्ष के स्तर भारत–कनाडा सुरक्षा संवाद की बैठकें आयोजित करना शामिल है। वर्ष 2014 लगभग 15 वर्ष की अवधि के बाद कनाडा के गवर्नर जनरल श्री डेविड जॉनसन की दिनांक 22 फरवरी से 2 मार्च, 2014 तक की राजकीय यात्रा अर्थात कनाडा से किसी पूर्ण राज्यपाल की यात्रा का साक्षी रहा है।

इस संबंध में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में वर्ष 2010 में सम्पन्न किए गए भारत–कनाडा सहयोग करार को सितम्बर, 2013 में लागू करना एक महत्वपूर्ण घटना रही है। इसी प्रकार के अन्य घटनाक्रमों में भारत–कनाडा श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन करार को अंतिम रूप देना, क्यूबेक राज्य के साथ सामाजिक सुरक्षा के बारे में समझबूझ कायम करना, ऊर्जा, सामुदायिक कालेज, अनुसंधानकर्ता जुटाव और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सम्पन्न किए गए द्विपक्षीय करार शामिल हैं। व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी ई पी ए) के बारे में तकनीकी बातचीत पर पर्याप्त प्रगति हुई है और दोनों देशों ने प्राथमिकता के आधार पर द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण करार (बी आई पी पी ए) को अंतिम रूप देने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

कनाडा के गवर्नर जनरल श्री डेविड जॉनसन ने दिनांक 22 फरवरी से 2 मार्च, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इनकी भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए – (क) भारत–कनाडा श्रव्य–दृश्य सहयोग करार; (ख) स्वास्थ्य और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ग्रान्ड चैलेंजिज कनाडा के मध्य सहयोग से संबंधित सहयोग कार्यक्रम; (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (इंडिया) और कनाडाई सामुदायिक कालेज संघ (कनाडा) के मध्य समझौता ज्ञापन; (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मिटाक्स इंक (कनाडा) के मध्य अकादमिक तथा अनुसंधान विकास के लिए आशय पत्र।

विदेशी मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने दिनांक 21 से 23 सितम्बर, 2013 तक कनाडा की यात्रा की और दिनांक 22 सितम्बर, 2013 को टोरंटों में कनाडा के विदेश मंत्री श्री जॉन बरीड के साथ भारत–कनाडा रणनीतिक संवाद की उद्घाटन बैठक में सह–अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्रों की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा बहु–पक्षीय मुद्दों पर उपयोगी विचार–विमर्श किया। विदेश मंत्री ने दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को ओटावा की भी यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री ईद फास्ट, प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री जॉय ओलिवर और नागरिकता तथा अप्रवास मंत्री श्री क्रिस अलेक्जेण्डर के साथ बैठकें कीं।

भारत–कनाडा कार्यालय स्तरीय ऊर्जा मंच को मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद में स्तरोन्नत करने के निर्णय के अनुसरण में भारत–कनाडा मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद की प्रथम बैठक दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 को ओटावा में आयोजित की गई। इसमें भारत पक्ष की ओर से योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कनाडा पक्ष की ओर से प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने सह–अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान भारत और कनाडा ने मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद के विचारार्थ विषयों, सहयोग के तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात हाइड्रो कार्बन, कोयला और विद्युत तथा ऊर्जा बाजार की स्थापना करने से संबंधित कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग तथा अल्बेरटा पेट्रोलियम विपणन आयोग और भारतीय तेल निगम लिमिटेड के मध्य सहयोग के लिए आशय–अभिव्यक्ति पर भी हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने भारत में कनाडाई निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 14–15 अप्रैल, 2014 को कनाडा की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। इन्होंने कनाडा के वित्त मंत्री श्री जेम्स फलाहेरटी और विदेश मंत्री जॉन बरीड से मुलाकात की तथा कनाडा की अग्रणी कम्पनियों के साथ विचार–विमर्श किया।

आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अरविंद मायाराम ने दिनांक 8 जुलाई, 2013 को ओट्टावा में कनाडा के सह–उप वित्त मंत्री श्री जॉन बोइविन के साथ भारत–कनाडा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति संवाद की प्रथम बैठक की सह–अध्यक्षता की।

भारतीय पक्ष के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में और कनाडाई पक्ष के संबंध में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय के नेतृत्व में भारत–कनाडा सुरक्षा संवाद की उद्घाटन बैठकें उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर आयोजित की गई। इस संबंध में प्रथम दौर का विचार–विमर्श करने के लिए सहायक मंत्रिमंडल सुरक्षा सचिव और कनाडा की प्रिवी काउंसिल के आसूचना ब्यूरो प्रमुख श्री डेविड विग्नोल्ट ने दिनांक 23 से 26 अप्रैल, 2013 तक भारत की यात्रा की। इसके बाद उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री नेहचल संधु की इस संबंध में दिनांक 24 से 27 जून, 2013 तक की कनाडा यात्रा के दौरान अनुवर्ती विचार–विमर्श किया गया।

आतंकवाद रोधी भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को ओट्टावा में बैठक आयोजित की गई। इसमें श्री विनय मोहन क्वात्रा, संयुक्त सचिव (सी टी –सी एस और पी पी तथा आर), विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जबकि श्री अरतुर विलकिन्सकी, महानिदेशक, सुरक्षा और आसूचना ब्यूरो, विदेश कार्य विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने कनाडाई पक्ष का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने आतंकवाद की चुनौती के मूल्यांकन को आपस में साझा किया तथा इसे रोकने के लिए द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय सहयोग पर विचार–विमर्श किया।

नवम्बर, 2012 में प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2015 तक 15 बिलियन डालर के वार्षिक व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वर्ष 2011 तथा 2012 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 5.2 बिलियन डालर का हो गया है। जनवरी से नवम्बर, 2013 की अवधि के लिए कुल द्विपक्षीय व्यापार 5.250 बिलियन डालर का हो गया है।

इस वर्ष के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी ई पी ए) के लिए तकनीकी बातचीत प्रगति पर रही; वर्ष 2013 में 7वें और 8वें दौर की द्विपक्षीय बातचीत की गई। दोनों देशों ने प्राथमिकता के आधार पर द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण करार (बी आई पी पी ए) को अंतिम रूप देने के संबंध में अपनी प्राथमिकता दोहराई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत–कनाडा संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें डा0 टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने और श्री सियोन कैनेडी, कनाडाई उप–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने अपने–अपने पक्ष का नेतृत्व किया। इस समिति ने इस संबंध में किए जा रहे कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2013–2014 की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, जैव–प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य, सतत विकास अवसंरचना, एयरोस्पेस, विज्ञान, संचार, भारत–कनाडा औद्योगिक अनुसंधान और विकास, अनुसंधान व्यवस्था और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है।

भारत–कनाडा संयुक्त शिक्षा कार्य समूह की प्रथम बैठक दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें सामुदायिक कालेज और उद्योग–शिक्षा संस्था सम्पर्क सहित सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व प्रोफेसर वेद प्रकाश, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कनाडा के पक्ष का नेतृत्व श्री पीटर मैक्गर्वन, सहायक उप–मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विकास, विदेश कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने किया।

कृषि

कृषि से संबंधित भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव (आई सी), कृषि मंत्रालय ने किया जबकि कनाडा के पक्ष का नेतृत्व डा0 जसपिन्दर कोमल, महानिदेशक, कृषि और कृषि–खाद्य पदार्थ कनाडा ने किया। इसमें अभिनिर्धारित किए गए प्राथमिकता क्षेत्रों में पशुधन विकास, उदीयमान प्रौद्योगिकी तथा कृषि विपणन शामिल है। अल्ब्रेटा की प्रीमियर सुश्री अलीसन रेड फोर्ड ने दिनांक 11 से 17 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की। उनकी यात्रा के दौरान अल्ब्रेटा और मेघालय, तथा अल्ब्रेटा और पंजाब के मध्य अलग–अलग कृषि सहयोग को बढ़ाने के बारे में संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए।

खनन

खान मंत्रालय ने टोरेंटो में आयोजित किए गए कनाडा सम्मेलन 2013 के वार्षिक संभावित और विकासकर्ता संघ (पी डी ए सी) में (3 से 6 मार्च तक) तथा पी डी ए सी 2014 में (2 से 5 मार्च तक) बड़े प्रतिनिधिमण्डल के साथ सहभागिता की। इसके साथ–साथ खान मंत्रालय और ब्रिटिश कोलम्बिया के ऊर्जा और खान मंत्रालय के मध्य भूविज्ञान तथा खनिज संसाधन में सहयोग के समझौता ज्ञापन के तहत गठित भारत–ब्रिटिश कोलम्बिया संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक दिनांक 12 मार्च, 2013 को वैंकूवर में आयोजित की गई। खान मंत्रालय और प्राकृतिक संसाधन विभाग, कनाडा के मध्य पृथ्वी विज्ञान तथा खनन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन के तहत गठित संचालन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 4 मार्च, 2014 को टोरेंटो में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त खान मंत्रालय और क्यूबेक आर्थिक विकास,नवाचार और निर्यात व्यापार मंत्रालय तथा क्यूबिक प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव मंत्रालय के मध्य खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन के तहत गठित भारत–क्यूबेक संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक दिनांक 5 मार्च, 2014 को टोरेंटो में आयोजित की गई। खान

मंत्रालय और ओंटेरियो के प्रोविन्स के मध्य भू–विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन के तहत गठित किए गए भारत–ओंटेरियो संयुक्त कार्य समूह की सातवीं बैठक दिनांक 7 मार्च, 2014 को सडबरी, ओंटेरियो में आयोजित की गई।

खान मंत्रालय और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के मध्य पृथ्वी विज्ञान और खनन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का दिनांक 13 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में और चार वर्ष के लिए नवीकरण किया गया।

इस्पात

केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने दिनांक 14 से 16 जुलाई, 2014 तक कनाडा की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इस्पात निर्माण और आपसी हित इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) तथा मैक्मास्टर विश्वविद्यालय, हैमिल्टन के मध्य समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

लौह और इस्पात के क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय तथा प्राकृतिक संसाधन विभाग, कनाडा के मध्य सहयोग के लिए नई दिल्ली में दिनांक 13 जनवरी, 2014 को इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री जॉय ओलीवर ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

परिवहन व्यवस्था

परिवहन व्यवस्था से संबंधित भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक दिनांक 5 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें श्री नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा श्री स्काट स्ट्रीनर, सहायक उप–मंत्री, परिवहन, कनाडा ने सह–अध्यक्षता की।

संयुक्त राज्य अमरीका

भारत और संयुक्त राज्य ने रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, व्यापार और निवेश, उच्चतर शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गहन सक्रियता को वर्ष 2013 में भी जारी रखा है। आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के विस्तृत क्षेत्र पर रणनीतिक तथा राजनीतिक परामर्श को जारी रखा गया जिसमें हिन्द महासागर क्षेत्र के संबंध में अतिरिक्त संवाद को शामिल करके और वृद्धि की गई है। यह वर्ष वरिष्ठ स्तर की 70 यात्राओं का साक्षी रहा है और इनमें प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की सितम्बर, 2013 में की गई अमरीका की सरकारी यात्रा भी शामिल है। अमरीकी पक्ष की ओर से की गई प्रमुख यात्राओं में जुलाई 2013 में की गई अमरीकी उप–राष्ट्रपति जोसेफ आर. बिडेन की भारत यात्रा और जून 2013 में की गई अमरीकी राज्य सचिव श्री जॉन एफ. कैरी की भारत यात्रा शामिल है। इस वर्ष की गई मुख्य द्विपक्षीय बातचीत के संबंध में वाशिंगटन में मई 2013 में आयोजित द्वितीय मंत्री स्तरीय होमलैण्ड सुरक्षा संवाद, जून 2013 में नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ भारत–अमरीका रणनीतिक संवाद बैठक, जून 2013 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय उच्चतर शिक्षा संवाद, अक्तूबर 2013 में भारत–अमरीका नागर विमानन शिखर सम्मेलन के लिए नागर विमानन मंत्री की अमरीका यात्रा और भारत–अमरीका ऊर्जा संवाद के लिए डा0 इरनेस्ट मोनिज, सचिव, अमरीकी ऊर्जा विभाग की मार्च, 2014 में भारत की यात्रा शामिल है।

संयुक्त राज्य अमरीका के उप–राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर. बिडेन की उप–राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ नई दिल्ली में संयुक्त बैठक (23 जुलाई, 2013)

प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा

प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने दिनांक 26 से 30 सितम्बर, 2013 तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की और दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से तृतीय शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठक में बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले दशक में भारत–अमरीकी संबंधों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत किया तथा इस पर सहमति व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा इस संबंध में अनेक क्षेत्रों में पहले ही गहन कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस शिखर–स्तरीय बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों में सह–विकास और सह–निर्माण के संदर्भ में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार; हिंद महासागर क्षेत्र को शामिल करने के लिए रणनीतिक परामर्श में वृद्धि; जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त कार्य समूह गठित करना और एच एफ सी के उपयोग के चरण को कम करना तथा द्विपक्षीय निवेश संधि के परिणाम को गति प्रदान करना शामिल है। दोनों नेताओं ने गुजरात में परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक वाणिज्यिक संविदा को अंतिम रूप देने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल को शुरू करने सहित ऊर्जा के संबंध में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया।

अमरीकी उप–राष्ट्रपति की यात्रा

अमरीकी उप–राष्ट्रपति जोसफ आर. बिडेन ने दिनांक 22 से 25 जुलाई, 2013 तक भारत की यात्रा की जो कि 27 वर्षों में किसी कार्यरत राष्ट्रपति की इस प्रकार की प्रथम यात्रा थी। उन्होंने उप–राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से विचार–विमर्श किया, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से भेंट की तथा प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह से मुलाकात की।

रणनीतिक वार्ता

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और अमरीकी राज्य सचिव श्री जॉन एफ. कैरी ने दिनांक 24 जून, 2013 को नई दिल्ली में भारत–अमरीकी रणनीतिक संवाद की चतुर्थ बैठक की सह–अध्यक्षता की। इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की और ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा,

रक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद रोधी कार्यक्रमों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के बारे में सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नागरिक परमाणु करार के पूर्णतः कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया और चार बहु–पक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत की सदस्यता के लिए साथ मिलकर कार्य करने के बारे में सहमति व्यक्त की। इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इरान और एशिया–प्रशांत क्षेत्र सहित आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया।

सचिव, कैरी के साथ उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भी था जिसमें अमरीकी ऊर्जा सचिव डा0 इरनेस्ट मोनिज, अमरीकी प्रशांत कमाण्ड के कमाण्डर एडमिरल सैमुअल जे. होल्डरेन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासक डा0 चार्ल्स बोल्डरेन, अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्रशासक श्री राजीव शाह, आयात–निर्यात बैंक के अध्यक्ष श्री फ्रेड होचबर्ग और अमरीकी व्यापार तथा विकास अभिकरण की निदेशक सुश्री लियोकेडिया जेक शामिल थे। इन अधिकारियों ने रणनीतिक संवाद व्यवस्था के अनुरूप अपने भारतीय समकक्ष अधिकारियों के साथ अलग से बैठकें कीं।

राजनैतिक और रणनीतिक परामर्श

आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में वरिष्ठ स्तर पर सतत रूप से राजनीतिक और रणनीतिक परामर्श जारी रखे गए। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति के बारे में फरवरी 2013 तथा दिसम्बर 2013 में परामर्श किया गया; भारत–अमरीका–अफगानिस्तान त्रिपक्षीय संवाद की तृतीय बैठक फरवरी, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत–अमरीका–जापान त्रिपक्षीय संवाद की चतुर्थ बैठक वाशिंगटन में मई 2013 में आयोजित की गई और इसके बाद पंचम बैठक नवम्बर 2013 में टोक्यो में आयोजित की गई। भारत–अमरीका–पूर्व एशिया परामर्श का छठा दौर मार्च, 2014 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया। मध्य एशिया के बारे में भी मार्च, 2014 में परामर्श किया गया। तत्कालीन विदेश सचिव श्री रंजन यथाई (फरवरी 2013); अमरीकी उप राज्य सचिव श्री विलियम बर्न्स (मई, 2013); अमरीकी राजनीकि कार्य उप राज्य सचिव सुश्री वेन्डी शेरमन (मई, 2013); राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन (अगस्त, 2013) और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिहं (दिसम्बर, 2013) की यात्राओं के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के व्यापक क्षेत्र के बारे में विचारों का उपयोगी आदान–प्रदान किया गया। इसके साथ–साथ अमरीकी विजिटिंग राजदूत की नेपाल (फरवरी 2013), आसियान (फरवरी, 2013), पाकिस्तान (अप्रैल, 2013), बंग्लादेश (अक्तूबर, 2013) और श्रीलंका (नवम्बर, 2013) की यात्रा के दौरान और अमरीकी सहायक राज्य सचिव, दक्षिण और मध्य एशियाई मामले सुश्री निशा देसाई बिस्वाल की यात्रा (मार्च, 2014) के दौरान भी नई दिल्ली में क्षेत्रीय मुद्दों पर परामर्श किया गया। दोनों पक्षों ने हिन्द महासागर क्षेत्र के संबंध में नए संवाद और संयुक्त राष्ट्र/बहु–पक्षीय मुद्दों के बारे में संवाद को शामिल करके इस प्रकार के परामर्श का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

आतंकवाद रोध/सुरक्षा

दोनों देशों के विधि प्रवर्तन और आसूचना अभिकरणों के मध्य विचारों के नियमित आदान–प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए आतंकवाद रोधी सहयोग को जारी रखा गया। द्वितीय होमलैण्ड सुरक्षा संवाद मई, 2013 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया और गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे तथा तत्कालीन अमरीकी होमलैंड सुरक्षा सचिव सुश्री जनेत नेपोलिटैनो ने इसकी सह–अध्यक्षता की जिससे इस समय जारी प्रचालन और क्षमता निर्माण सहयोग को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। दोनों पक्षों ने बड़े शहरों के लिए नीतियां निर्धारित करने, अवैध वित्त को रोकने के लिए मिलकर कार्य करने तथा इसे जब्त करने, साइबर सुरक्षा और बंदरगाह तथा सीमा सुरक्षा के बारे में सहयोग की समीक्षा की।

द्वितीय होमलैण्ड सुरक्षा संवाद के परिणाम के बारे में सहमति व्यक्त करने के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने अमरीका के वरिष्ठ पुलिस प्रमुखों और अमरीकी होमलैण्ड सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता से दिनांक 4–5 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में पुलिस प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया। कुछ अमरीकी कम्पनियों ने इस सम्मेलन के पास होमलैण्ड सुरक्षा प्रणाली और प्रौद्योगिकी के संबंध में लगाई गई प्रदर्शनी में भाग लिया। अमरीका की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के तीव्र प्रवेश को सुकर बनाने के लिए भी अमरीकी वैश्विक प्रवेश विश्वसनीय यात्री नेटवर्क कार्यक्रम में भारत को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

वर्ष 2008 में मुम्बई आंतकी हमले में शामिल होने के कारण डेविड कोलमैन हेडली तथा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध सहित दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2013 तक नई दिल्ली में आपसी विधिक सहायता संधि और प्रत्यर्पण संबंधी मुद्दों के बारे में परामर्श किया गया।

रक्षा

बढ़ते रक्षा व्यापार, संयुक्त कार्य–अभ्यास, कार्मिकों के आदान–प्रदान, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, जल्दस्युता रोधी प्रचालनों इत्यादि के कारण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सतत विस्तार के रूप में देखा गया है। वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एन. ए. के. ब्रोने ने जुलाई, 2013 में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की और इसके बाद थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने दिसम्बर, 2013 में अमरीका की यात्रा की। अमरीका की ओर से की गई मुख्य यात्राओं में अमरीकी नौसेना सचिव की मई, 2013 में अमरीकी प्रशांत कमाण्ड के कमाण्डर एडमिरल सैमुअल जे. लोकलियर ।।। की जून, 2013 में, थल सेनाध्यक्ष जनरल रेमण्ड टी. ओडिरनो की जुलाई, 2013 में तथा उप–रक्षा सचिव डा0 एश्टन कार्टर की सितम्बर 2013 में की गई यात्राएं शामिल हैं। जनरल विन्सेंट ब्रुक्स, अमरीकी सेना प्रशांत के कमाण्डर जनरल ने सेना कार्यकारी संचालन समूह की बैठक में

भाग लेने के लिए फरवरी, 2014 में यात्रा की।

वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में लम्बी दूरी के समुद्री टोही विमान बोइंग पी–81 और भारतीय वायु सेना में सी–17 ग्लोबमास्टर–।। सहित भारतीय रक्षा सेवाओं में प्रमुख अमरीकी रक्षा प्लेटफार्म को शामिल किया गया। दिसम्बर, 2013 में भारत तथा अमरीका ने 6 अतिरिक्त सी 130जे सुपर हरक्यूलस विमानों के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की निविदा पर हस्ताक्षर किए। इन प्रयासों को प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की सितम्बर 2013 में की गई यात्रा के दौरान घोषित 'रक्षा सहयोग के सिद्धांतों के बारे में संयुक्त घोषणा' जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रौद्योगिकी रिलीज के संदर्भ में अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारों के समान ही भारत को महत्व देने पर सहमति व्यक्त की थी और दोनों पक्षों ने एक वर्ष के भीतर परिवर्तनकारी सह–विकास और सह–निर्माण परियोजनाओं को अभिनिर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की थी, के तहत पर्याप्त महत्व प्रदान दिया गया है।

वाशिंगटन में जनवरी 2013 में आयोजित संयुक्त तकनीकी समूह की 15वीं बैठक में विचार–विमर्श के माध्यम से रक्षा अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखा गया। सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) तथा वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्री श्री अविनाश चन्दर की अगस्त, 2013 में अमरीका यात्रा तथा अमरीकी सहायक सचिव, रक्षा, अनुसंधान और इंजीनियरी श्री अलान शैफर की नवम्बर 2013 में भारत यात्रा के दौरान भी इस संबंध में उपयोगी विचार–विमर्श किया गया।

अमरीकी संयुक्त युद्ध बंदी, जो एकाउंटिंग कमाण्ड की कार्रवाई में गायब हो गए थे, का खोज अभियान पांच वर्ष के बाद नवम्बर 2013 में भारत में पुनः शुरू किया गया।

आर्थिक और वित्तीय सहयोग

अप्रैल से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान अमरीका को 29.30 बिलियन अमरीकी डालर के भारतीय माल का निर्यात किया गया और 16.73 बिलियन अमरीकी डालर का भारतीय आयात किया गया जिसके परिणामस्वरूप 12.57 बिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त व्यापार किया गया। अप्रैल से दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान अमरीका, भारतीय माल के संबंध में द्वितीय सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2014 तक भारत में कुल 11.84 बिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया जिससे अमरीका, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला पांचवा सबसे बड़ा अंशदानकर्ता बन गया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विनिर्दिष्ट पहलुओं का समाधान करने के विचार से भारत और अमरीका 2014 में नई दिल्ली में व्यापार नीति मंच की अगली बैठक की तैयारी करने के लिए कार्य–स्तरीय विचार–विमर्श कर रहे हैं। सितम्बर, 2013 में प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अमरीकी यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने द्विपक्षीय निवेश संधि का परिणाम शीघ्र प्राप्त करने के लिए बातचीत में गति लाने के बारे में सहमति व्यक्त की है।

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और अमरीकी कोष सचिव श्री जेरू लेऊ ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2013 को वाशिंगटन में आयोजित की गई भारत–अमरीका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी की चतुर्थ बैठक की सह–अध्यक्षता की। इस बैठक में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास स्टाक बढ़ाने तथा समूह–20 देशों सहित विभिन्न वैश्विक मंचों में सहयोग बढ़ाने पर विचार–विमर्श किया गया। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन और अमरीकी संघीय रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष श्री बेन बरनानके ने भी भाग लिया।

पुनर्गठित भारत–अमरीका मुख्य कार्यकारी मंच ने जुलाई 2013 में वाशिंगटन में अपनी बैठक आयोजित की। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने भाग लिया।

असैनिक परमाणु सहयोग

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने गुजरात में परमाणु विद्युत संयंत्र विकसित करने के लिए सितम्बर, 2013 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एन पी सी आई एल) और वेस्टिंग हाउस के मध्य प्रारंभिक संविदा पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग के वाणिज्यिक कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति हासिल की है। नागरिक परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत–अमरीकी कार्य समूह की पांचवी बैठक जुलाई 2013 में मुम्बई में आयोजित की गई जिसमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जारी अनुसंधान सहयोग परियोजनाओं के बारे में विचार–विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केन्द्र के तत्वावधान में संभावित सहयोग पर भी विचार–विमर्श किया। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और अमरीकी परमाणु विनियामक आयोग ने अक्तूबर, 2013 में तकनीकी सूचना के आदान–प्रदान और परमाणु सुरक्षा सामग्री के संबंध में सहयोग पर एक करार सम्पन्न किया। इस करार के तहत सूचना के आदान–प्रदान में सुरक्षा के विनियमन से संबंधित सूचना, कचरा प्रबंधन, निर्धारित परमाणु ऊर्जा सुविधाओं तथा परमाणु सुरक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित सूचना शामिल होगी।

ऊर्जा

तेल और गैस, कोयला, विद्युत और ऊर्जा कार्य कुशलता, नई प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं से भारत–अमरीकी ऊर्जा संवाद की कार्य संरचना के तहत ऊर्जा सहयोग को जारी रखा गया। इस ऊर्जा संवाद के सह–अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष योजना आयोग और अमरीकी ऊर्जा सचिव डा0 इरनेस्ट मोनिज ने चतुर्थ स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक तथा जून 2013 में रणनीतिक संवाद के अनुरूप और मार्जिन के आधार पर अप्रैल 2013 में नई दिल्ली में

अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग की समीक्षा की। अमरीकी ऊर्जा अवर सचिव श्री डेविड सेंडालो ने भी अप्रैल 2013 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ ऊर्जा सहयोग पर विचार–विमर्श किया। भारत और अमरीका ने मई 2013 में ऊर्जा वार्ता के तहत सतत विकास के संबंध में एक नया कार्य समूह गठित करने के बारे में समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया। ऊर्जा संसाधन ब्यूरो के राज्य विभाग में ऊर्जा राजनय के उप–सहायक सचिव श्री अमोस हास्टिन ने फरवरी, 2014 में भारत की यात्रा की। डा0 इरनेस्ट मोनिज, सचिव, अमरीकी ऊर्जा विभाग (यू एस डी ओ ई) ने मार्च 2014 में दिल्ली और मुम्बई की यात्रा की। डा0 मोनिज और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भारत–अमरीका ऊर्जा संवाद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक की सह–अध्यक्षता की।

अमरीकी राज्य विभाग के विशेष दूत की मई 2013 तथा नवम्बर, 2013 में यात्रा के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मुद्दो के समन्वयक, राजदूत कार्लोस पास्कुअल की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में भारत–अमरीका संवाद के तृतीय और चतुर्थ दौर के दौरान वैश्विक तेल और गैस बाजार में दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर उपयोगी विचार–विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री की अमरीकी यात्रा के मार्जिन पर भारत और अमरीका ने वहनीय ऊर्जा प्राप्त करने में कमी की समस्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवाचारी स्वच्छ ऊर्जा समाधान के विकास में सहायता प्रदान करके तथा इसका वित्त पोषण करके भारत की ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक नई पहल – स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा पहुंच को प्रोत्साहित करना (पी ई ए सी ई) से स्वच्छ ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है।

भारतीय और अमरीकी पक्ष की ओर से एक समान सार्वजनिक और प्राइवेट वित्त पोषण प्रतिबद्धता के साथ संयुक्त स्वच्द ऊर्जा अनुसंधान और विकास केन्द्र के तत्वावधान में घोषित समझौते के परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में संयुक्त नवाचारी अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013 में तीन सार्वजनिक–प्राइवेट बहु–सांस्थानिक संघों अर्थात (पद्ध भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान; ;पपद्ध ऊर्जा अनुसंधान और विकास की व्यवस्था करने के लिए अमरीका–भारत संयुक्त केन्द्र और ;पपपद्ध सतत उन्नत लिग्नो सेलुलोसिक बायोफ्यूल सिस्टम के लिए अमरीका–भारत संघ की स्थापना की गई है।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत–अमरीका सहयोग को सितम्बर 2013 में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य समूह का गठन करने के निर्णय से सुदृढ किया गया। दोनों देशों में एच एफ सी के चरणों को कम करने के लिए एच एफ सी के संबंध में भारत–अमरीका कार्यबल के पुनर्गठन के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। पर्यावरण और वन मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन ने वारसा, पोलैण्ड में नवम्बर 2013 में जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र कार्य संरचना कन्वेंशन के तहत पक्षकारों के सम्मेलन में अमरीकी विशेष दूत टोड स्टर्न के साथ इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में विचार–विमर्श किया।

उच्चतर शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री डा0 पल्लम राजू और अमरीकी राज्य सचिव श्री जॉन कैरी ने दिनांक 25 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–अमरीकी उच्चतर शिक्षा संवाद की द्वितीय बैठक में सह–अध्यक्षता की जिसमें इन्होंने सिंह–ओबामा 21वीं सदी ज्ञान पहल के तहत संयुक्त अनुसंधान भागीदारी के पुरस्कारों के द्वितीय दौर; अमरीकी विश्वविद्यालयों में उत्तर–डॉक्टरल अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान से सहायता प्राप्त 126 रमन फेलो की अंतिम सूची और भारत में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए अमरीकी विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु 'कनेक्ट इंडिया' कार्यक्रम की घोषणा की। सामुदायिक कालेज, मुक्त ऑन लाइन कोर्सवेयर और साइबर प्रणाली जैसे क्षेत्रों में भारतीय और अमरीकी संस्थाओं के मध्य सांस्थानिक सहयोग को पूरा करने के अनुरूप चार समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए। दोनों पक्षों ने व्यापक मुक्त ऑन लाइन पाठ्यक्रम (एम ओ ओ सी) सहित दोहरे विद्यार्थी आदान–प्रदान, अनुसंधान सहयोग, संकाय विकास को सुदृढ़ करने, सामुदायिक कालेजों की स्थापना करने में सहयोग, साइबर प्रणाली में सहयोग और प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन के तरीकों पर विचार–विमर्श किया। मानव संसाधन विकास मंत्री डा0 एम. एम. पल्लम राजू ने मई 2013 में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की और अमरीकी शिक्षा सचिव श्री अर्ने डंकन सहित वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों से बातचीत की। फरवरी 2013 में अमरीकी जन–राजनय और सार्वजनिक कार्य उप–राज्य सचिव सुश्री टारा डी. सोने शिन्दे के नेतृत्व में बारह सामुदायिक कालेजों के प्रतिनिधियों सहित बड़े प्रतिनिधिमण्डल ने नई दिल्ली में फरवरी, 2013 में आयोजित किए गए, 'कौशलों को शिक्षा में शामिल करने से संबंधित' सम्मेलन में भाग लिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले जारी सहयोग में वर्ष 2013 में भी वृद्धि जारी रही है। दोनों पक्ष भारत–अमरीका संयुक्त समिति की बैठक में अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य–योजना 2012–2014 के अनुसार आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान; वायुमण्डल, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान; स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान; डाटा साझा करने; विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और गणित की शिक्षा; नवाचार और 'विज्ञान में महिलाओं की स्थिति' के बारे में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। दोनों सरकारों की ओर से वित्त पोषित भारत–अमरीका विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंच (आई यू एस एस टी एफ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी अक्षय निधि तथा सिंह–ओबामा ज्ञान पहल जैसी संयुक्त पहल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रखा गया। आई यू एस एस टी एफ ने वर्ष 2012–2013 में 30 द्विपक्षीय कार्यशालाओं, चार उच्च विद्यालयों, 10 वर्चुअल संयुक्त अनुसंधान केन्द्रों, तीन नवाचार/प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रमों और अनेक दर्जन विद्यार्थी और संकाय फेलोशिप के लिए सहायता प्रदान की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अक्षय निधि बोर्ड ने जून, 2013 में पांच नए पुरस्कारों की घोषणा की। भारत की ओर से नवम्बर 2014 में आयोजित किए जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में अमरीका भागीदार देश होगा।

अंतरिक्ष

भारत–अमरीका अंतरिक्ष सहयोग से संबंधित संयुक्त कार्य समूह की चतुर्थ बैठक मार्च 2013 में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। इसने नासा और इसरो के मध्य कार्यान्वित किए जा रहे मौजूदा सहयोग कार्यक्रमों की समीक्षा की और चन्द्रमा तथा मंगल से संबंधित भावी मिशनों सहित नई सहयोग पहलों पर विचार करने का निर्णय लिया। इसरो और नासा ने सितम्बर, 2013 में संयुक्त राडार सैटेलाइट मिशन प्रणाली (दोहरी आवृत्ति एल और एस बैण्ड) को तैयार करने तथा शुरू करने के बारे में तकनीकी सहायता करार सम्पन्न किया। नासा ने इसरो के नवम्बर, 2013 के मंगल ग्रह कक्ष मिशन के लिए भी गहन अंतरिक्ष नौ संचालन सहायता प्रदान की है।

नागर विमानन

नागर विमानन मंत्री श्री अजीत सिंह ने भी भारत–अमरीका विमानन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिनांक 29 से 31 अक्तूबर, 2013 तक अमरीका की यात्रा की। इस बैठक में परिवहन सचिव, श्री एंथोनी आर. फॉक्स और निदेशक, अमरीकी व्यापार और विकास अभिकरण सुश्री लियोकेडिया आई. जैक सहित वरिष्ठ अमरीकी पदाधिकारियों ने भाग लिया। नागर विमानन मंत्रालय और अमरीकी परिवहन सुरक्षा प्रशासन ने दिसम्बर, 2013 में संवेदनशील सूचना साझा करने से संबंधित करार ज्ञापन सम्पन्न किया ताकि हवाई अड्डो पर तैनात जांच/स्कैन प्रणाली पर तकनीकी सूचना को साझा करने सहित विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को सुकर बनाया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था

संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था से संबंधित भारत–अमरीका संयुक्त कार्य समूह की दसवीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2013 को वाशिंगटन में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका शांति व्यवस्था संस्थाओं के मध्य सांस्थानिक व्यवस्था सहित संयुक्त राष्ट्र संघ शांति व्यवस्था और शांति वाहकों के प्रशिक्षण में सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान–प्रदान किया। दोनों देशों ने दिसम्बर, 2013 में 'शांति व्यवस्था प्रशिक्षण से संबंधित संयुक्त घोषणा' को जारी किया।

अन्य मामले

दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को डा0 देवयाना खोबरागडे, न्यूयार्क में भारत की महाकान्सुल को 'वीजा धोखाधडी' और 'झूठा विवरण' प्रस्तुत करने के आरोप में अमरीकी राज्य विभाग की राजनय सुरक्षा सेवा के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और बाद में अमरीकी न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया था। भारत सरकार ने इस मुद्दे को अमरीकी सरकार के सामने उठाया और डा0 खोबरागडे को गिरफ्तार करने तथा इस कार्रवाई को करने के तरीके के बारे में कड़ी आपत्ति दर्ज की। अमरीका में इस मामले की सुनवाई करने से उन्हें छूट प्रदान करने के भारत के अनुरोध को मना करने के अनुसरण में डा0 खोबरागडे अमरीका द्वारा पूर्ण राजनयिक छूट प्रदान किए जाने के बाद जनवरी 2014 में भारत वापस आ गई। अमरीकी न्याय विभाग ने दिनांक 14 मार्च, 2014 को डा0 खोबरागडे के विरूद्ध दूसरा आरोप पत्र इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किया कि प्रथम आरोप तथा गिरफ्तार करने के वारंट को दिनांक 12 मार्च, 2014 को अमरीकी न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था। भारत ने यह दोहराया है कि इस मामले में कोई दम नहीं है और अमरीका के न्यायालय को भारत में खोबरागडे के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दोनों पक्षों ने राजनयिक विशेषाधिकार और छूट से संबंधित सभी पहलुओं सहित इस प्रकरण से उत्पन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।

लैटिन अमरीकी और कैरेबियन देश

लैटिन अमरीकी और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय यात्राओं, नियमित विदेश कार्यालय परामर्शों और संयुक्त आयोग बैठकों, द्विपक्षीय करारों, विकास सहयोग परियोजनाओं तथा सांस्कृतिक संविदाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। भारत ने कैरेबियन क्षेत्र जहां भारतीय मूल के अधिक व्यक्ति रहते हैं, के साथ सुदृढ़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं। दक्षिण–दक्षिण सहयोग कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में इस क्षेत्र के देशों के लिए भारत की सहायता को हाल के वर्षों में आई टी ई सी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, सहायता अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। लैटिन अमरीकी और कैरेबियन क्षेत्र के साथ व्यापार और निवेश संबंध वर्ष 2000 में 2 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले बढ़कर वर्ष 2012 में 46 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। भारत ने चिली और मेरकोसुर (दक्षिणी बाजार) के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार करार (पी टी ए) किया है। भारत फरवरी 2014 में प्रशांत गुट में पर्यवेक्षक बन गया है। प्रशांत गुट के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2012–2013 में 13.75 बिलियन अमरीकी डालर था।

प्रशांत गुट देशों के साथ व्यापार अन्य लैटिन अमरीका के साथ कुल व्यापार का 30 प्रतिशत है।

एलएसी क्षेत्र में तेजी से समेकन प्रक्रिया चल रही है, सीईएलएसी (लातिन अमरीका तथा कैरिबियाई राज्यों) का गठन किया जाना इसी प्रक्रिया का द्योतक है। एसआईसीए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और भारत एसआईसीए देशों के साथ अपने संबंधों और इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने को महत्व देता है। एसआईसीए देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार तेजी से बढ़ रहा है जो 2012–13 में 1.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कैरिबियन समुदाय (कैरिकॉम) एक अन्य क्षेत्रीय समूह है जिसके साथ भारत के मजबूत संबंध है और वर्ष 2012–13 में इस क्षेत्र के साथ 3.07 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार हुआ।

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री ने रियो में 16–17 अक्टूबर, 2013 को एलएसी क्षेत्रीय राजदूत सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में लातिन अमरीका में राजनैतिक तथा आर्थिक रूझानों और एलएसी क्षेत्र के साथ–साथ मिलकर कार्य करने पर चर्चा की गई।

5 वें सीआईआई भारत का एलएसी कॉ–क्लेव

5वें सीआईआई भारत एलएसी कॉल्क्लेव का आयोजन दिनांक 9–10 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में किया गया। एलएसी क्षेत्र के 11 देशों ने इस कॉल्क्लेव में भाग लया। ऊर्जा, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, खनन, खाद्यवस्तु व्यापार, निवेश, वित्तपोषण, संभारतंत्र फार्मा, रसायन, पर्यटन, यात्रा एवं विकासमूलक सहभागिता जैसे कई विषयों में परस्पर सहयोग तथा कारोबारी अवसर पर चर्चा की गई।

अर्जेंटीना

भारत और अर्जेंटीना के बीच दोनों ओर से द्विपक्षीय यात्राओं के साथ ही वर्ष 2013 में उनके संबंधों को गति मीली। विदेश मंत्री श्री हेक्टर टिमरमैन ने 15–18 जून 2013 को भारत की यात्रा पर आए एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस यात्रा का दौरान उन्होंने श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री के साथ मिलकर चौथे भारत–अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) की सह–अध्यक्षता की। जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया उनमें राजनैतिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा सांस्कृतिक विषय शामिल थे। उन्होंने साझा हित के क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का भी आदान–प्रदान किया गया।

अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत के गवर्नर श्री फ्रांसिस्को पेरेज ने 15–16 अप्रैल, 2013 को गुजरात तथा नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने हेतु सीआईआई द्वारा आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया। चेन्नई में सैनलुई प्रांत, अर्जेंटीना की सरकार के तहत वाणिज्यिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन से संबंधित प्रथम कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सैनलुई प्रांत के गवर्नर श्री क्लॉडियो पॉग्गी ने 7–13 मई, 2013 तक भारत की यात्रा की।

ब्यनोस आयर्स, अर्जेंटीना में सेन्टर ऑफ इंटर अमेरिकन टैक्स एड्मिन्सट्रेसन (सीआईएटी) में शामिल होने के लिए डॉ. सुधा शर्मा, सदस्य, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और सुश्री प्रोमिला भारद्वाज, आयकर महानिदेशक (आयकर), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने अर्जेंटीना की यात्रा की। डॉ. टी रामासामी, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और प्रो.एन बालाकृष्णन, आईआईएससी, बंगलौर ने तृतीय विश्व विज्ञान आकदमी (टीडब्ल्यूएएस), 24वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए 1–3 अक्टूबर, 2013 तक की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम (पीओसी) पर डॉ. रामासामी और डॉ. लीनो बरानाओ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किए। पर्यटन सचिव श्री परवेज दीवान ने 15–24 नवम्बर, 2014 तक ब्यूनोस आयर्स में आयोजित पांचवें भारत महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए 14–16 नवम्बर, 2013 तक अर्जेंटीना की यात्रा की। कपड़ा सचिव, श्रीमती जोहरा चैटर्जी ने शिल्पकार मेले का उद्घाटन किया जो भारत महोत्सव का हिस्सा था।

सीलो थैलियों, खाद्य भण्डारण तथा संरक्षण के आयात की संभावनाओं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सहयोग संबंधी अध्ययन करने और व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिवों श्री अन्टोनी डीसा तथा श्री पी.के. दास ने क्रमशः 24–27 जून, 2013 तथा 9–11 अक्टूबर, 2013 को अर्जेंटीना यात्रा पर अलग से सरकारी शिष्टमण्डलों का नेतृत्व किया।

भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष दर वर्ष आधार पर 14: की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2011–12 में 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2012–13 में 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ।

हैदराबाद में आयोजित बायोएशिया 2014 में शामिल होने और साझा हित वाले क्षेत्रों का पता लगाने और संयुक्त उद्यम विशेषतः वैकल्पिक ऊर्जा तथा कृषि क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम शुरू करने की संभावना का पता लगाने के लिए डॉ. अन्टोनियो जुआन वॉनफट्टी, सांता के प्रांत के गवर्नर और डॉ. लीनो बारानाओ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अभिनव उत्पादन, मंत्री, अर्जेंटीना ने फरवरी, 2014 में भारत की यात्रा की।

बॉलिविया

भारत और बॉलिविया के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में बॉलिवियाई दूतावास खोले जाने के उपरांत यह संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। हालांकि, वर्ष 2012–13 में हुआ 57.38 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार क्षमता से काफी कम है, दोनों देश कारोबार का विस्तार करने तथा इसे विविधता पूर्ण बनाने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। कृषि,

खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा जैव सहयोग के नए क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

ब्राजील

इस वर्ष अधिकाधिक द्विपक्षीय बातचीत किए जाने से ब्राजील के साथ हमारे रणनीतिक भागीदारी और प्रबलित हुई। विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने ब्रासीलिया में 15 अक्टूबर, 2013 को अपने प्रतिपक्ष श्री लुईज अलबर्टो फिगुरीडो मकाडो के साथ भारत–ब्राजील संयुक्त आयोग की छठी बैठक की सह–अध्यक्षता की। सजायफ्ता कैदियों के स्थानांतरण के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007 में विदेश सेवा संस्थान, भारत और ब्राजील के रीओ ब्रॉस्को संस्थान, ब्राजील के सहयोग पर हस्ताक्षरित करार को नवीकृत किया गया। सीमाशुल्क में परस्पर सहायता पर वर्ष 2007 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार संयुक्त आयोग की बैठक के उपरांत लागू हुआ। दोनों पक्षों ने स्मरण किया कि बहुपक्षीय मंचों में समन्वयन और आईबीएसए, ब्रिक्स, बेसिक, जी–4 तथा जी–20 में वर्तमान सहयोग ब्राजील–भारत रणनीतिक सहभागिता के अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम हैं।

संयुक्त आयोग की बैठक में संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों अर्थात् व्यापार, अर्थव्यवस्था, खनन, ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, पर्यावरण तथा चिरस्थायी विकास, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद, कौंसुली मुद्दे और कानूनी मुद्दों में सहयोग पर चर्चा की गई। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति डिल्मा की भारत यात्रा के दौरान स्त्री–पुरूष समानता तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के प्रोन्नयन हेतु आशय विवरण (एसओआई) को लागू करने के लिए 29 अप्रैल, 2013 से 2 मई, 2013 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक 4 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने ब्राजील की यात्रा की। रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहेरा एफजीवी, रीओडी जनेरो ब्राजील में मार्च–मई 2013 तक द्वितीय अल्पावधिक आईसीसीआर पीठ के तौर पर जेबुलो वार्गस प्रतिष्ठान (एफजीवी) में प्रतिनियुक्ति पर थे। इस पीठ की स्थापना वर्ष 2012 में की गई। सैन्य स्टाफ के वाइस चीफ ले. जनरल एस.के.सिंह ने 7–9 अगस्त, 2013 तक ब्राजील की यात्रा की और जनरल एन्जो मार्टिन्स पेरी, ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल जोआकिम सिल्वा ई लूना, सैन्य स्टाफ चीफ के साथ बैठकें कीं। दक्षिण अफ्रीका में 59वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के संबंध में सम्मेलन–पूर्व एक अध्ययन हेतु 7–11 दिसंबर, 2013 तक डॉ. चरणजीत सिंह अटवाल, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष ने ब्राजील में पराना तथा साओ पोलो की यात्रा की। इसी संदर्भ में श्री रामेन्द्र चंद्र देबनाथ, अध्यक्ष, त्रिपुरा विधान सभा ने 9–12 सितंबर, 2013 तक रिओडी जनेरो की यात्रा की। श्री अविनाश चन्दर, रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने परियोजना प्रबंधन समीक्षा बैठक में भाग लिया और 2–6 सितंबर, 2013 तक रीओ डी जनेरो में मैसर्स ईएमबीआरएईआर पर चर्चा की। भारत–ब्राजील विज्ञान परिषद की 9वीं बैठक 27 सितंबर, 2013 को रीओ डी जनेरो में आयोजित की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता प्रो. सी.एन.आर. राव, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और प्रो. जेकब पालीस, अध्यक्ष, ब्राजिलियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने की। श्री एम एफ फारूकी, सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, 21–24 अक्टूबर, 2013 तक रीओ डी जनेरो ब्राजील में आयोजित फ्यूचरकॉम 2013 में हिस्सा लिया।

मंत्रालय के लोक राजनय प्रभाग और फ्यूनाग ब्राजीलियाई विदेश मंत्रालय के साथ सम्बद्ध एक लोक प्रतिष्ठान का आयोजन 3 अक्टूबर, 2013 को ब्रासीलिया में किया गया। ब्राजील के राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय दूतावास, ब्रासीलिया ने विभिन्न भारतीय भाषाओं से चुनी गई लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही ब्राजील के सात प्रमुख शहरों में शतवर्षीय समारोह मनाने के लिए 4 अगस्त से 3 अक्टूबर, 2013 तक भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।

इंटरनैशनल कांग्रेस ऑन आर्युवेद का आयोजन 12–14 नवम्बर, 2013 तक ब्राजील में स्टेट ऑफ गोईयाना में किया गया। यह कार्यक्रम आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, तथा गोईयाना राज्य सरकार द्वारा सह–प्रायोजित किया गया।

वर्ष के दौरान भारत से बड़ी संख्या में वाणिज्यिक शिष्टमण्डलों ने ब्राजील की यात्रा की। भारतीय कम्पनियों ने ब्राजील में क्षेत्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना जारी रखा और इन मेलों में फार्मास्युटिकल्स, चीनी मिल, तथा मशीनरी, वस्त्र मशीनरी, पर्यटन, हस्तशिल्प, ऑटोमोटिवध्वाहन आदि से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।

चिली

वर्ष के दौरान भारत और चिली के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए। श्री लुई मेयॉल, चिली के कृषि मंत्री ने 11–12 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की और श्री चरणदास महंत, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और डी. पुरन्देश्वरी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय चर्चा की। डॉ. फारूख अब्दुला, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने चिली के सीनेट के निमंत्रण पर एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल के साथ 11–15 सितंबर, 2013 तक चिली की यात्रा की। यात्रा के दौरान डॉ. फारूख अब्दुला ने चिली के विदेश मंत्री श्री अल्फ्रेड मोरेनो चार्मे से मुलाकात की और वह चिली के ऊर्जा मंत्री श्री जॉर्ज बन्सटर से भी मिले और भारत में ऊर्जा की स्थिति से अवगत कराया।

भारत और चिली ने द्विपक्षीय अधिमानता व्यापार करार (पीटीए) का विस्तार करने संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है और वे भविष्य में पीटीए को व्यापक आर्थिक सहभागिता करार (सीईपीए) के स्तर तक ले जाने के आशय से इसका विस्तार करने को इच्छुक है। भारत सरकार ने चिली के साथ दोहरा कराधान परिहार्य करार (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।

प्रथम भारत–चिली कोलोकियम का आयोजन 21–22 अक्टूबर, 2013 तक भारतीय दूतावास तथा यूनिवर्सिटी मेयर द्वारा किया गया। हस्तशिल्प निर्यात प्रोन्नयन परिषद (ईपीसीएच) और क्रीड़ा सामग्री निर्यात प्रोन्नयन परिषद (एसजीईपीसी) के शिष्टमण्डलों ने नवम्बर 2013 में चिली की यात्रा की और चिली के आयातकों के साथ क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।

श्री जे.डी. सीलम, राज्यमंत्री (राजस्व), वित्त मंत्रालय ने चिली के नए राष्ट्रपति डॉ. मिशेल बेशलेट शपथ ग्रहण समारोह में 10–11 मार्च, 2014 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया।

कोलम्बिया

वर्ष के दौरान भारत–कोलम्बिया संबंध और प्रगाढ़ हुए। कोलम्बिया के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डीगो मोलानो वेगा ने 17–24 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की। वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार होता रहा। एक 26 सदस्यीय फामैक्सिल शिष्टमण्डल क्रेता–विक्रेता बैठक (बीएसएम) हेतु और स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ बैठकों के लिए बोगोटा की यात्रा की। एपेक से एक 12 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 24–25 अक्टूबर, 2013 तक बीएसएम के लिए बोगोटा की यात्रा की। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित श्री अस्ताब देबू के नेतृत्व में तथा आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक 13 सदस्यीय समकालीन भारतीय नृत्य मण्डली ने 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक तीन दिनों के लिए बोगोटा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। निर्यात संवर्धन हस्तशिल्प परिषद के निमंत्रण पर 16–21 फरवरी, 2014 तक कोलम्बिया गणराज्य से प्रथम महिला श्रीमती मारिया क्लीमेंशिया ने भारत की यात्रा की।

इक्वाडोर

वर्ष के दौरान भारत और इक्वाडोर के संबंध और प्रगाढ़ हुए। डॉ. डी. पुरन्देश्वरी, राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) ने सीआईआई शिष्टमण्डल के साथ 18–20 अप्रैल, 2013 तक इक्वाडोर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और विदेश मामले, व्यापार एवं अखण्डता, इक्वाडोर गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल से सितंबर 2013 तक द्विपक्षीय व्यापार 1280.05 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। एक 26 सदस्यीय फारमेक्सिल शिष्टमण्डल ने बीएसएम हेतु 29–30 जुलाई, 2013 तक इक्वाडोर की यात्रा की और स्वाश्थ्य प्राधिकारियों से मुलाकात की। इक्वाडोर में एफआईटी केन्द्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ विदेश मंत्रालय और सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एड्वांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) के बीच फरवरी 2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना को शीघ्र निष्पादित किए जाने की संभावना है। इक्वाडोर के उप–राष्ट्रपति श्री जॉर्ज ग्लास ने भारत–एलएसी कॉन्क्लेव में एक मुख्य अतिथि के रूप में दिसम्बर 2013 में भारत यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम हमीद अंसारी से मुलाकात की और द्विपक्षीय राजनैतिक तथा आर्थिक संबंधों पर चर्चा की।

गुयाना

गुयाना के साथ हमारे पारम्परिक सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंधों का और विस्तार हुआ और ये संबंध और प्रगाढ़ हुए। भारत ने गुयाना में भारतीयों के आगमन की 175वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने इस प्रयोजनार्थ 15 लाख रू. का अनुदान दिया और भारतीय करारनामा पर एक सेमिनार में भी सक्रियता से हिस्सा लिया।

मैक्सिको

वर्ष के दौरान मेक्सिको के साथ भारत की विशिष्ट साझेदारी बढ़ती और विकसित होती रही। डॉ. डी पुरन्देश्वरी, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री ने 10–13 अप्रैल, 2013 तक मेक्सिको की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, डब्ल्यूटीओ संबंधी मुद्दे तथा कारोबारी वीजा जैसे मामलों की समीक्षा की गई और यह सहमति हुई कि मंत्री स्तरीय नियमित वार्ता से फलीभूत होते द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बल एवं दिशा मिलेगी। इस यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास, मेक्सिकन विदेश व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी कारोबार परिष और सीआईआई संयुक्त रूप से मेक्सिको सिटी में मेक्सिको भारत कारोबार सेमिनार का आयोजन किया जिसमें बड़े पैमाने पर मेक्सिको के कारोबारी तथा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मेक्सिको के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन (आईएफएआई) द्वारा 2–4 अक्टूबर, 2013 तक आयोजित 10 वें राष्ट्रीय पारदर्शित सप्ताह हेतु इस वर्ष भारत को अतिथि देश चुना गया। भारत से आने वाले प्रतियोगियों में भारत के मुख्य आसूचना आयुक्त श्रीमती दीपक संप्यू थे। लगभग 40 भारतीय कम्पनियों ने पहले ही मेक्सिको में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स, तथा ऑटो कल पुर्जे के क्षेत्र शामिल है। अप्रैल 2013 में सम्बद्ध मदरसन ग्रुप ने पुबेला में ऑटो कलपुर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया जो वॉक्सवागन तथा आऊडी जैसे कार बनाने वाली कम्पनियों के लिए ऑटोमोटिव कल पुर्जे बनाएगा। जुलाई 2013 में जाइडस फार्मास्युटिकल्स ने मेक्सिको में अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया। नवम्बर, 2013 में डॉ. रेड्टीज लैबोरेट्रीज ने कवेरनावाका में अपनी विनिर्माण सुविधा को सहयोग देने के लिए मेक्सिको सिटी में एक कार्यालय खोला। मेक्सिको द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में भी वृद्धि हो रही है। मेक्सिको के सिनेपोलिस ने पुणे में भारत का सर्वप्रथम मेगाप्लेक्स (तेरह स्क्रीनें) शुरू किया है। ईईपीसी इंडिया ने इंजीनियरी क्षेत्र के 15 फर्मों के एक व्यापार शिष्टमण्डल को 20–22 अक्टूबर, 2013 तक मेक्सिको भेजा।

16 सितम्बर, 2013 को मेक्सिको के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, नई दिल्ली में लब्ना आर्क स्मारक की प्रतिकृति का अनावरण किया। सुश्री गैब्रिएला क्वेवस, मेक्सिको सीनेट विदेश संबंध समिति के प्रमुख ने 22 से 28 जनवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की। भारत मेक्सिको विदेश कार्यालय परामर्श 7 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय श्री दिनकर खुल्लर ने भारतीय पक्ष की ओर से श्री कारलॉस दी इकाजा, मेक्सिको के उप विदेश मंत्री के साथ एफओसी की सह–अध्यक्षता की। श्री कार्लोस ने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

पराग्वे

ब्यूनॉस आयर्स में भारतीय दूतावास ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 19–28 सितम्बर, 2013 तक पराग्वे में भारतीय खाद्य महोत्सव की मेजबानी की जिसमें पराग्वे के विदेश मंत्रालय से कई लोग और जानेमाने स्थानीय व्यावसायिकों ने हिस्सा लिया।

पेरू

इस वर्ष भारत और पेरू के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 50 वां वर्ष मनाया। उपराष्ट्रपति श्री एम–हमीद अंसारी की दिनांक 26–29 अक्तूबर, 2013 तक की राजकीय यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए, जो वर्ष 1998 के बाद किसी वीवीआईपी की सर्वप्रथम पेरू यात्रा की। रक्षा सहयोग पर करार, संयुक्त आयोग की स्थापना पर ज्ञापन, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आदान–प्रदान कार्यक्रम और संग्रहालय विकास, चल सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार–प्रसार तथा प्रोन्नयन पर हस्ताक्षर किए गए। उप राष्ट्रपति श्री एम.हामिद अंसारी द्वारा एक नया भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शुरूआत की गई। लीमा में 26–28 अक्तूबर, 2013 तक एक भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप राष्ट्रपति श्री अंसारी और पेरू के उपराष्ट्रपति सुश्री मेरीसोल एस्पिनोजा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

एक आठ सदस्यीय पेरूवियन संसदीय शिष्टमण्डल ने 19–24 अप्रैल, 2013 तक भारत की राजकीय यात्रा की। फार्मास्युटिकल निर्यात यात्रा परिषद (फार्माक्सिल) से एक 24 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 31 जुलाई से 3 अगस्त 2013 तक पेरू की यात्रा की। परिवहन तथा संचार क्षेत्र से संबंधित एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए श्री कार्लोस पेयरडेस कनाल्स, परिवहन एवं संचार मंत्री के आमंत्रण पर श्री अधीर रंजन चौधरी, तक पेरू की यात्रा की।

उरूग्वे

राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) से एक शिष्टमण्डल (श्री शैलेन्द्र कुमार, एजीएम (एमआईएन), श्री दीवाकर कुण्डू, वरिष्ठ प्रबंधक (डीबी) ने 22–30 जुलाई, 2013 तक उरूग्वे तथा अर्जेंटिना की यात्रा की ताकि इन दोनों देशों में खनन तथा खानों में निवेश हेतु अवसरों का पता लगाया जा सके। मई 2013 में कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एक शिष्टमण्डल ने उरूग्वे की यात्रा की जिसमें चैम्बर से 12 शिष्टमण्डलों ने हिस्सा लिया।

वेनेजुएला

वेनेजुएला के साथ भारत के संबंधों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला क्योंकि वर्ष 2012 में वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। श्री ह्यगों चावेज फ्रियाज, पूर्व राष्ट्रपति के देहांत के बाद श्री निकोलस मदुरो मोरोस ने ने 14 अप्रैल, 2013 को आयोजित राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री निकोलस माडरो मोरोस की जीत पर तत्काल उन्हें बधाई दी। बॉलीवुड सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर, भारतीय दूतावास के सहयोग से वेनेजुएला के षसिनेमाटीका नैशियोनलष ने वेनेजुएला भर में स्थित थिएटरों में 24 से 31 मई, 2013 तक स्पैनिश सबटाइटल के साथ सात भारतीय फिल्में दिखाईं। जाने माने हिन्दी कवि श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी ने वेनेजुएला में 16 से 22 जून, 2013 तक आयोजित 10 वें विश्व कवि महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत पर दो फोटो प्रदर्शनियां कैराकास में साइमन बोलीवर यूनिवर्सिटी के सेन्ट्रल लाइब्रेरी में आयोजित की गई और इंडिया इन्कलेव ऑफ ए सब कॉन्टिनेन्ट जिसका आयोजन 20 मई, 2013 को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला में किया गया। श्री रफेल शमीरेज, पेट्रोलियम तथा खनन मंत्री और पीडीवीएसए, वेनेजुएला की राज्य तेल कम्पनी ने भारत की यात्रा की और अपने प्रतिपक्ष पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वीरप्पा मोइली के साथ 24 सितंबर, 2013 को व्यापक वार्ता की। मंत्री श्री रमीरेज द्वारा भारत की अनुवर्ती यात्रा के तौर पर ऊर्जा तथा संबंधित क्षेत्रों में अधिकाधिक द्विपक्षीय सहयोग तलाशने के लिए 7–9 अक्तूबर, 2013 तक काराकास में ष्प्रथम कारोबारी गोलमेज वेनेजुएला–भारतः अवसरों की पहचान तथा विकासष का आयोजन किया गया। इस गोलमेज बैठक में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की आठ भारतीय कम्पनियों ने हिस्सा लिया। 9 अक्तूबर, 2013 को विचार–विमर्श सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नौ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

द्वितीय भारत–वेनेजुएला संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) 20 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री और वेनेजुएला के विदेश मंत्री श्री ईलियास जोस जौवा मिलानो, ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। आर्थिक, वाणिज्यिक, कृषि, आईटी, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं कोंसुली जैसे विषयों में सहयोग सहित संपूर्ण

द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। वर्ष 2013–16 की अवधि हेतु सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए।

मध्य अमरीका

बेलीज

भारत के बीलीज के साथ संबंध और प्रगाढ़ एवं व्यापक हुए। भारत और बेली ने बेलमोपान में 18 सितंबर, 2013 को सूचना आदान–प्रदान करार पर हस्ताक्षर किए।

कॉस्टारिका

वर्ष के दौरान कॉस्टारिका के साथ हमारे प्रगाढ़ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध और प्रगाढ़ हुए। डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) सीआईआई शिष्टमंडल के साथ 13–15 अप्रैल, 2013 तक कॉस्टारिका की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कॉस्टारिका में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉस्टारिका के विदेश मंत्री सुश्री एनाबेल गॉन्जालेज ने 18–19 सितंबर, 2013 तक बंगलौर तथा दिल्ली की यात्रा की। डॉ. ऑस्कर एरियाज सांशेज, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा कॉस्टारिका के पूर्व राष्ट्रपति ने आईसीसीआर के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के तहत 25 मार्च से 4 अप्रैल, 2014 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और आईसीसीआर द्वारा आयोजित व्याख्यानों में हिस्सा लिया।

अल सल्वाडोर

श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने 1–4 जून, 2013 तक अल सल्वाडोर की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रथम महिला डॉ. वंदा पिगनाटो से मुलाकात की और साथ ही सन मार्टिन प्रतिष्ठित 'सियूडाड मुजेर' परियोजना भी देखा। उन्होंने उप–राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से अलग–अलग मुलाकात भी की। मंत्रालय द्वारा की गई पेशकश को लागू करने की प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रक्रियाएं एवं अनुभवों के बारे में एक दूसरे से सीखने तथा अनुभव बांटने के लिए अल सल्वाडोर से 10 युवा महिलाओं ने फरवरी–मार्च, 2014 तक भारत की यात्रा की।

ग्वाटेमाला

इस अवधि के दौरान भारत और ग्वाटेमाला के बीच द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों में एक नए युग की शुरूआत हुई। ग्वाटेमाला सरकार ने नई दिल्ली में 4 अप्रैल, 2013 को आवासीय राजनयिक मिशन की स्थापना की। नई दिल्ली में एलएसी क्षेत्र का यह 20वां दूतावास है। राज्य सभा अध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष ने ग्वाटेमाला कांग्रेस के अध्यक्ष को भारत आने का न्यौता दिया। ग्वाटेमाला के उपराष्ट्रपति ने ग्वाटेमाला में आए भूकंप से राहत हेतु भारत सरकार से 3 मई, 2013 को नैशनल पैलेस में आयोजित एवं समारोह में 100,000 अमरीकी डॉलर का सांकेतिक चेक प्राप्त किया। इंजीनियरी निर्यात प्रोन्नयन परिषद के एक शिष्टमण्डल ने 23–26 अक्तूबर, 2013 तक ग्वाटेमाला की यात्रा की और क्रेता–विक्रेता की अत्यंत सफल बैठक आयोजित की।

हुड्रांस

भारत सरकार ने हुड्रांस में जमास्ट्रन घाटी सिंचाई परियोजना हेतु 26.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी।

निकारागुआ

इस अवधि के दौरान निकारागुआ के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति मिली। निकारागुआ के विदेश मंत्री श्री सैमुअल सैन्टोज लोपेज ने 20–23 अगस्त, 2013 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और परस्पर हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। निकारागुआ के विदेश मंत्री को दवाइयों के दो कार्टन सौंपे गए। निकारागुआ के विदेश मंत्री ने राज्यमंत्री (जहाजरानी) श्री मिलिन्द मुरली देवड़ा से भी मुलाकात की और महत्वाकांक्षी अंतर सागर निकारागुआ कनाल परियोजना में भारत की भागीदारी पर चर्चा की। यात्रा पर आए मंत्री ने सीआईआई में उद्योग जगत के साथ भी बातचीत की। भारत सरकार ने निकारागुआ में दो विद्युत सब–स्टेशन स्थापित करने हेतु 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी। निकारागुआ के विदेश मंत्री ने 9–10 दिसंबर, 2013 को आयोजित 5वें सीआईआई भारत–एलएसी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया।

पनामा

इस अवधि के दौरान, भारत और पनामा के मंत्रियों तथा कारोबारी शिष्टमण्डलों की आपसी यात्राओं से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंध और प्रगाढ़ हुए। डॉ. डी पुरेन्देश्वरी, राज्यमंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) ने 16 से 18 अप्रैल, 2013 तक पनामा यात्रा पर सरकारी तथा कारोबारी शिष्टमण्डलों का नेतृत्व किया। उन्होंने 18 अप्रैल को पनामा में इंडिया शो का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने जैवविविधता एवं औषध अन्वेषण उत्कृष्टता केन्द्र हेतु 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी।

कैरिबियाई देश

क्यूबा

उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी की यात्रा से वर्ष 2013 में भारत–क्यूबा संबंध चरम सीमा तक पहुंच गया। क्यूबा के प्रथम उप–राष्ट्रपति के निमंत्रण पर श्री अंसारी के नेतृत्व में 29–30

अक्तूबर, 2013 तक एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने क्यूबा की यात्रा की जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री जितिन प्रसाद, चार संसद सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे।

इस यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति ने अलग से क्यूबा क्रांति के नेता कमांडेन्ट फिडल कास्त्रो तथा क्यूबा के राष्ट्रपति श्री रऊल कास्गो से मुलाकात की। प्रथम उपराष्ट्रपति श्री मिगेल हियाज कैनल बरमुजज और भारत के उपराष्ट्रपति श्री अंसारी ने संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति ने सेन्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित महोत्सव का भी उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान प्रसार भारती तथा क्यूबन इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन (आईसीआईटी) के बीच प्रसारण पर सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कृत्रिम हॉकी टर्फ बिछाने के लिए भारत ने क्यूबा को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान किया।

क्यूबा के विदेश मंत्री श्री ब्रूनो रॉड्रिक्ज पैरिल्ला ने 25 से 27 मई, 2013 तक भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। क्यूबा के विदेश मंत्री ने श्भारत के साथ क्यूबा–एलएसी संबंधश विषय पर आईसीडब्ल्यूए में व्याख्यान दिया।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में 15–18 सितंबर, 2013 तक एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने क्यूबा की यात्रा की।

भारत सरकार ने लेबियोफैम इंजेक्टेबल प्लांट (पशु टीका) (5.05 मिलियन अमरीकी डॉलर) और केमिकल बल्क ब्लेंडिंग प्लांट (2.71 मिलियन अमरीकी डॉलर) के प्रस्तावित आधुनिकीकरण हेतु क्यूबा के लिए ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी।

डॉमिनिकन गणराज्य

भारत के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सैन्टो डोमिंगो में 14 अगस्त, 2013 को राजदूत ने राष्ट्रीय दिवस समारोह की मेजबानी की। यह पहला अवसर था जब डॉमिनिकन गणराज्य में भारतीय राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेश व्यापार तथा निवेश मंत्री श्री जीन एलन रॉड्रिक्ज, उप विदेश मंत्री अलाजान्द्र लिरियानो और समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित हुए। डॉ मर्सीडीन योवन्ना रोड्रिक्स सिल्वर, प्रशासन एवं वित्त उपमंत्री के नेतृत्व में मुम्बई में 24 से 26 अप्रैल, 2013 तक आयोजित फार्मेक्सिल–2013 में 3 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने हिस्सा लिया। सैन्टो डॉमिन्गो में 14–21 अक्तूबर, 2013 तक एक भारतीय खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया।

हेती

एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय शिष्टमण्डल, जिसमें ले. जनरल रणबीर सिंह के नेतृत्व में महानिदेशक, असम राइफल्स केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे, ने हेयती में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय पुलिस एकक जत्थों से 5–9 अगस्त, 2013 तक मुलाकात की ताकि वहां तैनात तीनों जत्थों अर्थात् असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल तथा सीआईएसएफ के बारे में सटीक सूचना प्राप्त की जा सके। इस यात्रा के दौरान, हेती में संयुक्त राष्ट्र स्थायित्व मिशन (मिनूत्साह) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिष्टमण्डल ने मुलाकात की जिन्होंने भारतीय बलों के कार्य–निष्पादन की प्रशंसा की और भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भारतीय जत्थों को भेजते रहें। भारतीय जत्थों के विशिष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, उन्हें राष्ट्रपति भवन की रक्षा के साथ–साथ उच्च प्रोफाइल तथा महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।

जमेका

मृदा विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. शैलेश नायक ने हिन्द महासागर पर्वत श्रेणी में पॉलीमेटालिक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स के उत्खनन हेतु भारत के आवेदन का पक्ष लेने और किंग्सटन में 8 से 26 जुलाई, 2013 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सीबेड ऑथॉरिटी के 19वें सत्र में भाग लेने हेतु जमेका की यात्रा की। श्री एंथॉनी हिल्टन, जमाइका के उद्योग, निवेश तथा वाणिज्य मंत्री ने नासकॉम इंडिया लीडरशिप फोरम में शामिल होने के लिए फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय उद्योग जगत के नेताओं और साथ ही सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। किंग्सटन, जमाइका में सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने के लिए 2.1 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल लागत की प्रथम किस्त के रूप में जमाइका को 4.78 करोड़ रू. की रोकड़ सहायता प्रदान की गई।

सुरीनाम

भारत और सुरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा सूरीनाम मानक ब्यूरो के बीच पारामारीबो में दिनांक 15 जून, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सेन्ट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम के गवर्नर श्री जिलमोर हॉफड्राड ने जुलाई, 2013 में मुम्बई की यात्रा की और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग करने और भारतीय बैंक की एक शाखा खोलने की संभावना पर रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर के साथ चर्चा की। विपक्ष के नेता श्री चंद्रिका परसाद संतोखी के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय शिष्टमण्डल ने अगस्त, 2013 में भारत की यात्रा की और सुरीनाम में भारतीय मूल के लोगों (डायसपोरा) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप्रवासी भारतीय मंत्री श्री वायलार रवि से मुलाकात की। जून, 2013 में, तीन प्रोफेसर जीबी पंत इंस्टीट्यूट से प्रोंनिवेदिता सिंह, इग्नू से प्रो. कपिल कुमार और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से डॉ. अर्चना कुमार ने सूरीनाम के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिगेसी ऑफ स्लेवरी एंड इंडेचर्ड लेबर विषय

पर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और शोध पत्र प्रस्तुत किए। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 140वीं वर्षगांठ 5 जून, 2013 को मनाई गई। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के तहत नो इंडिया कार्यक्रम में एक सूरीनाम राष्ट्रिक ने अप्रैल–मई 2013 में आयोजित 24वें नो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दो सूरीनामी राष्ट्रिकों ने अगस्त–सितंबर 2013 में आयोजित 25वें नो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

त्रिनिदाद व टोबैगो

इस वर्ष भारत और त्रिनिदाद व टोबैगो के बीच सभी स्तरों पर गहन बातचीत चलती रही जिससे हमारे संबंध और अधिक विविध एवं सुदृढ़ हुए। डॉ रूडल यूनीलाल, आवास, भूमि तथा समुद्री मामले मंत्री त्रिनिदाद व टोबैगो के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 2 से 6 अप्रैल, 2013 तक भारत की यात्रा की। श्री अजय माकन, आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अतिथि शिष्टमण्डल के साथ शिष्टमण्डल स्तरीय वार्ताएं आयोजित कीं और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

श्री कृष्णा तीरथ, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने 29 मई से 31 मई, 2013 तक त्रिनीदाद व टोबैगो की यात्रा की। 30 मई 2013 को उन्होंने भारतीय आगमन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जो त्रिनीदाद व टोबैगो में हर वर्ष मनाया जाता है।

श्री साइमन ईयरवुड, स्थायी सचिव, जन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 24–30 जून, 2013 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने योजना आयोग के सदस्य डॉ. सईदा हमीद, और तिहाड़ जेल तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी) के पदाधिकारियों से मुलाकात की।

त्रिनीदाद व टोबैगो के नारियल क्षेत्र का मौके पर आकलन करने और एक खाका तैयार करने के लिए देश का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय नारियल विकास बोर्ड (सीडीवी), कोच्ची से एक दो सदस्यीय तकनीकी दल ने 31 मई से 9 जून, 2013 तक त्रिनीदाद व टोबैगो की यात्रा की।

भारतीय आगमन मनाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत में त्रिनिदाद व टोबैगो गणराज्य के उच्चायोग के सहयोग से 1 जून, 2013 को आईसीसीआर में चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत पर एक पांच दिवसीय प्रदर्शनी शमिलापश का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्री सुश्री चंद्रेश कुमारी कटोछ द्वारा 31 मई, 2013 को किया गया।

संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोछ के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय 3 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2013 तक त्रिनिदाद व टोबैगो की द्विपक्षीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान श्रीमती कटोच ने राष्ट्रपति एंटनी थॉमस अकीनास कारमोना से मुलाकात की और प्रधानमंत्री सुश्री कमला प्रसाद बसेसट और विदेश मंत्री विंस्टन डूकेस तथा कला एवं बहु संस्कृति मंत्री, डॉ. लिंकन डगलस से भी वह मिले।

आपदा राहत

आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मानवीय सहायता के रूप में सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट तथा ग्रेनेडीन्स (एसवीजी) में से प्रत्येक को 500000 अमरीकी डॉलर और डॉमिनिका राष्ट्रमण्डल को 300000 अमरीकी डॉलर की राशि का डोनेशन दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

9

संयुक्त राष्ट्र में भारत

संयुक्त राष्ट्र आम सभा का 68वां सत्र

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय सरकारी शिष्टमण्डल ने न्यूयॉर्क में 27 सितंबर से 30 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) के 68वें सत्र के उच्च स्तरीय खण्ड में हिस्सा लिया।

आम सभा में 28 सितंबर, 2013 को आम चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने तथा इसे पुर्नगठित करने का आग्रह किया ताकि यह वर्तमान राजनैतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित कर सके। 68वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा में उत्तर 2015 विकास एजेंडा हेतु मंच तैयार करना विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबी उपशमन को उत्तर 2015 विकास एजेंडे का आधार स्तम्भ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और जोर देकर उस खतरे से आगाह किया कि यदि यह विश्व एक मजबूत अर्थव्यवस्था के विकास की कीमत पर अभिशासन संबंधी मुद्दे पर बल देता है तो हम इस एजेंडे को पूरा करने से चूक जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ष्एक सार्थक उत्तर 2015 एजेंडे में खाद्य एवं पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, जल, स्वच्छता, ऊर्जा और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव न बरतने जैसे मुद्दों पर समान रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिएष्। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर वैश्विक कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। हमें विशेषतः संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट, संगठित तथा निरन्तर वैश्विक कार्रवाई हेतु अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दुहराने की आवश्यकता है। उन राष्ट्रों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उन्हें हथियार, प्रशिक्षण अथवा धन उपलब्ध कराते हैं। और न ही वे अपनी जमीन को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने संबंधी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 68वें सत्र हेतु 23–30 सितम्बर, 2013 तक न्यूयॉर्क की यात्रा की। इस अवधि के दौरान चीन, मिस्र, लीबिया, फिलीस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमरीका से अपने प्रतिपक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अवसर पर आयोजित कई बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया जिनमें जी–4 विदेश मंत्रियों की बैठक, सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत जीसीसी राजनैतिक वार्ता, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक, चिरस्थायी विकास पर उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच और परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक उच्च स्तरीय बैठक आदि शामिल हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान–की मून से भी मुलाकात की।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर आम सभा में 26 सितंबर, 2013 को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेते हुए विदेश मंत्री ने एक समयबद्ध तरीके से परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी कार्ययोजना के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु भारत के निरन्तर सहयोग की पुरजोर तरीके से अभिपुष्टि की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर भारत की एक विश्वसनीय न्यूनतम रोकथाम नीति और पहले प्रयोग न करने संबंधी अपनी दृढ़ता है और वह परमाणु हथियारों की होड़ सहित किसी भी हथियारों के होड़ में शामिल होने से इन्कार करता है।

श्री ई–अहमद, विदेश राज्यमंत्री ने 9–14 अक्तूबर, 2013 तक न्यूयॉर्क की यात्रा की और यूएनजीए वैश्विक विकास मुद्दों की द्वितीय समिति की आम चर्चा में हिस्सा लिया और भारत की ओर से 10 अक्तूबर, 2013 को अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी समिति में महिलाओं की तरक्की शीर्षक एजेंडे पर 11 अक्तूबर, 2013 को आयोजित आम चर्चा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने आगे रवांडा, पूर्व यूगोस्लाविया हेतु अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल्स और आपराधिक ट्रिब्यूनलों हेतु अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट तंत्र विषय पर संयुक्त परिचर्चा के दौरान 14 अक्तूबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा को सम्बोधित किया।

श्रीमती प्रनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री ने 21–27 अक्तूबर, 2013 को न्यूयॉर्क की यात्रा की और आम सभा तथा सुरक्षा परिषद संबंधी विचार–विमर्श में हिस्सा लिया। उन्होंने मध्यपूर्व में परिस्थिति पर चर्चा में भाग लिया और 22 अक्तूबर, 2013 को भारत की ओर से वक्तव्य दिया। उन्होंने 25 अक्तूबर, 2013 को अफ्रीकी विकास हेतु नई सहभागिता विषय पर यूएनजीए को सम्बोधित किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 28 सितम्बर, 2013 को यूएनजीए के 68वें सत्र के उच्च स्तरीय दौर की बैठक में अपने सम्बोधन में वैश्विक अभिशासन संस्थाओं में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भविष्य में 'बहुपक्षवाद को प्रासंगिक एवं कारगर रखने के लिए' बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। यह वह सही स्थान है जहां से इसकी शुरूआत की जा सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि ष्संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार एवं इसकी पुर्नसंरचना अवश्य की जानी चाहिए ताकि यह वर्तमान राजनैतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। अधिक से अधिक विकासशील देशों को स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2015 तक सुधार प्रक्रिया को पूरा कर लेने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ष्आज से दो वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान अस्तित्व में आये प्रत्येक राष्ट्र ने इस सभा में अपनी जगह बनाई है, न केवल गौरव के साथ अपितु उनके मन में कुछ उम्मीदें भी हैं। वर्ष 2015 हमारी सफलताओं पर जश्न मनाने का मौका है और यह सुनिश्चित करने का अवसर है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन तथा सुरक्षा परिषद में चिर प्रतीक्षित सुधारों को पूरा करके इस शताब्दी के लिए तैयार है।

68वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अवसर पर 26 सितम्बर, 2013 को जी–4 विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की जहां सुरक्षा परिषद सुधारों के बारे में विचारों का आदान–प्रादन किया गया। ब्राजील के बाह्य संबंध मंत्री, जर्मनी के विदेश मामले संबंधी संघीय मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रियों ने इस बात का उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के लगभग 70 वर्षों के बाद भी सुरक्षा परिषद में सुधार दीर्घ प्रतीक्षित है। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान चुनौतियों सहित अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में सुरक्षा परिषद के समक्ष आ रही कठिनाइयों ने इस आवश्यकता पर और बल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए ताकि 21वीं सदी की भौगोलिक राजनैतिक वास्तविकताएं परिलक्षित हो। उन्होंने स्मरण किया कि लगभग 10 वर्ष पहले 2005 विश्व शिखर सम्मेलन के आउटकम दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की और इसलिए वर्ष 2015 तक मौजूदा करार को ठोस परिणाम में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मंत्रियों ने इस बात पर भी बल दिया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता, स्थायी तथा अस्थायी दोनों, के विस्तार हेतु सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त पुरजोर समर्थन को ध्यान में रखते हुए, यह सदस्य राष्ट्रों के बीच बातचीत प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होना चाहिए और अंतर सरकारी बातचीत (आईजीएन) के अध्यक्ष की सिफारिशों की तर्ज पर आगे की बातचीत के आधार के रूप में एक संक्षिप्त कार्य दस्तावेज तैयार करने का आह्वाहन किया। उन्होंने विस्तारित परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीका के प्रतिनिधिमण्डल हेतु उन्होंने अपने समर्थन की पुनः अभिपुष्टि की।

जी–4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत तथा जापान) के संयुक्त राष्ट्र मामले के महानिदेशकों की बैठक 11 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिषद सुधार पर विचारों का आदान–प्रदान करना था। जी–4 महानिदेशकों ने न्यूयॉर्क में यूएनएससी सुधारों से संबंधित वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और साथ ही इस प्रक्रिया को तत्काल पाठ् आधारित अंतर सरकारी बातचीत की दिशा में ले जाने के लिए भावी योजनाओं पर भी विचार किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार हेतु यू.एन. सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापक समर्थन का उल्लेख किया ताकि 21वीं शताब्दी की भौगोलिक राजनैतिक वास्तविकताओं और साथ ही इस परिषद को और अधिक प्रतिनिधिमूलक, कारगर तथा पारदर्शी स्वरूप को बेहतर ढंग से परिलक्षित कर सके।

विदेश मंत्रालय और रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आईडीएए) द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं' विषय पर संयुक्त रूप से एक दिवसीय आउटरीय सेमीनार का आयोजन 12 फरवरी, 2014 को किया गया जिसमें विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने बीज व्याख्यान दिया और सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसकी पुरातन संरचना संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सदस्यता को परिलक्षित करे।

शांति बहाली

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना संबंधी अपनी नीति को सक्रियता से जारी रखा जिनमें शांति स्थापन विशिष्ट समिति और यूएनएससी शांति स्थापना कार्य समूह के भीतर समापन वक्तव्य तथा विचार–विमर्श शामिल है। शांति स्थापना अधिदेशों हेतु निर्णय प्रक्रिया में सैन्यबल भेजने वाले देशों की अधिकाधिक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन्यबल प्रतिपूर्ति दरों जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सैन्य बल भेजने वाले देशों के सरोकार शामिल हैं, से संबंधित लम्बित समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रक्रिया में सैन्यबल भेजने वाला सबसे बड़ा तथा समनुरूप योगदानकर्ता रहा है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रक्रिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्यबल

भेजने वाला देश था जिसके तहत 7923 सैन्यबलों तथा पुलिस कर्मियों को नौ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में और अफगानिस्तान में एक पर्यवेक्षण मिशन के लिए तैनात किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (4037), दक्षिण सूडान (2093), लेबनान (897) हेयती (429) और सीरिया–इज्राइल सीमा गोलान हाइट्स (194) कुछ प्रमुख मिशन हैं जिनमें भारतीयों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। इसके अलावा भारत का यूएनडीओएफ (गोलान हाइट्सद्ध में भारत का एक फोर्स कमांडर है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सैन्य बलों तथ पुलिस कर्मियों द्वारा निर्धारित उच्च कार्य निष्पादन मानकों को विश्व भर में सराहा गया है।

राष्ट्रमण्डल

भारत जो राष्ट्रमण्डल का सबसे बड़ा सदस्य–राष्ट्र है, जहां संघ की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हैए ने संगठन के कार्यकलापों में व्यापक तौर पर लगा रहा। भारत राष्ट्रमण्डल बजट में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमण्डल कोष (सीएफटीसी) में पांचवां सबसे बड़ा अंशदाता है ।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कोलम्बो में 15.17 नवम्बर, 2013 तक आयोजित राष्ट्रमण्डल सरकार प्रमुख की बैठक ;सीएचओजीएमद्ध में एक अधिकारिक अधकारिक भारतीय शिष्ट्रमण्डल का नेतृत्व किया। सीएचओजीएम 2013 का विषय था ष्साम्याता आधारित विकास समावेशी विकास। विदेश मंत्री ने पूर्व सीएचओजीएम राष्ट्रमण्डल विदेश मंत्रियों की बैठक में भी 13.14 नवम्बरए 2013 तक हिस्सा लिया। कमेटी ऑफद होल ;सीओडब्ल्यूद्ध की वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठकें 10.12 नवम्बरए 2013 तक आयोजित की गई। इस अवधि क दौरानए कोलम्बों में कॉमनवेल्थ विजनेस फोरम (12.14 नवम्बर) कॉमनवेल्थ पिपुल्स फोरम (10.14 नवम्बर) की बैठकें भी आयोजित की गई। सीएचओजीएम में सरकार प्रमुखों ने राष्ट्रमण्डल, के भीतर तथा विश्व स्तर पर घटनाक्रमों की समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन का ध्यान उत्तर. 2015 वैश्विक विकास कार्यढांचे जयवायु प्रतिकूल छोटे राष्ट्रों के लिए वित्तपोषण हासिल करने की क्षमता छोटे राष्ट्रों की ऋण संबंधी चुनौतियों हेतु समाधानए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश राष्ट्रमण्डल देशों के नागरिकों के लिए सीमा पर अड़चनों को कम करने हेतु उपायों पर केन्द्रित रहा। सीएचओजीएम के समापन पर नेताओं के सीएचओजीएम 2013 विज्ञप्ति को अपनाया जिसमें व्यापक तौर पर अंतराष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। राष्ट्राध्यक्षों ने युवाओं के लिए मंगमपुरा वचनबद्धता को भी अंगीकृत किया जिसके तहत चिरस्थायी तथा समावेशी विकास के केन्द्र में युवा लोगए चिरस्थायी समावेशी तथा सम्यक विकास पर कोलम्बो घोषणा (सीएचओजीएम के विषय पर आधारित) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश पर कोट्टे व्यत्तव्य ।

भारत श्रीलंका में आयोजित सीएचओजीएम 2013 में पुर्नगठित राष्ट्रमण्डल मंत्रीस्तरीय कार्य समूह ;सीएमजीद्ध में 2013.15 तक की अवधि हेतु एक सदस्य बना । सीएमएजी जिसकी स्थापना 1995 के सीएचओजीएम में ऑकलैंड में हुई थीए राष्ट्रमण्डल मौलिक राजनैतिक मूल्यों के गंभीर अथवा निरन्तर उल्लंघनों से संबंधित मामलों को देखता है । विदेश मंत्री ने लंदन में 13.14 मार्च तक आयोजित 43 वीं सीएमएजी बैठक में हिस्सा लिया । फिजी ही एक मात्र मुद्दा है जो इस समय सीएमएजी के औपचारिक एजेंट में शामिल है ।

राष्ट्रमण्डल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने राष्ट्रमण्डल संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 6.9 फरवरी, 2013 तक नई दिल्ली की यात्रा की और पुनः 18.22 नवम्बर, 2013 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

जलदस्युता

ब्रसेल्स में 9 सितंबर, 2013 तक द्वितीय भारत.यूरोपीय संघ जलदस्युता रोधी वार्ता आयोजित की गई। दोनों पक्षों में जलदस्युता रोकथाम के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों के बारे में एक. दूसरे को अवगत कराया और यूरोपीय संघ तथा भारत से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर चर्चा की ।

सोमालिया के अपतट पर जलदस्युता संबंधी संपर्क समूह की 14 वीं समापन बैठक न्यूयॉर्क में 1 मई, 2013 को आयोजित की गई । इस समापन बैठक का विषय 4 'प्रोग्रेस अगेंस्ट सोमाली पायरेसीः सिग्निफिकेन्ट बट रीवर्सिबल.वी मस्ट स्टे द फोर्स' था । समापन तथा संबंधित बैठकों में भारतीय शिष्टमण्डल ने हमारी चिंताओं से अवगत कराया जिनमें अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र और जहाजों पर प्राइवेट तौर पर अनुबंधित सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों का उपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं ।

सोमालिया के अपतट पर जलदस्युता संबंधी संपर्क समूह की 15 वीं समापन बैठक जिबोती में 14 नवम्बरए 2013 को आयोजित की गई। श्री संदीप कुमार, संयुक्त सचिव (वाना) विदेश मंत्रालय ने समापन बैठक हेतु भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया ।

जनतांत्रिक पहलकदमियां

(i) **जनतांत्रिक समुदाय (सीओडी):** विदेश मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 17.18 जनवरी, 2013 तक जनतांत्रिक समुदाय का एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से डॉ एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और श्री लूवसनवंदन बोल्ड, मंगोलिया के विदेश मंत्री, जनतांत्रिक

समुदाय के वर्तमान पीठ द्वारा किया गया। इस सम्मेलन मं 17 सदस्य राष्ट्रों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूएनडी संघ तथ यूनेस्को) ने भाग लिया ।

(ii) **बाली जनतांत्रिक मंच (बीडीएस):** बाली इण्डोनेशिया में 7–8 नवम्बर, 2013 तक 6 बाली जनतांत्रिक मंच (बीडीएस. पअ) की बैठक का आयोजन किया गया। श्री बृजबिहरी टंडन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीडीएस.पअ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बीडीएस.पअ का विषय 'कान्सॉलिडेटिंग डेमोक्रेसी इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी' था ।

(iii) **संयुक्त राष्ट्र जनतांत्रिक कोष (यूएनडीईएफ)** : संयुक्त राष्ट्र जनतांत्रिक कोष की शुरूआत भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणामस्वरूप था और संयुक्त रूप से इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और यू.एन. महासचिव कोफी अन्नान द्वारा न्यूयॉक में 14 सितम्बर, 2005 को की गई। 31.56 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान देकर भारत यूएनडीईएफ में अंशदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है। भारत समझता है कि यह कोष जनतांत्रिक मूल्यों तथा प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के बाबत एक कारगर साधन है और अपने सर्वोच्च शासी निकाय सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में यूएनडीईएफ में एक प्रमुख भूमिका निभाई है ।

आतंकवाद

श्री अलेक्जेन्डर ईवान्स, समन्वयक, अलकायदा तालिबान अनुवीक्षण दल संयुक्त राष्ट्र ने श्री हन्स जेकब स्किन्डलर दल का सदस्य के साथ 24.25 फरवरीए 2014 तक भारत की यात्रा की और विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अल.कायदा तथा तालिबान प्रतिबंध शासन व्यवस्था की कारगरता को बढ़ाने के लिए तौर–तरीके पर विचार करने हेतु बातचीत की ।

द्विपक्षीय परामर्श

भारत जापान (17 मई, 2013), नौर्वे (16 जनवरी, 2014) तथा यू.के. (12 मार्च, 2014) के साथ विभिन्न यू. एन. मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श किया। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व श्री नवतेज सिंह सरनाए अपर सचिव (आई.ई ओ) विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।

समूह 77. विदेश मंत्रियों के साथ वार्षिक बैठक :

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 26 सितंबरए 2013 को न्यूयॉर्क में समूह 77 के विदेश मंत्रियों की 37 वें वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेवृत्व किया। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि यह समूह रियो 20 के निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रियाओं तथा 2015 के बाद विकास कार्यसूची में अग्रणी रहे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास विकासशील देशों के मुख्य प्राथमिकताओं की सशक्त छाप है।

समूह 15 (जी–15)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर सितंबर, 2013 में न्यूयॉर्क में आयोजित समूह 15 (जी–15) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत ने जी–15 के अंतर्गत क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता परियोजनाओं तथा अन्य कार्यकलापों को करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बौद्धिक सम्पदा प्रवजन तथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषय पर चार क्षेत्रों को अनुमोदित किया। भारत भी जी–15 को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में जुटा रहा और संस्थागत तंत्र तथा क्षेत्रीय सहयोग संबंधी कार्यसमूहों में की जाने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

चुनाव

वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत की उपस्थिति और मजबूत हुई। भारत जो कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में 1950 में इसके गठन के समय से ही सदस्य रहा है, को पुनः पांच वर्ष की अवधि के लिए पेरिस में में 13 नवम्बर, 2013 को 37 वें यूनेस्कों महासम्मेलन में चुन लिया गया। मॉन्ट्रियल में 24 सितंबर, से 4 अक्तूबर, 2013 तक 38 वें असेम्बली बैठक के दौरान भारत को काउंसिल ऑफ इंटरनैशनल सिविल एविएशन ओर्गनाईजेशन में पांच वर्ष के लिए चुन लिया गया कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स (सीएनडी) में 2014.17 की अवधि हेतु एचआईवी/एड्स/यूएन एड्स संबंधी संयुक्त यूएन कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड में 2014.17 हेतुय अप्रैल में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ बुमन (सीएसडब्ल्यू) में 201416 हेतु; और यूनाईटेड नेशंसएंटीटीफॉर जेन्डर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ बुमन में 2014–16 हेतु; नवम्बर, 2013 में चुना गया। भारत को लंदन में 25 नवम्बर से 4 दिसंबर, 2013 तक आयोजित इंटरनैशनल मेरीटाइम ऑर्गनाईजेशन (आएमओ) की कार्यकारी परिषद में 2014–15 हेतु पुनः चुन लिया गया ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखारीक्षक श्री शशिकांत शर्मा को जुलाई, 2014 से छः वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक बोर्ड में चुन लिया गया जिन्होंने 1 नवम्बर, 2013 को आयोजित चुनाव में 124.62 मतों से जीत हासिल थी । भारत की उम्मीदवार डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को 12 सितम्बर, 2013 को आयोजित चुनाव में डब्ल्यूएचओ दक्षिण.पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया। श्री देवेश उत्तम,

प्रथम सचिव, भारतीय स्थायी मिशन (पीएमआई) न्यूयॉर्क को प्रशासनिक एवं बजट प्रश्नों संबधी सलाहकार समिति में 2014–16 के कार्यकाल के लिए अनुमोदन के द्वारा चुना गया।

आर्थिक तथा विकास संबंधी मुद्दें

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसॉक)

भारत ने जीनेवा में 1–26 जुलाई, 2013 तक आयोजित आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के स्वायत्त सत्र में भाग लिया। भारतीय शिष्टमण्डल ने चिरस्थायी विकास एवं सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार (एसटीआई), और संस्कृति की संभावना विषय पर वार्षिक मंत्रीस्तरीय समीक्षा हेतु सम्बोधित किया ।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विशेष कार्यक्रम

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 25 सितंबर, 2013 को यूएनजीए के अध्यक्ष की मेजवानी में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विशेष कार्यक्रम में भारतीय शिष्टमंण्डल का नेतृत्व किया । भारत ने इस बात पर बल दिया कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में समाविष्ट गरीबी उन्मूलन तथा प्रमुख मानक विकास उद्देश्यों पर वर्ष 2015 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिक से अधिक ध्यान होना चाहिए ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवजन तथा विकास पर उच्च्स्तरीय वार्ता :

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 'मेकिंग माइग्रेसन वर्क' (प्रवजन को कारागर बनाना) विषय पर न्यूयॉर्क में 3–4 अक्तूबर, 2013 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवजन तथा विकास पर द्वितीय उच्च-स्तरीय वार्ता में भारतीय शिष्टमंण्डल का नेतृत्व किया। इस वार्ता के समापन पर एक घोषणा की गई जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवजन पर एक कारगर तथा समावेशी एजेंडे की दिशा में कार्य किया जाए जो विकास को समेकित करता हो तथा मानवाधिकार के प्रति सम्मान हो ।

विकास हेतु वित्तपोषण पर छठी उच्चस्तरीय वार्ता

विकास एवं प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों तथा शिखर सम्मेलनों के परिणामों हेतु वित्तपोषण के लिए 'द मॉन्टेरी मतैक्य दोहा घोषणाः क्रियान्वयन की स्थिति तथा आगे के कार्य' नामक समग्र विषय पर न्यूयॉर्क में 7–8 अक्तूबर, 2013 को विकास हेतु वित्तपोषण पर छठी उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित की गई। श्री अरूण जेटली संसद सदस्य तथा भारतीय शिष्टमंण्डल के सदस्य ने भारत की ओर से वक्तव्य दिया ।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों और विकलांगों के लिए अन्य अंतरर्राष्ट्रीय सम्मत विकास लक्षयों पर उच्च स्तरीय बैठक

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा ने न्यूयॉर्क में 23 सितम्बर, 2013 को एमडीजी एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सम्मत अन्य विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूएनजीए की उच्च् स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया इस बैठक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था : (वर्ष 2015 और इसके बाद निःशक्तता के साथ विकास की कार्यसूची' भारत ने समर्थकारी समावेशी परिवेश के निर्माण के संबंध में अपनी प्रतिबृद्धिता की पुनः पुष्टि की ताकि सभी निःशक्त व्यक्तियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने और समाज में अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लायक बनाया जा सके।

एशिया व प्रशान्त महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी)

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, डॉ डी पुरंदेश्वरी ने 25 अप्रैल से 1 मई, 2013 तक बैंकाक में यूएनईएससएपी के 69 वें वार्षिक आयोग सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। इस सत्र का विषय केन्द्रित शीर्षक थाः 'प्राकृतिक आपदाओं एवं बड़े आर्थिक संकट के बाद उबरने की क्षमता के निर्माण का अवसर' इस विषय से संबंधित मंत्रालय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और जी.20 रूस शिखर सम्मेलन एशिया प्रशान्त महासागर से सन्दर्भ के बारे में उच्च स्तरीय परामर्श का आयोजन किया गया था। वार्षिक सत्र के दौरान 17 संकल्प अंगीकृत किए गए थे। एशिया प्रशान्त सांख्यिकी संस्थान (एसआईएपी) की शासी परिषद का चुनाव इस सत्र के दौरान किया गया था। भारत को शासी परिषद में दुबारा चुन लिया गया तथा इसके मतों की संख्या अधिकतम रही ।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री केशव देसीराजू ने 16–20 सितम्बर, 2013 तक बैंकाक में यूएनएससीईएपी और एशिया. प्रशान्त जनसंख्या सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंण्डल का नेतृत्व किया। भारत ने थाईलैण्ड सरकार के सहयोग से यूएनईएससीएपी द्वारा सयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा बैंकाक में 26–28 अगस्त, 2013 में आयोजित एशिया प्रशात मंत्रालयी वार्ताः वर्ष 2015 के बाद एमडीजी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य तक में भाग लिया। यूएनईएससीएपी द्वारा बैंकॉक में 4.8 नवम्बर, 2013 तक एशियाई परिवहन मंत्रियों के द्वितीय मंच का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने भाग लिया था और इस मंच पर सतत विकास

एवं क्षेत्रीय एकीकरण के साधन के तौर पर परिवहन से संबंधित एक मंत्रालयी घोषणा को अंगीकार किया गया था ।

17–20 दिसम्बर, 2013 तक यूएनईएससीएपी द्वारा आर्थिक सहयोग व एकीकरण विषयक प्रथम मंत्रालयी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, डॉ ई. एम.एस. नाचियरप्पन ने उक्त सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया ।

यूएन हैबिटेट

यूएन है बिटेट की शासी परिषद के 24 वें सत्र का आयोजन 15–19 अप्रैल, 2013 तक नैरोबी में किया गया था और आवास एवं शहरी विकास मत्री श्री अजय माकन ने इसमें भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया था। उन्होंने नैरोबी में 14 अप्रैल, 2013 को आवास एवं शहरी विकास के संबंध में एशिया प्रशान्त मंत्रियों के सम्मेलन के ब्यूरो की बैठक में भी भाग लिया ।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)

भारत यूनिडो के औद्यौगिक विकास बोर्ड तथा कार्यक्रम एवं बजट समिति (पीबीसी) का सदस्य बना हुआ है। श्री सौरव चन्द, सचिव (डीआईपीपी) ने 5–6 सितम्बर, 2013 तक वियना की यात्रा की जहाँ उन्हें भारत तथा यूनिडो के बीच वर्ष 2013–17 की अवधि के दौरान सहयोग के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा दक्षिण दक्षिण औद्यौगिक सहयोग हेतु यूनिडो केन्द्र (यूसीएसएसआईसी) से संबंधित भारत-यूनिडो परियोजना के दूसरे चरण पर हस्ताक्षर करने के लिए यूनिडो के महानेशक ली यंग ने 12–14 नवम्बर, 2013 तक भारत की यात्रा की।

भष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी)

भारत ने भष्ट्राचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (युएनसीएसी) में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह की बैठक, जो 10–12 अप्रैल, 2013 तक वियना में आयोजित की गई थी, में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अपराध निवारण तथा आपराधिक न्याय आयोग के 22 वें सत्र 27–31 मई, 2013 तक कार्यान्वयन समीक्षा समूह की बैठक (युएनसीएसी का चौथा सत्र) 25–29 नवम्बर, 2013 तक पनामा सिटी में यूएनसीएसी में पक्षकार राज्यों (सीओएसपी) के सम्मेलन के 5 वें सत्र में भाग लिया । भारत ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए यूएनसीएसी के महत्व पर बल दिया जबकि ज्यादातर अन्य देश इसका महत्व कम आँक रहे थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी अकादमी (आईएसीए)

भारत ने लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया स्थित अन्तराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध अकामदी ;आईएसीएद्ध की सदस्यता स्वीकार कर ली। स्वीकृति विलेख 29 मई 2013 को प्रस्तुत किया गया था और भारत के लिए यह जुलाई 2013 से लागू हो गया ।

अन्तर.संसदीय संघ (आईपीयू)

लोकसभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने जेनेवा में अक्तूबरए 2013 में आयोजित अन्तर संसदीय संघ की 129वीं एसेम्बली में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। भारतीय प्रतनिधिमण्डल ने आईपीयू एसेम्बली के चार खण्डों आर्थात पेनल विचार.विमर्श निमित विषयों से संबंधित आईपीयू समितिए आपातकालीन मद तथा एसेम्बली के उपरांत सत्र में सक्रिय भागीदारी की । राज्य सभा के उपादक्ष्य प्रोण पीण जेण कूरियन ने जेनेवा में 16.20 मार्च 2014 तक आयोजित अन्तर–संसदीय संघ की 130 वीं एसेम्बली में उच्चस्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया ।

विश्व डाक संघ (यूपीयू)

भारत विश्व डाक संघ के क्रियाकलापों से जुड़ा रहा। सुश्री पी. गोपीनाथन, सचिव (डाक) ने अक्तूबर, 2013 में जेनेवा में विकास हेतु वित्तीय समामेलन सहायक विषयक वैश्विक मंच में भागीदारी की।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

जेनेवा में आईटीयू परिषद की बैठकों के अलावा भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के क्रियाकलापों में भाग लिया । विश्व दूरसंचारध्सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी संबंधी पांचवी नीति मंच की मईए 2013 में जेनेवा में आयोजित बैठक और साथ ही डब्ल्यू एसआई एस मंच 2013 में दूरसंचार विभाग के उच्चस्तरीय शिष्टमंण्डल ने भाग लिया । भारत ने विचार–विमर्श में तत्परतापूर्वक भाग लिया जिससे छः मुद्दों पर वैचारिक सहमित हुई जिसमें ब्रॉडबैण्ड तथा इन्टरनेट गवर्नेस शामिल है । संचार एवं दूरसंचार प्रैद्योगिकी के साथ.साथ सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने 18 नवम्बरए 2013 को आयोजित कनेक्ट एशिया पैसीफिक सम्मिट तथा थाईलैण्ड सरकार के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 19.22 नवम्बरए 2013 तक बैंकॉक में आयोजित टेलीकॉम वर्ल्ड में भाग लिया ।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

डॉ एल.एस. राठौर, महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

(आईएमडी) को डब्ल्यू एमण्ओ की परिषद के कार्यपालक के रूप में चुना गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य के रूप में भारत ने वर्ष 2013 के दौरान डब्ल्यूएमओ में संस्थानात्मक विकास को क्रमिक बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारत को जलवायु सेवाओं से संबंधित अन्तरसरकारी बोर्ड (आईबीसीएस) की जुलाई, 2013 में आयोजित पहली बैठक में सह–अध्यक्ष चुना गया। उक्त अन्तरसरकारी बोर्ड डब्ल्यू एम ओ कांग्रेस (अक्तूबर, 2012) के असाधारण सत्र द्वारा स्थापित निकाय है जो जलवायु सेवाओं के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क (जीएफसीएस) का कार्यान्वयन करता है। भारत द्वारा नवस्थापित निकाय को दिए जाने वाले महत्व को देखते हुए भारत ने आईबीसीएस को अपने अंशदान के तौर पर 9,00,000 अमरीकी डॉलर का अंशदान किया ।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

भारत का विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्थायी समिति, जेनेटिक संसाधन परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विषयक अन्तर.सरकारी समिति के साथ.साथ संगठनात्मक एवं बजटीय मुद्दों से संबंधित बैठकों में अपना रचनात्मक सहयोग बनाए रखा। ट्रेडमार्क से संबंधित मैडरिड प्रोटोकोल के लिए भारत की स्वीकृति महत्वपूर्ण घटना थी। वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने चिह्नों के अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैडरिड करार विषयक प्रोतोकोल के लिए भारत की स्वीकृति का विलेख सौंप दिया और डब्ल्यूआईपीओ द्वारा 8 अप्रैल, 2013 को आयोजित उच्चस्तरीय नीति वार्ता में भी भाग लिया। विकास कार्य समूह के सदस्य के रूप में भारत ने डब्ल्यूआईपीओ की संबंधित समितियों के कार्यों के संबंध में विकास कार्य अनुशंसाओं को शामिल करने को बढ़ावा देने अनुशंसा करने की दिशा में तत्परतापूर्वक कार्य किया ।

भारत ने जूनए 2013 में मारकेश राजनय सम्मेलन में भी भाग लिया जिसमें 'दृष्टिहीन' दृष्टिबाधित या अन्यथा मुद्रण निःशक्तता बाले व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कृतियों की प्राप्ति हेतु मार्केस संधि को अंगीकार किया गया ।

सचिव औद्योगिक नीति एवं संवर्ध विभाग (डीआईपीपी) ने डब्ल्यूआईपीओ की महासभा की जेनेवा में आयोजित महासभा की बैठक में भाग लिया। भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर जेनेटिक संसाधनों, परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृति अभिव्यक्त से संबंधित डब्ल्यूआईपीओ अन्तर.सरकारी समिति (आईजीसी) के अधिदेशों का वर्ष 2014.15 के लिए नवीकरण कटने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और पाठ को अंतिम रूप देने की सुस्पष्ट संभावना और यहाँ तक कि अगले दो वर्षों में राजनयिक सम्मेलन का आयोजन करने और कानूनन बाध्यकारी करार के अंगीकरण में महती भूमिका निभाई ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) भारत ने व्यापार एवं विकास बोर्ड की यूएनसीटीएडी की बैठकों में, एकल–वर्षी तथा बहुवर्णी विशेषक बैठकों में अपनी भागीदारी जारी रखी और इसके माध्यम से इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संस्थान को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया । न्यूएनसीटीएडी सभी देशों खासकर विकासशील देशों के लाभ के लिए व्यापार एवं विकास के क्षेत्र में यथार्थपरक नीति विश्लेषण में सहायक रहा है । भारत ने जून 2013 में वर्ष 2015 के बाद एक संगत कार्ययोजना हेतु नए आर्थिक दृष्टिकोण विषयक न्यूएनसीटीएडी लोक संगोष्टि के आयोजन में विशेष योगदान किया है । भारत ने सितम्बरए 2013 में व्यापार एवं विकास बोर्ड की बैठक के 60 वें सत्र में भी भाग लिया । भारत ने वर्ष 2015 के बाद सतत विकास कार्यसूची विषयक प्रथम जेनेवा वार्ताए जो नवम्बरए 2013 में आयोजित की गई थीए में भी भाग लिया ।

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास आयोग (यूएससीएसटीडी)

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रोद्योगिकी व विकास आयोग के सदस्य के रूप में भारत ने जूनए 2013 में जेनेवा में आयोजित 16 वें सत्र में भाग लिया । भारत ने अधिक सहयोग विषयक कार्यचालन समूह (डब्ल्यूजीईसी) की बैठक में भी तत्पतापूर्वक भाग गया। उक्त समूह का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था और इसे वर्ष 2005 में वर्ल्ड सम्मिट ऑनद इन्फॉरमेशन सोसायटी द्वारा अंगीकृत ट्यूनीस एजेण्डा में यथावर्णित अधिक सहयोग की अनुशंसा का अधिदेश दिया गया था। भारत ने सीएसटीडी और कार्यचालन समूह की कार्यवाही के दौरान आईबीएसए देशों तथा समान विचार वाले अन्य देशों के साथ समन्वयन बनाए रखा ।

अंन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी)

भारत ने आईटीसी की अन्तर सरकारी बैठकों में भाग लिया। आईटीसीयूएनसीटीएडी का एक सहायक निकाय है। आईटीसी संयुक्त परार्मर्शी समूह (जेएजी) का 47 वां सत्र मई 2013 में आयोजित किया गया था जिसमें वर्ष 2013–16 हेतु आईटीसी की रणनीतिक योजना सहित आईटीसी के कार्यकलापों पर विचार किया गया था ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत ने जेनेवा में 20.28 मई, 2013 तक विश्व स्वास्थ्य सभा के 66 वें सत्र में भाग लिया। डब्ल्यूएचओ की बैठक के अवसर पर भारत

तथा ब्रिटेन के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए गए। पोलियो को समाप्त करने की देशा में भारत के प्रयासों की डब्ल्यूएचओ द्वारा सराहना की गई। भारत ने इस बात पर बल दिया कि अनिवार्य स्वास्थ्य संरक्षण सेवाओं पर प्रत्येक नागरिक का हक है। इसने कल्याण के आंतरिक मूल्यों अर्थात जीवन की गुणवत्ताए औचित्य व सामाजिक न्याय के लिए स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया क्योंकि नए वैश्विक विकास लक्ष्यों में इसे प्रमुख स्थान दिया गया है ।

अंन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

भारत ने आईएलओ के अंन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनए जिसका आयोजन 5.20 जूनए 2013 तक जेनेवा में किया थाए के 102 वें सत्र में भाग लिया । श्रम व रोजगार राज्य मंत्री और असमए दिल्ली व तमिलमाडु के श्रमंत्रियों के इस सम्मेलन में भाग लिया । आईएलसी के दौरान निर्धनों तथा सीमान्त कामगारों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान की दिशा में भारत की प्रगतिशील योजनाओं को मान्यता दी गई। इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीपी), नई पेन्शन योजना ;एनपीएसद्ध को आई एलओ के संघटकों में कामगारों के सामाजिक संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण माना गया। इस संबंध में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के उपाय में आईएलओ संगठन के भीतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसडीवाई), निपुणता विकास नीति(एनएसडीपी), नई पेंशन योजना (एनपीएस) की पहचान की गई थी।

भारत ने आईएलओ के शासी निकाय(जीबी) के 319वें सत्र में भाग लिया जिसका आयोजन अक्तूबर 2013 में किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने शासी निकाय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन के कार्यचालन में भाग लेने के लिए कार्यकारी दल के चर्चा में भी भाग लिया। भारत ने यह कहा कि सामाजिक न्याय सहित समावेशित वैश्विकरण के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के वैश्विक प्रयास तभी किए जाएंगे यदि आईएलओ सामाजिक न्याय घोषणा, 2008 के अनुसार अपनी विकास कार्यसूची में अच्छे कार्य को प्रोत्साहन दे सकें।

आईएलओ के महानिदेशक ने मई, 2013 में भारतीय श्रमिक सम्मेलन में भाग लिया तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और श्रमिक मामलों में भारत द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा की।

एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस)

वर्ष 2013 के दौरान भारत ने एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड की अध्यक्षता की। भारत ने पीसीवी के अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2013 में ईसीओएसओसी की बैठक के दौरान यूएनएआईडीएस के संकल्प पारित करने को सुविधाजनक बनाया। प्रथम बार सभी कार्यसूची मदों पर आम सहमति से निर्णय लिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यसूची 2015 के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य लक्ष्ण के साथ–साथ बहुक्षेत्रीय कार्रवाई के अन्य लक्ष्यों के अंतर्गत एचआईवी लक्ष्यों को शामिल करने का निर्णय किया। भारतीय अध्यक्षता के दौरान जेनरीक एन्टी रेट्रोवायरल ड्रग्स की आपूर्ति सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एड्स के विरूद्ध कार्रवाई में भारत के योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समिति

नैशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर (एनआरएससी) से तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 12–21 जून, 2013 को विएना में आयोजित यूएनसीओपीयूओएस के 56वें सत्र में भाग लिया।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे

सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) की उद्घाटन बैठक

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 24 सितंबर, 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच की प्रारंभिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। भारत ने सतत विकास के लिए सशक्त राजनैतिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की तथा इस बात पर जोर दिया कि एचएलपीएफ एक कार्यान्मुखी सहयोग मंच होना चाहिए जिसमें बेहतरीन प्रक्रियाओं तथा अनुभवों को साझा करने, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाने, सभी स्तरों पर मुख्य धारा में सतत विकास के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया हो।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अवसंरचना अभिसमय

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन ने नवंबर, 2013 में वारशॉ, पोलेंड में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र में अवसंरचना अभिसमय में दलों के 19वें सम्मेलन (सीओपी 19) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में दलों के सम्मेलन की 9वीं बैठक में क्वातो प्रोटोकाल (सीएनपी 9) को भी शामिल किया गया था।

मूल समूह के भाग के रूप में चैन्नई, भारत (फरवरी, 2013), केप टाउन दक्षिण अफ्रीका (जुलाई, 2013), फोज दो इगुवाकु, ब्राजील

(सितंबर, 2013) तथा हांगजू, चीन (अक्तूबर, 2013) में बैठकों सहित वार्सा सम्मेलन से पहले भारत, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच निकट समन्वय जारी चलता रहा। भारत ने समान विचारधारा वाले विकास उद्देश्यों के समूहों के साथ मिलकर कार्य किया जिसने वार्सा सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

यूएनईपी के स्थायी प्रतिनिधियों की खुली समिति की बैठक 24–28 मार्च, 2014 को नैरोबी में आयोजित की गई थी जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस बैठक में 23–27 जून, 2014 को नैरोबी में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की प्रारंभिक सभा के लिए कार्यसूची पर चर्चा की गई थी।

मरूस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीसीडी)

मरूस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संबंध में दलों के सम्मेलन के 11वें सत्र (सीओपी–11) 16–27 सितंबर, 2013 को विंडहॉक नामीबिया में आयोजित की गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समिति की 11वीं बैठक तथा अभिसमय कार्यान्वयन समीक्षा के लिए समिति की 12वीं बैठक (सीआरआईसी–12) सीओपी के समान्तर आयोजित की गई थी (सीओपी–11) दोरान 41 निर्णय पारित किए गए थे। इस बैठक में अंतरमंत्रालयी प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। भारत को एशिया प्रशांत समूहों का अध्यक्ष चुना गया है तथा वह 2015 में (सीओपी–12) तक इस पद पर रहेगा।

बेसल रोटरडैम तथा स्टोकलोम अभिसमय

बेसल रोटरडैम तथा स्टोकलोम अभिसमय के दलों के सम्मेलन की बैठक मई, 2013 में साथ–साथ आयोजित की गई थी। भारत ने ब्राजील, चीन, मिस्र तथा ईरान सहित अन्य विकासशील देशों की सहायता से रोटरडैम तथा स्टॉकहोम अभिसमय के अंतर्गत अनुपालन प्रक्रियाओं के निर्णय को स्थगित करवाया। भारत ने ऐसी (सीओपी) के परिणामों में सामान्य परंतु विभाजित दायित्वों को दोहराने की आवश्यकता का पक्ष लिया।

आर्कटिक परिषद

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा ईटली के साथ भारत को मई, 2013 में आयोजित किरुणा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान आर्कटिक परिषद ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। आर्कटिक परिषद वर्ष 1996 में गठित एक उच्चस्तरीय मंच है जो सामान्य आर्कटिक मुद्दों विशेष रूप से आर्कटिक में सतत विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग समन्वय एवं आदान–प्रदान संवर्धित करने के लिए है। भारत ने अक्तूबर, 2013 में व्हाइट होर्स कनाडा में आयोजित वरिष्ठ आर्कटिक अधिकारियों की बैठक के साथ–साथ आर्कटिक परिषद के कार्यसमूहों तथा तदर्थ बलों की बैठकों में भी भाग लिया।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर खुला कार्य समूह (ओडब्ल्यूजी)

सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज (रियो+20) में सतत विकास के लिए लक्ष्यों के एक सेट का अधिदेश दिया गया था तथा इस परियोजन के लिए 30 सदस्यों के खुले कार्यसमूह (ओडब्ल्यूजी) सहित विषयक क्षेत्रों की एक श्रृंखला पर स्टॉक जांच तथा अवधारणात्मक चर्चा का पहला चरण मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक समाप्त हो गया। इसमें ओडब्ल्यूजी की कुल 8 बैठकें शामिल थीं। भारत ने भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के तिगड़ी के रूप में ओडब्ल्यूजी की बैठकों में भाग लिया तथा विकासशील देशों की मुख्य एवं संपूर्ण उद्देश्यों एवं विकास प्राथमिकताओं के लिए प्राथमिकता के रूप में गरीबी उन्मूलन सहित एसडब्ल्यूजी का सेट तैयार करने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से चर्चा में योगदान दिया।

लघु द्वीप विकासशील राज्यों के लिए प्रारंभिक समिति की प्रथम बैठक

भारत ने 24–26 फरवरी, 2014 को न्यूयॉर्क में आयोजित तीसरे एसआईडीएस सम्मेलन के लिए प्रारंभिक समिति (प्रेपकॉम) की प्रथम बैठक में भाग लिया। प्रारंभिक समिति की बैठक के अवसर पर 24 फरवरी, 2014 को एसआईडीएस 2014 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष शुरु करने के लिए अपराह्न में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था भारत ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एसआईडीएस सम्मेलन आयोजित करने के लिए 2,50,000 अमरीकी डॉलर का वित्तीय योगदान दिया।

सामाजिक एवं मानव अधिकार मुद्दे

मानव अधिकार परिषद (एचआरसी)

भारत ने मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में 2013 में आयोजित तीन नियमित सत्रों की कार्रवाई में भाग लिया तथा वर्ष के दौरान एचआरसी द्वारा पारित किए गए कुछ संकल्पों को तैयार करने में रचनात्मक भूमिका निभाई।

भारत को वर्ष 2014 के लिए एचआरसी के ब्यूरो में एशिया प्रशांत समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मानवाधिकार परिषद ने कई विषयगत मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा सीरिया, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, म्यामां, ईरान तथा श्रीलंका (तीसरी बार) के विरुद्ध देश विशेष संकल्प पारित करके

देश विशेष स्थिति तथा म्यांमा में मुस्लिम मानवाधिकार स्थिति पर अध्यक्ष के वक्तव्य पर ध्यान केन्द्रित किया।

भारत ने वर्ष के दौरान विचार की गई कुल 42 देशों की रिपोर्टों में 17 राष्ट्र रिपोर्टों पर वक्तव्य देकर एचआरसी की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया में भी भाग लिया। भारत ने यूपीआरएस कोलंबिया तथा बुरूंडी के लिए ट्रायका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। भारत ने अप्रैल, 2013 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा इसके कारण और परिणामों पर संयुक्त विशेष रिपोर्टकर्ता सुश्री रशिदा मंजू की यात्रा को सुविधाजनक बनाया।

चार प्रख्यात भारतीय महत्वपूर्ण संधि निकायों तथा मानवाधिकार संरचनाओं के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य करते रहे जिनमें श्री दिलीप लाहिरी (रंगभेद के उन्मूलन पर समिति के उपाध्यक्ष) श्री चंद्र शेखर दास गुप्ता (उपाध्यक्ष, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति) श्री अनंद ग्रोवर (वास्तविक एवं मानसिक समस्या के सर्वोच्च धारणीय मानकों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार पर विशेष रिपोर्टकर्ता) श्री किशोर सिंह (शिक्षा के आधार पर विशेष रिपोर्टकर्ता)

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद नें 22 जनवरी, 2014 को मोन्ट्रेक्स (स्वीटजरलैंड) में आयोजित सीरिया पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मंत्री स्तरीय आयोजन में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य सीरिया में गृहयुद्ध के लिए एक राजनीतिक समाधान का पता लगाना था।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

भारत ने 30 सितंबर से 4 अक्तूबर, 2013 को आयोजित जेनेवा में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की कार्यकारी समिति के 64वें सत्र में भाग लिया इस वर्ष भारत ने यूएनएचसीआर के विचार–विमर्श में भी भाग लिया। भारत ने शरणार्थियों के लिए नागरिक पंजीकरण पर संकल्प पारित करने से संबंधित चर्चा में भी हिस्सा लिया।

अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन (आईओएम)

भारत ने नवंबर, 2013 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन परिषद के 103वें सदस्य के विचार–विमर्श में भी रचनात्मक भूमिका निभाई। इस सत्र ने 2015 के बाद विकास कार्यसूची पर चालू विचार–विमर्श में वित्तपोषण की मुख्य संरचना तथा आईओएम की भूमिका पर संकल्प पारित किया। भारत ने इसके मुख्य मानवीय अधिशेष तथा व्यवस्थित तरीके से आईओएम द्वारा उत्प्रवासन प्रबंधन का पालन करने की आवश्यकता भी दोहराई।

सचिव प्रवासी भारतीय कार्यालय मंत्रालय ने जुलाई, 2013 में आईओएम द्वारा आयोजित सर्वप्रथम डायसपोरा द्वारा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया जिसमें डायसपोरा समुदाय को शामिर करने सहायता करने तथा सशक्तिकरण के तरीकों पर चर्चा की गई थी।

आपदा जोखिम में कमी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआईएसडीआर)

आपदा जोखिम में कमी करने के लिए चौथा वैश्विक मंच मई, 2013 में जेनेवा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमईए) से वरिष्ठ अधिकारियों सहित सचिव (सीमा प्रबंधन) गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई दल (एनडीआरएफ) ने वैश्विक मंच में भाग लिया। इसके बाद उसी महीने के प्रारंभ में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मंच का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया।

आपदा जोखिम कमी के लिए महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री मार्ग्रेट वाल्सट्रोम ने दिसम्बर, 2013 में भारत की यात्रा की। उन्होंने गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तथा साथ ही उड़ीसा राज्य की यात्रा भी की और साइक्लॉन फेलिन पर कार्रवाई को आपदा प्रबंधन में उल्लेखनीय सफलता बताया।

उत्प्रवासन तथा विकास के लिए वैश्विक मंच

उत्प्रवासन के लिए मुख्य मूल एवं गंतव्य देश के रूप में भारत ने उत्प्रवासन एवं विकास विचार–विमर्श विशेष रूप से जीएफएमडी के संचालन समूह, मंच के भविष्य पर आंकलन दल तथा मंच मित्रों के वैश्विक मंच में भाग लिया। अब उत्प्रवासन एवं विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी) वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन तथा विकास पर उच्चस्तरीय बैठक के बाद गठित किया गया था जोकि अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन एवं विकास पर मूल पारगमन एवं गंतव्य देशों में वार्ता प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक व्यापक वैश्विक मंच है। वर्ष 2013–14 के दौरान जीएफएमडी के वित्तपोषण के लिए जीएफएमडी अध्यक्ष को 50,000 अमरीकी डॉलर का भारतीय अंशदान सौंपा गया।

यूनेस्को

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 5–20 नवंबर, 2013 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन के 37वें सत्र के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 37वें सत्र में शिक्षा पर सर्वोच्च संकेन्द्रण सहित 2014–2021 के दौरान यूनेस्को के लिए मध्यावधि रणनीति पारित की। इस सत्र में यूनेस्को के वर्ग 2 केन्द्र की स्थापना के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में 'एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों के लिए विश्व प्रकृती विरासत प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का मार्ग प्रशस्त करने से संबंधित संकल्प पारित किया गया' डॉ. शशि थरूर ने नवंबर, 2013

यूनेस्को द्वारा आयोजित ने ब्रीक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक तथा ब्रीक्स–यूनेस्को बैठक में भी भाग लिया।

भारत को 26 जून से 5 जुलाई, 2013 तक पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आईओसी सभा के 27वें सत्र में अंतरसरकारी समुद्र विज्ञानी आयोग (आईओसी) की कार्यकारी परिषद में भी निर्वाचित किया गया। भारत सरकार ने 2013–2017 की अवधि के लिए डॉ. कर्णसिंह को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में पुनर्नामित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2013 दिया गया था।

ई–9 के समूह के देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत ने यूनेस्को में नीतिगत वार्ता का नेतृत्व किया जिसमें 2015 के बाद उभरते विकास कार्यसूची में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। भारत ने यूनेस्को के साथ मिलकर 27–28 जून, 2013 को नई दिल्ली में ष्इनक्लूजीव रेलीवेंट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑलष पर तकनीकी बैठक की सह–अध्यक्षता की।

वर्ष 2013 में यूनेस्को ने स्वामी विवेकानंद की 150वां जन्म दिवस मनाया इस अवसर पर 7 अक्तूबर, 2013 को भारत ने एक समारोह आयोजित किया। वर्ष 2013 को यूनेस्को द्वारा अमृता शेरगिल की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारत तथा हंगरी ने संयुक्त रूप से 24 सितंबर–2 अक्तूबर 2013 को यूनेस्को में अमृता शेरगिल के स्मरण पर एक प्रदर्शनी आयोजित की।

अंतर्राष्ट्रीय कानून

भारत ने हिंद महासागर में पोलिमेटलिक सल्फाइड के गवेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीवेज प्राधिकरण के समक्ष के अनुमोदन के लिए एक कार्ययोजना का आवेदन प्रस्तुत किया। फरवरी 2014 में विधिक एवं तकनीकी प्राधिकरण आयोग ने इसकी जांच की तथा इस पर विचार किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत के बाद जर्मनी में भी ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें वही क्षेत्र शामिल थे जो भारत के आवेदन में है। जुलाई, 2014 में प्राधिकरण परिषद अंतिम अनुमोदनधनिर्णय के लिए भारत के अनुमोदन पर विचार करेगा।

जनवरी, 2014 में भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति के आंकलन तथा वैश्विक रिपोर्टिंग के लिए नियमित प्रक्रिया के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में चेन्नई में एक कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला की रिपोर्ट को महासागर तथा सागर विधि की कार्यसूची मद के अंतर्गत यूएनजीए के सरकारी दस्तावेज के रूप में जारी किया जाएगा।

विधि एवं संधि प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन के उपाय

वैश्विक आतंकवादरोधी रणनीति के भाग के रूप में यूएनजीए ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि आतंकवाद के संबंध में गलत अथवा असत्यापित सूचना के प्रसार से बचने के लिए तथ्यों पर आधारित उपयुक्त सूचना के आदान प्रदान में तेजी लाई जाए। यूएनजीए ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने भू–भाग में राष्ट्रिकों अथवा व्यक्तियों का अभियोजन सुनिश्चित करें जिन्होंने किसी अथवा हर प्रकार के आतंकवाद गतिविधि का वित्तपोषण किया अथवा वित्तीय सहायता की है। 8–12 अप्रैल, 2013 को न्यूयॉर्क में आतंकवाद पर तदर्थ समिति की बैठक हुई जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि आम सभा के 68वें सत्र में छठी समिति अंतर्राष्ट्रीय आतंकावद पर व्यापक अभिसमय के मसौदे पर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तथा इस विषय–वस्तु पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के प्रश्न पर विचार–विमर्श करने के लिए एक कार्यकारी समूह स्थापित करे।

महासागर तथा सागर कानून

महासागर तथा सागर कानून पर संयुक्त राष्ट्र खुली औपचारिक परामर्श दायित्व प्रक्रिया ('औपचारिक परामर्शदायी प्रक्रिया') की 14वीं बैठक 17–20 जून, 2013 को आयोजित की गई थी तथा महासभा संकल्प 67/78 के अनुसरण में इसके विचार–विमर्श समुद्री पर्यावरण पर महासागर के अमलीकरण के प्रभाव नामक शीर्षक पर केन्द्रित किए गए थे। इस बैठक में भारत सहित 76 राज्यों के प्रतिनिधियों, 13 अंतरसरकारी संगठनों और अन्य निकायों और 8 गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इस प्रभाग ने बैठक के दौरान उठाए गए कई विधिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से सलाह दी।

एशिया–अफ्रीका कानूनी परामर्शदात्री संगठन (एएएलसीओ)

एशिया–अफ्रीका कानूनी परामर्शदात्री संगठन (एएएलसीओ) का 52वां वार्षिक सत्र नई दिल्ली में 9–12 सितंबर, 2013 के दौरान आयोजित हुआ था। भारत सहित छत्तीस सदस्य राष्ट्रों ने इस सत्र में भाग लिया। इस सत्र का उद्घाटन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ई. अहमद द्वारा किया गया था, जिन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। इस सत्र में, डॉ. नीरू चंद्रा, संयुक्त सचिव (एल एण्ड टी) को एएएलसीओ के बावनवें वार्षिक सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने सभी एजेंडा मदों पर वक्तव्य दिए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सत्र की प्रथम आम बैठक में आम वक्तव्य भी दिए।

सोमालिया के तट पर जलदस्युता पर संपर्क

समूह (सीजीपीसीएस)

भारत ने सोमालिया के तट पर जलदस्युता पर संपर्क समूह के कानूनी मुद्दे पर कार्यसमूह II में भाग लेना जारी रखा। कार्यसमूह ने जलदस्युता की कार्यवाही के संदेह वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दोषसिद्ध व्यक्तियों को कैद दिए जाने सहित जलदस्युता का मुकाबला करने से संबंधित सभी कानूनी मुद्दों पर राष्ट्रों तथा संगठनों को कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखा। इस कार्यसमूह ने जलदस्युता के संदिग्ध किशोरों से कैसे व्यवहार किया जाए, सहित इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचलित कार्यों को साझा करने की योजनाओं तथा मानवाधिकार के मामलों पर विस्तृत चर्चा की। कार्य समूह ने जलदस्युता– संगठन चलाने वालों पर मुकदमें की कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क और जहाजों पर संविदा वाले सशस्त्र सुरक्षा कार्मिकों तथा नौका सुरक्षा डिटैच्मेंट के उपयोग सहित मुकदमा–पश्चात स्थानांन्तरण प्रणाली, मुकदमा चलाने की कार्रवाइयों के कार्यान्वयन पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा।

विदेश मंत्रालय का विधि तथा संधि (एल एण्ड टी) प्रभाग व्यापक जलदस्युता–विरोधी प्रारूप विधेयक तैयार करने में संलग्न था, जो विधेयक संसद में लंबित है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विशेष समिति

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संगठन की भूमिका के सुदृढ़ीकरण संबंधी विशेष समिति कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो इस प्रकार हैं: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनाय अन्य समितियों/निकायों से समन्वय, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित काम में लगी हैं, विशेषकर प्रतिबंधों से विपरित रूप से प्रभावित विकासशील राष्ट्रों को सहायता देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उपयोग के लिए एल एण्ड टी प्रभाग ने विशेष समिति के समक्ष मुद्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार किया है। महा सभा ने विशेष समिति से अनुरोध किया कि वह इस विषय पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेए ताकि यू एन चार्टर के तहत प्रतिबंधो को लागू करने से प्रभावित विकासशील राष्ट्रों को सहायता दी जा सके। साथ हीए भविष्य में इसे लागू करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य उपायों की पहचान करने में अपने कार्यात्मक तरीकों में सुधार करे। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रूख यह रहा है कि सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने के फैसले के एक भाग के रूप मेंए प्रभावित विकासशील राष्ट्रों के प्रति मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

राष्ट्रों का आह्वान किया गया है कि वे सुरक्षा परिषद के कार्यों के लिए कोष को अद्यतन करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यों के लिए कोष में बैकलॉग समाप्त करने के लिए न्यास कोष के लिए स्वैच्छिक योगदान करें। भारत ने कोष तथा इसके कार्यों को अद्यतन करने/प्रकाशित करने से संबंधित इन प्रयासों का समर्थन किया है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

भारत ने क्रमशः मध्यस्थता और सुलहए सुरक्षा हितों और ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएलद्ध और इसके काम समूहों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठकों में भाग लिया। संधि आधारित निवेशक राष्ट्र मध्यस्थता में पारदर्शिता पर यूएनसीआईटीआरएएल नियमों के संशोधित पाठ को अंतिम रूप देने और अपनाने के लिए 8–26 जुलाई 2013 के दौरान वियना अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आस्ट्रिया) में 46वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया था। ऑनलाईन विवाद निपटारे पर कार्यसमूह का 28वां सत्र 18.22 नवंबरए 2013 के दौरान वियना में हुआ था। ई–कामर्स विवादों के लिए ऑनलाईन विवाद निपटान तंत्रों के लिए कानूनी नियम तैयार करने हेतु इस कार्यसमूह को समर्थन दिया गया थाए क्योंकि विवाद सुलझाने के परंपरागत तरीकों को अपनाने से समय लगता है और यह महंगा भी हैय ई. कामर्स क्रासबॉर्डर विवादों के लिए बने बनाए शीघ्र व कम लागत वाले समझौते की आवश्यकता होती है। साथ हीए इससे विलंब व बोझों से बचा जा सकता है जो इसमें लगने वाले आर्थिक मूल्यों को कम भी कर देता है। सुरक्षा हितों संबंधी कार्य समूह चल संपत्ति पर सुरक्षा हितों (ऋण भार) के पंजीकरण के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए राष्ट्रों को दिशानिर्देश देने हेतु सिद्धांतों/नियमों को अंतिम रूप दे रही है। यह सम्पत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति पर अधिकतम संभव ऋण प्राप्त करने/उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (यूएनआईडीआरओआईटी)

भारत ने तुर्की के इस्ताम्बूल में 11–13 नवंबर, 2013 के दौरान संपन्न इंटरमेडियेटेड सुरक्षा संबंधी मूल नियमों को अंगीकार करने हेतु यूएनआईडीआरओआईटी राजनयिक सम्मेलन द्वारा स्थापित उभरते बाजारए मुद्दोंए अनुवर्ती कार्रवाई तथा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में जेनेवा सुरक्षा अभिसमय को दिए गए कार्य की जांच करनाए वित्तीय बाजार कानून में यूएनआईडीआरओआईटी द्वारा भविष्य के कार्य तथा इसको बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रस्ताओं पर विचार करना और प्रारूप संगठन उपकरण पर भी विचार करना थाए जिसका उद्देश्य उन देशों को मार्गदर्शन प्रदान करने का है जो इस अभिसमय में यह बदलावा चाहते हैं कि कैसे अभिसमय के उपबंधों को शामिल किया

जाए और इसे अपने घरेलू कानूनी प्रणाली में समाहित किया जाए।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (एचसीसीएच)

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन एक अंतर–सरकारी संगठन है जिसमें 74 सदस्य हैं और भारत मार्चए 2008 से इसका सदस्य राष्ट्र है। यह निजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी–नियमों के श्उत्तरोत्तर एकीकरणश के लिए कार्य करता है। एल एण्ड टी प्रभाग ने वुहानए चीन में एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा सम्मेलन में भाग लिया जिसका आयोजन वृहत्तर सिविल तथा वाणिज्यिक संदर्भ में फैसलों के प्रवर्तन तथा पहचान के नियमों के आमेलन पर विचारों के आदान प्रदानए और सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में विदेशी फैसलों तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्र की पहचान तथा प्रव्रतन के क्षेत्र में हेग सम्मेलन के जारी कार्यों पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए किया गया था। एल एण्ड टी प्रभाग ने एक घरेलू कानून के तहत विदेशी फैसलों को मान्यता तथा कार्यान्वयन के संबंध में भारत के कानूनी रूख व्यक्त किया।

अन्टार्कटिका

भारत प्रभाग ने 20–29 मई, 2013 के दौरान ब्रुसेल्सए बेल्जियम में आयोजित अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री समिति (एटीसीएम) की XXXVI वीं बैठक में भाग लियाए जिसे विभिन्न कार्य समूहों के तहत प्रारंभ किया गया थाः क) अंटार्कटिक का सीइपी (पर्यावरण संरक्षा पर समिति, ख) पर्यटन पर कार्य समूह, ग) कानूनी तथा सांस्थानिक मामलों पर कार्यसमूह, घ) प्रचालनात्मक मामलों पर कार्य समूह।

विभिन्न समूहों की बातचीत के परिणामस्वरूप विभिन्न संकल्पों को अंगीकार किया गया थाए कानूनी तथा सांस्थानिक समूहए जिसके बारे में चर्चा के बाद एटीसीएम की पूर्ण बैठक में अंगीकार करके किया गया। कार्य समूहों द्वारा अंगीकार किए गए सभी प्रारूप संकल्पों को विधिक तथा सांस्थानिक कार्य समूह को भेजा गया हैए तीन प्रमुख मुद्देए जिनपर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थीए वे थेरू कद्ध क्षेत्राधिकार मुद्दाय खद्ध दायित्व अनुलग्नय और गद्ध मेड्रिड प्रोतोकॉल के लिए समर्थन मजबूत करना।

जल संसाधन

भारत ने सिंधु जल संधि के तहत स्थापित स्थायी सिंधु आयोग की बैठकों में हिस्सा लिया। एल एण्ड टी प्रभाग सिंधु जल संधि के तहत स्थापित किए गए मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष भारत की स्थिति प्रस्तुत करने और समन्वय के कार्यों में सक्रियता से कार्यरत था। भारत ने क्रमशः 24–26 मार्च, 2013 को लाहौर, पाकिस्तान में और 22–24 सितंबर, 2013 के दौरान दिल्ली में आयोजित सिंधु जल आयोग के 108वीं और 109वीं बैठक में भाग लिया। इन बैठकों में, एचईपीज (जल विद्युत परियोजनाओं) जैसे पाकाल डल, रातले, लोवर कालनाई और मियार, आदि पर चर्चा की गई। भारत ने जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों तथा सीडब्ल्यूसी से भाग लेने वाले विशेषज्ञों के साथ 11–12 अप्रैल, 2013 को जम्मू व कश्मीर में वुलर झील संरक्षण परियोजना के निरीक्षण के लिए स्थल दौरे में भी भाग लिया।

समुद्री सीमांकन पर बांग्लादेश के साथ विवाद

बांग्लादेश ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुलग्नक टप्प के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 287 के तहत बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ समुद्री सीमा के सीमांकन पर मध्यस्थता की शुरूआत की है। फरवरीए 2010 मेंए पांच सदस्यों वाली एक मध्यस्थता पैनल का गठन यूएनसीएलओएस के अनुलग्नक टप्प के अनुच्छेद 3 के अनुरूप किया गया था। एल एण्ड टी प्रभाग बांग्लादेश मेमोरियल के प्रति भारत के जवाब में भारत की भागीदारी के कार्य हेतु कानूनी सलाहकारों तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक करने में सक्रियता से लगा हुआ था। यह स्मरण किया जा सकता है कि बांग्लादेश ने 31 जनवरीए 2013 को भारत के काउन्टर मेमोरियल को एक उत्तर सौंपा। भारत ने अपना उत्तर 31 जुलाईए 2013 को प्रस्तुत किया।

न्यायाधिकरण नेए बांग्लादेश के अनुरोध परए भारत और बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित बेस प्वाइंट की समीक्षा के लिए मुहाना क्षेत्र और पक्षकारों के संगत तटों पर साइट का दौरा किया। न्यायाधिकरण के लिए स्थल दौरा 23.25 अक्तूबरए 2013 के दौरान आयोजित किया गया। इसके पश्चातए 9–18 दिसंबरए 2013 के दौरान द हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में इस मामले के मौखिक सुनवाई की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई श्री जी.ई वाहनवतीए भारत के अटॉर्नी जनरल और मौखिक सुनवाई डॉ. नीरू चड्ढाए संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकारए विदेश मंत्रालयए जो भारत की एजेंट भी हैंए द्वारा की गई। बांग्लादेश पक्ष सेए श्री ए.एच. महमूद अलीए सांसदए बांग्लादेश के विदेश मंत्री की अगुवाई वाली एक प्रतिनिधिमंडल तथा डॉ. दीपु मानीए पूर्व विदेश मंत्री और बांग्लादेश के एजेंट ने मौखिक सुनवाई प्रारंभ की। पक्षकारों ने लिखित बहस की प्रस्तुति के दौरान अधिकतमवादी तरीका अपनायाए जिसे मौखिक सुनवाई के दौरान दोहराया गया। पक्षकार इस तथ्य के प्रति जागरूक थे कि न्यायाधिकरण का फैसला उनके दावों से भिन्न हो सकता है। यूएनसीएलओएस के तहतए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होता है और पक्षकारों पर बाध्यकारी भी होता है। न्यायाधिकरण का फैसला वर्ष 2014 के मध्य में आने की प्रत्याशा है।

प्रत्यर्पण तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता

एल एण्ड टी प्रभाग ने प्रत्यर्पण संधियों, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर करार, सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक सहायता और सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यर्पण पर करार को अंतिम रूप देने के लिए बाहरी देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लिया। सफल वार्ताओं के परिणामस्वरूपए बांग्लादेश और थाईलैण्डके साथ प्रत्यर्पण संधि पर पाठ को अंतिम रूप दिया गया। बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि 23 अक्तूबरए 2013 से लागू हो चुकी है। कुवैत तथा वियतनाम के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी संधि के पाठ पर हस्ताक्षर किए गए और स्पेन के साथ अद्याक्षरित किए गए और विदेशों में अपराध की सजा काटने पर अंतर–अमरीकी अभिसमय के प्रस्ताव की इस प्रभाग द्वारा जांच की गई है और इस पर विचार किया जा रहा है। इस प्रभाग ने क्यूबाए इथयोपिया और द फिलीपिन्स के साथ पूर्ण संधि को अंतिम रूप देने के लिए इन देशों के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि के प्रति प्रारूप की जांच की। एल एण्ड टी प्रभाग ने घरेलू के साथ साथ विदेशी क्षेत्राधिकारों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुरोधों तथा प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच की तथा उन पर कानूनी सलाह लिया।

पुनरीक्षण

एल एण्ड टी प्रभाग ने रक्षा सहयोग संबंधी अनेक करारों और वाह्य अंतरिक्ष मामलोंए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनए अंतर देशीय संगठित अपराध तथा औषध की अवैध आवाजाही/स्वापकों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के करारों की भी की जांच की हैय और गोपनीयता पर करारोंय हाइड्रोलॉजिकल आंकड़े साझा करनेए गैस तथा ऊर्जाए सांस्कृतिक सहयोगए श्रव्य–दृश्यए सड़क परिवहनए रेलए व्यापारए परियोजनाओंए डीटीएएए शिक्षाए पर्यटनए जलवायु परिवर्तनए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षाए लाभकारी रोजगारए हाइड्रोग्राफी और सीमाशुल्क सहयोग आदि पर द्विपक्षीय करारों की जांच की है।

भारत ने इस वर्ष के दौरान बाहरी देशों के साथ अनेक परस्पर/द्विपक्षीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर/अनुसमर्थन किए हैं। **परिशिष्ट-I** पर एक व्यापक सूची दी गई है। वर्ष 2013 के दौरान जारी किए गए पूरी शक्ति के साधन/पाठ **परिशिष्ट-II** पर और वर्ष 2013 के दौरान प्रोसेस किए गए अनुसमर्थन के साधनों/पाठों की सूची **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

10

भारत ने वैश्विक तथा भेदभावरहित परमाणु अप्रसार के साथ–साथ सामान्य तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में विभिन्न बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण मंचों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में परमाणु निशस्त्रीकरण के विशेष प्राथमिकता के साथ निशस्त्रीकरण तथा अप्रसार की अपनी नीतियों का अनुपालन करना जारी रखा। भारत ने यूएन प्रथम समितिए यूएन निशस्त्रीकरण आयोग ;यूएनडीसीद्धए निशस्त्रीकरण सम्मेलन ;सीडीद्धए जैविक तथा जहरीले हथियारों पर अभिसमय ;बीटीडब्ल्यूसीद्धए रासायनिक हथियार अभिसमय ;सीडब्ल्यूसीद्धए कतिपय पारंपरिक हथियारों पर अभिसमय ;सीसीडब्ल्यूद्ध और छोटे हथियारों तथा हल्के हथियारों पर यूए कार्रवाई कार्यक्रम ;यूएनपीओए ऑन एसएएलडब्ल्यूद्ध की बैठकों में सक्रियता से भाग लिया। भारत ने निशस्त्रीकरण अभिसमय की अध्यक्षता हेतु 2013 के सत्र में छह राष्ट्राध्यक्षों में से एक स्थान पाया। निशस्त्रीकरण सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने सम्मेलन में ठोस कार्य प्रारंभ करने के लिए हर प्रयास किए और सम्मेलन के सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किए। भारत ने हथियार व्यापर संधि राजनयिक सम्मेलन ;एटीटीद्धए आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों ;एआरएफद्ध और एशिया में विश्वासोत्पादक उपायों तथा बातचीत सम्मेलन ;सीआईसीए) में भी हिस्सा लिया। भारत ने निशस्त्रीकरण तथा अप्रसार के मुद्दों पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श किए और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के साथ अपनी वार्ता को आगे बढ़ाया। विदेश मंत्रालय ने भारत के निर्यात नियंत्रण कानून तथा व्यापक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) अधिनियमए 2005 के कार्यान्वयन की अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। निशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसायटी संगठनों के साथ नियमित संपर्क जारी रखे गए।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा

भारत ने 2013 यूएनजीए में वैश्विकए भेदभावरहित और सत्यसाधनीय परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद दिनांक 26 सितंबरए 2013 को न्यूयार्क में आयोजित परमाणु निशस्त्रीकरण पर महा सभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने व्यापक विनाश के सभी हथियारों के वैश्विक उन्मूलन के लिए भारत के लगातार समर्थन की पुनःपुष्टि की और वर्ष 1988 में महा सभा में परमाणु हथियार मुक्त तथा अहिंसात्मक विश्व व्यवस्था के लिए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना को याद किया तथा भारत के इस विश्वास को व्यक्त किया कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को एक वैश्विक तथा भेदभाव रहित सहमत तरीके से पारस्परिक फ्रेमवर्क तथा वैश्विक प्रतिबद्धता द्वारा कदम दर कदम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नाम) के सदस्य के रूप मेंए भारत ने 2013 पहली समिति के श्परमाणु निशस्त्रीकरण पर महा सभा के 2013 की उच्च स्तरीय बैठक पर अनुवर्ती कार्रवाईश पर समूह के संकल्प का समर्थन किया। अन्य बातों के साथ साथ इस संकल्प में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया तथा परमाणु हथियार पर सम्मेलन पर बातचीत के तत्काल प्रारंभ किए जाने की मांग की और निर्णय किया कि 2018 से पहले ही यूएन द्वारा परमाणु निशस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।

2013 प्रथम समिति में परमाणु हथियार पर आम बहस और विषयवादी वादविवाद के दौरानए परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया और इस विषय पर भारत द्वारा प्रस्तावित अनेक उपायों को दोहराया। परमाणु निशस्त्रीकरण से जुड़े प्राथमिकताओं के बावजूदए भारत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरा करने वाले परमाणु हथियारों तथा अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के लिए फिसाइल सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने वाले एक बहुपक्षीय, भेदभावरहित और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन संधि के लिए अपने समर्थन को भी दोहराया।

भारत का संकल्प, जिसका शीर्षक है, श्व्यापक विनाश के हथियार प्राप्त करने में आतंकवादियों को रोकने के उपायश्ए हैए जिसे पहली बार वर्ष 2002 में पेश किया गया थाए को पुनः सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। इस संकल्प को वर्ष 2013 में 77 देशों द्वारा मिलकर प्रायोजित किया गयाए जो वर्ष 2002 से दस अधिक था।

"परमाणु हथियार के प्रयोग के निषेध पर अभिसमय" पर भारत का संकल्प किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार के प्रयोग की धमकी अथवा उपयोग पर प्रतिबंध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर बातचीत प्रारंभ करने के लिए निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन बुलाने को दोहराया। इस संकल्प को प्रथम समिति में बहुतायत मतों से अपनाया गया था। भारत का तीसरा संकल्प श्परमाणु खतरे को कम करनाश ने डी–एलर्टिंग तथा डी–टार्गेटिंग के माध्यम सहित परमाणु हथियार के गलती से प्रयोग पर आंतरिक खतरे को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने और परमाणु सिद्धातों पर समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस संकल्प को भी बहुतायत मतों से अंगीकार किया गया था। प्रथम समिति ने 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप निर्णय को भी अंगीकार किया।

भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर ओपन–एन्डेड कार्य समूह की बैठकों में भाग लिया जो 2012 महा सभा के संगत संकल्पों के अनुसरण में वर्ष 2013 में जेनेवा में बुलाई गई थी। वर्ष 1988 की कार्य योजनाके लिए सम्मेलन के साथा साथ परमाणु निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सहमत बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की आवश्यकता सहित परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत के विचार को ओपन एण्डेड कार्य समूह की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया।

यूएन निशस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

यूएन निशस्त्रीकरण आयोग ने वर्ष 2013 के लिए अपने व्यापक सत्र 1–9 अप्रैल, 2013 के दौरान आयोजित किया। अपने वर्ष 2012–14 चक्र के लिए आयोग द्वारा अंगीकार किए गए एजेंडा के अनुरूप, इस आयोग ने पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में परमाणु निशस्त्रीकरण तथा सीबीएमएससे संबंधित इसके दो मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने वर्ष 2014 में संस्तुतियों पर सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग के विचार विमर्शों में सक्रियता से भाग लिया।

निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सीडी)

भारत ने 18 फरवरी से 15 मार्च, 2013 के लिए अध्यक्षता की जो वर्ष 2013 के सत्र के लिए निशस्त्रीकरण सम्मेलन के छह अध्यक्षों में से एक है। भारत ने इस सम्मेलन के दो प्रमुख मुद्दों नामतः परमाणु निशस्त्रीकरण तथा फिसिल मटिरियल कटऑफ संधि (एफएमसीटी) परए भारत ने वर्ष के लिए सम्मेलन के छह अध्यक्षों के बीच परामर्शों के अनौपचारिक तंत्रों की बैठकों में भाग लिया। वर्ष के दौरान सम्मेलन में हुई विभिन्न चर्चाओं में, भारत ने कार्य के लिए कार्यक्रम अपनाकर सीडी में ठोस कार्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर देना जारी रखा। भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण के चार प्रमुख मुद्दोंए फिसाईल मटेरियल कटऑफ संधि (एफएमसीटी)ए वाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना (पीएआरओएस) और नकारात्मक सुरक्षा आश्वासन (एनएसए) सहित सीडी के एजेंडे के सभी मुद्दोंपर अपने दृष्टिकोण भी साझा किए। तत्कालीन विदेश सचिवए श्री रंजन मथाई ने 18 जूनए 2013 को सम्मेलन में भाषण दिया और विश्व समुदाय के एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण बातचीत मंच के रूप में सम्मेलन के लिए भारत द्वारा दिए गए महत्व की पुनःपुष्टि की। भारत ने एक भेदभाव–रहित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से पुष्टिकर फिसाइल मटिरियल कट ऑफ संधि (एफएमसीटी) के सम्मेलन में वार्ताओं के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरा करता है। भारत ने रेखांकित किया कि एफएमसीटी वार्ताओं के लिए सहमत समर्थन है और यह कि यह उस समर्थन को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं है। भारत ने अपना विश्वास भी व्यक्त किया कि इस सम्मेलन में सदस्य हैं, विश्वसनीयता है और इसके समर्थन देने की प्रक्रिया के नियम भी हैं। 2014 के सत्र के दौरानए भारत ने कार्य के कार्यक्रमए जो कार्यान्वयन में आनेवाले समय में ठोस और प्रगतिशील में सुदृढ़ हैए को पेश करने में एक अनौपचारिक कार्य समूह स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन किया।

परमाणु हथियारों पर मानवीय प्रभाव पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (13.14 फरवरी, 2014)

मैक्सिको में भारत के मिशन ने 13–14 फरवरी, 2014 के दौरान नायारित में परमाणु हथियार के मानवीय प्रभाव पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ओस्लो में पिछले सम्मेलन (मार्च, 2013) की ही तरह, पी–5 देशों, इजराइल तथा डीपीआरके ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में ओस्लो में हुई चर्चाओं, परमाणु हथियारों के विस्फोट के मानवीय प्रभाव पर आधारभूत वैश्विक चिन्ता, को आगे बढ़ाने की मांग की गई। आस्ट्रिया नवंबर/दिसंबर, 2014 में आगामी सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है।

कतिपय परंपरागत हथियार अभिसमय (सीसीसीडब्ल्यू)

भारत ने सीसीसीडब्ल्यू को महत्व देना जारी रखा जो कतिपय परंपरागत हथियारों के प्रयोग से उत्पन्न मानवीय चिन्ताओं को दूर करने और ऐसे हथियारों की सैन्य आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से काम करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के नियमों तथा सिद्धांतों को मजबूत करने में सीसीसीडब्ल्यू की उपलब्धियों में विश्वास करना जारी रखा। भारत ने सीसीसीडब्ल्यू की वार्षिक बैठकों में तथा इसके संशोधित प्रोतोकॉल ।। (एपी ।।) और प्रोतोकॉल ट में सक्रिय तथा रचनात्मक रूप से भाग लेना जारी रखा।

जेनेवा में 14–15 नवंबरए 2013 के दौरान हुई सीसीसीडब्ल्यू के पक्षकार राष्ट्रों की वार्षिक बैठक मेंए भारत ने सभी प्रमुख

उपयोगकर्ताओं और कतिपय परंपरागत हथियारों को साथ लाने में यूएन फ्रेमवर्क के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में सीसीसडब्ल्यू को अपना समर्थन रेखांकित किया। भारत ने सीसीसीडब्ल्यू में जहरीले स्वचलित हथियारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के की जांच और 2014 में इस मामले पर विशेषज्ञों की अनौपचारिक बैठक के लिए बातचीत समर्थन पर चर्चा का समर्थन किया। 13 नवंबरए 2013 को हुए संशोधित प्रोतोकॉल ।। की 15 वीं वार्षिक बैठकम मेंए भारत ने एपी ।। में निहित तरीकों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और एंटी–पर्सनल लैण्डमाइन्स के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की भारत ने एपी ।। के तहत इंप्रोवाइज्ड विस्फोटर उपकरण (आईईडीएस) पर लगातार कार्य करने का भी समर्थन किया। 11.12 नवंबरए 2013 के दौरान आयोजित प्रोतोकॉल ट के 7वें वार्षिक सम्मेलन मेंए भारत ने जेनेरिक सुरक्षात्मक उपायोंए युद्ध के बचे विस्फोटकों की रिकार्डिंग तथा संचारए सहयोग और सहायता और प्रभावितों की सहायता सहित सभी मामलों पर बातचीत में योगदान दिया। भारत ने अप्रैलए 2013 में संपन्न प्रोतोकॉल ट तथा एपी दृष्प दोनों की विशेषज्ञों की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। श्आईईडीएसपर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत का योगदानश पर एक प्रस्तुतीकरण विशेषज्ञों की एपी.ष्प की बैठक में प्रस्तुत की गई। भारत ने 2–6 दिसंबरए 2013 के दौरान जेनेवा में आयोजित एंटी–पर्सनल लैण्डमाइन अभिसमय (ओटावा अभिसमय) के राज्य पक्षकारों की 13वीं बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थिति दर्ज की।

हथियार व्यापार संधि (एटीटी)

सहमति बनाने में मार्च 2013 में राजनयिक सम्मेलन की असफलता के बाद 2 अप्रैल, 2013 को एक यूएनजीए संकल्प को मतदान द्वारा हथियार व्यापार संधि को अंगीकार किया गया था। भारत ने हालांकि इस संधि पर बातचीत करने के लिए राजनयिक सम्मेलनों में सक्रियता से भाग लिया लेकिन एटीटी संकल्पपर तटस्थ रहा क्योंकि संधि का पाठ आतंकवाद तथा गैर राष्ट्र कार्यकर्ताओं में कमजोर था, जिसमें संधि के विशिष्ट प्रतिषेधों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। भारत ने यह भी इंगित किया कि बिना सहमति के राष्ट्र पक्षकारों के विरूद्ध नियंत्रण से बाहर के एकपक्षीय उपायों के लिए निर्यातक देशों के हाथों की कठपुतली नहीं रह सकती। भारत इस समय रक्षा, सुरक्षा और विदेशी नीतिगत हितों के उद्देश्यों के लिए एटीटी के मूल्यांकन पूर्ण तथा सावधानीपूर्वक कर रहा है।

जैविक जहरीले हथियारों पर अभिसमय (बीटीडब्ल्यूसी)

भारत ने 12–16 अगस्त, 2013 के दौरान बीटीडब्ल्यूसी के विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक और 913 दिसंबर, 2013 के दौरान आयोजित राष्ट्र पक्षकारों की बैठक में ठोस योगदान किया। 2013 की विशेषज्ञों की बैठकों मेंए भारत ने व्यापक विनाश के हथियारों के सम्पूर्ण प्रकारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भेदभावरहितए प्रथम बहुपक्षीय संधि के रूप में बीटीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वोच्च महत्व की बात दोहराई। भारत ने अभिसमय के प्रभावकारिता में सुधार करने, इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, और इसके सार्वभौमिकरण के प्रयासों को समर्थन व्यक्त की। बीटीडब्ल्यूसी की बैठक में तीन मदों (एस एण्ड टी के सहयोग और सहायता, समीक्षा तथा विकास तथा राष्ट्रीय कार्यान्वयन) पर व्यापक चर्चा की गई, जैसा कि 7वीं समीक्षा सम्मेलन द्वारा निर्णय लिया गया था।

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

भारत ने अप्रैल 2013 में (राष्ट्र पक्षकारों (सीएसपी) के सम्मेलन के विशेष सत्र) ओपीसीडब्टल्यू के तीसरे समीक्षा सम्मेलन, आम समिति की बैठकों और सम्पूर्णता से समिति में महत्वपूर्ण वार्ताओं में, कार्यकारी परिषद के सत्रों (16.19 जुलाई, 2013, 8.11 अक्तूबर, 2013 और 4.7 मार्च, 2014), और राज्य पक्षकारों के सम्मेलनों (2–5 दिसंबरए 2013) मेंए रासायनिक हथियारों के विनाशए उद्योग निरीक्षणए राष्ट्रीय कार्यान्वयनए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगए तथा सहायता के मुद्दों पर पहले के वर्षों की ही तरहए हेग में रासायनिक हथियारों (ओपीसीडब्ल्यू) के प्रतिषेध के लिए संगठन में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। भारत समीक्षा सम्मेलन पर ओपन एण्ड कार्य समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न रहा जबकि इसने प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों पर सलाहकार बोर्ड (एबीएएफ), और वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड (एसएबी) सहित संगठन के विभिन्न निकायों के अलावा, सीडब्ल्यूसीके संदर्भ में आसियान समूह तथा नाम समूह जैसे समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओपीसीडब्ल्यू के राष्ट्र पक्षकारों के सम्मेलन के 18 वें सत्र में, भारत ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्य में ओपीसीडब्ल्यू द्वारा स्थापित ट्रस्ट निधि में एक मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय अंशदान का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा, विनाश सत्यापन कार्यकलाप के लिए ओपीसीडब्ल्यू को भारतीय निर्यातों की सेवाएं का प्रस्ताव के साथ साथ सीरियाई रासायनिक हथियारों के विनाश के लिए यूएन–ओपीसीडब्ल्यू संयुक्त मिशन में व्यक्तिगत योगदान के लिए प्रशिक्षण स्लॉटों का प्रस्ताव था।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरण्केण सिन्हा ने 27 से 29 जूनए 2013 के दौरान संत पिटर्सबर्ग में रूसी संघ की सरकार द्वारा आयोजित '21वीं सदी में परमाणु ऊर्जाश विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन और 16–20 सितंबर, 2013 के दौरान वियना में आयोजित आईएईए की 57वें आम सम्मेलन के सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस प्रतिनिधिमंडल की माहनिदेशक (डीजी), आईएईएए श्री युकीया अमानो और

महानिदेशकए ओईसीडीए परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ बैठकें हुईं और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं। अध्यक्षए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ;एईआरबीद्धए श्री एस.एस. बजाज ने यूके नियामक और यूएस एनएसआरसी के साथ अलग से बैठक हुई और उन्होंने वरिष्ठ परमाणु नियामकों के साथ सम्मेलन में भाग भी लिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री श्री वी. नारायण सामी ने परमाणु सुरक्षाः 1–5 जुलाईए 2013 के दौरान वियना में आयोजित वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने पर प्रथम आईएईए मंत्रीस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। मंत्री ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुसमर्थन/प्रतिबद्धता, आईएईए की परमाणु सुरक्षा निधि में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय योगदान और भारत द्वारा स्थापित किए जा रहे परमाणु ऊर्जा भागीदारी के वैश्विक केन्द्र के स्कूल के माध्यम से प्रशिक्षण अवसरों के प्रावधानों सहित इस संबंध में भारत द्वारा विभिन्न कार्यवाइयों और चलाए गए क्रियाकलापों पर उपस्थित लोगों को बताया।

श्री एस.एस. बजाज, अध्यक्ष, एईआरबी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने परमाणु सुरक्षा बैठकपर आईएईए अभिसमय में भाग लेने के लिए 24 मार्च से 5 अप्रैल, 2014 के दौरान वियना का दौरा किया।

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 26.28 जून, 2013 के दौरान वियना में, 2.4 अक्टूबर, 2013 के दौरान ओटावा में और 13.15 जनवरी, 2014 के दौरान पटाया में एनएसएस शेरपा बैठकों में भाग लिया।

तीसरा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन द हेग में विश्व मंच पर 24–25 मार्चए 2014 के दौरान संपन्न हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में एक 7–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ;विदेश सचिव सहितद्ध द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्वभर में परमाणु आतंक को रोकना था। इस सम्मेलन में 53 देशों और चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने शिखर सम्मेलन में एक पूर्ण वक्तव्य दिया और शिखर सम्मेलन के दौरान 25 मार्च को रानी मैक्सिमा से मुलाकात की और हालैण्ड के विदेश मंत्री तिमरमान से मिले।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 2 जुलाईए 2013 को ब्रुनई में 20वें एआरएफ मंत्रीस्तरीय बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कीए जो 1 जुलाईए 2013 की ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक के ठीक पहले हुई थी।

भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकए तीन अंतर–सत्रीय समूह की बैठकेंए आपदा राहत पर पांच अंतर– सत्रीय बैठकेंए समुद्री सुरक्षाए आतंकवाद का मुकाबला करने और अंतरराष्ट्रीय अपराधोंए परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरणए विश्वासोत्पादक उपायों और निवारक कूटनीति और विभिन्न सहयोग गतिविधियों और सेमिनारों में भाग लिया। राज्यमंत्री ;रक्षाद्ध ने 28.30 अगस्तए 2013 के दौरान ब्रुनईए दारेस्सलाम में द्वितीय आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस ;एडीएमएम प्लसद्ध में हिस्सा लिया। भारत ने वरिष्ठ सरकारी बैठकों और विशेषज्ञ कार्य समूह के साथ ही एडीएसओएम प्लसए मानवीय सहायता और और आपदा राहत (एचएडीआरद्ध पर विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठकोंए समुद्री सुरक्षाए सैन्य चिकित्साए आतंकवाद से मुकाबला और एडीएमएम की शांति आपरेशन प्लस 8 प्रक्रिया पर और आसियान क्षेत्रीय मंच रक्षा प्रमुख विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / संस्थानों की बैठक और आसियान क्षेत्रीय मंच रक्षा अधिकारियों की वार्ता (डीओडी) में हिस्सा लिया।

एशिया में विश्वासोत्पादक उपायों तथा बातचीत पर सम्मेलन (सीआईसीए)

एशिया में बातचीत तथा विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए) एशियाई क्षेत्र में शांतिए सुरक्षा और सम्पन्नता को बढ़ावा देने के लिए वार्ता तथा सहयोग हेतु एक 24–सदस्यीय क्षेत्रीय मंच है। वर्ष के दौरानए भारत ने सीआईसीए फ्रेमवर्क के तहत विशेष कार्य समूहों (एसडब्ल्यूजी) और वरिष्ठ पदाधिकारी समूह (एसओसी) की बैठकों और सहयोगात्मक कार्यकलापों में भाग लिया। भारत ने एशियाई वास्तविकताओं में समाहित कदम–दर–कदम तरीके के विकास तथा सहमति पर आधारित सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों में विश्वासोत्पादक उपाय (सीबीएमएस) को और पुख्ता करने तथा लागू करने के लिए इसके सहयोग को रेखांकित किया है।

निर्यात नियंत्रण

वर्ष 2013 में, भारत ने सभी चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं नामतः परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीआरसी), ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) और वासेनार व्यवस्था (वाशिंगटन) के साथ वार्ता इस विचार से जारी रखा कि इन व्यवस्थाओं की पूर्ण सदस्यता के उद्देश्य की प्राप्ति में मिलकर प्रगति कर सके।

28 जून, 2013 को वियना में भारत तथा परमाणुआपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के बीच एक आउटरीच बैठक हुई। विदेश सचिव श्री रंजन मथाई की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक एनएसजी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई जिसकी अगुवाई इसके

वर्तमान अध्यक्ष चेक गणराज्य के राजदूत वेरोनिका स्मीगोलोवा कर रहे थे। यह बैठक भारत और एनएसजी के बीच नियमित आउटरीच बैठकों की एक कड़ी के रूप में हुई। एनएसजी ने प्राग प्लेनरी के बाद इसके कार्यकलापों के संबंध में अद्यतन स्थिति का ब्यौरा दिया। भारत ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ एनएसजी के साथ संपर्क बढ़ाने में अपनी सतत रूचि दिखलाई। आउटरीच बैठकें संयुक्त सचिव (डीएण्डआईएसए), विदेश मंत्रालय के स्तर पर दिल्ली में हेग कोड ऑफ कंडक्ट (एचसीओसी) के साथ साथ एजीए एमटीसीआर तथा डब्ल्यूए के साथ हुईं।

अन्य मुद्दे

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह और जर्मन विदेश कार्यालय की स्टेट सेक्रेटरी हेराल्ड ब्राउन ने भारतीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और जर्मन संघ के चांसलर ऑगेला मार्केल द्वारा अप्रैल, 2013 में बर्लिन में द्वितीय भारत–जर्मनी सरकारी परामर्श, जहां दोनों सरकारें उच्च प्रौद्योगिकी में व्यापार तथा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुईं थीं, में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहरा करने के लिए बर्लिन में 9 सितंबर, 2013 को प्रथम भारत–जर्मनी उच्च प्रौद्योगिकी भागीदारी समूह की अध्यक्षता की।

विदेश सचिवए श्रीमती सुजाता सिंह और प्रभारी अमरीकी हथियार नियंत्रण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अंडर सेक्रेटरी सुश्री रोज़ गोतेमोयेलर की अगुवाई में भारत.अमरीकी रणनीतिक सुरक्षा बातचीत 11 दिसंबरए 2013 को वाशिंगटन डीसी में हुई। इस बातचीत में पारस्परिक हितों के वैश्विक तथा क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ निशस्त्रीकरण तथा अप्रसार के क्षेत्र में बहुपक्षीय विकासों पर चर्चा की गई।

वर्ष के दौरान, भारत ने फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस तथा अमरीका सहित विभिन्न देशों से निशस्त्रीकरण, अप्रसार मुद्दों और निर्यात नियंत्रण मुद्दों पर कार्यात्मक समूह परामर्श किया।

11 बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 27 मार्च, 2013 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। डरबन शिखर सम्मेलन का व्यापक विषय था. शब्रिक्स और अफ्रीकारू विकास, एकीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए भागीदारी'। इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल थे – बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्थारू समग्र विकास और वृद्धि की ओरय वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधारय वैश्विक शांतिए सुरक्षा और स्थिरताय अवसंरचना के लिए वित्तपोषण और सतत विकासरू ब्रिक्स.नीत नया विकास बैंकए विकास और सतत वृद्धि के लिए भागीदारीय औद्योगिक क्षमता की उन्नति तथा विस्तारय और समग्र और तीव्र विकास के लिए अवसंरचना। शिखर सम्मेलन के बादए प्रधान मंत्री ने अफ्रीका की क्षमता की उपलब्धतारू अवसंरचना पर ब्रिक्स और अफ्रीका सहयोग के विषय के तहत आयोजित ब्रिक्स नेता. अफ्रीका वार्ता मंच में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर ई–थेकवीनी घोषणा जारी की गई। डरबन शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम में यह दावा किया गया कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स.नीत नया विकास बैंक स्थापित करने पर सहमति जताई है। अन्य परिणामों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की प्रारंभिक क्षमता से ब्रिक्स देशों के बीच आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के सृजन के जरिए वित्तीय सुरक्षा नेट बनानाए ब्रिक्स व्यापार परिषद स्थापित करना और एक ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद की स्थापना करना शामिल था। दो करारों – अफ्रीका अंतर. बैंक सहयोग तंत्र अर्थात ब्रिक्स परस्पर अवसंरचना सह वित्तपोषण औरए सतत विकास के लिए ब्रिक्स परस्पर सहयोग और सह. वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किए गएय भारत की ओर से इन करारों पर एक्जिम बैंक ने हस्ताक्षर किए।

प्रधान मंत्री ने सितंबर 2013 में सेंट पिटर्सबर्गए रूस में आठवें ळ. 20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भी भाग लिया। इन नेताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था की गतिविधियोंए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधारए दोहा विकास दौरए ब्रिक्स. नीत नया विकास बैंक और ब्रिक्स देशों में आपात रिजर्व व्यवस्था पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के बाद एक मीडिया नोट जारी किया गया।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने न्यूयार्क में यूएन महा सभा के दौरान 26 सितंबर 2013 को ब्राजील द्वारा आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। मंत्रियों ने पांचवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा प्राधिकृत ब्रिक्स वार्षिक कार्य योजना (ई थेक्विनी कार्य योजना) के कार्यान्वयन में प्रगति प्रगति का जायजा लियाए 2014 में ब्राजील में आयोजित होने वाले छठे शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और विशेषकर सीरिया तथा मध्यपूर्व की स्थिति के साथ साथ साइबर सुरक्षा सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद एक मीडिया नोट जारी किया गया।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले 25 सितंबर 2013 को ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक हुई। शेरपाओं ने अन्य बातों के साथ–साथ यूनेस्को के साथ ब्रिक्स आउटरीच और लैटिन अमरीकी समुदाय और कैरिबियाई राष्ट्र (सीईएलएसी), ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए विचारार्थ विषय, आदि पर चर्चा की। संयुक्त सचिव ;एमईआरद्धए विदेश मंत्रालय ने बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स शेरपागण जुलाई 2013 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में भी मिले। ब्रिक्स शेरपा, श्री पीनाक रंजन चक्रवर्ती, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय और श्री दिनेश भाटियाए संयुक्त सचिव (एमईआर) ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

विदेश मंत्री ने 24 मार्च 2014 को परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान हेग में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों के अपने–अपने क्षेत्रों में गतिविधियों पर चर्चा करना था। इस बैठक के बादए दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष वक्तव्य जारी किया।

इस अवधि के दौरान हुए अन्य उच्च स्तरीय ब्रिक्स बैठकों में शामिल हैं–कृषि मंत्रियों की बैठक (29 अक्तूबर 2013; प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका), वित्त मंत्रियों की बैठक (10 अक्तूबर 2013; वाशिंगटन डी. सी.), स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक (7 नवंबर, 2013; पश्चिमी समरसेट, दक्षिण अफ्रीका), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक (6 दिसंबर

2013; केप टाउन, दक्षिण अफ्रीकाद्ध और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक (9–12 फरवरी, 2014; प्रिटोरिया)।

भारत के प्रतियोगिता आयोग ने 20–22 नवंबर 2013 के दौरान नई दिल्ली में तीसरा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सहित 37 देशों से लगभग एक सौ प्रतियोगियों एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए।

मार्च, 2012 में ब्रिक्स दिल्ली घोषणा में किए गए घोषणा में दिल्ली कार्य योजना द्वारा दिए गए समर्थन के अनुरूप, शहरी विकास मंत्रालय ने 1 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में प्रथम ब्रिक्स शहरी अवसंरचना मंच की मेजबानी की।

इस अवधि के दौरान अन्य ब्रिक्स बैठकों में शामिल हैं – ब्रिक्स देशों के औषध नियंत्रण एजेंसियों की बैठक (30 जून, 2013; मास्को, रूसद्धए आर्थिकए व्यापार और निवेश मुद्दों पर संपर्क समूह की बैठक (22 नवंबर, 2013; प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका), ब्रिक्स सहकारी सोसाइटियों की बैठक ;26.28 अक्तूबर 2013य केप टाउनए दक्षिण अफ्रीका), दूसरा ब्रिक्स शहरीकरण मंच की बैठक (26–29 नवंबर 2013; डरबन, दक्षिण अफ्रीकाद्ध और तीसरा ब्रिक्स मित्रता शहर और स्थानीय सरकार सहयोग मंच की बैठक ;26.29 नवंबर 2013य डरबनए दक्षिण अफ्रीकाद्धय साइबर सुरक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूह की प्रथम बैठक ; 19.21 फरवरी 2014 को रूडरबनद्धय और बैठक ब्रिक्स सांख्यिकी प्राधिकारियों की बैठक ;10.12 फरवरी 2014रू रियो डी जेनेरियोद्ध।

पंद्रह का समूह (जी–15)

यूएनजीए के 68वें सत्र के दौरानए 27 सितंबर 2013 को न्यूयार्क में जी–15 के विदेश मंत्रियों की 36वीं बैठक की मेजबानी श्रीलंका ने की। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका के विदेश मंत्री द्वारा की गई। इस बैठक का प्रमुख परिणाम केन्या द्वारा श्रीलंका से जी.15 के 15वें शिखर सम्मेलन के बाद जी–15 की अध्यक्षता प्राप्त करना रहाय श्री दिनेश भाटियाए संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने इस बैठक में विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व किया। श्रीलंका ने कोलंबों में 9–15 नवंबर 2014 के दौरान 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

20 का समूह (जी20)

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 5.6 सितंबर 2013 के दौरान सेंट पिटर्सबर्गए रूस में आयोजित 8वें जी–20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। प्रधान मंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया रू (i) विकसित देशों द्वारा अपनाई जा रही अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों से क्रमानुसार बाहर निकलना जिसने विकासशील दुनियां की विकास संभावनाओं को हानि पहुंचाई हैय (ii) जी–20 विचार विमर्शों में विकास आयाम की अग्रता सुनिश्चित करना विशेषकर रोजगार सृजनए अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना और मध्यम स्थितियों में उच्चतर विकास बनाए रखने के लिए विकासशील देशों में क्षमता सृजनय और ;पपपद्ध वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में शासन में सुधार। उन्होंने आग्रह किया कि शिखर सम्मेलन विकास के पुनरूत्थान के लिए मिलकर काम करनेके लिए सामुहिक प्रतिबद्धता के स्पष्ट संकेत भेजा जाना चाहिएए जो गुणवत्ता वाले रोजगार में सतत विकास सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने उभरते बाजार में अवसंरचना वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

जी.20 प्रक्रिया में भारत की भागीदारी इस बात से रोकती है कि एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण साझीदारी है। भारत जी–20 के प्रारंभ से ही शेरपा ट्रेक और वित्तीय ट्रेक दोनों में जी–20 की तैयारी में सक्रियता से संलग्न रहा है। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सभी आठ जी.20 शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। जी.20 शिखर सम्मेलनों में भारतीय एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की वृहत्तर समग्रता लाने की आवश्यकता सुनिश्चित करना और इसमें सुधार लाना, प्रश्रयवादी रूखों से बचना औरए सबसे बढ़करए यह सुनिश्चित करने से प्रभावित रहा कि विकासशील देशों की विकास संभावनाओं को हानि न पहुंचे।

इब्सा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) वार्ता मंच

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 25 सितंबर 2013 को न्यूयार्क में इब्सा विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का विशेष महत्व रहा क्योंकि यह इब्सा के 10वीं वर्षगांठ के वर्ष के दौरान हुई। इस बैठक के एजेंडे में समकालिक मुद्दे शामिल थे जिसमें शामिल हैं मध्य एशिया, सीरिया, अफगानिस्तानए मिस्रए आदि में गतिविधियांए वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक शासन में सुधार और जलवायु परिवर्तनए सतत विकासए डब्ल्यूटीओए दोहा दौरा आदि अन्य वैश्विक मुद्दों के साथ साथ इब्सा सहयोग को सुचारू तथा ठोस बनाने के तरीकों तथा साधन शामिल थे। एक संयुक्त वक्तव्य भी इस बैठक के बाद जारी किया गया।

इस मंत्री–स्तरीय बैठक से पहले 24 सितंबर, 2013 को इब्सा फोकल प्वाइंट (वरिष्ठ अधिकारीगण) की एक बैठक हुई। श्री दिनेश भाटियाए संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इब्सा फोकल प्वाइंट की भी बैठक प्रिटोरियाए दक्षिण अफ्रीका में जुलाई 2013 में हुई। संयुक्त सचिव (एमईआर) ने जुलाई 2013 में इब्सा एजेंडा पर चर्चा करने के लिए ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

कृषिए संस्कृतिए रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, मानव व्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा निवेश और यातायात पर इब्सा संयुक्त कार्य समूहों की बैठक जनवरी–मई 2013 की अवधि के दौरान नई दिल्ली में हुई। इब्सा महिला मंच की 5वीं बैठक की मेजबानी 16 मई 2013 को नई दिल्ली में श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला व बाल विकास मंत्री द्वारा की गई। इब्सा स्थानीय शासन मंच की बैठक नई दिल्ली में 8–9 अप्रैल, 2013 के दौरान हुई।

हिंद महासागर रिम संगठन (आईओआरए)

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 1 नवंबर 2013 को पर्थ, आस्ट्रेलिया में आयोजित भारतीय समुद्री रिम संगठन क्षेत्रीय सहयोग मंत्रीपरिषद (सीओएम) की 13वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारत ने इस बैठक में इस संगठन की अध्यक्षता आस्ट्रेलिया को सौंप दी। इस बैठक में हिंद महासागर रिम संगठन (आईओआरए) के नए नाम को स्वीकार किया गया। 13वें सीओएम में भारतीय ओसन रिम संगठन की पर्थ घोषणा को अंगीकार किया गया जो हिंद महासागर और इसके संसाधनों के शांतिपूर्ण, उत्पादक तथा सतत उपयोग के सिद्धांतों पर आधारित था। बैठक के अंत मेंए पर्थ वक्तव्य जारी किया गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रथम आईओआरए मंत्रीस्तरीय मंच में भाग लिया जो 21 जनवरी 2014 को अबु धाबी में आयोजित किया गया था। यह बैठक अबु धाबी सतत सप्ताह के भाग के रूप में आईओआरए सचिवालय द्वारा यूएई विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ;आईआरईएनएद्ध के सहयोग से आयोजित की गई। अबु धाबी घोषणा बैठक के बाद जारी की गई।

इस अवधि के दौरानए मंत्रालय ने आईओआरए के तहत अनेक कार्यक्रम प्रायोजित किए। इनमें शामिल हैंरू आईओआरए सदस्य राष्ट्रों के राजनयिकों के लिए तीसरा विशेष पाठ्यक्रम ;सितंबर 2013य नई दिल्लीद्ध कोस्टल जोन प्रबंधन के लिए बहुविषयक समुद्रिक ऑब्जर्वेशन पर द्वितीय कार्यशाला ;सितंबर 2013य गोवाद्धए आईओआरए सदस्य राष्ट्रों के लिए मत्स्य प्रबंधन पर कार्यशाला ;दिसंबर 2013य कोच्चीद्ध और आईओआरए कविता महोत्सव मार्च 2014य ;नई दिल्लीद्ध। भारत ने भी मार्च 2014 में नैरोबीए केन्या में श्मरीटाइम अफ्रीका की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आईओआरए सम्मेलनश आयोजित करने में आईओआरए सचिवालयए भारतीय समुद्र अनुसंधान समूह ;आईओआरजीद्ध और केन्या की सहायता करने में आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल हो गया।

रूस, भारत और चीन (आरआईसी)

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 10 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में रूसए भारत और चीन (आरआईसी) के विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी की। इसके एजेंडा में शामिल थे वैश्विक ध्क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा आउटलुक ख्अफगानिस्तानए मध्य एशियाए सीरिया की स्थितिए ईरान के परमाणु मुद्देए आदि और अप्रसारए निशस्त्रीकरण, आदि से संबंधित मुद्दे, आतंकवाद मादक द्रव्य अवैध व्यापार का मुकाबला और अन्य चुनौतियां संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर आरआईसी सहयोग, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन में सुधार के आरआईसी तरीके और आरआईसी त्रिपक्षीय सहयोग को सुचारू बनाना। मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

भारत ने श्सीमित क्षेत्रीय संपर्कश की अपनी व्यक्त नीति के तहत ओईसीडी के साथ संपर्क बनाए रखा। मौजूदा नीति को पुनः व्यक्त करने के लिए ओईसीडी के साथ ठोस वार्ता करके भारत सरकार के सभी साझेदारों के साथ चर्चा करके समीक्षा की गई।

भारत ने वर्ष के दौरान ओईसीडी के उप सचिव जनरल थ्राइस सहित वरिष्ठ पदधारियों का स्वागत किया। भारत ने मईए 2013 में ओईसीडी के मंत्रिस्तरीय परिषद की वार्षिक बैठक में भाग लिया जहां पेरिस में भारत के राजदूत और श्री दिनेश भाटियाए संयुक्त सचिव ;एमईआरद्ध ने इसके पूर्ण सत्रों में भाग लिया और ओईसीडी के साथ इसके संपर्क पर भारत के विचारों को आगे बढ़ाया।

आसियान–भारत

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बेगावानए ब्रुनई दारेस्सलाम में 10 अक्तूबर 2013 को आयोजित 11वें आसियान.भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। दिसंबर 2012 में भागीदारी को श्रणनीतिक भागीदार' तक उठाने के बाद से यह प्रथम आसियान–भारत शिखर सम्मेलन था। नेताओं ने शांतिए प्रगति और साझी संपन्नता (2010–2015) के लिए आसियान–भारत साझेदारी के कार्यान्वयन कार्य में हुई अच्छी प्रगति का स्वागत भी किया। भारत आसियान समुदाय निर्माण प्रक्रिया में भारत के सतत समर्थन का आसियान नेताओं द्वारा स्वागत किया गया।

आसियान भारत कार्यनीतिक भागीदारी के सम्पूर्ण तीव्रीकरण के मद्देनजरए जाकार्ताए इंडोनेशिया में आवासीय दूत के साथ एक अलग से आसियान के लिए भारतीय मिशन की स्थापन की घोषणा11वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में किया गया।

11 वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बादए विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने ब्रुनई दारेसलाम में 1 जुलाईए 2013 को आयोजित आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने ब्रुनई दारेसलाम

में 21 अगस्त, 2013 को आसियान आर्थिक मंत्रियों तथा भारतीय परामर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। कृषि तथा वानिकी पर तीसरे आसियान भारत मंत्रीस्तरीय बैठक 28 सितंबर, 2013 को हुई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केन्द्रीय कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री शरद पवार ने की। आसियान भारत रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के सरकारी प्रयासों में सहायता करने के लिए नई दिल्ली में 21 जून, 2013 को विदेश मंत्री द्वारा एक आसियान भारत केन्द्रका उद्घाटन किया गया। आसियान और भारत के बीच व्यापार बढ़ता रहा। यह 2012–13 (अक्तूबर, 2013 तक) में 76.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था। आसियान और भारत का 2015 तक 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार का लक्ष्य है।

आसियान और भारत के बीच संपर्क एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बनी रही जो 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा दोहराया गया। भारत ने बालिकपापन में 10 जून, 2013 को आसियान संपर्क समन्वय समिति (एसीसीसी) के साथ वार्षिक बैठक प्रारंभ की, जो चीन और जापान के बाद ऐसा करने वाला तीसरा वार्ता साझीदार बन गया।

श्री विश्वनाथन पेरूमलए सांसद की अगुवाई में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 17–23 सितंबर, 2013 को ब्रुनई दारेसलाम में आयोजित 34 वें आसियान अंतर संसदीय सभा (एआईपीए) में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

आसियान और भारत ने 2013 में लोगों के बीच आपसी संपर्क को 20 आसियान पत्रकारों और आठ भारतीय पत्रकारों के लिए मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से, 250 आसियान विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 40 आसियान छात्रों की भागीदारी, भारत और आसियान देशों दोनों में से 20 किसानों के किसान आदान–प्रदान कार्यक्रम के साथ साथ एफएसआई में महीने भर का वार्षिक आसियान राजनयिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित, मजबूत करना जारी रखा।

ट्रैक वन एण्ड ए हाफ बातचीत दिल्ली वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से जारी रही। दिल्ली वार्ता V, का शीर्षक 'भारत–आसियानरू भागीदारी और संपन्नता के लिए दृष्टिकोण, नई दिल्ली में 19–20 फरवरीए 2013 के दौरान आयोजित हुआ। दिल्ली वार्ता VI का शीर्षक था ष्भागीदारी औरसंपन्नता के लिए आसियान–भारत दृष्टिकोणष् जिसका आयोजन 6–7 मार्च, 2014 तक नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री ने किया। दस आसियान देशों के विदेश मंत्रियों और उप विदेश मंत्रियोंए आसियान महा सचिवए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। 10 सितंबर, 2013 को विएनटिएनए लाओ पीडीआर में विदेशमंत्री द्वारा थिंक टैंक के आसियान–भारत नेटवर्क के द्वितीय गोल मेज का उद्घाटन किया।

आसियान.भारत रणनीतिक भागीदारी में अनेक क्षेत्रों के 26 अंतर. सरकारी तंत्र हैं जिसमें कृषि, पर्यावरण तथा वानिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा वाणिज्य, पर्यटन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, लघु तथा मध्यम उद्यम शामिल हैं। विभिन्न क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आसियान.भारत सहयोग कोष ाय आसियान.भारत विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास कोषय और आसियान.भारत ग्रीन कोष से वित्तपोषण से कार्यान्वित होना जारी रहे।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10 अक्तूबर, 2013 को ब्रुनई दारेस्सलाम में 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ;इएएसद्ध एशिया प्रशान्त क्षेत्र का अद्वितीय मंच हैए जिसका नेतृत्व 18 देशों के नेता कर रहे हैं। विदेशमंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 2 जुलाई, 2013 को ब्रुनई दारेस्सलाम में तीसरे ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। प्रथम आरसीईपी मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और ब्रुनई दारेस्सलाम में अगस्त, 2013 में द्वितीय इएएसआर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई थी। राज्य मंत्रीए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 26 सितंबरए 2013 को बालीए इंडोनेशिया में सातवें इएएस ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सचिव ;आर्थिक कार्यद्धए ने 12 अक्तूबरए 2013 को वाशिंगटन डीसी में हुए ईएएस वित्त मंत्रियों की तीसरी अनौपचारिक बैठक में प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारत ने 13 नवंबरए 2013 को आसियान संपर्क समन्वय समिति और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पर अनौपचारिक परामर्श में भाग लिया।

आठवें ईएएस में खाद्य सुरक्षा को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में विचार किया गया और खाद्य सुरक्षा पर आठवें एशिया शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र को अंगीकार किया गया। मत्स्य पालन प्रबंधन और समुद्री पर्यावरण संरक्षा के माध्यम से ईएएस ट्रैक प्र अध्ययन समूह इस घोषणापत्र के कार्यान्वयन की प्रथम पहल के रूप में स्थापित किया गया है। इस अध्ययन समूह की पहली बैठक ब्रुनई में 3–5 दिसंबर, 2013 के दौरान हुई थी।

8–9 नवंबर, 2012 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित 'इएएस. भारत कार्यशाला 2012: भूकंप के खतरे के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय फ्रेमवर्क बनानाश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप मेंए भारत ने सूचनाए ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) में

एक वर्चुअल ज्ञान केन्द्र (वीकेसी) और ईएएस देशों के राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर एजेंसियों के बीच निविदा के 24ग7 प्वाइंट नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की।

भारत तथा आस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य सचिव ने मलेरिया नियंत्रण तथा मलेरिया रोधी दवाओं से प्रतिरोधक्षमता से निपटने के लिए 7वें ईएएस क्षेत्रीय घोषणा के अनुवर्ती के रूप में एशिया प्रशान्त नेता मलेरिया गठबंधन के तहत उत्तम दवाओं की पहुंच पर एक टास्कफोर्स की सहअध्यक्षता करने पर सहमत हुए। इस टास्क फोर्स की प्रथम बैठक सिडनी, आस्ट्रेलिया में 12 मार्च, 2014 को हुई। आठवें ईएएस मेंए भारत ने ईएएस भागीदार देशों के साथ सहायोग के भविष्य की संभावनाओं की तलाश के लिए श्ट्रामासेन्टर और नर्सिंगपर फोकस के साथ टर्सियरी हेल्थकेयर पर गोलमेजश का भी प्रस्ताव किया।

8वें ईएएस मेंए नेताओं ने नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित करने में हुई प्रगति का स्वागत किया। आठ देशों – आस्ट्रेलियाए ब्रुनई दारेस्सलामए कम्बोडियाए लाओ पीडीआरए म्यामारए न्यूजीलैण्डए सिंगापुर और भारत ने नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीन ने 23 अक्तूबर, 2013को प्रधान मंत्री के बीजिंग दौरे के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार (आरसीईपी) की जारी बातचीत में भाग ले रहा है जिसे 7वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं।

एशिया–यूरोप बैठक (एएसईएम)

भारत ने वर्ष 2007 में एएसईएम में शामिल होने के बाद से पहली बार गुडगांव, दिल्ली एनसीआर में 11–12 नवंबर 2013 के दौरान 11वें एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक (एएसईएम एफएमएम 11) की मेजबानी की। 34 विदेश मंत्रियों और 11 उप विदेश मंत्रियों सहित सभी 51 एएसईएम सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया। क्रमशः 4–5 सितंबर 2013 और 9.10 नवंबर 2013 को दो प्रारंभिक एएसईएम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (एसओएमएस) गुडगांव में हुए।

'एएसईएमरू विकास और विकास के लिए भागीदारी सेतु' विषय के अंतर्गतए एएसईएम एफएमएम 11 वार्ताओं में आर्थिक और वित्तीय मामलों, सतत विकासए गैर–पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ–साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित आम हित के मुद्दों पर चर्चा की गई।

पूर्व एएसईएम बैठकों की घोषणात्मक प्रकृति से अलग होकर, एएसईएम एफएमएम 11 'डिलिवरेबल्स' वार्ता से ध्यान हटाने में सफल रहा। आपदा प्रबंधनए जल प्रबंधनए पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाए एसएमई सहयोगए ऊर्जा प्रभावकारिता प्रौद्योगिकी और उच्चतर शिक्षा सहित बारह क्षेत्रों में एशिया और यूरोप के बीच ठोस सहयोग की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए एएसईएम में इसने एक नई दिशा की शुरूआत की।

एएसईएम एफएमएम 11 के दौरानए एशिया.यूरोप फाउन्डेशन (एएसईएफ) और भारत ने श्मीडिया और हरित विकासः एशिया और यूरोप में सतत विकास पर रिपोर्टिंग विषय पर 10–12 नवंबर 2013 को दिल्ली–एनसीआर में 9वां एएसईएफ पत्रकार वार्तासमूह की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में एएसईएम देशों के 30 पत्रकारों और नौ पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया।

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बीआईएमएसटीईसी)

प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने ने पाई ताउ, म्यामा में 3–4 मार्च, 2012 के दौरान तीसरे बिम्स्टीक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन से पहले 14वें मंत्रीस्तरीय बैठक (विदेश मंत्री की अगुवाई में) और 16वे एसओएम (एफएस की अगुवाई में) नेताओं ने तीसरे बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन घोषणा जारी कीए जिसने क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क को गति प्रदान की। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश, भूटान, म्यामां, नेपाल और श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई।

तीसरे बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणामों में दोहा में बिम्स्टिक सचिवालय की सथापना के लिए एमओए पर हस्ताक्षर करना, इसके पहले महा सचिव की नियुक्ति, भारत में बिम्स्टिक जलवायु और मौसम केन्द्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और भूटान में बिम्स्टिक सांस्कृतिक उद्योग आयोग तथा ऑब्जर्वेटरी पर एमओयू। बिम्स्टिक में भारत का नेतृत्व और प्रतिबद्धता को अन्य सदस्यों द्वारा सराहा गया। भारत सचिवालय के वार्षिक बजट में से 32 प्रतिशत अंशदान का वायदा किया है।

भारत ने संपर्क पहल की आगुवाई की और इस क्षेत्र में प्राथमिकता वाले यातायात परियोजनाओं के लिए बिम्स्टिक यातायात अवसंरचना तथा संभारतंत्र (बिटीआईएलएस) को सुकर बनाया। भारत ने आतंकवाद से मुकाबले में अग्रणी भूमिका निभाई और करारों के स्वरूप पर बातचीत की और एजेंसियों के बीच सहायोग बढ़ाने को बढ़ावा दिया। पर्यटन में, एक बिम्स्टिक सूचना केन्द्र की स्थापना की गई और वर्ष 2015 बिम्स्टिक पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारत पर्यावरण और मौसम पर बेम्स्टिक केन्द्र की स्थापना कर रहा है।

एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी)

श्री ई. अहमद, राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2013 को बहरीन में 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लियाए जिसमें मनामा

घोषणा को अपनाया गया और कुवैत में अनंन्तिम सचिवालय स्थापित करके संस्थानीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जिसमें थाईलैण्ड के श्री बुंदित लिम्सचुन को इसके महा सचिव बने। उन्होंने इससे पहले 29 मार्च, 2013 को दुशान्बे में 11वीं मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लिया था। ईरान ने 7–8 मई, 2013 के दौरान प्रथम संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। थाईलैण्ड ने 17 जुलाई, 2013 को बैंकाक में एसीडी क्षेत्रीय संपर्क पर एक कार्य समूह बैठक का आयोजन किया।

संघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

बहुपक्षीय दिशा में भारत ने निरीक्षक देशों के लिए खुले विभिन्न एससीओ मंचों पर वर्ष 2005 से सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भारत एमसीओ के निरंतर विकास पर नजर रखते हुए विकास और सुरक्षा में अपने अनुभवों को साझा करता रहा है। भारत ने अपने विभिन्न संरक्षण पहलों में एससीओ के साथ अपने संपर्क के भाग के रूप में अक्तूबर 2013 में बिस्केक में वैश्विक स्नो लेपर्ड संरक्षण मंच में भाग लिया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने सितंबर 2013 में बिश्केक में आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 28–29 नवंबर 2013 के दौरान ताश्कंद में एससीओ–परिषद–राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। सचिव (ईआर/एडी), विदेश मंत्रालय श्री पी.एस. राघवन ने मास्को में दिसंबर 2013 में एससीओ ऊर्जा क्लब के आगामी दौर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

एससीओ के महा सचिव, श्री देमेत्री फेडेरोविक मेजेन्तेव ने 23–24 फरवरी, 2014 को विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह के निमंत्रण पर नई दिल्ली की यात्रा की। श्री मेजेन्स्तेव ने विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात भी की और रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में विद्वानों से बातचीत की।

12 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

भारत सार्क की सहयोगात्मक परियोजनाओं को त्वरित करने तथा जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध रहाए जो दक्षिण एशिया के लोगों को अपने साझे लक्ष्य तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

भारत ने विभिन्न सार्क बैठकों जैसे 11–12 फ़रवरी, 2013 के दौरान ढाका में आयोजित कृषि और ग्रामीण विकास पर तकनीकी समिति की 7 वीं बैठकय 5–6, मार्च 2013 के दौरान थिम्पू में आयोजित एचआईवी / एड्स पर सार्क क्षेत्रीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक का विशेष सत्र (2012–2016); 10–14 मार्च, 2013 के दौरान ढाका में आयोजित 'तीसरा प्रशिक्षण कार्यशाला और सार्क ऑस्ट्रेलिया परियोजना की अंतिम समीक्षा बैठकय 15–16 मार्च, 2013 के दौरान श्रीलंका में आयोजित ऊर्जा पर सार्क कार्य समूह की सातवीं बैठकय इस्लामाबाद में 18–23 मार्चए 2013 के दौरान आयोजित सार्क क्षेत्र के लिए स्त्री–पुरूष समानता और आगे बढ़ने के मार्ग पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमय सार्क कलाकार शिविर और सार्क सांस्कृतिक केन्द्र, कोलंबो द्वारा आयोजित 25–28 मार्चए 2013 के दौरान मालदीव में चित्रों की प्रदर्शनीय 04–05 अप्रैलए 2013 के दौरान काठमांडू में आयोजित गरीबी उन्मूलन पर सार्क सचिवालय की 5 वीं बैठक से पहले गरीबी उन्मूलन पर सार्क मंत्रियों की तीसरी बैठकय 11–12 अप्रैलए 2013 के दौरान पारोए भूटान में आयोजित और दक्षिण एशिया में महिलाओं और बच्चों की तस्करी और बाल कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित सार्क सम्मलेन को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यबल की 5 वीं बैठकय 17–18 अप्रैलए 2013 के दौरान काठमांडू में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/समकक्ष निकायों के प्रमुखों की समिति की आठवीं बैठकय 23–24 अप्रैलए 2013 के दौरान काठमांडू में आयोजित वित्तीय मुद्दों पर सार्क अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की छठी बैठकय 22–23 मईए 2013 के दौरान काठमांडूए नेपाल में आयोजित दोहरे कराधान और कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता से बचाव पर सार्क सक्षम प्राधिकारी की दूसरी बैठकय 04–05 जूनए 2013 के दौरान काठमांडू में आयोजित निर्माण सामग्री पर सेक्टर तकनीकी समिति की तीसरी बैठकय 20–21 जूनए 2013 के दौरान श्रीलंका में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग पर सार्क उप समूह की नौवीं बैठकय 19–20 जून, 2013 के दौरान ढाका में आयोजित रेलवे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठकय 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2013 के दौरान काठमांडू में सार्क सचिवालय द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई मुक्त वाणिज्य क्षेत्र (साफ्टा) (चरण –III) के तहत संवेदनशील सूची में कटौती पर कार्य समूह की दूसरी बैठक और गैर टैरिफ उपाय और पैरा टैरिफ उपायों पर साफ्टा विशेषज्ञ समिति की विशेष बैठकय इमीग्रेशन और वीजा विशेषज्ञों की कोर ग्रुप की बैठक 13–15 अगस्तए 2013 के दौरान सार्क सचिवालयए काठमांडू में आयोजित की गई जिसमें मौजूदा सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईसीद्ध की समीक्षा की गईय 15 अगस्त 2013 को सार्क सचिवालयए काठमांडू में आयोजित एक "सार्क आप्रवासन सम्पर्क नेटवर्क (एसआईएलएन) स्थापित करने के प्रस्ताव का कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठकय साफ्टा विशेषज्ञों की समिति की आठवीं बैठक से पहले साफ्टा की मंत्रिस्तरीय परिषद की सातवीं बैठक 21–23 अगस्त, 2013 के दौरान कोलंबोए श्रीलंका में आयोजित की गई जिसमें साफ्टा के तहत अंतर–सार्क व्यापार प्रवाह बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया और ऐसा इसके नियमों और शर्तों को कुछ सदस्य राष्ट्रों द्वारा बनाई गई द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था में व्याप्त नियमों व शर्तों से अधिक आकर्षक बनाकर किया गयाय सार्क वित्त सचिवों की छठी बैठक से पहले सार्क के वित्त मंत्रियों की छठी बैठक 29–30 अगस्त, 2013 के दौरान कोलंबो में आयोजित हुईए जिसमें भारत द्वारा मुद्रा के लिए एसडब्ल्यूएपी व्यवस्था लागू करने की सराहना की गई और उल्लेखनीय किया गया कि भूटान ने पहले ही इस व्यवस्था के तहत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैय 09–10 सितम्बर 2013 के दौरान काठमांडू में सार्क सचिवालय और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एचआईवी और एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए समर्थनए संरक्षण और देखभाल के लिए सार्क क्षेत्रीय सामरिक फ्रेमवर्क पर प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठकय मंत्रियों के सार्क परिषद की अनौपचारिक बैठक में विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने भाग लिया जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अड़सठवें सत्र के मौके पर 25 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया।

भारत में सार्क से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलाप चलाए गएः

• चौथा सार्क युवा कैम्प का आयोजन आरजीएनआईवाईडी कैम्पसए श्रीपेरूम्बुदुर में 11–15 फरवरीए 2013 के दौरान युवा मामले तथा खेल मंत्रालय और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

• संघ लोक सेवा आयोगए भारत ने नई दिल्ली में 22–23 मार्च, 2013 के दौरान आईसीटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

• भारत ने 20–21 मई, 2013 के दौरान उदयपुरए राजस्थान में सार्क मोटर वाहन पर प्रारूप क्षेत्रीय करार पर बातचीत के लिए विशिषज्ञ समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रीए डॉ. सीण्पीण् जोशी ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस विशेषज्ञ समूह ने प्रारूप करार के पाठ पर विस्तृत विचार–विमर्श किया।

• श्रम मंत्री भारत सरकार ने वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के आईएलओ के सहयोग से नई दिल्ली में 29–31 मई, 2013 के दौरान द्वितीय क्षेत्रीय बाल श्रम कार्यशाला का आयोजन किया।

• भारत ने दक्षिण एशिया (नई दिल्लीए 24–25 मई, 2013) में शहरी ढेर के लिए भूकंप के खतरे कम करने पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कार्यशाला का आयोजन किया।

• भारत ने 9–10 अक्तूबर, 2013 के दौरान नई दिल्ली में स्वास्थ्य व जनसंख्या कार्यकलाप पर तकनीकी समिति की चौथी बैठक की मेजबानी की जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्क द्वारा की गई पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

• एक तीन दिवसीय बैण्ड महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबरए 2013 के दौरान नई दिल्ली में किया गया जिसमें आठ सार्क देशों के 14 संगीत बैण्ड ने कलाप्रदर्शन किया। इस महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा किया गया।

• सार्क चार्टर दिवस की समृति में, जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय सार्क क्षेत्रीय केन्द्र तथा शीर्ष निकायों ने नई पीढ़ी के बीच सार्क के संदेश के प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया।

• विद्युत पर विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक 19 दिसंबरए 2013 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें 'ऊर्जा सहयोग (बिजली) के लिए सार्क अंतर–सरकारी कार्यढ़ांचा करार' को अंतिम रूप देने संबंधी मामलों पर विचार किया गया।

• 'सार्क लोक ऋण प्रबंधक मंच' की द्वितीय बैठक भारत में 6–7 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई।

• दक्षिण एशिया में उच्चतर शिक्षा की स्थिति पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 13–14 जनवरी, 2014 के दौरान आयोजित किया गया।

• अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा अंतरण मूल्यन पर सार्क सेमिनार एनएडीटीए नागपुर में 4–7 मार्च, 2014 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कराधानए दोहरे कराधान तथा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अत्यंत विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री परिषद (अंतर–शिखर सम्मेलन) का पैंतीसवां सत्र मालदीव में 17–20 फरवरी, 2014 के दौरान हुआ। अंतर–शिखर सम्मेलन से पहले, सार्क प्रभागाध्यक्षों (कार्यक्रम समिति बैठकए 17 फरवरी), विदेश सचिव ;18–19 फरवरी, विशेष सत्र और स्थायी समिति) के स्तर पर तैयारी बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में सार्क सचिवालय, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा सार्क विशेषज्ञता प्राप्त निकायों सहित सार्क तंत्र को मजबूत करने के लिए सार्क सचिवालय द्वारा कराए गए अध्ययनों पर विचार किया गया। समिति ने संस्तुति दी कि सार्क सम्मेलन वर्तमान में प्रत्येक वर्ष आयोजित करने की प्रथा के स्थान पर इसे प्रत्येक दो वर्षों में एक बार आयोजित किया जाए। बैठक आयोजित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय सीमा तय की जा सकती है। सार्क सचिवालयों के कामकाज में सुधार लाने के लिए अनेक संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया। बैठक में चयनीत समापन और क्षेत्रीय केन्द्रों के विलय पर सहमति व्यक्त की गई। इन बैठकों में मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर सार्क करारए सेवा में व्यापार पर सार्क समझौते (एसएटीआईएस)ए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू)ए सार्क विकास कोष (एसडीएफ) आर्थिक और वित्तीय सहयोग से संबंधित मुद्दोंए परिवहनए पर्यावरणए स्वास्थ्यए सुरक्षा और सहयोग पर समुद्रपारीय देशों से सहयोग से संबंधित मामलों पर विचार किया गया। भारत ने मोटर वाहन पर प्रारूप क्षेत्रीय करार और परिवहन पर अंतर सरकारी समूह की बैठक पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करने की पेशकश की।

■■

13

विकास सहयोग

जनवरी, 2012 में विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का शीघ्र एवं सक्षम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकास सहभागिता प्रशासन (डीपीए) स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल की थी। हाल के वर्षों में भौगोलिक तथा क्षेत्रीय दोनों ही स्तरों पर इन कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार हुआ है। विकास साझेदारी को भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विकास परियोजनाओं को संकल्पना, प्रमोचन, निष्पादन तथा पूर्णता के स्तरों के माध्यम से सक्षमतापूर्वक नियंत्रित करने की प्रक्रिया की स्थापना के लिए डीपीए को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सरल तथा उन्नत करना है। डीपीए मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के साथ निकट समन्वय से कार्य करता है, जो शुरू किए जाने वाली परियोजनाओं के चयन पर सहभागी देशों के साथ प्रधान वार्ताकार और माध्यम बना रहेगा। परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन की जिम्मेदारी डीपीए पर है।

इस मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय प्रभागों से डीपीए को परियोजनओं के हस्तांतरण में परियोजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के माध्यम से विविध क्षेत्रों में बहु–आयामी परियोजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने के संबंध में डीपीए की क्षमताओं के अनुसार प्रगति हुई है। विभिन्न विकासशील देशों तथा अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमा, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा अफ्रीकी देशों में विकास परियोजनाओं के लिए ऋण श्रृंखला के अंतर्गत परियोजनाएं इसके निर्माणाधीन चरणों में डीपीए के मुख्य संकेंद्रित क्षेत्र हैं। नागरिक एवं सैनिक क्षमता निर्माण वाले तकनीकी सहायता कार्यक्रम में विस्तार हुआ है।

ऋण श्रृंखला (एलओसीएस)

हाल के वर्षों में भारत की विकास सहायता का एक मुख्य माध्यम अल्पतम विकसित तथा विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला प्रदान करना रहा है। ऋण श्रृंखला अफ्रीका, एशिया तथा लातिन अमेरिका में भारत की विकास सहयोग रणनीति का एक महत्वपूर्ण संघटक बना रहा। द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से ऋण श्रृंखला के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले देश विकास प्राथमिकताओं के अनुसार भारत से वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर सकते हैं तथा अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

पिछले कुछ दशकों से 11 बिलियन अमरीकी डॉलर की 195 ऋण श्रृंखलाएं आबंटित की गई हैं जिनमें से अफ्रीकी देशों के लिए 6.659 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा गैर–अफ्रीकी देशों के लिए 4.345 बिलियन अमरीकी डॉलर आबंटित की गई हैं। 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान अफ्रीका के लिए 1497.47 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखलाएं आबंटित की गई हैं जिसमें सूडान में मशकौर शुगर परियोजना के लिए 125 मिलियन अमरीकी डॉलर, इथोपिया तथा जिबूती के बीच रेलवे लाइन परियोजना के लिए इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य को 300 मिलियन अमरीकी डॉलर, विद्युत पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए लाइबेरिया गणराज्य को 144 मिलियन अमरीकी डॉलर, निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचित कृषि परियोजनाओं के लिए रवांडा गणराजय को 120 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1200 कम लागत वाले मकानों के निर्माण के लिए मोजाम्बिक गणराज्य को 47 मिलियन अमरीकी डॉलर, जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन के लिए बेनिन गणराज्य को 42.61 मिलियन अमरीकी डॉलर, सिंचाई विकास परियोजनओं के लिए सियरा लियोन गणराज्य को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर, विद्युत पारेषण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं आदि के लिए टोगो गणराज्य को 82 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल है। अन्य देशों को 479.79 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला स्वीकृत की गई थी जिसमें रेल परियोजनाओं के लिए म्यांमा को 155 मिलियन अमरीकी डॉलर, श्रीलंका में साम्पुर थर्मल विद्युत परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर, जल संसाधन एवं सिंचाई प्रणली के विकास के लिए कंबोडिया को 36.92 मिलियन अमरीकी डॉलर, सिंचाई प्रणालियों के विकास के लिए लाओस को 30.94 मिलियन अमरीकी डॉलर, सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए होंडुरस को 26.5

मिलियन अमरीकी डॉलर तथा प्रक्षेप्य उत्पाद संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए क्यूबा को 5.0492 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल है।

पिछले वर्षों में श्रीलंका को दी गई ऋण श्रृंखलाओं के अंतर्गत चालू परियोजनाओं में कफी प्रगति हुई है। 416.39 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ट्रैक कार्यों में धीरे–धीरे प्रगति हुई है। मेडावाछय्या–मधु क्षेत्र का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा मई 2013 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। औमान्थई–पलई क्षेत्र मार्च 2014 में पूरा कर लिया गया है; मधु चर्च–तलईमन्नार क्षेत्रों का कार्य अगले कुछ महीनों में पूरा होने की संभावना है। पिछले साल प्रारंभ किए गए पलाई–कान्केसंथुरई रेलवे लाइन पर लाइनें बिछाने का कार्य (146.34 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा उत्तरी रेलवे लाइन पर सिग्नल एवं दूर संचार उपस्कर (86.52 मिलियन अमरीकी डॉलर) का कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तथा सिलोन विद्युत बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम साम्पुर विद्युत परियोजना के लिए विद्युत की खरीद, कोयले की आपूर्ति तथा भूमि पट्टे पर लेने के लिए करारो पर त्रिन्कोमलई में हसताक्षर किए गए हैं। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत शामिल जैटी एवं पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

वर्ष 2010 में भारत सरकार ने बांग्लादेश को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की। इसमें से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर बांग्लादेश सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं के इस्तेमाल के लिए 2012 में अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ऋण श्रृंखला के अंतर्गत उपलब्ध शेष 800 मिलियन अमरीकी डॉलर 16 परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया जिसका कुल योग 794.15 मिलियन अमरीकी डॉलर था। इसमें ढांचागत परियोजनाएं आपूर्तियां शामिल हैं। बसों, माल डब्बों, ब्रेक वैन्स तथा लोकोमोटिव की खरीद का कार्य पूरा हो गया है। रेल ब्रिज, रेल लाइन आदि के निर्माण की परियोजना कार्यान्वयन के अलग–अलग स्तरों पर है। ऋण श्रृंखला की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बांग्लादेश सरकार तथा अन्य हित धारकों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक का निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को विभिन्न क्षेत्रों जेसे बिजली उत्पादन एवं पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण जल संसाधन विकास तथा सिंचाई के लिए ऋण श्रृंखला प्रदान की गई है। 45 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत वियतनाम में 200 मेगावाट की नाम चियेन जलविद्युत परियोजना जुलाई 2013 में सफलतापूर्वक शुरू की गई। कुल 89 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो ऋण श्रृंखला के अंतर्गत, लाओ पीडीआर में चलाई जा रही सिंचाई प्रणाली तथा पारेषण लाइन/उप–स्टेशन परियोजनाओं का कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

नोपाल सरकार को दो ऋण श्रृंखलाएं प्रदान की गई हैं, पहली 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्ष 2007 में तथा दूसरी 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्ष 2010 में। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत, सड़क परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं, विद्युत पारेषण तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 97.18 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल लागत वाले 15 अनुबंध को अनुमोदित किया गया है।

250 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला विद्युत पारेषण, राजमार्ग, पुल तथा सिंचाई परियोजनाओं सहित ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुमोदित की गई है। जून 2013 में इस ऋण श्रृंखला के अंतर्गत कुल 175.39 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली विद्युत क्षेत्र की चार परियोजनाओं का अनुमोदन मिला है। चल रही परियोजनाओं की मानीटरिंग के भाग के रूप में, समीक्षा मिशनों ने नेपाल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिजी तथा बांग्लादेश का दौरा किया। भारतीय मिशनों तथा एक्जिम बैंक जो भारत सरकार की ऋण श्रृंखला का उधारदाता एजेंट है, से कार्य–निष्पादन रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं।

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता से विकास परियोजनाएं:

अन्य देशों से अपने विकास अनुभवों को बांटना तथा विकास एवं आर्थिक उन्नति के मार्गों से अवगत कराने की भारत की नीति को आगे बढाने के लिए विकास सहयोग एक मुख्य घटक है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, अफगानिस्तान, भूटान, मालद्वीव, म्यांमा, नेपाल तथा श्रीलंका द्वारा विकास के लिए उनकी प्राथमिकता के अनुरूप अवसंरचना, जलविद्युत, विद्युत पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में मुख्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। भारत के पड़ोसी देशों से सीमा–पार संपर्क को मजबूत करने की पहल सतोषजनक प्रगति कर रही है। भारत की अफगानिस्तान के लिए पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास की ओर प्रतिबद्धता, अफगानिस्तान द्वारा प्राथमिकता दिए गए विकास के लिए अवसंरचना, विद्युत, विद्युत पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से पूरी की जा रही है। अफगानिस्तान में चल रही परियोजनाओं में हेरात प्रांत में सलमा बांध (42 मेगावाट) का पुनर्निर्माण, दोशी तथा चारीकार में 2 उप–स्टेशन, अफगान संसद का निर्माण, स्टोर पैलेस की पुनर्स्थापना, भारतीय चिकित्सा मिशनों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं तथा दवाइयों की व्यवस्था, खाद्यान्न तथा उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुटों के रूप में 1.1 मिलियन टन गेहूं का दान, काबुल में इंदिरा

गांधी अंतर्राष्ट्रीय बाल अस्पताल के लिए सहायता, एक कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन, एक खनन संस्थान की स्थापना तथा बसों की आपूर्ति और संबद्ध डिपोट अवसरंचना का विकास, कम्प्यूटरों; तथा अन्य अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है।

अफगानिस्तान के साथ भारत के विकास सहयोग में शिक्षा एवं क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें अफगान राष्ट्रिकों के लिए वार्षिक 1000 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (आईसीसीआर द्वारा आयोजित); 674 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) छात्रवृत्ति; तथा अफगान लोक प्रशासन (सीएपी) कार्यक्रम के अंतर्गत 30 भारतीय सिविल सेवकों की प्रतिनियुक्ति शामिल है। पिछले सात वर्षों के दौरान एक लघु विकास परियोजना स्कीम के प्रथम दो चरणों में संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्वामित्व और प्रबंधन पर केंद्रित समुदाय आधारित परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया, जिनका सामुदायिक जीवन पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। लघु विकास परियोजनाओं (नवंबर 2012 में प्रारंभ) का तीसरा चरण देश के सभी प्रांतों सहित 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त परियोजनाएं को पूरा करेगा। इस योजना के अंतर्गत 60 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

म्यांमा में कई सीमा पार परियोजनाओं सहित अनेक विकासमूलक सहयोग परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। चालू सीमा पार परियोजनाओं में कलादान बहुमॉडल परिवहन परियोजना शामिल है (जो भारत के बंदरगाहों के बीच संपर्क व्यवस्था उपलब्ध कराएगी)।

यंगोन, म्यांमा में कलादान–1 बराज का निर्माण

श्रीलंका के हतोन डिकोया अस्पताल का निर्माण

म्यांमा में कई सीमापार परियोजनओं सहित विविध प्रकार की विकास सहयोग परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सीमापार चल रही परियोजनाओं में कलादान बहुविध परिवहन परियोजना (जो कि भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में बंदरगाहों को म्यामां के सीतवे बंदरगाह से और उसके बाद मिजोरम में सड़क द्वारा भारत–म्यामां सीमा को जोड़ेगा); म्यामां होते हुए भारत को थाईलैंड से जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग; कलेवा–याग्यी क्षेत्र में 120 किमी सड़क का निर्माण तामू–कलेवा–कालेमयो क्षेत्र में 71 पुलों का निर्माण तथा अन्य सड़क परियोजनाएं जैसे रिह (भारत–म्यामां सीमा)– तिद्दिम (म्यामां) शामिल है। हमारे म्यामां के साथ विकास सहयोग के महत्वपूर्ण आयामों में कृषि में उपज तथा गुणवत्ता बढाने (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र और एक चावल जैव–पार्क), सूचना प्रौद्योगिकी (मंडलै में म्यामां सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी)); स्वास्थ्य (यानगोन शिशु चिकित्सालय तथा सित्वे जनरल होस्पीटल का अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन); यांगोन एवं नौ–पाई–ताउ में भाषा प्रयोगशालाओं तथा ई–संसाधन केंद्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण संस्थाओं की स्थापना शामिल है।

भारत सरकार सहयोग के अंतर्गत नेपाल सरकार के राष्ट्रीय विकास प्रयासों में सहायता करने के लिए काफी संख्या में परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं। सीमा–पार परियोजनाएं; स्वास्थ्य क्षेत्र (काठमांडू में 200 बिस्तरों वाले आपातकालीन और ट्रौमा सेंटर का निर्माण); अवसंरचना; क्षमता निर्माण (हेतौदा में पोलिटेकनिक की स्थापना); नेपाल की नगरपालिका में फायर इंजन की आपूर्ति; आदि विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए परियोजनाओं की सीमा और प्रकृति में विविधता है।

श्रीलंका सरकार की प्राथमिकता के आधार पर, डिकोया में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना, कांकेसंथुरै बंदरगाह का विकास, जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण तथा थिरुकातेस्वरम मंदिर की मरम्मत संबंधी परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। 8 दिसंबर 2013 को श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने कैंडी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय की भारतीय गैलेरी का उद्घाटन किया।

भारत, प्रमुख आवास निर्माण की पहल के माध्यम से श्रीलंका में आतंरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आई डी पी) के पुनर्स्थापना में सहयोग कर रहा है। भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच 17 जनवरी, 2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत भारत, उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतो में ओनर–ड्रिवेन मॉडल प्रक्रिया में 43,000 मकानों की मरम्मत एवं निर्माण तथा मध्य एवं यूवा प्रांतों में एजेंसी ड्रिवन मॉडल के आधार पर 6000 आवासीय इकाइयों का निर्माण तीन वर्षों की अवधि में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1000 मकानों के निर्माण की प्रायोगिक परियोजना 2012 में पूरी हो गई थी। वर्तमान में, आवासीय परियोजना के द्वितीय चरण में उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में °ड्ढिदृ{ध्ड्डु•ड्ढ्र मॉडल के तहत आईडीपी के लिए 43000 मकानों (38000 निर्माण तथा 5000 मरम्मत) का निर्माण प्रगति पर है। ओनर–ड्रिवन मॉडल में लाभार्थी के स्वयं के मकान का निर्माण शामिल है; निर्माण के चरणों से जुड़ी धनराशि उनके बैंक खाते में चार किस्तों में भेज दी जाती है। वर्ष 2013 के अंत तक 10,250 मकानों का कार्य पूरा हो चुका था, शेष सभी के अगले दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

परियोजना के तीसरे चरण की प्रक्रिया अर्थात् मध्य/यूवा प्रांतों में एजेन्सी–ड्रिवन मॉडल के अंतर्गत 4000 मकानों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है तथा श्रीलंका सरकार द्वारा भूमि की पहचान करने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के इस भाग की प्रारंभिक डिजाइन तथा विकास का कार्य उसके बाद शुरू किए जाने की संभावना है।

अफ्रीका तथा अन्य क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी, सहयोग के परामर्शी मॉडल पर आधारित है जो कि, अफ्रीकी देशों की आवश्यकताओं जवाबदेह तथा विकास अनुभवों को साझा करने के लिए जवाबदेह है। विशेष तौर पर पिछले 10 वर्षों में, विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ विकास साझेदारी के माध्यम से आर्थिक विकास तथा क्षमता निर्माण में हमारे आदान–प्रदान में पर्याप्त तेजी है। 2008 तथा 2011 में आयोजित दो भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–प और प्प) वे इस महाद्वीप के साथ हमारी साझेदारी को और अधिक बल प्रदान किया है।

अनुदान सहायता के तहत, वर्तमान वर्ष के दौरान मालावी, नामीबिया, तथा रवांडा के कृषि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान की है। रवांडा में भारत ने 35 शैक्षिक संस्थानों के लिए एक मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से सोलर फोटोबोल्ट इस उपस्कर प्रदान करने की वचनबद्धता दी है। दक्षिणी सूडान में ग्रामीण तकनीकी पार्कों (आरटीपी), कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण आईएएफएस परियोजना है जिसके लिए 425 मिलियन रुपयों की राशि निर्धारित की गई है। इन आरटी पाक को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, (एनआईआरडी) हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अफ्रीकी कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिबद्धताओं के तहत विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय प्रशासन, वाटररोड प्रबंधन, ग्रामीण लघु उद्यमों के संवर्धन पेय जल प्रबंधन तथा सहयोग मूलक गरीबी न्यूनीकरण उपायों जैसे क्षेत्रों में वर्तमान वर्ष में एनआईआरडी द्वारा आयोजित किया जाना निर्धारित है।

आतिथ्य तथा पर्यटन, पुरातत्व संरक्षण, आईटी व कला तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी में इस अविधि के दौरान कई द्विपक्षीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। माले में आतिथ्य तथा पर्यटन के भारत–मालदीव मित्रता संकाय निर्माण कार्य समाप्त होने के करीब है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कंबोडिया के वा प्रॉम मंदिर, लाओ पीडीआर में वाट फॉ मंदिर तथा म्यांमा में आनंदा मंदिरों के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन कार्यों को जारी रखा है। 5 दिसम्बर, 2013 को सीएम रीप में अंकोर पर आयोजित तीसरे अंतर–सरकारी सम्मेलन में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ता प्रॉम मंदिर अपने कार्य का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसकी सम्मेलन में काफी सराहना की गई थी। आसेह (।बमी), इंडोनेशिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में निर्माण क्षेत्र कार्य, इंडोनेशियाई प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। वर्ष के दौरान उलानबटोर–मंगोलिया में राजीव गांधी पॉलीटेक्निक कॉलेज फॉर आर्टट्स एण्ड प्रोडक्शन के स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण; अर्मेनिया में टेलीमेडिसिन परियोजना की स्थापना; तथा फिलीस्तीन में स्कूल के निर्माण पर कार्य शुरू किया गया। दोमिनिकन गणराज्य में आईसीटी केंद्र का काम पूरा कर लिया गया; कई अन्य कार्य जारी हैं।

आपदा राहत के लिए सहायता

भारत ने, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को राहत सहायता प्रदान की है। फिलीपींस में प्रचण्ड तूफान हैयान से हुई व्यापक क्षति को देखते हुए, भारत ने आश्रय हेतु टैट, कंबल तथा तारफोलिन, दवाइयां, तैयार खाद्य, पानी साफ करने वाला रसायन, बिस्कुट, इत्यादि सहित राहत साग्रमी भेजी है। यमन, मार्शल द्वीप, मेडागास्कर तथा नामीबिया को नकद तथा वस्तुओं के रूप में राहत सहायता प्रदान की है।

तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण (आईटीईसी, स्कॉप तथा कोलंबो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना)

भारतीय प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, अफ्रीका कार्यक्रम हेतु विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्काप) तथा क्षमता निर्माण वर्ष 2013–14 में विकासशील विश्व भारत की ओर से सहायता का अभी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसे कि पिछले वर्ष था। इन कार्यक्रमों की उपयोगिता तथा ससंगतता इनमें भाग लेने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से पता चलती है। 2013–14 के दौरान 161 विकासशील देशों को 8000 से अधिक नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किया गया (परिशिष्ट–iv पर सूची)। नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, 47 संस्थानों में लगभग 280 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिसमें मुख्यतः कौशल तथा विद्या विशेष के विविध श्रेणियों में कार्यरत पेशेवरों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण है। सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को वित्त एवं लेखा, लेखापरीक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार, अंग्रेजी भाषा, प्रबंधन, नियोजन तथा प्रशासन, संसदीय अध्ययन, अपराध रिकार्ड, मास कम्यूनिकेशन, वस्त्र, ग्रामीण विद्युतिकरण, पर्यावरण, तथा नवीकरणीय ऊर्जा, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास, एसएमई तथा उद्यमशीलता विकास से संबंधित सामान्य पाठ्यक्रमों ने भी कई भाग लेने वालों को आकर्षित किया गया है। नागरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव देने वाले संस्थानों की सूची (परिशिष्ट–v पर है)।

एशिया तथा प्रशांत के सहकारी एवं आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना एक क्षेत्रीय अंतर–सरकारी संगठन है। 2013–14 के दौरान, 18 कोलंबों योजना सदस्य देशों के लिए 500 प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित योजना सदस्य देशों के लिए सचिवालय के विवेकाधिकार पर प्रस्तुत 90 स्लॉट शामिल हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में

मानव संसाधन विकास, लेखा परीक्षा, एवं लेखा, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर शिक्षा, संसदीय मामले, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जल संसाधन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, वित्तीय प्रबंधन, वीमा इत्यादी शामिल है।

आईटीईसी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय है। तथापि, हाल के वर्षों में, क्षेत्रीय तथा अतर क्षेत्रीय संदर्भों में प्रकट किए गए सहयोग कार्यक्रमों के लिए आईटीईसी संसाधनों का उपयोग किया गया है, जैसा कि आसियान, बिमस्टेक, मेकोंग गंगा, सहयोग (एमजीसी), अफ्रीका हेतु आर्थिक समिति, अफ्रीकी संघ, अफ्रो–एशियन ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ), पान अफ्रीकी संसद, कैरीबियाई समुदाय (कैरीकॉम), राष्ट्रमंडल, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ, क्षेत्रीय सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र संगठन (आईओआर–एआरसी) तथा भारत अफ्रीका मंच शिखर सममेलन।

जैसा पूर्व के वर्षों में, आईटीईसी/स्काप के भूतपूर्व छात्रों के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों में यह आईटीईसी दिवस के रूप में मनाया जाता था।

विशेष पाठ्यक्रम

आईटीईसी के तहत नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, सहभागी देशों के विशिष्ट अनुरोध पर विशेष पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित/अनुसूचित किया गया। 2013–14 में, नए क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रमों का विस्तार किया गया, जैसा कि चुनाव प्रबंधन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र तथा चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईडीईएम), नई दिल्ली), सरकारी निष्पादन प्रबंधन, मित्रवत् विदेशी देशों के सिविल सेवकों का पेशामध्य प्रशिक्षण, इत्यादि। अरबी तथा स्पैनिश बोलने वाले देशों के लिए संसदीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण ब्यूरो में भारतीय संसदीय अभ्यासों पर प्रशिक्षण संचालित किया गया था। मारीशस, म्यांमा, मोजाम्बिक, भूटान तथा बांग्लादेश के कार्यकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) में डब्ल्यूटीओ केंद्र ने डब्ल्यूटीओ से संबंधित विषयों पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

रक्षा प्रशिक्षण

आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में रक्षा प्रशिक्षण सहभागी देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों में लोकप्रिय रहा है। 2013–14 के दौरान, साझीदार देशों को 1500 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किया गया है। ये पाठ्यक्रम सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के हैं तथा इनमें सुरक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, रक्षा प्रबंध, इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिकल इंजीनियरी, समुद्री जल विज्ञान, उग्रवाद रोधी और जंगल युद्ध पद्धति तथा साथ ही तीनों सेनाओं में युवा अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली तथा रक्षा सेवा स्टॉफ महाविद्यालय, वेलिंगटन में प्रमुख रक्षा पाठ्यक्रमों में काफी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा विकसित देशों से स्व–वित्तपोषित आधार पर अधिकारी भी आकर्षित हुए हैं।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा–परीक्षण, विविध विशेषज्ञता, कृषि, औषद्य विज्ञान, सांख्यिकी एवं जन सांख्यिकी, लोक प्रशासन, तथा वस्त्र सहित अन्य क्षेत्रों में परामर्श देने तथा विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए विभिन्न नागरिक तथा रक्षा क्षेत्रों से 34 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे। लाओस, मारीशस, सेशल्स, इथोपिया, लेसोथो, नामीबिया, युगांडा तथा वियतनाम ने प्रशिक्षण व सलाहकार क्षमताओं मे रक्षा दलों की सेवाएं प्राप्त की थी। विशेषज्ञें की प्रतिनिधियुक्ति से सहयोगी देशों में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का निर्माण करने में सहायता मिली है।

निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन

14

निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग (आईटीपी) मंत्रालय के आर्थिक राजनय को निश्चित रणनीति तथा केंद्र बिंदु प्रदान करता है। यह प्रादेशिक प्रभागों, मिशनों तथा केंद्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों की श्रृखंला तथा शीर्ष उद्योग संगठनों के सथ समन्वय करते हुए निवेश तथा व्यापार संवर्धन कार्यकलापों का समर्थन करके प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सहित व्यापार एवं विदेश निवेश अन्तर्वाह का प्रोत्साहन करता है। यह वित्त, वाणिज्य, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अन्य के बीच शिक्षा के साथ संपर्क रखने वाले मंत्रालयों का नीतिगत मुद्दों पर सूचना प्रदान करता है तथा इन मंत्रालयों द्वारा गठित समितियों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी करता है।

मंत्रालय के बजट शीर्ष के बाजार विस्तार कार्यकलापों के तहत, इस प्रभाग ने वर्ष 2013–14 में, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों को, निर्यात तथा निवेश बढ़ाने पर लक्ष्य किए गए उनके संवर्धन प्रयासों का समर्थन करने के लिए, 5 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। वाणिज्य विभाग की बाजार अभिगम उपक्रमण (एमएआई) योजना पर एक अधिकार प्राप्त सदस्य के रूप में, इस प्रभाग ने निर्यात संवर्धन कार्यकलापों तथा व्यापार मेलों के लिए इनपुट प्रदान किया है, जिसका इस वर्ष के दौरान उपयोग किया जाएगा।

यह प्रभाग, आर्थिक कार्यविभाग के विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड में मंत्रालय का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो, विदेशी बैंकों के भारत में शाखा खोलने तथा भारतीय बैंकों के विदेशों में शाखा खोलने पर वित्तीय सेवा विभाग के स्वचालित मार्ग तथा अंतर–मंत्रालयी समिति द्वारा जो शामिल नहीं है उन विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों का कार्य देखता है। आईटीपी तथा विधिक व संधि प्रभागों ने, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करारों (बिप्पा) के मॉडल टेक्सट में संशोधन हेतु गठित समिति पर विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रभाग ने यूएई तथा संयुक्त राज्य के साथ बिप्पा संधि वार्ता में भी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था।

आईटीपी, विदेशों/वायु मार्गों के साथ वायु सेवा करारों (एएसए) से संबंधित सभी मामलों तथा इन मामलों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ निकटता से कार्य करने हेतु, मंत्रालय का एक मॉडल प्रभाग है। आईटीपी प्रभाग ने, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई तथा वियतनाम के साथ आयोजित द्विपक्षीय वायु सेवा वार्ता और दिसंबर 2013 मे डरबन मे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि सम्मेलन में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

आईटीपी प्रभाग, भारत तथा यूएई के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टासक फोर्स (एचएलटीएफ) की 3 मार्च, 2014 को मुंबई में आयोजित द्वितीय बैठक मे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व मे गए प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा था।

इस प्रभाग ने, कैबिनेट सचिवालय के संरक्षण में गठित परियोजना मॉनीटरिंग समिति तथा पोर्ट परियोजनाओं पर जहाजरानी मंत्रालय की समिति पर विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, आईटीपी प्रभाग ने परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद तथा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की कार्य समितियों पर भी कार्य किया था। इसके साथ–साथ, सचिव (आर्थिक संबंध) ने एक्जिम बैंक तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), निवेश भारत तथा ग्लोबल इन्नोवेरान एण्ड टेक्नॉलॉजी अलायंस (जीआईटीए) के बोर्ड मे सरकार की ओर से नामिति के रूप में संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी सेवा जारी रखी।

मई, 2013 में, आईटीपी प्रभाग ने निर्यात संवर्धन परिषद तथा एपेम्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बैठक की मेजबानी की, जिसमें 26 निर्यात संवर्धन परिषदों तथा 4 एपेम्स बिजनेस चैंबर्स ने भाग लिया था। जून, 2013 में, इस प्रभाग ने टेलीकॉम उपकरण तथा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) के साथ सहयोग से टेलीकॉम क्षेत्र पर बैठक की मेजबानी की, जिसमें आवासीय राजदूतों/उच्चायुक्तों ने भाग लिया। आईटीपी प्रभाग के सहयोग से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 19 नवंबर, 2013 को "कांफ्रेंस ऑन अफ्रीका–ए लैंड ऑफ ऑपोरच्यूनिटी" को मेजबानी की। विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से सीआईआई ने 9–10 दिसम्बर, 2013 को दो दिनों के "सीआईआई भारत लेटिन अमरीका तथा कैरीबियाई कॉनक्लेव" शिखर सम्मेलन आयोजित करने में फिक्की (एफआईसीसीआई) की सहायता की, जो मार्च 2014 में आयोजित की गई।

आईटीपी प्रभाग की वेबसाइट इंडिया इन बिजनेस ने भारतीय

अर्थव्यवस्था, नई नीति उपक्रमण, स्थिति के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों, इत्यादि की वर्तमान स्थिति पर सूचना उपलब्ध कराना जारी रखा है। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वाणिज्यिक मुद्दों पर साप्ताहिक तथा मासिक न्यूजलेटर भेजा जाता है जो उन्हें समयबद्ध अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है।

आईटीपी प्रभाग के वार्षिक प्रकाशन का नवीनतम संस्करण "इंडिया इन बिजनेस" का 10 जनवरी,2014 को विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह द्वारा विमोचन किया गया था। इस वर्ष का संस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ–साथ कर तथा विनियामक आयामों का ओवरव्यू प्रदान करता है। तथा विदेशी सीधे निवेश की विधिक, प्रशासनिक तथा अनुपालन आयामों को भी शामिल करता है। इस प्रकाशन का 10 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है तथा विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों को भेजा जा रहा है।

■■

ऊर्जा सुरक्षा

15

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग, विदेश मंत्रालय में ऊर्जा संबंधित मामलों के लिए नोडल बिंदु तथा समन्वयन प्रभाग के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा सुरक्षा के अलावा, इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों के चार्टर में देश की खाद्य सुरक्षा, उर्वरक तथा खनिज संसाधन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। यह पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, खान, स्टील, कृषि, खाद्य व उर्वरक सहित कई मंत्रालयों व विभागों के साथ निकट समन्वय भी बनाए रखता है तथा ऊर्जा/उर्वरक/ खनिज संसाधन हेतु विदेशी आपूर्त्ति को और अधिक विविधता प्रदान करने के उनके प्रयासों में सहायता करता है।

भारत ने, 13–14 जनवरी, 2013 को आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) की तीसरी महासभा बैठक में भाग लिया। भारत ने नई दिल्ली में अप्रैल, 2013 में क्लीन एनर्जी मिनिसटेरियल (सीईएम) की मेजबानी की। भारत ने 6–7 मई, 2013 को सिओल में आईपीईईसी पर आयोजित 7वीं नीति समिति बैठक में भाग लिया था। भारत ने 27–29 मई, 2013 को ब्लादीवोस्टक में एशिया–प्रशांत ऊर्जा मंच की पहली बैठक में भाग लिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ. वीरप्पा मोइली ने 10 सितंबर, 2013 को टोकियो, जापान में आयोजित दूसरी एलएनजी उत्पादक–उपभोक्ता सम्मेलन तथा 11–12 सितंबर,2013 को सिओल, दक्षिणी कोरिया में आयोजित 5वीं एशियन मंत्रालयी ऊर्जा के गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी ने 25–27 सितंबर, 2013 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 7वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ कार्यकारिणी बैठक में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सचिव (विद्युत), श्री पी.के.सिंहा ने 19–20 नवंबर, 2013 को पेरिस में आयोजित द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) मंत्रालयी बैठक में भाग लिया था। बैठक के दौरान आईईए तथा विद्युत मंत्रालय संयुक्त वक्तव्य पर सहमत हुए। आईईए तथा ब्राजील,चीन,भारत,इंडोनेशिया,रूसी परिसंब तथा दक्षिण अफ्रीका साझेदारी जारी रखने में पारस्परिक हितों से संबोधित संयुक्त घोषणा पर सहमत हुए थे।

भारत ने एससीओ सदस्यों, पर्यवेक्षकों तथा वार्त साझेदारों के मंत्रालयी स्तर का ष्ऊर्जा क्लबष् बनाए जाने संबंधी ज्ञापन पर 6 दिसम्बर, 2013 को हस्ताक्षर किए। भारत ने, 17–19 दिसम्बर,2013 तक बैंकाक, थाईलैण्ड में एशिया तथा प्रशांत (एसकाप) हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कमीशन द्वारा धारणीय विकास हेतु ऊर्जा पर प्रथम नीति वार्ता में भी भाग लिया था। 18–19 जनवरी, 2014 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआईएनए) के चौथे सत्र, तथा 21 जनवरी, 2014 को प्रथम हिंद महासागर रिम एसोशिएशन (आईओआरए) नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयी मंच में भाग लेने के लिए डॉ. फारूख अब्दुल्ला, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व मे एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 18–23 जनवरी, 2014 तक आबूधाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा की।

ऊर्जा दक्षता सहयोग (आईपीईईसी) नीति समिति (पोको) के लिए 8वीं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बैठक 23–24 जनवरी, 2014 को पेरिस में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने किया था। इस प्रभाग ने, आस्ट्रेलियाई प्रेसिडेंसी के तहत मेलबोर्न में 10–13 फरवरी, 2014 को आयोजित जी–20 ऊर्जा धारणीय कार्य दल की बैठक में भाग लिया था।

द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकें

भारत–जर्मनी ऊर्जा मंच ने 11–14 फरवरी, 2013 तक अपनी बैठक का आयोजन बर्लिन में किया था। भारत ई यू ऊर्जा पैनल के तहत, 21–12 मई, 2013 को नई दिल्ली में पारेषण तथा वितरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। "तेल तथा गैस आपूर्त्ति में संवर्धन के लिए अन्य विदेशों के साथ रणनीतिक संबंधों के माध्यम से भारतीय ऊर्जा सुरक्षा" पर एक कार्यशाला 23–24 अक्तूबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान, ऊर्जा संपन्न देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा तथा सहयोग पर ईयू का अनुभव साझा किया था। आस्ट्रेलिया के साथ ऊर्जा तथा खनिज पर 8वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 11–13 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 17वें भारत–ईराक संयुक्त आयोग की बैठक 7–8 जुलाई, 2013 को बगदाद में आयोजित की गई थी।

भारत–कनाडा ऊर्जा वार्ता की शेरपा स्तर की उद्घाटन बैठक 7–10 अगस्त, 2013 तक ओटावा, कनाडा में आयोजित की गई थी। इसके उपरांत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के नेतृत्व में भारत–कनाडा ऊर्जा वार्ता का प्रथम राउंड 28 अक्तूबर, 2013 को ओटावा में आयोजित किया गया था। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर रूस–भारत अंतर–सरकारी कमीशन के तहत उर्जा तथा उर्जा दक्षता पर रूस–भारत कार्यदल का 18वां सत्र 3 अक्तूबर, 2013 को मास्को में आयोजित किया गया जिसके दौरान उर्जा दक्षता ब्यूरो तथा रूसी उर्जा एजेंसी के बीच उर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर कार्य आरंभ किया गया था। 21 अक्तूबर, 2013 को 14वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। पेट्रोटेक 2014 के साथ, जनवरी, 2014 में आयोजित द्विवार्षिक बैठक के दौरान डॉ. एम.वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री तथा लीबिया, यूएई, बहरीन, कनाडा, इक्वेडोर, युगांडा, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबेजान, ओजाम्बिक तथा प्रीमीयर ऑफ अलबर्टा के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों के दौरान, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के क्षेत्र मे सहयोग को और अधिक संवर्धित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया था। भारत–यूएसए उर्जा वार्ता 11 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 7वां भारत–ईयू उर्जा पैनल बैठक 27 मार्च, 2014 को ब्रूसेल्स में आयोजित की गई थी। दूसरे भारत आस्ट्रेलिया उर्जा वार्ता 31 मार्च, 2014 को ब्रिसबेन (आस्ट्रेलिया) में आयोजित की गई थी।

तापी (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना

इस प्रभाग ने तापी पाइपलाइन परियोजना पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा गेल के साथ निकटता से समन्वय किया था। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री ने 9 जुलाई, 2013 को असघाबात में तापी परियोजना के लिए संचालन समिति की 17वीं बैठक में भाग लिया था। तापी परियोजना के लिए तकनीकी कार्य दल की 25वीं बैठक 27 फरवरी, 2014 को दुबई में आयोजित की गई थी। तापी लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) सभी चार देशों द्वारा बनाई गई तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड ने इस एसपीवी में भारत की ओर से जुड़ गया। यह परियोजना संकाय लीडर के चयन के लिए प्रतीक्षारत है, जो इस पाइपलाइन को बनाएगा तथा परिचालित करेगा।

उर्जा क्षेत्र के साथ बातचीत

इस प्रभाग ने, भारत में परिचालित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया। ये बैठकें मंत्रालय की ओर से आउटरीच प्रयास हैं तथा यह प्रभाग को इस मंत्रालय के दृष्टिकोण, प्रतिपुष्टि तथा समर्थन व्यक्त करने में तथा इसके मिशनों/केंद्रों को उर्जा/उर्वरकों/मिनरल इत्यादि के क्षेत्र में उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता करता है। विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों से तेल तथा गैस अवसरों पर प्राप्त सूचना इस दल के सदस्यों के साथ साझा किया गया था।

3 सितम्बर, 2013 को फिक्की (एफआईसीसीआई) तथा इस प्रभाग द्वारा उर्जा सुरक्षा पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने यहां उद्घाटन भाषण दिया था। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा सीआईआई के सहयोग से दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 27 नवंबर 2013 को आयोजित किया गया था। इस प्रभाग ने टेरी (टीईआरआई) द्वारा आयोजित ग्लोबल गैल सिनारियों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था।

इस प्रभाग ने कई मंत्रालयों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता भी की है तथा इन सम्मेलनों में उच्च स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित करने में मिशनों/केंद्रों के साथ समन्वय करने का प्रयास भी किया है। 2013 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, दिसम्बर,2013 में 8वां एशिया गैस साझेदारी शिखर सम्मेलन व द्विवार्षिक, अंतर्राष्ट्रीय ऑयल एण्ड गैस कांफ्रेंस तथा प्रदर्शनी, ग्रेटर नोएडा तथा नई दिल्ली में इंडिया एक्सपो सेंटर व मार्ट में 12–15 जनवरी, 2014 के दौरान पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण के तहत आयोजित पेट्रोटेक 2014 शामिल है। 12 जनवरी, 2014 को इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

मिशनों तथा केंद्रों को उपस्करों से लैस करने तथा विभिन्न पणधारकों को सुग्राही बनाने के प्रयास में, इस प्रभाग ने सुसंगत अनुसंधान दस्तावेजें व सामग्रियों भी निकाली हैं। इस प्रभाग ने उर्जा सुरक्षा 2013 पर चार अनुसंधान रिपोर्टों को अधिकृत किया है, जिसमें (क) सार्क–जनिक क्षेत्र में प्रचेलित रिस्क एवर्स एटीट्यूड को परिवर्तित करने के मार्ग व तरीकों (ख) संसाधन संपन्न देशों में संभार तंत्र नियंत्रण (ग) विशिष्ट तकनीकों का अभिगम तथा उसकी पहचान करना (घ) उर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में पड़ोसी देश के साथ सहयोग पर अनुसंधान दस्तावेज शामिल हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने मैट्रिक्स तैयार करने पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर भारत खनिज देशों से हाइड्रोकार्बन तथा उर्वरक का आयात करता है, उन देशों को निर्यात कर सकता है। इस प्रभाग ने, 18–19 अप्रैल, 2013 को कंपाला, युगांडा में आयोजित मिशनों के प्रादेशिक प्रमुखों के सम्मेलन (पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका तथा पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों के लिए) तथा 7–8 नवंबर, 2013 के बहरीन में आयोजित (पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा खाड़ी क्षेत्रों के लिए) बहरीन में आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिया था।

आतंकवाद विरोध एवं नीति नियोजन

16

आतंकवाद विरोध (सीटी)

भारत ने, वर्ष के दौरान आतंकवाद निरोध (सीटी) पर भागीदार देशों के साथ संयुक्त कार्य दल के माध्यम से, अपनी अवसंरचनात्मक वार्ता जारी रखी है। भारत ने निम्नलिखित देशों/संगठनों के साथ संयुक्त कार्य दल आतंकवाद निरोध का आयोजन कियाः–

क्रम. सं.	देश/संगठन का नाम	तारीख	स्थान
1.	इस्रायल	20 फरवरी, 2013	नई दिल्ली
2.	चीन	10–12 अप्रैल, 2013	बीजिंग
3.	बिमस्टेक	8–9 मई, 2013	कोलंबों
4.	इंडोनेशिया	6 जून, 2013	नई दिल्ली
5.	कनाडा	10–11 दिसम्बर, 2013	ओटावा
6.	उजबेकिस्तान	27–28 फरवरी, 2014	ताशकंद

भारत, वैश्विक आतंकवाद निरोध मंच (जीसीटीएएफ) के 30 संस्थापक सदस्यों मे से एक है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। जीसीटीएफ नागरिक क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञ तथा संसाधन जुटाने की तथा आपराधिक न्याय प्रणाली व अति हिंसा निरोध जैसे क्षेत्रों में नियामकों को प्रस्तुत करने की मांग करता है। वर्तमान में जीसीटीएफ में पांच कार्यदल हैं जो निम्नलिखित कार्य देखते हैं। (i) आपराधिक न्याय/विधिक नियम; (ii) अतिहिंसावाद निरोध; (iii) साहेल में क्षमता निर्माण; (iv) अफ्रीका क्षेत्र के हॉर्न में क्षमता निर्माण तथा (v) दक्षिण पूर्व एशिया में क्षमता निर्माण।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान

नीति नियोजन तथा अनुसंधान के अधिकार क्षेत्र में, इस प्रभाग ने, विदेश नीति पर अनुसंधान तथा प्रबंध में शामिल भारत शैक्षिक जगत, विचारक–मंडल, अनुसंधान संगठनों तथा विदेश नीति संस्थानों को अपना समर्थन देना जारी रखा है, तथा भारत के बाह्य संबंधों के विभिन्न पहलूओं पर विचार–विमर्श करने के लिए सेमिनारों, सम्मेलनों तथा शिक्षा आयोजित करने हेतु उनकी वित्तीय सहायता की है। प्रभाग के ऐसे आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से, मंत्रालय ने नया सापेक्ष प्राप्त किया है तथा विदेश नीति तथा वैश्विक कार्यों के कई क्षेत्रों पर विशेषज्ञों की राय की सूचना दी है। प्रभाग द्वारा अंतशः/पूर्णतः अनुदान प्राप्त सेमीनारों, सम्मेलनों तथा शिक्षा, जो देश के विभिन्न संस्थानों में आयोजित की गई है, उसकी सूची परिशिष्ट–टप पर दी गई है।

इस प्रभाग ने विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव के लिए भाषण का मसौदा तैयार किया था। इस प्रभाग ने कैबिनेट के लिए विदेश मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों/घटनाओं का मासिक सार तैयार करना तथा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से संकलन, छपाई तथा वितरण करना जारी रखा है। इस प्रभाग ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन के 2014 के संस्करण के अध्याय ष्भारततथा विदेशष की सामग्री का मिलान तथा संकलन किया है। इस प्रभाग ने 13 मार्च, 2014 को विदेश सचिव के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जिसके लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है। इस प्रभाग ने, फरवरी, 2014 में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों को परिचालित किए जाने हेतु "विदेश मंत्रालय के कार्यकलापों का संक्षिप्त सार" पर एक बुकलेट भी तैयार किया।

स्थिति कक्ष

स्थिति कक्ष इस मंत्रालय का बहु–आयामी, बहुविध संपन्न तथा अत्याधुनिक परिसर है। मंत्रालय के संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ के रूप में इसकी मुख्य भूमिका के अलावा, सभी प्रभागों द्वारा टेलीफोन/वीडियों कांफ्रेंसिंग, इत्यादि सहित प्रस्तुतीकरण तथा कांफ्रेंसों जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभावी रूप से इस परिसर का उपयोग किया जाता है। 17 मिशनों में वीडियों क्रांगेसिंग सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

सीमा प्रकोष्ठ

सीमा प्रकोष्ठ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के समन्वय से भारत की बाह्य सीमाओं के सभी पहलूओं की जांच तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित सभी मानचित्रों के प्रकाशन की जांच करता है। यह विदेश मंत्रालय के अन्य प्रभागों को सीमा से संबंधित मामलों पर नक्शानवीसी परामर्श तथा तकनीकी मूल मानचित्रों के संकलन तथा डिजिटलाइजेशन में सहायता करता है। यह प्रकोष्ठ सीमा खम्बों के अनुरक्षण/मरम्मत तथा भारतीय भू–भाग के अतिक्रमण की रिपोर्टों

(डाटाबेस इत्यादि के रख–रखाव सहित संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य सरकारों के साथ संपर्क करने का कार्य भी करता है। यह समुद्री जल सीमा से संबंधित सूचना के संकलन तथा डिजिटलाइजेशन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तथा महाद्वीपीय जलमग्न तट के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करता है। यह रक्षा मंत्रालय के समन्वयन से प्रतिबंधित मानचित्रों की शीट की संविक्षा तथा नौसेना जलविज्ञान कार्यालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित सभी मानचित्रों/दस्तावेजों/सूचनाओं का संग्रह केंद्र है। सीमा प्रकोष्ठ ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा (भू–भाग तथा समुद्र तटीय) पर विभिन्न आंतरिक/अंतर–मंत्रालयी बैठकों में भी भाग लिया है।)

■■

नयाचार

17

विदेश मंत्रालय का प्रोतोकॉल प्रभाग ने राज्य प्रमुख के जनवरी 2013 से मार्च, 2014 के दौरान उपराष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री के स्तर पर 106 भारत आने वाली तथा 19 बाहर जाने वाली यात्राओं का समन्वय किया था। 2013 तथा 2014 में यात्राओं के कैलेण्डर की सूची (मार्च 2014 तक) निम्नलिखित है।

प्रोतोकॉल प्रभाग ने इन बहुपक्षीय सम्मेलनों/बैठकों के आयोजन का समन्वय किया– लोकतांत्रिक समुदाय के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन (17–18 जनवरी, 2013); 15वां आसिया ने भारत वरिष्ठ कार्यकारी बैठक (21 फरवरी, 2013); एसेम वरिष्ठ कार्यकारी बैठक, गुडगांव (3–4 सितंबर, 2013); एसेम वरिष्ठ कार्यकारी बैठक तथा एसेम विदेश मत्रियों की बैठक, गुड़गांव (11–12 नवंबर, 2013); दिल्ली वार्ता–टप (6–7 मार्च, 2014)।

इस अवधि के दौरान, ग्वाटेमाला तथा लातविया ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला; बेल्जियम ने चेन्नई में अपना महाकोंसुल खोला; तथा हंगरी ने बैंगलुरू, मुंबई, चेन्नई,पणजी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली,चण्डीगढ़,तिरूवनंतपुरम शहरों में 19 मानद कोंसुलेट खोलें। 37 मिशन प्रमुखों ने अपने प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति जी को सौंपें। नई दिल्ली के राजनयिक मिशनों/अतर्राष्ट्रीय संगठनों में 93 नए पद सृजित किए गए।

2013 के लिए यात्राओं का कैलेण्डर

राज्य प्रमुख/सरकार/उपराष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई राजकीय/शासकीय यात्राएं

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री राजकेरूर पुरयाग, मॉरीशस के राष्ट्रपति	3–10 जनवरी
2.	श्री जिग्मे खेसर नामजिल वांगचुक, भूटान के राजा तथा रानी जेटसुन पेमा वांगचुक	23–30 जनवरी
3.	श्री फ्रैंकोइस हॉउलैंड, फ्रांस के राष्ट्रपति	14–15 फरवरी
4.	डॉ. मोहम्मद मोर्सी, मिस्र के राष्ट्रपति	18–20 मार्च
5.	श्री ली केक्वांग, चीनी जनवादी गणराज्य के राज्य परिषद् के प्रधानमंत्री	19–22 मई
6.	श्री नूरी कामिल अल मालिकी, इराक के प्रधानमंत्री	22–25 अगस्त
7.	सुश्री एलेन जॉन्सन, लाईबेरिया के राष्ट्रपति	9–13 सितम्बर
8.	श्री विक्टोर ओर्बान, हंगरी के प्रधानमंत्री	16–18 अक्तूबर
9.	शेख जाबेराल–मुबारक अल हामाद अल–सबह, कुवैत के प्रधानमंत्री	7–10 नवंबर
10.	श्री नुएन फहु ट्रॉग, वियतनाम के कम्यूनिष्ट पार्टी के महासचिव	19–22 नवंबर
11.	जापान के सम्राट एवं साम्राज्ञी	30 नवंबर और 05 दिसम्बर

राज्य के प्रमुख/सरकार/उपराष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के द्वारा सरकारी/कार्यकारी यात्राएं

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	सुश्री आशी संगे छोड़ेन वांगचुक भूटान की राज माता	9–18 जनवरी
2.	श्री अनोट टांग, कीरीवाती के राष्ट्रपति (डीएसडीएस) के लिए	29 जनवरी से 3 फरवरी
3.	श्री डोनाल्ड रामोतार, गुयाना के राष्ट्रपति (डीएसडीएस) के लिए	30 जनवरी से 4 फरवरी

4.	श्री ल्योक्ष्ण जिग्मी बाई थिंगले भूटान के प्रधानमंत्री	7–9 फरवरी
5.	सेवानिवृत्त माननीय डेविड कैमरोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री	18–20 फरवरी
6.	सहजादा सलमान बिन हमाद अल खलीफा, बहरीन के क्राउन प्रिंस	17–18 मार्च
7.	डॉ. ओलाफर रगनार ग्रिमशन, आईसलैंड के राष्ट्रपति	31 मार्च से 6 अप्रैल
8.	श्री पुष्पकमल डहल,नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री	27–30 अप्रैल
9.	श्री हामिद करजई, अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति	20–22 मई
10.	श्री जोसेफ आर विडेन जूनियर, संयुक्त राज्य अमेरीका के उप राष्ट्रपति	22–25 जुलाई
11.	श्री मोहम्मद करीम खलीली, अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति	20–23 अगस्त
12.	श्री ल्योंक्ष्ण सेरिंग टोबग। भूटान के प्रधानमंत्री	30 अगस्त से 4 सितम्बर
13.	दा आगा खान,	17–28 सितम्बर
14.	द प्रिंस ऑफ वेल्स	6–14 नवम्बर
15.	श्री डेविड कैमरून, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री	13–14 नवम्बर
16.	श्री हामिद करजई, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	12–15 दिसम्बर

विदेश मंत्री तथा समकक्षों के द्वारा सरकारी यात्राएं

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री दाई बिनगुओ, राज्य पार्षद, चीन	9–12 जनवरी
2.	श्री लवसनबंडन बोल्ड, मंगोलिया के एफएम	15–17 जनवरी
3.	सिनेटर बॉब का, ऑस्ट्रेलिया के एफएम	19–22 जनवरी
4.	श्री राशिद मेरेडोव, तुर्कमेनिस्तार के उप प्रधानमंत्री तथा एफएम	21–22 जनवरी
5.	प्रो. जीएल पेरिस, श्रीलंका के एफएम	21–22 जनवरी
6.	श्री जीम पॉल एडम, सेशल्स के एफएम	30 जनवरी से 3 फरवरी
7.	श्री कमलेश शर्मा, एसजी राष्ट्रमंडल	6–10 फरवरी
8.	श्री उर्मश पाएट, एसटोनिया के एफएम	12–13 फरवरी
9.	श्री पॉलो साकाडुरा कबराल पोर्टस, पुर्तगाल का एफएम	3–8 मार्च
10.	श्री एर्रलान इद्रीसोव, कजाकिस्तान के एफएम	3–5 मार्च
11.	डॉ. बोथानिया शवान, सीरियाई राष्ट्रपति के विशेष दूत	5–9 मार्च
12.	श्री टाइट कारलाटियन रोमानिया के एफएम	7–8 मार्च
13.	शेख नासर, कुवैत से मंत्री	10–14 मार्च
14.	डॉ. ज्लाट को लगुमडीजा, मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष तथा बोस्निया तथा हर्जेगुविना के विदेश मंत्री तथा श्रीमती अमिना लगुमडीजा	24–28 मार्च
15.	श्री एलमार मम्मादयारोव, अजर्बेजान गणराज्य के विदेश मंत्री तथा श्रीमती कमलिया मम्मादायारोव	2–5 मई
16.	श्री एर्की तुओमियोजा, फिनलैंड के विदेश मंत्री	6–8 मई
17.	श्री ब्रुनो एडुआर्डो रौडरिग्ज पारिला, क्यूबा गणराज्य के विदेश मंत्री	25–28 मई
18.	श्री मुर्रे मकुले न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री	4 जून
19.	श्री हेक्टर मार्कोस टाइमर मैन, अर्जेटीना गणराज्य के विदेश तथा वर्शिप मंत्री	15–18 जून

20.	श्री मीरो स्लाव लैजकैक, स्लोवाक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश एवं यूरोपीय कार्य मंत्री	17–20 जून
21.	श्री जॉन एफ केरी, संयुक्त राज्य अमरीका के राज्य सचिव	23–25 जून
22.	श्री फाम–बिन–मिन, मियतनामी समाजवादी गणराज्य के विदेश मंत्री	10–12 जुलाई
23.	श्री दीपू मोनी, बांग्लादेश लोक जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्री	25–27 जुलाई
24.	श्री के सांमुगम, सिंगापुर गणराज्य के विदेश तथा कानून मंत्री तथा डॉ. सुब्बाय्या सीता लक्ष्मी	28–30 जुलाई
25.	श्री मुसा फाकी महामत, चाड के विदेश मंत्री	12–13 अगस्त
26.	प्रो. जी एल पेरिस, श्रीलंका के विदेश मंत्री	18–19 अगस्त
27.	श्री सेमुअल संटोस लोपेज, निकारागुआ के विदेश मंत्री	20–23 अगस्त
28.	श्री तोकेलिना फिनीकासो, तुबालू के विदेश मंत्री	21–25 अगस्त
29.	श्री एडगर्स रिंकेविक्स, लातीबिया के विदेश मंत्री	14–20 सितम्बर
30.	जुली बिसप, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री	15–18 नवंबर
31.	श्री कमलेश शर्मा, महासचिव राष्ट्रमंडल	18–22 नवंबर
32.	श्री नबिल फहमी, मिस्र के विदेश मंत्री	4–6 दिसम्बर
33.	शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन, यूएई के विदेश मंत्री	11–12 दिसम्बर
34.	श्री निकोला पोपोस्की, मैसीडोनिया के प्रधानमंत्री	16–18 दिसम्बर
35.	श्री नबिन इलाराबी, अरब राज्यों के लिग के महासचिव	16–18 दिसम्बर
36.	श्री एलियास गउआ मिलानो, वेनेजुएला के विदेश मंत्री	19–21 दिसम्बर

राज्य के प्रमुखों/सरकारी/उप राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला व समकक्ष स्तर की निजी/पारगमन यात्राएं।

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री ल्योनक्षेण जिग्मी वाई थिनले, भूटान के प्रधानममंत्री	28 जनवरी
2.	सुश्री आशी दोर्जी वांगमों वांगचुक, भूटान की राजमाता	6–21 फरवरी
3.	श्री महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति	8–9 फरवरी
4.	श्री राजा परवेज अशरफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री	9 मार्च (जयपुर/अजमेर)
5.	श्री एडवर्ड किवानुका सेकानी, युगाण्डा के उप राष्ट्रपति (सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–20 मार्च
6.	श्री डेनियल काबलान डंकन, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री (सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–19 मार्च
7.	डॉ. गाय सकॉट, जाम्बिया के उप राष्ट्रपति (सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–20 मार्च
8.	श्री रूई दुआर्ते बैरोस गिनी विसाऊ के प्रधानमंत्री सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–20 मार्च
9.	श्री जोसेफ एन बोआकी, लाईबेरिया के उप राष्ट्रपति सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–24 मार्च
10.	श्री फिलेमोन यांग, कैमरून के प्रधान मंत्री सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	16–19 मार्च
11.	श्री जेरवाईस रूफीकिरी, बुराण्डी के उप राष्ट्रपति सीआईआई एक्जिम बैंक कनक्लेव)	17–20 मार्च
12.	श्री स्प्रेंट दबविडो नाउरू के राष्ट्रपति	16–30 मार्च
13.	श्री ओलाण्टा हुमाला टासो, पेरू के राष्ट्रपति (पारगमन)	5 और 9 अप्रैल
14.	श्री पुष्प कमल दहल, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री	27–30 अप्रैल
15.	माननीया सुश्री बुसुमी डेनाइस, बुरूण्डी गणराज्य की प्रथम महिला	13–16 मई
16.	माननीय श्री शेर महादुर देउबा, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री	9–14 जून

17.	सुश्री सैण्ड्रा रोलॉफ्स, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री	20–22 जून
18.	श्री माधव कुमार, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री	24–28 जुलाई
19.	बेल्जियम की राजकुमारी आस्ट्रीड	23–30 नवंबर
20.	भूटान की दादी	6–26 दिसम्बर
21.	श्री राजकेश्वर पुरयाग, मॉरीशस के राष्ट्रपति	12–19 दिसम्बर

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

क्रम सं.	प्राधिकारी	दिनांक
1.	उपराष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा	14–17 जनवरी
2.	राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा	3–5 मार्च
3.	राष्ट्रपति की मॉरीशस यात्रा	11–13 मार्च
4.	प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा	25–28 मार्च
5.	प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा	10–12 अप्रैल
6.	उपराष्ट्रपति की तजाकिस्तान यात्रा	14–17 अप्रैल
7.	उपराष्ट्रपति की उजबेकिस्तान यात्रा	21–24 मई
8.	उपराष्ट्रपति की इथोपिया यात्रा	25–26 मई
9.	प्रधानमंत्री की जापान तथा थाइलैंड की यात्रा	27–31 मई
10.	उपराष्ट्रपति की इरान यात्रा	4–5 अगस्त
11.	प्रधानमंत्री की सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा	4–7 सितम्बर
12.	प्रधानमंत्री की यूएसए यात्रा	24 सितम्बर से 01 अक्तूबर
13.	राष्ट्रपति की बेल्जियम तथा तुर्की यात्रा	2–8 अक्तूबर
14.	प्रधानमंत्री की ब्रुनेई तथा जकारा यात्रा	9–12 अक्तूबर
15.	प्रधानमंत्री की रूस तथा चीन यात्रा	20–24 अक्तूबर
16.	उपराष्ट्रपति की पेरू,क्यूबा तथा यू.के यात्रा	2 नवंबर
17.	राष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका यात्रा	10–11 दिसम्बर

2013 में विदेश मंत्री की विदेश यात्रा

क्रम सं.	यात्रा किया गया देश	दिनांक
1.	पेरिस	9–11 जनवरी
2.	थिफ्पू	14–15 जनवरी
3.	बर्लिन (जर्मनी) और ब्रुसेल्स	27–31 जनवरी
4.	चीली और अर्जेटीना	4–10 फरवरी
5.	ढाका	16–17 फरवरी
6.	अबुधावी	12–13 मार्च
7.	टोकि;ो ञजापान)	26–27 मार्च
8.	बनलन ञजर्मनी)	9–12 अप्रैल
9.	कम्पाला ञयूगाण्डा)	17–20 अप्रैल

10.	टलमाती (कजाकिस्तान) औरमास्को (रूस)	25–30 अप्रैल
11.	तेहरान और एसफाहान (ईरान)	3–5 मई
12.	बीजिंग (चीन)	9–10 मई
13.	जेद्दाह (साऊदी अरब)	24–27 मई
14.	बैंकाक (थाईलैंड)	29–31 मई
15.	ओस्लो (नार्वे) तथा ऑक्सफोर्ड (यू के)	11–14 जून
16.	ब्गदाद (इराक)	19–20 जून
17.	बंदर सेरी बेगावान (ब्रुनेई) तथा सिंगापुर	29 जून से 5 जुलाई
18.	काठमांडु (नेपाल)	9 जुलाई
19.	बुडापेस्ट ञहंगरी)	14–16 जुलाई
20.	इस्तांबुल तथा अंकारा ञतुर्की)	23–25 जुलाई
21.	लाओ पीडीआर	8–10 सितम्बर
22.	बिशकेक, ताशकंद तथा समरकंद	12–15 सितम्बर
23.	कनाडा,यूएसए तथा रूस	21 सितम्बर से 4 अक्तूबर
24.	श्रीलंका	7–8 अक्तूबर
25.	इण्डोनेशिया	10–12 अक्तूबर
26.	ब्रासिलिया	14–17 अक्तूबर
27.	मनीला तथा सिंगापुर	20–24 अक्तूबर
28.	पर्थ, ऑस्ट्रेलिया	30 अक्तूबर से 2 नवंबर
29.	श्रीलंका	13–17 नवंबर
30	बहरीन	7–9 दिसम्बर

2014 की यात्राओं का कैलेण्डर

राज्य प्रमुख / सरकारी / उपराष्ट्रपति तथा समकक्षों की सरकारी यात्रा।

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुम, मालदीव के राष्ट्रपति तथा श्रीमती फातिमाथ इब्राहिम	1–4 जनवरी
2.	सुश्री पार्क ग्यून ह्ये, आरओके की राष्ट्रपति	15–18 जनवरी
3.	श्री जोआचिम गाउक, जर्मनी के राष्ट्रपति	4–9 फरवरी
4.	बहरीन के राजा हमाद बिन इसा अल खलीफा	18–20 फरवरी
5.	डेविड जॉन्सटन, कनाडा के गवर्नर जनरल	22 फरवरी से 2 मार्च

राज्य प्रमुखों / सरकारी / उपराष्ट्रपति समकक्षों की सरकारी / कार्यकारी यात्राएं।

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	जिग्मे खेसर नामजिल वांगचुक, भूटान के राजा तथा रानी जेटसून पेमा वांगचुक	6–10 जनवरी
2.	श्री शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री तथा श्रीमती अकी आबे	25–27 जनवरी
3.	डॉ. अली मुहम्मद शेन, जंजीबार के राष्ट्रपति	1–9 फरवरी
4.	थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री शिरीनधौर्न	23–28 फरवरी
5.	क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल्लअजीज अल सौद, साऊदी अरब के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री	26–28 फरवरी

विदेश मंत्री तथा समकक्ष स्तरों की सरकारी यात्रा।

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री मनकियूर निदाय, सेनेगल के विदेश मंत्री	14–16 जनवरी
2.	श्री माधव कुमार घीमेरे, नेपाल के विदेश मंत्री	14–16 जनवरी
3.	प्रो. जीएल पेरिस, श्रीलंका के विदेश मंत्री	28–30 जनवरी
4.	रातु इनोके कुबुआबोला, फिजी के विदेश मंत्री	9–12 जनवरी
5.	यांग जीएची, चीन के एस आर	10–12 जनवरी
6.	श्री दीमित्री फेडोरोबिच मेजेंटसेव, एस जी, संघाई सहयोग संगठन	23–25 फरवरी
7.	श्री दीमित्री रोगोजिन, रूसी संघ सरकार के उपाध्यक्ष	26– फरवरी
8.	डॉ. मोहम्मद जावेद जारीफ, ईरान के विदेश मंत्री	27–28 फरवरी
9.	श्री युसूफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला, ओमान के विदेश मंत्री	27–फरवरी से 01 मार्च
10.	श्री जॉन डब्ल्यू एशे, यूएनजीए के राष्ट्रपति	19–22 मार्च

राज्य के प्रमुखों/सरकारी/उप राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला व समकक्ष स्तर की निजी/पारगमन यात्राएं।

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	श्री आमिद करजई, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	5 मार्च
2.	लेसोथो के प्रधानमंत्री	7–10 मार्च

भारत में राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

क्रम सं.	पदाधिकारी	दिनांक
1.	बिमस्टेक के लिए म्यांमा के प्रधानमंत्री	3–4 मार्च
2.	काबुल के उपराष्ट्रपति	11– मार्च

2014 में विदेश मंत्री की विदेश यात्रा।

क्रम सं.	जिस देश की यात्रा की गई	दिनांक
1.	जिनेवा	21–23 जनवरी
2.	मोरक्को,ट्यूनिस,सुडान,	29–जनवरी से 5 फरवरी
3.	कंधार,	15– फरवरी
4.	माले	19–21 फरवरी
5.	ने पी ताओ ञम्यांमा)	2–4 मार्च
6.	लंदन,यू.के	12–14 मार्च
7.	अम्सटर्डम, द हेग	23–26 मार्च

कोंसली, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ

18

विदेश मंत्रालय का कोंसुली, पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग सेवा केंद्रों (पीएसके) के अपने नेटवर्क के माध्यम से पासपोर्ट सेवा प्रदान करता है तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों के माध्यम से विदेश में रहने वाले भारतीय/विदेशी राष्ट्रिकों को कोंसुली वीजा तथा पासपोर्ट सेवा प्रदान करता है।

पासपोर्ट सेवाएं

हाल के वर्षों में, पासपोर्ट जारीकरण, सरकार द्वारा दी जा रही प्रमुख तथा प्रत्यक्ष सांविधिक/सार्वजनिक सेवाओं में से एक सेवा के रूप में उभरी है। भारतीय पासपोर्ट (तिब्बति शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाणपत्रों जैसे अन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ, भारत में वापसी के लिए आपात प्रमाणपत्र, पुलिस निकासी प्रमाण पत्र तथा जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा अनुमति) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन तथा इसके 37 पासपोर्ट कार्यालयों के इसके नेटवर्क सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 77 पीएसके तथा कार्यात्मक/आने वाली 16 पासपोर्ट सेवा लघु केंद्रों को जोड़कर पासपोर्ट कार्यालय के विस्तारित शाखाओं के रूप में इस नेटवर्क का अत्यधिक विस्तार किया गया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को कोंसुली दस्तावेजों के सत्यापन को छोड़कर पासपोर्ट,ओसीआई कार्ड, पीआईओ कार्ड तथा अन्य कोंसुली सेवाएं 180 भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है।

पासपोर्टों की बढ़ती मांग

पिछले छः दशकों में, पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के कार्यक्षेत्र तथा मात्रा में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। जनवरी–दिसम्बर 2013 के दौरान, मंत्रालय ने लगभग 97 लाख पासपोर्ट तथा संबंधित सेवा आवेदनों पर कार्य किया है। 37 पासपोर्ट कार्यालय, मुख्यालय तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के कार्यालय ने पुलिस निकासी प्रमाण पत्रों (पीसीसी) सहित 73 लाख पासपोर्ट सेवा संबंधित आवेदन प्राप्त किया है, जिसके जवाब में 71.3 लाख पासपोर्ट तथा संबंधित दस्तावेज 2012 में 62.5 लाख की तुलना में जारी किए गए हैं (2092 राजनयिक पासपोर्ट तथा 23038 सरकारी पासपोर्ट सहित) अर्थात औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित 180 भारतीय मिशनों/केंद्रों ने 13.83 लाख पासपोर्ट, ईसी तथा अन्य पासपोर्ट संबंधित विविध सेवाएं प्रदान की है। अतः भारत सरकार ने, एक वर्ष में कुल लगभग 85.17 लाख पासपोर्ट सेवाएं प्रदान की है, जो वर्ष 2000 से तीन गुणा से अधिक की वृद्धि है।

पासपोर्ट फीस के तौर पर सरकार के राजस्व में स्थिर वृद्धि/वर्ष 2013–14 में सभी पासपोर्ट सेवाओं से कुल अपेक्षित राजस्व 1800 करोड़ रुपए है। (1600 कासेढ़ के बीई असँकड़ों से अधिक)। वित्त वर्ष 2013–14 में केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) को 438 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, जिसका गठन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1959 में किया गया था, तथा जिसके प्रमुख संयुक्त सचिव तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी हैं, जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपीलीय प्राधिकारी तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम 1978 के तहत विभाग प्रमुख के तौर पर भी कार्य करते हैं। 31 दिसंबर, 2013 तक केंद्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग की कुल स्वीकृत संख्या 2697 थी। मंत्रालय ने सीपीओ संवर्ग की पुनर्संरचना तथा विस्तार के द्वारा सीपीओ कार्मिकों के सेवा स्थितियों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिक्त उपलब्ध पदों को भर्ती नियमों की पात्रता सेवा में पदों/छूट के आवश्यक संशोधनों/पदों को कम करने के साथ तीव्र पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। मंत्रालय ने 21 मार्च, 2013 को संशोधित उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है, जिसका पूर्व निर्धारित तथा परस्पर सहमति के मानकों की तुलना में परिमित वित्तीय व्यक्ति विशेष निष्पादन पूर्व प्रभावी होगा। सीपीओ कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं की पहचान करने तथा इस प्रकार देश में बेहतर शासन में योगदान देने के उद्देश्य से पासपोर्ट पुरस्कार की स्थापना की गई, जो पासपोर्ट सेवा दिवस (24 जून) को चुने गए कार्मिकों तथा पासपोर्ट कार्यालयों को प्रतिवर्ष दी जाएगी।

भौतिक अवसंरचना

सीपीवी प्रभाग पटियाला हाउस एनेक्सी से कार्य करता है। 37 पासपोर्ट कार्यालयों में, 18 अपने स्वयं के भवनों से कार्य कर रहे हैं, 4 भारत सरकार के भवनों से तथा शेष 15 किराए के भवनों से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय की नीति के अनुसरण में सभी पासपोर्ट कार्यालयों को इनके अपने भवनों में ले जाने के लिए में स्टेट–ऑफ–आर्ट भवनों का निर्माण करने के लिए भू–खण्ड प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने अब तक 7 जगहों पर भू–खण्ड प्राप्त किया है, जो श्री नगर, अमृतसर, देहरादून, मुंबई,पुणे,भोपाल तथा जालंधर है। जालंधर में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अमूतसर में हाल ही में निर्माण कार्य शुरू हुआ है। पासपोर्ट कार्यालय, सूरत अपने नव निर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया है। (विदेश मंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया था)। पीओ भोपाल जो एक जीर्ण–शीर्ण भवन से कार्य कर रहा था, उसे राज्य सरकार के भवन में किराए पर लेकर एक नए सुसज्जित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मुंबई में नए पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण कार्य समापन के करीब है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफल कार्यान्वयन

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) एक महत्वाकांक्षी मिशन मोड परियोजना है जो सफलतापूर्वक पीपीपी मोड में तथा सेवा प्रदाता के तौर पर टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के साथ राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के रूप में भी सफलतापूर्वक चल रहा है। 2011–12 के दौरान पूरे देश में सफल रोल–आउट के पश्चात्, वर्तमान में यह योजना 14 जून, 2012 से प्रचालन तथा रख–रखाव दौर में है।

सर्वोत्तम श्रेणी सुविधाओं के साथ 77 पीएस के 37 पीओ के विस्तारित भुजाओं के रूप में देश भर में स्थापित किया गया है, इस प्रकार पासपोर्ट आवेदकों को विस्तारित अभिगम प्रदान कर रहा है। 24स7 का राष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जो टॉल फ्री नंबर का उपयोग करने (1800–258–1800) पर 17 भाषाओं में वास्तविक समय स्थिति तथा अद्यतन सूचना प्रदान करता है। यह कॉल सेंटर प्रतिदिन 20,000 से अधिक कॉल सुनता है। http://passportindia.gov.in पोर्टल भी अद्यतन वास्तविक समय सूचना प्रदान करता है। पासपोर्ट पुस्तिका के आपूर्त्ति प्रबंधन हेतु भारत सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) तथा डाक से सुपुर्दगी हेतु भारतीय डाक के साथ आवेदकों के निजी विवरणों के सत्यापन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस प्रणाली के साथ इस परियोजना का समाकलन किया है। जैसे ही पासपोट्र प्रेषित किया जाता है आवेदक को एसएमएस/ई–मेल अलर्ट भेजा जाता है। यह परियोजना विदेश स्थित 180 मिशनों/केंद्रों को, यह परियोजना वास्तविक समय की अद्यतन सूचना प्रदान करता है तथा साथ ही आप्रवासी प्राधिकारियों को भी सूचना प्रदान करता है।

31.03.2014 तक 1.56 करोड़ पासपोर्ट सेवा संबंधित आवेदनों पर कार्य किया गया था साथ नई प्रणाली के माध्यम से 1.41 करोड़ सेवाएं पूरी की गई है। कुल 77 पीएस के में लगभग 35,000 नागरिकों से आवेदन प्राप्त होते हैं।

आवेदकों को द्रुत पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए तथा बेहतर आउटरीच सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रचालन में 77 पीएस के के अलावा मंत्रालय, ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में 16 पासपोर्ट लघु केंद्र (पीएसएलके) स्थापित के लिए प्रतिबद्ध है। जुलाई 2012 से आइजोल में एक पीएसएल के पहले से ही कार्य कर रहा है।

एक द्विभाषी ऑनलाइन पोर्टल http://passportindia.gov.in जिसे पासपोर्ट सेवा प्रदान करना पासपोर्ट सेवा पर व्यापक तथा नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए, नियुक्ति प्रक्रिया, दस्तावेज तैयार करना, स्थिति विषयक पूछताछ तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, जो कभी भी कहीं भी अभिगम और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सितंबर 2013 में अद्यतन किया गया था। इसे समय–समय पर पासपोर्ट सेवा विकास को सलाहकारों तथा प्रेस निर्मुक्तियों के साथ अद्यतन रखा जाता है।

पीएसपी के कार्यान्वयन का धन्यवाद, देश में पासपोर्ट सेवा सुपुर्दगी में नोटिस करने योग्य सुधार हुआ है। देश भर में, 24 प्रतिशत पासपोर्ट तीन दिन के भीतर जारी किया गया है; 60 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट 7 दिनों के भीतर 82 प्रतिशत 14 दिनों के भीतर जारी किया गया है (पुलिस सत्यापन के लिए किए गए समय को छोड़कर)। तत्काल पासपोर्ट के मामले में, 10 प्रतिशत उसी दिन तथा 64 प्रतिशत तीन दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है। यदि हम पुलिस सत्यापन में लिए जाने वाले समय को एंड टू एंड सुपुर्दगी प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो, 49 प्रतिशत पासपोर्ट एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है। जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या के अनुसार श्रेष्ठ पांच राज्यों में केरल,तमिलनाडु,महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश है, जो कुल आवेदन का 55 प्रतिशत से अधिक है। पिछले 350 से नई प्रणाली में बढ़ाकर 1610 पब्लिक डीलिंग काउंटर बनाए गए है तथा पब्लिक डीलिंग समय 4 घंटे प्रतिदिन से बढ़कर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है।

पुलिस सत्यापन

पासपोर्टों के समयबद्ध प्रेषण में पुलिस सत्यापन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों के साथ करीब से जुड़ा रहता है। पुलिस सत्यापन पूरा कर लिए जाने वाले समय का पूरे देश का औसत दिन 49 है तथा 37 प्रतिशत पीवी 21 दिनों की अपेक्षित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाती है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कम पीवी प्रक्रिया समय को सतत् बनाए रखा है। उदाहरणस्वरूप, नई प्रणाली

के तहत, दिल्ली औसतन 13 दिन में पुलिस सत्यापन पूरा कर लेता है, जिसके अनुसरण में आंध्र प्रदेश द्वारा (17 दिन), हरियाणा (19 दिन), केरल (27 दिन), तथा चण्डीगढ़ (27 दिन)। मंत्रालय के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक जिले अधिमत जिला पुलिस मुख्यालय सत्यापन मॉडल को अपना रहे हैं। 31 मार्च, 2014 तक, 724 पुलिस जिलों में से 449 ने नई प्रणाली को अपनाया है तथा जिला मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

कार्यात्मक संवर्धन

अधिक यूजर फ्रेंडली पोर्टल http://passportindia.gov.in सितंबर 2013 में शुरू किया गया था। नियोजित भेंट () प्राप्त करने के संबंध मे समस्याओं को देखते हुए मंत्रालय ने जुलाई 2013 से ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली शुरू की है। तब से नियोजित भेंट की उपलब्धता मे देखने योग्य सुधार हुआ है। कुछ श्रेणी के आवेदकों एवं सेवाओं के लिए ष्वॉक–इनष् सुविधा उपलब्ध है। तथापि, पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1.1.2013 से 31.12.2013 के अवधि के लिए 27 पीओ द्वारा सप्ताहांतों में समय–समय पर 81 पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया गया था। इन मेलों के दौरान, 32,525 पासपोर्ट आवेदनों का कार्य पूरा किया गया।

एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्लिकेशन, जिसकी शुरूआत मार्च, 2013 में एन्ड्रॉयड प्लेटटफार्म पर हुई थी, को विंडोज तथा एपल आईओएस प्ले्टफार्म पर उपलब्धॉ कराया गया था। यह एप्लि केशन स्मार्कर्ट फोन पर पीएसके लोकेटर, लागू शुल्कध, जमा करने के तरीके, पासपोर्ट आवेदनों की स्थिरति पर नजर रखने सहित पासपोर्ट संबंधी सूचना उपलब्धी कराता है।

नागरिकों को उनके पासपोर्ट आवेदनों तथा लबित कार्यों की प्रगति के संबंध अलर्ट तथा अपडेट प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पूरे देश में नवंबर 2013 में प्रिमीयम वैकल्पिक एसएमएस सेवा शुरू की थी। यह सेवा किसी भी मोबाइल फोन से प्राप्त की जा सकती है। यह सुव्यवस्थित मुफ्त एसएमएस/ई–मेल सूचना के अतिरिक्त सेवा है।

पीएसके से दूर रहने वाले लोगों तक पहुँचने के उद्देश्य से, विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने फर्रूखाबद, औरेया, इटावा, हरदोई तथा कन्नौज जिलों में रहने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लाभ हेतु दो दिनों के लिए फतेहगढ़ में 14 दिसम्बर, 2013 को सबसे पहला पासपोर्ट सेवा कैंप का उद्घाटन किया था। यह एक अन्य नवाचार नागरिक केंद्रीत उपाय है जो आरटी चालित लोक सेवा को उनके घरों के करीब ले जाता है। 1.1.2014 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, 8 पासपोर्ट सेवा कैंपों का आयोजन किया गया, 1214 पासपोर्ट आवेदनों को पूरा किया गया था।

नागरिक–केंद्रित सेवाओं को घरों के करीब लाने के लिए एक लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से ऊपर के सुविस्तृत नेटवर्कों के माध्यम से उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के 15 चुने गए सीएससी स्थानों पर आरंभिक मोड में पासपोर्ट संबंधित सेवा आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग सेवा पाईलेट मोड सीएससी ई–गवर्मेंस सेवा भारत लिमिटेड के सहयोग से मंत्रालय ने, डाइट वाई द्वारा संवर्धित, 19 मार्च, 2014 को आरंभ किया गया था।

विदेशों में पासपोर्ट सेवा

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने 13.83 लाख पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाएं पूरी की है। दो देश, सऊदी अरब तथा यूएई ने विदेशों में कुल सेवा का 43.4 प्रतिशत योगदान किया है (स्थानवार,दुबई रियाद तथा जेद्दा ने 39.4 प्रतिशत सेवाएं प्रदान की) पासपोर्ट सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष 12 देशः सऊदी अरब, यूएई, यूएस, कुवैत, यूके, कतर, ओमान, सिंगापुर, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, इटली तथा बहरीन हैं। उन्होंने विदेशों में कुल पासपोर्ट सेवा का 87 प्रतिशत संकलित योगदान किया है। इस परियोजना को सरकार के उच्चतम स्तर पर पहचान मिली हैं, जो केस स्टडीज का विषय रहा है; तथा कई पुरस्कार भी जीता है।

पासपोर्ट सेवा दिवस तथा पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने नई दिल्ली में (24–25 जून, 2013) दो दिवसीय पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, तथा 24 जून को ष्पासपोर्ट सेवादिवसष् घोषित किया जिसे इस वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर, मत्री ने (i) ऑनलाइन पासपोर्ट फीस भुगतान सेवा, (ii) विविध प्रकार की पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल आधारित एम पासपोर्ट सेवा एस तथा (iii) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) की भौतिक अवसंरचना में सुधार की ओर एक कदम आगे बढ़ने के तौर पर सूरत में नए पासपोर्ट भवन के उद्घाटन के प्रतीक स्वरूप एक पट्टिका का अनावरण किया। नागरिकों को प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं के पहचान के तौर पर, मंत्री जी ने चुने गए कार्मिकों तथा पासपोर्ट कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पीएसपी के तहत, मंत्रालय ने एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किया है जिसमें टॉल फ्री नम्बर (1800–258–1800), के साथ राष्ट्रीय कॉल सेंटर है जो 17 भाषाओं में 24x7 आधार पर कार्य करता है, इसे विभिन्न सेवाओं, शिकायत तथा नागरिकों की प्रतिपुष्टि का कार्य देखने के संबंध में सूचना का प्रसार देखने के लिए स्थापित किया गया था, और फिलहाल केंद्रीय प्रणाली प्लेटफार्म पर कार्य करता है। एक सहायता पटल की भी स्थापना की गई थी। जिसे http://passportindia.gov.in पोर्टल के माध्यम

से नागरिकों द्वारा खोला जा सकता है तथा जहां सुझाव तथा शिकायतें भेजी जा सकती है एवं साथ इसकी ऑनलाइन स्थिति को भी मॉनीटर किया जा सकता हैं। वर्तमान में यह लगभग 2000 कॉल प्रतिदिन सुनता है। (इसमें से 42 प्रतिशत हिंदी में तथा 29 प्रतिशत अंग्रेजी में)।

संयुक्त सचिव (पीएसपी) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के तहत सीपीवी प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त; सभी पीओ, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली वेबसाइट (सीपीजीआरएएम) के माध्यम से लोक शिकायतों का निपटान करता है, इसमें 6026 शिकायत 1.1.2013 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई, जिसमे से 5013 मामलों का निपटान कर दिया गया है। उनके आवेदनों पर अद्यतन स्थिति तथा आगे की कार्रवाई हेतु निर्देशों के साथ इसे वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है, जिसे जनता द्वारा उनके हितों के लिए आसानी से देखा जा सकता है। 1. 1.2013 से 31.3.2013 की अवधि के दौरान (सीपीजीआरएएम सहित) सीपीवी प्रभाग द्वारा 38,489 लोक शिकायत पेटीशन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 36,944 का निपटान कर दिया गया है। शिकायत पेटीशन कर दिया गया है। आवेदकों की सहायता तथा 9938 का निपटान कर दिया गया है। आवेदकों की सहायता तथा उनकी शिकायतों का तीव्र निपटान करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में सूचना तथा सुविधा पटल, लोक शिकायत प्रकोष्ठ तथा हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है। पासपोर्ट कार्यालयों तथा पीएस के में अनुकूल स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटियां लगाइर गई है। समयसीमा के अंतर्गत किसी भी शिकायत की पूछताछ तथा निवरण के लिए सभी पीओ में में से लोक शिकायत निवारण तंत्र है।

प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग से एक दल ने पासपोर्ट आवेदनों को जमा करने की नई प्रक्रिया, को समझने के लिए पीएस के, हेराल्ड हाऊस, नई दिल्ली का 2 अगस्त, 2013 को दौरा किया वहां लोगों से बातचीत की, उसके पश्चात् सीपीवी प्रभाग का दौरा किया था सीपीवी प्रभाग के शिकायत तंत्र का आकलन किया। लोक शिकायत के निवारण में सुधार के लिए किए गए मंत्रालय के प्रयासों की प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने सराहना की।

पासपोर्ट अदालत तथा मेला

पीओ, पासपोर्ट आवेदकों के शिकायत के निवारण के लिए नियमित पासपोर्ट अदालत आयोजित करता है। ये अदालत कुछ 7000 पुराने तथा जटिल मामलों को निपटाने में काफी उपयुक्त सिद्ध हुई है। नियोजित भेंट प्राप्त करने में नागरिकों द्वारा झेली जा रही परेशानियों का समाधान करने के लिए तथा पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए पीओ द्वारा समय समय पर पासपोर्ट मेला आयोजित किया गया जाता है। 27 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान 31.12.2013 तक पासपोर्ट मेलों के दौरान 32,525 पासपोर्ट आवेदनों को निपटाया गया था। 1.1.2014 से 31.3.2014 की अवधि के में 67 पासपोर्ट मेला आयोजित किया गया था। जिसके दौरान 37,810 पासपोर्ट आवेदनों का निपटान किया गया।

हज यात्रीः विशेष अभियान

जैसाकि हज समिति द्वारा निर्णय लिया गया था (संसद के 2002 के संख्या 35 अधिनियम के तहत गठित कि केवल वैध पासपोर्ट धारक ही हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतः, सभी प्रत्याशित हज आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे हज 2013 की घोषणा से पूर्व अपना पासपोर्ट जारी करवाएं। हज 2013 के लिए 6 फरवरी, 2013 तथा 30 मार्च 2013 के बीच नए नियामकों के अनुसार भारतीय हज समिति द्वारा आवेदन प्राप्त किए गए थे। 1,25,000 आवेदनों के आबंटित हज कोटा की तुलना में विहित समय सीमा तक हज समिति द्वारा 3 लाख आवेदन प्राप्त किया गया था। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को प्रत्याशित हज आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन को उचच प्राथमिकता देने तथा नोडल कार्यालय नियुक्त करने उन्हें तीव्र पासपोर्ट जारीकरण के लिए अपेक्षित सहायता; सुविधा काउंटर खोलने; ऐसे आवेदकों के लिए नियोजित भेंट के स्लॉट आरक्षित करना तथा ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोध/शिकायत पेटीशन का शीघ्रता से प्रबंध करने का निर्देश जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

1 जुलाई, 2.13 से सीपीवी प्रभाग पासपोर्ट कार्यालयों तथा सीपीवी प्रभाग से संबंधित ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदनों के लिए भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल में एक पृथक अनुभाग प्रचालित कर रहा है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान इस प्रभाग द्वारा कुल 4598 ऑनलाइन तथा पोस्टल आरटीआई आवेदन प्राप्त किए गए तथा उनका निपटान किया गया (इसमें से 3298 आवेदनों को आरटीपीओ को उनकी ओर से कार्रवाई के लिए भेजा गया तथा सीपीवी प्रभाग से 1300 उत्तर भेजे गए)। इसी अवधि के दौरान, 884 पोस्टल तथा ऑनलाइन प्रथम अपील भी प्राप्त किए गए और उनका निपटान किया गया। 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए 1508 ऑनलाइन तथा पोस्टल आरटीआई आवेदनों का निपटान किया गया। इसी अवधि के दौरान 2014 पोस्टल तथा ऑनलाइन प्रथम अपील प्राप्त हुए तथा उनका निपटान भी किया गया।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत)

पीआईए के निर्णयों के विरूद्ध अपील पासपोर्ट अधिनियम की धारा–11 के तहत प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया सांविधिक अधिकार है। 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान 322 अपील मामलों को शामिल करते हुए 9 अपील सत्र हुए। सुनवाई के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार, 236 सकारण आदेश जारी किए गए।

यात्रा दस्तावेजों को तैयार करना तथा उसका निजीकरण

सभी भारतीय दस्तावेज आईएसपी, नासिक द्वारा तैयार किए जाते हैं। फोटोग्राफ तथा आँकड़ों के धुंधला होने की समस्या का निवारण करने के क्रम में तथा समग्र गुणता, कार्यात्मकता तथा भारतीय पासपोर्टों की सुरक्षा, विविध उपायों से बेहतर बनाने जैसे पासपोर्ट पुस्तिका में आँकड़ा पृष्ठ को पृष्ठ संख्या–2 पर तथा पर्यवेक्षण पृष्ठ को अंतिम पृष्ठ पृष्ठ संख्या 35 पर पीआईए के हस्ताक्षर तथा मुहर को ऊपरी कवर के अंदर की ओर पृष्ठ संख्या–1 के सामने स्थानांतरित करने, पासपोर्ट धारक के अनुषंगी ष्घोस्ट इमेजष् (लेटर स्क्रीन इमेज) को उसके वैयक्तिक आँकड़े को आँकड़ा पृष्ठ पर शामिल करने को 1 अप्रैल, 2013 के प्रभाव से कार्यान्वित कर दिया गया है। ("2012 सीरिज की पुस्तिका")। सभी पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालयों तथा चुनिंदा विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर प्रदान किया गया है। 150 विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों तथा सहायक सचिव (पासपोर्ट) का कार्यालय, अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए घोस्ट इमेज सुरक्षा फीचर के साथ मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी), सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली के केंद्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में छापी गई 1 सीआईपीपीएस द्वारा 1.1.13 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान 1,13,469 पासपोर्ट की छपाई की गई। 1.1.2014 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, सीआईपीपीएस ने 41,604 पासपोर्ट छापे हैं।

ई–पासपोर्ट

मशीन द्वारा पठनीय यात्रा दस्तावेज में बायोमीट्रिक डाटा को शामिल करने के लिए आईसीएओ की सिफारिशों के अनुसार भारत ने मौजूदा पासपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के ई–पासपोर्ट में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। राजनयिक तथा आधिकारिक श्रेणियों के ई–पासपोर्ट जारीकरने के आरंभिक चरण के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर, मंत्रालय ने, सामान्य श्रेणी के लिए भी ई–पासपोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। ई–पासपोर्ट महत्वपूर्ण कार्यों तथा हेर–फेर में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा एक व्यक्ति को कई पासपोर्ट जारी करने से भी रोकेगा, इस प्रकार पासपोर्ट जारीकरने में उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ई–पासपोर्ट परियोजना को गति प्रदान करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है।

भारत बांग्लादेश पासपोर्ट को समाप्त करना

भारत और बांग्लादेश के बीच संशोधित यात्रा व्यवस्था पर 28 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षार किए जाने के बाद मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 15 नवम्बर, 2013 से भारत–बांग्लादेश पासपोर्ट जारी न किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

वर्ष 2013 के दौरान, श्री ए आर घनश्याम, अतिरिक्त सचिव (सीपीबी/हज) एमईए की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मशीन रीडेबल ट्रैवल डाक्यूमैंट, बायोमैट्रिस एवं सुरक्षा मान दण्ड सीम्पोजियम एवं प्रदर्शनी का अयोजन आईसीएओ मुख्यालय, मौन्टरियल में 22–24 अक्तूबर, 2013 को किया गया। श्री मुकेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं सीपीआईओ ने 18वीं और 19वीं पीकेडी ब्रोर्ड बैठक में 27–28 नवंबर, 2013 को आबधाबी में और 31 मार्च–1 अप्रैल, 2014 को पेरिस में भाग लिया। लोगों को सूचित करने हेतु की अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने सभी गैर मत्रीनी पढ़े जाने वाले पासपोर्टों (एमआरपी) को वैश्विक रूप से हटाने के लिए 24 नवंबर, 2015 का समय सीमा तय की है, लिए एक लोक जागरूकता अभियान शुरू किया था। 25 नवंबर,2015 से, विदेशी सरकारें एक गैर–एमआरपी धारित पासपोर्ट के साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के प्रवेश और वीजा देने पर रोक लगा सकती है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी सभी हस्तलिखित जिनमें फोटो चिपकी हुई है गैर एमआरपी पासपोर्ट माना गया है। सभी 20 वर्ष की वैद्धता वाले पासपोर्ट भी इसी श्रेणी में आएगें। भारत सरकार ने 2001 से एमआरपी पासपोर्ट जारी करने शुरू किए है। सभी नए भारतीय पासपोर्ट आईसीएओ अनुपालनकर्त्ता एमआरपी पासपोर्ट हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय आईसीएओ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले पासपोर्ट जारी करते हैं।

डिजिटाईजेशन परियोजना

भारतीय मिशनों/केंद्रों पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई और पीआईओ आवेदनों के लिए "क्रियेशन आफ इमेज रिट्रिवलेबल डाटाबेस" की परियोजना को जून 2012 में 3 वैडंरों के पैनल को सौंपा गया था। प्रथम सत्र में कौंसूली दस्तावेजों का डीजिटाईजेशन, लंदन, सन फ्रांसिस्कों, रियाद, दुबई और अबूधाबी में शुरू किया गया, जोकि लखनऊ को छोड़कर सम्पन्न हो गया। परियोजना में अन्य 34

भारतीय मिशनों/केंद्रों को कवर किया जाएगा, इनमें से 9 मिशनों/केंद्रों में कार्य पहले से शुरू हो चुका है। 31.3.2014 तक लगभग 7.28 करोड़ पन्नों को डिजिटाईज किया जा चुका था। एक बार लागू होने के बाद इस परियोजना से विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में आँकड़ों का संग्रहण फाइलों का समय पर निपटान और एकरूपता आएगी।

संसदीय समितियों का आरपीओ/पीएसके का दौरा

कई संसदीय समितियों द्वारा अनेकों प्रश्नों, परीक्षा एवं निरीक्षण/अध्ययन दौरों से पासपोर्ट सेवाओं में संसद के हित की पुष्टि हुई है।

(क) 10 जनवरी, 2013 को श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा, संसद सदस्य एवं अध्यक्ष के नेतृत्व में प्राकलन समिति और अन्य नौ संसद सदस्यों ने "भारत में पासपोर्ट सेवा" के विशेष संदर्भ में पासपोर्ट कार्यालय गोआ का दौरा किया। 1 जून, 2013 को श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा, संसद सदस्य एवं अध्यक्ष की अगुवाई में प्राकलन समिति ने आरपीओ चंडीगढ का दौरा किया।

(ख) 16 जनवरी, 2013 को श्री अनंत कुमार, अध्यक्ष के नेतृत्व मे विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने श्री रंजन मथाई विमर्श उस समय के विदेश सचिव के नेतृत्व में मंत्रालय के के साथ "पासपोर्ट सेवा परियोजना लक्ष्य तथा उपलब्धियां विषय पर विचार विमर्श किया। 17 दिसंबर, 2013 को श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय संसदीय स्थायी समिति ने श्रीमती सुजाता सिंह, विदेश सचिव के नेतृत्व में ष्पासपोर्ट सेवापरियोजना–लक्ष्य तथा उपलब्धियांष् विषय पर दोबारा विचार–विमर्श किया गया था।

(ग) श्री अनंत कुमार के नेतृत्व मे विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति ने 12–18 जुलाई, 2013 की अवधि के दौरान बंगलोर,भोपाल,दिल्ली (हेराल्ड हाउस तथा गुडगांव) तथा गाजियाबाद में स्थित पीएस के की यात्रा की। समिति ने पीएसके प्रचालन के अनुसार नागरिकों को प्रदान की गई सेवा का अध्ययन किया तथा पिछले एक साल के दौरान पीएसपी द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

(घ) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने विदेश मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु 4 जनवरी 2013 को आरपीओ चेन्नई, 2 फरवरी,2013 को आरपीओ जयपुर, 18.5.2013 को पीओ जम्मू, 16 जुलाई, 2013 को पीओ गाजियाबाद, 20 नवंबर, 2013 को आरपीओ बंगलोर तथा 16 जनवरी, 2014 को पीओ भुवनेश्वर की यात्रा की।

लोक आउटरीच

इसके आउटरीच के विस्तार के रूप में, सीपीवी प्रभाग सेवा प्रदाता के सहयोग से विभिन्न पासपोर्ट संबंधित मुद्दों पर शामिल सूचना पर "पासपोर्ट पत्रिका" एक अर्धवार्षिक बुलेटिन शुरू कर रहा है। कइर पीओ मे मीडिया रोड शो का भी आयोजन किया गया, जहां पासपोर्ट सेवाओं की सुपुर्दगी मे सुधारों पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग तथा पीजी ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव/विदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए अपने मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम में केस अध्ययन के तौर पर पीएसपी को शामिल किया है।

वीजा

विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों द्वारा वीजा जारी किया जाना

मिशनों/केंद्रों द्वारा वीजा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है, जिसकी शुरूआत 2006 में की गई थी। वीजा जारीकरण प्रक्रिया की सुरक्षा स्थिति को संवर्धित करने के क्रम में, सरकार ने, 2012 में भारत की यात्रा करने के लिए वीजा मांगने वाले विदेशियों के लिए बायोमीट्रिक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया है, जो आईबीएफआरटी (आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग) परियोजना का भाग था। सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में इस योजना के कार्यान्वयन को 2014 तक पूरा कर लिए जाने का अनुमान है। 31.03.2014 तक, आईवीएफआरटी योजना (बिना बायोमीट्रिक्स के) विदेश स्थित 139 भारतीय मिशनों/केंद्रों में शुरू कर दी गई है। बायोमीट्रिक प्रक्रियाओं के नामांकन के साथ आईवीएफआरटी योजना के कार्यान्वयन से भारत में प्रामणिक विदेशियों के आवागमन को सरलीकृत करने के अलावा वीजा जारीकरण तंत्र के सुरक्षा आयामों की स्थिति संवर्धित होगी।

सीपीवी प्रभाग द्वारा वीजा जारी किया जाना

सीपीवी प्रभाग ने (31.12.2013 तक) 7092 वीजा तथा 1.1.2014 से 31.3.2014 की अवधि तक विदेशी राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों को 1373 वीजा जारी किया है। सीपीवी प्रभाग ने स्थानांतकरण तथा कार्यालयी कार्यों के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों में कार्यग्रहण करने के लिए भारत सरकार के कार्मिकों को 8139 वीजा नोट (31.12.2013 तक) तथा 1.1.2014 से 31.3.2014 की अवधि के लिए 169 वीजा नोट भी जारी किया है।

भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा वीजा/कोंसुली/पासपोर्ट कार्य का आउटसोर्सिंग

विदेश मत्रालय ने 2006–07 के दौरान विदेश स्थित मिशनों/केंदों मे वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग शुरू की है। इसके पश्चात् पासपोर्ट तथा कोंसुली सेवाओं की आउटसोर्सिंग भी शुरू की गई है। 31.3.2014 को 70 विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने पासपोर्ट/वीजा कोंसुली सेवाओं तथा संकलन कार्य की आउटसोर्सिंग की है। सीपीवी सेवाओं तथा बायोमीट्रिक प्रक्रियाओं की शुरूआत की आउटसोर्सिंग से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था तथा 5–7 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एचओएम सम्मेलन के दौरान इसकी समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश सचिव ने की थी। श्री ए.आर. घनश्याम, अपरन सचिव (सीपीवी/हज) की अध्यक्षता मे एक अंतर–मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने वीजा आउटसोर्सिंग तथा कांसुली सेवाओं पर यू. एस.ए में भारतीय राजदूत तथा केंद्र प्रमुखों से बातचीत के लिए 21 अक्तूबर, 2013 को वाशिंगटन की यात्रा की।

वीजा छूट करार

भारत का 60 देशों के साथ वीजा छूट करार है, जिसके द्वारा राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा की आवश्यकता से छूट मिली हुई है। वर्ष 2013 में, फ्रांस,माल्टा, लिथुआनिया, किर्गीजस्तान तथा ग्रीस के साथ वीजा छूट करार पर हस्ताक्षर किया गया।

कोंसुली मामले

अपोसल अभिसमय परियोजना

मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में सत्यापन प्रकोष्ठ, विदेशों में निजी तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु लोगों के शैक्षिक, वाणिज्यिक तथा निजी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए सत्यापन सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय व्यावसायिक संस्थानों को निर्यात तथा विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए विदेश विदेश मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक दस्तावेजों के सत्यापन कराए जाने की भी आवश्यकता है। प्रमाणीकरण दो प्रकार के हैं। साधारण सतयापन तथा अपोसल प्रामाणीकरण। अपोसल प्रमाणीकरण कराए जाने की आवश्यकता तब काराई जाती हैं जब उन दस्तावेजों का इस्तेमाल उन देशों में होना है जा हेग अपोसल अभिसमय के सदस्य देश हैं। सामान्य सत्यापन मुक्त है, जबकि अपोसल स्टीकर में चिपकाए जाने हेतु पोस्टल आर्डर के माध्यम से 50 रुपए प्रति दस्तावजे/प्रति पृष्ठ के शुल्क का प्रभार लिया जाएगा। जनवरी से दिसंबर 2013, की अवधि के लिए, सीपीवी प्रभाग के सत्यापन प्रकोष्ठ ने 373358 निजी तथा 1,77,509 वाणिज्यिक दस्तावेजों को सत्यापित किया तथा अपोसल सदस्य देशों में उपयोग हेतु 2,90,864 दस्तावेजों को अपोसल किया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान हैदाराबाद, चेन्नई, कोलकाता तथा गुवाहाटी मे विदेश मंत्रालय के चार सचिवालय शाखाओं में 44,490 दस्तावेज सत्यापित/अपोसल किए गए। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा कोंसुली दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। जुलाई 2012 से 2 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा सत्यापन/अपोसल के लिए दस्तावेजों का संकलन/सुपुर्दगी के कार्य की आउटसोर्सिंग 5 कंपनियों को की गई है। ये कंपनियां प्रति दस्तावेजे 22 रुपए (निजी), 18 रुपए (शैक्षिक) तथा 16 रुपए (वाणिज्यिक) सेवा प्रभाव वसूल करती है।

प्रत्यर्पण मामले तथा कानूनी सहायता

जनवरी तथा दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान, भारत ने बांग्लादेश (जनवरी 2013), अजरबेजान (अप्रैल 2013) तथा थाईलैंड (मई 2013) के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था। वियतनाम (अगस्त 2013) तथा बांग्लादेश (अक्तूबर 2013) के साथ प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों की अदला बदली की। 1.1.2013 से 31.3.2014 के दौरान भारत ने सात प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त किया है–यूएसए से चार, यूके से चार तथा ईरान से एक– तथा सात प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है–यूएसए को दो, यूएइर को चार तथा सऊदी अरब को एक। इसके अलावा, स्थानीय अभियोजन हेतु 62 अनुरोध प्राप्त किया है। (यूएई से 56, सऊदी अरब से 5 तथा कुवैत से एक)। आगे, भारत ने 5 लोगों का दूसरों देशों को प्रत्यर्पण किया है (यूएसए–4 तथा यूके–५)। दूसरे देशों ने भारत को तीन लोग प्रत्यर्पित किया है। (यूएई–3)। इसके अतिरिक्त, भारत ने स्थानीय अभियोजन के लिए 7 अनुरोध प्राप्त किया है। (5 यूएई तथा 2 सऊदी अरब से)। आगे, एक व्यक्ति को यूएई से भारत प्रत्यर्पित किया गया है।

कोंसुली मुद्दे

विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों के हितों तथा कल्याण को सुरक्षित रखने के क्रम में आस्ट्रेलिया, ईरान, यूएन, यूएस, चीन, रूसी संघ, यूएई इत्यादि सहित कई देशों के साथ कोंसुली मामले पर भारत सरकार कई द्विपक्षीय संयुक्त कार्य दल की स्थापना की है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुत्ती अल हमाद, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में यूएई से एक 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 17–18 जून, 2013 को कोंसुली मामले पर आयोजित संयुक्त समिति के बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अशोक के कांथा, सचिव ने किया था। इस वार्ता के दौरान कोंसुली, पासपोर्ट, वीजा तथा प्रत्यर्पण के कई मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

सऊदी अरब में नितकत (आम माफी)

सऊदी अरब राज्य (केएसए) ने 3 जुलाई, 2013 तक सऊदी अरब में अवेध निर्वासितों के ठहराने के नियमितीकरण के लिए नितकता की

घोषणा की थी। उनके वहां ठहरने तथा भारत में वापस भेजने के सरलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कइर उपाय किए गए है; जिसमें रियाद तथा जेद्दा में हमारे मिशनों में आपात प्रमाण–पत्र के जिए शुल्क (जीएसआर 303) (ई) दिनांक (13 मई, 2013), अतिरिक्त मानव शक्ति की तैनाती, विस्तारित कार्य समय शामिल है। निताकत के आखिरी महीने के लिए मंत्रालय से एक कार्यकारियों का एक दल रियाद तथा जेद्दा भेजा गया था। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, ई/आई रियाद तथा (जीआई, जेद्दा से कई ईसी जारी किए गए थे, जो क्रमशः 65000 तथा 20,000 थे। कई मंचों के अनुरोध पर तथा निर्वासितों के कल्याण को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने निताकत की तिथि 14 नवंबर 2013 तक बढ़ा दी थी।

प्रशासन एवं स्थापना

19

प्रशासन प्रभाग इस मंत्रालय तथा विदेश स्थित 180 मिशनों/केन्द्रों में सक्षम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। संवर्ग प्रबंधन प्रशासन प्रभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, कैरियर प्रगति तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त देयताओं का निपटारा शामिल है। इसके अलावा यह प्रभाग विदेशों में नए मिशनों/केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ कार्मिकों से संबंधित सभी संबद्ध नियमों तथा विनियमों को तैयार करने, संशोधन करने तथा सुधार करने का कार्य भी करता है।

भारत के वैश्विक प्रोफाइल तथा आदान–प्रदान में हाल ही के वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है। सदा से बढ़ती मानव संसाधन को मांग को पूरा करने के लिए आई एफ एस संवर्ग में व्यापक विस्तार करने का कार्य वर्ष 2008 से चल रहा है यह कार्य 10 वर्ष की अवधि अर्थात 2018 तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष विभिन्न स्तरों पर 50 पद शामिल किए जाते हैं तथा मंत्रालय ने इस प्रक्रिया के 6 चरण पहले से ही पूरे कर लिए हैं। मंत्रालय ने 2011–12 में भारतीय विदेश सेवा ख संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिसे विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठकों के साथ शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया है ताकि विचारार्थ अधिकारियों की पदोन्नति की जा सके तथा नई भर्ती के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों के समक्ष आवश्यक आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अनुसार इस मंत्रालय ने संशोधित प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार की है, जिसमें विदेश मंत्रालय के सभी संवर्गों में उनके कैरियर के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण अपेक्षाएं शामिल हैं। संशोधित ढाँचे के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने कैरियर के तीन विभिन्न चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है। यह मंत्रालय संशोधित प्रशिक्षण अवसंरचना में शामिल उद्देश्य के आधार पर विस्तृत प्रशिक्षण मॉडल तैयार कर रहा है।

इस मंत्रालय में कर्मचारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 4086 है, (विवरण के लिए परिशिष्ट देखें) इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों की तैनाती भारत तथा विदेश स्थित 180 मिशनों/केन्द्रों में की जाती है। इसमें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" (आईएफएस "बी") के कर्मचारी, दुभाषिया संवर्ग, विधि एवं संधि संवर्ग तथा पुस्तकालय संवर्ग शामिल है, परन्तु समूह "घ" तथ संवर्ग वाह्य पद शामिल नहीं हैं।

1 अप्रैल, 2013 से 30 मार्च, 2014 के दौरान सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में की गई भर्ती का विवरण परिशिष्ट ग में दिया गया है, जिसमें आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती भी शामिल है।

विदेश मंत्रालय ने अपने कार्यकरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा भाषा कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कई वर्षों के दौरान इस सेवा के भीतर विदेशी भाषा कौशल वाले व्यक्तियों का एक व्यापक तथा बड़ा पूल सृजित किया गया है, ताकि ये अधिकारी अपने राजनयिक दायित्व प्रभावशाली ढंग से निभा सकें। इस मंत्रालय के अधिकारियों के भाषा कौशल का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

यह मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों को भी उचित अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है, ताकि कार्मिकों में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय ने भारत सरकार के संबद्ध नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उचित पदों की पहचान की है।

वर्ष 2013–14 में भारत सरकार ने सित्तवे, म्यामां में भारत का एक नया प्रधान कौंसल खोलने का निर्णय लिया था इस समय इस में नए केंद्र को खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

सतर्कता एकक

28.10.2013 से 20.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विनिर्धारित शपथ विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों तथा विदेश मंत्रालय में विभिन्न विभागों में दिलाई गई। मंत्रालय 1 जनवरी, 2013 से 50 करोड़ तथा इससे अधिक मूल्य के सभी प्रापणों/परियोजनाओं के लिए भावी बोलीदाताओं/विक्रेताओं के साथ सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रभाग द्वारा इस वर्ष के दौरान निपटाए जा रहे मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

- 31.12.2012 तक लंबित मामलों की संख्या : 78
- 1.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान जांच के लिए प्राप्त मामलों की संख्या : 40
- 31.03.2014 तक मामलों की कुल संख्या : 118
- 1.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान औपचारिक दण्ड लगाकर बंद किए गए मामलों की संख्या : 13
- 1.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान दण्ड रहित, मौत, वीआरएस आदि के कारण बंद किए गए मामलों की संख्या : 30
- 1.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान बंद किए गए मामलों की कुल संख्या : 43
- 31.03.2014 तक लंबित मामलों की संख्या :75

कल्याण प्रभाग

कल्याण प्रभाग मंत्रालय के कर्मचारियों के आम कल्याण का कार्य देखता है। इसमें विदेश मंत्रालय के कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस/इंजीनियरी/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा केंद्रीय विद्यालय में उनके बच्चों की शिक्षा, साउथ ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू भवन और पटियाला हाउस में कैंटीन सेवाओं का प्रबंधन, मंत्रालय के मृत कर्मचारियों के परिवार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के मामलों की सिफारिश करने सहित उनके परिवारों का मानसिक आघात प्रबंधन, विवादों के मामले तथा सामान्य सेवाओं के लिए पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों का हस्तक्षेप, विदेश स्थित मिशनों तथा मुख्यालय में मनोरंजन केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता; सांप्रदायिक सौहार्द, स्टाफ लाभ निधि, रेड क्रास तथा सशस्त्र ध्वज दिवस जैसे ध्वज दिवसों के लिए व्यवस्था शामिल है।

कल्याण प्रभाग केंद्रीय विद्यालय द्वारा इस मंत्रालय को आबंटित 60 सीटों पर इस मंत्रालय के अधिकारियों के बच्चों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। ये सीटें विदेशों में तैनात अधिकारियों के बच्चों के लिए है, जिन्हें तैनाती से वापसी के बाद प्रवेश की आवश्यकता होती है। कल्याण प्रभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंजीनियरी सीटें (डिग्री/डिप्लोमा) तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चिकित्सा सीटें भी आबंटित की जाती हैं। ये सीटे अधिकारियों के उन बच्चों को दी जाती है, जिन्होंने विदेशों से अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली है तथा इनका वितरण गुणत्ता क्रम के अनुसार किया जाता है। अधिकारियों के बच्चों को 74 इजीनियरिंग सीटें तथा 3 चिकित्सा सीटें आबंटित की गयी थी।

कल्याण प्रभाग इस मंत्रालय के अधिकारियों एवं स्टाफ के सदस्यों के अंशदान से पिछले कई वर्षों से गठित स्टाफ लाभ निधि संचालित कर रहा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस मंत्रालय के स्टाफ के सदस्यों की मृत्यु के मामले में अंत्येष्टि व्यय पूरा करने के लिए प्रति मृत्यु 15000/– की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मृत व्यक्तियों के कुल 12 आश्रितों को यह राहत प्रदान की गयी थी। कल्याण अनुभाग की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय पति/पत्नी संघ ने इन मंत्रालय के मृत कर्मचारियों (समूह–प्ट) के 8 आश्रितों को क्रमशः 35000 की राशि के चैक प्रस्तुत किए थे। कल्याण प्रभाग इस मंत्रालय के मृत कर्मचारियों के वित्तीय रूप से जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के मामले में ईएएसए का साथ समन्वय भी करता है।

स्टाफ के किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में कल्याण प्रभाग स्टाफ के शेष सदस्यों की वित्तीय स्थिति की जांच करता है तथा यह जांच भी करता है कि क्या मृत व्यक्ति का पति/पत्नी अथवा कोई बच्चा अवर श्रेणी लिपिक तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक दृष्टि से योग्य है। कल्याण प्रभाग परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करता है। निदेशक (एडीपी) की अध्यक्षता में एक समिति इन पदों पर उत्पन्न रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करती है।

यइ प्रभाग विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों तथा भारत के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को मनोरंजन सुविधाओं तथा खेल गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। यह प्रभाग अंतरमंत्रालयी खेल गतिविधियों की व्यवस्था करता है। यह सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, शस्त्र बल ध्वज दिवस जैसे विभिन्न ध्वज दिवस मनाने की व्यवस्था भी करता है तथा इन समारोहों के लिए राशि एकत्र करता है। कल्याण प्रभाग जवाहर लाल नेहरू भवन, साउथ ब्लॉक तथा पटियाला हाउस में स्थित विदेश मंत्रालय की विभागीय कैंटीनों का संचालन करता है। यह प्रभाग विदेशों से वापस आने वाले कर्मचारियों को शीघ्र घरेलू सेवाएं प्रदान में सहायता करने के लिए करने के लिए स्कूलों, एमटीएनएल राशन कार्ड कार्यालयों इत्यादि को भी पत्र जारी करता है।

स्थापना

स्थापना प्रभाग को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के कार्यालय एवं आवासीय परिसार के अनुरक्षण एवं रखरखावए कार्यालय स्थान तथा मंत्रालय के आवासीय परिसर के आबंटनए दिल्ली में मंत्रालय के लिए दूरसंचारए फर्नीचर तथा कार्यालय उपस्करों की खरीद एवं आपूर्ति का कार्य भी सौंपा गया था। यह विदेशों में स्थित मिशनों एवं केंद्रों में तैनात अधिकारियों के लिए भत्तों एवं विशेष अनुदानों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करता है। यह प्रभाग सुशोभित क्राकरी कटलरी एवं ग्लासए गलीचोंए ब्रास की मुहरोंए राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि के साथ साथ सरकारी वाहनोंए चांसरी तथा आवासीय स्थान किराए पर लेए होटलों को पैनलबद्ध करनेए बागवानी तथा

विदेश स्थित मिशनोंध्केंद्रों के सुरक्षा तथा अनुरक्षण संविदाओं सहित विशेष प्रथम मदों की खरीद एवं आपूर्ति से संबंधित मामलों भी देखता है। इस प्रभाग को दिल्ली स्थित मंत्रालय के कार्यालयों के लिए तथा मिशनों और केंद्रों को भेजने के लिए ओब्जेक्ट डी आर्ट के चयन तथा खरीद और साथ ही तोशाखाना का कार्य भी सौंपा गया है।

साउथ ब्लॉकए जवाहर लाल नेहरू भवनए पटियाला हाउसए शास्त्री भवन तथा आईएसआईएल बिल्डिंग में मंत्रालय के कार्यालयों के सुचारू कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के उपाय भी किए गए है। मंत्रालय ने कई अतिरिक्त प्रभागों को साउथ ब्लॉक से जेएनबी में स्थानांतरित कर दिया हैए ताकि उस इमारत में स्थान की कमी दूर की जा सके तथा उसकी विरासत की विशेषताएं बरकरार रखने में सहायता की जा सके। कर्मचारियों को उपयुक्त कार्य.परिवेश प्रदान करने के लिए कार्यालय की सभी इमारतों में रख.रखाव मानकों का अनुवीक्षण एवं सुधार किया गया था। जेएनबी को दिल्ली के सर्वाधिक अनुरक्षित सरकारी कार्यालयों में से एक माना जाता है। इस इमारत की पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं में वृद्धि करने के प्रयास भी चल रहे हैं। जेएनबी में समिति कक्षए बहु.उद्देश्यीय हाल तथा अन्य बैठक सुविधाओं का उपयोग नियमित रूप से मंत्रालय की आंतरिक बैठकों तथा अन्य मंत्रालयोंधविभागों द्वारा आयोजित सम्मेलनों के लिए किया जाता हैए जिसमें विदेशी प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं।

चाणक्यपुरी, के जी मार्ग, गोल मार्केट तथा द्वारका में मंत्रालय के आवासीय परिसरों की मौजूदा स्थिति को अतिरिक्त सुविधाएं एवं अनुरक्षण व्यवस्थाए लैंडस्केपिंग एवं गार्डनिंग इत्यादि के माध्यम से समुन्नयन किया जाता है। के जी मार्ग तथा आर के आश्रम मार्ग आवासीय परिसरों की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए सिविल कार्य अग्रणी चरण में हैं।

विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों से विशेष प्रापणए चालू किफायत उपायों की दृष्टि से सरकारी वाहनों की अपेक्षाए चांसरी भवन तथा आवासीय परिसर किराए पर लेनेए होटल एवं बागबानी सेवाएं पैनलबद्ध करने और सुरक्षा एवं अनुरक्षण संविदाओं से संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की गयी थी। विदेशों में कार्यरत भारत आस्थानी कर्मचारियों के वेतन को मुद्रा के उतार.चढ़ाव की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए विदेशी भत्ते की समीक्षा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। कठिन स्टेशनों पर भारत.आस्थानी कर्मचारियों को हार्डशिप भत्ते के भुगतान के लिए नियम तैयार किए जा चुके हैं तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ओडीए समिति की सिफारिशों के आधार पर विदेश स्थित मिशनोंध्केंद्रों तथा मंत्रालय के उपयोग के लिए कई कलात्मक वस्तुएं खरीदी गयी है। वित्त मंत्रालय तोशाखाना में प्राप्त उपहार मदों का मूल्यांकन करता है। आरटीआई की भावना के अनुसार तोशाखाना में प्राप्त उपहारों की सूचना तिमाही आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।

परियोजना प्रभाग

यह प्रभाग किराए की देयता कम करने के लिए निर्मित संपदा के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करता है तथा जिन स्टेशनों पर प्लाट अधिगृहित किए गए हैंए वहां निर्माण.पूर्व तथा निर्माण कार्यकलापों में शीघ्रता लाता है। विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलित निम्न भू. संपदा मूल्यों के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिग्रहण के लिए उपलब्ध उपयुक्त संपदाओं का पता लगाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इस समय विदेशों में स्थित 91 केंद्रों पर मिशनध्केंद्र प्रमुखों के लिए 85 चांसरी एवं आवास भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसके अलावा विदेश स्थित तीन केंद्रों पर सांस्कृतिक केंद्रों के लिए संपदा अधिगृहीत की जा चुकी है।

यह प्रभाग विभिन्न विनिर्माण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करता रहता हैए ताकि समय पर उनका प्रारम्भनध्समापन सुनिश्चित किया जा सके। आबुजा, आदिब अबाबा, बहरीन, बैंकाक, बर्लिन, ब्रासिलिया, ब्रुनी, कैंनबरा, दार.ए. सलाम, ढाका, दोहा, इस्लामाबाद, गैबरोन, काबुल, काठमांडु, खारतुमए निक्सियाए आस्लोए पोर्ट लुईस (चांसरी एवं विश्व हिंदी सचिवालय), पोर्ट ऑफ स्पेनए सेंटियागो, सिंगापुरए ताशकंद, वार्सा, बैलिंगटन, सिडनी, कोलालम्पुर, डबलिन और कोलंबो तथा पेरिस स्थित चांसरी तथाध्अथवा आवासों पर विर्निर्माण और पुनर्निर्माण कार्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा वास्तुकार रेखाचित्र तैयार करने से लेकर विर्निर्माण/आधुनिकरण की वास्तविक प्रगति के भिन्न–भिन्न चरणों में हैंए यह प्रभाग ठोस प्रयासों के माध्यम से ब्रासिलिया में चांसरी एवं आवासीय परिसर का विनिर्माण कार्य पूरा करने तथा बहरीन में निविदा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चांसरी एवं आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रस्तुत करने का कार्य पूरा करने में समर्थ रहा है। आबुजा तथा काबुल में निर्माण परियोजनाएं पूरा होने वाली है। इस समय अभिकल्पन एवं निविदा चरण में अधिकांश परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2015 में विर्निर्माण चरण तक पहुंच जाने की संभावनाएंए जिनमें दारे.सलामए खार्तूमए निकासियाए पोर्ट ऑफ स्पेन एवं पोर्ट लुईस (चांसरी तथा डब्ल्यूएचएप), ताशकंद एवं वैलिंगटन शामिल है।

दुबई में चांसरी भवन का आधुनिकीकरण लगभग पूरा होने वाला है। पेरिस तथा वांशिगटन में सांस्कृतिक स्कंधध्भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रयोग करने के लिए संपदा का आधुनिकीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

निर्मित संपदा के अधिग्रहण में वाशिंगटन (मिशन सांस्कृतिक स्कंध), पोर्ट मोर्सबी (चांसरी एवं आवास) उल्लेखनीय है। काबुल हेल्सिंकी

तथ जगरेब संपदा की खरीद के प्रस्ताव अग्रणी चरण में है। हनोई ;चांसरी तथा राजदूत आवासद्धए यांगोन ;चांसरीद्ध तथा बेलग्रेड ;राजदूतावास आवासद्ध में निर्मित संपदा के पट्टे पर अधिग्रहण के लिए स्थानीय सरकार के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इसके अलावाए गोगांछु ;चांसरी एवं आवास के लिए भूमिद्धए बैंकाक ;आईबीपी तथा राजदूतावास आवास के लिए प्लाटद्धए सुवा ;चांसरी एवं आईसीपी के लिए भूमि के प्लॉटद्ध का अधिग्रहण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरानए संशोधित अनुमानों में मंत्रालय के पूंजी परिव्यय बजट के अंतर्गत 270 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। चालू अधिग्रहणधविर्निर्माण परियोजनाओं तथा वत्तीय वर्ष 2014–15 मे पूरी होने वाली परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजटीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की गयी है।

■■

सूचना का अधिकार और मुख्य जन सूचना अधिकारी का कार्यालय

20

मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पूर्ण कार्यान्वुयन के प्रयासों को जारी रखा। मंत्रालय में प्राप्तय आवेदनों पर अधिनयम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच इन अधिनियमों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आदान–प्रदान सत्र का आयोजन किया गया।

1 जनवरी, 2013–31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, सूचना प्राप्तक करने हेतु कुल 2090 आवेदन मंत्रालय में प्राप्त हुए। आवेदनों में पूछे जाने वाले विषयों में विदेशों से संबंध, प्रशासनिक मामले, हज यात्रा तथा द्विपक्षीय दौरों तथा उनपर होने वाले खर्चे शामिल थे। सीपीवी प्रभाग, विदेश स्थिमत मिशनों/केन्दोंन, भारतीय सांस्कृततिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और भारतीय विश्वग कार्य परिषद (आईसीडब्यूतिद ए) इस अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण के रूप में अपने–अपने रिकार्ड खुद रखते हैं।

मंत्रालय ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की संस्तुकतियों को कार्यान्वित किया है और सूचना का अधिकार आवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान को दुरूस्ति करने के लिए एक आरटीआई सेल की स्थासपना की गई है। इस सेल के साथ–साथ मंत्रालय के विभिन्नृ प्रभागों में जन सूचना अधिकारी (पीआईओज) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएएज) इन आवेदनों पर समय से कार्रवाई कर रहे हैं।

संबंधित अधिकारी आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग यथा अधिसूचित सुनवाई करता रहता है। आरटीआई कक्ष अनुसूची के अनुसार सीआईसी के पास तिमाही विवर्णिका दायर करता रहता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने अप्रैल, 2013 में आनलाइन आरटीआई आवेदन स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। मंत्रालय ने इस प्रणाली को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया है तथा आनलाइन आवेदनों को नियमित रूप से निकाला जाता है तथा संबंधित सीपीआईओध्लोक अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। इस मंत्रालय के प्रयासों के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ईआईपीओ योजना (इलेक्ट्रानिक इंडियन पोस्टल आर्डर शुरू किया है, जिसके द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से पोस्टल आर्डर की खरीद की सुविधा हमारे सभी 176 मिशनोंध्केंद्रों को भी प्रदान कर दी जाती है)

21 ई–गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी

इस मंत्रालय ने साइबर मुद्दों से संबंधित अंतर–मंत्रालयी विचार–विमर्श में भाग लिया। फरवरी तथा मार्च, 2013 में क्रमशः रूस तथा फ्रांस के साथ वार्ता आयोजित की गयी थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, संवर्धित सहयोग पर यूएन–सीएफटीडी कार्य समूह तथा साइबर अपराध पर यूएनपी/डीपी ओपन एन्डेड गर्वनमेंटल वर्किंग ग्रुप के संबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञ समूह सहित वैश्विक साइबर मुद्दों से संबंधित द्विपक्षीय विचार–विमर्श में भाग लिया।

साइबर सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मुख्यालय के स्टाफ तथा अधिकारियों तथा विदेशों में तैनाती पर जाने वाले अधिकारियों के साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर विशेष जोर देना जारी रखा।

ईजी एंड आईटी प्रभाग इस मंत्रालय को हर प्रकार का आईटी समर्थन तथा विदेश स्थित मिशनोंध्केंद्रों और मंत्रालय में प्रचालनरत रेह विभिन्न ई–शासन एप्लिकेशनों को समर्थन देता रहा। आईवीएफआरटी (उत्प्रवासन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) का ऑनलाइन वीजा संघटक गृह मंत्रालय के नेतृत्व में 135 भारतीय मिशनों/केंद्रों में संचालित किया गया है। विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों में आई मास (एकीकृत मिशन एकांउटिंग साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है, ताकि इन मिशनों/केंद्रों द्वारा लेखांकन की रिपोर्टिंग को सुचारू बनाया जा सके) पासपोर्ट तथा ऑनलाइन वीजा जैसी मंत्रालय की ई–सेवाओं को ई–ताल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड एग्रीगेशन लेयर) के साथ एकीकृत किया गया है, जो कि राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड योजना है, इस मंत्रालय ने (कॉम्प) डीडीओ साफ्टवेयर तथा ई–प्रापण मिशन मोड परियोजना भी लागू की है।

■■

समन्वय प्रभाग

22

संसद अनुभाग

मंत्रालय का संसद अनुभाग संसद से संबद्ध है तथा संसद से संबंधित सभी कार्य के लिए नोडल बिंदु है। इस कार्य में संसद प्रश्नों के उत्तर के संबंध में संसदीय आश्वासनों की पूर्ति, ध्यानाकर्षण नोटिस एवं प्रस्ताव, अपनी ओर से दिए वाले वक्तव्य, विदेश नीति पर बहस, विधायी कार्य, संसद में रिपोर्ट तथा दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ संपर्क करना शामिल है। संसद सत्र के प्रारंभ से पहले यह अनुभाग प्रधानमंत्री कार्यालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए संसद के आगामी सत्र में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सारांश भी संकलित करता है। संसद अनुभाग संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्राओं तथा संसदीय मैत्री गुटों के कार्यकलापों के लिए के लिए लोक सभा राज्य सभा सचिवालयों के साथ भी आदान–प्रदान करता है। यह अनुभाग विदेश मामलों पर परामर्शदायी समिति की बैठक आयोजित करने तथा विदेश मामलों पर स्थायी संसदीय समिति और अन्य संसदीय समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

समन्वय अनुभाग

समन्वयय अनुभाग राज्यों् के राज्यिपालों, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति केन्द्री य मंत्रियों, राज्यय सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों्, राज्यं विधान सभाओं के सदस्योंद, न्या यपालिका के सदस्यों, सरकारी पदाधिकारियों आदि की विदेश यात्राओं के लिए सभी प्रस्तावों पर राजनीतिक दृष्टि से अनापत्तिन प्रदान करने की कार्रवाई करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक अनापत्ति समय समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, दौरे के राजनीतिक तथा कार्यात्मक औचित्य, आयोजित की गई बैठकें और संबंधित भारतीय मिशनोंध्केन्द्रों की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। अप्रैल, 2013–मार्च, 2014 के दौरान, समन्वय अनुभाग ने ऐसे दौरों के लिए 2014 राजनीतिक अनापत्तियां जारी की।

अनुभाग विदेशी गैर–अनुसूचित उड़ानों तथा राजनयिक उड़ानों और नौसैनिक जहाजों की यात्राओं के लिए राजनयिक अनापत्तियां प्रदान करने से संबंधित कार्यों को भी देखता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रभाग ने विदेशी गैर–अनुसूचित उड़ानों के लिए 490 अनापत्तियां और विदेशी नौसैनिक जहाजों की यात्राओं के लिए 47 राजनीतिक अनापत्तियां जारी कीं।

समन्वय अनुभाग विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोहों में भारतीय खिलाड़ियों और खेल–कूद टीमों की भागीदारी के लिए और विदेशी खिलाड़ियो टीमों की भारत यात्रा के लिए अनुमोदन प्रदान करने की कार्रवाई करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान ऐसे 134 मामलों पर अनापत्ति के लिए कार्रवाई की गई थी।

यह अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यूष्टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मैत्री और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के लिए अनापत्ति देने के अनुरोधों की भी जांच करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, इस प्रभाग ने भारत में 834 सम्मेलनों/सेमिनारों आदि के लिए अनापत्ति जारी की। इसके अलावा, प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए भारत आने वाले विदेशी विद्वानों के दौरों के 1408 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, प्रशिक्षण एवं शोध के लिए विदेशी विद्वानों के भारत आगमन के 143 अनुरोधों पर कार्रवाई की गयी।

समन्वय अनुभाग विदेशी राष्ट्रिकों को पदम अवार्ड प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है। समन्वय अनुभाग द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशनोंध्कंद्रों से नामांकन प्राप्त किया जाता है और मंत्रालय की सिफारिशों से गृह मंत्रालय को अवगत कराया जाता है।

समन्वय प्रभाग द्वारा मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनोंध्केंद्रों में आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई), सदभावना दिवस (20 अगस्त) और कौमी एकता सप्ताह (19–25 नवंबर) भी मनाया जाता हैय (प) मुख्यालय में और विदेश स्थित मिशनोंध्केंद्रों, दोनों स्थानों पर अधिकारियों को शपथ दिलाई गयी थी।

शिक्षा अनुभाग

शिक्षा अनुभाग इस मंत्रालय को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों पर स्व–वित्तपोषित विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस/बीई/बी.फार्मेसी और भारत की विभिन्न संस्थाओं से डिप्लोमा पाठक्रम पूरा करने के लिए 65 मित्र, पड़ोसी एवं विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है। शिक्षा अनुभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं और शोध पाठक्रमों में चयनात्मक प्रशिक्षण इंटर्नशिप सहित इंजीनियरी, चिकित्सा, प्रबंधन, अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठक्रमों के स्नातक एवं परा–स्नातक पाठक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान करने की भी कार्रवाई की जाती है।

शैक्षिक वर्ष 2013–14 के दौरान नामांकित सीटों के लिए शिक्षा अनुभाग में विदेशी नागरिकों से प्राप्त 1 संसाधित आवेदनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

शैक्षिक वर्ष 2013–14 के दौरान 23 एमबीबीएस सीटों के संबंध में और 25 के संबंध में नामांकन/चयन के लिए मिशनों/केंद्रों से 49 आवेदन प्राप्त किए थे। बीडीएस सीटों के थी।

शैक्षिक वर्ष 2012–13 के दौरान 60 बीई सीटों तथा 2 बी फार्मा सीटों के संबंध में 83 आवेदन प्राप्त हुए।

चिकित्साण विज्ञान संस्थायन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्नाधत्कोगत्तेर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 17 सीटें प्रदान की गई थीं।

2013–14 की अवधि के दौरान, 1686 विदेशी छात्रों को भारत में विभिन्नम पाठ्यक्रमों के अध्यतयन के लिए अनापत्ति– प्रदान की गई थी। इस अनुभाग ने विदेशी छात्रों/राष्ट्रिकों के वैकल्पिक प्रशिक्षण/पर्यवेक्षक/शोध/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नामांकन/चयन के लिए उन्हें अनापत्ति प्रदान की।

■■

विदेश प्रचार तथा लोक राजनय

23

विदेश प्रचार

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग को मीडिया से संबंधित कार्य करने के लिए नामित किया गया है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के विचारोंधस्थिति को स्पष्ट करता है। हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में हासिल की गई उपलब्धियों और सफलताओं का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रचार.प्रसार करता है तथा भारत के निकट तथा दूर के पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों पर सूचनाओं का प्रचार.प्रसार करता है। इस कार्य को अति.विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों की प्रेस कवरेज को सुविधाजनक बनाकरए मीडिया के लिए नियमित तथा विशेष संक्षिप्त टिप्पणियों तथा पृष्ठभूमि वार्तालापों का आयोजन करकेए प्रेस विज्ञप्तियों और टिप्पणियों को जारी करके और विदेशी पत्रकारों के परिचय यात्राओं का आयोजन करके किया जाता है। इस वर्ष मंत्रालय ने एक एकीकृत स्मार्टफोन एप शुरू करके मोबाइल सेवा शुरू की है। इस एप्लीकेशन में पासपोर्टए वीजा तथा कोंसली सेवाओं के बारे में सूचना जैसी अन्य सुविधाओं तथा तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को पहल डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करता है। मार्चए 2014 में एमईए एंडिया मोबाइल एप्स को अद्यतन किया गया हैए ताकि एमईएए की वेबसाइट पर नई सूचना को अपलोड करते ही प्रयोक्ताओं के बेहतर से सेवाएं प्रदान करने के लिए पुंश नोटिफिकेशन शामिल किया जा सके।

गणमान्य लोगों के विदेश दौरों की प्रेस कवरेज

इस प्रभाग द्वारा दौरों का उपयुक्त मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपतिए उपराष्ट्रपतिए प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले मीडिया के लिए सभी संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं की जाती हैंए जिसमें पूर्णतः सुसज्जित मीडिया केंद्रों की स्थापना एवं प्रचालन, मीडिया ब्रीफिंग एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस प्रभाग ने राष्ट्रपति की बेल्जियम एवं तुर्की यात्राए उपराष्ट्रपति की तजाकिस्तानए उज्बेकिस्तान, इथोपिया, इरान, पेरू, क्यूबा, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (फुनान्टे किंगडम) एवं अफगानिस्तान यात्रा तथा प्रधान मंत्री की जर्मनी, जापान, थाईलैंड, रूस, यूएसए, ब्रुनी, इंडोनेशिया, मास्को, चीन तथा म्यांमा यात्रा के साथ जाने वाले मीडिया प्रतिनिधिमंडल को सुविधाएं प्रदान की। विदेश नीति के क्षेत्र में प्रयासों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वर्ष के दौरान विभिन्न अवसरों पर मुख्य रूप से ब्रुनीए कनाडाए चीन हंगरीए इरानए इराकए कजाखस्तानए किर्गीस्तानए लाओ पीडीआरए नेपालए नार्वेए रूसए सऊदी अरबए सिंगापुरए श्रीलंकाए तुर्की ए यूएसएए युगांडाए उज्बेकिस्तानए स्विटजरलैंडए माराक्कोए तुमिनियाए सूडानए अफगानिस्तानए मालदीव के तथा नीदरलैंड में दिए गए वक्तव्यों एवं भाषणों का प्रसार करके प्रदर्शित किया।

भारत आने वाले वीवीआईपी व्यक्तियों की यात्रा का प्रेस कवरेज

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के सशक्त आदान–प्रदान में वर्ष के दौरान भारत आने वाले अपातरीय यात्राओं में काफी तेजी आई है। उनमें जापान के सम्राट एवं सामग्री, भूटान नरेश, थाइलैंड की राजकुमारी, सऊदी अरब के शहजादे तथा बहरनी के सम्राट अफगानिस्तान, पूएयर, नेपाल, लिबेरिया, जर्मनी जंजीबार, मालदीव और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, चीन स्लोवाकिया, इराक, भूटान, कुवैत हंगरी व जापान, वियतनाम के महासचिव, कनाडा के गवर्नर जनरल, क्यूबा, फिनलैंड, अजरबेजान, यूएसए, अर्जेनटिना, न्यूजीलैंड, वियतनाम, टुबालु, निकारागुआ, श्रीलंका, चाढ़, लाल्विया, वेनेजुएला, मेसीडोनिया, यूएसई, इरान, ओमान, क्वमिंग के महासचिव माननीय आंगा खान, संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के अध्यक्ष की यात्रा प्रमुख है। इन यात्राओं को उपयुक्त कवरेज देने के लिए भारत आस्थानी विदेशी मीडिया तथा भारत यात्रा पर आने वाले मीडिया को सहायता प्रदान की गयी थी। यह प्रभाग प्रथम भारत. चीन मीडिया मंच आयोजित करने में सक्रिय था तथा इसने नवंबरए 2013 में एशिया.योरोप विदेश मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक कवर किया।

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय

सरकारी प्रवक्ता के कार्यालय ने भारत की विदेश नीति के संचालन से संबंधित रोजमर्रा के घटनाक्रमों पर सूचना के प्रसार के लिए केंद्रों के रूप में काम किया। इस कार्यालय ने प्रमुख घटनाक्रमों पर नियमित ब्रीफिंग का आयोजन करके पूरे वर्ष के दौरान भारतीय एवं

विदेशी मीडिया के साथ संपर्क स्थापित किया जिनका भारत की विदेश नीतिए आवक एवं जावक उच्च स्तरीय दौरों तथा रोजमर्रा के विदेश प्रचार महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से सरोकार था। वर्ष 2013.14 के दौरानए इस प्रभाग द्वारा 255 प्रेस विज्ञप्तियांए 87 प्रेस वार्ताए 26 संयुक्त प्रेस वक्तव्य तथा 62 मीडिया एडवाइजरी जारी की गई। मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को पृष्ठभूमि संबंधी ब्रीफिंग उपलब्ध कराकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार के दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य का संप्रेषण करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के साथ प्रधान मंत्रीए विदेश मंत्री तथा अन्य गणमान्य लोगों के साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। इन साक्षात्कारों की प्रतिलिपियां मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अपने यू ट्युब चैनल ीजजचरूध्ण्लवनजनइमण्बवउध्नेमतध्उमं पदकपं पर मीडिया संपर्कों का लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रारंभ किया। संयुक्त प्रेस सम्मेलनों तथा राजकीय यात्राओं के दौरान हैदराबाद हाउस में आयोजित होने वाले संयुक्त प्रेस सम्मेलनों तथा करार पर हस्ताक्षर के समारोहों जैसे सभी मीडिया कार्यक्रमों के वीडियो भी यु.ट्यूब पर अपलोड किया गया एमईए इंडिया मोबाइल एप शुरू होने के बाद मंत्रालय के सूचना प्रयासों में एक नया उपस्कर शामिल किया गया है।

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट http://mea.gov.in/ भारत सरकार के सर्वाधिक व्यापक रूप से देखे जाने वाले वेबसाइटों में से एक है और यह इस प्रभाग के प्रचार.प्रसार प्रयासों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 25 सितंबरए 2012 को मंत्रालय के नए नवीकृत वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया जिसमें विविध प्रकार से उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा वास्तुशिल्पीय विशेषताओं का समावेश किया गया है। वेबसाइट के प्रेस अनुभाग को वास्तविक समय के आधार पर प्रधान मंत्रीए मंत्रियोंए प्रेसए सरकारी प्रवक्ताओं और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की संक्षिप्त टिप्पणियों द्वारा विदेश नीति पर भाषणों/साक्षात्कारों/विवरणों से अद्यतन बनाया जाता है। इस वर्ष से प्रारंभ कर के, वीडियो ब्रिफ्रिंग भी वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट दो सरकारी वेबसाइटों में से एक हैए जिसमें भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाता है। हमारे अधिकांश मिशनों की वेबसाइटों का पुनः अभिकल्पन किया गया है तथा मंत्रालय के वेबपोर्टल के मानक टेम्पलेट के अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म

देश तथा विदेश में व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का सफलतापूर्व प्रयोग कर रहा है:.

- YouTube http://www.youtube.com/MEAIndia;
- YouTube Public Diplomacy: https://www.youtube.com/user/Indiandiplomacy;
- Facebook http://www.facebook.com/MEAIndia;
- Facebook Public Diplomacy: https://www.facebook.com/IndianDiplomacy;
- Flickrhttp://www.flickr.com/photos/meaindia;
- Google+ https://plus.google.com/u/0/103329416703761384109/posts;
- Twitter@IndianDiplomacy, @MEAIndia Posts.

बीबीआईपी व्यक्तियों की भारत तथा विदेश यात्रा के संबंध में वीडियोए फोटोग्राफ तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों तथा मंत्रालय के अन्य समारोहों का प्रसार वास्तविक समय पर लगभग इन मंचों के माध्यम से किया जाता है। इन प्रयासों को व्यापक समर्थन मिला है।

हिन्दी, ऊर्दू एवं अरबी वेबसाइट

वेबसाइट के हिन्दी खंड को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। आम जनता के साथ–साथ भारतीय मीडिया के प्रतिनिधि भी हिन्दी वेबसाइट की सराहना कर रहे हैं। विदेश प्रचार प्रभाग ने अब ए एन आई के साथ वेबसाइट के ऊर्दू एवं अरबी में अनुवाद की भी व्यवस्था की है। इन साइटों को भारत में एवं हमारे पड़ोसी देशों में ऊर्दू मीडिया के साथ–साथ अरबी भाषी देशों द्वारा बड़े पैमाने पर एक्सेस किया जाता है। यह मंत्रालय स्पेनिश, अरबी तथा ऊदू के लिए विशेष वेबसाइटों का निर्माण कर रहा है, जिसे विदेश मंत्रालय की वेब पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय मोबाइल एप्लिकेशन

विदेश मंत्रालय ऐसे प्रथम मंत्रालयों में से एक हैए जिन्होंने अपना मोबाइल एप शुरू किया है। विदेश मंत्रालय का मोबाइल एप्लीकेशन मंत्रालय में मौजूद पूरी डिजिटल व्यवस्था को मोबाइल मंच पर लाने के लिए एकीकृत करता हैए जिसे विदेश सचिव श्री रंजन मथाई ने 29 जुलाई, 2013 को शुरू किया था। 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस मोबइल एप के पहले से ही रजिस्टर कर लिया हैए जो भारत तथा विदेशों में इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इस समय यह एक एंड्रायड तथा आईओ एप मंचों पर उपलब्ध है तथा एकल डिजिटल मोबाइल मंच पर पासपोर्टए वीजा तथा कोंसली सेवाओं सहित इसके आउटरीच कार्यकलापों तथा मंत्रालय के नागरिक केंद्रित सेवाओं से संवर्धित सूचना प्रदान करता है। एमईए की वेबसाइट पर नई सूचना अपलोड होते ही मोबाइल पर नियमित एलर्ट भेजकर प्रयोक्ताओं के प्रयोग के लिए संवर्धित करने के लिए इस एप में पुश

नोटिफिकेशन नई विशेषता है।

भारत–अफ्रीका सम्पर्क वेबसाइट

विदेश प्रचार प्रभाग और आथएएनएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत–अफ्रीका सम्पर्क वेबसाइट भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। इस वेबसाइट पर विकास सहयोग पर विशेष बल के साथ भारत एवं अफ्रीका पर समाचार, लेख एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वेबसाइट को www.indiaafricaconnect.in पर अक्सेस किया जा सकता है तथा इसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

विदेशी पत्राकारों की परिचय यात्रा

विदेशी मीडिया में भारत का बेहतर और समकालीन चित्रण प्रस्तुत करने के लिए भारत में विदेशी पत्रकारों की परिचय यात्रा इस प्रभाग के प्रयासों का मुख्य घटक है क्योंकि ये पत्रकार भारत की राजनीतिए विदेश नीतिए अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में होने वाले विकास के बारे में अद्वितीय, प्रत्यक्ष प्रभाव की जानकारी प्राप्त करते हैं।

मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ भी यात्रा पर आए इन पत्रकारों की बैठकें आयोजित की गयी। इस वर्ष के दौरान भारत के पडोसी देशों के पत्रकारों सहित विश्व के विभिन्न भागों के 12 देशों से लगभग 180 विदेशी पत्रकारों को भारत आमंत्रित किया गया। इनमें नेपाल, मालदीवए बांग्लादेश चीनए भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गीजस्तान, कजाखस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चैक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस, रोमानिया, बुल्गानिया, क्रोएशिया तथा सर्विया शामिल हैं। परिचय यात्राओं में पाकिस्तान से अटारी एवं अमृतसर में एकीकृत जांच केंद्र के लिए 22 संपादकों तथा वरिष्ठ पत्रकारों का समूह शामिल है। इसके अलावा, अल्जीरिया, जोर्डन, इराक, लेबनान, मिस्र, सूडान, मोरक्को, फिलीस्तीन, यमन, लीबिया, ट्यूनेशिया तथा सीरिया जैसे पश्चिम एशियाई देशों से 22 संपादकों/वरिष्ठ पत्रकारों, श्रीलंका से 20 वरिष्ठ संपादकों/पत्रकारों तथा कोलंबिया, फिलीपींस, म्यांमा, मलेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रूनी, स्टेसलाम, इंडोनेशिया तथा लाओ पीडीआर से 20 संपादकों/पत्रकारों की परिचय यात्राएं आयोजित की गयी।

प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा सम्मेलन

यह प्रभाग पड़ोसी तथा विकासशील देशों में मीडिया संगठनों मे क्षमता निर्माण के उद्देश्य से कार्यकलाप करता है तथा इसने मार्च, 2013 में अफगानिस्तान के 30 युवा पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया। नेपाल तथा भूटान के 20 युवा पत्रकारों ने दिसंबरए 2013 में प्रिंट तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया तथा मार्च, 2014 में ऐसे प्रशिक्षण के लिए 28 युवा एवी एवं प्रिंट मीडिया पत्रकार भारत आए। मंत्रालय ने आपसी सूझबूझ संवर्धित करने के लिए तथा सूचना अंतर को पूरा करने के लिए चुनिंदा अफ्रीकी देशों में सूत्रधारों की तैनाती के लिए पीटीआई तथा आईएएनएस को भी सहायता प्रदान की है।

मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2013 को प्रथम भारत–चीन मीडिया मंच भी आयोजित किया, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा चीन जनवादी गणराज्य के राज्य परिषद सूचना कार्यालय में मंत्री श्री कैण मिंग झाओ द्वारा किया गया था। दोनों देशों से प्रमुख मीडिया व्यक्तियों ने इस मंच में भाग लिया।

11–12 नवंबर, 2013 में आयोजित 11वें ऐसेम विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए एसेम देशों से विदेश मंत्रियों के साथ आने वाले विदेशी मीडिया प्रतिनिधिमंडल को भी सुविधा प्रदान की गयी थी।

विदेशी श्रव्य एवं दृश्य एजेंसियों द्वारा वृत्तचित्र

इस प्रभाग के कार्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र विदेशी श्रव्य एवं दृश्य एजेंसियों द्वारा वृत्तचित्र पर कार्यवाही करना है। इस अवधि के दौरान भारत में वृत्तचित्रों की शुटिंग के लिए मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशी प्रोडक्शन एजेंसियों से 60 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इस प्रभाग ने विदेशों से वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओंध्सीमाशुल्क सुविधा पत्र जारी करने के लिए मिशन/केंद्रों के अनुरोधों पर भी कार्यवाही कीए जिनकी शुटिंग के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिए गए हैं। ऐसे पत्र जारी करने से पूर्व इन अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की गयी है। इस अवधि के दौरान 80 सीमाशुल्क सुविधा पत्र जारी किए गए थे।

भारत आस्थानी विदेशी मीडिया को संभारतंत्रीय सहायता

यह प्रभाग 200 भारत अस्थानी विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करता हैए ताकि वे प्रत्ययन दस्तावेजोंए वीजा तथा आवासीय परमिटों के मामले में सहायता के साथ.साथ हित के विभिन्न मुद्दों पर संबद्ध सूचना की व्यवस्था के माध्यम से सरलता से कार्य करने में उनकी सहायता की जा सके।

लोक राजनय

एक्सपीडी प्रभाग को विशेष रूप से भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं तथा सामान्य रूप से भारत के हितों की प्रस्तुत करने तथा मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए इस प्रभाग ने निर्णय लेने वालोंए मीडिया, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, विद्यार्थियों तथा सामान्य लोगों से लेकर विभिन्न हितधारकों तक पहुंच बनी है। फेसबुक, ट्विटर बैंक लोकप्रिय सामाजिक मीडिया भेजने के साथ–साथ प्रभाग की वेबसाइट का

प्रयोग इस मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यकलापों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। विदेशों में भारत की रचनात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए वृत्तचित्र फिल्मोंए पुस्तकों तथा द्विमासिक पत्रिका भारत परिदृश्य को प्रिंट तथा डिजिटल फार्मेट में प्रकाशित किया गया है।

आउटरीच कार्यकलाप:

एक्सपीडी प्रभाग ने कई आउटरीच कार्यकलाप किए थे, जिनमें भारत तथा विदेशों में विदेश नीति पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का समर्थन करना, भारत तथा विदेशों में ट्रैक 1.5 फार्मेट में प्रमुख विचार–केंद्रों के साथ वार्ता करना भारत में कई संस्थानों में प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करना तथा विदेशों से प्रमुख व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना शामिल है।

विभिन्न व्याख्यान श्रंखला

लोगों तक पहुँचने के क्रियाकलापों की लोक राजनय पहल के रूप में, जिसका उद्देश्य भारतीय विदेश नीति की रूप–रेखा, इसके मुद्दों को सामान्य जन को और विशेषकर युवाओं, को स्पष्ट करना है। प्रभाग ने भूतपूर्व राजनायिको और वरिष्ठ मंत्रालयी कार्यकारियों को देश में चहुँ ओर विभिन्न प्रमुख संस्थानों में व्याख्यान देने हेतु लगाया गया है। वर्ष 2013–14 में 12 व्याख्यान आयोजित किए गए, जबकि 31 मार्च, 2014 तक 2014–15 वर्ष में पहले से ही 5 व्याख्यान दिए जा चुके हैं, इस योजना में आईआईटी और आईआईएम के साथ–साथ भारत के विभिन्न भागों में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। व्याख्यान श्रंखला का विवरण www.mea.gov.in पर उपलब्ध है।

लोक नीति उद्बोधन

प्रभाग ने कर्नाटक सरकार की सहभागिता में 29 जुलाई, 2013 को बंगलूरू में श्री सलमान खुर्शीद विदेश कार्य मंत्री (ईएएम) द्वारा प्रथम लोक नीति उद्बोधन आयोजित किया गया। अपने व्याख्यान में, विदेश कार्य मंत्री (ईएएम) ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की विदेश नीति में लोगों की सहभागिता और जुड़ाव महत्वपूर्ण है चूँकि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की बात को मजबूती प्राप्त होती है। विदेश कार्य मंत्री ने कर्नाटक में आधारित कोरपोरेट हाऊस के 60 के लगभग सीईओ से भी चर्चा की और देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आर्थिक आदान–प्रदान में विदेश मंत्रालय की भूमिका के बारे में बतलाया। विदेश कार्य मंत्री द्वारा द्वितीय लोक नीति उद्बोधन का आयोजित देहरादून में 17 अगस्त, 2013 को किया गया था। श्रोतागणों में, जिनमें सिविल सोसाईटी के प्रबुद्ध सदस्य और वरिष्ठ रक्षा वैक्तिक और विद्यार्थी शामिल है, ने उद्बोधन के उपरांत प्रश्न–उत्तर सत्र में बढ–चढ़ कर भाग लिया।

वृत्तचित्र का विशेष प्रदर्शन

टेरी मैक्लुहान पुरस्कार विजेता फिल्मकार द्वारा शांति के लिए एक शैरानी सीमांत गांधी बादशाह जान के चलचित्र का विशिष्ट फिल्मांकन प्रभाग द्वारा 20 जनवरी, 2014 को खान अब्दुल गफ्फार खान की 26वीं बरसी पर आयोजित किया गया।

राजनायिक कॉर्प्स की ब्रीफ्रिंग:

एक मासिक विशिष्टता, नई दिल्ली में आधारित राजनायिक कॉर्प्स की ब्रिफिंग जनवरी 2014 से पिछले माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में राजनायिक निकायों के बारे मे ब्रीफ शुरू हो चुका है। राजनायिक समुदाय का जबाव अभिभूत करने वाला है।

भारत वैश्विक:

विदेश मंत्रालय और अखिल भारतीय रेडियों (अखिल भारतीय रेडियों एफएम गोल्ड) संयुक्त पहल, भारत वैश्विक एक अद्वितीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और रेडियों श्रोताओं को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों के नजदीक लाया जाना है। इस देश–विशिष्ट कार्यक्रम में, प्रत्येक सप्ताह हमारे राजदूतों में से हर एक को ने अपने क्रमशः देश के साथ हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण आश्य के बारे में, रूचिपूर्ण उदाहरणों, तथ्यों, देश के प्रोफाईल, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों, भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों, भारतीय निवेश द्विपक्षीय व्यापार गठबंधन, व्यक्तिओं व्यक्तिपरक संबंध और भारतीय डायसपोरा संबंधों के बारे में वकतव्य दिया। प्रत्येक रूपक 8–10 मिनट का है और प्रत्येक शुक्रवार को 2:30 पूर्वाह्न को एआईआरएफएम गोल्ड चैनल (106 हर्डस) पर प्रसारित किया जाता है। भारत वैश्विक के सभी ऐपीसोड पौडकास्ट पर उपलब्ध है और मोबाइल/आईपैड पर एमपी फार्मट में डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्य सचिवों से मुलाकात:

राज्य सरकारों और संघ शामिल सरकारों के मुख्य सचिवों की, श्रीमती सुजाता सिंह, विदेश सचिव के साथ 13 मार्च, 2014 को एक बैठक का आयोजन, राज्यों और संघ शामिल प्रदेशों से संबंधित विदेश नीति मामलें जैसे कि पासपोर्ट,वीजा और कांसुलर मुद्दे, पुलिस सत्यापन,प्रोतोकाल संबंधित मामले और आर्थिक राजनय से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु आयोजित की गई थी।

ट्रैक 1.5 परिचर्चा:

राजनय अध्ययन संस्थान (आईडीएस), रियाद से एक 4 सदस्यी दल ने आवजर्वर अनुसंधान प्रतिस्ठान के साथ 1.5 ट्रैक परिचर्चा के लिए नई दिल्ली का भ्रमण किया, जिसका आयोजन 26 अप्रैल,

2013 को किया गया।

फ्रांस के साथ, प्रथम ट्रैक 1.5 पहल का आयोजन पैरिस में 23–24 मई, 2013 को किया गया। आवजर्वर अनुसंधान प्रतिष्ठान और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान केंद्र ने दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा की।

चतुर्थ आस्ट्रेलिया–भारत गोल मेज परिचर्चा का आवजर्वर अनुसंधान प्रतिष्ठान के साथ 3–7 फरवरी, 2014 को लोवी अंतर्राष्ट्रीय नीति संस्थान, सिडनी में आयोजित की गई।

ट्रैक–II परिचर्चाः

पाकिस्तान के साथ ट्रैक–II की 35 वी चक्र पहलः भारत–पाकिस्तान नीमराणा पहल 17–21 अगस्त, 2013 को दिल्ली में आयोजित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय विचारकों के साथ परिचर्चा

छठी एमईए–आईआईएसएस विदेश नीति परिचर्चा का आयोजन 3–4 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में किया गया। एमईए–आईआईएसएस अन्तर्राष्ट्रीय स्टैटजिक स्टडीज संस्थान लंदन के सहयोग से आयोजित किया गया।

एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने "गल्फ और एशिया राजनैतिक संबंधों और विकसित परिदृश्य में रणनीतिक विकल्प" कैम्ब्रिज,यू.के में गल्फ अनुसंधान केंद्र द्वारा 1–7 जुलाई, 2013 के दौरान आयोजित किया गया।

प्रतिनिधिमंडलों का आगमन

चीनी प्रवक्ता की अगुवाई में एक शिष्टमंडल के साथ नई दिल्ली ने 14 मई, 2013 को लोक राजनय, आउटरीच और कूटनीतिक के क्षेत्र में उनके क्रमशः दृष्टिकोणों और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए संवाद आयोजित की गई थी।

श्रीमती वर्नाडेटे मारीयानी गियरलिंगर, आर्थिक नीति और यूरोपियन एकीकरण की उप मंत्री, आर्थिक, परिवार एवं युवा मामलों के आस्ट्रियन मंत्रालय के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ एक परिचर्चा सत्र का आयोजन विभाग ने करवाया।

कूरू, नाईजीरिया में नीति और कूटनीति अध्ययन राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीपीएस) से एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल ने विभाग के साथ परिचर्चा की।

सेमीनार और सम्मेलनः

एक्स पीडी प्रभाग ने निम्नलिखित का आयोजन करने हेतु सहयोग दिया है। इस आशय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोगः ट्रैड चुनौतियों और परिप्रेक्ष्य' का आयोजन 2–3 मई, 2013 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना तंत्र और राष्ट्रमंडल सचिवालय, वाणिज्य और उद्योग के सार्क चैबंर की सहभागिता में आयोजित किया गया। टैगोर पर 1–2 जून, 2013 को एक सेमिनार आयोजित किया गया। जुलाई 2013 में वियना में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 'नैगोशिएटिंग एथनिसिटी': पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक विशेषताओं की नीतियों और प्रदर्शन को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 24 अगस्त, 2013 को भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य मे पावर मैट्रिक्स पर एक सेमिनार का आयोजन 24 अगस्त, 2013 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अतंर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी कोलकाता, द्वारा किया गया। 'क्षेत्रवाद, उप क्षेत्रवाद और तारतम्य' की थीम पर 18–19 अगस्त, 2013 को राजवाल, मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जदवपुर संगठन और मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विद्यार्थियों को साथ लेते हुए, युवा भारतीयों के जयपुर चैप्टर में 19 सितंबर, 2013 को भारत के लोक राजनय पर प्रस्तुतिकरण; विदेश नीति पर युवा फोरम और सरकारी विधि कालेज द्वारा मुंबई में 11–12 अक्तूबर, 2013 को एक विदेश नीति कान्केलेव और अंतर कालेज प्रश्नोत्तर प्रतिस्पर्धा का आयोजन; भारतीय सागर अध्ययन की सोसाईटी द्वारा 26–27 अक्तूबर, 2013 पर भारतीय सागर और केंद्रीय एशिया भूमि लॉकड स्टेटों पर एक सम्मेलनः 8–9 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में भारत, चीन और सम्पर्क राष्ट्रः अंतर सांस्कृतिक आदान–प्रदान की टैगोर परम्परा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; विदेश कार्य के युवा फोरम मुंबई और आवजर्वर अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा समन्वित द्वारा 10–19 नवंबर,2013 को वैश्विक सुशासन पर तृतीय एशिया फोरम; 'क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सुद्धिकरण और सांस्कृतिक संबंध प्रोन्नति' कलकत्ता फोरम की 9वीं कुनमिंग 21–22 नवंबर, 2013 को कोलकत्ता में आयोजित की गई है; 10–12 दिसम्बर, 2013 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'वैश्विक क्रम का पुर्नदृश्यावलोकनः दक्षिण से परिप्रेक्ष्य संबंधों पर सम्मेलन; राष्ट्रीय संबंधों पर सम्मेलन; 17 जनवरी, 2014 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए); में 'स्वास्थ्य संबंध' पुनुरूद्धार के रास्ते की ओर; 'भारत और अफ्रीका' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 8–9 फरवरी, 2014 को सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन (आईएससीएम), कोलकत्ता में भारत–म्यांमा संबंधों पर अंतर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 11–12 मार्च, 2014 को पाण्डेचेरी विश्वविद्यालय में भारतीय विदेश नीति में संघीय अनिवार्यता पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। बांग्लादेश ने कुलपतियों से 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 4 से 19 दिसम्बर, 2013 को भारत की यात्रा की थी। अफ्रीकी देशों से 9 युवा सांसदों ने 8 से 15 मार्च, 2014 को यात्रा की थी। अफ्रीकी देशों से 29 युवा पत्रकारों ने 8–23 मार्च, 2013 को जामिया मिलिया

इस्लामिया से दिल्ली में आयोजित अवसर जमाल किदवई दूरसंचार शोध केंद्र में प्रशिक्षण भारत की यात्रा की थी।

भारत परिप्रेक्ष्य

एक द्विमासिक फलैगशिप प्रकाशन अब 14 भाषाओं में मुद्रित किया जा रहा है तथा व्यवसायिक *http://www.indiaperspectives.in* पर भी उपलब्ध है भारत परिप्रेक्ष्य 14 भाषाओं मे सभी मोबाइल मंचों तथा एपल गुगल प्ले ओर एंडराएड जैसे सभी स्टोरों पर भी उपलब्ध है इस पत्रिका के परिचालन में विशेष रूप से युवाओं में कई गुना विस्तार हुआ है। जो कि डिजिटल विषय वस्तु एक्सैस करने के लिए अधिक से अधिक माबाईल उपकरणों का उपयोग कर रहे है।

भारत फाईल

विदेश प्रचार तथा लोक राजनय द्वारा एक प्रवर्तनकारी कार्यक्रम है इससे दूरदर्शन चैनल विश्व में कही से और भारत से सर्वश्रेष्ठ समाचारों से संबंधित विडियोस का उपयोग कर सकते है इसका डाउनलोड एवं संम्पादन कर सकते है। यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

भारत–चीन सांस्कृतिक संबंधों पर विश्वकोष

भारत–चीन सांस्कृतिक संबंधों पर विश्वकोष को संयुक्त संकलन समिति (जेसीसी) की प्रथम बैठक बीजिंग में 1–2 अप्रैल, 2013 को आयोजित की गई थी। बैठक में विश्वकोष परियोजना के भविष्य के कदम और महत्वपूर्ण समय–सीमा पर निर्णय लेने पर विचार–विमर्श किया गया। जेसीसी की दूसरी बैठक, नई दिल्ली में 30–31 अक्तूबर, 2013 को आयोजित की गई। दोनों पक्ष विश्व कोष के लिए प्रविष्टियों के लिए दिशानिर्देशों को सरल करने पर सहमत थे। जेसीसी की तृतीय बैठक 21–22 जनवरी, 2014 को बीजिंग, चीन में आयोजित की गई थी और चौथे दौर का आयोजन 24–26 मार्च, 2014 को नई दिल्ली मे किया गया।

प्रकाशन

वर्ष के दौरान कॉफी टेबल पुस्तकों सहित उच्च स्तरीय प्रकाशन अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में शुरू किए गए थे ताकि भारतीय राजदूत व वरिष्ठ वार्ताकार उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सौंप सकें। पुस्तक समिति की 29वीं,30वीं तथा 31वीं बैंठकें आयोजित की गई थी जिनमें भारतीय महिलाएं, की सकारात्मक ध्वनि का भाव प्रस्तुत करने के लिए वितरण करने हेतु पुस्तकें तथा बच्चों की रूचि की पुस्तकों की खरीद पर विचार किया गया था इसके अलावा देश भक्ति संगीत तथा शास्त्रीय संगीत लोक प्रति बालीवुड और वाद्य संगीत की पुस्तकों को भी खरीद एवं प्रसार के लिए अनुशांसित किया गया था। 8 मार्च, 2014 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक काफी टेबल पुस्तक जारी की गई थी।

भारत–अफ्रीका एक सांझी भावी पहल

भारत–अफ्रीका के अंतर्गत आयोजित एक प्रतियोगिता, युवा आर्दशवादियों के लिए एक समापन समारोह, एक विदाई समारोह, आयोजित किया गया, नई दिल्ली में 6–7 अप्रैल, 2013 को एक साझा पहल आयोजित की गई थी हैदराबाद में बूट शिविर के दौरान विकसित नए सहयोगी व्यापारिक विचारों पर युवा आर्दशवादियों ने प्रस्तुतिकरण दिए थे तथा प्रमाणपत्र दिए गए थे।

फिल्म एवं संगीत

दूरदर्शन ने मार्च 2014 से 8 से 8:30 बजे के प्राईम टाईम स्लाट पर सप्ताह में 2 बार अपने राष्ट्रीय चैनल पर एसपीडी वृत चित्र फिल्मों का प्रकाशन पहले से ही शुरू कर दिया गया है निम्नलिखित फिल्में पूरी कर ली गई है। गोआना में इंडियन डायसपोरा, सूरीनाम तथा जमैका; ब्रीजिंग वर्ड रूट से रूट्स; टी स्टोरी ऑफ इंडियन एक्रास दी सैवन सी ब्रिजिंग वर्ड; वन थाउसैंड और वन नाईटः इंडियन ड्रीम अंडर अरेबियन स्काई; डी परफैक्ट मैच; ए लैंड स्टेरनजरी फैलिमियर; ग्रामरूट से ग्लोबल; टी क्वानटम इंडियन; जागृति एक्स्प्रैस; योगाः एलाइंनिग टू टी सोर्स श्रीलंका में भारत की विकास समर्थित परियोजनाएं।

हिन्दु नैक्टर वंडरिग इन सैक्रड इंडिया, टैफ मेड इन इंडिया, बांबे नुवावा तथा श्याम बेनेगल की वृत चित्र फिल्मों के फाईनल कट का प्रिव्यु वृत चित्र जांच समूह द्वारा किया गया था।

उस्ताद अमजद अली खान, पडिंत हरी प्रसाद चौरसिया, पंडित रवि शंकर उस्ताद विलायती खान तथा अन्य के शास्त्रीय वाह्य संगीत शामिल करके 'द मास्टरो' की चार सीडी का एक सैट निकाल गया था तथा विदेश स्थित मिशनरियों को भेजा गया था।

कालेज तिलनियां में फिल्म निर्माता यासमीन किदवई द्वारा निर्मित एसपीडी वृत चित्र फिल्म 'नो प्राब्लम' को जंजीबार अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृतचित्र का पुरस्कार मिला था तथा इसे सात अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सरकारी रूप से चयनित किया गया था। दोहा में अलजजिरा फिल्म महोत्सव में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन अवार्ड प्राप्त हुआ था। इस फिल्म को 30 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में दादा साहब फाल्के महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

निर्माता विनय कुमार बेही द्वारा निर्मित एक्सपीडी वृतचित्र फिल्म का प्रिमियर 16 फरवरी, 2014 को इंडिया हैबिटाट सेंटर में आयोजित किया गया था। दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने इसकी सराहना की थी तथा इसे जर्मन और स्पेनिश भाषाओं में डब किया जा रहा है। स्लवानिया दूरदर्शन चैनल पर इसके प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

विश्व स्तरीय फोटोग्राफी तथा वीडियों प्रतियोगिता इंडिया इज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अवसर पर तथा 2013 संकलन की घोषणा करने के लिए 3 जून, 2013 को एक समारोह आयोजित किया गया था विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए थे। इस समारोह में श्री अनुराग कश्यप "(इंडिया इज 2012 के ब्रांड एम्बैस्डर) के द्वारा बनाई गई एक लघु फिल्म का समारोह में फिल्मांकन किया गया था।

तृतीय पर्वत गूज महोत्सव 9–11 अगस्त, 2013 को थिम्फू,भूटान में आयोजित किया गया। इस महोत्सव को सियाही द्वारा भारत–भूटान प्रतिष्ठान के सहयोग से आयोजित किया गया। एक्सपीडी वृतचित्र, अ.ला. कोर्ट, सिक्स यार्ड ग्रेस और मृणालिनी साराभाई, का महोत्सव में फिल्मांकन किया गया। भूटान की महामहिम, महारानी ने, महोत्सव का उद्घाटन किया।

'दी ईनर पाथ' नामक एक बौद्ध फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, 6 सितंबर, 2013 को ईएएम द्वारा किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन एशिया सिनेमा के उन्नयन के लिए नैटवर्क (एनईटीपीएसी) द्वारा किया गया। महोत्सव के भाग के रूप में, बौद्धों पर विभिन्न फिल्मों जिनमें एक्सपीडी प्रभाग द्वारा तैयार की गई शामिल है, का फिल्मांकन किया गया।

लोक सेवा प्रसारण ट्रस्ट (पीएमबीटी) का वार्षिक ओपेन फ्रेम महोत्सव का आयोजन 11–21 सितंबर, 2013 को किया गया। पीएसबीटी द्वारा बनाई गई एक्सपीडी प्रभाग की दो फिल्मों का फिल्मांकन आलोचनात्मक श्रेणी में किया गया। ये दोनों 'दी क्वांटम इंडियन' और साझा मुस्लिम मिस्टीक मुयुजिक आफ इंडियन हैं।

पुरस्कार

एक्सपीडी प्रभाग ने सचिव, संचार और आईटी मंत्रालय से भारत में लोक राजनय के लिए विषय वस्तु में दक्षता के लिए एनटीए आईसीटी विश्व संचार अवार्ड प्राप्त किया है। यह पुरस्कार दूरसंचार विभागों और इलैक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग, नवीन और नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद और कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय घरेलू उद्योग संगठनों द्वारा कार्यालयी रूप से समर्थित है।

24 विदेश सेवा संस्थान

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) के लिए एक महत्वपूर्ण विकास मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अनुसार एक नए प्रशिक्षण फ्रेमवर्क को अंगीकार करना था। नए प्रशिक्षण फ्रेमवर्क को विदेश कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा अनुमोदित किया गया और जुलाई 2013 में विदेश सचिव द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सम्प्रेषित किया गया।

एक एमईए कार्यकारी कार्यशाला 14–15 मार्च, 2014 को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी। विदेश सचिव, श्रीमती सुजाता सिंह ने मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यशाला में भाग लिया। इसका उद्देश्य योग्यता को बढ़ाना सामान्य मूल्यों का पुर्नस्थापन और सेवा की आवश्यकताओं की पुर्नवीक्षा था। यह एमईए के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रथम समेकित संगठन की अपनी तरह की एक कार्यशाला थी।

2011 बैच के प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद, 7 जून, 2013 को एफएसआई में श्री सलमान खुर्शीद, विदेश कार्य मंत्री, मुख्य अतिथि के साथ, एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। 2011 बैच के सबसे उत्तम प्रवीक्षार्थी के लिए विदेश कार्य मंत्री का स्वर्ण पदक सुश्री मानुस्मृति को दिया गया। राजदूत बिमल सान्याल मैमोरियल पदक श्री कार्तिक जी अय्यर को सर्वोत्तम शोध निबंध के लिए दिया गया। डीन के कमौन्ड्रशन प्रमाणपत्र को श्री राजीव कुमार मिश्रा और सुश्री सी सुषमा को प्रदान किया गया। सर्वोत्तम खिलाड़ी ट्राफी श्री जिनसी के माटम को प्रदान की गई।

2012 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थी (ओटी) ने दिसम्बर, 2012 मे एफएसआई में कार्यभार गृहण किया। उनके वर्ष भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन व्याख्यानों के साथ–साथ विभिन्न संस्थानों के साथ जोड़ कर किया गया। इसमें कई सारे विषयों पर माडयूल जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक राजनय, सांस्कृतिक राजनय और सामाजिक विकास शामिल है। इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्थापना, लेख, प्रोतोकॉल, कान्सूलर मामले, बाह्य प्रचार, लोक राजनय, प्रतिनिधित्व योग्यता और भारत का सांस्कृतिक विरासत पर माडयूल भी शामिल हैं।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को समवर्ती सामाजिक विकास मुद्दों, अव्यस्क अधिकार और समस्याएं, सूचना का अधिकार और मानव अधिकार मुद्दों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। सामूहिक विचार–विमर्श, मामलों का अध्ययन और प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुतकरण को भी अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच सृजनात्मक सोच विकसित करने हेतु शामिल किया गया। एक पांच साप्ताहिक पाठ्यक्रम विदेश व्यापार भारतीय संस्थान के साथ सहयोग से उनमें प्रबंधन और आर्थिक मुद्दों में उनकी कुशलता को विकसित करने के लिए आयोजित किया गया। अधिकारी प्रशिक्षुओं को विदेश के भारतीय मिशनों के कार्य से अवगत करवाने के लिए, अधिकारी प्रशिक्षुओं को बैंकाक और क्वालालम्पुर मे दी समूहों में भारतीय मिशनों का भ्रमण करवाया गया।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारतीय सेना, नेवी और वायुसेना के साथ एचैमेंट पर भेजा गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड, एआरसी, मुम्बई में भ्रमण किया और अग्रणी वित्तीय संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ परस्पर चर्चा के सत्र किए। एक 'भारत दर्शन' टूर प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए देश के समृद्ध सांस्कृति भिन्नता, विरासत और आर्थिक और पर्यटक समृद्धि से रूबरू होने के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश में चारों ओर विभिन्न राज्यों में एक माह लम्बा जिला एटैचमेंट शामिल किया गया जहां अधिकारी प्रशिक्षुओं को मूल स्तर पर प्रशासन के बारे में सीखने और राज्य और जिला प्रशासन की कार्यात्मकता को सीखने का मौका मिलता है। प्रशिक्षु अधिकारियों को मंत्रालय में डैस्क अटैचमैंट काल पर भी भेजा गया जहां वे भाषा प्रशिक्षण के लिए विदेश में नियुक्ति करने से पूर्व वास्तविक कार्य के लिए विदेश में नियुक्ति करवाने से पूर्व वास्वतिक कार्य का अनुभव प्राप्त करें।

2013 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने दिसंबर, 2013 में कार्यभार गृहण किया।

1996 बैच के निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए ई–मेल आधारित मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2013 में दिया गया।

आईएफएस अधिकारियों का पति/पत्नियों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 24–28 फरवरी, 2014 को किया गया। इसमें भारत की विदेश नीति, विदेश में भारतीय राजनायिक के जीवन, मेजबानी और प्रतिनिधित्व कौशल पर व्याख्यान थे। एफसीआई और विदेश मंत्रालय पत्नी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया था।

20 मई से 3 जून, 2013 को मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों (एसओ) के लिए एक रिफ्रैशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुभाग अधिकारियों के लिए अन्य रिफ्रैशर पाठ्यक्रम, जिनमें कान्सूलर और वाणिज्यक मामले शामिल हैं, 3–14 मार्च, 2014 को आयोजित किया गया। मंत्रालय के सहायकों और लिपिकों के लिए तीन आधारभूत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बीपीसी) का 12–26 जुलाई, 2013 को, 17–26 सितंबर, 2013 और 2–16 जनवरी, 2014 को आयोजन किया गया। सात आईएमएएस पाठ्यक्रमों का सहायकों और लिपिकों के लिए 2–11 अप्रैल, 2013, 5–14 जून, 2013, 17–26 जनू, 2013, 27 जून–8 जुलाई, 2013, 19–29 अगस्त, 2013, 18–30 दिसम्बर, 2013 और 19–28 फरवरी, 2014 को आयोजन किया गया।

आतंरिक सेवा प्रशिक्षण

27 जून, 2013 को रक्षा एटैची के लिए एक उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

विदेश राजनायिकों के लिए कार्यक्रम

एफएसआई विश्व के चहूँ ओर देशों के साथ दोस्ती की दरारों को भरने के प्रयास में विदेशी राजनायिको के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में रत हैं। एफसीआई द्वारा विदेशी राजनायिकों के लिए दो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (पीसीएफडी) का 17 अप्रैल से 17 मई, 2013 और 3 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2013 को क्रमशः सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक देशों के 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बांग्लादेश के राजनायिकों और आईओआर–एआरसी सहित 20 प्रतिभागियों के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का आयोजन 4–13 सितंबर, 2013 को आयोजित किया गया था।

आसियान राजनायिकों के लिए एक माह लम्बे विशिष्ट पाठ्यक्रम का नवंबर–दिसम्बर, 2013 को आयोजन किया और आठ आसियान देशो से तीस राजनायिकों और आसियान सचिवालय ने भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों के दौरान, कक्षा में दिए गए प्रशिक्षण के अतिरिक्त विदेशी राजनायिकों को विभिन्न स्थानों पर और एतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता के संस्थान और दिल्ली के बाहर ले जाया गया।

एफएसआई ने सितंबर और नवंबर, 2013 में विनियम कार्यक्रम पर भारत आने वाले 250 आसियान विद्यार्थियों के लिए भारत विदेश नीति पर व्याख्यान भी आयोजित किए गए।

विदेश सहभागी संस्थानों के साथ संबंध

एफसीआई ने पिछले वर्ष ईराक,ईरान लाईबेरिया और कुवैत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वियतनाम से 7 सदस्यीय दल ने 8 अप्रैल, 2013 को एफसीआई का भ्रमण किया और डीन, एफएसआई से मुलाकात की। मि. कुई जियाकी की अगुआई में एक चार सदस्यी चीनी प्रतिनिधिमंडल ने 16 अप्रैल, 2013 को प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री पैट्रिक हेंस अंतर्राष्ट्रीय राजनाम प्रशिक्षण प्रमुख की अगुआई में जर्मनी के एक 5 सदस्यी दल ने 29 मई, 2013 को एफसीआई का भ्रमण किया। सुश्री रहिमाह यूप, निदेशक, आईडीएफआर की अगुआई में मलेशियन राजनायिक के एक दल ने 27 अगस्त, 2013 को प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए भ्रमण किया। मोजाम्बिक से एक 6 सदस्यीय समेकित प्रतिनिधिमंडल ने 27 नवंबर, 2013 को एफएसआई का भ्रमण किया।

25

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिन्दी का प्रचार–प्रसार

मंत्रालय के पास हमारे मिशनों/केंद्रों पोस्टो की सहभागिता सहित विदेश में हिंदी के उन्नयन और उन्नति के लिए सुसंगठित कार्यक्रम है। इस योजना के तहत, हिंदी पाठ्यपुस्तकों सहित हिंदी शिक्षण सामग्री और बाल पुस्तकें, हिंदी पुस्तकें, हिंदी सीखने की सी. डी., कम्प्यूटरों पर कार्य करने के लिए हिंदी का सॉफ्टवेयर शब्दकोश इत्यादि को शैक्षिक संस्थाओं और अन्य एन जी ओ को भेजे जाते हैं। मंत्रालय के मिशन/केंद्र आदि विभिन्न विदेशी संस्थानों को और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय मिशनों द्वारा विदेश में हिंदी संबंधी क्रियाकलापों के लिए भी समर्थन सहायता प्रदान करते हैं।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन विदेश में हिंदी को बढ़ावा देने और उन्नयन करने की पहल में से एक है। इन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों को विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा हिंदी के उन्नयन और विदेशों में भारतीय संस्कृति सम्मिलित स्थानीय आयोजनों के संगठन के साथ आयोजित किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन सउल और बैंकॉक में आयोजित किए गए हैं।

हिंदी को एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आगे बढ़ाने हेतु, भारत और मॉरीशस के मध्य एक द्विपक्षीय करार के तहत एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरीशस में की गई है। सचिवालय के क्रियाकलापों में विदेश मंत्रालय और मॉरीशस सरकार के उसके मॉरीशस सहभागी सहयोग करते हैं।

मंत्रालय विदेशी विद्यार्थियों को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य में सहयोग प्रदान करता है। प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ को प्रदान करने का प्रावधान है। इस वर्ष 71 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को विदेश मंत्रालय ने उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा। मंत्रालय ने 'हिंदी दिवस' के अवसर पर 'हिंदी पखवाड़े' का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। दो प्रसिद्ध हिंदी कवियों को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया गया।

'हिंदी दिवस–2013' के अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और साथ ही विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा अलग–अलग हिंदी प्रतियोगिताएं आयाजित की गईं। इन कार्यकलापों के आयोजन के लिए विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को विशेष अनुदान संस्वीकृत किए गए।

हिंदी सलाहकार समिति विदेश मंत्री (ई ए ए) की अध्यक्षता में कार्य करती है। विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में 26 जनू, 2013 को आयोजित की गई।

विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मुख्यालय के साथ–साथ सभी मिशनों/केंद्रों में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस वर्ष भी विदेशी सेवा संस्थान परिसर में 10 जनवरी को 'विश्व हिन्दी दिवस' का आयोजन किया। चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, मंगोलिया, कजाकिस्तान आदि देशों के विदेशी छात्र केंद्रीय हिन्दी संस्थान के आगरा व दिल्ली केन्द्र में हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हिन्दी सीखने वाले विदेशी छात्रों के लिए 'निबंध प्रतियोगिता' आयोजित की गई थी। 20 सफल सहभागियों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर एक लघु 'काव्य पाठ' का भी आयोजन किया गया था।

राजभाषा संसदीय समिति ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने हेतु 2013–2014 के दौरान जम्मु, जयपुर,गाजियाबाद और बैगंलूर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यलयों की यात्रा की।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) 26

सांस्कृतिक संबंधों हेतु भारतीय परिषद (आईसीसीआर) की स्थापना 9 अप्रैल, 1950 को भारत बाह्य सांस्कृतिक संबंधों को सूत्रबद्ध करने और नीतियों का कार्यान्वयन करने और कार्यक्रमों के उद्देश्य से; सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने और भारत और अन्य देशों के आपसी समझ विकसित करने; संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित और विकसित करने; और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संसाधनों/उपायों को करने के लिए की गई थी।

परिषद विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत विदेशी विद्यार्थियों द्वारा अंडर–ग्रेजुएट, पोस्ट–ग्रेजुएट और डाक्टरी कार्यक्रमों के साथ–साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कि अभियांत्रिकी फॉमेसी, लेखांकन व्यापार प्रबंधन और प्रबंध इत्यादि को करने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। 2013–14 के शैक्षिक वर्ष में, परिषद ने 120 देशों को कवर करते हुए 3465 छात्रवृत्तियां प्रदान की और अपने खाते में 5200 के लगभग छात्रवृत्ति धारकों को बढ़ा लिया।

विदेशी विद्यार्थियों के लिए कल्याण क्रियाकलापों के भाग के रूप में परिषद ने नई दिल्ली में "21वां अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी महोत्सव" "संस्कृति द्वारा मित्रता" के नाम से 11 नवंबर, 2013 में नई दिल्ली का आयोजन किया गया था। 19 देशों के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों ने इस महोत्सव में भाग लिया और अपने पारम्परिक और भिन्न सांस्कृतियों की झलक प्रस्तुत की।

परिषद ने अपने छात्रवृत्ति धारकों व साथ ही साथ स्ववित्त पोषित विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याण उपायों जिनमें, भारत के साथ अपनत्व बढ़ाने और बृहद ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करने के कैंप (15 शीतकालीन कैम्प जनवरी 2013 में 7 ग्रीष्म कालीन कैंप मई–जून, 2013 में आयोजित किए गए) का आयोजन किया गया। आईएफएस प्रवीक्षार्थियों के लिए मई 2013 में भारतीय संस्कृति पर एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विदेश स्थित 35 कलाकारों प्रर्दशर्नियों के लिए प्रायोजन प्रदान किया जिसमें कैलीग्राफी कला, भारतीय स्थापत्य, समकालीन भारतीय कला एवं लघु भित्तिचित्रकला जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। परिषद ने पेरू और त्रिनिडाड एवं टौबेगों से दो प्रदर्शिनियों की मेजबानी की और अपने क्षैतिज श्रृंखला के तहत भारत में 22 प्रर्दशर्नियां लगाई। परिषद ने विदेश का दौरा करने के लिए वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया।

आईसीसीआर में विभिन्न देशों में 85 सांस्कृतिक समूहों का प्रायोजन किया। इसमें जर्मनी मे पूर्णकालीक भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए 5 सांस्कृतिक समूहों का भी प्रायोजन किया जिसमें भारत के राष्ट्रपति और बेल्जियम नरेश की उपस्थिति में जर्मनी में "कनैकटिंग कल्चर्सः डेज आफ डंडिया" महोत्सव के समापन तथा "यूरोपेलिया इंडिया" फैल्टिवल इन बैल्जियम के उद्घाटन के समारोह को प्रतीक बनाने के लिए पंडित बिरजू महाराज की मंडली द्वारा "रितू संहारा" के प्रस्तुतिकरण का आयोजन शामिल था।

परिषद भारत के अंदर आने वाले विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों तथा इसके बाहर सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का संचालन करती है। परिषद ने भारत के विभिन्न भागों में सूफी महोत्सव का आयोजन किया जिसमें स्पेन, अजरबैजान, रूस ट्यूनेशिया, गुजरात तथा मुंबई आदि की मंडलियों द्वारा दिनांक 4–16 फरवरी, 2013 तक कलामंचन किया गया।

चौथा अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव, जिसमें भारत के अलावा ईरान, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्वीडन तथा मिस्र के कलाकारों ने भाग लिया, का आयोजन 9–15 फरवरी, 2014 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में किया गया।

फरवरी 2013 में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड मेले में परिषद ने कांगो, गिनी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की। इसने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा श्रीलंका से आए समूहों द्वारा दी गई प्रस्तुति के साथ 15 से 27 फरवरी, 2013 तक विश्व वाद्ययंत्र उत्सव, भारत में अन्य स्थानों और नई दिल्ली में 14–27 मार्च, 2013 तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय जैज उत्सव, 28–30 मार्च, 2014 तक चौथा अंतर्राष्ट्रीय जैज उत्सव, 12–19 अक्तूबर, 2013 भारत के विभिन्न भागों में कजाकिस्तान, फ्रांस, मलेशिया, रूस, मैक्सिको और चीन से आए समूहों द्वारा समकालीन तथा लोक नृत्य प्रस्तुति, 29 नवंबर–01 दिसंबर, 2013 तक विदेश मंत्रालय की ओर से एक एजेंसी कार्य की तरह 7वें दक्षिण एशियाई बैण्ड उत्सव का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने वियतनाम, भूटान, चेक गणराज्य, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, कोलम्बिया, मैक्सिको, लिथवेनिया, इटली तथा मिस्र से आए 15 विदेशी सांस्कृतिक समूहों के दौरे की मेजबानी की। परिषद ने भारत में 95 समूहों के भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए और 67 गैर–सरकारी

संगठनों/सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

परिषद ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन पीठें स्थापित कीं। 01 जनवरी, 2013 से मार्च 2014 के दौरान 10 पीढ़े स्थापित की गईं जोकि ऑस्ट्रेलिया (03 पीठ), बेल्जियम, कनाडा, जमैका, स्वीडन, थाइलैण्ड, उक्रेन तथा यूएसए में स्थित है। नई पीठों की स्थापना के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 11 समझौता ज्ञापनों पर वार्ता के लिए अनुमोदन दे दिया है।

परिषद ने वस्तुतः चार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किएए नामशः (i) 7–9 मार्च, 2013 तक नई दिल्ली में "वर्ल्ड रिलिजियन्सः डाइवर्सिटीए नॉट डिसेन्शन" विषय पर इंटरफेथ पर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया, (ii) 11–।3 जुलाई, 2013 तक "दर्शन व विज्ञानः भारत–जर्मन वार्ता एवं आयाम", (iii) 09–10 अक्तूबर, 2013 तक ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित "विवेकानंदः नए विश्व के लिए उनकी दृष्टि और विरासत, और (iv) साउथ एशियन स्टडिज़ एशोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मोनाश विश्वविद्यालय के सहयोग से 20–23 फरवरी, 2014 के दौरान मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में "विवेकानंद– मानव और उसके योगदानों का पुनः मूल्यांकन"।

परिषद द्वारा 07–09 मार्च, 2013 के दौरान आयोजित आंतरिक इंटरफेथ सम्मेलन की कार्यवाहियों पर आधारित एक पुस्तक सेज पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित की गई थी और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर 04 मार्च, 2014 को उप राष्ट्रपति श्री एम. हामीद अंसारी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 24–26 मार्च, 2014 के दौरान परिषद और आई.आई.सी ने संयुक्त रूप से "वर्तमान और भविष्य के लिए पारंपरिक संस्कृति का महत्व" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

आई सी सी आर संस्कृति एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत परिषद ने क्रमशः इण्डोनेशिया और स्पेन से दो वरिष्ठ फेलो और ईरान, सर्बिया तथा स्लोवेनिया से तीन कनिष्ठ फेलो नियुक्त किए।

परिषद ने विदेशों में आयोजित कार्यक्रम (ओ वी पी) के तहत विश्व के विभिन्न भागों के लिए 16 प्रतिष्ठित विद्वानों की यात्राओं को प्रायोजित किया और अन्य 13 लेखकों/शिक्षकों को बेल्जियम में "यूरोपालिया–इंडिया" उत्सव में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया। "विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम" के तहत परिषद ने विदेश से 14 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यात्रा की मेजबानी की।

इस समय आई सी सी आर 36 पूर्ण केन्द्रों और 02 उप केन्द्रों को संचालित कर रहा है। परिषद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तथा कार्यक्रमों की विविधताए दोनों में वृद्धि करने में समर्थ रही है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को न केवल नृत्य एवं संगीत कक्षाओं के माध्यम से बल्कि कला एवं मूर्तिकला की प्रदर्शनी, दर्शनशास्त्र, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक रुझानों, भारत में सिनेमा आदि से संबंधित स्थानीय और भारत से आए आगंतुकों, दोनों द्वारा साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा भी प्रचार–प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक केन्द्रों का केन्द्र बनाना है।

परिषद पांच भिन्न भाषाओं में पांच पत्रिकाओं, जैसे "इंडियन होरिजोन" (त्रैमासिक, अंग्रेजी), "गगनांचल" (छमाही, हिंदी), "पेपलेस डी ला इंडिया" (स्पेनिश, छमाही), राकोन्त्र आवेक लैंद (फ्रेंच, छमाही) और "ठकाफत–उल–हिंदी" (अरबी, त्रैमासिक) का भारत में तथा विदेश में वितरण के लिए प्रकाशन करता है ।

हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए परिषद भारत तथा विदेशों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे हिंदी सम्मेलन, संगोष्ठी और भारत तथा विदेश में पुस्तकों का लोकापर्ण। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए परिषद विदेश स्थित अपने केन्द्रों में हिदी शिक्षकों को नियुक्त करता है। परिषद विदेश स्थित भारतीय मिशनों और भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को हिंदी की पुस्तकें, शब्दकोश, पत्रिकाएं तथा अपनी हिंदी प्रकाशन "गगनांचल" भी भेजता है। विदेशी नागरिकों को हिंदी भाषा पढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विश्व में विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पीठें स्थापित की हैं। परिषद ने अपने सभागार में "अक्षरम" के सहयोग से फरवरी 2013 में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव और 21 अप्रैल, 2013 को कविता सम्मेलन आयोजित किया था और यू.के में भारत के उच्चायोग तथा हिंदी समिति द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिता में चयनित छात्रों के लिए भी भारत भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया था। जनवरी 2013 से मार्च 2014 के दौरान परिषद ने "गगनांचल" के अंक 36 के 1,2,3, व 4–5 (मिश्रित अंक) प्रकाशित किया और एक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया।

परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा सौंपा गया वयैक्तिक पुस्तक समूह और पाण्डुलिपि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पुस्कालय के सत्व है। मौलाना आजाद की वयैक्तिक पुस्तकों तथा पाण्डुलिपि की सूची पुस्तक रूप में तीन भाषाओं- अरबी, उर्दू तथा फारसी में मुद्रित हुई है। दशकों से पुस्तकालय कई गुना बढ़ा है और वर्तमान में इसके 50,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं। परिषद ने ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालयों को नियंत्रित करने तथा भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों का समन्वय जारी रखा है।

इस अवधि के दौरान परिषद ने गुरदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 06 व्यक्तियों की आवल प्रतिमाएं ईरान, स्पेन, फिलीपीन्स, स्लोवेनिया, मैक्सिको तथा फिलीस्तीन को भेजी थी। ■■

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

27

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अफ्रीका, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, लातिन अमेरिका तथा यूरोपीय संघ में राजनैतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक घटनाक्रमों के बारे में शोध एवं अध्ययन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है और व्यापक वैश्विक भू–रणनीतिक तथा भू–राजनैतिक परिवेशों का विश्लेषण किया। इन निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार सप्रू हाउस पेपर्स जारी किए गए, इश्यू/ब्रीफ्स तथा दृष्टिकोणों के रूप में किया गया जिन्हें भा.वि.का.प. की वेबसाइट पर डाला गया है।

भा.वि.का.प. ने बड़ी संख्या में कार्यक्रमों, व्याख्यानों, सम्मेलनों तथा आउटरीच कार्यकलापों का आयोजन किया। पुस्तकालय में सुधार करके नई पुस्तकें मंगाई गईं। भा.वि.का.प. के सभागार का नवीनीकरण कार्य पूरा हो गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भा.वि.का.प. अभिशासन नियमावली के आधार पर भा.वि.का.प. के प्रचालन हेतु विनियमों का मसौदा तैयार किया गया था।

शोध संकाय में एक निदेशक (शोध), 15 शोध फेलो और लघु अवधि के लिए भर्ती किए गए दो प्रशिक्षक और पूरे विश्व में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के घटनाक्रमों और आर्थिक रुझानों, राजनैतिक तथा सुरक्षा पर अध्ययन तथा अनुसंधान और व्यापक वैश्विक भू–रणनीति तथा आर्थिक परिवेश का विश्लेषण से जुड़े विद्वान शामिल हैं। उन्होंने ये परिणाम मीडिया में लैबों और इस अवधि के दौरान भा.वि.का.प. के 03 सप्रू हाउस पेपर्स, 16 पुस्तकों तथा 14 ईश्यू ब्रीफ्स और 46 दृष्टिकोण के प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशन के द्वारा प्रचारित किया।

अपने आउटरीच पहल के रूप में भा.वि.का.प. ने अपने वेबसाइट को और अधिक पाठक अनुकूल तथा सामग्री से प्रचुर बनाने के लिए पुनररूत्थान किया। विदेश नीति मुद्दों से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसने पुस्तक अनुसंधान अनुदान, सप्रू हाउस पेपर अनुदान तथा सम्मेलन अनुदान भी संस्थापित किया है। जबकि भा.वि.का.प. की अपनी इन–हाउस अनुसंधान क्षमता का तेजी से निर्माण हो रहा है, प्रतिष्ठित विद्वानों तथा विदेश नीति के पूर्ण व्यावसायिकों को भारत के मुख्य क्षेत्रों या देशों या मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों से संबंधों पर परियोजनाओं का विशिष्ट क्षेत्रों पर अनुसंधान करने के लिए तैनात किया जा रहा है। भा.वि.का.प. ने ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं की मेजबानी भी की।

02 फरवरी, 2012 को स्थापित चीन से संबंधित कोर समूह ने पाण्डुलिपि के प्रकाशन का कार्य पूरा किया जिसे अब प्रकाशित किया जा चुका है। पाकिस्तान से संबंधित कोर समूह ने सात बैठकें आयोजित की हैं और अब विद्वानों तथा विशेषज्ञों के द्वारा एक सार–संग्रह तैयार कर रहा है। उसी प्रकार अफगानिस्तान से संबंधित कोर समूह ने भी दो बैठकें आयोजित की हैं और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों तथा विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन कर रहा है। म्यांमा से संबंधित कोर समूह भी प्रस्तावित है।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका तथा मालदीव से संबंधित भा.वि.का.प. कोर समूह संबंधित देशों में समकालीन घटनाओं की निगरानी तथा विश्लेषण करती है। जहां उपयुक्त हो, अध्ययन तथा नीति सिफारिश, विदेश मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया जाता है।

प्रकाशन

इस अवधि के दौरान भा.वि.का.प. की पत्रिका "भारत त्रैमासिक" नियमित रूप से प्रकाशित जा रही थी। इसके अतिरिक्त भा.वि.का.प. ने निम्नलिखित शीर्षकों से संबंधित प्रकाशन निकाले हैं–

दी 18थ नेशनल कांग्रेस ऑफ दी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चीनः ए मेजर टर्निंग प्वाइंट फॉर चीन, 2013, भा.वि.का.प.; ज्योत्सना बक्शी द्वारा जियोपोलिटिक्स डायनिज्म ऑफ इंडिया – ताजिकिस्तान रिलेशंस, प्रथम भा.वि.का.प. निवेदिता रे को भारत–अफ्रीका अकादमिक कांफ्रेंस–अफ्रीका एण्ड इंडिया; ए पार्टनरशिप फॉर डेवेलपमेंट एण्ड ग्रोथ, पी.एम कामथ की इंडिया ऐज एन इमर्जिंग मेजर पावरः फॉरेन – पालिसी थ्रस्ट एरियाज, सांडीपानी की जिकोलोनाइजेसन, डेवेलपमेंट एण्ड डायसपोरा; दी एफ्रो–इंडियन ऐक्सपिरियन्स, इंडिया–वियतनामः एजेंडा फॉर स्ट्रेन्थनिंग पार्टनरशिप, राजीव भाटिया, विजय सखूजा, विकास रंजन; इंडिया एण्ड जी.सी.सी कंट्रीज, ईरान एण्ड इराकः इमर्जिंग सिक्यूरिटी पर्सस्पेक्टीव, सुधीर देवड़े, स्वर्ण सिंह, रीना मार्वाह; ट्रांसफॉर्मिंग

साउथ–एशिया इमपेरेटिव्स फॉर ऐक्शन, राजीव भाटिया, स्वर्ण सिंह, रीना मार्वाह; इंडिया एण्ड एशिया – एक्सपैंडिंग दी पार्टनरशिप, राजीव भाटिया, विजय सखूजा; इंडिया–अजरबैजानः दी सिल्क रूट कनेक्शन, निवेदिता रे; बेस्ट ऑफ इंडिया क्वार्टरलीः ए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, अमीतव त्रिपाठी, राजीव के. भाटिया तथा विजय सखूजा द्वारा भा.वि.का.प. अनुसंधान लैब 2012, भा.वि.का.प. तथा किर्गीस्तान गणराज्य, बिश्केक, विदेश मंत्रालय के राजनयिक अकादमिक द्वारा फर्स्ट इंडिया–सेंट्रल एशिया डायलॉग; स्कंद तयाल द्वारा इंडिया एण्ड रिपब्लिक ऑफ कोरिया–इनगेज्ड डेमोक्रेसिज़; ज्योत्सना बक्शी द्वारा जियोपालिटिकल डायनिज्म ऑफ इंडिया ताजिकिस्तान रिलेशंस, व्हाट्स न्यू ऐट आई.सी.डब्ल्यू. ए (जून 2012 – अप्रैल 2013), इवालविंग पॉलिटिको–स्ट्रैटिजक डायनैमिक्स इन दी गल्फ, जाकिर हुसैन, न्यू फ्रंटीयर्स इन साउथ–साउथ इनरोजमेंट रिलेशनशिप बिटविन इंडिया एण्ड लातिन अमेरिका एण्ड कैरीबियन, अप्रैल 2013, सारंग सिडोर; ए ब्रीज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स, लीगल प्रिनसिपल्स ऑफ ट्रांसबाउण्ड्री रीवर, मई 2013, गणेश श्रीकुमार वर्मा; वियतनाम–इंडिया रिलेशंस एन दी लाइट ऑफ इंडियाज लूक इस्ट पॉलिसी, फरवरी 2012, वो जोन विन्ह, रिजनल इंटीग्रेटेशन इन लैटीन अमेरिका एण्ड दी कैरीबियन ट्रेण्ड्स एण्ड चैलेंजेज, मार्च 2013 एसमीरा मार्लगडाडा; मार्लगडाडा; मरकोसूर, मर्काडोः ए स्टडी ऑन दी ओरिजिन्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रकचर, लेटेस्ट डेवेलपमेंट्स एण्ड दी कन्टेम्पोरेरी ट्रेड पार्टनर्स आफ मरकोसर, फरवरी 2013, नीतिन आर्य, चाइनास चैंजिंग अपरोच टू स्ट्रैटेजी एण्ड नेगोशिएशन, जनवरी 2013, दत्तेश डीय पारुलेकर, थर्ड आईसीडब्ल्यू हैंड बुक, इंडिया वियतनाम एजेंडा फॉर स्ट्रेन्थनिंग पार्टनरशिप, राजीव के भाटिया, विजय सखूजा और विकास रंजन, इंडिया ऐज इमर्जिंग मेजर पॉवर; फॉरेन पॉलिसी थ्रस्ट एरियाज, पी. एम. कामथ, इंडिया एण्ड एशिया; डिपेनिंग दी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, राजीव के. भाटिया, विजय सखुजा और इदरानी तालूकर, रबीन्द्रनाथ टैगोर . एनवाय ऑफ इंडिया; हिज विजन ऑफ इंडिया एण्ड दी वर्ल्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस 09–10 मई, 2013, फ्रर्स्ट इंडिया . सेंट्रल एशिया डायलॉग, बिश्केक (जून 12–13, 2012), इंडिया–सेंट्रल एशिया डायलॉग ।। अल्माटी, कजाकिस्तान 17–18 जून, 2013 (बुकलेट); ट्राईलेटरल डायलॉग ऑन इंडियन ओशियन (टी डी आई ओ) ओ19–20 सितंबर, 2013, इंडियाज फॉरेन पालिसी डिप्लोमैटिक ब्रेकथ्रू एण्ड क्रिटिकल गैप, 7–9 अक्तूबर, 2013 (बुकलेट), इंडिया–वेस्ट अफ्रीकाः ए डायनैमिक रिलेशनशिप एण्ड इमर्जिंग ट्रेन्ड्स, अक्रा, घाना, 14–15 अक्तूबर, 2013 (बुकलेट) भा. वि. का. प. अफ्रीका–भारत चौथा अकादमिक सम्मेलन, इंडिया–फ्रांकोफोन अफ्रीकाः इश्यूज एण्ड चैलेंजेज, डकार, सेनेगल 17–18 अक्तूबर, 2013 (बुकलेट) भा. वि. का. प. अफ्रीका–भारत पांचवां अकादमिक सम्मेलन; सम्मेलन ट्रांसफोर्मिंग साउथ एशियाः इमपेरेटिव्स और स्ट्रैटेजिक प्रोस्पेक्ट्स, राजीव के भाटिया और विजय सखुजा; दिल्ली डायलॉग 5; इंडिया आशियानः विजन फॉर पार्टनरशिप एण्ड प्रोस्पेरिटी; इंडिया–पोलैण्ड रीलेशन इन 21 सेंचुरीः वीस्टास फॉर फ्यूचर कोरपोरेशन।

आउटरीच

भा. वि. का. प. के आउटरीच कार्यक्रमों में देश भर के कई भारतीय विश्वविद्यालयों तथा बुद्धिजीवियों के साथ संयुक्त सम्मेलन तथा संगोष्ठियां शामिल हैं। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में कई देशों में सम्मेलन, संगोष्ठियां और व्याख्यान शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान भा. वि. का. प. ने कुल 92 कार्यक्रमों को आयोजित किया, जिसमें 12 व्याख्यान, 27 सम्मेलन/संगोष्ठियां, 16 द्विपक्षीय सामरिक वार्ताएं, 35 पैन चर्चाएं/ पृष्ठभूमि और 2 पुस्तक लोकार्पण / विमोचन / चर्चाएं कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन हैं, 22–24 जनवरी, 2013 तक "विश्व मामलों में भारतः अगली शताब्दी", 4–5 फरवरी 2013 तक "अरब दुनियाः लोकतंत्र की ओर उन्मुख और इसके निहितार्थ'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1–2 मार्च 2013 तक 'दक्षिण चीन समुद्रः वैश्विक संघर्ष का एक ज्वलंत बिंदु', 4–5 मार्च 2013 तक भा. वि. का. प. – पी. के. राय मेमारियल कॉलेज संयुक्त संगोष्ठी, 'भारत हिस्पैनिक वार्ताः सांस्कृतिक अंतर को पूरा करना' पर 6–8 मार्च 2013 तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 25–26 मार्च 2013 तक 'भारत का दक्षिण एशियाई विदेश शिखर सम्मेलन, 6 अप्रैल 2013 को "श्रीलंका में विकास – भारत के हित और सरोकार" पर एशिया केन्द्र बैंग्लूर में बैंग्लूर संयुक्त शिखर सम्मेलन, 24 अगस्त 2013 को एशिया केन्द्र, बैंग्लूरू में "अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी – भारत के लिए निहितार्थ'' पर भा. वि. का. प.–एशिया केन्द्र, बैंग्लूर का संयुक्त शिखर सम्मेलन 7–9 अक्टूबर 2013 तक ''भारत की विदेश नीतिः राजनयिक दरार और महत्वपूर्ण अंतराल'' पर भा. वि. का. II.– जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 2013 की वार्ता, 25–26 अक्टूबर 2013 तक "भारत–पूर्व अफ्रीका वार्ताः सहयोग के अवसरों की तलाश" ख्मनीपाल विश्वविद्यालय के सहयोग से, पर मनीपाल में आई.ए.एफ. एस.–IIः द्वितीय आंतरिक भा. वि. का. प. अफ्रीका अकादमिक सम्मेलन, 25 नवंबर 2013 को भा. वि. का. प. की प्रथम बैठक ने अफ्रीका तथा पश्चिम अफ्रीका सम्मलेनों से डीब्रीफिंग सत्रों से संबंधित सलाहकार समूहों को पुनर्गठित किया, पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग को वित्तीय सहयोग, 10–11 जनवरी 2014 तक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनः राज्य, समाज और चीन में सांस्कृतिक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना।

भारत से बाहर आयोजित किए गए आउटरीच कार्यक्रमों में निम्नालिखित कार्यक्रम शामिल थे :

5–8 मार्च, 2013 को म्याथमां में मुख्यत राजनीतिक साझेदारों के साथ बातचीत और म्यामां रणनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय; अध्ययन (एमआईएसआईएस) द्वारा आयोजित "भारत–म्यामां संबंध" पर सेमिनार में भाग लेने के लिए आई सी डब्ल्यू ए के प्रतिनिधिमंडल का म्यामां दौरा आईसीडब्यूमिन, – एमजीआईएमओ (मास्को राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान) बातचीत : 21–23 मई, 2013 को सेंट पीटर्सबर्ग तथा मास्को में आरआईएसी तथा संगठनों के साथ बातचीत आईसीडब्यू ए दृ इंस्टीाट्यूट ऑफ ओरिएन्टसल स्टडिज (अलमाटी, कजाकिस्तोन) 17–18 जून, 2013 को अलमाटी कजाकिस्तान में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से द्वितीय वार्षिक भारत–मध्य एशिया बातचीत चीन में अपने समकक्ष संस्थाओं के साथ बातचीत 2–6 सितंबर, 2013 को चाइनीज पिपुल्स0 इंस्टीटयूट ऑफ फॉरन अफेयर्स (सीपीआईएफए), बीजिंग और संघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआईआईएस) के साथ समझौता ज्ञापन तथा बातचीत आईएएफएस– ।। : 14–15 अक्तूबर, 2013 के दौरान "भारत–पश्चिम अफ्रीकाः एक सक्रिय संबंध तथा उभरता रूझान" पर अकरा (घाना) में तीसरा आईसीडब्यूक्र ए – अफ्रीका शैक्षिक सम्मेलनय आईएएफएस – ।। : 17–18 अक्तूबर, 2013 को डकार (सेनेगल) में चौथा आईसीडब्यूक् ए – अफ्रीका शैक्षिक सत्र और 17–21 मार्च, 2014 को एआईआईए–आईसीडब्यू बातचीत में भाग लेने के लिए आईसीडब्यूए का आस्ट्रेलिया (केनबरा, मेलबॉर्न तथा सिडनी) का दौरा।

भारत से बाहर आयोजित आउटरिज कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल हैं, भा. वि. का. प. ने वर्ष के दौरान सामयिक विषयों पर कई व्याख्यान, संगोष्ठियां तथा पैनल चर्चाएं आयोजित की।

भा. वि. का. प. का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हैं, श्री पुष्प कमल दयाल 'प्रचण्ड', नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, 29 अप्रैल 2013; श्री अब्दुल्ला शाहिद, सभापति, पीपल्स मजलिस (संसद) मालदीव, 7 मई 2013, श्री ली. के यांग, चीन जनवादी गणराज्य के राज्य परिषद के प्रधानमंत्री, 21 मई 2013 ब्रूनो ईडूयोर्जे रोडिरग परीला, क्यूबा के विदेश मंत्री 27 मई 2013, श्री हेन बिन्ह मिन्ह, वियतनाम जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्री, 12 जुलाई 2013 श्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, 26 जुलाई 2013, डी विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री, 17 अक्टूबर 2013 क रातू इनोके कूबूआबोला, फिजी गणराज्य के विदेश कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री, 11 फरवरी 2014 को राजदूत जॉन डब्ल्यू अशे संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू. एन. डी. ए.) के 68 वें सत्र के अध्यक्ष, 21 मार्च 2014।

सप्रु हाउस पुस्तकालय, 1955 में अपने स्थापना में ही भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए एक मुख्य स्रोत केन्द्र के रूप में उभरा है। पुस्तकालय में लगभग 141000 पुस्तकें, पत्रिकाएं, मानचित्र और संयुक्त राष्ट्र/यूरोपीय संघ के दस्तावेज हैं। सभी संग्रहण डिजिटल अनुक्रमणिका के माध्यम से देखा जा सकता है और भा. वि. का. प. वेब पोर्टल पर ऑन–लाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग के माध्यम से खोजा जा सकता है। सप्रु हाउस पुस्तकालय का अधिकांश भाग अनुसंधान विद्वानों को डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है, जैसाकि भा. वि. का. प. पत्रिका भारत त्रैमासिक के सभी संग्रहण हैं। अत्याधुनिक साइबर पुस्तकालय से संपन्न सप्रु हाउस पुस्तकालय का संपर्क अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ है जो कि भा. वि. का. प. के विद्वानों को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

पुस्तकालय का लक्ष्य दक्षिण एशिया पर केन्द्रित भारतीय विदेश नीति के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेजों और अनुसंधान सामग्री को व्यापक बनाना है। चूंकि यह हमारे अनुसंधान परियोजनाओं की निरंतर बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए और इसकी सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रयासरत है इसलिए कर्मचारी को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

प्रचार–प्रसार

भा. वि. का. प. ने अपने निर्गतों एवं कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार की नीति शुरू की है ताकि यह अधिक से अधिक संभावित वैश्विक मंचों तक पहुंच सके तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सरोकारों एवं आकांक्षाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। प्रकाशन अलर्ट परिचालित करने और साथ ही वेबसाइट में फेरबदल करने और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की वैश्विक वेबकास्टिंग संबंधी एक प्रणाली मौजूद होने से भा. वि. का. प. के अभिदेश के प्राप्त करने में काफी सहुलियत हुई। भा. वि. का. प. ने परिषद के बारे में वैश्विक स्तर पर स्रोताओं को सूचनाएं देने के लिए अपनी प्रचार– प्रसार विवरणिका को अद्यतन बनाया है एवं इसका फिर से मुद्रण भी करवाया है।

28

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर.आई.एस) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त विचार केंद्र है। इस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों तथा विकास सहयोग पर नीतिगत अनुसंधान में विशिष्टता प्राप्त है। संस्थान की अभिकल्पना विकासशील देशें के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी नीतिगत वार्ताओं और क्षमता निर्माण को संपोषित करने वाले एक मंच के रूप में की गई है। आर.आइ.एस के अनुसंधान कार्यक्रम में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों की सहायता करना मुख्यतः शामिल है। संस्थान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर भारत सरकार को नीतिगत विचार प्रदान करता है और विभिन्न ट्रैक–II प्रक्रियाओं में संलग्न है। आर.आई.एस जिन संस्थाओं से संबद्ध है, उनसे गहन समन्वय से कार्य करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत सामंजस्य को सुदृढ़ बनाया जा सके।

इस अवधि के दौरान आर.आई.एस द्वारा आयोजित चयनित मुख्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) नई दिल्ली में 8 जनवरी 2013 को वर्ष 2013 और आगे के लिए क्षेत्रीय सहकारी पहल पर उभरते तरीकों के विषय पर पैनल चर्चा।

(ii) आर.आई.एस ने भारतीय विकास सहयोग नीति पर एक कार्यशाला नई दिल्ली में 15 जनवरी 2013 को आयोजित की गई। भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम (एफ.आई.डी.सी) में भारतीय विकास सहयोग नीति पर पैनल चर्चा हुई तथा इसमें क्षेत्रीय संकेन्द्रण एवं विकास सहयोग और विषयगत संकेन्द्रण एवं विकास सहयोग पर भी एक–एक सत्र शामिल था। कार्यशाला में अन्य के अलावा भाग लेने वालों में श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आर.आई.एस, श्री पी.एस. राघवन, अपर सचिव (डी.पी.ए) विदेश मंत्रालय, श्री एस.एस. मुखर्जी, डी.जी, आई.सी.डब्ल्यू.ए और श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव (डीपीए–II) विदेश मंत्रालय शामिल थे।

(iii) आर.आई.एस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नैतिकता (जीईएसटी) के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में 28 जनवरी 2013 को भारत में विज्ञान, पौद्योगिकी और नवीनताः प्रवेश, न्यायसंगतता और समावेश के मुद्दों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण तथा नवीकरण नीति और भारतीय संदर्भ में प्रवश एवं समावेश के विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, सिन्थेटिक जीव विज्ञान पर सत्र भी शामिल है। कार्यशाला में अन्य के अलावा डॉ. विश्वजीत धर, आर.आई.एस के महानिदेशक, डॉ. सचिन चतुर्वेदी, आर.आई.एस के वरिष्ठ साथी, डॉ. के. रविश्रीनिवास, आर.आई.एस में सहयोगी साथी, डॉ. टी रामास्वामी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, अर्थशास्त्र के मद्रास स्कूल के प्रो. एन.एस. सिद्धार्थन, डॉ. एस.आर. राव, सलाहकार, डी.बी.टी, भारत सरकार, प्रो. ई. हरिबाबू, सम–कुलपति, हैदराबाद का केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रो. इंदिरा घोष, सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल, जे.एन.यू तथा प्रो. प्रणव देसाई, विज्ञान नीति में अध्ययन के लिए केंद्र, जे.एन.यू, नई दिल्ली शामिल थे।

(iv) आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 4 फरवरी 2013 को भारत–म्यामां के बीच सामरिक साझेदारी पर विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया। श्री हर्षवर्धन श्रींगला, संयुक्त सचिव (बी.एस.एम), विदेश मंत्रालय ने भारत–म्यामां के रिश्तों पर एक अवलोकन पेश किया। सत्र में– श्री पी.एस.राघवन, अपर सचिव, विदेश मंत्रालय ने भारत–म्यामां आर्थिक साझेदारीः भारत के विकास में सहयोग पर, डॉ. वी.एस. शेशाद्री, म्यामां में भारत की राजदूत ने भारत–म्यामां आर्थिक साझेदारीः व्यापार, निवेश, वित्त और संयोजकता पर, श्री राजीव भाटिया, महानिदेशक (आई.सी.डब्ल्यू.ए) ने भारत–म्यामां आर्थिक साझेदारीः ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन पर, और, श्री वाय.एस शहरावत, अध्यक्ष, भारत का भूमि पत्तन प्राधिकरण व सुश्री पेट्रिका मुखिम, सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत–म्यामां आर्थिक साझेदारीः भारत के पूर्वोत्तर का विकास जैसे विषयों पर प्रस्तुतिकरण किया।

(v) आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 12–13 फरवरी, 2013 को

आई.डी.आर.सी–सीआरडीआई के साथ संयुक्त रूप से भारत–कनाडा आर्थिक सहयोग पर एक संवाद आयोजित किया। इसमें (क) व्यापार एवं व्यापक आर्थिक मुद्दे: एक अवलोकन; (ख) ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्रों में सहयोग (ग) आप्रवासन मुद्दे: (घ) नवीनता, उत्पात एवं प्रौद्योगिकी (च) द्विपक्षीय निवेश के मुद्दे (छ) आगे के रास्तों के लिए पैनल चर्चा पर सत्र शामिल थे।

(vi) आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 15–16 अप्रैल 2013 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से दक्षिण–दक्षिण सहयोग: समस्याएं एवं उभरती चुनौतियों के विषय पर दक्षिणी प्रदाताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें अन्य के अलावा श्री वी. होगवू आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के लिए अवर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र, श्री रंजन मथाई, पूर्व विदेश सचिव, श्री दिनेश भाटिया, संयुक्त सचिव (एम.ई.आर), विदेश मंत्रालय, राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष आर.आई.एस और डा. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आर. आई.एस उपस्थित थे।

(vii) आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 2–3 मई, 2013 को विदेश मंत्रालय के राष्ट्रमंडल सचिवालय तथा लोक राजनय प्रभाग के सहयोग से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग: प्रवृत्तियों, चुनौतियों और संभावनाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आधार वयाख्यान दिया तथा डा. साइरस रूस्तम जी, निदेशक आर्थिक मामला प्रभाग, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन ने विशेष भाषण दिया।

(viii) आर.आई.एस ने यू.एन.सी.टी.ए.डी के सहयोग से नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 2013 को भारत में उद्यम नवीनिकरण को बढावा देने के लिए एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया।

(ix) आर.आई.एस, टीईआरआई, एन.ई.पी.ए.डी एवं मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 22 अक्टूबर 2013 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनता के लिए अफ्रीका–भारत सहयोग पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें अन्य के अलावा श्री अस्टन पीटरसन कजारा, वित्त, आयोजन एवं आर्थिक विकास के युगांडा मंत्री (निजीकरण), प्रो. जितिसा.इसा कोनाटे, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीनीकरण की बुरकीना फासो मंत्री और डा. मुशैबू मुहम्मद–अल्फा, वातावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनीकरण, घाना के उपमंत्री शामिल थे। श्री रवि बांगर, अपर सचिव, विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया।

(x) आर.आई.एस, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क तथा वैश्विक दक्षिण पर फोकस ने नई दिल्ली में 29 अक्टूबर 2013 को दोहा से बाली तक : विकास एजेंडा की चुनौतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(xi) आर.आई.एस– एफआईडीसी, यूरोपीय रिपोर्ट विकास ने नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 2013 को विकास सहयोग, व्यापार एवं वित्त : उभरते शैक्षिक आयाम पर एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव, डीपीए–II, विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण पेश किया। सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल हैं श्री गुस्तवो मार्टिन प्रेडा, निदेशक, विकास नीति, यूरोपीय आयोग, डा. स्टीफन क्लिंगोबिल, जर्मन विकास संस्थान, बॉन, डॉ. जेम्स मैकी, विकास नीति प्रबंधन के लिए युरोपीय केंद्र, नीरदलैंड तथा आर.आई.एस से वरिष्ठ साथी।

(xii) आर.आई.एस ने बांग्लादेश विदेश व्यापार संस्थान तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर 3–5 दिसंबर, 2013 को विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मौके पर बाली में व्यापार एवं विकास के लिए संगोष्ठी अयोजित की। संगोष्ठी का विषय था : अल्प विकसित देशों तथा विकासशील देशों के लिए डब्ल्यू.टी.ओ व्यापार सुविधाएं और चुनौतियां।

(xiii) आर.आई.एस में 12 दिसंबर, 2013 को भारत–चीन सहयोग तथा वैश्विक आर्थिक शासन जैसे विषयों पर कार्यशाला हुई।

(xiv) एफआईडीसी कार्यक्रम के रूप में, आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2014 को भारतीय विकास सहयोग नीति: विचार–विमर्श की एक स्थिति के विषय पर सम्मेलन आयोजित किया। सुश्री सुजाता मेहता, विशेष सचिव (ईआर एवं डीपीए), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन की कार्यसूची में चर्चा के लिए विषयो में शामिल थे: उत्तर–दक्षिण तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग: भारत को वास्तव में अद्वितीय क्या बनाता है; भारत विकास सहयोग नीति; सी.एस.ओ, मीडिया एवं विकास सहयोग नीति; तथा विकास सहयोग नीति और व्यापार क्षेत्र। श्री कुमार तुहिन संयुक्त सचिव (डीपीए II), विदेश मंत्रालय ने सत्र की अध्यक्षता की।

(xv) आर.आई.एस ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ तथा आसियान–भारत केंद्र के सहयोग से आर.आई.एस नई दिल्ली में 31 जनवरी, 2014 को आसियान–भारत समुद्रीय परिवहन सहयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने आधार व्याख्यान दिया। संगोष्ठि की कार्यसूची में महा क्षेत्रीय करार:

आसियान–भारत व्यापर एवं समुद्री संयोजकता; आसियान–भारत बंदरगाह व शिपिंग नेटवर्क : समुद्रीय मार्गों की पहचान, उभरती संरचना और चुनौतियां, आसियान–भारतीय समुद्री परिवहन सहयोग : आगे के रास्ते। सुश्री रेनु पाल, संयुक्त सचिव (आसियान एम एल), विदेश मंत्रालय ने सत्रों की अध्यक्षता की।

(xvi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नैतिकता, एकरूपता समावेश : वैश्विक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर नई दिल्ली में 6–7 मार्च 2014 को एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की कार्यसूची में उभरती हुई प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति में नैतिकता तथा एकरूपता; खाद्य प्रौद्योगिकी; नैनोटेक्नोलॉजी, सिन्थेटिक जीव विज्ञान; आगे के लिए ठोस कदम; भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति की नैतिकता; मिशन एवं प्रौद्योगिकी नीति में संचार एवं वचनबद्धता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसमें भाग लेने वालो में श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आर.आई.एस, डॉ. के विजय राघवन, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. वाए.एस. राजन, आई.एस.आर. ओ, बंगलौर और डॉ. एस.आर.राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग शामिल थे।

(xvii) आर.आई.एस में आसियान–भारत केंद्र; सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय; दक्षिण एशियाई, अध्ययन के लिए संस्थान ने संयुक्त रूप से आर.आई.एस में 6 मार्च, 2014 को भारत–सिंगापुर संबंध पर एक वार्तालाप आयोजित की। श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय इसमें एक मुख्य प्रवक्ता थे। बैठक में भारत की लुक इस्ट नीति, भारत–सिंगापुर संबंधों और आसियान–भारत संबंधों जैसे विषयों पर खुली चर्चा हुई।

(xviii) डब्लयू.डब्ल्यू.एफ– भारत और आर.आई.एस ने नई दिल्ली में 21 मार्च, 2014 को लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र चंगथंग पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई।

आर.आई.एस में आसियान–भारत केंद्र

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने नई दिल्ली में 21 जून 2013 को आर.आई.एस में आसियान–भारत केंद्र का उद्घाटन किया। श्री के. शन्मुगम, सिंगापुर विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 30 जुलाई 2013 को आर.आई.एस में आसियाई–भारत केंद्र पर उद्घाटन भाषण दिया।

आसियान–भारत विचार केंद्र नेटवर्क पर दूसरी गोलमेज

आर.आई.एस, आसियान सचिवालय, विदेश मंत्रालय तथा लाओ पीडीआर के विदेश मंत्रालय, विदेश मामलों के संस्थान ने विएना में 10 सितंबर, 2013 को आसियान–भारत विचार केंद्र नेटवर्क (एआईएनटीटी) की दूसरी गोलमेज आयोजित की। डॉ. थॉमलॉल सिसोलिथ, उप प्रधानमंत्री तथा लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री ने शुरूआती भाषण दिया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. ए.के.पी मोचतन, उप महासचिव, समुदाय एवं कारपोरेट मामलों के विभाग, आसियान सचिवालय, जकार्ता ने विशेष भाषण दिया1 इस अवसर पर आर.आई.एस की आसियान–भारत की सामरिक साझेदारी : आसियान–भारत विचार केंद्र नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य पर एक किताब भी प्रकाशित की गई।

राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष आर.आई.एस, राजदूत डा. वी.एस. सेशाद्री, सलाहकार और श्री सयान समन्ता, परामर्शदाता ने 28 नवंबर 2013 को ने पाई तौ, म्यामां में हुई ''भारत और म्यामां के बीच संयोजकता के गलियारों से विकास के गलियारों तक'' पर एक सम्मेलन में भाग लिया।

आर.आई.एस ने काफी संख्या में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें शामिल हैं– 11 फरवरी से 8 मार्च 2013 को विदेश मंत्रालय के आईटीईटी/एससीएएपी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे तथा विकास नीति (आई.ई.आई.डी.पी); 10 फरवरी से 7 मार्च 2014 तक विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम आईटीईटी/एससीएएपी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे तथा विकास नीति; 29 जनवरी 2013 को व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण की वैश्विक और क्षेत्रीय आयामों पर कार्यशाला, विदेशी राजनयिकों के लिए, विदेश मंत्रालय के विदशी सेवा संस्थान (एफएसआई) की ओर से 56 वां विदेशी राजनयिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम; 10 सितंबर 2013 को विदेशी राजनयिकों के लिए विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान तथा तीसरे आईओआर–आरसी और बांग्लादेशी राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण के अंतर्गत व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आयामों पर कार्यशाला; 18 अक्टूबर 2013 को विदेशी राजनयिकों के लिए विदेश मंत्रालय के एफ.एस.आई और 58 वें विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ और मौसम परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक और क्षेत्रीय आयामों के विषय पर कार्यशाला। जानकारी के लिए आर.आई.एस की वेबसाईट www.ris.org.in पर देखा जा सकता है।

आरआईएस प्रकाशन

आरआईएस प्रकाशनों की एक सूची अनुबंध XII पर दी गई है।

बजट

वर्ष 2013–14 के लिए आर.आई.एस को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 5.35 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। ■■

पुस्तकालय

29

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय में 1,00,000 से भी अधिक पुस्तकें, मानक चित्रों का विशाल संग्रह, सूक्ष्म फिल्में और सरकारी दस्तावेज हैं। यह नीति योजना और अनुसंधान को सहायता देने हेतु आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। पुस्तकालय लगभग 350 पत्र/पत्रिकाओं और अखबारों (ऑनलाईन पत्रिकाएं तथा डाटाबेस) का क्रय करता है। इसके अलावा पुस्तकालय में ''ईआईयू ऑनलाइरन सेवाएं'', ''मार्केटलाईन फॉम डाटा मॉनिटरिंग'', ''बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल'', ''केसिंग वर्ड न्यूज आरकाईव'', ''न्यूजपेपर डाइरेक्ट'', ''जेएसटीओआर'' आदि मंत्रालय के मुख्यालय, भारतीय मिशनों तथा विदशों में कार्यरत कर्मचारियों के अपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इन ऑनलाईन डाटाबेस तथा पत्र/पत्रिकाओं को यूजरनेम और पासवर्ड के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है। आवश्यक जानकारी समय–समय पर मुख्यालय के मंत्रालय तथा भारतीय मिशनों और विदेश स्थित केंद्रों को परिचालित कराई जाती है तथा वह विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाईट http://mealib.nic.in पर भी उपलब्ध है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकालय से जुड़ी गतिविधियां जैसे किताबों की खरीद और पत्र/पत्रिकाओं तथा डाटाबेस का क्रय आदि का प्रबंध करती है। वर्तमान समिति में संयुक्त सचिव (सीटी, सीएस और पीपी व आर) अध्यक्ष, टेरीटोरियल प्रभाग से तीन निदेशक सदस्य और निदेशक (पुस्तकालय व सूचना) सदस्य सचिव हैं।

पुस्तकालय की एक आंतरिक कम्प्यूटर प्रणाली है जिसमें बारह कम्प्यूटर और एक सरवर है। यह प्रणाली डाटा को हिंदी में भरने और पुनः प्राप्त करने की भी सहायता प्रदान करती है। पुस्तकालय में विदेशी मामलों और सामयिक विषयों पर भी सीडी–रोम डाटाबेस है। एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर 'लिबसिस' के प्रयोग से सभी दस्तावेज/ग्रंथसूची सेवाओं के साथ–साथ अन्य पुस्तकालय परिचालन सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। पुस्तकालय में इन्ट्रानेट के माध्यम से सभी किताबें, मानचित्र, सूक्ष्मफिल्में, दस्तावेज तथा पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त चयनित लेखों की जानकारी ऑनलाईन भी उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की जानकारी पुस्तकालय की वेबसाईट (http://mealib.nic.in) जो विदेश मत्रालय की वेबसाईट (www.mea.gov.in) पर देखी जा सकती है। मंत्रालय की पुस्तकालय की वेबसाईट http://mealib.nic.in को नियमित तौर पर अद्यतित किया जा रहा है।

पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले सभी नए दस्तावेजों जैसे पुस्तकें, मानचित्र, सूक्ष्म फिल्में, पत्र–पत्रिकाओं से चयनित लेखों को नियमित आधार पर विदेश मामलों से संबंधित डाटाबेस में डाला जाता है जिसे फेयर्स (FAIRS) कहा जाता है। इस डाटाबेस तथा सीडी रॉम डाटाबेस के प्रयोग से पुस्तकालय वर्तमान जानकारी सेवा और ग्रंथ सूची तथा संदर्भ सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा पुस्तकालय नियमित तौर पर जारी करता है:

विदेश मामलों से संबंधी प्रलेखन बुलिटिन (एफ.ए.डी.बी): अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संबंधित विषयों पर चयनित लेखों की एक सूची।

नए संस्करण : पुस्तकालय में पुस्तकों/प्रकाशनों की व्याख्यात्मक सूची जोड़ी गई।

आयोजनों का वृतांत : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर मुख्य समाचार पुस्तकालय, मंत्रालय के विदेशी सेवा अधिकारियों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों को सामूहिक ई–मेल आईडी पर दैनिक समाचार वृतांत, बुक एलर्ट तथा आर्टिकल एलर्ट नियमित रूप से जारी करता है।

पुस्तकालय ने एन.आई.सी के सहयोग से विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998–99 तक) और विदेश मामलों का रिकॉर्ड (1955 से 1999) का एक पूर्ण विषय सीडी–रोम संस्करण निकाला है। सीडी–रोम की जानकारी खोज व संयोजनों से पुनः प्राप्त की जा सकती है जिसमें किसी भी दिए गए शब्द या संयुक्त शब्दों की बुलेटिन खोज शामिल है। यह सीडी–रोम संस्करण 1 जनवरी 2000 को उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया गया है तथा यह परामर्श हेतु पुस्तकालय में उपलब्ध है।

जवाहर लाल नेहरू भवन में 2011 में एक अलग ''दुर्लभ पुस्तकों के लिए पुस्तकालय'' स्थापित किया गया और एक ''1824–1947 की दुर्लभ पुस्तकों की सूची'' प्रकाशित की गई जिसमें 500 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें हैं और यह पुस्तकालय में उपलब्ध है।

पुस्तकालय के प्रतिनिधियों ने सिंगापुर में हुए वार्षिक आईएफएलए

2013 सम्मेलन तथा समिति की बैठकों में भाग लिया। पुस्तकालय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अन्य व्यावसायिक संगठनों और संघों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मलन/संगोष्ठियों में भाग लिया जिनमें एसएलए, आईएलए, आईएएसएलआईसी और सीजीएलए शामिल है। निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) 2013–15 के लिए आईएफएलए के सरकारी सूचना एवं आधिकारिक प्रकाशन अनुभाग (जीआईओपीएस) के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने गए। एएलआईओ वर्ष 2013–15 के लिए आईएफएलए के सरकारी पुस्तकालय (जीएल) अनुभाग के नए अध्यक्ष चुने गए। एएलआईओ, आईएफएलए पत्रिका के ई सी सदस्य तथा आईएफएलए के मानक नियमावली के लिए डब्ल्यू जी सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहा है। पुस्तकालय का एएलआईओ बीजिंग में स्थित हमारे मिशन के पुस्तकालय के स्वचालन में सहयोग करता है।

पुस्तकालय दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को समय समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। पुस्तकालय उसके अनुसंधान विद्वानों सहित सभी उपयोगकर्ताओं का पुस्तकालय तथा उसके डाटाबेस जैसे सीडी–रोम डाटाबेस में प्रवेश के लिए स्वागत करता है। अनुसंधान विद्वानों सहित सभी पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को फोटोकॉपी और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की सुविधा प्राप्त है।

वित्त और बजट

30

विदेश मंत्रालय के लिए वर्ष 2013–14 का कुल परिव्यय बजट (संशोधित अनुमान चरण पर) रुपए 11793.65 करोड़ था जो वर्ष 2012–13 के बजट (रुपए 10120–69 करोड़) से 23.37 प्रतिशत ज्यादा था। इस बजट का मुख्य अंश योजना तथा गैर–योजना निधि के अंतर्गत अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए रखा गया है।

योजना

विदेश मंत्रालय बजट का योजना घटक भारत के पड़ोसी देशों जैसे भूटान, अफगानिस्तान, तथा म्यामां में कई बड़ी विकास परियोजनाओं, पनबिजली परियोजनाओं, कृषि, उद्योग आदि को पूरा करता है।

योजना बजट शीर्ष में भूटान हमारा एक प्रधान लाभार्थी है। कई महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएं जैसे पुनातसंगचु पनबिजली परियोजनाएं– I और II तथा मंगदेछू पनबिजली परियोजना चलाई जा रही है। योजना घटक से वित्त पोषण के लिए अफगानिस्तान भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अफगानिस्तान में काबुल से पुल–ए–खुमारी तक डबल सरकिट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के अतिरिक्त घटकों के रूप में अब दोशी और चरिकार पर दो उप–केंद्रों का निर्माण हो रहा है। म्यामां में कलादन बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना पर भी काफी प्रगति हुई है।

गैर–योजना

भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में वित्त वर्ष 2013–14 में प्रधान लाभार्थी में भूटान (रु. 2640.5 करोड़), बांग्लादेश (रु. 580 करोड़), अफगानिस्तान (रु. 525 करोड़), श्रीलंका (रु. 410 करोड़), नेपाल (रु. 380 करोड़), म्यामां (रु. 255 करोड़), अफ्रीकी देश (रु. 250 करोड़) थे। कई अन्य लाभार्थी में मालद्वीप, मंगोलिया, लैटिन अमेरिका के देश, यूरेशिया और अन्य क्षेत्र शामिल है।

मंत्रालय को 31.03.2014 तक पासपोर्ट जारी करने से, वीजा शुल्क से तथा अन्य प्राप्तयों से रु. 4046.66 करोड़ के बराबर राजस्व प्राप्ति हुई है। राजस्व प्राप्तियां रु. 1846.54 करोड़ (पासपोर्ट), रु. 1895.57 करोड़ (वीजा शुल्क), रु. 304.29 करोड़ (अन्य), रु. 0.25 करोड़ (सरकारी होटल, अतिथि गृह आदि से प्राप्ति) और रु. 0.01 करोड़ (आर.टी.आई.) से थी।

2013–14 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बजट आबंटन का कुल सेक्टोरल विश्लेषण यह बताता है कि रु. 11793.65 करोड़ के कुल आबंटन में से 60 प्रतिशत (रु. 7038.15 करोड़) बजट तकनीकी और आर्थिक सहयोग (रु. 5411.65 करोड़) के अंतर्गत परियोजनाओं तथा विदेशी सरकारों को ऋण और अग्रिम पर खर्च किया गया था। मिशनों और केंद्रों को बजट का 15 प्रतिशत (रु. 1738.23 करोड़) आबंटित किया गया था। अन्य आबंटन विशेष राजनयिक व्यय (12 प्रतिशत), पासपोर्ट तथा आप्रवास (4 प्रतिशत), पूंजी परिव्यय 2 प्रतिशत), विदेश मंत्रालय सचिवालय (2 प्रतिशत) और अन्य (1 प्रतिशत) पर किए गए थे।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

अन्य देशों के साथ भारत द्वारा संपन्न किए गए अथवा नवीकृत संधियों / अभिसमय / करार 2013–2014

क. बहुपक्षीय

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
1	चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड करार से संबंधित प्रोतोकोल		1 अप्रैल, 2013	

ख. द्विपक्षीय

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
1.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सेंटर नेशनल डी इटयूड्स स्पैशियल्स (सीएनईएस) के बीच अंतरिक्ष में दीर्घावधिक सहयोग के लिए आशय पत्र विवरण	14 फरवरी, 2013	14 फरवरी, 2013	
2.	भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आशय–पत्र	14 फरवरी, 2013	14 फरवरी, 2013	
3.	वर्ष 2013–2015 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान	14 फरवरी, 2013	14 फरवरी, 2013	
4.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय तथा परिवहन सागर एवं मात्स्यिकी मंत्रालय के बीच रेल क्षेत्र में अनुवर्ती कार्रवाई एवं सहयोग बढ़ाना	14 फरवरी, 2013	14 फरवरी, 2013	
5.	कोरिया गणराज्य के रणनीति एवं वित्त मंत्रालय और भारत गणराज्य के वित्त मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	07 फरवरी, 2013	07 फरवरी, 2013	
6.	अगरतला (भारत) और अखौरा (बांग्लादेश) के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए रेल अवसंरचना के विकास के लए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	16 फरवरी, 2013	16 फरवरी, 2013	

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
7.	भारत–बांग्लादेश फांउडेशन की स्थापना के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	16 फरवरी, 2013	16 फरवरी, 2013	
8.	आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन पर रोक के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडेन अधिराज्य की सरकार के बीच केन्द्रीय अभिसमय में संशोधन करने वाला प्रोतोकोल	07 फरवरी, 2013		
9.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश विदेश सेवा अकादमी, विदेश मंत्रालय , बांग्लादेश जनावादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	10 फरवरी, 2013	10 फरवरी, 2013	
10.	भारत गणराज्य और अजरबेजान गणराज्य के बीच सिविल मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि	04 अप्रैल, 2013		
11.	आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता के संबंध में भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच संधि	04 अप्रैल, 2013		
12.	भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	04 अप्रैल, 2013	18 अप्रैल, 2013	
13.	मानकीकरण, अनुकूलता आकलन और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग हेतु गुणवत्ता आवसंरचना संबंधी एक भारत–जर्मनी कार्यकारी समूह के गठन के संबंध में भारत गणराज्य के उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं जनवितरण मंत्रालय और जर्मनी के संधीय गणराज्य के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के संघीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त आशय की घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
14.	सिविल सुरक्षा अनुसंधान पर भारत–जर्मनी सहयोग से संबंधित संयुक्त आशय की घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
15.	उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के शिक्षा और अनुसंधान के संघीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	11 अप्रैल, 2013		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
16.	हरित ऊर्जा गलियारों की स्थापना के संबध में भारत–जर्मनी विकास सहयोग पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय और भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के बीच संयुक्त आशय की घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
17.	भारत में विदेशी भाषा के रूप में जर्मन भाषा को बढ़ावा देने के संबंध में भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय विदेश कार्यालय के बीच संयुक्त आशय की घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
18.	कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के खाद्य, कृषि और उपभोक्ता सुरक्षा के संघीय मंत्रालय (बीएमईएलवी) के बीच संयुक्त घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
19.	सौर्य ऊर्जा केन्द्र के संबंध में भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन	11 अप्रैल, 2013		
20.	भारतीय और चीनी शहरों एवं राज्यों / प्रातों के बीच सहयोग और संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच करार	20 मई, 2013		20 मई, 2013
21.	श्रेष्ठ एवं समकालीन साहित्यों के परस्पर अनुवाद और प्रकाशन में सहयोग पर भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के स्टेट प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		20 मई, 2013
22.	चीन जनवादी गणराज्य के तिब्बत स्वायत क्षेत्र में भारतीय सरकारी तीर्थयात्रा (कैलाश मानसरोवर यात्रा) के संबंध में भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच प्रोतोकोल	20 मई, 2013		20 मई, 2013
23.	भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के बीच कार्यक्रम	20 मई, 2013		20 मई, 2013

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
24.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा संगरोधन के सामान्य प्रशासन के बीच भारत द्वारा चीन को भैंस के मांस के निर्यात के संबंध में समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		20 मई, 2013
25.	मैरिन इंडस्ट्री, भारत सरकार, भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवक्षण, निरीक्षण और संगरोधन के सामान्य प्रशासन के बीच मात्स्यिकी उत्पादों का आयात एवं निर्यात व्यापार से संबंधित सहायोग पर समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		20 मई, 2013
26.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोधन के सामान्य प्रशासन के बीच खाद्य एवं खाद्य वस्तुओं के व्यापार एवं सुरक्षा संबंधी करार	20 मई, 2013		20 मई, 2013
27.	जल किफायत सिंचाई के क्षेत्र में सहयोग पर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, भारत गणराज्य और राष्ट्रीय विकास एंव सुधार आयोग, चीनी जनवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		20 मई, 2013
28.	चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में यालुजाग्वु/ब्रह्मपुत्र नदी की जल वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने के संबध में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		05 जून, 2013
29.	जलमल उपचार के क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के बीच समझौता ज्ञापन	20 मई, 2013		20 मई, 2013
30.	भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच समुद्री नौवहन करार	24 मई, 2013		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
31.	परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा सरकार के बीच करार के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार और कनाडा के परमाणु सुरक्षा आयोग के बीच करार	14 मार्च, 2013 नई दिल्ली में 21 मार्च, 2013 कनाडा में		21 मार्च, 2013 कनाडा में
32.	कोरिया गणराज्य के राजनीति एवं वित्त मंत्रालय और भारत गणराज्य के वित्त मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	07 फरवरी, 2013		07 फरवरी, 2013
33.	आपातकालीन स्थिति के दुष्प्रभावों को रोकने एवं समाप्त करने में सहयोग के लिए भारत–रूस संयुक्त आयोग का विनियमन	10 अप्रैल, 2013		
34.	चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में यालुजांग्बु/ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जल वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत गणराज्य और जलविज्ञान एवं जल संसाधन ब्यूरो, तिब्बत स्वायत क्षेत्र, चीन जनवादी गणराज्य के बीच कार्यान्वयन योजना	30 मई, 2013		5 मई, 2013
35.	वर्ष 2013–2016 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और क्यूबा गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	27 मई, 2013		27 मई, 2013
36.	आपातकालीन स्थति के दुष्प्रभावों को रोकने एवं समाप्त करने में सहयोग के लिए भारत–रूस संयुक्त आयोग का विनियमन	10 अप्रैल, 2013		
37.	जर्मनी संघीय गणराज्य के खाद्य, कृषि व उपभोक्ता संरक्षण के संघीय मंत्रालय (बीएमईएलवी) और नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआई) और जर्मन एसोसिएशन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स (बीडीपी) के द्विपक्षीय "सहयोग का कार्यक्रम" के लिए अपने अधिदेश के अनुसार कार्य करते हुए कृषि मंत्रालय तथा जर्मनी संघीय गणराज्य के खाद्य, कृषि और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के बीच संयुक्त घोषणा	11 अप्रैल, 2013		11अप्रैल, 2013

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
38.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और अजरबैजान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर प्रोतोकोल	3 मई, 2013		3 मई, 2013
39.	सौर्य ऊर्जा केन्द्र, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक नं. 14 सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, भारत और अपने फ्राउन होफर इंस्टीट्यूट फोर सोलर एनर्जी सिस्टम (आईएसई) के रूप में फ्राउन होफर–जेसेलसेफ्ट जुर फोर्डरंग डेर आंगेवांडटेन फोरशंग ई. V हैन सस्त्रा बे 27 सी, 80686 मंचेन के बीच समझौता ज्ञापन	11 अप्रैल, 2013		11अप्रैल, 2013
40.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और फ्रास गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय और समुद्री परिवहन एवं मात्स्यिकी मंत्रालय के बीच रेल क्षेत्र में अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं सहयोग सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त वक्तव्य ।	14 फरवरी, 2013		
41.	सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	12 जून, 2013		12 जून, 2013
42.	मानकीकरण, अनुकूलता आकलन तथा उत्पाद सुरक्षा में सहयोग हेतु गुणवत्ता अवसंरचाना पर एक जर्मनी–भारत कार्यकारी समूह के स्थापना के संबंध में जर्मन संघीय गणराज्य के संघीय आर्थिक कार्य एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत गणराज्य के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त आशय घोषणा	11 अप्रैल, 2013		
43.	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए अल्पावधिक वीजा में परस्पर छूट देने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार	17 जून, 2013		
44.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, विदेश मंत्रालय, ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	4 मई, 2013		4 मई, 2013

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
45.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और ईरान के मानक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (आईएसआईआरआई) के बीच समझौता ज्ञापन	4 मई, 2013		4 मई, 2013
46.	जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	4 मई, 2013		4 मई, 2013
47.	सूरीनाम मानक ब्यूरो और भारतीय मानक ब्यूरों के बीच समझौता ज्ञापन	14 जून, 2013		14 जून, 2013
48.	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम संबंधी करार में संशोधन करते हुए भारत गणराज्य की सरकार और पोलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच प्रोतोकोल	29 जनवरी, 2013		
49.	स्टैण्ड बाई क्रेडिट फैसिलिटी 2011 के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और मालद्वीव गणराज्य की सरकार के बीच करार संबंधी परिशिष्ट	10 सितम्बर, 2013		
50.	भारत के योजना आयोग और जापान के आर्थिक कार्य, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच 7 वीं भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अवसर पर संयुक्त विवरण	12 सितम्बर, 2013		
51.	ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ईराक गणराज्य के तेल मंत्रालय के बीच समझौता	23 अगस्त, 2013		
52.	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय और इराक गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	23 अगस्त, 2013		
53.	करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चीन जनवादी गणराज्य के मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार के बीच करार	3 जनवरी, 2012		
54.	एक संयुक्त आयोग की स्थापना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और लाईबेरिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	11 सितम्बर, 2013		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
55.	तेल एवं गैस के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और लाईबेरिया गणराज्य के भूमि, खान और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	11 सितम्बर, 2013		
56.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, लाइबेरिया गणराज्य के बीच समझौता	11 सितम्बर, 2003		

परिशिष्ट–II

जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज

क्र.सं.	अभिसमय / संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
1.	भारत गणराज्य तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार	23 जनवरी, 2013
2.	भारत गणराज्य की सरकार तथा गिब्राल्टर गणराज्य की सरकार के बीच टैक्स के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान संबंधी करार	23 जनवरी, 2013
3.	भारत गणराज्य तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण के संबंध में संधि	25 जनवरी, 2013
4.	भारत गणराज्य की सरकार तथा पॉलिश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम पर करार के संशोधन के लिए भारत सकरार गणराज्य तथा पोलैंड गणराज्य सरकार के बीच प्रोतोकॉल	29 जनवरी, 2013
5.	भारत गणराज्य की सरकार तथा स्वीडन राज्य की सरकार के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम पर हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोतोकॉल	4 फरवरी, 2013
6.	भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम पर हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोतोकॉल	12 फरवरी, 2013
7.	भारत गणराज्य तथा पुर्तगाल गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा के संबंध में करार	21 फरवरी, 2013
8.	भारत गणराज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा मॉरीशस गणराज्य के सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और सुधार संस्थान मंत्रालय के बीच वरिष्ठ नागरिक तथा विकलांग व्यक्तियों के संबंध में समझौता ज्ञापन	19 फरवरी, 2013
9.	भारत गणराज्य की सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	28 फरवरी, 2013
10.	रोमानिया के संचार एवं सूचना समाज मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन	27 फरवरी, 2013
11.	भारत गणराज्य तथा अजरबैजान गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहयोग के संबंध में संधि	14 मार्च, 2013

परिशिष्ट–II

क्र.सं.	अभिसमय / संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
12.	भारत गणराज्य तथा अजरबैजान गणराज्य के बीच सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में विधिक एवं न्यायिक सहयोग संबंधी संधि	26 मार्च, 2013
13.	भारत गणराज्य की सरकार तथा माल्टा सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	28 मार्च, 2013
14.	भारत गणराज्य की सरकार तथा लिचिस्टिन रियासत की सरकार के बीच कर मामलों पर सूचना के आदान–प्रदान हेतु करार	1 मार्च, 2013
15.	भारत गणरज्य की सरकार तथा अल्बानिया गणराज्य के मंत्री परिषद के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	19 जून, 2013
16.	भारत गणराज्य के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड तथा ऑस्ट्रेलियन सीमा शुल्क सेवा के बीच सीमा शुल्क मामलों पर सीमा शुल्क सहयोग तथा आपसी प्रशासनिक सहायता के संबंध में 6 मार्च 2006 को हुए समझौता ज्ञापन में संशोधन	10 जुलाई, 2006
17.	भारत गणराज्य की सरकार तथा मोरक्को राज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोतोकॉल	1 अगस्त, 2013
18.	भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलाइज सरकार के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान करने हेतु करार	29 अगस्त, 2013
19.	भारत गणराज्य की सरकार तथा क्रोआतिया गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	29 अगस्त, 2013
20.	भारत गणराज्य तथा डेनमार्क राज्य के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोतोकॉल	11 सितंबर, 2013
21.	भारत गणराज्य तथा ब्राजील गणराज्य के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोटोकॉल	17 सितंबर, 2013
22.	नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन	8 अक्टूबर, 2013

परिशिष्ट–III

दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/सहमति दस्तावेज

क्र.सं.	अनुसमर्थन/सहमति दस्तोज	अनुसमर्थन जारी करने की तिथि
1.	भारत गणराज्य की सरकार तथा अल–सल्वाडोर गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवीनीकरण में सहयोग के संबंध में करार	27 फरवरी, 2013
2.	भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच सीमा–शुल्क मामलों में आपसी सहयोग के संबंध में करार	13 अगस्त, 2013
3.	भारत गणराज्य तथा जापान के बीच सामाजिक सुरक्षा के संबंध में करार	26 दिसंबर, 2012
4.	भारत गणराज्य तथा कनाडा के बीच सामाजिक सुरक्षा के संबंध में करार	26 दिसंबर, 2012
5.	भारत गणराज्य की सरकार तथा अर्जेन्टीना गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग में सहयोग के संबंध में करार	14 फरवरी, 2013
6.	भारत गणराज्य की सरकार तथा बोस्निया और हर्जिगोविना के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में करार	14 फरवरी, 2013
7.	भारत गणराज्य की सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य के बीच आय में करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	14 फरवरी, 2013
8.	भारत गणराज्य की सरकार तथा इंडोनेशिया सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	1 फरवरी, 2013
9.	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार–विरोधी अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करने के संबंध में करार पर सहमति	6 फरवरी, 2013
10.	भारत गणराज्य की सरकार, ब्राजील गणराज्य की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराजय की सरकार के बीच आई.बी.एस.ए के अंतर्गत पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी त्रिपक्षीय करार	11 फरवरी, 2013
11.	भारत गणराज्य की सरकार तथा यूक्रेन मंत्री परिषद के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार	21 फरवरी, 2013
12.	भारत गणराज्य तथा वियतनाम सामाजिक गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण के संबंध में संधि	7 मार्च, 2013
13.	भारत गणराज्य की सरकार तथा गिब्राल्टर सरकार के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान हेतु करार	7 मार्च, 2013

परिशिष्ट–III

14.	भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए अभिसमय को संशोधित करते हुए प्रोतोकॉल	18 मार्च, 2013
15.	भारत गणराज्य की सरकार तथा गिब्राल्टर सरकार के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान हेतु करार	7 मार्च, 2013
16.	भारत गणराज्य तथा ऑस्टिया गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा के संबंध में करार	2 अप्रैल, 2013
17.	भारत गणराज्य तथा रोमानिया के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम हेतु करार	2 अप्रैल, 2013
18.	भारत गणराज्य तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण के संबंध में संधि	20 मार्च, 2013
19.	भारत गणराज्य तथा पुर्तगाल गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा के संबंध में करार	9 अप्रैल, 2013
20.	अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के निशान (सहमति) के विषय में हुए मेड्रिड करार से संबंधित न्यायाचार	1 अप्रैल, 2013
21.	भारत गणराज्य की सरकार तथा पोलिश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए करार को संशोधित करते हुए भारत गणराज्य की सरकार तथा पोलैंड गणराज्य की सरकार तथा पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच नयाचार	12 अप्रैल, 2013
22.	भारत गणराज्य की सरकार तथा लेचिस्टिन रियासत की सरकार के बीच कर मामलों में सूचना के आदान–प्रदान के संबंध में करार	12 अप्रैल, 2013
23.	भारत गणराज्य की सरकार तथा स्वीडन राज्य की सरकार के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हुए अभिसमय को संशोधित करते हुए नयाचार	18 अप्रैल, 2013
24.	भारत गणराज्य तथा अजरबैजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	18 अप्रैल, 2013
25.	भारत गणराज्य की सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	17 मई, 2013
26.	भारत गणराज्य की सरकार तथा बहरीन राज्य की सरकार के बीच कर संबंधी सूचना के आदान–प्रदान हेतु करार	17 मई, 2013
27.	भारत गणराज्य की सरकार तथा उरुग्वे पूर्वी गणराज्य की सरकार के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	17 मार्च, 2013

परिशिष्ट–III

28.	भारत गणराज्य तथा अजरबैजान गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों पर आपसी विधिक सहयोग के संबंध में संधि	3 मार्च, 2013
29.	थाईलैंड राज्य तथा भारत गणराज्य के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी संधि	3 मार्च, 2013
30.	भारत गणराज्य की सरकार तथा माल्टा सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	31 मई, 2013
31.	भारत गणराज्य की सरकार तथा कोलंबिया गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	31 मई, 2013
32.	भारत गणराज्य की सरकार तथा अलबानिया गणराज्य के मंत्री परिषद के बीच आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	19 जुलाई, 2013
33.	भारत गणराज्य तथा थाईलैंड राज्य के बीच प्रत्यर्पण के संबंध में संधि	19 जुलाई, 2013
34.	भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच सीमा–शुल्क मामलों पर आपसी सहयोग संबंधी करार	13 अगस्त, 2013
35.	भारत गणराज्य तथा मोरक्को राज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम हेतु हुए अभिसमय को संशोधित करते हुए प्रोतोकॉल	9 सितंबर, 2013
36.	भारत गणराज्य तथा तुर्की गणराज्य के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में करार	27 सितंबर, 2013

परिशिष्ट–IV

आईटीईसी तथा एससीएएपी देशों की सूची
आईटीईसी देश

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
1.	अफगानिस्तान	31.	कोलंबिया
2.	अल्बानिया	32.	डोमिनीक गणराज्य
3.	अल्जीरिया	33.	कोमोरोस
4.	अंगोला	34.	कांगो
5.	अंगुइला	35.	कुक्स द्वीप
6.	एंटीगुआ एंड बरमुडा	36.	कोस्टारिका
7.	अर्जेन्टीना	37.	आइवरी कोस्ट
8.	अर्मेनिया	40.	चैक गणराज्य
9.	अजरबैजान	41.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
10.	बहामास	42.	गिबोटी
11.	बहरीन	43.	डोमीनिक गणराज्य
12.	बांग्लादेश	44.	इक्वाडोर
13.	बार्बाडोस	45.	मिस्र
14.	बेलारूस	46.	अल–सल्वाडोर
15.	बेलाइच	47.	इक्वेटोरियल गुयाना
16.	बेनिन	48.	एरिट्रिया
17.	भूटान	49.	एस्टोनिया
18.	बोलीविया	50.	इथापिया
19.	बोस्निया–हर्जेगोविना	51.	फिजी
20.	ब्राजील	52.	गेबन
21.	ब्रूनी दार–ए–स्लम	53.	जार्जिया
22.	बुल्गारिया	54.	ग्रेनेडा
23.	बुर्कीना फासो	55.	ग्वाटेमाला
24.	बरून्डी	56.	गुयाना
25.	कंबोडिया	57.	गुयाना बिसाऊ
26.	केप वर्डे द्वीप	58.	गुयाना
27.	केमन द्वीप	59.	हैती
28.	केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य	60.	हांडूरस
29.	चाड	61.	हंगरी
30.	चिली	62.	इंडोनेशिया

परिशिष्ट–IV

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
63.	ईरान	95.	नाईजर
64.	ईराक	96.	ओमान
65.	जमैका	97.	पलाऊ
66.	जोर्डन	98.	फिलीस्तीन
67.	कजाकिस्तान	99.	पनामा
68.	किरिबति	100.	पपुआ न्यूगिनी
69.	कोरिया (डीपीआरके)	101	पराग्वे
70.	किर्गिस्तान	102.	पेरू
71.	लाओस	103.	फिलीपिन्स
72.	लातविया	104.	पोलैंड
73.	लेबनान	105.	कतर
74.	लाईबीरिया	106.	साओ टोम गणराज्य
75.	लीबिया	107.	रोमानिया
76.	लिथुआनिया	108.	रूस
77.	मेसीडोनिया	109.	रवांडा
78.	मेडागास्कर	110	समोया
79.	मलेशिया	111	सेनेगल
80.	मालदीव	112.	सर्बिया
81.	माली	113.	सिंगापुर
82.	मार्सल द्वीप	114.	स्लोवाक गणराज्य
83.	मौरितानिया	115.	सोलोमन द्वीप
84.	मेक्सिको	116.	सोमालिया
85.	माइक्रोनेशिया	117.	श्रीलंका
86.	मोलदोवा	118.	सेंट किट्स एवं नेविस
87.	मंगोलिया	119.	सेंट लूसिया
88.	मान्टीनीग्रो	120.	सेंट विन्सेंट एवं ग्रेनाडिन्स
89.	मान्ट्सेरेट	121.	सूडान
90.	मोरक्को	122.	दक्षिण सूडान
91.	म्यांमा	123.	सूरीनाम
92.	नौरू	124.	सीरिया
93.	नेपाल	125.	ताजीकिस्तान
94.	निकारागुआ	126.	थाईलैंड

परिशिष्ट–IV

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
127.	तिमोर लेस्ट	**स्काप देशों की सूची**	
128.	टोगा	143.	केमरून
129.	टोंगा	144.	केमरून
130.	ट्रिनिदाद एंड टोबेगो	145.	गांबिया
131.	ट्यूनीशिया	146.	घाना
132.	तुर्की	147.	केन्या
133.	तुर्कमेनिस्तान	148.	लिसोथो
134.	तुर्क एवं कैकोज द्वीप	149.	मलावी
135.	तुवालु	150.	मॉरीशस
136.	यूक्रेन	151.	मोजाम्बिक
137.	उरूग्वे	152.	नमीबिया
138.	उजबेकिस्तान	153.	नाईजीरिया
139.	वनुआतु	154.	सेशेल्स
140.	वेनेजुएला	155.	सियरा लिओन
141.	वियतनाम	156.	दक्षिण अफ्रीका
142.	यमन	157.	स्वाजीलैंड
		158.	तंजानिया
		159.	यूगांडा
		160.	जांबिया
		161.	जिम्बाब्वे

परिशिष्ट–V

पैनल में शामिल आइटेक/स्कैप प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्रम सं.	संस्थान का नाम	शहर
लेखा, लेखापरीक्षा, बैंकिंग एवं वित्त पाठ्यक्रम		
01.	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
02.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा	नोएडा
03.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	पुणे
आई टी, दूरसंचार एवं अंग्रेजी पाठ्यक्रम		
04.	एप्टेक लिमिटेड	नई दिल्ली
05.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग	मोहाली
06.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग	नोएडा
07.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी व प्रबंधन उत्कृष्टता को मुंबई	
	08– सी.एम.सी. लिमिटेड	नई दिल्ली
09.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराबाद
10.	एन.आइ.आइ.टी. लिमिटेड	नई दिल्ली
11.	यू.टी.एल. प्रौद्योगिकी लिमिटेड	बंगलौर
प्रबंधन पाठ्यक्रम		
12.	भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	हैदराबाद
13.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान	दिल्ली
14.	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
एसएमई/ग्रामीण विकास पाठ्यक्रम		
15.	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान	अहमदाबाद
16.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नोएडा
17.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संस्थान	हैदराबाद
18.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
विशिष्ट पाठ्यक्रम		
19.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
20.	मानव पुनर्वास प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
21.	भारतीय जनसंचार संस्थान	नई दिल्ली
22.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र	कोलकाता
23.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (भारतीय मानक ब्यूरो)	नोएडा
25.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	चेन्नै

परिशिष्ट–V

क्रम सं.	संस्थान का नाम	शहर
26.	राष्ट्रीय शैक्षाणिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
27.	पोस्टल स्टाफ कॉलेज	गाजियाबाद
28.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान व सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
29.	वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	नोएडा
तकनीकी पाठ्यक्रम		
30.	केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाबाद
31.	केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान	हैदराबाद
32.	केंद्रीय औजार अभिकल्प संस्थान	हैदराबाद
33.	केंद्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन	नई दिल्ली
34.	जैव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	केरल
35.	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, प्रशिक्षण संस्थान	हैदराबाद
36.	भारतीय उत्पाद प्रबंधन संस्थान	कंसबहल, उड़ीसा
37.	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान	देरहादून
38.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की, जल विज्ञान विभाग
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की, जल संसाधन विकास व प्रबंधन विभाग
40.	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा व अनुसंधान संस्थान	सास नगर, पंजाब
41.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ	कोयंबटूर
पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पाठ्यक्रम		
42.	वैकल्पिक जल ऊर्जा केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,	रूड़की
43.	बेयरफुट कॉलेज	तिलोनिया, राजस्थान
44.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र	चेन्नै
45.	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंगलुरू
46.	सौर ऊर्जा केंद्र	गुड़गांव
47.	टीईआरआई (ऊर्जा व संसाधन संस्थान)	नई दिल्ली

परिशिष्ट–VI

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठी तथा प्रारंभ की गयी अध्ययन परियोजनाएं, जिनका आंशिक या पूर्ण वित्तपोषण नीति आयोजना एवं अनुसंधान प्रभाग द्वारा किया गया

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	परिशिष्ट संस्थान
1.	कलकत्ता विश्वविद्यालय परिसार, अलीपुर, कोलकाता में विदेश नीति अध्ययन संस्थान को आवर्ती अनुदान	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
2.	आईडीएसए द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान सहित पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बेहतर समझ के लिए संस्थागत आधार विकसित करने के लिए अध्ययन परियोजनाओं को जारी रखना	आईडीएसए, नई दिल्ली
3.	गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा समकालीनयुग में "भारत–चीन संबंधः अवसर, बांधाएं और दृष्टिकोण" के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	गढ़वाल विश्वविद्यालय
4.	अफ्रीकी अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा "जन समुदाय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा" विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
5.	एशियाई केंद्र, बंगलुरू द्वारा (i) पश्चिमी एशिया में संकट तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व (ii) दक्षिणी चीन सागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर में भारत के हित" विषयक दो संगोष्ठीयां	एशियाई केंद्र, बंगलुरू

परिशिष्ट–VII

01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2013 तक पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट सेवाओं का विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की कुल संख्या (सामान्य+तत्काल)	जारी किए गए सामान्य पासपोर्टों की संख्या	जारी किए गए तत्काल पासपोर्टों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या (सामान्य+तत्काल)	विविध आवेदन पत्रों की संख्या	उपलब्ध कराई गई विविध सेवाएं	जारी किए गए कुल पासपोर्ट तथा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाएं
अहमदाबाद	3,27,352	3,19,545	2,855	3,22,400	9,843	9,471	3,31,871
अमृतसर	88,042	84,115	3,377	87,492	5,539	5,472	92,964
बंगलौर	4,48,308	3,87,600	37,410	4,25,010	12,238	11,989	4,36,999
बरेली	78,565	70,947	2,954	73,901	1,865	1,797	75,698
भोपाल	1,10,844	88,614	13,019	1,01,633	1,145	1,107	1,02,740
भुवनेश्वर	78,191	72,434	5,878	78,312	3,234	3,094	81,406
चंडीगढ़	2,94,220	2,73,953	7,720	2,81,673	13,586	13,017	2,94,690
चेन्नई	3,60,236	3,21,038	33,570	3,54,608	13,068	12,745	3,67,353
कोचीन	2,69,940	2,14,672	54,619	2,69,291	18,049	17,918	2,87,209
कोएम्बटूर	98,185	97,942	3,987	1,01,929	1,401	1,383	1,03,312
देहरादून	49,945	42,260	4,288	46,548	1,513	1,468	48,016
दिल्ली	4,07,700	3,30,428	65,346	3,95,774	*12958	*12814	4,08,588
गाजियाबाद	1,12,523	97,411	12,530	1,09,941	1,864	1,786	1,11,727
गोवा	43,684	44,831	716	45,547	2,905	2,821	48,368
गुवाहाटी	62,443	41,484	9,260	50,744	1,355	1,072	51,816
हैदराबाद	5,90,964	5,51,699	34,505	5,86,204	46,108	44,253	6,30,457
जयपुर	1,95,661	1,85,290	7,077	1,92,367	10,244	9,964	2,02,331
जालंधर	1,63,348	1,65,498	1,163	1,66,661	17,317	17,115	1,83,776
जम्मू	26,162	25,700	20	25,720	941	917	26,637
कोलकाता	3,45,096	3,09,693	18,909	3,28,602	8,911	8,630	3,37,232
कोझीकोड	2,46,978	2,18,255	29,447	2,47,702	8,470	8,423	2,56,125
लखनऊ	4,27,546	3,91,375	10,673	4,02,048	19,799	19,180	4,21,228
मदुरई	1,89,982	1,86,878	104	1,86,982	8,566	8,214	1,95,196
मालापुरम	2,16,747	1,84,527	42,964	2,27,491	4,461	4,416	2,31,907
मुम्बई	3,35,380	3,04,831	35,735	3,40,566	8,279	7,919	3,48,485
नागपुर	80,448	69,624	5,947	75,571	1,023	1,000	76,571

परिशिष्ट–VII

01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2013 तक पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट सेवाओं का विवरण

पटना	1,78,754	1,58,569	2,433	1,61,002	8,732	8,449	1,69,451
पुणे	1,81,397	1,58,461	20,015	1,78,476	3,619	3,509	1,81,985
रायपुर	30,061	27,498	2,697	30,195	271	258	30,453
रांची	62,620	57,559	1,056	58,615	1,897	1,833	60,448
शिमला	28,842	23,957	2,864	26,821	1,466	1,449	28,270
श्रीनगर	65,052	59,660	138	59,798	821	236	60,034
सूरत	1,18,572	1,23,152	1,479	1,24,631	6,796	6,652	1,31,283
थाने	2,06,103	1,83,310	13,924	1,97,234	4,903	4,690	2,01,924
त्रिची	1,64,704	1,57,212	1,417	1,58,629	10,773	9,901	1,68,530
त्रिवेन्द्रम	1,65,338	1,35,935	28,650	1,64,585	10,862	10,785	1,75,370
विशाखापट्टनम	1,22,213	1,12,872	7,534	1,20,406	25,551	24,835	1,45,241
कुल	69,72,146	62,78,829	5,26,280	68,05,109	3,04,373	2,94,582	71,05,691

* (600 आईसी सहित)

प्रोतोकॉल

क	37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (पासपोर्ट+विविध सेवाएंसेवाएं =6805 09+294582	71,05,691
ख	विदेश मंत्रालय, पीवी–11 अनुभाग अनुभाग (सरकारी तथा राजनयिक पासपोर्ट)	25,130
ग	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3,008
घ	भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा जारी पासपोर्ट+ईसी+विविध सेवाएं	13,83,686
	कुल योग	85,17,515

परिशिष्ट–VIII

31.12.2013 तक केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग की क्षमता

समूह एवं पद का नाम	कुल स्वीकृत स्वीकृत पद
स्मूह 'क'	
पासपोर्ट अधिकारी	17
उप पासपोर्ट अधिकारी	71
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135
उप–योगः	**223**
स्मूह 'ख' (राजपत्रित)	
पासपोर्ट स्वीकृति अधिकारी	320
अधीक्षक	245
उप–योगः	**565**
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	
सहायक	428
हिंदी अनुवादक	23
समूह 'ग' (अराजपत्रित)	
प्रवर श्रेणी लिपिक	628
प्रवर श्रेणी लिपिक (हिंदी)	04
अवर श्रेणी लिपिक	648
ड्राईवर	00
आशुलिपिक	30
कार्यालय सहायक	148
उप योगः	**1,909**
कुल योगः	**2,697**

परिशिष्ट–IX

31 मार्च, 2014 तक मुख्यालयों तथा विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों की संवर्ग क्षमता वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित पद तथा बाह्य संवर्ग आदि को शामिल करते हुए

क्र.सं.	संवर्ग/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रेड–I	5	28	33
2	ग्रेड –II	6	40	46
3	ग्रेड –III	38	126	164
4	ग्रेड –IV	54	148	202
5	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान	98	231	329
6	(i) कनिष्ठ वेतनमान	10	25	35
	(ii) परिवीक्षार्थी आरक्षित	62		62
	(iii) अवकाश आरक्षित	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	19		19
	(v) प्रशिक्षण आरक्षित	7		7
	उप– योग	**314**	**598**	**912**
	भारतीय विदेश सेवा (ख)			
7	(i) ग्रेड –I	126	120	246
	(ii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	6		6
8	(i) एकीकृत ग्रेड –II एवं III	351	225	576
	(ii) अवकाश आरक्षित	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	16		16
	(iv) प्रशिक्षण आरक्षित	25		25
9	(i) ग्रेड – IV	186	431	617
	(ii) अवकाश आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	55		55
10	(i) ग्रेड – V/VI	157	88	245
	(ii) अवकाश आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	14		14
11	(i) साइफर संवर्ग का ग्रेड II	40	149	189
	(ii) अवकाश आरक्षित	24		24
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	377	508	885
	(ii) अवकाश आरक्षित	47		47
	(iii) प्रशिक्षा आरक्षित (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	12		12
13	द्विभाषिया संवर्ग	7	26	33
14	एल.एड टी. संवर्ग	23	1	24
	उप–योग	**1626**	**1548**	**3174**
	कुल योग	**1940**	**2146**	**4086**

परिशिष्ट–X

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मंत्रालय में भर्ती के आंकड़े तथा आरक्षित रिक्तियां

क्र.सं.	समूह	रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछला वर्ग
1.	समूह क	188	32	14	9
2.	समूह ख	193	26	16	21
3.	समूह ग	180	14	4	27
	कुल	**561**	**72**	**34**	**57**

परिशिष्ट–XI

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता वाले भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1.	अरबी	98
2.	बहासा इंडोनेशिया	10
3.	बहासा मलय	02
4.	बर्मी	05
5.	चीनी	67
6.	डच	00
7.	फ्रेंच	73
8.	जर्मन	31
9.	हिब्रू	06
10.	इटालियन	01
11.	जापानी	20
12.	कजाक	01
13.	किसवाहिली	06
14.	कोरियाई	04
15.	नेपाली	02
16.	फारसी	18
17.	पुर्तगाली	20
18.	पुस्तू	02
19.	रूसी	83
20.	सर्वो क्रोएशियन	01
21.	सिंहली	04
22.	स्पेनिस	68
23.	थाई	00
24.	तुर्की	07
25.	यूक्रेनियन	01
26.	वियतनामी	03
27.	जॉन्खा	01

परिशिष्ट–XII

आरआईएस प्रकाशनों की सूची

पुस्तकें

- द लीविंग ट्री : ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ इन चाइना एंड इंडिया

रिपोर्ट

- दक्षिण–दक्षिण सहयोग प्रदाता सम्मेलन की रिपोर्टः मुद्दे व उभरती चुनौतियां
- भारत–चीन व्यापार संबंध
- आसियान–भारत रणनीतिक भागीदारीः आसियान–भारत के विचारकों के नेटवर्क का परिदृश्य
- भारतीय स्वैच्छिक संगठनों 2013 का परिदृश्य
- एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणः राष्ट्रीय पहल एवं क्षेत्रीय सहयोग के अवसर

विचार–विमर्श पत्र

- भारत की नवोन्मेष नीतियों का मूल्यांकन–विश्वजीत धर तथा सव्यसाची साहा
- जनाकिंकी परिवर्तन प्रतिभा पलायन तथा मानव पूंजीः सेवा–चालित दक्षिण एशिया में निकास संभावनाएं विश्वजीत धर एवं सायन सामंत
- लद्दाख की चांगथांग सीमा प्रदेशः एक प्रारंभिक जांच– सिद्दिकी वाहिद
- भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पूर्वी एशिया आर्थिक क्षेत्रवाद के कुछ निहितार्थ तथा आरसीईपी राम उपेंद्र दास
- पार–अटलांटिक व्यापार एवं निवेश भागीदारी वी एस शेषाद्रि
- 2008 का वित्तीय संकट तथा आर्थिक शक्ति अंतरणः क्या
- अभिसरण है–विकास भागीदारी परियोजनाओं में राज्य व समुदाय की भागीदारी का संतुलनः नेपाल में भारतीय एसडीपी से उभरते साक्ष्य सचिन चतुर्वेदी, सुशील कुमार तथा शशोक मेंरिइटा
- द ट्रांस पैसीफिक पार्टनरशिप (टीपीपी)–वी. एस. शेषाद्रि
- संभार तंत्र, व्यापार एवं उत्पादन नेटवर्कः प्रबीर डे तथा अमृता साहा

नीतिगत सार

- चीन की अर्थव्यवस्थाः स्थिर, परंतु टिकाऊ बनाने की जरूरत दिसंबर, 2013
- खाद्यान्न प्रबंधन नीति, भारतीय खाद्य निगम और खाद्य सुरक्षा– जुलाई, 2013 के निहितार्थ
- दक्षिणी अफ्रीका को भेषजीय पेटेंटों की जांच क्यों करनी चाहिए– टीएसी, एमएसएफ तथा आरआईएस जनवरी, 2013

एफआईडीसी नीतिगत सार

- दक्षिण–दक्षिण सहयोग की विशेषताएं तथा वैश्विक गत्यात्मकता–जनवरी, 2014
- कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष में भारत–अफ्रीका सहयोगः नए अवसर एवं चुनौतियां

मेकांग–गंगा नीति सार

6 नवंबर, 2013

पत्रिकाएं

दक्षिण एशिया इकोनॉमिक जर्नल

- खंड 14, संख्या 1, मार्च, 2013
- खंड 14, संख्या 2, दिसंबर, 2013

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी विकास समीक्षा

- खंड 15, संख्या 1, मार्च, 2013
- खंड 15, संख्या 2, जुलाई, 2013
- खंड 15, संख्या 3, नवंबर, 2013

परिशिष्ट–XIII

वर्ष 2013–14 में बजट आबंटन (बीई) 11719 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2012–13 से 22.73% अधिक है। 2013–14 में संशोधित अनुमान 11793.65 करोड़ रुपए है, जो बजट अनुमान 2013–14 11719 करोड़ रुपए से 0.64% अधिक है।

वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय (राजस्व एवं पूंजी)

वर्ष	वस्तविक (करोड़ रुपए में)	पूववर्ती वर्ष की अपेक्षा परिवर्तन का :
2008 - 09	6630.73	45.02
2009 - 10	6290.77	-5.13
2010 - 11	7153.27	13.71
2011 - 12	7872.76	10.06
2012 - 13	10120.88	28.55
2013 - 14 (बीई)	11719.00	22.73
2013 - 14 (आरई)	11793.65	0.64

वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय (राजस्व एवं पूंजी)

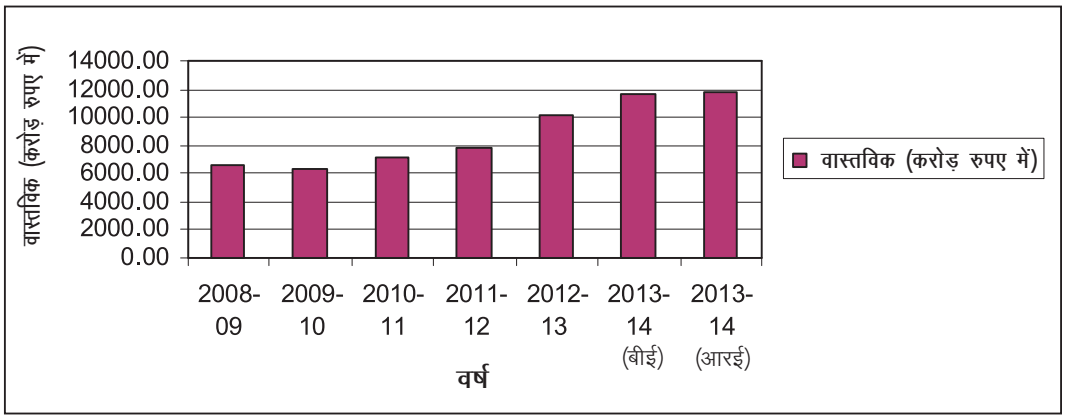

बजट आबंटन में अंतर का रूख वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक

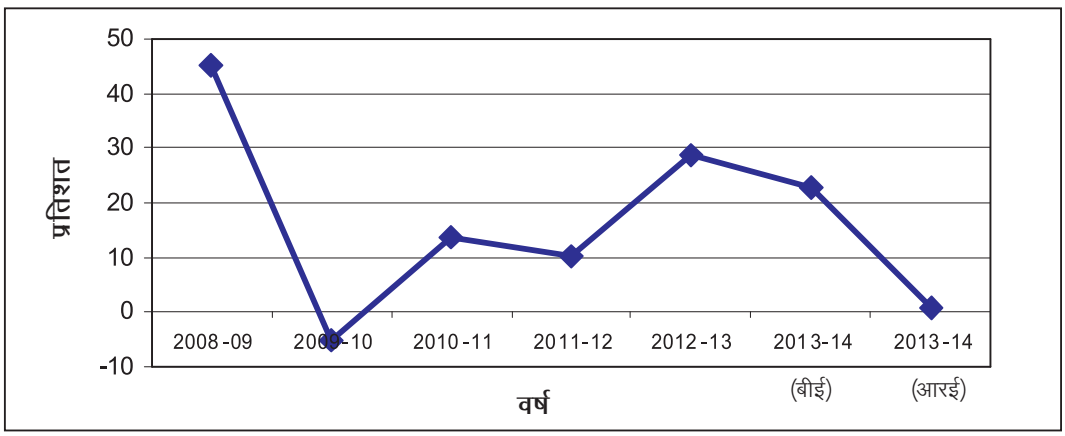

परिशिष्ट–XIV

वर्ष 2013–14 के बजट (संशोधित अनुमान) में प्रमुख क्षेत्रों को आबंटन

क्षेत्र	आबंटन (करोड़) रुपए में)
तकनीकी व आर्थिक सहयोग	5411.65
राजदूतावास एवं मिशन	1738.23
विदेशी सरकारों को ऋण व अग्रिम	1626.50
विशेष राजनयिक व्यय	1420.00
पासपोर्ट एवं आप्रवासन	432.48
अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान	299.23
विदेश मंत्रालय सचिवालय	261.67
पूंजीगत परिव्यय	270.00
संस्थानों को अनुदान	209.12
अन्य	124.77
कुल	**11793.65**

प्रमुख क्षेत्रों को आबंटन (2013–14)

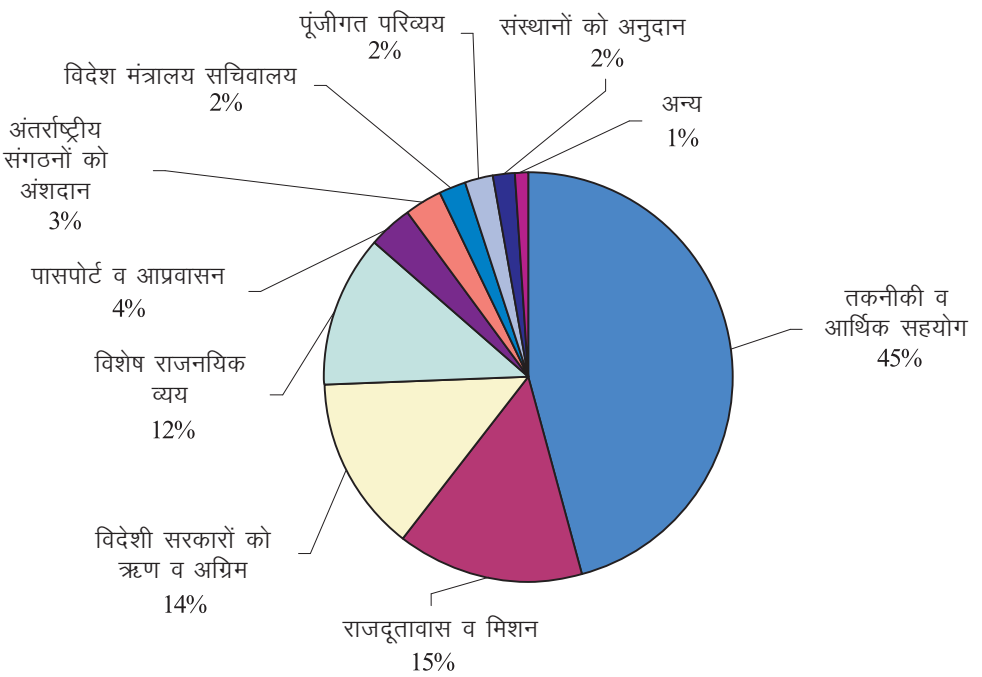

परिशिष्ट–XV

भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के मुख्य लक्ष्य

चालू वित्त वर्ष 2013–14 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के मुख्य लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है (ये आंकड़े संशोधित अनुमान 2013–14 से संबंधति है):

क्रम.सं.	तकनीकी सहयोग बजट	(करोड़ रू. में)	भारत की कुल सहायता का % एवं ऋण बजट
1.	भूटान	2640.5	48.79
2.	बांग्लादेश	580.00	10.72
3.	अफगानिस्तान	525.00	9.70
4.	श्रीलंका	410.00	7.58
5.	नेपाल	380.00	7.02
6.	म्यामां	255.00	4.71
7.	अफ्रीकी देश	250.00	4.62
8.	यूरेशियाई देश	25.00	0.46
9.	मालदीव	10.00	0.18
10.	लातिन अमरीकी देश	5.00	0.09
11.	मंगोलिया	1.50	0.03
12.	अन्य	329.65	6.09
	कुल	5411.65	100.00

परिशिष्ट–XVI

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा से संबंधित लंबित पैराओं की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	जिन पैराओं / पीए रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी लेखा परीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तु की गई है, उनकी संख्या	जिन पैराओं / पीए रिपोर्ट के संबंध में एटीएन लंबित है उनका ब्यौरा		
			ऐसे एटीएन की संख्या जो पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजी गई है।	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजी गई परन्तु टिप्पणी सहित वापस कर दी गई और मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	ऐसे एटीएन की संख्या जिन्हें लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित किया गया है परन्तु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1	2003	-	-	-	-
2	2004	-	-	-	-
3	2005	-	-	-	-
4	2006	-	-	-	-
5	2007	-	-	-	-
6	2008-09	-	-	-	-
7	2009-10	-	-	-	-
8	2010-11	-	-	1	-
9	2011-12	-	-	-	-
10	2012-13	-	-	1	-
11	2013	-	1	1	-
	कुल	-	**1**	**3**	-

अप्रैल, 2014 को समाप्त वर्ष की नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण लेखा टिप्पणियों का सार निम्नवत है:

1	कॉन्सुलर स्कंध का निष्पादन	अनेक मिशन तथा केन्द्र वीजा तथा अन्य कौंसली सेवाओं के लिए मंत्रालय द्वारा विहित शुल्क नहीं ले रहे थे जिसके परिणामस्वरूप 37.26 करोड़ रू. की वसूली कम हुई। मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण 21.55 करोड़ रू का शुल्क नहीं लगाया गया। कौंसल में प्राप्त राशि को सरकारी खाते में भेजने में पर्याप्त विलंब हुआ। विदेश स्थित मिशन निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर रहे थे जिससे सेवा प्रदाताओं के चयन में वित्तीय अनौचित्य तथा पारदर्शिता का अभाव रहा। पैराग्राफ 3.1

2	विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में वीजा सहायता सेवाओं की आउटसोर्सिंग	सीजीआई, मिशन में वीजा सहायता सेवाओं को आउटसोर्सिंग के लिए निविदा मूल्यांकन तथा सेवा प्रदाताओं के चयन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही जिससे ऐसे विक्रेता का चयन किया गया जो न्यूनतम बोलीदाता नहीं था। एच सी आई, लंदन में सेवा प्रदाता को 3.63 करोड़ रू. का अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिसका कारण केन्द्रों को प्रचालित वीजा सेवा केन्द्रों की संख्या से संबद्ध करने पर विचार नहीं किया जाना था। इसके अतिरिक्त, करार के प्रावधान के गलत निर्वचन के कारण सेवा प्रदाता को वीजा आवेदकों पर प्रशासनिक शुल्क लगाकर 1.96 करोड़ रू. का अतिरिक्त लाभ दिया गया। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में सेवा प्रदाता प्रति आवेदन न्यूनतम 18.95 अमरीकी डॉलर मेलिंग चार्जेज की तुलना में न्यूनतम 21 अमरीकी डॉलर की वसूली करते रहे जिससे सेवा प्रदाता को 1.16 करोड़ रू. का अनुचित लाभ मिला। मॉडल करार के महत्वपूर्ण प्रावधानों से सेवा प्रदाताओं के कार्यकरण एवं उनके द्वारा प्रदत सेवाओं पर मिशन/केन्द्र के नियंत्रण में कमी आई। सीजीआई फ्रैंकफर्ट ने कौंसली सेवाओं के लिए स्टाफ की क्षमता की समीक्षा नहीं की थी, भारतीय दूतावास, पेरिस में कौंसल स्टाफ की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। पैराग्राफ 6.6
3	सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ	मंत्रालय ने संपत्ति कर में वृद्धि के आधार पर प्रति वीजा आवेदन सेवा शुल्क की वर्तमान दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक सेवा प्रदाता को 3.45 करोड़ रू का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। पैराग्राफ 5.1
4	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कार्यचालन	ब्यौरा संलग्न पैराग्राफ अध्याय–1

अध्याय I : विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का कार्यचालन

मुख्य–मुख्य बातें:

- परिषद ने महासभा तथा शासी निकाय की बैठकें विहित संख्या में आयोजित नहीं की। इसने 2007–08 से 2009–10 का अपना बजट अनुमोदन हेतु वित्त समिति शासी निकाय तथा महासभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

(पैरा 1.2.1.1, 1.2.1.2 तथा 1.2.1.3)

- परिषद ने वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक की वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार नहीं की। यह चूक परिषद के संविधान तथा शासी निकायके निदेशों का उल्लंघन है।

(पैरा 1.2.1.4)

- परिषद ने कार्यक्रमों की प्रमाणकारिता के मूल्यांकन हेतु प्रणाली गठित करने के बारे में वित्त समिति तथा शासी निकाय के निदेशों का अनुपालन नहीं किया।

(पैरा 1.2.1.5)

- परिषद ने अपनी एक छात्रवृत्ति योजना का पर्याप्त प्रचार नहीं किया जिससे स्लॉट के उपयोग में कमी आई तथा प्रतिनिधित्व अपर्याप्त रहा।

(पैरा 1.2.2.1)

- परिषद ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 25: स्लॉट का आबंटन उन देशों को किया जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम / शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के संबंध में कोई विधिमान्य करार मौजूद नहीं था।

(पैरा 1.2.2.2)

- विदेशों में 14 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाने का अनुमोदन दिया गया था जबकि परिषद ने 17 केन्द्र खोले / परिषद बिना अपेक्षित अनुमोदन के 8 अतिरिक्त आईसीसी खोलने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है।

(पैरा 1.2.3.3)

- परिषद के विदेश स्थित भारतीय सांस्कृति केन्द्रों में निदेशकों के पद पर तैनाती की गई थी जबकि वित्त मंत्रालय से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी।

(पैरा 1.2.4.2.क)

- परिषद ने आईसीसी में निदेशकों के रूप में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति तथा वेतन व भत्तों के भुगतान के संबंध में मार्गनिर्देशों / मानदण्डों का निर्धारण नहीं किया है।

(पैरा 1.2.4.2.ख)

- परिषद ने विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों के लिए कलाकारों के चयन एवं प्रायोजन हेतु नियमों, विनियमों एवं मानदण्डों का निर्माण नहीं किया।

(पैरा 1.2.5)

- वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान 70 देशों को भेजे गए चार शिष्टमंडलों पर होने वाले 8.15 करोड़ रू. का व्यय सक्षम प्राधिकारी अर्थात आईसीसीआर के अध्यक्ष से अनुमोदित नहीं था और इसलिए अप्राधिकृत था।

(पैरा 1.2.6.1)

- परिषद में खरीद प्रक्रिया तथा भुगतान हेतु बिलों के संबंध में कार्रवाई के मामले में काफी खामियां थीं।

(पैरा 1.2.6.2)

संक्षिप्तियां

आल्को	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक
एसोचौम	एसोसिएट्स चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
एयू	अफ्रीकी संघ
एडब्ल्यूजी–एलसी	दीर्घावधिक सहयोगात्मक कार्रवाई पर एडी–एचओसी कार्य समूह
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक
बार्क	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
बिमस्टेक	बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बिप्पा	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा सुरक्षा करार विज्ञान संस्थान
ब्रिक	ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन
सीबीएम	विश्वास उत्पादक उपाय
सीबीआरएन	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु
सीलैक	लातिन अमरीकी तथा कैरीबियाई देशों का समुदाय
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी करार
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलएमवी	कंबोडिया, लाओ पीडीआर, बर्मा एवं वियतनाम
सीपीआईओ	मुख्य जन सूचना अधिकारी
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा
टीएए	दोहरा कर परिवर्जन करार
इएएसए	विदेश मंत्रालय स्पाउजेज संघ
इकोसोक	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्जिम	भारतीय निर्यात–आयात बैंक
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
एफआईडीसी	भारतीय विकास सहयोग संघ
एफएमसीटी	फिसाइल सामग्री कट ऑफ संधि
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
जी–20	समूह बीस
जीसीटीएफ	वैश्विक आतंकवाद निरोध मंच
जीएफएमडी	वैश्विक देशांतरण तथा विकास मंच
जीओआई	भारत सरकार
एचईपी	जल–विद्युत परियोजना
एचआरसी	मानवाधिकार मंच
आईएएफएस	भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
आईएएनएस	भारत–एशिया समाचार सेवा
इबसा	भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच
आईध्सी	स्वतंत्र प्रभार
आईसीएओ	अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
आईडीपी	आंतरिक विस्थापित व्यक्ति
आईडीएफआर	राजनय तथा विदेश संबंध संस्थान
आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएमसी	भारतीय जन संचार संस्थान
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईओएम	अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन
आईओएनएस	बौद्धिक विज्ञान संस्थान
आईओआर–एआरसी	क्षेत्रीय सहयोग पर हिंद महासागर परिधि संघ
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीयू	अंतरसंसदीय संघ
आईआरईएनए	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटेक	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
आईटीएमए	अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माता संघ
आईवीएफआरटी	उत्प्रवासन,वीजा तथा विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग

जेसीबीसी	व्यापार सहयोग संयुक्त समिति
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलसीएस	थल सीमा शुल्क केंद्र
एलडीसी	अल्पतम विकसित देश
एलओसी	ऋण श्रृंखला
एमईपी	यूरोपीय संसद सदस्य
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमजीसी	मैकांग–गंगा सहयोग
एमओईएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपी	सांसद
एमटीसीआर	मिसाइल तकनीक नियंत्रण प्रणाली
नाम	गुट–निरपेक्ष आन्दोलन
नासा	राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रशासन
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
निफ्ट	राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
एनपीटी	अप्रसार संधि
एनएससी	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
ओसीआई	भारतीय समुद्रपारीय नागरिकता
आईसीडी	आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन
ओपीसीडब्ल्यू	रासायनिक हथियार निषेध संगठन
ओटीएस	प्रशिक्षु अधिकारी
फारमैक्सिल	भारत भेषज निर्यात संवर्धन परिषद
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीटीए	अधिमानिक व्यापार करार
पीटीआई	भारतीय प्रेस ट्रस्ट
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा परियोजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरजीओबी	भूटान सरकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
साफ्टा	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र
साऊ	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक

एस्कैप	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एसडीपी	लघु विकास परियोजना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईडी	सामरिक आर्थिक वार्ता
सिका	मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसआर	विशेष प्रतिनिधि मंडल
टेरी	टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
उनासुर	दक्षिण अमरीकी राष्ट्र संघ
अनसिट्रल	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
यूएसीओपीयूओएस	बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीएसटीडी	विज्ञान तथा तकनीक विकास पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूनीस्कैप	एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूनिफिल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनओडीसी	स्वापक तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
एक्सपीडी	विदेश प्रसार तथा लोक राजनय प्रभाग

विदेश मंत्रालय
भारत सरकार

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है :
www.mea.gov.in